Monthly Current Affairs-September

S. No.	Contents	Page No
1.	महत्वपूर्ण दिन और विषय	02
2.	बैंकिंग और अर्थव्यवस्था	03
3.	व्यापार	77
4.	नेशनल करेंट अफेयर्स	92
5.	इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स	143
6.	स्टेट करेंट अफेयर्स	162
7.	रैंक और सूचकांक	181
8.	समझौता और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर	184
9.	राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार	207
10.	नियुक्तियां	212
11.	डिफेन्स	227
12.	स्पोर्ट्स	241
13.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	258
14.	अधिग्रहण और विलय	269
15.	किताबें और लेखक	275
16.	शोक सन्देश	275

Click Here to Subscribe Our Yearly Mock Test Package

महत्वपूर्ण दिन और विषय

तारीख	दिन	थीम
1-7 सितंबर	राष्ट्रीय पोषण सप्ताह	हैल्दी डाइट गाविंग अफोर्डेबल फॉर ऑल
2 सितंबर	विश्व नारियल दिवस	
5 सितंबर	अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस	
5 सितंबर	राष्ट्रीय शिक्षक दिवस	
8 सितंबर	विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस	
8 सितंबर	विश्व साक्षरता दिवस	प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर ए वर्ल्ड इन ट्रांजीशन: बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटीज
14 सितंबर	हिंदी दिवस	
15 सितंबर	अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस	
15 सितंबर	राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस	
16 सितंबर	विश्व ओजोन दिवस	'मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल: ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना'
हर साल सितंबर का तीसरा शनिवार	अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस	
17 सितंबर	विश्व रोगी सुरक्षा दिवस	रोगी सुरक्षा के लिए रोगियों को शामिल करना
18 सितंबर	विश्व बांस दिवस	
21 सितंबर	अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस	डिग्निटी, फ्रीडम, एंड जस्टिस फॉर ऑल
21 सितंबर	विश्व अल्जाइमर दिवस	नेवर टू अर्ली, नेवर टू लेट
22 सितंबर	विश्व गुलाब दिवस	
23 सितंबर	अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस	
25 सितंबर	अंत्योदय दिवस	
27 सितंबर	विश्व पर्यटन दिवस	
28 सितंबर	विश्व समुद्री दिवस	50 पर MARPOL - हमारी प्रतिबद्धता जारी है
28 सितंबर	विश्व रेबीज दिवस	ऑल फॉर 1, वन हेल्थ फॉर ऑल
29 सितंबर	विश्व हृदय दिवस	दिल का उपयोग करें, दिल को जानें
29 सितंबर	खाद्य हानि और बर्बादी के बारे में जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस	

बैंकिंग और अर्थव्यवस्था

IDRCL के साथ विलय में असहमति पर बैड बैंक के अध्यक्ष कर्णम सेकर ने इस्तीफा दे दिया

कर्णम शेखर, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया (NARCL) के अध्यक्ष, जिसे आमतौर पर बैड बैंक के रूप में जाना जाता है, ने संस्था की संरचना और कामकाज में मतभेदों के कारण इस्तीफा दे दिया है।

भारतीय राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्गठन कंपनी (NARCL) के चेयरमैन शेखर ने सार्वजनिक क्षेत्र की NARCL का इंडिया डेट रिजॉल्यूशन कंपनी लिमिटेड (IDRCL) में विलय का प्रस्ताव आने के तुरंत बाद इस्तीफा दे दिया।

विलय प्रस्ताव की उत्पत्ति:

रिपोर्ट में कहा गया है कि दो संस्थाओं के विलय का प्रस्ताव सबसे पहले IDRCL की ओर से आया था, जिसके अध्यक्ष भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के पूर्व प्रबंध निदेशक (MD) दिवाकर गुप्ता थे।

वित्त मंत्रालय को यह सुझाव दिया गया था कि व्यापार के अवसरों को अनुकूलित करने और लागत को कम करने के लिए दोनों संस्थाओं का विलय किया जाना चाहिए।

NARCL और IDRCL की वर्तमान भूमिकाएँ:

मौजूदा संरचना के तहत, NARCL, 'प्रमुख इकाई' के रूप में काम करते हुए, विभिन्न बैंकों से खराब ऋण खातों के अधिग्रहण और समेकन का कार्य करती है।

दूसरी ओर, IDRCL एक समाधान एजेंट के रूप में कार्य करता है, जो संकटग्रस्त संपत्तियों की समाधान प्रक्रिया में विशेषज्ञता रखता है

बैड बैंक क्या है?

बैड बैंक एक वित्तीय इकाई है जो बैंकों से गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (NPA), या ख़राब ऋण खरीदने के लिए स्थापित की जाती है।

बैड बैंक स्थापित करने का उद्देश्य बैंकों की बैलेंस शीट से खराब ऋणों को हटाकर उन पर पड़ने वाले बोझ को कम करने में मदद करना है और उन्हें बिना किसी बाधा के ग्राहकों को फिर से ऋण देने के लिए प्रेरित करना है।

NARCL के बारे में:

शामिल: जुलाई 2021 में वाणिज्यिक बैंकों की तनावग्रस्त संपत्तियों के निपटान में मदद के लिए 'बैड बैंक' के रूप में।

प्रबंध निदेशक: एन सुंदरएआर

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) के पास NARCL का 51% स्वामित्व है।

जबकि FI या ऋण प्रबंधन कंपनियों के पास 49% हिस्सेदारी होगी।

IDRCL के बारे में:

IDRCL एक सेवा कंपनी या एक परिचालन इकाई है, जो बाजार पेशेवरों और टर्नअराउंड विशेषज्ञों की संपत्ति और लूप का प्रबंधन करेगी।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) और सार्वजनिक FI के पास अधिकतम 49% हिस्सेदारी होगी और बाकी निजी क्षेत्र के ऋणदाताओं के पास होगी।

ADB ने हैदराबाद में सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन परियोजनाओं के लिए 3.32 करोड़ रुपये की मंजूरी दी

प्रोफेसर प्रशांत साहू द्वारा समन्वित बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस (BITS) हैदराबाद, तेलंगाना, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) बॉम्बे, महाराष्ट्र और IIT खड़गपुर, पश्चिम बंगाल के प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों की एक टीम ने शहरी पारगमन के लिए प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए एशियाई विकास बैंक का 3.99 लाख अमेरिकी डॉलर (3.32 करोड़ रुपये) का अनुदान जीता है। हैदराबाद की सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों में इसका परीक्षण और कार्यान्वयन करें। विशेषज्ञों की टीम हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड (HMRL) के प्रबंध निदेशक (MD) NVS रेड्डी के मार्गदर्शन में मेट्रो रेल और सार्वजनिक पारगमन यात्रियों के लिए अंतिम-मील सुरक्षा में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी समाधान विकसित करने पर काम कर रही थी।

TUTEM स्थापना कार्यशाला BITS में आयोजित की गई थी, हैदराबाद कैंपस, मुख्य अतिथि के रूप में DGP अंजनी कुमार और सम्मानित अतिथि के रूप में MD, HMRL NVS रेड्डी थे।

नवीनतम समाचार:

अगस्त 2023 में, एशियाई विकास बैंक (ADB) और चौथे भागीदार एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (चौथा भागीदार) एक स्वतंत्र बिजली उत्पादक (IPP) ने वाणिज्यिक और औद्योगिक ग्राहकों को स्वच्छ और कम लागत वाली ऊर्जा आपूर्ति बढ़ाने के लिए 25 मेगावाट सौर फोटोवोल्टिक-आधारित बिजली संयंत्र के निर्माण और संचालन के लिए 1.2 बिलियन भारतीय रुपये (लगभग 14.7 मिलियन डॉलर) के दीर्घकालिक ऋण पर हस्ताक्षर किए।

अगस्त 2023 में, भारत एशियाई विकास बैंक (ADB) के साथ साझेदारी में नई दिल्ली में एक जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए तैयार है।

ADB के बारे में:

स्थापना: 19 दिसंबर 1966
मुख्यालय: मांडलुयॉन्ग, फिलिपींस
राष्ट्रपति: मासात्सुगु असकावा
सदस्यता: 68 देश

नवाचार आधारित हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए IIT बॉम्बे ने HSBC के साथ साझेदारी की

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-बॉम्बे (IIT-B) ने ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को अधिक कुशल, लागत प्रभावी और स्केलेबल बनाने की दिशा में तकनीकी प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन (HSBC) के साथ भागीदारी की है।

इस सहयोग का उद्घाटन 24 अगस्त, 2023 को दिल्ली में केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा किया गया था।

उन नवोन्मेषी परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जो हरित हाइड्रोजन को एक रणनीतिक वैकल्पिक ईंधन के रूप में स्थापित करने में मदद करेंगी; एक मजबूत, हरित हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के निर्माण में मदद करना और ऊर्जा-स्वतंत्र राष्ट्र के सरकार के दृष्टिकोण को प्राप्त करना।

यह साझेदारी ग्रीन हाइड्रोजन संक्रमण में वैश्विक नेतृत्व प्राप्त करने की दिशा में नीतिगत सहायता प्रदान करने पर केंद्रित सरकार के राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को बढ़ावा देने में मदद करेगी।

हरित हाइड्रोजन कार्यक्रम में नवाचार:

IIT बॉम्बे और HSBC के बीच साझेदारी IIT भर के शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों और छात्रों को ऐसी महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों और समाधान विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी जो हरित हाइड्रोजन उत्पादन, भंडारण, परिवहन और उपयोग में प्रमुख चुनौतियों का समाधान करती हैं।

संचालन समिति और प्रस्ताव मूल्यांकन:

इस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, IIT बॉम्बे परियोजना प्रस्तावों को आमंत्रित करेगा, जिसका मूल्यांकन HSBC इंडिया के प्रतिनिधियों, प्रोफेसरों और बहु-विषयक क्षेत्रों के संकाय सदस्यों की एक संचालन समिति द्वारा किया जाएगा।

राष्ट्रीय लक्ष्य और प्रभाव:

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अनुसार, 2030 तक, भारत को प्रति वर्ष कम से कम 5 MMT (मिलियन मीट्रिक टन) की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करने की उम्मीद है।

इससे देश में लगभग 125 गीगावॉट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ेगी और भारत को अपने शुद्ध शून्य दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी।

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के बारे में:

कैबिनेट मंत्री: अश्विनी वैष्णव
राज्य मंत्री: राजीव चन्द्रशेखर

IIT बॉम्बे को ग्रीन एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी रिसर्च हब की स्थापना के लिए पूर्व छात्रों से 18.6 मिलियन अमरीकी डालर का दान प्राप्त हुआ

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) बॉम्बे को ग्रीन एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी रिसर्च हब की स्थापना के लिए एक पूर्व छात्र से 18.6 मिलियन अमरीकी डालर (153 करोड़ से अधिक) का दान मिला है।
यह ऐतिहासिक योगदान वैश्विक जलवायु संकट से निपटने में संस्थान की भूमिका को फिर से परिभाषित करेगा।
यह हब उपनगरीय पवई में IIT बॉम्बे परिसर में एक अत्याधुनिक शैक्षणिक भवन के भीतर स्थित होगा और इसका फोकस गंभीर रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक विस्तारित होगा।

मुख्य विचार:

केंद्रित क्षेत्रों में जलवायु जोखिमों का मूल्यांकन करना और प्रभावी शमन रणनीतियों का विकास करना, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और व्यापक पर्यावरण निगरानी शामिल है।
इसके अतिरिक्त, हब जलवायु समाधानों को आगे बढ़ाने और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा देना चाहता है।
यह बैटरी प्रौद्योगिकी, सौर फोटोवोल्टिक्स, जैव ईंधन, स्वच्छ वायु विज्ञान, बाढ़ पूर्वानुमान और कार्बन कैप्चर सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुसंधान की सुविधा प्रदान करेगा।
इसके अलावा, हब उद्योग-अनुरूप शैक्षिक प्रशिक्षण की पेशकश करेगा और वैश्विक विश्वविद्यालयों और निगमों के साथ रणनीतिक सहयोग विकसित करेगा।

सावर्ट ने 'द एड एस्ट्रा फंड': दुनिया का पहला पूर्णतः स्वचालित निवेश फंड लॉन्च किया

सावर्ट भारत के सबसे बड़े निवेश सलाहकारों में से एक, ने हैदराबाद, तेलंगाना में अपनी पहली और प्रमुख पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवा (PMS) लॉन्च की, जिसे द एड एस्ट्रा फंड-विश्व का पहला पूर्ण स्वचालित निवेश फंड कहा जाता है।
अपने लॉन्च के दिन, द एड एस्ट्रा फंड ने 31 करोड़ रुपये की निवेश प्रतिबद्धताएं हासिल कीं, जो मजबूत प्रारंभिक निवेशक रुचि का संकेत है।
फंड ने वित्तीय वर्ष 2024 (FY24) के अंत तक 350 करोड़ रुपये के एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) तक पहुंचने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।

ऐड एस्ट्रा फंड के बारे में:

एड एस्ट्रा फंड एक दीर्घकालिक निवेश माध्यम है।
सावर्ट लंबी अवधि को न्यूनतम 3 वर्ष और अधिकतम 7-10 वर्ष के रूप में परिभाषित करता है।
एड एस्ट्रा फंड को पोर्टफोलियो मंथन को यथासंभव कम रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
एड एस्ट्रा फंड एक केंद्रित पोर्टफोलियो बनाए रखेगा, मुख्य रूप से स्टॉक।
ऐड एस्ट्रा फंड विभिन्न क्षेत्रों और बाजार पूंजीकरण के प्रति अज्ञेयवादी है, इस प्रकार विभिन्न निवेश अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित करता है।
इस फंड में निवेश के अवसर की खोज से लेकर बाहर निकलने तक एंड-टू-एंड रिसर्च ऑटोमेशन की सुविधा है, यानी संपूर्ण अनुसंधान और निवेश निर्णय लेने की प्रक्रिया उनके AI रिसर्च सिस्टम APART (एडवांस्ड प्रोसेस ऑटोमेशन एंड रिसर्च टेक्नोलॉजी) द्वारा संचालित होती है, जिसमें 3 इंजन शामिल हैं (क्वांट, आइरिस, सिनैप्स)।

क्या चीज़ APART को एक कक्षा से अलग करती है?

लोकप्रिय तकनीकी और गणितीय विश्लेषण-ग्रस्त क्वांट फंडों के विपरीत, APART एक पैमाने और गति पर संपूर्ण मौलिक और गुणात्मक विश्लेषण को भी कवर करता है जो मानव अनुसंधान टीम के व्यावहारिक दायरे से परे है।
APART मौजूदा बाजार स्थितियों और अवसरों के अनुरूप, मानव फंड मैनेजर की तुलना में तेजी से विकसित और अनुकूलित होता है।

सावर्ट के बारे में:

स्थापित: 2017
मुख्यालय: हैदराबाद, तेलंगाना
CEO: संकर्ष चंदा

श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस ने भारत में पर्यावरण अनुकूल किफायती हाउसिंग फाइनेंस को आगे बढ़ाने के लिए IFC के साथ सहयोग किया है

श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (SHFL), एक अग्रणी किफायती आवास वित्त कंपनी, जिसके 65,000 ग्राहकों के साथ भारत में 130 से अधिक शाखाएं हैं और विश्व बैंक के एक सदस्य, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) ने भारत में स्व-निर्मित घरों के लिए एक किफायती हरित आवास ऋण उत्पाद लॉन्च करने के लिए साझेदारी की घोषणा की है।

मुख्य विचार:

यह परियोजना किफायती स्व-निर्माण खंड के ग्राहकों के लिए IFC के उत्कृष्ट डिजाइन फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी (EDGE) प्रमाणन उपकरण और हरित किफायती आवास की रिपोर्टिंग के लिए प्रभाव निगरानी उपकरण (CAFI) को तैनात करेगी। यह EDGE सॉफ्टवेयर, मानकों और प्रमाणन प्रणाली के सिद्धांतों और अनुप्रयोगों पर SHFL टीमों के लिए क्षमता निर्माण का प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा।

EDGE प्रमाणीकरण SHFL को उन घरों की पहचान करने में सहायता करेगा जो ऊर्जा, पानी और सन्निहित ऊर्जा सामग्री में कम से कम 20% बचत के साथ अपने पर्यावरणीय पदचिह्न को कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

इस साझेदारी को यूरोपीय संघ (EU) द्वारा एक्सीलरेटिंग क्लाइमेट-स्मार्ट एंड इनक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर इन साउथ एशिया (ACSIIS) कार्यक्रम के तहत वित्त पोषित किया गया है, जो भारत में जलवायु-स्मार्ट, टिकाऊ बुनियादी ढांचे के निवेश का समर्थन करता है।

प्रबंध निदेशक और CEO, SHFL: रवि सुब्रमण्यम।

नवीनतम समाचार:

अगस्त 2023 में, विश्व बैंक समूह का एक सदस्य अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC), एक प्रमुख आवास वित्त कंपनी आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (IIFL HFL) में $100 मिलियन तक का निवेश करने के लिए तैयार है, जिसका उद्देश्य भारत में महिला उधारकर्ताओं सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) और कम आय वाले समूहों (LIG) के लिए आवास वित्त तक पहुंच बढ़ाना है।

IFC के बारे में:

स्थापना: 20 जुलाई, 1956
मुख्यालय: वाशिंगटन, डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका
प्रबंध निदेशक: मुख्तार डिओप
सदस्यता: 186 देश

IFC एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो कम विकसित देशों में निजी क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए निवेश, सलाहकार और परिसंपत्ति-प्रबंधन सेवाएं प्रदान करता है।

मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड ने मुथूट फिनकॉर्प वन लॉन्च किया

मुथूट पप्पाचन समूह (मुथूट ब्लू) की केरल स्थित प्रमुख इकाई मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड (MFL) ने "मुथूट फिनकॉर्प वन" की शुरुआत की है, जो एक अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो ऋण, निवेश, सुरक्षा और भुगतान सहित वित्तीय समाधानों की एक एकीकृत श्रृंखला प्रदान करता है, जो सभी एक ही ऐप के माध्यम से सुलभ है।

मुथूट फिनकॉर्प वन का लॉन्च मुथूट फिनकॉर्प की भारत भर में विविध वित्तीय आवश्यकताओं को सहज और सुविधाजनक तरीके से पूरा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

मुथूट फिनकॉर्प वन के बारे में:

मुथूट फिनकॉर्प वन एक ऑल-इन-वन डिजिटल वित्तीय प्लेटफ़ॉर्म है जो MSME और गोल्ड लोन प्राप्त करना, डिजिटल गोल्ड और NCD में निवेश करना, भुगतान और प्रेषण करना, बीमा खरीदना और विदेशी मुद्रा का आदान-प्रदान करना सरल और सुविधाजनक बनाता है।
यह वित्तीय सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है।
इसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) ऋण और गोल्ड लोन शामिल हैं, जिनका लाभ घरेलू या मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड की शाखाओं से लिया जा सकता है।
इसके अतिरिक्त, प्लेटफ़ॉर्म डिजिटल गोल्ड और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (NCD) जैसे निवेश विकल्प प्रदान करता है।
MFL के CEO: शाजी वर्गीस

RBI के LRS के तहत जावक प्रेषण Q1 में 50% बढ़कर 9.1 बिलियन डॉलर हो गया

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS) ने उल्लेखनीय वृद्धि प्रदर्शित की है, बाहरी प्रेषण में 50.64% की वृद्धि के साथ, वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में $9.1 बिलियन तक पहुँच गया है।
यह उछाल विभिन्न कारकों से प्रभावित हुआ है, जिसमें कर नियमों में बदलाव और अंतरराष्ट्रीय यात्रा पैटर्न में धीरे-धीरे सामान्य स्थिति में वापसी शामिल है।

मुख्य विचार:

खंड-वार विकास को बढ़ावा:
जावक प्रेषण में उल्लेखनीय वृद्धि का श्रेय कई क्षेत्रों में मजबूत वृद्धि को दिया जा सकता है।
LRS योजना के तहत स्रोत पर कर संग्रह (TCS) की समय-सीमा में बदलाव, अंतरराष्ट्रीय यात्रा के पुनरुत्थान के साथ मिलकर, इस प्रवृत्ति को बढ़ाने में सहायक रहा है।
त्रैमासिक गति:
पिछले वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही की तुलना में बाह्य प्रेषण में 17% की वृद्धि देखी गई, जो प्रेषण गतिविधियों में निरंतर गति का संकेत देता है।
वैश्विक प्रवाह असमानताएँ:
नीदरलैंड और जापान ही ऐसे एकमात्र देश थे जहां आमद में बढ़ोतरी देखी गई।
संभावित रूप से इन देशों और भारत के बीच विशिष्ट आर्थिक गतिशीलता को दर्शाता है।
गंतव्य अंतर्दृष्टि:
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के आंकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र $4.5 बिलियन के इक्विटी प्रवाह के साथ शीर्ष स्थान पर रहा।
जून तिमाही में $5.2 बिलियन के मुकाबले 13.5% की गिरावट दर्ज की गई।
कर्नाटक इस अवधि के दौरान 46% की गिरावट के साथ $1.5 बिलियन से कम रह गया।
गुजरात $3.2 बिलियन से $730 मिलियन तक 77% की गिरावट देखी गई।
1.9% की गिरावट के साथ $1.9 बिलियन होने के बावजूद, दिल्ली FDI इक्विटी प्रवाह के लिए दूसरा सबसे बड़ा गंतव्य बनकर उभरा।
FDI और इक्विटी प्रत्यावर्तन:
RBI के आंकड़ों से पता चला कि वित्तीय वर्ष की शुरुआती तिमाही के दौरान सकल FDI प्रवाह 28% घटकर 17.6 बिलियन डॉलर हो गया।
बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा इक्विटी के प्रत्यावर्तन में वृद्धि, जो पिछले वर्ष के 6.2 बिलियन डॉलर की तुलना में जून तिमाही में 10.4 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई, वैश्विक आर्थिक स्थितियों के जवाब में विकसित हो रही रणनीतियों पर प्रकाश डालती है।
TCS विनियमन और स्थगन:

FY23 के केंद्रीय बजट के दौरान, सरकार ने उदारीकृत विदेशी प्रेषण पर TCS को मौजूदा 5% से बढ़ाकर 20% करने का प्रस्ताव रखा, जो शिक्षा और चिकित्सा उपचार को छोड़कर सभी उद्देश्यों के लिए 7 लाख रुपये से अधिक की राशि पर लागू होता है।
प्रारंभ में इसे 1 जुलाई, 2023 से शुरू करने की योजना थी, वित्त मंत्रालय ने बाद में इसके कार्यान्वयन को 1 अक्टूबर, 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया।

LRS योजना के बारे में:

LRS 2004 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा शुरू की गई एक विदेशी मुद्रा नीति पहल है।
उदारीकृत प्रेषण योजना के तहत, नाबालिगों सहित सभी निवासी व्यक्तियों को किसी भी अनुमेय चालू या पूंजी खाता लेनदेन या दोनों के संयोजन के लिए प्रति वित्तीय वर्ष (अप्रैल - मार्च) 2,50,000 अमेरिकी डॉलर तक स्वतंत्र रूप से भेजने की अनुमति है।
LRS सीमा को प्रचलित वृहत और सूक्ष्म आर्थिक स्थितियों के अनुरूप चरणों में संशोधित किया गया है।
प्रेषक के नाबालिग होने की स्थिति में, LRS घोषणा पत्र पर नाबालिग के प्राकृतिक अभिभावक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जाना चाहिए।
यह योजना कॉरपोरेट्स, साझेदारी फर्मों, HUF (हिंदू अविभाजित परिवार), ट्रस्ट आदि के लिए उपलब्ध नहीं है।

सेबी ने एक्सचेंजों के MD और CEO के लिए साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए

मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने स्टॉक एक्सचेंजों, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन और डिपॉजिटरी सहित मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस (MIIs) के बीच साइबर सुरक्षा और लचीलापन बढ़ाने के उद्देश्य से नए दिशानिर्देशों का एक सेट पेश किया है।
ये दिशानिर्देश, तुरंत प्रभावी, MII के आईटी सिस्टम में कमजोरियों की पहचान और उन्हें बंद करने को सुनिश्चित करने के लिए सख्त साइबर ऑडिट प्रथाओं और व्यापक प्रक्रियाओं को अनिवार्य करते हैं।

दिशानिर्देशों की मुख्य बातें:

साइबर ऑडिट आवृत्ति:
बाजार अवसंरचना संस्थानों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान कम से कम 2 बार व्यापक साइबर ऑडिट करना आवश्यक है।
इस सक्रिय दृष्टिकोण का उद्देश्य संभावित साइबर खतरों का नियमित रूप से आकलन करना और उनका समाधान करना है।
अनुपालन का प्रमाणन:
MII को अपने प्रबंध निदेशक (MD) या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) से अनुपालन की घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।
यह घोषणा संगठन की आईटी प्रणालियों में कमजोरियों की पहचान करने और उन्हें सुधारने के लिए मजबूत प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन को प्रमाणित करती है।
इसमें साइबर सुरक्षा उपायों को चलाने के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन या हतोत्साहन संरचनाओं की स्थापना भी शामिल है।
स्टाफिंग सुरक्षा संचालन केंद्र (SOC):
MII को यह प्रदर्शित करना आवश्यक है कि उन्होंने अपने सुरक्षा संचालन केंद्र (SOC) के कर्मचारियों के लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित किए हैं।
यह केंद्र साइबर सुरक्षा बुनियादी ढांचे का एक महत्वपूर्ण घटक है जो सुरक्षा घटनाओं की निगरानी करता है, उनका पता लगाता है और उन पर प्रतिक्रिया देता है।
सेबी परिपत्र और सलाह अनुपालन:
MII को सेबी द्वारा जारी सभी प्रासंगिक साइबर सुरक्षा परिपत्रों और सलाह का अनुपालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
यह सुनिश्चित करता है कि वे विकसित हो रहे साइबर खतरों और शमन रणनीतियों से अपडेट रहें।
NCIIPC को कमजोरियों की रिपोर्ट करना:

MII जिन्हें नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर (NCIIPC) द्वारा 'महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, उन्हें NCIIPC को अपने "संरक्षित सिस्टम" में पहचानी गई कमजोरियों पर नियमित अपडेट प्रदान करना अनिवार्य है।
यह राष्ट्रीय स्तर पर साइबर जोखिमों के प्रबंधन के लिए एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है।

कार्यान्वयन स्थिति का संचार:

MII को 30 दिनों के भीतर सेबी को इन नए दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में सूचित करना आवश्यक है।
यह रिपोर्टिंग उन्नत साइबर सुरक्षा उपायों को अपनाने में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है।

नवीनतम समाचार:

जुलाई 2023 में, सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों के लिए सख्त समयसीमा के साथ प्रकटीकरण मानदंडों को कड़ा कर दिया और घटनाओं की भौतिकता निर्धारित करने के लिए मानदंड पेश किए।

सेबी के बारे में:

स्थापना: 12 अप्रैल 1988 को एक कार्यकारी निकाय के रूप में और 30 जनवरी 1992 को सेबी अधिनियम, 1992 के माध्यम से वैधानिक शक्तियां दी गईं।
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र
अध्यक्ष: माधबी पुरी बुच (सेबी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला)
सेबी भारत में वित्त मंत्रालय (MoF), भारत सरकार के स्वामित्व के तहत प्रतिभूतियों और कमोडिटी बाजारों के लिए नियामक निकाय है।

सेबी ने वैकल्पिक निवेश नीति सलाहकार समिति के लिए नया पैनल बनाया

पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपनी वैकल्पिक निवेश नीति सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है और इसे वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) क्षेत्र के आगे के विकास को प्रभावित करने वाले कई मुद्दों पर सलाह देता है।

मुख्य विचार:

समिति सदस्यता विस्तार:

सेबी के मुताबिक समिति, शुरुआत में मार्च 2015 में गठित की गई थी, फरवरी 2022 में इसकी संरचना में हालिया बदलाव हुआ।
अब, समिति का विस्तार कर इसमें 25 सदस्यों को शामिल किया गया है, जो पिछली संख्या 20 से अधिक है।

समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य:

समिति की अध्यक्षता इंफोसिस के सह-संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति ने की है, और इसने AIF (वैकल्पिक निवेश कोष) उद्योग पर 3 रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं।
मूर्ति के अलावा, समिति में सेबी, वित्त मंत्रालय, AIF खिलाड़ियों और उद्योग संघों के सदस्य शामिल हैं।
विशेष रूप से, इंडियन प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल एसोसिएशन (IVCA) की पूर्व अध्यक्ष रेणुका रामनाथ को समिति में IVCA के नए अध्यक्ष कार्तिक रेड्डी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।
समिति के पैनल को सेबी को किसी भी बाधा पर सलाह देने के लिए अनिवार्य किया गया है जो वैकल्पिक निवेश उद्योग के विकास और इस खंड के साथ-साथ भारत में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में बाधा डाल सकता है।

सेबी के बारे में:

स्थापना: 12 अप्रैल 1988 एक कार्यकारी निकाय के रूप में और सेबी अधिनियम, 1992 के माध्यम से 30 जनवरी 1992 को वैधानिक शक्तियां दी गईं
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र
अध्यक्ष: माधबी पुरी बुच (सेबी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला)

SEBI भारत में प्रतिभूति और कमोडिटी बाजारों के लिए नियामक निकाय है जो वित्त मंत्रालय (MoF), भारत सरकार के स्वामित्व के तहत है।

फिच ने SBI और 5 अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए स्थिर आउटलुक के साथ BBB- रेटिंग बरकरार रखी है

फिच रेटिंग्स ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI), बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB), पंजाब नेशनल बैंक (PNB), केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया (BOI), और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (UBI) सहित भारत के 6 प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की क्रेडिट रेटिंग की पुष्टि की है, सभी को स्थिर दृष्टिकोण के साथ BBB-रेटिंग मिली है।
स्थिर दृष्टिकोण के साथ BBB- रेटिंग के अलावा, फिच रेटिंग्स ने इन बैंकों के लिए निम्नलिखित रेटिंग की भी पुष्टि की है:
बीबी पर व्यवहार्यता रेटिंग
बीबीबी पर सरकारी समर्थन रेटिंग-
इन बैंकों में, SBI को असाधारण राज्य समर्थन प्राप्त करने की सबसे अधिक संभावना वाले बैंकों के रूप में पहचाना गया है। स्थिर दृष्टिकोण देश की संप्रभु रेटिंग के अनुरूप है।
इस बीच, रेटिंग एजेंसी ने स्थिर दृष्टिकोण के साथ दूसरे सबसे बड़े राज्य के स्वामित्व वाले ऋणदाता बैंक ऑफ बड़ौदा और इसकी न्यूजीलैंड की सहायक कंपनी BBB- की दीर्घकालिक रेटिंग की भी पुष्टि की।

PhonePe ने Share.Market ऐप के लॉन्च के साथ स्टॉक ब्रोकिंग व्यवसाय में प्रवेश किया

वॉलमार्ट समर्थित भुगतान दिग्गज फोनपे ने अपनी वित्तीय सेवाओं में विविधता लाने के प्रयासों के तहत शेयर (डॉट) मार्केट नाम से अपना स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म पेश किया है।
नया मोबाइल ऐप उपयोगकर्ताओं को स्टॉक, म्यूचुअल फंड और ETF (एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड) में व्यापार और निवेश करने की अनुमति देगा।

मुख्य विचार:

शेयर (डॉट) मार्केट ऐप मार्केट इंटेलिजेंस और मात्रात्मक अनुसंधान-आधारित वेल्थबास्केट्स, एक स्केलेबल प्रौद्योगिकी मंच प्रदान करके डिस्काउंट ब्रोकिंग को बढ़ाता है।
यह एक मोबाइल ऐप और एक समर्पित वेब प्लेटफॉर्म के रूप में उपलब्ध होगा, जो खुदरा निवेशकों को स्टॉक खरीदने, इंट्रा डे ट्रेडों में संलग्न होने, क्यूरेटेड वेल्थबास्केट्स और म्यूचुअल फंड खरीदने में सक्षम करेगा।
वेल्थबास्केट सेबी-पंजीकृत मध्यस्थों द्वारा स्टॉक/निवेश उत्पादों का क्यूरेटेड संग्रह है जो सक्रिय इक्विटी पोर्टफोलियो निर्माण को सक्षम करने वाले विशिष्ट विषयों, क्षेत्रों या बाजार के रुझानों के साथ संरेखित होता है।
फिनटेक दिग्गज का लक्ष्य इस नए लॉन्च के साथ अपने उपयोगकर्ता आधार के बीच स्टॉक ट्रेडिंग और निवेश में बढ़ती रुचि का लाभ उठाना है।
शेयर (डॉट) मार्केट 199 रुपये का एकमुश्त ऑनबोर्डिंग मूल्य लेता है जिसमें 31 मार्च, 2024 तक ट्रेडों पर 400 रुपये तक शून्य ब्रोकरेज जैसे लाभ शामिल हैं।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO), शेयर (डॉट) मार्केट: उज्ज्वल जैन

नवीनतम समाचार:

जुलाई, 2023 में PhonePe, एक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म, ने PayMate, एक अग्रणी डिजिटल बिजनेस-टू-बिजनेस (B2B) भुगतान और सेवा प्रदाता के साथ साझेदारी की, ताकि उपयोगकर्ताओं को "आयकर भुगतान" नामक PhonePe ऐप पर अपने आयकर का भुगतान करने की अनुमति मिल सके।

फ़ोनपे के बारे में:

स्थापना: 2015
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र
संस्थापक और CEO: समीर निगम

सेबी ने मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस (MII) को एक एकीकृत ऑनलाइन विवाद समाधान पोर्टल बनाने का निर्देश दिया

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस (MII) को एक एकीकृत ऑनलाइन विवाद समाधान पोर्टल (ODR पोर्टल) स्थापित करने और संचालित करने का निर्देश दिया है।
यह पोर्टल भारतीय प्रतिभूति बाजारों में उत्पन्न होने वाले विवादों को सुलझाने के लिए ऑनलाइन सुलह और ऑनलाइन मध्यस्थता का लाभ उठाएगा।
स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी और क्लियरिंग कॉरपोरेशन सहित MII को ODR प्लेटफॉर्म को विकसित करने और संचालित करने के लिए सहयोग करने का काम सौंपा गया है।

बाज़ार सहभागियों की भागीदारी:

प्रतिभूति बाजार के भीतर सभी संस्थाएं, जैसे सूचीबद्ध कंपनियां, निर्दिष्ट मध्यस्थ, और विनियमित संस्थाएं जिन्हें सामूहिक रूप से "बाजार सहभागियों" के रूप में जाना जाता है, को ओडीआर पोर्टल पर नामांकन करना आवश्यक है।

विवाद समाधान प्रक्रिया:

विवाद समाधान प्रक्रिया की शुरुआत के संबंध में, सेबी ने निम्नलिखित चरणों की रूपरेखा तैयार की है:
निवेशकों को शुरू में सीधे शिकायत दर्ज करके संबंधित बाजार भागीदार के साथ अपनी शिकायतों का समाधान करना होगा।
यदि शिकायत का संतोषजनक समाधान नहीं होता है, तो निवेशक स्कोर्स (सेबी शिकायत निवारण प्रणाली) पोर्टल के माध्यम से इसे बढ़ा सकते हैं।
यदि उपलब्ध विकल्पों के समाप्त होने के बाद भी शिकायत अनसुलझी रहती है, तो निवेशक ओडीआर पोर्टल के माध्यम से विवाद समाधान शुरू कर सकते हैं।
वैकल्पिक रूप से, निवेशक ओडीआर पोर्टल के माध्यम से विवाद समाधान शुरू कर सकते हैं यदि बाजार सहभागियों के साथ शुरू में दर्ज की गई शिकायत संतोषजनक ढंग से हल नहीं हुई थी, या किसी भी बाद के चरण में वृद्धि हुई थी।
इसके अतिरिक्त, बाजार सहभागी उस विवाद को सुलझाने के लिए निवेशक को कम से कम 15 कैलेंडर दिनों का नोटिस देने के बाद ओडीआर पोर्टल के माध्यम से विवाद समाधान शुरू कर सकते हैं, जिसे उनके बीच संतोषजनक ढंग से संबोधित नहीं किया गया है।

कार्यान्वयन चरण:

नया ढांचा दो चरणों में लागू किया जाएगा:
चरण 1: ODR पोर्टल का विकास, MII द्वारा ODR संस्थानों को सूचीबद्ध करना, 1 अगस्त, 2023 तक इन ODR संस्थानों द्वारा समाधानकर्ताओं और मध्यस्थों को पैनल में शामिल करना शामिल है।
ODR पोर्टल पर ट्रेडिंग सदस्यों और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों का पंजीकरण 15 अगस्त, 2023 तक होगा, दलालों और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के खिलाफ शिकायतें दर्ज करना और उनका समाधान 16 अगस्त, 2023 से शुरू होगा।
फेस II:15 सितंबर, 2023 तक ओडीआर पोर्टल पर अन्य सभी बाजार सहभागियों का पंजीकरण शामिल है।
अन्य सभी बाजार सहभागियों के खिलाफ शिकायतें दर्ज करने और उनके समाधान की शुरुआत 16 सितंबर, 2023 से शुरू होगी।

NPCI ने 'फाल्कन' पेश किया: भारत की अपनी ब्लॉकचेन-समर्थित ओपन-सोर्स पहल

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने 'फाल्कन' पेश किया है, जो एक ओपन-सोर्स प्रोजेक्ट है, जिसे 'हाइपरलेजर फैब्रिक' पर आधारित और कुबेरनेट्स क्लस्टर पर समर्थित ब्लॉकचेन के प्रबंधन और उपयोग को सरल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

उद्देश्य:

नेटवर्क और वेब3 समाधानों की कुशल, विश्वसनीय और स्वचालित तैनाती के लिए वितरित खाता प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने में ब्लॉकचेन डेवलपर्स की सहायता करना।
यह विशेष रूप से ब्लॉकचेन-आधारित भुगतान समाधानों में नवाचार को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

NPCI की इस पेशकश से ब्लॉकचेन डेवलपर्स को नेटवर्क के साथ-साथ वेब3 समाधानों की कुशल, विश्वसनीय और स्वचालित तैनाती की सुविधा के लिए वितरित लेजर तकनीक का उपयोग करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

हाइपरलेजर क्या है?

इन्वेस्टोपेडिया के अनुसार, हाइपरलेजर फैब्रिक की शुरुआत डिजिटल एसेट और IBM द्वारा की गई थी।
हाइपरलेजर फैब्रिक एक एंटरप्राइज़-स्तरीय अनुमति ब्लॉकचेन नेटवर्क है।
यह ढांचा ब्लॉकचेन-आधारित उत्पादों और समाधानों को बनाने के लिए एक आधार के रूप में कार्य करता है।

कुबेरनेट्स क्लस्टर क्या हैं?

2014 में Google इंजीनियरों जो बेडा, ब्रेंडन बर्न्स और क्रेग मैकलुकी द्वारा विकसित, कुबेरनेट्स एक ओपन-सोर्स प्लेटफ़ॉर्म है जो पैकेज्ड सॉफ़्टवेयर कोड के प्रबंधन में सहायता करता है, जिसे कंटेनरीकृत एप्लिकेशन भी कहा जाता है।
कुबेरनेट्स क्लस्टर नोड्स का एक सेट है जो कंटेनरीकृत एप्लिकेशन चलाता है।
कुबेरनेट्स कंटेनर प्रबंधन से संबंधित विभिन्न परिचालन कार्यों को स्वचालित करता है, जिसमें तैनाती, स्केलिंग, निगरानी और बहुत कुछ शामिल है।
2020 में, NPCI ने 'वज्र' पेश किया, जो एक ब्लॉकचेन-संचालित प्रणाली है जो NPCI उत्पादों के लिए भुगतान समाशोधन और निपटान प्रक्रियाओं को स्वचालित करती है।
ये तकनीकी प्रगति वित्तीय क्षेत्र में नवाचार के प्रति NPCI के समर्पण को दर्शाती है।

NPCI के बारे में:

स्थापित: 2008
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र, भारत
MD और CEO: दिलीप अस्बे
NPCI भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणालियों के संचालन के लिए एक छाता संगठन है, जो भारत में एक मजबूत भुगतान और निपटान बुनियादी ढांचा बनाने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारतीय बैंक संघ (IBA) की एक पहल है।

मास्टरकार्ड ने ऑनलाइन भुगतान सुरक्षा बढ़ाने के लिए ALT ID समाधान पेश किया

मास्टर कार्ड भुगतान उद्योग की एक वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी ने अतिथि चेकआउट लेनदेन के लिए एक ALT ID (वैकल्पिक पहचानकर्ता) समाधान पेश किया है।

ALT ID के बारे में:

ALT ID ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अतिथि चेकआउट लेनदेन के दौरान कार्डधारकों द्वारा प्रदान किए गए वास्तविक कार्ड नंबरों के लिए एक वैकल्पिक पहचानकर्ता बनाने के लिए मास्टरकार्ड द्वारा विकसित एक कस्टम-निर्मित क्षमता है।
इस समाधान का प्राथमिक उद्देश्य व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए ऑनलाइन भुगतान सुरक्षा को बढ़ाना है।
मास्टरकार्ड का ALT ID समाधान उन कार्डधारकों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो अपने कार्ड की जानकारी सहेजे बिना लेनदेन करना पसंद करते हैं, जिसे आमतौर पर अतिथि चेकआउट कहा जाता है।
यह इस पद्धति के माध्यम से किए गए ऑनलाइन भुगतान की सुरक्षा को मजबूत करते हुए, प्रत्येक कार्ड के लिए एक वैकल्पिक पहचानकर्ता स्थापित और सुरक्षित रूप से संग्रहीत करता है।
इससे पहले, मास्टरकार्ड ने कार्डधारकों के लिए संवेदनशील कार्ड विवरण प्रकट किए बिना लेनदेन को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए कार्ड-ऑन-फ़ाइल टोकननाइजेशन समाधान पेश किया था।

मास्टरकार्ड के बारे में:

स्थापित: 1966
मुख्यालय: न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका
CEO: माइकल माइबैक

जून 2023 में बैंक क्रेडिट में सालाना 16.3% की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के ऋण के क्षेत्रीय परिनियोजन के आंकड़ों के अनुसार, सेवाओं, खुदरा और कृषि और संबद्ध गतिविधियों जैसे क्षेत्रों से ऋण की मजबूत मांग के कारण जून 2023 में बैंक ऋण में साल-दर-साल 16.3% की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई, जबकि 2022 में यह 15% थी।

मुख्य विचार:

सेक्टर के अनुसार ऋण वृद्धि की मुख्य बातें:

सेवा क्षेत्र: जून 2023 में ऋण वृद्धि 2022 में 12.8% से बढ़कर 26.7% (वर्ष-दर-वर्ष) हो गई।
यह वृद्धि मुख्य रूप से 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC)' और 'व्यापार' द्वारा ऋण उठाव में सुधार के कारण थी।
व्यक्तिगत ऋण: जून 2023 में 20.9% (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि दर दर्ज की गई, जबकि जून 2022 में यह 18.1% थी।
इस वृद्धि को मुख्य रूप से 'आवास' और 'वाहन' से संबंधित ऋणों द्वारा समर्थन मिला।
कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ: जून 2023 में ऋण वृद्धि बढ़कर 19.7% (वर्ष-दर-वर्ष) हो गई, जो 2022 में 12.9% थी।
उद्योग क्षेत्र: जून 2023 में इस क्षेत्र में ऋण वृद्धि घटकर 8.1% (वर्ष-दर-वर्ष) हो गई, जो जून 2022 में 9.5% थी।
उद्योग के आकार के अनुसार ऋण वृद्धि: आकार के लिहाज से, बड़े उद्योगों को ऋण 6.4% (2022 में 3.2%) बढ़ा।
मध्यम उद्योगों के साथ-साथ सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए ऋण की वृद्धि घटकर क्रमशः 13.2% (47.8%) और 13% (29.2%) रह गई।
जून 2023 के लिए बैंक ऋण की क्षेत्रीय तैनाती पर डेटा 40 चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCB) से एकत्र किया गया था, जो सभी एससीबी द्वारा तैनात कुल गैर-खाद्य ऋण का लगभग 93% प्रतिनिधित्व करता है।

RBI के बारे में:

स्थापना: 1 अप्रैल 1935
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र, भारत
गवर्नर: शक्तिकांत दास
उप गवर्नर: महेश कुमार जैन, एम. राजेश्वर राव, माइकल पात्रा और टी. रबी शंकर

RBI ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को UPI के माध्यम से क्रेडिट लाइन की पेशकश करने की अनुमति दी

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCB) (भुगतान बैंकों, लघु वित्त बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को अब व्यक्तियों के लिए उनकी पूर्व सहमति से पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइनों का उपयोग करके भुगतान की सुविधा प्रदान करने की अनुमति दी है। एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI) प्रणाली।
UPI वर्तमान में बचत खातों, ओवरड्राफ्ट खातों, प्रीपेड वॉलेट और क्रेडिट कार्ड के साथ लिंकेज का समर्थन करता है।
क्रेडिट लाइनें अब UPI प्रणाली के भीतर एक फंडिंग खाता विकल्प के रूप में शामिल हैं।

मुख्य विचार:

इस सुविधा के तहत, व्यक्तिगत ग्राहक की पूर्व सहमति से, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा व्यक्तियों को जारी पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइन के माध्यम से भुगतान, UPI सिस्टम का उपयोग करके लेनदेन के लिए सक्षम किया जाता है।
बैंक इन क्रेडिट लाइनों के उपयोग के लिए नियम और शर्तें स्थापित कर सकते हैं, जिनमें क्रेडिट सीमा, क्रेडिट अवधि, ब्याज दरें और बहुत कुछ जैसे पहलू शामिल हैं।
वर्तमान में, UPI भारत में खुदरा डिजिटल भुगतान का 75% हिस्सा संभालता है।
वर्तमान में, UPI लेनदेन बैंकों में जमा खातों के बीच सक्षम होते हैं, कभी-कभी वॉलेट सहित प्री-पेड उपकरणों द्वारा मध्यवर्ती होते हैं।
अब जमा खातों के अलावा, बैंकों में पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइनों से स्थानांतरण को सक्षम करके UPI के दायरे का विस्तार करने का प्रस्ताव है।
UPI ने अगस्त, 2023 के महीने में 10 बिलियन लेनदेन को पार करके एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया।
जुलाई में UPI लेनदेन की संख्या 9.96 बिलियन (996.4 करोड़) और जून, 2023 में 9.33 बिलियन थी।

RBI के बारे में:
स्थापना: 1 अप्रैल 1935
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र, भारत
राज्यपाल: शक्तिकांत दास
उप राज्यपाल: स्वामीनाथन जानकीरमन, माइकल पात्रा,एम. राजेश्वर राव, टी रबी शंकर

SBI ने सुचारू लेनदेन के लिए eRupee सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) के साथ UPI इंटरऑपरेबिलिटी को सक्षम किया है

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने ग्राहक सुविधा बढ़ाने के लिए अपने डिजिटल रुपया (eRupee) के साथ UPI इंटरऑपरेबिलिटी की शुरुआत की है, जिसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) के रूप में भी जाना जाता है।
यह सुविधा SBI को सक्षम करते हुए 'ईरुपी बाय SBI' एप्लिकेशन के माध्यम से उपलब्ध है
CBDC उपयोगकर्ता तेज और सुरक्षित लेनदेन के लिए व्यापारी UPI QR कोड को स्कैन करें।

मुख्य विचार:
दिसंबर 2022 में RBI की खुदरा डिजिटल ई-रुपी परियोजना में SBI की भागीदारी ने इस एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे रोजमर्रा के लेनदेन में डिजिटल मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा मिला।
SBI का अनुमान है कि इस एकीकरण का डिजिटल मुद्रा पारिस्थितिकी तंत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, जो सुरक्षित और कुशल लेनदेन समाधान प्रदान करेगा।
व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले UPI प्लेटफॉर्म के साथ CBDC के लिंकेज में भारत में भुगतान परिदृश्य को नया आकार देने की क्षमता है, जिसमें CBDC रोजमर्रा के वित्तीय लेनदेन में अधिक केंद्रीय भूमिका निभा रहा है।

CBDC क्या है?
CBDC किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा जारी संप्रभु मुद्रा के इलेक्ट्रॉनिक रूप हैं।
वे भौतिक नकदी के समान, डिजिटल रूप में आधिकारिक मुद्रा का प्रतिनिधित्व करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, और सरकार द्वारा समर्थित हैं।
CBDC ब्याज नहीं कमाते हैं, लेकिन उन्हें बैंक जमा जैसे अन्य प्रकार के धन में परिवर्तित किया जा सकता है।
भारत का डिजिटल रुपया, एक CBDC, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा 1 दिसंबर, 2022 को पायलट आधार पर लॉन्च किया गया था।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2022-23 में CBDC को लागू करने की घोषणा की, जो डिजिटल अर्थव्यवस्था के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का संकेत है।
CBDC मुद्रा को डिजिटल बनाने की वैश्विक प्रवृत्ति का हिस्सा हैं और डिजिटल लेनदेन करने का एक सुरक्षित और कुशल साधन प्रदान करते हैं।

SBI के बारे में:
स्थापना: 1806
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र
अध्यक्ष: दिनेश खारा

मध्यस्थ दावा सत्यापन के लिए एक प्रदर्शन सत्यापन एजेंसी स्थापित करने का सेबी का प्रस्ताव

पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) निवेश सलाहकारों, अनुसंधान विश्लेषकों और पोर्टफोलियो प्रबंधकों सहित पंजीकृत मध्यस्थों द्वारा प्रदर्शन के किसी भी दावे को मान्य करने के लिए एक प्रदर्शन सत्यापन एजेंसी (PVA) स्थापित करने का प्रस्ताव लेकर आया है।
PVA का प्राथमिक उद्देश्य मान्य प्रदर्शन डेटा के आधार पर बिचौलियों को उनके उत्पादों के विपणन में सुविधा प्रदान करना होगा।

प्रस्तावित PVA निवेश सलाहकारों, अनुसंधान विश्लेषकों और पोर्टफोलियो प्रबंधकों जैसे मध्यस्थों को निवेशकों को मान्य प्रदर्शन डेटा प्रदर्शित करने में सक्षम करेगा।
इस सत्यापन का उद्देश्य मध्यस्थों की विश्वसनीयता बढ़ाना और उनकी सेवाओं की पहुंच का विस्तार करना है।

मुख्य विचार:

वर्तमान में, परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों (AMC) और पोर्टफोलियो प्रबंधकों सहित मध्यस्थ, बड़े पैमाने पर अपने प्रदर्शन दावों को स्वयं सत्यापित करते हैं।
इन मध्यस्थों द्वारा किए गए दावे अधिकतर स्व-सत्यापित होते हैं और वर्तमान में ऐसे दावों को मान्य करने के लिए कोई समर्पित एजेंसी नहीं है।
तदनुसार, नियामक ने निवेश सलाहकारों (IA), अनुसंधान विश्लेषकों (RA), पोर्टफोलियो प्रबंधकों AMC और स्टॉक ब्रोकरों जैसे पंजीकृत मध्यस्थों द्वारा निवेश सलाह, 'खरीद, बिक्री, होल्ड' सिफारिश, म्यूचुअल फंड योजना, पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवा, एल्गोरिदम से संबंधित दावों को सत्यापित करने के लिए पीवीए नामक एक स्वतंत्र निकाय बनाने का प्रस्ताव दिया है।
यह सुझाव दिया गया है कि पीवीए बाजार अवसंरचना संस्थानों (MII) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी या कई MII द्वारा संयुक्त रूप से समर्थित इकाई होनी चाहिए, जिसका उद्देश्य मध्यस्थों को PVA द्वारा किए गए सत्यापन के आधार पर अपने उत्पादों का विपणन करने में सक्षम बनाना होगा।
प्रस्ताव के तहत, एजेंसी को रणनीतियों पर ग्राहक डेटा की गोपनीयता सहित बिचौलियों के डेटा और दावों या प्रदर्शन को संसाधित करने की आवश्यकता होगी।

नवीनतम समाचार:

जुलाई, 2023 में पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचीबद्ध कंपनियों के लिए सख्त समयसीमा के साथ प्रकटीकरण मानदंडों को कड़ा कर दिया और घटनाओं की भौतिकता निर्धारित करने के लिए मानदंड पेश किए।

सेबी के बारे में:

स्थापना: 12 अप्रैल 1988 एक कार्यकारी निकाय के रूप में और सेबी अधिनियम, 1992 के माध्यम से 30 जनवरी 1992 को वैधानिक शक्तियां दी गईं
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र
अध्यक्ष: माधबी पुरी बुच (सेबी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला)
SEBI भारत में प्रतिभूति और कमोडिटी बाजारों के लिए नियामक निकाय है जो वित्त मंत्रालय (MoF), भारत सरकार के स्वामित्व के तहत है।

RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023 में 'ए+' रेटिंग प्राप्त हुई

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2023 में 'A+' रेटिंग से सम्मानित किया गया है।
ग्लोबल फाइनेंस के अनुसार, दास को दुनिया भर के 3 केंद्रीय बैंक गवर्नरों की सूची में शीर्ष स्थान पर रखा गया है।
रिपोर्ट में A+ श्रेणी में 2 अन्य केंद्रीय बैंक गवर्नर भी शामिल हैं: स्विट्जरलैंड के थॉमस जे. जॉर्डन और वियतनाम के गुयेन थी होंग।

सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड के बारे में:

सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड ग्लोबल फाइनेंस द्वारा एक वार्षिक प्रकाशन है,और यह 1994 से केंद्रीय बैंक गवर्नरों के प्रदर्शन का आकलन और ग्रेडिंग कर रहा है।
रिपोर्ट 101 महत्वपूर्ण देशों और क्षेत्रों में केंद्रीय बैंक गवर्नरों के प्रदर्शन का आकलन और ग्रेडिंग करती है, जिसमें यूरोपीय संघ, पूर्वी कैरेबियन सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन स्टेट्स जैसी संस्थाएं शामिल हैं।
ग्रेड सूची के साथ पूर्ण सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 अक्टूबर, 2023 में जारी होने वाला है।

रेटिंग मानदंड:

रिपोर्ट में ग्रेड 'ए' से 'एफ' तक के पैमाने पर आधारित हैं और मुद्रास्फीति नियंत्रण, आर्थिक विकास लक्ष्यों, मुद्रा स्थिरता और ब्याज दर प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करते हैं।
'ए' ग्रेड उत्कृष्ट प्रदर्शन को दर्शाता है, जबकि 'एफ' पूर्ण विफलता को दर्शाता है।

सेंट्रल बैंक के गवर्नर 'ए' ग्रेड अर्जित करते हैं:

ब्राजील के रॉबर्टो कैंपोस नेटो, इज़राइल के अमीर यारोन, मॉरीशस के हरवेश कुमार सीगोलम और न्यूजीलैंड के एड्रियन ऑर, कोलंबिया के लियोनार्डो विलार, डोमिनिकन गणराज्य के हेक्टर वाल्डेज़ अल्बिजु, आइसलैंड के असगीर जोंसन और इंडोनेशिया के पेरी वारजियो।

नवीनतम समाचार:

जून 2023 में, RBI के प्रमुख शक्तिकांत दास को लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा 2023 के लिए 'गवर्नर ऑफ द ईयर' की उपाधि से सम्मानित किया गया था।

बजाज ऑटो कंज्यूमर फाइनेंस को गैर-बैंकिंग वित्तीय गतिविधियां शुरू करने के लिए RBI प्रमाणपत्र मिला

बजाज ऑटो कंज्यूमर फाइनेंस लिमिटेड (BACFL), बजाज ऑटो की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को जमा न लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) के रूप में संचालन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है।
सार्वजनिक जमा स्वीकार किए बिना गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के व्यवसाय को शुरू करने/चलाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत RBI से प्रमाणन पंजीकरण 31 अगस्त 2023 को जारी किया गया था।

पृष्ठभूमि:

2021 में, बजाज ऑटो ने 100% कैप्टिव वित्त सहायक कंपनी 'बजाज ऑटो कंज्यूमर फाइनेंस' की स्थापना की घोषणा की।
जुलाई 2023 में, BACFL ने गैर-बजाज ऑटो ब्रांडों से दोपहिया खरीद को शामिल करने के लिए अपनी वित्तपोषण सेवाओं का विस्तार करने के लिए NBFC लाइसेंस के लिए RBI को आवेदन किया।

बजाज ऑटो कंज्यूमर फाइनेंस के बारे में:

स्थापित: 2021
मुख्यालय: मुंबई, महरा
CEO: राकेश मक्कड़
बजाज ऑटोकंज्यूमर फाइनेंस बजाज समूह की दूसरी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है।
समूह में बजाज फाइनेंस और बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी हैं, जो दोनों वित्तीय सेवा कंपनी बजाज फिनसर्व की सहायक कंपनियां हैं।

पंजाब नेशनल बैंक ने MSME के लिए GST चालान के आधार पर तत्काल ऋण के लिए PNB GST सहाय ऐप पेश किया

राज्य के स्वामित्व वाले पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने PNB GST सहाय ऐप लॉन्च किया है, जो माल और सेवा कर (GST) सहाय योजना पर आधारित एक मोबाइल एप्लिकेशन है, जो एक एंड-टू-एंड डिजिटल उत्पाद है जिसके तहत GST चालान का उपयोग करके ऋण दिया जा सकता है।
इस एकीकरण के साथ, PNB ऋण प्रक्रिया में GST चालान को एकीकृत करके सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को निर्बाध ऋण प्रवाह सक्षम करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है।
यह पहल भारत में MSME क्षेत्र और डिजिटल क्रेडिट पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को आगे बढ़ाने की बैंक की रणनीति के अनुरूप भी है।

PNB GST सहाय ऐप के लाभ:

PNB GST सहाय ऐप पूरी ऋण प्रक्रिया को डिजिटल बनाता है और उधारकर्ताओं के लिए किसी भी मैन्युअल हस्तक्षेप को खत्म करने में मदद करता है और प्रक्रिया को अधिक लागत प्रभावी, तेज और सुचारू बनाता है।

यह ऐप ऋण राशि को सीधे बैंक में रखे गए उधारकर्ता के चालू खाते में जमा कर देगा।
यह आवेदक/उधारकर्ता और बैंक के बीच की खाई को पाटेगा।

ऋण उपलब्धता और सीमा:

ऐप के माध्यम से, PNB के साथ सक्रिय खाता रखने वाले सभी GST-पंजीकृत MSME 10,000 रुपये से 2 लाख रुपये प्रति चालान तक के ऋण के लिए बैंक की GST सहाय सेवा तक पहुंच सकेंगे, जो प्रति उधारकर्ता 10 लाख रुपये की सीमा के अधीन है।
यह समाधान उधारकर्ताओं को पूर्व भुगतान के विकल्प के साथ एक बार परेशानी मुक्त पुनर्भुगतान प्रक्रिया की भी अनुमति देगा।

नवीनतम समाचार:

ऐप के माध्यम से, PNB के साथ सक्रिय खाता रखने वाले सभी GST-पंजीकृत MSME प्रति चालान 10,000 रुपये से 2 लाख रुपये तक के ऋण के लिए बैंक की GST सहाय सेवा का उपयोग करने में सक्षम होंगे, जो प्रति उधारकर्ता 10 लाख रुपये की सीमा के अधीन है।
यह समाधान उधारकर्ताओं को पूर्व भुगतान के विकल्प के साथ एक बार की परेशानी मुक्त पुनर्भुगतान प्रक्रिया की अनुमति देगा।

PNB के बारे में:

स्थापना: 19 मई 1894
मुख्यालय: द्वारका, दिल्ली, भारत
MD एवं CEO: अतुल कुमार गोयल
टैगलाइन: यू कैन बैंक अपॉन

भारत और सिंगापुर ने ट्रेड ट्रस्ट प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहला लाइव पेपरलेस लेनदेन सफलतापूर्वक आयोजित किया

भारत और सिंगापुर ने ट्रेड ट्रस्ट प्लेटफॉर्म का उपयोग करके पहले लाइव पेपरलेस लेनदेन का संचालन किया, जो भारत और सिंगापुर के बीच डिजिटल कनेक्शन में एक मील का पत्थर साबित हुआ।
यह लेन-देन भारत-सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज़ बैठक और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के बाद हुआ

मुख्य विचार:

2022 में, एक संयुक्त भारत-सिंगापुर मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें भारत-सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन (ISMR) के उद्घाटन सत्र के परिणामों के बारे में जानकारी दी।
यह ISMR की पहली बैठक थी, जो आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के बीच एक नया मंत्रिस्तरीय मंच है।
ISMR मौजूदा सहयोग को गहरा करने और नए और उभरते क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभप्रद सहयोग के अवसरों की पहचान करने का प्रयास करता है।

नवीनतम समाचार:

फरवरी 2023 में, भारत और सिंगापुर ने दोनों देशों के बीच निर्बाध सीमा पार लेनदेन के लिए अपने संबंधित ऑनलाइन भुगतान सिस्टम भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) और सिंगापुर के PayNow को जोड़ा।

सिंगापुर के बारे में:

प्रधान मंत्री: ली सीन लूंग
राजधानी: सिंगापुर
मुद्रा: सिंगापुर डॉलर

CCI ने गन जंपिंग के लिए NTPC पर ₹40 लाख का जुर्माना लगाया

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने गन जंपिंग के अपराध में NTPC लिमिटेड पर 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

गन जंपिंग तब होती है जब संयोजन में शामिल पार्टियां लेनदेन को पूरा करने से पहले सीसीआई को सूचित करने में विफल रहती हैं।
यह जुर्माना इसलिए लगाया गया क्योंकि NTPC ने CCI को पूर्व सूचना के बिना रत्नागिरी गैस एंड पावर में 35.47% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया था।

मुख्य विचार:

CCI ने NTPC को लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने के लिए 60 दिन की अवधि दी है।
CCI ने निर्धारित किया है कि NTPC प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 43ए के तहत जुर्माने के लिए उत्तरदायी है।
गन जंपिंग में, संयोजन के पक्ष CCI को किसी संयोजन राष्ट्र के समापन से पहले सूचित करने में विफल रहते हैं या 210-दिवसीय स्टैंडस्टिल दायित्व का उल्लंघन करते हैं।
गन जंपिंग में CCI को भेजे गए नोटिस पर भी झूठी घोषणा की जाती है।

CCI के बारे में:

स्थापना: 14 अक्टूबर 2003
मुख्यालय: नई दिल्ली
अध्यक्ष: रवनीत कौर
CCI भारत में मुख्य राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नियामक है।
यह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है।
CCI विभिन्न प्रतिस्पर्धा-विरोधी मामलों की जांच कर रही है, जिनमें प्रौद्योगिकी कंपनियों से संबंधित मामले भी शामिल हैं।

NTPC लिमिटेड के बारे में:

स्थापना: 7 नवंबर 1975
मुख्यालय: नई दिल्ली, दिल्ली, भारत
अध्यक्ष और MD: गुरदीप सिंह
NTPC लिमिटेड, जिसे पहले नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता था, बिजली मंत्रालय और भारत सरकार के स्वामित्व में एक भारतीय केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जो बिजली उत्पादन और अन्य गतिविधियों में लगा हुआ है।

RBI ने राजधानी को-ऑप अर्बन बैंक के साथ नवनिर्माण सहकारी शहरी बैंक के समामेलन को मंजूरी दे दी

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नवनिर्माण सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना के साथ राजधानी सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना के समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है।
इस योजना को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44ए की उप-धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंजूरी दी गई है।

SBI ने ग्राहक सेवा बिंदुओं के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए आधार-आधारित नामांकन की शुरुआत की

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने एक नई सुविधा शुरू की है जो ग्राहकों को अपना आधार कार्ड प्रदान करके सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नामांकन करने की अनुमति देती है।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अध्यक्ष दिनेश खारा ने नई सुविधा का अनावरण किया जो बैंक के ग्राहक सेवा बिंदुओं (CSP) पर उपलब्ध होगी, जिसका उद्देश्य विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नामांकन की प्रक्रिया को सरल बनाना है।
ग्राहक अब अपने आधार का उपयोग करके प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), और अटल पेंशन योजना (APY) जैसी महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में आसानी से नामांकन कर सकते हैं।
ग्राहक करेंगेउन्हें ग्राहक सेवा केंद्र (CSP) पर अपनी पासबुक ले जाने की आवश्यकता नहीं है।

पेटीएम ने संपर्क रहित UPI और क्रेडिट/डेबिट कार्ड भुगतान के लिए कार्ड साउंडबॉक्स डिवाइस पेश किया

Paytm पेटीएम कार्ड साउंडबॉक्स पेश किया है, जो वीज़ा, मास्टरकार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस और रुपे सहित मोबाइल और कार्ड भुगतान की सुविधा के लिए डिज़ाइन किया गया एक उपकरण है।
इस उत्पाद का उद्देश्य क्रेडिट और डेबिट कार्ड से भुगतान के लिए "टैप एंड पे" समाधान की पेशकश करके व्यापारियों को अपने व्यवसाय का विस्तार करने में मदद करना है।
यह पेटीएम साउंडबॉक्स के साथ ऑडियो-आधारित पुष्टि करण के पेटीएम के पहले के नवाचार पर आधारित है।

टिप्पणी:

पेटीएम देश में इन-स्टोर भुगतान में बदलाव लाते हुए, पेटीएम साउंडबॉक्स के साथ ऑडियो-आधारित पुष्टिकरण लॉन्च करने वाली पहली कंपनी थी।

प्रमुख विशेषताऐं:

यह डिवाइस ₹5,000 तक की सीमा के साथ कार्ड से भुगतान के लिए "टैप एंड पे" कार्यक्षमता की अनुमति देता है।
यह तीव्र भुगतान अलर्ट के लिए चौथी पीढ़ी (4जी) नेटवर्क पर काम करता है।
स्पष्ट ऑडियो भुगतान अलर्ट के लिए 4W स्पीकर से लैस।
लंबे समय तक चलने वाली बैटरी लाइफ, 5 दिनों तक चलने वाली।
11 भाषाओं में लेनदेन अलर्ट प्रदान करता है, जिसे व्यापारी पेटीएम फॉर बिजनेस ऐप के माध्यम से अनुकूलित कर सकता है।
नियर फील्ड कम्युनिकेशन (NFC)-सक्षम स्मार्टफोन उपयोगकर्ता टैप करके भुगतान कर सकते हैं।
यह एक प्वाइंट ऑफ सेल (PoS) यूनिट, एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) क्विक रिस्पांस (QR) कोड कार्ड और लेनदेन की पुष्टि के लिए एक साउंड बॉक्स की कार्यक्षमता को जोड़ती है।
कार्ड साउंडबॉक्स डिवाइस व्यापारियों के लिए दो महत्वपूर्ण चुनौतियों को संबोधित करता है: कार्ड भुगतान स्वीकार करना और तत्काल ऑडियो लेनदेन अलर्ट प्राप्त करना।

नवीनतम समाचार:

अगस्त 2023 में, भारत की प्रमुख भुगतान और वित्तीय सेवा कंपनी पेटीएम की मूल कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (OCL) ने दो भुगतान उपकरणों - पेटीएम पॉकेट साउंडबॉक्स और पेटीएम म्यूजिक साउंड बॉक्स को लॉन्च किया, ताकि गैर-प्रचार के दौरान व्यापारियों के लिए बेहतर भुगतान अनुभव प्रदान किया जा सके।

पेटीएम के बारे में:

स्थापना: 2010
मुख्यालय: नोएडा, उत्तर प्रदेश, भारत
संस्थापक और CEO: विजय शेखर शर्मा

फेडरल बैंक ने प्री-अप्रूव्ड पर्सनल लोन के लिए व्हाट्सएप लेंडिंग प्लेटफॉर्म पेश किया

फेडरल बैंक पूर्व-अनुमोदित व्यक्तिगत ऋणों के लिए आवेदन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए एक व्हाट्सएप लेंडिंग प्लेटफॉर्म पेश किया है।
मंच का उद्घाटन फेडरल बैंक के चेयरमैन एपी होता ने किया

प्रमुख विशेषताऐं:

यह नवोन्मेषी चैनल पूर्व-अनुमोदित व्यक्तिगत ऋणों के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल और सुव्यवस्थित करता है।
यह आमतौर पर पारंपरिक ऋण आवेदन प्रक्रियाओं से जुड़ी अनावश्यक जटिलताओं और देरी को समाप्त करता है।
ग्राहक बैंक के समर्पित व्हाट्सएप नंबर, 9633 600 800 पर एक सरल "हाय" संदेश भेजकर ऋण आवेदन प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।

फेडरल बैंक के बारे में:

मुख्यालय: अलुवा, कोच्चि, केरल, भारत

MD एवं CEO: श्याम श्रीनिवासन
टैगलाइन: योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर

इंडियन बैंक ने मोबाइल-फर्स्ट सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पेश करने के लिए वनकार्ड के साथ सहयोग किया

इंडियन बैंक मोबाइल-फर्स्ट, कॉन्टैक्टलेस और मेटल-को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पेश करने के लिए वनकार्ड के साथ साझेदारी की है।
कार्ड एक मोबाइल ऐप के साथ आता है जो कार्डधारकों को अपनी बातचीत को नियंत्रित करने की अनुमति देता है।

मुख्य विचार:

यह अंतर्राष्ट्रीय धातु क्रेडिट कार्ड शून्य ज्वाइनिंग और वार्षिक शुल्क के साथ आजीवन वैधता सहित कई अनुरूप लाभ प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है।
यह कार्ड कार्डधारकों को फीचर-पैक ऐप में अपने क्रेडिट कार्ड इंटरैक्शन के हर पहलू की देखरेख / ट्रैक करने की अनुमति देता है।
उपयोगकर्ता वास्तविक समय के लेनदेन को ट्रैक कर सकते हैं, खर्चों का प्रबंधन कर सकते हैं, भुगतान को EMI में बदल सकते हैं, पुरस्कार को भुना सकते हैं, पुनर्भुगतान को संभाल सकते हैं, मासिक बजट की योजना बना सकते हैं, क्रेडिट सीमा समायोजित कर सकते हैं, और भुगतान कर सकते हैं।
क्रेडिट कार्ड के अलावा, वनकार्ड एक मोबाइल-पहला मेटल क्रेडिट कार्ड है जिसे जारीकर्ता बैंकों के साथ साझेदारी में एफपीएल टेक्नोलॉजीज द्वारा प्रबंधित किया जाता है।

वनकार्ड के बारे में:

मुख्यालय: पुणे, महाराष्ट्र
CEO: अनुराग सिन्हा

इंडियन बैंक के बारे में:

स्थापना: 15 अगस्त 1907
मुख्यालय: चेन्नई, तमिलनाडु
MD और CEO: शांति लाल जैन
टैगलाइन: योर ओन बैंक

डिजिटल उत्पाद प्रदान करने के लिए शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक ने फिनटेक इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म फाल्कन के साथ साझेदारी की

शिवालिक लघु वित्त बैंक उत्तर भारत में मुख्यालय, ने तत्काल डिजिटल फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और बचत खातों जैसे वित्तीय उत्पादों को विकसित करने के लिए एक फिनटेक कंपनी फाल्कन के साथ साझेदारी की है।
साझेदारी एक तकनीकी मंच विकसित करने में मदद करेगी जो विरासत प्रणालियों से बेहतर प्रदर्शन करेगी और तकनीकी कंपनियों के साथ-साथ बैंक को भी सक्षम बनाएगी।

प्रमुख विशेषताऐं:

इस अगली पीढ़ी के प्लेटफॉर्म का एक प्रमुख लाभ यह है कि यह नए वित्तीय उत्पादों को लॉन्च करने के लिए आवश्यक लागत और समय को कम करेगा।
प्लेटफ़ॉर्म कई पूर्व-सुसज्जित सुविधाओं के साथ आता है, जिसमें नो-कोड मोबाइल और वेब एप्लिकेशन शामिल हैं।
इससे ग्राहकों के लिए उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफेस बनाना आसान हो जाता है।
प्लेटफ़ॉर्म में एक मजबूत डेवलपर हब शामिल है, यह दर्शाता है कि इसे वित्तीय उत्पादों को बनाने और बनाए रखने में डेवलपर्स का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
इसमें सुरक्षित सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट (SDK) और एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (API) का भी उल्लेख है, जो वित्तीय प्रौद्योगिकी में सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डालता है।

फाल्कन के सह-संस्थापक और CEO:

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में:

मुख्यालय: सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत
प्रबंध निदेशक: अंशुल स्वामी
शिवालिक शहरी सहकारी बैंक अर्थात् शिवालिक मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक (SMCB) से परिवर्तन करने वाला भारत का पहला लघु वित्त बैंक बन गया।

मनिपालसिग्ना हेल्थ को IRDAI द्वारा कर्नाटक राज्य जागरूकता बीमा योजना के लिए प्रमुख बीमाकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया

मणिपालसिग्ना स्वास्थ्य बीमा कर्नाटक में राज्य बीमा जागरूकता योजना के लिए भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा प्रमुख स्वास्थ्य बीमाकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है।

उद्देश्य:

कर्नाटक में बीमा कवरेज का विस्तार करना और स्वास्थ्य बीमा के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
मणिपालसिग्ना स्वास्थ्य बीमा के बारे में जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, यह सुनिश्चित करेगा कि कर्नाटक के नागरिकों को बीमा कवरेज तक पहुंच मिले।

मुख्य विचार:

मणिपालसिग्ना का व्यापक बहु-वितरण नेटवर्क व्यापक दर्शकों तक स्वास्थ्य बीमा जानकारी के प्रसार की सुविधा प्रदान करेगा।
मणिपालसिग्ना स्वास्थ्य बीमा के लिए अपने अभिनव दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है, जो कर्नाटक में जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य बीमा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने में मदद करेगा।
स्वास्थ्य सेवा वितरण में मणिपाल समूह की स्थानीय उपस्थिति और विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए, कंपनी का लक्ष्य IRDAI के "2047 सभी के लिए बीमा" के लक्ष्य का समर्थन करना है।
मणिपालसिग्ना ने स्वास्थ्य और वित्तीय कल्याण दोनों को सुनिश्चित करने में स्वास्थ्य बीमा की आवश्यक भूमिका पर जोर देने के लिए एक नई कन्नड़ टैगलाइन, "स्वास्थ्य बीमा अवष्यका" (स्वास्थ्य बीमा एक आवश्यकता है) पेश की है।
प्रबंध निदेशक और CEO, मणिपालसिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस: प्रसून सिकदर

SBI कार्ड ने अपने सुपर-प्रीमियम कार्ड 'ऑरम' के लिए उन्नत सुविधाएँ पेश कीं

भारत में सबसे बड़े क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता, एसबीआई कार्ड ने अपने सुपर प्रीमियम कार्ड के लिए सी-सूट अधिकारियों और उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों को लक्षित 'AURUM' नामक नई सुविधाएँ पेश की हैं।

AURUM के बारे में:

'AURUM' एक केवल-निमंत्रण कार्ड है, जिसे शुरुआत में फरवरी 2021 में लॉन्च किया गया था और अब यह अपने उपयोगकर्ताओं को उन्नत लाभ प्रदान करता है, जिसमें नए वार्षिक खर्च-आधारित मील के पत्थर और स्वागत लाभ से लेकर अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय लाउंज लाभ और गोल्फ विशेषाधिकार शामिल हैं।
इन संवर्द्धनों के साथ, 'AURUM' कार्डधारक अब अपने खर्च के आधार पर सालाना ₹2 लाख तक के लाभ का आनंद ले सकते हैं।
यह कार्ड कार्डधारकों को असीमित अंतरराष्ट्रीय लाउंज पहुंच प्रदान करता है, साथ ही साथ आने वाले मेहमानों के लिए 4 अंतरराष्ट्रीय लाउंज यात्रा भी प्रदान करता है।
इसके अलावा, कार्ड एक स्वागत योग्य उपहार के रूप में एक साल की क्लब मैरियट सदस्यता भी प्रदान करता है।
इस विशेष के लिए शामिल होने और वार्षिक सदस्यता शुल्ककार्ड 9,999 रुपये का है
हालाँकि, जब कार्डधारक कार्ड सदस्यता वर्ष के भीतर 12 लाख रुपये खर्च करने का लक्ष्य हासिल कर लेता है तो यह शुल्क वापस ले लिया जाता है।

SBI कार्ड के बारे में:

स्थापित: मई 1998
मुख्यालय: गुरूग्राम, हरियाणा, भारत
MD और CEO: अभिजीत चक्रवर्ती
SBI कार्ड को भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और GE कैपिटल द्वारा लॉन्च किया गया है।

इंडियन बैंक ने NESL के DDE प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन लॉकर समझौते के निष्पादन का विस्तार किया

इंडियन बैंक नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (NESL) के डिजिटल दस्तावेज निष्पादन (DDE) प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑन-लाइन लॉकर समझौते के निष्पादन की सुविधा का विस्तार करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक (PSB) बन गया, जो भारत की पहली सूचना उपयोगिता है और भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (IBBI) के साथ पंजीकृत है।
24/7 उपलब्ध ऑनलाइन लॉकर समझौतों की शुरूआत का उद्देश्य ग्राहक सुविधा को बढ़ाना है और समझौते के निष्पादन में लगने वाले समय को कम करना है।

DDE के बारे में:

DDE कागज रहित ई-स्टांप और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर (ई-साइन) सुविधा के साथ एक पूरी तरह से स्वचालित अनुबंध निष्पादन मंच है।
ई-साइन की सुविधा में आधार आधारित (OTP/बायोमेट्रिक) और डोंगल-आधारित डिजिटल हस्ताक्षर शामिल हैं।
प्लेटफ़ॉर्म व्यक्तिगत और एकाधिक हस्ताक्षरकर्ताओं को अनुक्रम में दस्तावेज़ निष्पादित करने की पेशकश करता है, जिससे संयुक्त खाता धारकों को भी आसानी से ऑन-लॉकर समझौतों को निष्पादित करने की सुविधा मिलेगी।
ग्राहक लेनदेन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं और वास्तविक समय में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य (65बी) प्रमाणपत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
संपूर्ण डिजिटल प्रक्रिया भौतिक स्टाम्प पेपर और हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर देती है, जिससे यह तेज़ और अधिक कुशल हो जाती है।

सेबी मार्च 2024 तक एक घंटे का व्यापार निपटान लागू करेगा

बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI), प्रतिभूति लेनदेन के निपटान में लगने वाले समय को काफी कम करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष, मार्च 2024 के अंत तक भारत में एक घंटे का व्यापार निपटान शुरू करने की योजना बना रहा है।
सेबी ने प्रतिभूति बाजार में तात्कालिक निपटान प्राप्त करने के अंतिम लक्ष्य के साथ वर्तमान निपटान चक्र से एक घंटे के निपटान में परिवर्तन के लिए एक रोडमैप अपनाया है।

मुख्य विचार:

कार्यान्वयन की समय सीमा: एक घंटे के निपटान में परिवर्तन पहले होने की उम्मीद है, तात्कालिक निपटान के लिए अंतिम कदम के लिए अतिरिक्त 6 से 8 महीने पर विचार किया जाएगा।
प्रौद्योगिकी तत्परता: एक घंटे का व्यापार निपटानकार्यान्वयन में तेजी आ रही है क्योंकि आवश्यक प्रौद्योगिकी अवसंरचना पहले से ही मौजूद है। इसके विपरीत, तात्कालिक निपटान के लिए और अधिक प्रौद्योगिकी विकास की आवश्यकता होती है।
ASBA जैसी सुविधा: सेबी ने जनवरी 2024 की लक्ष्य लॉन्च तिथि के साथ द्वितीयक बाजार में व्यापार के लिए अवरुद्ध राशि (ASBA) जैसी सुविधा द्वारा समर्थित एप्लिकेशन लॉन्च करने की योजना बनाई है।
ASBA आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) अनुप्रयोगों के लिए सेबी द्वारा विकसित एक प्रक्रिया है।

एक घंटे के व्यापार निपटान के क्या लाभ हैं?

मौजूदा टी+1 निपटान चक्र के तहत, यदि कोई निवेशक प्रतिभूतियां बेचता है, तो पैसा अगले दिन उस व्यक्ति के खाते में जमा हो जाता है।

एक घंटे के निपटान में, यदि कोई निवेशक कोई शेयर बेचता है, तो पैसा एक घंटे में उनके खाते में जमा हो जाएगा, और खरीदार को एक घंटे के भीतर अपने डीमैट खाते में शेयर मिल जाएंगे।

व्यापार समझौता क्या है?

निपटान एक दोतरफा प्रक्रिया है जिसमें निपटान तिथि पर धन और प्रतिभूतियों का हस्तांतरण शामिल होता है।
एक व्यापार समझौता तब पूरा माना जाता है जब किसी सूचीबद्ध कंपनी की खरीदी गई प्रतिभूतियाँ खरीदार को सौंप दी जाती हैं और विक्रेता को पैसा मिल जाता है।
टी+1 के वर्तमान चक्र का मतलब है कि व्यापार-संबंधित निपटान वास्तविक लेनदेन के एक दिन या 24 घंटों के भीतर होता है।
भारत चीन के बाद शीर्ष-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में T+1 निपटान चक्र शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया, जिससे परिचालन दक्षता, तेज़ फंड प्रेषण, शेयर डिलीवरी और शेयर बाजार सहभागियों के लिए आसानी हुई।

सेबी के बारे में:

स्थापना: 12 अप्रैल 1988 को एक कार्यकारी निकाय के रूप में और 30 जनवरी 1992 को सेबी अधिनियम, 1992 के माध्यम से वैधानिक शक्तियां दी गईं।
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र
अध्यक्ष: माधबी पुरी बुच (सेबी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला)
सेबी भारत में वित्त मंत्रालय (MoF), भारत सरकार के स्वामित्व के तहत प्रतिभूतियों और कमोडिटी बाजारों के लिए नियामक निकाय है।

हिताची पेमेंट सर्विसेज ने NPCI के सहयोग से भारत का पहला UPI-ATM पेश किया

जापान स्थित हिताची लिमिटेड की 100% सहायक कंपनी हिताची पेमेंट सर्विसेज ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के सहयोग से भारत का पहला यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI)-ऑटोमेटेड टेलर मशीन (ATM) लॉन्च किया है।
हिताची मनी स्पॉट UPI ATM नामक UPI-ATM, भौतिक ATM कार्ड की आवश्यकता को समाप्त करते हुए, कार्ड रहित नकदी निकासी की सुविधा देता है।
यह UPI-ATM व्हाइट लेबल एटीएम (WLA) के रूप में काम करता है, जो गैर-बैंकिंग संस्थाओं द्वारा संचालित एक प्रकार का ATM है।

UPI-ATM (इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विदड्रॉल - ICCW) की मुख्य विशेषताएं:

अनुकूलता: UPI-ATM विभिन्न प्रणालियों के साथ संगत है, जिससे पहुंच में वृद्धि होती है।
कार्ड रहित लेनदेन: उपयोगकर्ता भौतिक ATM कार्ड की आवश्यकता के बिना लेनदेन कर सकते हैं।
लेन-देन की सीमा: यह मौजूदा UPI दैनिक सीमा और जारीकर्ता बैंक की UPI-ATM लेनदेन सीमा के अनुरूप, प्रति लेनदेन ₹10,000 तक की नकद निकासी की अनुमति देता है।
सुविधा: UPI-ATM नकदी निकासी के लिए ATM कार्ड ले जाने की आवश्यकता को समाप्त कर देता है, जिससे बेहतर सुविधा मिलती है।
एकाधिक खाता पहुंच: उपयोगकर्ता यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ऐप के जरिए कई खातों से नकदी निकाल सकते हैं।

वित्तीय समावेशन और पहुंच:

वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना: उम्मीद है कि UPI-ATM बैंकिंग सेवाओं तक आसान पहुंच की सुविधा देकर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगा, विशेष रूप से सीमित पारंपरिक बैंकिंग बुनियादी ढांचे और कम कार्ड पहुंच वाले क्षेत्रों में।
सुदूर क्षेत्रों में पहुंच: इस नवोन्मेषी अवधारणा को भारत के दूरदराज के हिस्सों में भी नकदी तक त्वरित पहुंच प्रदान करने और वित्तीय सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

यह बैंकों द्वारा दी जाने वाली कार्ड रहित नकद निकासी से किस प्रकार भिन्न है?

QR-आधारित UPI नकद निकासी: बैंकों द्वारा दी जाने वाली वर्तमान कार्डलेस नकद निकासी के विपरीत, जो मोबाइल नंबर और OTP पर निर्भर है, UPI-ATM QR-आधारित UPI नकद निकासी के माध्यम से कार्य करता है।

UPI आवेदन की आवश्यकता: UPI-ATM का उपयोग करने के लिए, व्यक्तियों को अपने एंड्रॉइड या iOS स्मार्टफोन पर एक UPI एप्लिकेशन इंस्टॉल करना होगा। लेन-देन करने के लिए UPI एप्लिकेशन आवश्यक है।

हिताची पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के बारे में:

स्थापित: 2008
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र
MD और CEO: सुमिल विकमसी
हिताची पेमेंट सर्विसेज एकमात्र व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर है जो भारत में 3,000 से अधिक स्थानों पर नकद जमा सुविधा प्रदान करती है।
हिताची 65,500 से अधिक ATM के एक बड़े नेटवर्क का प्रबंधन करती है, जिसमें 27,500 नकदी रीसाइक्लिंग मशीनें और 9,500 व्हाइट लेबल ATM (WLA) शामिल हैं।

AMFI ने परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों (AMC) के लिए एजेंट के रूप में कार्य करने की इच्छुक प्रत्यक्ष म्यूचुअल फंड फर्मों के लिए दिशानिर्देश स्थापित किए हैं

एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) ने उनके साथ केवल निष्पादन प्लेटफॉर्म (EOP) के रूप में पंजीकरण करने में रुचि रखने वाले प्रत्यक्ष योजना वितरकों के लिए 1 करोड़ रुपये की शुद्ध संपत्ति की आवश्यकता स्थापित की है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) नेअनिवार्य है कि प्रत्यक्ष म्यूचुअल फंड (MF) योजनाओं को वितरित करने के लिए विशेष रूप से समर्पित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को EOP बनना चाहिए।
वे इसे एक्सचेंजों (EOP श्रेणी 2) या AMFI (EOP श्रेणी 1) के साथ पंजीकरण करके हासिल कर सकते हैं।

मुख्य विचार:

जबकि AMFI ने पंजीकरण के लिए दिशानिर्देश प्रदान किए हैं, इसने अधिकतम शुल्क सीमा निर्दिष्ट नहीं की है जो EOP अपनी सेवाओं के लिए ले सकते हैं।
सेबी का विनियमन सितंबर में लागू हुआ, और यह इन प्लेटफार्मों को EOP के रूप में पंजीकृत करना अनिवार्य करता है, जिसके अनुपालन की समय सीमा दिसंबर निर्धारित की गई है।
EOP के रूप में AMFI के साथ सफलतापूर्वक पंजीकरण करने के बाद, एमएफ वितरण प्लेटफार्मों को अपनी प्रत्यक्ष योजनाओं की ऑनलाइन बिक्री शुरू करने के लिए फंड हाउसों के साथ समझौते स्थापित करने की आवश्यकता होती है।

AMFI के बारे में:

स्थापना: 22 अगस्त, 1995
CEO: श्री एनएस वेंकटेश
एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) पेशेवर, नैतिक और स्वस्थ मानकों को बनाए रखते हुए भारतीय म्यूचुअल फंड उद्योग को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है।
इसका प्राथमिक लक्ष्य म्यूचुअल फंड और उनके यूनिट धारकों के हितों की रक्षा करना और उन्हें बढ़ावा देना है।
अब तक, AMFI 44 परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है जो सेबी के साथ इसके सदस्यों के रूप में पंजीकृत हैं।

PSB एलायंस ने 6,800 स्थानों पर डोर-स्टेप बैंकिंग सेवाएं शुरू कीं

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) द्वारा स्थापित एक कंपनी PSB एलायंस प्राइवेट लिमिटेड ने जून 2024 तक पूरे भारत में 6,800 केंद्रों तक विस्तार करने की योजना बनाई है, जो वर्तमान 100 केंद्रों से काफी वृद्धि है, जिसका उद्देश्य अपनी DSB सेवाओं के कवरेज में काफी वृद्धि करना है।
PSB एलायंस संयुक्त रूप से 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के स्वामित्व में है, प्रत्येक बैंक की कंपनी में 8.33% हिस्सेदारी है। यह सहयोगी स्वामित्व संरचना DSB सेवाओं के सामूहिक विस्तार को सक्षम बनाती है।

Click Here to Subscribe Our Yearly Mock Test Package

मुख्य विचार:

कम लेनदेन शुल्क: PSB एलायंस का लक्ष्य DSB लेनदेन से जुड़े शुल्कों को कम करना है।
उनका लक्ष्य लेनदेन लागत को प्रति लेनदेन ₹50 से कम करना है, जो कि ₹75 के वर्तमान शुल्क (₹13.50 के GST को छोड़कर) से एक महत्वपूर्ण कमी है।
DSB सेवाओं की रेंज: PSB एलायंस द्वारा वर्तमान में दी जाने वाली DSB सेवाओं में शामिल हैं:
₹1,000 से ₹10,000 तक की लेनदेन सीमा के साथ नकद जमा सेवाएँ।
फंड ट्रांसफर सेवाएं, ₹25,000 की संचयी दैनिक सीमा के साथ अधिकतम 3 फंड ट्रांसफर अनुरोधों की अनुमति देती हैं।
डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र सेवाएँ।
नामांकन सेवाएँ
PSB एलायंस के मुख्य कार्यकारी और प्रबंध निदेशक: राजिंदर मिराखुर

भारत में UPI लेनदेन अगस्त 2023 में पहली बार 10 बिलियन के आंकड़े को पार कर गया

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के अनुसार, यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने अगस्त 2023 में लेनदेन की मात्रा 10 बिलियन को पार कर लिया, जो भुगतान के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
30 अगस्त, 2023 तक, UPI पर मासिक लेनदेन संख्या 10.24 बिलियन तक पहुंच गई थी, जिसका कुल शुद्ध लेनदेन मूल्य ₹15.18 ट्रिलियन था।
UPI केवल घरेलू उपयोग तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि इसका उपयोग छोटे-टिकट लेनदेन के लिए तेजी से किया जाता है। इसके अलावा, यह भारत की विदेश नीति का एक अभिन्न अंग बन गया है।

UPI क्या है?

UPI एक एकीकृत प्रणाली है जो कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लिकेशन (किसी भी भाग लेने वाले बैंक के) में समेकित करती है, जो एक ही मंच के भीतर विभिन्न बैंकिंग सुविधाएं, निर्बाध फंड रूटिंग और व्यापारी भुगतान की पेशकश करती है।
UPI "पीयर टू पीयर" संग्रह अनुरोधों का भी समर्थन करता है, जिससे उपयोगकर्ता की सुविधा और आवश्यकता के अनुसार निर्धारित भुगतान सक्षम हो जाता है।
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने शुरुआत में 2016 में पायलट आधार पर UPI की शुरुआत की थी।
UPI ने अक्टूबर 2019 में अपना पहला अरब मासिक लेनदेन मील का पत्थर हासिल किया, जो इसके अपनाने में उल्लेखनीय वृद्धि का संकेत देता है, इसे चार गुना बढ़ने में चार साल से भी कम समय लगा।

नवीनतम समाचार:

NPCI के आंकड़ों के अनुसार, जुलाई 2023 में, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने 9.96 बिलियन लेनदेन दर्ज किए, जिसका महीने का कुल मूल्य 15.34 लाख करोड़ रुपये था।

NPCI के बारे में:

स्थापित: 2008
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र, भारत
MD और CEO: दिलीप अस्बे
NPCI भारत में मजबूत खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली बनाने और संचालित करने के लिए एक प्रमुख संगठन है।
यह भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारतीय बैंक संघ (IBA) की एक पहल है।

PNB ने निर्बाध लेनदेन के लिए CBDC और UPI के बीच इंटरऑपरेबिलिटी की शुरुआत की

राज्य के स्वामित्व वाले पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने अपने डिजिटल रुपया मोबाइल एप्लिकेशन में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) इंटरऑपरेबिलिटी फीचर के साथ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) लॉन्च किया है।
यह कदम RBI के CBDC पायलट प्रोजेक्ट के अनुरूप है और भारत के भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में एक नई क्षमता को उजागर करता है।
PNB ग्राहक अब अपने व्यापारियों को भुगतान के लिए UPI QR कोड को स्कैन करने या किसी व्यापारी आउटलेट पर लेनदेन पूरा करने के लिए PNB डिजिटल रुपया ऐप का उपयोग कर सकते हैं।
भले ही व्यापारियों के पास CBDC वॉलेट नहीं है, PNB डिजिटल रुपया ऐप उपयोगकर्ता इन व्यापारियों के UPI QR पर लेनदेन करने के लिए अपने CBDC वॉलेट का उपयोग कर सकते हैं।
इस नई कार्यक्षमता वाला ऐप वर्तमान में एंड्रॉइड उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध हैप्ले स्टोर और iOS यूजर्स के लिए भी लाइव किया जाएगा।

नवीनतम समाचार:

विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस (21 अगस्त, 2023) पर, देश के अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने "पेंशनर्स लाउंज" की शुरुआत की है, जो शाखा के भीतर एक समर्पित स्थान है जो पेंशनभोगियों और वरिष्ठ नागरिकों को उनकी सभी बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करता है।

PNB के बारे में:

स्थापना: 19 मई 1894
मुख्यालय: द्वारका, दिल्ली, भारत
MD एवं CEO: अतुल कुमार गोयल
टैगलाइन: यू कैन बैंक अपॉन

RBI और NPCI ने UPI और संवादी भुगतान के लिए क्रेडिट लाइन शुरू की

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल के दौरान UPI, UPI लाइट एक्स, टैप एंड पे, हैलो! UPI और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा कंवर्सल बिल पेमेंट्स पर क्रेडिट लाइन सहित कई नए डिजिटल भुगतान उत्पादों को लॉन्च किया है।

उद्देश्य:

भारत में एक समावेशी, लचीला और टिकाऊ डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र बनाना।
लक्ष्य UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) को प्रति माह 100 अरब लेनदेन संसाधित करने का लक्ष्य हासिल करने में मदद करना है।

हैलो! UPI:

हैलो! UPI उपयोगकर्ताओं को ऐप, दूरसंचार कॉल और IoT उपकरणों सहित विभिन्न चैनलों के माध्यम से वॉयस-सक्षम UPI भुगतान करने में सक्षम बनाता है।
यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लेनदेन का समर्थन करता है और जल्द ही क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा।
हैलो! UPI को खंडों में विभाजित किया गया है: UPI पर संवादात्मक भुगतान, बिलपे कनेक्ट।

UPI पर संवादात्मक भुगतान:

संवादी भुगतान एआई-सक्षम लेनदेन के उपयोग पर प्रकाश डालते हैं, जिससे डिजिटल भुगतान के लिए मानव-मशीन इंटरैक्शन की सुविधा मिलती है।
इस नवाचार का उद्देश्य पूरे देश में डिजिटल भुगतान की पहुंच और उपयोग का विस्तार करना है।

अन्य लॉन्च:

NPCI ने हिंदी और अंग्रेजी में भुगतान भाषा मॉडल को सह-विकसित करने के लिए IIT मद्रास में AI4भारत के साथ साझेदारी की है।

बिलपे कनेक्ट:

भारत बिलपे ने पूरे भारत में बिल भुगतान के लिए एक राष्ट्रीयकृत नंबर पेश किया है, जिससे ग्राहकों के लिए मैसेजिंग ऐप के माध्यम से अपने बिल प्राप्त करना और भुगतान करना सुविधाजनक हो गया है।

UPI पर क्रेडिट लाइन:

NPCI ने UPI पर क्रेडिट लाइन शुरू की है, जिससे बैंकों से UPI के माध्यम से पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइन की अनुमति मिलती है।

इस पहल का उद्देश्य ऋण तक पहुंच बढ़ाना, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और डिजिटल बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र को सुव्यवस्थित करना है।

ऑफ़लाइन भुगतान के लिए UPI LITE X:

UPI LITE X को ऑफ़लाइन भुगतान के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो उपयोगकर्ताओं को निरंतर इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता के बिना पैसे भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।

यह खराब कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में भी तेजी से लेनदेन के लिए नियर फील्ड कम्युनिकेशन (NFC) तकनीक का उपयोग करता है।

UPI टैप करें और भुगतान करें:

UPI टैप एंड पे ग्राहकों को एक सुविधाजनक और कुशल भुगतान पद्धति की पेशकश करते हुए केवल NFC-सक्षम QR कोड को टैप करके भुगतान पूरा करने की अनुमति देता है।

ये उत्पाद लॉन्च भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति घोषणाओं के अनुरूप हैं, जो डिजिटल भुगतान और वित्तीय नवाचार को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बैंक की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं।

ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के बारे में:

ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (GFF) सबसे बड़ा फिनटेक सम्मेलन है।

इसका आयोजन NPCI, पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल (FCC) द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।

टियर 2 और टियर 3 शहरों के लिए बुनियादी ढांचे के ऋण का प्रारंभिक बैच शीघ्र ही जारी किया जाएगा

केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय शहरी बुनियादी ढांचा विकास कोष (UIDF) के तहत टियर-2 और टियर-3 शहरों में चल रही परियोजनाओं के लिए ऋण की पहली किस्त वितरित करने की तैयारी कर रहा है।

UIDF के बारे में:

UIDF की स्थापना प्राथमिकता क्षेत्र की ऋण कमी को दूर करने के लिए की गई है।

उद्देश्य: इस फंड का उपयोग सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा टियर-2 और टियर-3 शहरों में शहरी बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए किया जाएगा।

सीवेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल आपूर्ति और स्वच्छता, नालियों/तूफान जल निकासी आदि के निर्माण और सुधार जैसी बुनियादी सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और प्रभाव-उन्मुख परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाता है।

इस फंड के लिए प्रारंभिक राशि ₹10,000 करोड़ है।

UIDF को ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (RIDF) की तर्ज पर तैयार किया गया है।

राज्यों को UIDF तक पहुंच के दौरान उचित उपयोगकर्ता शुल्क अपनाने के लिए 15वें वित्त आयोग के अनुदान के साथ-साथ मौजूदा योजनाओं से संसाधनों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

इसमें वर्तमान में 459 टियर-2 शहर और 580 टियर-3 शहर शामिल हैं।

ब्याज दर और पुनर्भुगतान शर्तें:

UIDF ऋण पर ब्याज दर बैंक दर शून्य से 1.5% निर्धारित है।

मूल ऋण राशि दो साल की अधिस्थगन अवधि के साथ, ड्रा तिथि से 7 वर्षों के भीतर 5 समान वार्षिक किस्तों में चुकानी होगी।

ब्याज भुगतान तिमाही आधार पर किया जाता है।

टियर-2 और टियर-3 शहर क्या हैं?

NHB, UIDF के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी, 2011 की जनगणना के अनुसार टियर-2 शहरों को 50,000 से एक लाख से कम आबादी वाले शहरों और टियर-3 शहरों को 1 लाख से दस लाख से कम आबादी के रूप में परिभाषित करती है।

RIDF के बारे में:

RIDF की स्थापना सरकार द्वारा 1995-96 में चल रही ग्रामीण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए की गई थी।

इस फंड का रखरखाव राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा किया जाता है।

योगदान: घरेलू वाणिज्यिक बैंक कृषि के लिए निर्धारित प्राथमिकता क्षेत्र ऋण में अपनी कमी की सीमा तक फंड में योगदान करते हैं।

मास्टरकार्ड और KredX ने व्यवसायों और आपूर्तिकर्ताओं के लिए प्रोत्साहन के साथ B2B भुगतान बढ़ाने के लिए साझेदारी की

मास्टरकार्ड ने बिजनेस टू बिजनेस (B2B) डिजिटल भुगतान को बदलने के लिए भारत के सबसे बड़े आपूर्ति श्रृंखला वित्त मंच क्रेडएक्स (मिनियन्स वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड) के साथ रणनीतिक रूप से भागीदारी की है, जिससे उद्यमों और विक्रेताओं दोनों को लाभ होगा।

B2B भुगतान के बारे में:

B2B भुगतान में उपभोक्ता लेनदेन को छोड़कर, दो व्यवसायों के बीच वस्तुओं या सेवाओं के लिए मुद्रा का आदान-प्रदान शामिल है।

इन व्यवसायों में निगम, खुदरा विक्रेता, थोक विक्रेता और स्टार्टअप शामिल हो सकते हैं।

वाणिज्यिक कार्ड सेवा का एकीकरण:

सहयोग के हिस्से के रूप में, मास्टरकार्ड अपनी वाणिज्यिक कार्ड सेवा को क्रेडएक्स प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत करेगा, जिससे B2B भुगतान से जुड़ी जटिलताओं को समाप्त किया जाएगा, विशेष रूप से कार्ड के माध्यम से किए गए।

प्लेटफ़ॉर्म की मुख्य विशेषताएं:

प्लेटफ़ॉर्म गतिशील छूट, शीघ्र भुगतान विकल्प और मूल्य खोज जैसी सुविधाएँ प्रदान करता है, जो उद्यमों और विक्रेताओं दोनों के लिए नकदी प्रवाह को बढ़ाता है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) द्वारा संचालित, यह व्यवसायों के लिए पूर्ण खरीद-से-भुगतान की पेशकश के रूप में कार्य करेगा, जिससे उन्हें चालान के तेज़ और अधिक कुशल मिलान और प्रसंस्करण में मदद मिलेगी।

स्मार्ट बोली एल्गोरिदम:

प्लेटफ़ॉर्म में एक स्मार्ट बिड एल्गोरिदम शामिल है जो उद्यमों को विक्रेताओं द्वारा दी जाने वाली सर्वोत्तम छूट दरों की खोज करने में मदद करता है।

उन्नत परिचालन दक्षता:

छूट-पूर्व प्रक्रियाओं को छूट-पश्चात भुगतानों के साथ एकीकृत करके, प्लेटफ़ॉर्म कंपनियों के लिए परिचालन दक्षता को बढ़ाता है।

यह आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करता है, सुचारू संचालन में योगदान देता है।

सामान्य चुनौतियों का समाधान:

सहयोगी मंच का लक्ष्य B2B भुगतान में विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करना है, जिसमें लंबी लेखांकन और समाधान प्रक्रियाएं, सीमित विक्रेता स्वीकृति और बार-बार चार्जबैक शामिल हैं।

यह इन-हाउस पेमेंट गेटवे या पॉइंट-ऑफ-सेल (PoS) मशीनों के बिना छोटे विक्रेताओं के बीच भी डिजिटल भुगतान को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

आपूर्ति श्रृंखला वेग:

वित्तीय नवाचार के माध्यम से आपूर्ति श्रृंखला वेग में तेजी लाना KredX के मूल्य प्रस्ताव का एक प्रमुख पहलू है।

आपूर्ति श्रृंखलाओं के भीतर नकदी प्रवाह और परिचालन दक्षता में सुधार करके साझेदारी इस लक्ष्य के अनुरूप है।

क्रेडक्स के बारे में:

स्थापित: 2015
मुख्यालय: बैंगलोर, कर्नाटक
CEO: मनीष कुमार

सेबी ने निवेशक सुरक्षा और शिक्षा निधि भुगतान के लिए केवल-ऑनलाइन मोड को अनिवार्य किया है

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कहा है कि सेबी निवेशक सुरक्षा और शिक्षा कोष (IPEF) खाते में भुगतान अब केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया जा सकता है।

उद्देश्य:

भुगतान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और फंड में योगदान करने वाले सभी व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए पहुंच बढ़ाना।

ऑनलाइन भुगतान के तरीके:

बिचौलियों के पास अब विभिन्न ऑनलाइन भुगतान विधियों का उपयोग करके IPEF को भुगतान करने की सुविधा है, जिनमें शामिल हैं:
नेट बैंकिंग
राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS)
डेबिट कार्ड
एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI)

IEPF क्या है?

IEPF कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1999 के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205C के तहत स्थापित एक फंड है। यह फंड 2 प्रमुख उद्देश्यों को पूरा करता है:

निवेशक जागरूकता: इसका उद्देश्य निवेशकों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देना, उन्हें वित्तीय मामलों और निवेश से संबंधित विषयों के बारे में शिक्षित करना है।

निवेशक सुरक्षा: IEPF निवेशकों के हितों के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में भी कार्य करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके फंड सुरक्षित हैं और उचित रूप से प्रबंधित किए जाते हैं।

सेबी के बारे में:

स्थापना: 12 अप्रैल 1988 एक कार्यकारी निकाय के रूप में और सेबी अधिनियम, 1992 के माध्यम से 30 जनवरी 1992 को वैधानिक शक्तियां दी गईं
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र
अध्यक्ष: माधबी पुरी बुच (सेबी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला)
SEBI भारत में प्रतिभूति और कमोडिटी बाजारों के लिए नियामक निकाय है जो वित्त मंत्रालय (MoF), भारत सरकार के स्वामित्व के तहत है।

सेबी ने ग्रो को अपना उद्घाटन इंडेक्स फंड लॉन्च करने की मंजूरी दी

एसेट मैनेजमेंट कंपनी ग्रो म्यूचुअल फंड को बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड नाम से अपना पहला इंडेक्स फंड लॉन्च करने की मंजूरी मिल गई है।

ग्रो म्यूचुअल फंड को अपनी पहली नई फंड पेशकश (NFO) - ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड के लिए मंजूरी मिल गई जेरोधा ने बाजार नियामक को दो योजनाओं, जेरोधा टैक्स सेवर (ELSS) निफ्टी लार्ज मिडकैप 250 इंडेक्स फंड और जेरोधा निफ्टी लार्ज मिडकैप 250 इंडेक्स फंड (जेडएन250) को लॉन्च करने के लिए मसौदा प्रस्ताव दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं।

NFO क्या है?

एक नया फंड ऑफर (NFO) किसी निवेश कंपनी द्वारा पेश किए गए किसी भी नए फंड के लिए पहली सदस्यता पेशकश है।

एक नया फंड ऑफर तब होता है जब एक फंड लॉन्च किया जाता है, जिससे फर्म को प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए पूंजी जुटाने की अनुमति मिलती है।
म्यूचुअल फंड एक निवेश कंपनी द्वारा विपणन किए जाने वाले सबसे आम नए फंड प्रस्तावों में से एक है।

ग्रो म्यूचुअल फंड के बारे में:

मुख्यालय: बेंगलुरु, कर्नाटक
CEO: वरुण गुप्ता

SBI कार्ड ने MSME क्षेत्र को लक्ष्य करते हुए 'सिंपलीसेव मर्चेंट SBI कार्ड' पेश किया है

भारत के सबसे बड़े प्योर-प्ले क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता, SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड (SBI कार्ड) ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए 'सिंपलीसेव मर्चेंट SBI कार्ड' लॉन्च किया है, जिसमें अल्पकालिक क्रेडिट विकल्प और अन्य विशेष लाभ शामिल हैं।
कार्ड का आधिकारिक तौर पर अनावरण भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष श्री दिनेश खारा द्वारा मुंबई, महाराष्ट्र में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के दौरान किया गया था।
'सिंपलीसेव मर्चेंट SBI कार्ड' का उद्देश्य ब्याज मुक्त अल्पकालिक ऋण विकल्प प्रदान करके MSME की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है, जिससे उन्हें औपचारिक ऋण तक आसान और समय पर पहुंच प्रदान की जा सके।
यह कार्ड RuPay नेटवर्क पर काम करता है, जो भारत में एक घरेलू भुगतान नेटवर्क है, और इसे UPI-सक्षम तृतीय-पक्ष एप्लिकेशन के माध्यम से भुगतान करने के लिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI) से जोड़ा जा सकता है।

SBI कार्ड के बारे में:

स्थापित: मई 1998
मुख्यालय: गुड़गांव, हरियाणा
MD एवं CEO: अभिजीत चक्रवर्ती
SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड, जिसे पहले SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, भारत में एक क्रेडिट कार्ड कंपनी और भुगतान प्रदाता है।

एयू स्मॉल फाइनेंस ने 'जेनिथ मेटल क्रेडिट कार्ड' का अनावरण किया

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने अपने बैंकिंग समाधानों की श्रृंखला के अतिरिक्त 'जेनिथ + सुपर प्रीमियम मेटल क्रेडिट कार्ड' लॉन्च किया।

प्रमुख विशेषताऐं:

लाउंज प्रवेश: कार्ड प्रीमियम लाउंज एक्सेस प्रदान करता है, जो कार्डधारकों को आरामदायक और शानदार यात्रा अनुभव प्रदान करता है।
वैयक्तिकृत द्वारपाल सेवाएँ: कार्डधारक सुविधा और सहायता को बढ़ाते हुए वैयक्तिकृत द्वारपाल सेवाओं तक पहुंच सकते हैं।
स्वागत लाभ: कार्ड में प्रीमियम ब्रांड वाउचर या 5000 रुपये मूल्य के रिवॉर्ड पॉइंट के साथ एक स्वागत पैकेज शामिल है, जो नए कार्डधारकों को तत्काल लाभ प्रदान करता है।
इस क्रेडिट कार्ड की एक उल्लेखनीय विशेषता अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए 0.99% का कम विदेशी मुद्रा मार्कअप है।
यह इसे वैश्विक लेनदेन और विदेशी मुद्रा खर्च के लिए फायदेमंद बनाता है।
कार्डधारक 1 साल की मानार्थ ताज एपिक्योर सदस्यता के साथ विशेष भोजन अनुभव का आनंद ले सकते हैं, जिससे कार्ड की पेशकश में और अधिक मूल्य जुड़ जाएगा।

नवीनतम समाचार:

मई 2023 में, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बिजनेस कैशबैक रुपे क्रेडिट कार्ड को रोल आउट करने के लिए रुपे के साथ साझेदारी की, जो स्व-नियोजित ग्राहकों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक अभिनव समाधान है।

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के बारे में:

स्थापना: 1996
मुख्यालय: जयपुर, राजस्थान
MD एवं CEO: संजय अग्रवाल

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस ने रणनीतिक साझेदारी में प्रवेश किया

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक (AU SFB) और बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के विविध ग्राहक आधार को उनकी वित्तीय सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए जीवन बीमा उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है।
समझौते पर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के कार्यकारी निदेशक उत्तम टिबरेवाल और बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के MD और CEO तरुण चुघ ने हस्ताक्षर किए।
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का उद्देश्य बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस से विभिन्न प्रकार के जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश करके ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी-आधारित समाधानों का लाभ उठाना है।

मुख्य विचार:

इस साझेदारी के माध्यम से, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए और मौजूदा ग्राहक अब बजाज आलियांज लाइफ के खुदरा उत्पादों में से चुन सकते हैं, जिसमें टर्म इंश्योरेंस, बचत योजनाएं, सेवानिवृत्ति समाधान और निवेश उत्पाद शामिल हैं।
जीवन बीमाकर्ता, बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस, ग्राहकों को निर्बाध सेवा विकल्प प्रदान करने के लिए बैंक के साथ मिलकर सहयोग करेगा।
इसमें ग्राहकों के प्रश्नों के समाधान के लिए एयू डिजिटल प्लेटफॉर्म पर व्हाट्सएप और चैटबॉट जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग करना शामिल है।
इसके अतिरिक्त, सुचारु ग्राहक अनुभव सुनिश्चित करने के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित बैंक कर्मचारी जीवन बीमा व्यवसाय का प्रबंधन करेंगे।

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में:

मुख्यालय: जयपुर, राजस्थान, भारत
MD एवं CEO: संजय अग्रवाल

बजाज आलियांज लाइफ ने नई बचत योजना पेश की - बजाज आलियांज लाइफ ACE

बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने "बजाज आलियांज लाइफ ACE" नामक एक नई बचत योजना शुरू की है।

बजाज आलियांज लाइफ ACE के बारे में:

बजाज आलियांज लाइफ ACE एक गैर-लिंक्ड, भाग लेने वाली प्रारंभिक-आय जीवन बीमा योजना है।
यह ग्राहकों को उनकी विशिष्ट वित्तीय आवश्यकताओं और लक्ष्यों के अनुरूप नकदी प्रवाह को अनुकूलित करने में अधिक लचीलापन प्रदान करता है।

प्रमुख विशेषताऐं:

गतिशील आय विकल्प: ग्राहकों के पास अपनी पसंदीदा आय राशि, आय प्रारंभ वर्ष, आय अवधि चुनने और यहां तक कि अपने विशिष्ट वित्तीय उद्देश्यों के अनुरूप परिपक्वता लाभों को समायोजित करने की सुविधा है।
यह सुविधा सुनिश्चित करती है कि योजना वित्तीय आवश्यकताओं की एक विस्तृत श्रृंखला को पूरा कर सकती है।
शीघ्र या आस्थगित आय विकल्प: पॉलिसीधारक पॉलिसी की शुरुआत से ही आय प्राप्त करना शुरू करने या इसे 5 साल तक के लिए स्थगित करने का निर्णय ले सकते हैं।
यह लचीलापन उन्हें अपनी वित्तीय परिस्थितियों और जरूरतों के आधार पर योजना तैयार करने की अनुमति देता है।

आय अवधि: यह योजना न्यूनतम 10 वर्ष से लेकर 100 वर्ष की आयु तक की आय अवधि चुनने में लचीलापन प्रदान करती है।
लक्ष्य संरक्षण लाभ: यह विकल्प आश्वस्त करता है कि पॉलिसीधारक के परिवार को पूरी पॉलिसी अवधि के दौरान आय प्राप्त होती रहेगी, यहां तक कि पॉलिसीधारक की मृत्यु की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में भी।
महिलाओं के लिए अतिरिक्त लाभ: बजाज आलियांज लाइफ ACE एक अतिरिक्त सुविधा प्रदान करता हैआय लाभ विशेष रूप से महिलाओं के लिए डिज़ाइन किया गया है।
यह सुविधा महिलाओं को बेहतर वित्तीय सुरक्षा और लचीलेपन के साथ अपने जीवन के लक्ष्यों के लिए योजना बनाने में सशक्त बनाती है।

बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बारे में:

स्थापना: 2001
मुख्यालय: पुणे, महाराष्ट्र
MD एवं CEO: तरूण चुघ
बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, भारत की अग्रणी निजी जीवन बीमा कंपनियों में से एक, बजाज फिनसर्व लिमिटेड, भारत में सबसे विविध गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों में से एक बजाज फिनसर्व लिमिटेड और दुनिया के अग्रणी वैश्विक बीमाकर्ता और परिसंपत्ति प्रबंधक में से एक आलियांज एसई के बीच एक संयुक्त उद्यम (JV) है।

आईडेमिया, एयरटेल पेमेंट्स बैंक और HMD ग्लोबल ने फीचर फोन पर डिजिटल रुपया सक्षम करने के लिए सहयोग किया है

इडेमिया वैश्विक पहचान प्रौद्योगिकी और बायोमेट्रिक समाधान प्रदाता, ने फीचर फोन पर डिजिटल रुपया भुगतान सक्षम करने के लिए एक ऑफ़लाइन प्रणाली शुरू करने के लिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक (भारती एयरटेल की सहायक कंपनी) और HMD ग्लोबल (नोकिया फोन के निर्माता) के साथ साझेदारी की है।

डिजिटल रुपया क्या है?

डिजिटल रुपया भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) के रूप में जारी भारतीय फिएट मुद्रा का एक प्रतीकात्मक डिजिटल प्रतिनिधित्व है।
यह पहल RBI द्वारा जारी CBDC को एप्लिकेशन इंटरफ़ेस के माध्यम से फीचर फोन पर उपलब्ध कराने का पहला प्रयास है।

साझेदारी की मुख्य विशेषताएं:

तीनों संगठन आने वाले महीनों में एक उन्नत ऑफ़लाइन भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए सहयोग करेंगे जो फीचर फोन उपयोगकर्ताओं को डिजिटल रुपया (RBI द्वारा जारी CBDC) का उपयोग करने की अनुमति देता है, जो उद्योग में अपनी तरह की पहली पहल है।
नोकिया फ़ीचर फ़ोन उपयोगकर्ताओं पर प्रभाव: निकट भविष्य में व्यावसायिक रूप से लॉन्च होने के बाद, यह पहल भारत में नोकिया फीचर फोन के उपयोगकर्ताओं को डिजिटल रुपये तक पहुंचने में सक्षम बनाएगी।
इस सहयोग का उद्देश्य नोकिया फीचर फोन उपयोगकर्ताओं को नवीनतम तकनीक प्रदान करना है और सभी के लिए एक समावेशी डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

इडेमिया के बारे में:

मुख्यालय: कौरबेवोई, फ्रांस
CEO: पियरे बैरियल

एयरटेल पेमेंट्स बैंक के बारे में:

स्थापित: जनवरी 2017.
मुख्यालय: नई दिल्ली, दिल्ली
MD और CEO: अनुब्रत बिस्वास

HMD ग्लोबल के बारे में:

स्थापित: 1 दिसंबर 2016
मुख्यालय: एस्पो, फिनलैंड
कार्यकारी अध्यक्ष और CEO: जीन-फ्रेंकोइस बारिल

फोनपे स्मार्टस्पीकर्स ने अमिताभ बच्चन के साथ सेलिब्रिटी वॉयस फीचर पेश किया

PhonePe ने प्रतिष्ठित भारतीय अभिनेता अमिताभ बच्चन के सहयोग से अपने स्मार्टस्पीकर पर अपनी तरह का पहला सेलिब्रिटी वॉयस फीचर लॉन्च किया है।
यह नवोन्वेषी सुविधा भारत भर में PhonePe स्मार्टस्पीकरों को अमिताभ बच्चन की विशिष्ट आवाज का उपयोग करके ग्राहक भुगतान को मान्य करने में सक्षम बनाती है।
उद्योग की यह पहली सेलिब्रिटी वॉयस सुविधा वर्तमान में हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है, भविष्य में इसे अन्य भाषाओं के लिए रोल आउट करने की योजना है।

मुख्य विचार:

इन स्मार्टस्पीकरों ने एक साल पहले अपनी शुरुआत की थी और तब से इन्हें महत्वपूर्ण लोकप्रियता हासिल हुई है।
वर्तमान में, देश के 90% से अधिक हिस्से को कवर करते हुए, 19,000 पोस्टल कोड में फैले 4 मिलियन डिवाइस व्यापारी भागीदारों द्वारा उपयोग में हैं।
अमिताभ बच्चन की विशेषता वाली एक सेलिब्रिटी आवाज के शामिल होने से व्यापारियों और ग्राहकों दोनों के लिए भुगतान अनुभव बेहतर हो जाएगा, जिससे यह पहले से कहीं अधिक इंटरैक्टिव हो जाएगा।

फ़ोनपे के बारे में:

स्थापित: 2015
मुख्यालय: बेंगलुरु, कर्नाटक, भारत
CEO: समीर निगम

भारतीय स्टेट बैंक ने डिजिटल किराया भुगतान के लिए 'नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड' पेश किया

भारतीय स्टेट बैंक, देश के सबसे बड़े बैंक ने आवागमन के अनुभवों को बढ़ाने और डिजिटल भुगतान अपनाने को बढ़ावा देने के प्राथमिक लक्ष्य के साथ 'नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड' पेश किया है।

उद्देश्य:

महानगरों, बसों, वॉटर फ़ेरी, पार्किंग सुविधाओं और अन्य सहित परिवहन के कई तरीकों में एक ही कार्ड के भीतर डिजिटल टिकट किराया भुगतान को सरल बनाना।
परिवहन के अलावा, 'नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड' का उपयोग खुदरा और ई-कॉमर्स लेनदेन के लिए भी किया जा सकता है, जो उपयोगकर्ताओं को सुविधाजनक और बहुमुखी भुगतान समाधान प्रदान करता है।

मुख्य विचार:

'नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड' RuPay और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) तकनीक द्वारा संचालित है, जो इसे लाखों भारतीयों के लिए उनके दैनिक आवागमन में एक संभावित गेम-चेंजर बनाता है।
SBI MMRC मेट्रो लाइन 3 और आगरा मेट्रो जैसी प्रमुख मेट्रो लाइनों में NCMC-आधारित टिकटिंग समाधान लागू करने की प्रक्रिया में भी है, जिससे इस सुविधाजनक भुगतान पद्धति की पहुंच का और विस्तार हो सके।

NCMC क्या है?

NCMC की सिफारिश नंदन नीलेकणि समिति ने की थी, जिसका गठन भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा किया गया था

उद्देश्य:

नकदी रहित लेनदेन को बढ़ावा देना और परिवहन के विभिन्न तरीकों में यात्री भुगतान के एकीकरण की सुविधा प्रदान करना।
NCMC को आधिकारिक तौर पर 4 मार्च, 2019 को लॉन्च किया गया था।

यह RuPay प्लेटफ़ॉर्म पर संचालित होता है, जिसे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया (NPCI) द्वारा विकसित किया गया है।
NCMC एक व्यापक संपर्क रहित परिवहन समाधान प्रदान करता है, जो महानगरों, बसों और उपनगरीय रेलवे के लिए एक स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली के रूप में कार्य करता है।

नवीनतम समाचार:

अगस्त 2023 में, SBI कार्ड ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए अल्पकालिक क्रेडिट विकल्पों और अन्य विशेष लाभों की पेशकश के साथ 'सिंपलीसेव मर्चेंट SBI कार्ड' लॉन्च किया।

SBI के बारे में:

स्थापना: 1 जुलाई 1955
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र, भारत
अध्यक्ष: दिनेश कुमार खरा
CFO: कामेश्वर राव कोदावंती

बैंक ऑफ बड़ौदा ने देशभर में 6,000 से अधिक ATM पर UPI ATM सुविधा शुरू की

बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) ने देश भर में अपने ATM पर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) -ऑटोमेटेड टेलर मशीन (ATM) सुविधा सक्षम कर दी है, यह नई सुविधा ग्राहकों को डेबिट या क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता के बिना ATM से नकदी निकालने की अनुमति देगी।
BoB को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के सहयोग से और NCR कॉरपोरेशन द्वारा संचालित UPI ATM लॉन्च करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र बैंक माना जाता है।

मुख्य विचार:

बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक और भाग लेने वाले जारीकर्ता बैंकों के ग्राहक जो किसी भी UPI-सक्षम मोबाइल ऐप का उपयोग करते हैं, वे अपने डेबिट कार्ड की आवश्यकता के बिना नकदी निकालने के लिए UPI ATM सेवा का उपयोग कर सकते हैं।
UPI ATM सेवा इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विदड्रॉल (ICCW) तकनीक का उपयोग करती है, जो ATM के माध्यम से कार्डलेस कैश निकासी की सुविधा प्रदान करती है।
यह नवाचार QR-आधारित नकद निकासी को सक्षम बनाता है, जिससे भौतिक कार्ड की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

UPI-ATM ICCW सेवा की मुख्य विशेषताएं:

अंतर-संचालित: यह सेवा इंटरऑपरेबल है, जिसका अर्थ है कि इसका उपयोग कई बैंकों में किया जा सकता है।
कार्ड-रहित लेनदेन: यह कार्ड-रहित लेनदेन की अनुमति देता है, सुरक्षा और सुविधा बढ़ाता है।
लेन-देन की सीमा: ग्राहक रुपये तक निकाल सकते हैं. प्रति लेनदेन 10,000, और यह राशि दैनिक UPI सीमा और जारीकर्ता बैंक द्वारा UPI-ATM लेनदेन के लिए निर्धारित सीमाओं के अधीन है।
सुविधा: यह सेवा ATM से नकद निकासी के लिए भौतिक कार्ड ले जाने की आवश्यकता को समाप्त कर देती है।
एकाधिक खाता पहुंच: ग्राहक अपने UPI मोबाइल ऐप का उपयोग करके कई खातों से नकदी निकाल सकते हैं।
UPI ATM लेनदेन भी तेज, सुविधाजनक और सुरक्षित हैं क्योंकि वे प्रत्येक लेनदेन के लिए एकल-उपयोग गतिशील QR कोड उत्पन्न करते हैं और एक सुरक्षित बैंकिंग अनुभव सुनिश्चित करते हैं।

नवीनतम समाचार:

अगस्त 2023 में, जापान स्थित हिताची लिमिटेड की 100% सहायक कंपनी हिताची पेमेंट सर्विसेज ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के सहयोग से भारत की पहली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) -ऑटोमेटेड टेलर मशीन (ATM) लॉन्च की।

BOB के बारे में:

स्थापना: 20 जुलाई 1908
मुख्यालय: वडोदरा, गुजरात, भारत

MD और CEO: देबदत्त चंद
टैगलाइन: इंडियास इंटरनेशनल बैंक

एक्सिस बैंक ने 'ओपन एक्सपीरियंस' नाम से अपना क्रेडिट कार्ड अभियान लॉन्च किया

ऐक्सिस बैंक भारत में निजी क्षेत्र के एक प्रमुख बैंक ने 'ओपन एक्सपीरियंस' शीर्षक से अपने क्रेडिट कार्ड अभियान का अनावरण किया है।
यह अभियान समकालीन समय में 'अनुभव' की अवधारणा में एक उल्लेखनीय बदलाव को पहचानता है।
यह स्वीकार करता है कि आज के उपभोक्ता केवल भौतिक लाभ से अधिक की तलाश में हैं और सार्थक अनुभव की तलाश में हैं।

मुख्य विचार:

ओपन एक्सपीरियंस' एक्सिस बैंक के पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं से परे जाकर ऐसे अनुभव प्रदान करने के मूल लोकाचार के साथ संरेखित है जो आधुनिक उपभोक्ता की आकांक्षाओं के साथ गहराई से मेल खाते हैं।
यह अभियान कार्डधारकों को असाधारण लाभ और अद्वितीय अनुभव प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई क्रेडिट कार्ड पेशकशों की एक श्रृंखला पेश करता है।
लोव लिंटास द्वारा विकसित, अभियान संचार के लिए प्राथमिक माध्यम के रूप में टेलीविजन के साथ एक मल्टी-चैनल रणनीति का उपयोग करता है।
इसे रणनीतिक आउटडोर विज्ञापन प्लेसमेंट के माध्यम से और बढ़ाया गया है।
इस अभियान के माध्यम से एक्सिस को एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए एक मजबूत प्राथमिकता और इच्छा पैदा करने और इस 'अनुभव' पीढ़ी के लिए प्रासंगिक बने रहने की उम्मीद है।

नवीनतम समाचार:

अगस्त 2023 में, भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंकों में से एक एक्सिस बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (RBIH) द्वारा पेश किए गए सार्वजनिक तकनीकी प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट (PTPFC) द्वारा संचालित 2 उधार उत्पाद, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) और असुरक्षित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) ऋण लॉन्च किए हैं।

एक्सिस बैंक के बारे में:

स्थापना: 3 दिसंबर 1993
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र, भारत
MD एवं CEO: अमिताभ चौधरी
टैगलाइन: बढ़ती का नाम जिंदगी

वैश्विक व्यापार वित्त अंतर 2022 में 2.5 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ गया -ADB सर्वेक्षण

एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) ने अपना 2023 ट्रेड फाइनेंस गैप्स, ग्रोथ और जॉब्स सर्वे जारी किया, जिससे पता चला कि वैश्विक व्यापार वित्त गैप 2022 में अभूतपूर्व रूप से $2.5 ट्रिलियन तक बढ़ गया, जबकि दो साल पहले यह $1.7 ट्रिलियन था।
यह अंतर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए वित्तपोषण अनुरोधों और दी गई वास्तविक स्वीकृतियों के बीच असमानता को दर्शाता है।

अंतर के पीछे के कारक:

व्यापार वित्त अंतर में इस पर्याप्त वृद्धि में कई कारकों ने योगदान दिया, जिनमें बढ़ती ब्याज दरें, आर्थिक अनिश्चितताएं, मुद्रास्फीति और भू-राजनीतिक अस्थिरता शामिल हैं।
इन स्थितियों ने बैंकों की व्यापार वित्तपोषण प्रदान करने की क्षमता को कम कर दिया।
कोविड के बाद निर्यात वृद्धि: सर्वेक्षण में कहा गया है कि COVID-19 महामारी के बाद, वैश्विक वस्तुओं के निर्यात में पर्याप्त वृद्धि देखी गई, 2021 में 26.6% और 2022 में 11.5% की वृद्धि हुई।

निर्यात में इस वृद्धि के कारण व्यापार वित्त की मांग में वृद्धि हुई।
वित्त पोषण में चुनौतियाँ: निर्यात मांग में वृद्धि के बावजूद, सर्वेक्षण में पाया गया कि बढ़े हुए आर्थिक जोखिमों ने व्यापार वित्त को सुरक्षित करना अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया है, जिससे एक महत्वपूर्ण व्यापार वित्त अंतर पैदा हो गया है।
वैश्विक व्यापार में गिरावट: अप्रैल 2023 तक, मूल्य के संदर्भ में, वैश्विक व्यापार निर्यात में साल-दर-साल मंदी का अनुभव हुआ, 2022 की आखिरी तिमाही में शून्य-विकास दर के बाद लगभग 3% की गिरावट दर्ज की गई।
सर्वेक्षण को वैश्विक स्तर पर व्यापार वित्त स्वास्थ्य का प्रमुख संकेतक माना जाता है।
इसमें लगभग 50 देशों के 137 बैंकों और 185 कंपनियों का डेटा शामिल है।

मुख्य विचार:

व्यापार वित्त अंतर पिछले वर्ष की तुलना में 47% बढ़ गया जब यह 1.7 ट्रिलियन डॉलर था।
यह मुद्दे की भयावहता को रेखांकित करता है, विशेष रूप से यह देखते हुए कि लगभग 80% वैश्विक व्यापार किसी न किसी प्रकार के वित्तपोषण पर निर्भर करता है।
सर्वेक्षण से पता चला कि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण जैसी भू-राजनीतिक घटनाओं का व्यापार वित्त पोर्टफोलियो पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, 60% बैंकों ने उल्लेखनीय प्रभाव की सूचना दी।
ESG और डिजिटलीकरण पर ध्यान दें: पहली बार, 2023 के सर्वेक्षण में आपूर्ति श्रृंखलाओं और व्यापार वित्त अंतर पर उनके प्रभाव का आकलन करने के लिए पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) मुद्दों और डिजिटलीकरण की जांच की गई।
कई उत्तरदाताओं का मानना था कि ESG संरेखण में व्यापार वित्तपोषण अंतर को कम करने की क्षमता थी।
ADB का व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला वित्त कार्यक्रम (TSCFP): ADB, अपनी एएए क्रेडिट रेटिंग के साथ, व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला वित्त कार्यक्रम (TSCFP) संचालित करता है, जो 200 से अधिक भागीदार बैंकों को ऋण और गारंटी प्रदान करता है।
यह कार्यक्रम आयात और निर्यात को बढ़ाकर, आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर और उन बाजारों को लक्षित करके व्यापार का समर्थन करता है जहां निजी क्षेत्र चुनौतियों का सामना करता है।
2009 के बाद से, TSCFP ने उन बाजारों में 45,510 लेनदेन में 57 बिलियन डॉलर के व्यापार की सुविधा प्रदान की है, जो आमतौर पर निजी क्षेत्र के लिए चुनौतीपूर्ण होते हैं।
TSCFP हरित, लचीला, समावेशी और सामाजिक रूप से जिम्मेदार वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है।

नवीनतम समाचार:

अगस्त, 2023 में, भारत एशियाई विकास बैंक (ADB) के साथ साझेदारी में नई दिल्ली में एक जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए तैयार है।

ADB के बारे में:

स्थापना: 1966
मुख्यालय: मनीला, फिलीपींस
राष्ट्रपति: मासात्सुगु असकावा
सदस्यता: 68 सदस्य, जिनमें 49 क्षेत्रीय सदस्य (एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देश) और 19 गैर-क्षेत्रीय सदस्य (क्षेत्र के बाहर के देश) शामिल हैं।

HDFC बैंक ने डिजिटल उपभोक्ता ऋण को सरल बनाने के लिए 'कार्डलेस EGEMI की शुरुआत की

HDFC बैंक एंड-टू-एंड डिजिटल उपभोक्ता ऋण - 'कार्डलेस EGEMI की पेशकश करने के लिए फिनटेक शॉपसे के साथ साझेदारी की है।
'कार्डलेस EGEMI कार्यक्रम उपभोक्ता ऋण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है, जिससे भौतिक दस्तावेजों या व्यापक सहायता की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

मुख्य विचार:

ग्राहक भाग लेने वाले शॉपसे या बैंक व्यापारी स्थानों पर QR कोड स्कैन करके आसानी से अपनी खरीद को समान मासिक किस्तों (EMI) में परिवर्तित कर सकते हैं।
विभिन्न ब्रांडों और व्यापारियों के साथ यह एकीकरण सुनिश्चित करता है कि ग्राहक तेजी से क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं, आमतौर पर 5 मिनट के भीतर।
मौजूदा HDFC बैंक ग्राहकों को 'कार्डलेस EGEMI कार्यक्रम के हिस्से के रूप में पूर्व-अनुमोदित ऋण प्रस्ताव प्राप्त होंगे।
नए ग्राहक पहचान के रूप में अपने पैन कार्ड और मोबाइल नंबर का उपयोग करके 12 महीने की पुनर्भुगतान अवधि के साथ 60,000 रुपये तक का तत्काल उपभोक्ता टिकाऊ ऋण सुरक्षित कर सकते हैं।
शॉपसे इंडिया के CEO: पल्लव जैन

HDFC बैंक के बारे में:

स्थापित: 1 जुलाई 2023 (HDFC-HDFC बैंक के बीच विलय के माध्यम से)
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र, भारत
MD एवं CEO: शशिधर जगदीशन
टैगलाइन: वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों (HNI) और महिलाओं के लिए दो विशिष्ट डेबिट कार्ड पेश किए

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (UBI) ने दो नए डेबिट कार्ड वेरिएंट पेश किए हैं - एक मेटल कार्ड जो अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स (HNI) के लिए तैयार किया गया है और दूसरा कार्ड महिलाओं के लिए विशेष लाभ वाला है।
ये दोनों नए शुरू किए गए डेबिट कार्ड भारत में घरेलू भुगतान नेटवर्क RuPay नेटवर्क पर जारी किए गए हैं।
इन दो डेबिट कार्ड का शुभारंभ मुंबई, महाराष्ट्र में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO, ए. मणिमेखलाई और NPCI (नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) की मुख्य परिचालन अधिकारी प्रवीणा राय की भागीदारी के साथ हुआ।

अल्ट्रा HNI मेटल कार्ड के बारे में:

अल्ट्रा HNI मेटल कार्ड में एक विशिष्ट धातु डिज़ाइन है।
अपने प्रीमियम लुक के अलावा, इसमें कई लाभ भी शामिल हैं
बीमा कवरेज।
ओवर-द-टॉप (OTT) चैनलों की सदस्यता।
अंतरराष्ट्रीय लाउंज तक पहुंच
व्यापारी-विशिष्ट छूट
कार्ड नियर फील्ड कम्युनिकेशन (NFC) तकनीक से लैस है, जो ट्रांजिट सेवाओं के लिए टैप-एंड-पे सहित संपर्क रहित भुगतान को सक्षम बनाता है।

महिला कार्ड (RuPay प्लैटिनम) के बारे में:

रुपे प्लेटिनम कार्ड के रूप में वर्गीकृत महिला कार्ड, कई प्रकार के लाभ प्रदान करता है, जिनमें शामिल हैं:
स्तन, डिम्बग्रंथि और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के लिए निःशुल्क कैंसर देखभाल कवरेज।
नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच।
यह कार्ड महिलाओं को मूल्यवान स्वास्थ्य संबंधी कवरेज प्रदान करके सशक्त बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में:

स्थापना: 1919
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र
CEO: ए मणिमेखलाई
टैगलाइन: गुड पीपल टू बैंक विथ

एक्सिस बैंक ने अग्रणी इलेक्ट्रॉनिक ऑडिट बैलेंस कन्फर्मेशन प्लेटफॉर्म कन्फर्मेशन के साथ साझेदारी की है

ऐक्सिस बैंक भारत में एक अग्रणी निजी क्षेत्र के बैंक ने कन्फर्मेशन के साथ एक रणनीतिक गठबंधन बनाया है, जिसे दुनिया के अग्रणी इलेक्ट्रॉनिक ऑडिट बैलेंस कन्फर्मेशन प्लेटफॉर्म के रूप में मान्यता प्राप्त है।

साझेदारी के बारे में:

इस साझेदारी के माध्यम से, एक्सिस बैंक ऑडिटर्स के बैलेंस कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट (बीसीसी) भेजने और प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीकों को अपनाएगा।

यह बदलाव कागज-आधारित प्रक्रियाओं की आवश्यकता को समाप्त कर देता है।

इलेक्ट्रॉनिक पुष्टिकरण में परिवर्तन एक्सिस बैंक को ग्राहक के हस्तक्षेप की आवश्यकता के बिना लेखापरीक्षकों के पुष्टिकरण अनुरोधों का तुरंत जवाब देने का अधिकार देता है।

यह भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय ऑडिटिंग मानकों के अनुरूप है, जिससे दक्षता और अनुपालन बढ़ता है।

कन्फर्मेशन के साथ एक्सिस बैंक का एकीकरण इसे एक विशाल वैश्विक नेटवर्क से जोड़ता है जिसमें 170 देशों में फैली 16,000 से अधिक ऑडिट फर्मों के साथ 4,200 से अधिक बैंक और विभाग शामिल हैं।

यह नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक ऑडिट बैलेंस पुष्टिकरण प्रमाणपत्रों के सुरक्षित आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करता है।

RBI ने वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात (I-CRR) को खत्म करने की योजना बनाई है

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात (I-CRR) को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का निर्णय लिया है।

एक सुचारू संक्रमण सुनिश्चित करने और सिस्टम तरलता और मुद्रा बाजार के कामकाज में व्यवधान को रोकने के लिए, RBI ने 3 चरणों में I-CRR फंड जारी करने का समय निर्धारित किया है: 9 सितंबर को 25%, 23 सितंबर, 2023 को 25% और 7 अक्टूबर, 2023 को शेष 50%।

इस चरणबद्ध रिलीज़ का उद्देश्य विशेष रूप से आगामी त्योहारी सीज़न के दौरान ऋण मांग को पूरा करने के लिए बैंकों की क्षमता को बढ़ाना है।

I-CRR से संबंधित निर्णय का नकद आरक्षित अनुपात (CRR) पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो 4.5% पर बना हुआ है।

वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात (I-CRR) क्या है?

बैंकिंग प्रणाली में अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करने के लिए वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात (I-CRR) की शुरुआत की गई थी।

इस अतिरिक्त तरलता में योगदान देने वाले कारकों में 2,000 रुपये के नोटों की वापसी, RBI का सरकार को अधिशेष हस्तांतरण और सरकारी खर्च में वृद्धि शामिल थी।

मुख्य विचार:

I-CRR को हटाने के साथ, विशेषज्ञों का अनुमान है कि मुद्रा बाजार दरें नरम हो जाएंगी।

RBI ने बैंकों को 19 मई, 2023 और 28 जुलाई, 2023 के बीच अपनी जमा राशि (शुद्ध मांग और समय देनदारियों) में वृद्धि पर 10% का वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात (I-CRR) बनाए रखने का निर्देश दिया था।

RBI के उपायों के कारण, 22 अगस्त, 2023 को चालू वित्तीय वर्ष में पहली बार भारत की बैंकिंग प्रणाली में तरलता घाटे में स्थानांतरित हो गई।

हालाँकि, 6 सितंबर, 2023 तक बैंकिंग प्रणाली में 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक की तरलता अधिशेष थी।

RBI के बारे में:

स्थापना: 1 अप्रैल 1935

मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र, भारत

राज्यपाल: शक्तिकांत दास

उप राज्यपाल: स्वामीनाथन जानकीरमन, माइकल पात्रा,एम. राजेश्वर राव, टी रबी शंकर

HSBC इंडिया ने कॉर्पोरेट सेवा पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए 'ONDC इन ए बॉक्स' पेश किया

हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत या HSBC बैंक इंडिया ने मुंबई, महाराष्ट्र में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (GFF) 2023 के दौरान ONDC को निर्बाध रूप से सक्षम बनाने की दिशा में कॉरपोरेट्स के लिए वन-स्टॉप-शॉप प्रस्ताव, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ('ONDC) इन ए बॉक्स' लॉन्च किया है।
इस लॉन्च के साथ, HSBC इंडिया ONDC-सक्षम प्रस्ताव पेश करने वाला भारत का पहला विदेशी बैंक बन गया।

ONDC क्या है?

ONDC वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सहयोग से उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की एक पहल है।
इसका प्राथमिक उद्देश्य एक खुला और इंटरऑपरेबल नेटवर्क बनाना है जो खरीदारों और विक्रेताओं को दोनों पक्षों को एक ही मंच पर होने की आवश्यकता के बिना लेनदेन करने की अनुमति देता है।
ओएनडीसी विभिन्न उद्योगों में अपना प्रभाव बढ़ाते हुए, व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर समावेशिता, प्रतिस्पर्धात्मकता और खुलेपन को बढ़ावा देना चाहता है।

'ONDC इन ए बॉक्स' के बारे में:

HSBC इंडिया ने 'ONDC इन ए बॉक्स' प्रस्ताव के लिए इकोसिस्टम पार्टनर्स प्रोटीन ईगॉव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (प्रोटियन) और शायर ओमनीचैनल प्राइवेट लिमिटेड (आद्या) के साथ सहयोग किया है।
HSBC इंडिया के 'ONDC इन ए बॉक्स' प्रस्ताव में HSBC इंडिया द्वारा दी जाने वाली बैंकिंग सेवाएं शामिल हैं, जबकि सक्षमता के लिए आवश्यक ONDC मॉड्यूल प्रदान किए गए हैं।
बॉक्स में ONDC कॉर्पोरेट ग्राहकों को न केवल HSBC इंडिया द्वारा प्रदान किए गए भुगतान और निपटान टूलकिट के साथ बल्कि ONDC सक्षमता के लिए आवश्यक आवश्यक प्रौद्योगिकी स्टैक के साथ भी सशक्त बनाता है।

HSBC इंडिया के बारे में:

स्थापना: 1959
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र
CEO: हितेन्द्र दवे
यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत एक विदेशी बैंक है और इस प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा विनियमित है।

ONDC के बारे में:

CEO: टी कोशी
ONDC, एक निजी गैर-लाभकारी धारा 8 कंपनी है जिसे भारत सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा खुले ई-कॉमर्स को विकसित करने के लिए स्थापित किया गया है।

प्रोटीन के बारे में:

स्थापना: 1995
मुख्यालय: मुंबई, महरा
MD और CEO: सुरेश सेठी

स्पाइस मनी और विम्बो के पेयू सहयोग ने ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के लिए 'स्पाइस पे UPI समाधान' पेश किया

स्पाइस मनी, उभरते भारत के लिए 'नैनो प्रेन्योर्स' बनाने वाली फिनटेक कंपनी डिजीस्पाइस टेक्नोलॉजीज की सहायक कंपनी ने ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक अभिनव UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) समाधान 'स्पाइस पे' पेश करने के लिए पेयू के तहत एक कंपनी विम्बो के साथ साझेदारी की है।

स्पाइस मनी और विंबो के बीच यह सहयोग ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करने पर केंद्रित है, जिसमें तत्काल प्रीपेड कार्ड, वॉलेट इंटरऑपरेबिलिटी के लिए लिंक किए गए UPI ID और मोबाइल नंबर सीडिंग की चुनौती से निपटने के लिए eKYC (इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर) समाधान शामिल हैं।

उद्देश्य:

भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) की क्षमताओं का विस्तार करके डिजिटल विभाजन को पाटना, डिजिटल लेनदेन को और अधिक सुलभ बनाना।

मुख्य विचार:

2022 में, भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो कुल 759 मिलियन तक पहुंच गई।
इसमें से 420 मिलियन निवास करते थेशहरी क्षेत्रों में, जबकि 339 मिलियन ग्रामीण क्षेत्रों में थे।
2025 तक भारत में कुल 900 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ता होने की उम्मीद है।
ग्रामीण भारत के महत्वपूर्ण योगदान का अनुमान है, सभी नए इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में से 56% इन क्षेत्रों से उभर रहे हैं।
हालाँकि, ग्रामीण क्षेत्रों को अद्वितीय बुनियादी ढाँचे की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो UPI को अपनाने में बाधा बनती हैं।
निष्क्रिय या निष्क्रिय बैंक खातों के साथ चुनौतियों का सामना करने वाले व्यक्तियों के लिए, स्पाइस मनी एक लिंक किए गए यूपीआई आईडी के साथ एक स्टैंडअलोन प्रीपेड वॉलेट खाता पेश करेगा।
यह नवाचार पारंपरिक बैंक खातों की आवश्यकता को समाप्त करता है, जिससे डिजिटल वित्तीय सेवाएं अधिक सुलभ हो जाती हैं।
स्पाइस मनी के सह-संस्थापक, कार्यकारी निदेशक और सीईओ: संजीव कुमार।
विब्मो के CEO: सुरेश राजगोपालन

RBI ने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में I-प्रोसेस सर्विसेज स्थापित करने के ICICI बैंक के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी

ICICI बैंक बैंक की नवीनतम नियामक फाइलिंग के अनुसार, कुछ शर्तों के अधीन, आई-प्रोसेस सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (आई-प्रोसेस) को अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से मंजूरी मिल गई है।

आई-प्रोसेस के बारे में:

आई-प्रोसेस की स्थापना 2005 में भारत के कुछ प्रमुख वित्तीय संस्थानों के लिए स्टाफिंग समाधान सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
आई-प्रोसेस में 25,000 से अधिक व्यक्तियों की कर्मचारी क्षमता है और पूरे भारत में लगभग 500 स्थानों पर इसकी उपस्थिति है।
आई-प्रोसेस के अधिग्रहण की कुल लागत 15.40 करोड़ रुपये आंकी गई है।
यह राशि लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार और आवश्यक अनुमोदन प्राप्त होने पर मूल्य निर्धारण को अंतिम रूप देने के अधीन है।
ICICI बैंक के पास वर्तमान में iProcess में 19% हिस्सेदारी है।

ICICI बैंक के बारे में:

स्थापना: 5 जनवरी 1994
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र, भारत
MD एवं CEO: संदीप बख्शी

सेबी ने NYMEX WTI कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस वायदा अनुबंधों पर NSE के विकल्प लॉन्च को मंजूरी दे दी

भारत के अग्रणी एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से अपने कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट के भीतर NYMEX WTI कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस वायदा अनुबंधों के लिए वायदा पर विकल्प पेश करने की मंजूरी मिल गई है।
15 मई, 2023 को, NSE ने पहले अपने कमोडिटी डेरिवेटिव्स सेक्शन में रुपये-मूल्य वाले NYMEX WTI कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस वायदा अनुबंध लॉन्च किए थे।

मुख्य विचार:

प्रारंभिक लॉन्च के बाद से विभिन्न क्षेत्रों के 100 से अधिक व्यापारिक सदस्य इन अनुबंधों से जुड़े लेनदेन में लगे हुए हैं।
वायदा अनुबंधों पर विकल्पों को शामिल करना व्यापक कमोडिटी सेगमेंट में NSE के उत्पाद प्रसाद के एक महत्वपूर्ण विस्तार का प्रतिनिधित्व करता है।
इन अनुबंधों को निगमों, मूल्य श्रृंखला प्रतिभागियों और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI की विभिन्न श्रेणियों जैसे व्यक्तियों, कॉर्पोरेट और पारिवारिक कार्यालयों सहित) सहित बाजार सहभागियों को उनके कमोडिटी-संबंधित जोखिम के प्रबंधन के लिए अधिक कुशल उपकरण प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

NSE के बारे में:

स्थापित: 1992
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र, भारत
अध्यक्ष: गिरीश चंद्र चतुर्वेदी
MD और CEO: आशीषकुमार चौहान
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड भारत के अग्रणी स्टॉक एक्सचेंजों में से एक है।
NSE विभिन्न वित्तीय संस्थानों जैसे बैंकों और बीमा कंपनियों के स्वामित्व में है।

सेबी के बारे में:

स्थापना: 12 अप्रैल 1988 एक कार्यकारी निकाय के रूप में और सेबी अधिनियम, 1992 के माध्यम से 30 जनवरी 1992 को वैधानिक शक्तियां दी गईं
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र
अध्यक्ष: माधबी पुरी बुच (सेबी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला)
SEBI भारत में प्रतिभूति और कमोडिटी बाजारों के लिए नियामक निकाय है जो वित्त मंत्रालय (MoF), भारत सरकार के स्वामित्व के तहत है।

थॉमस कुक इंडिया ने RuPay फॉरेक्स कार्ड लॉन्च करने के लिए NPCI के साथ सहयोग किया

थॉमस कुक (इंडिया) लिमिटेड UAE जाने वाले भारतीय यात्रियों के लिए रुपे प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड लॉन्च करने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा के बाद इसके शेयरों में 5% की बढ़ोतरी देखी गई।
परिचयथॉमस कुक रुपे कार्ड शुरुआत में यूएई बाजार को लक्षित कर रहा है।
यह कदम भारत से विशेष रूप से संयुक्त अरब अमीरात जैसे छोटी दूरी के गंतव्यों के लिए आउटबाउंड यात्रा की बढ़ती प्रवृत्ति के अनुरूप है।
यह सहयोग NPCI प्रमाणित भागीदार CARD91 की सहायता से संभव हुआ है।
यह विदेश यात्रा करने वाले भारतीय यात्रियों के लिए भारत की "मेड इन इंडिया" पहल के साथ संरेखित करते हुए, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान समाधान प्रदान करने के लिए NPCI के वैश्विक कार्ड भुगतान नेटवर्क का लाभ उठाता है।

थॉमस कुक (इंडिया) लिमिटेड के बारे में:

स्थापना: 1881
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र, भारत
MD और CEO: महेश अय्यर

थॉमस कुक लिमिटेड एक भारतीय ट्रैवल एजेंसी है, जो विदेशी मुद्रा, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू छुट्टियां, वीजा, पासपोर्ट, यात्रा बीमा और MICE सहित यात्रा सेवाएं प्रदान करती है।

भारती एक्सा लाइफ ने बेहतर सुरक्षा के साथ बीमा को सुव्यवस्थित करने के लिए "इनकम लाभ" लॉन्च किया

भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस बीमा को सरल बनाने और ग्राहकों को अधिकतम सुरक्षा प्रदान करने के लक्ष्य के साथ "भारती एक्सा लाइफ इनकम लाभ" नामक एक नया बीमा उत्पाद पेश किया है।
यह योजना पॉलिसीधारकों को वित्तीय सुरक्षा और निरंतर आय प्रवाह दोनों प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है।

भारती एक्सा लाइफ इनकम लाभ के बारे में:

भारती एक्सा लाइफ इनकम लाभ एक गैर-लिंक्ड, गैर-भागीदारी वाली व्यक्तिगत बचत योजना है जिसमें जीवन बीमा कवरेज शामिल है।
जो ग्राहक इस योजना का विकल्प चुनते हैं, वे चुनी हुई पॉलिसी अवधि के आधार पर 10 से 12 साल की अवधि के लिए गारंटीकृत आय की एक स्थिर धारा की उम्मीद कर सकते हैं।
प्रारंभ में, आय भुगतान भुगतान किए गए वार्षिक प्रीमियम का 100% निर्धारित किया गया है। 5 साल के बाद (10 साल की पॉलिसी अवधि के लिए), यह भुगतान बढ़कर 150% हो जाता है।
12 साल की पॉलिसी अवधि के लिए, 6 साल के बाद, आय भुगतान 200% तक बढ़ जाता है।
नियमित आय भुगतान के अलावा, पॉलिसीधारक या नामांकित व्यक्ति को आय अवधि के अंतिम वर्ष में एक गारंटीकृत एकमुश्त राशि प्राप्त होती है। इसका उपयोग महत्वपूर्ण जीवन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है।
इस उत्पाद का प्राथमिक उद्देश्य पॉलिसीधारकों और उनके परिवारों की वित्तीय भलाई को बढ़ाना है।

भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के बारे में:

मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र
MD और CEO: पराग राजा
भारती एक्सा लाइफ इंश्योरेंस भारती एंटरप्राइजेज (51%) और फ्रांसीसी बीमा कंपनी एक्सा (49%) के बीच एक संयुक्त उद्यम (जेवी) है।

RBI को अक्टूबर 2023 तक कॉल मनी मार्केट में डिजिटल रुपया पायलट शुरू करने की उम्मीद है

भारतीय रिज़र्व बैंक का (RBI) के कार्यकारी निदेशक अजय कुमार चौधरी ने घोषणा की कि RBI अक्टूबर 2023 तक इंटरबैंक उधार या कॉल मनी मार्केट में लेनदेन के लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) का पायलट लॉन्च करने की संभावना है।
थोक CBDC के लिए एक पायलट, जिसे डिजिटल रुपया-थोक (EW) के रूप में जाना जाता है, नवंबर 2022 में शुरू किया गया था।
खुदरा CBDC के लिए पायलट 1 दिसंबर, 2022 को शुरू किया गया था।
प्रारंभ में, इसका उपयोग सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाज़ार लेनदेन के निपटान के लिए किया जाता था।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2022-23 में CBDC की शुरूआत की घोषणा की गई थी और वित्त विधेयक 2022 के पारित होने के साथ RBI अधिनियम, 1934 की संबंधित धारा में आवश्यक संशोधन किए गए थे।
भाग लेने वाले बैंक: थोक CBDC पायलट परियोजना के लिए RBI द्वारा नौ बैंकों का चयन किया गया था, जिनमें भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और HSBC शामिल हैं।
डिजिटल रुपया (ER) एक डिजिटल टोकन के रूप में है जो कानूनी निविदा का प्रतिनिधित्व करता है और कागजी मुद्रा और सिक्कों के समान मूल्यवर्ग में जारी किया जाता है।
ER को बैंकों जैसे वित्तीय मध्यस्थों के माध्यम से वितरित किया जाता है, और उपयोगकर्ता भाग लेने वाले बैंकों द्वारा पेश किए गए डिजिटल वॉलेट के माध्यम से इसके साथ लेनदेन कर सकते हैं।
G20 शिखर सम्मेलन के दौरान RBI प्रदर्शनी मंडप में वित्तीय क्षेत्र में विभिन्न डिजिटल पहलों का प्रदर्शन कर रहा है।

इनमें फ्रिक्शनलेस क्रेडिट के लिए पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म (PTP), CBDC, UPI वन वर्ल्ड, रुपे ऑन-द-गो और शामिल हैं।

कॉल मनी क्या है?

कॉल मनी, जिसे "मनी एट कॉल" के रूप में भी जाना जाता है, एक अल्पकालिक ऋण है जिसे ऋणदाता द्वारा मांगे जाने पर तुरंत पूरा भुगतान करना होता है।
इसमें भुगतान और परिपक्वता का कोई निर्धारित कार्यक्रम नहीं है, और पुनर्भुगतान के लिए पूर्व सूचना की आवश्यकता नहीं है।
इसके अलावा, कॉल मनी के ऋणदाता को पुनर्भुगतान के बारे में उधारकर्ता को पूर्व सूचना देने की आवश्यकता नहीं है।

इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट क्या है?

इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट हैएक अल्पकालिक मुद्रा बाजार जो बड़े वित्तीय संस्थानों को अंतरबैंक दरों पर पैसा उधार लेने और उधार देने की अनुमति देता है, ब्याज की दर जो बैंक एक दूसरे से धन उधार लेने पर लेते हैं।
कॉल मनी मार्केट में ऋण बहुत कम होते हैं, आमतौर पर एक सप्ताह से अधिक नहीं चलते हैं।
इन ऋणों का उपयोग अक्सर बैंकों को आरक्षित आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करने के लिए किया जाता है।
इसका उपयोग विशेष रूप से बैंकों द्वारा नहीं किया जाता है।
इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट ग्राहकों में अन्य वित्तीय संस्थान, म्यूचुअल फंड, बड़े निगम और बीमा कंपनियां शामिल हो सकती हैं।

RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने फिनटेक कंपनियों से स्व-नियामक संगठन (SRO) स्थापित करने का आग्रह किया

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) गवर्नर शक्तिकांत दास ने फिनटेक संस्थाओं से एक स्व-नियामक संगठन (SRO) स्थापित करने का आग्रह किया है।
SRO के रूप में मान्यता प्राप्त करने में रुचि रखने वाली फिनटेक संस्थाओं को RBI के पास आवेदन करना होगा।
RBI उपयुक्त संस्थाओं को मान्यता पत्र जारी करेगा।

वित्तीय प्रौद्योगिकी क्या है?

फिनटेक, वित्तीय प्रौद्योगिकी का संक्षिप्त रूप है, इसमें सॉफ्टवेयर, मोबाइल एप्लिकेशन और व्यवसायों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए पारंपरिक वित्तीय सेवाओं को बढ़ाने और स्वचालित करने के लिए डिज़ाइन की गई विभिन्न प्रौद्योगिकियां शामिल हैं।
फिनटेक में मोबाइल भुगतान ऐप्स से लेकर एन्क्रिप्टेड लेनदेन वाले जटिल ब्लॉकचेन नेटवर्क तक अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है।
फिनटेक कंपनियां मोबाइल बैंकिंग, पीयर-टू-पीयर भुगतान सेवाओं (जैसे, जीपे, फोनपे), स्वचालित पोर्टफोलियो प्रबंधन (जैसे, फिंटू, मोतीलाल ओसवाल), और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (जैसे, ज़ेरोधा, ग्रो) सहित वित्तीय सेवाओं को संशोधित, बढ़ाती या स्वचालित करती हैं।

फिनटेक कंपनियों से RBI की उम्मीदें:

उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाएँ: RBI को उम्मीद है कि फिनटेक कंपनियाँ स्थानीय कानूनों के अनुपालन में उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं, गोपनीयता और डेटा सुरक्षा मानदंडों को विकसित करेंगी।
नैतिक व्यावसायिक प्रथाएँ: फिनटेक फर्मों को नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं को बढ़ावा देना, मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और गलत बिक्री से बचना आवश्यक है।

स्व-नियामक संगठन (SRO) क्या है:

एक SRO एक गैर है-सरकारी संगठन (NGO) ग्राहकों की सुरक्षा और नैतिकता, समानता और व्यावसायिकता को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ एक विशिष्ट उद्योग के भीतर नियमों और मानकों को स्थापित करने और लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
SRO नियम और विनियम स्थापित करने के लिए उद्योग हितधारकों के साथ काम करते हैं।
वे स्व-नियामक प्रक्रियाओं को निष्पक्ष रूप से संचालित करते हैं, एक अनुशासित वातावरण सुनिश्चित करते हैं और आवश्यक होने पर दंड लगाते हैं।

SRO उन चिंताओं को संबोधित करते हैं जो उद्योग के संकीर्ण हितों से परे हैं, जैसे कि श्रमिकों, ग्राहकों और पारिस्थितिकी तंत्र में अन्य प्रतिभागियों की सुरक्षा।

SRO के कार्य:

संचार चैनल: मान्यता प्राप्त एसआरओ अपने सदस्यों (फिनटेक संस्थाओं) और RBI के बीच दोतरफा संचार चैनल के रूप में कार्य करता है।

मानक स्थापित करना: SRO अपने सदस्यों के बीच पेशेवर और नैतिक बाजार व्यवहार को बढ़ावा देने, न्यूनतम बेंचमार्क और मानक स्थापित करने के लिए काम करते हैं।

शिकायत निवारण: वे अपने सदस्यों के बीच मुद्दों के समाधान के लिए एक समान शिकायत निवारण और विवाद प्रबंधन ढांचे की स्थापना करते हैं।

RBI के बारे में:

स्थापना: 1 अप्रैल 1935

मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र, भारत

राज्यपाल: शक्तिकांत दास

उप राज्यपाल: स्वामीनाथन जानकीरमन, माइकल पात्रा,एम. राजेश्वर राव, टी रबी शंकर

कैशफ्री पेमेंट्स ने सदस्यता-आधारित व्यवसायों के लिए 'क्यूआर पर ऑटोपे' शुरू करने के लिए एनपीसीआई के साथ सहयोग किया है

कैशफ्री भुगतान भुगतान और API बैंकिंग समाधान क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी ने 'QR पर ऑटोपे' पेश करने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के साथ सहयोग किया है।

उद्देश्य:

ग्राहक अधिग्रहण, प्रतिधारण और समग्र विकास में सुधार के लिए सदस्यता-आधारित व्यवसायों का समर्थन करना।

मुख्य विचार:

कैशफ्री पेमेंट्स का 'ऑटोपे ऑन क्यूआर' सब्सक्रिप्शन व्यवसायों को दो क्लिक में जनादेश निर्माण प्रक्रिया को सरल बनाकर विज्ञापन व्यय पर निवेश पर अपनी वापसी (RoI) को बढ़ाने में सक्षम बनाता है।

सदस्यता-आधारित कंपनियां अपने सदस्यता QR कोड को ऑनलाइन विज्ञापनों, समाचार पत्रों, वेबसाइटों, टीवी और उत्पाद पैकेजिंग सहित विभिन्न विपणन चैनलों में सहजता से एकीकृत कर सकती हैं।

पारंपरिक, समय लेने वाली प्रक्रिया के बजाय जहां ग्राहकों को एक ऐप डाउनलोड करने, एक खाता स्थापित करने और एक योजना का चयन करने की आवश्यकता होती है, 'ऑटोपे ऑन QR' ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को दो-चरणीय वर्कफ़्लो में सुव्यवस्थित करता है जिसमें QR कोड स्कैनिंग और 30 सेकंड के भीतर UPI ऐप के माध्यम से ई-जनादेश अनुमोदन शामिल है।

इससे ग्राहकों के लिए ऐप डाउनलोड करने या वेबसाइट पर पंजीकरण करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, जिससे प्रत्येक ग्राहक के लिए एक अद्वितीय सदस्यता के त्वरित सक्रियण की अनुमति मिलती है।

कैशफ्री पेमेंट्स अपने उत्पादों को शक्ति प्रदान करने वाले मूलभूत भुगतान और बैंकिंग बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए बैंकों के साथ सहयोग करता है।

कैशफ्री पेमेंट्स को शॉपिफाई, विक्स, पेपाल, अमेज़ॅन पे, पेटीएम और गूगल पे सहित प्रमुख प्लेटफार्मों के साथ एकीकृत किया गया है, जो इसे व्यवसायों और ग्राहकों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए सुलभ बनाता है।

नवीनतम समाचार:

मई 2023 में, कैशफ्री पेमेंट्स और यस बैंक ने निर्यातकों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संग्रह सेवा 'ग्लोबल कलेक्शंस' की पेशकश करने के लिए साझेदारी की, जो यस बैंक के खाताधारक हैं।

कैशफ्री भुगतान के बारे में:

स्थापना: 2015

मुख्यालय: बैंगलोर, कर्नाटक
CEO और सह-संस्थापक: आकाश सिन्हा

NPCI के बारे में:

स्थापित: 2008
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र, भारत
MD और CEO: दिलीप अस्बे
NPCI भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक प्रमुख संगठन है।
यह भारत में एक मजबूत भुगतान और निपटान बुनियादी ढांचा बनाने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारतीय बैंक संघ (IBA) की एक पहल है।

मास्टरकार्ड, इन्वेस्ट इंडिया और पर्यटन मंत्रालय ने अपग्रेडेड Priceless.com का अनावरण किया

मास्टर कार्ड अनमोल भारत कार्यक्रम शुरू करने के लिए इन्वेस्ट इंडिया और पर्यटन मंत्रालय के साथ साझेदारी की है।
अनमोल भारत अभियान भारत की 'देखो अपना देश' पहल के अनुरूप है, जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का पता लगाने के लिए बढ़ावा देता है।
इस पहल का उद्देश्य दिल्ली, आगरा, जोधपुर, देहरादून और पुणे सहित विभिन्न शहरों में सावधानीपूर्वक तैयार किए गए सांस्कृतिक, पाक और कल्याण अनुभवों की पेशकश करके भारत के भीतर अनुभवात्मक यात्रा में क्रांति लाना है।
मास्टरकार्ड इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूट के ट्रैवल इंडस्ट्री ट्रेंड्स के 2023 के आंकड़ों के अनुसार, यात्रा अनुभवों पर उपभोक्ता खर्च में मार्च 2019 की तुलना में 65% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।
भारत में 'priceless.com' का पुन: लॉन्च मास्टरकार्ड के अपने कार्डधारकों को अद्वितीय और अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करने के वैश्विक प्रयास का हिस्सा है।

मास्टरकार्ड के बारे में:

स्थापना: 1966
मुख्यालय: न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका

इन्वेस्ट इंडिया के बारे में:

स्थापना: 2009
मुख्यालय: नई दिल्ली, दिल्ली
CEO: निवृत्ति राय
इन्वेस्ट इंडिया भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी है, जिसे भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के तत्वावधान में एक गैर-लाभकारी उद्यम के रूप में स्थापित किया गया है।
यह 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत सभी निवेशकों को भारत में अपना व्यवसाय स्थापित करने, संचालित करने और विस्तार करने की सुविधा प्रदान करता है और सशक्त बनाता है।

पर्यटन मंत्रालय के बारे में:

कैबिनेट मंत्री: जी किशन रेड्डी
राज्य मंत्री: श्रीपद नाइक,अजय भट्ट

RBI ने बैंकों और NBFC के लिए ऋण निपटान के बाद संपत्ति दस्तावेज जारी करने के लिए 30 दिन की समय सीमा निर्धारित की है

बैंक और NBFC RBI द्वारा ऋण खाते के निपटान के 30 दिनों के भीतर संपत्ति दस्तावेज जारी करने का निर्देश दिया गया है।
ये निर्देश विनियमित संस्थाओं के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के जिम्मेदार ऋण आचरण के अंतर्गत आते हैं।

मुख्य विचार

सभी बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) और परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (ARC) को सभी मूल चल/अचल संपत्ति दस्तावेजों को जारी करने के लिए कहा गया है।
उन्हें ऋण खाते की पूर्ण चुकौती/निपटान के बाद 30 दिनों की अवधि के भीतर किसी भी रजिस्ट्री में पंजीकृत शुल्क हटाने के लिए भी कहा गया है।
उधारकर्ता को उस बैंकिंग आउटलेट/शाखा से दस्तावेज़ एकत्र करने का विकल्प दिया जाएगा जहां ऋण खाता सेवित किया गया था।
उधारकर्ता को उसकी प्राथमिकता के अनुसार, विनियमित इकाई के किसी अन्य कार्यालय से दस्तावेज़ एकत्र करने का विकल्प दिया जाएगा जहां दस्तावेज़ उपलब्ध हैं।
मूल चल/अचल संपत्ति दस्तावेजों को जारी करने में देरी के मामले में, विनियमित इकाई उधारकर्ता को इस तरह की देरी के कारणों के बारे में बताएगी।
यदि विनियमित इकाई को देरी के लिए दोषी ठहराया जाता है, तो उसे देरी के प्रत्येक दिन के लिए उधारकर्ता को 5,000 का मुआवजा देना होगा।
ये निर्देश उन सभी मामलों पर लागू होंगे जहां मूल चल/अचल संपत्ति दस्तावेजों की रिहाई 1 दिसंबर, 2023 को या उसके बाद होनी है।
RBI अब उधारकर्ता को उसकी प्राथमिकता के अनुसार मूल चल/अचल संपत्ति दस्तावेजों को या तो उस बैंकिंग आउटलेट/शाखा से एकत्र करने का विकल्प प्रदान करता है जहां ऋण खाता परोसा गया था या आरई के किसी अन्य कार्यालय जहां दस्तावेज उपलब्ध हैं।
प्रभावी तिथि को या उसके बाद जारी किए गए ऋण स्वीकृति पत्रों में मूल चल/अचल संपत्ति दस्तावेजों की वापसी की समयसीमा और स्थान का उल्लेख किया जाएगा।

बैंक ऑफ बड़ौदा ने उत्सव अभियान "BOB के संग त्योहार की उमंग" का अनावरण किया

बैंक ऑफ बड़ौदा "बॉब के संग त्योहार की उमंग" अवकाश अभियान की शुरुआत की घोषणा की, जो 31 दिसंबर, 2023 तक चलेगा।
बैंक ऑफ बड़ौदा से 4 नए बचत खातों का शुभारंभ, साथ ही घरों, कारों, लोगों और शिक्षा के लिए ऋण पर आकर्षक ब्याज दर प्रचार, कंपनी के त्योहारी प्रस्तावों में से एक हैं।
बैंक ने चार नए बचत खाते लॉन्च किए - लाइट बचत खाता -
आजीवन बिना न्यूनतम शेष वाला खाता;
BRO बचत खाता - छात्रों (16 से 25 वर्ष) के लिए एक शून्य शेष बचत खाता;
परिवार खाता - एक पारिवारिक बचत खाता जिसे पूरे परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है
NRI पावरपैक खाता।
BoB ने एक आवर्ती जमा योजना, एक BOB SDP (व्यवस्थित जमा योजना) भी शुरू की।
देबदत्त चंद, प्रबंध निदेशक और CEO

सेबी ने फॉरेंसिक ऑडिट में गैर-प्रकटीकरण, प्रतिकूल जानकारी छिपाने के लिए रिलायंस होम फाइनेंस, शीर्ष अधिकारियों पर 21.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

सेबी ने रिलायंस होम फाइनेंस पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
यह जुर्माना LODR (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) नियमों का उल्लंघन करने और फोरेंसिक रिपोर्ट के प्रतिकूल निष्कर्षों का खुलासा करने में विफलता के लिए लगाया गया है।
मुख्य कार्यकारी रवींद्र शरद सुधालकर, कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी पारुल जैन और CFO पिंकेश शाह पर क्रमशः ₹2 लाख, ₹2.5 लाख और ₹2 लाख का जुर्माना लगाया गया है।

जनवरी 2020 में, रिलायंस होम फाइनेंस ने बताया कि ग्रांट थॉर्नटन द्वारा की गई फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं थे।
हालाँकि, बाद में यह बताया गया कि उनकी कंपनी ने "संभावित रूप से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े" उधारकर्ताओं के एक समूह को लगभग ₹12,000 करोड़ का ऋण दिया था।
इससे पहले 6 फरवरी 2023 को सेबी ने इन चारों की ओर से दायर सेटलमेंट एप्लिकेशन को खारिज कर दिया था

विश्व बैंक ने भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की सराहना की

विश्व बैंक ने अपने G20 दस्तावेज़ में शामिल निष्कर्षों को जारी करते हुए कहा है कि भारत ने केवल 6 वर्षों में वित्तीय समावेशन लक्ष्य हासिल किए हैं, अन्यथा कम से कम 47 साल लग जाते।
विश्व बैंक द्वारा तैयार नीति दस्तावेज़, जन धन बैंक खातों, आधार और मोबाइल फोन (JAM ट्रिनिटी) जैसे डिजिटल भुगतान अवसंरचना (DPI) के बिना, भारत को 80% की वित्तीय समावेशन दर हासिल करने में 47 साल लग सकते हैं जो कि देश ने सिर्फ छह साल में हासिल किया

मुख्य विचार

विश्व बैंक के दस्तावेज़ में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि इंडिया स्टैक डिजिटल आईडी, इंटरऑपरेबल भुगतान, एक डिजिटल क्रेडेंशियल लेजर और खाता एकत्रीकरण को मिलाकर DPI दृष्टिकोण का उदाहरण देता है।
पिछले वित्तीय वर्ष में UPI लेनदेन का कुल मूल्य भारत की नाममात्र GDP का लगभग 50% था।
"DPI के उपयोग से भारत में ग्राहकों को जोड़ने की बैंकों की लागत 23 डॉलर से घटकर 0.1 डॉलर हो गई। मार्च 2022 तक, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के कारण भारत ने सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 1.14% के बराबर $33 बिलियन की कुल बचत की।
रिपोर्ट के अनुसार, इसके लॉन्च के बाद से, प्रधान मंत्री जन धन योजना (PMJDY) खातों की संख्या मार्च 2015 में 147.2 मिलियन से तीन गुना होकर जून 2022 तक 462 मिलियन हो गई।
इनमें से 56% खाताधारक महिलाएं हैं, जिनकी संख्या 260 मिलियन से अधिक है।
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कैसे पिछले दशक में, भारत ने DPI का लाभ उठाते हुए दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल गवर्नमेंट-टू-पीपल आर्किटेक्चर में से एक का निर्माण किया।
रिपोर्ट में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि इंडिया स्टैक ने KYC प्रक्रियाओं को डिजिटल और सरल बना दिया है, जिससे लागत कम हो गई है; ई-KYC का उपयोग करने वाले बैंकों ने अपनी अनुपालन लागत $0.12 से घटाकर $0.06 कर दी।

WB के बारे में:

मुख्यालय: वाशिंगटन, डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका
स्थापित: जुलाई 1944,
अध्यक्ष: अजय बंगा.

यस बैंक ने हाइपरयूपीआई लॉन्च करने के लिए जसपे के साथ साझेदारी की

यस बैंक हाइपरयूपीआई - NPCI की प्लग-इन सेवा - लॉन्च करने के लिए जसपे के साथ साझेदारी की है, जो मर्चेंट ऐप्स को इन-ऐप UPI भुगतान बनाने की अनुमति देती है।
यस बैंक से जुड़े व्यापारी अब अपने ग्राहकों को अपना UPI ऐप खोले बिना एक-क्लिक UPI अनुभव प्रदान कर सकते हैं।
यह प्लग-इन सॉफ़्टवेयर डेवलपमेंट किट (SDK) UPI-ऑन-क्लाउड स्टैक पर बनाया गया है, जो कई उपभोक्ता और व्यापारी ऐप्स के लिए UPI भुगतान का भी समर्थन करता है।
UPI प्लग-इन SDK लेनदेन यात्रा को केवल एक क्लिक तक कम करके भुगतान अनुभव को सरल बनाता है।
इससे लेनदेन की गति में सुधार हुआ और सफलता दर 90% से अधिक हो गई।
हाइपरयूपीआई मैंडेट (आवर्ती भुगतान) और तृतीय-पक्ष सत्यापन (TPV) जैसी उन्नत सुविधाओं का समर्थन करता है।

इसे रिएक्ट-नेटिव, फ़्लटर और कॉर्डोवा जैसे विभिन्न तकनीकी ढांचे में व्यापारी के ऐप्स में आसानी से एकीकृत किया जा सकता है।
जसपे क्लाउड पर UPI PSP बनाने वाली पहली फिनटेक कंपनी थी, जिसने 99.99% से अधिक का अपटाइम और 5,000 का उच्चतम लेनदेन (TPS) दर्ज किया है।

इंडसइंड बैंक ने 'वर्चुअल कमर्शियल क्रेडिट कार्ड' लॉन्च किया, जो कॉरपोरेट्स और ट्रैवल एजेंटों को परेशानी मुक्त सीमा पार भुगतान के लिए सशक्त बनाता है

इंडसइंड बैंक ने निगमों और ट्रैवल एजेंटों के लिए सीमा पार लेनदेन के लिए 'वर्चुअल कमर्शियल कार्ड' पेश किया।
वीज़ा और जसपे के सहयोग से विकसित, यह वर्चुअल कार्ड सुरक्षा की उन्नत परतें प्रदान करता है, जिससे उपयोगकर्ता प्रत्येक लेनदेन के लिए सेटिंग्स को अनुकूलित कर सकते हैं।
नियंत्रण का यह स्तर एक सुरक्षित और निर्बाध अंतर्राष्ट्रीय भुगतान अनुभव सुनिश्चित करता है।
'वर्चुअल कमर्शियल क्रेडिट कार्ड' उन व्यवसायों की ज़रूरतों को पूरा करता है जो विभिन्न विदेशी मुद्राओं में एकाधिक बुकिंग करते हैं।

इंडसइंड बैंक के बारे में

इंडसइंड बैंक लिमिटेड एक भारतीय वित्तीय सेवा है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। इंडसइंड बैंक का उद्घाटन अप्रैल 1994 में तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने किया था।
CEO: सुमंत कठपालिया, मुख्यालय: मुंबई

RBI ने पैमाने आधारित नियमों के तहत 'ऊपरी परत' में 15 NBFC की सूची जारी की

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए इन उधारदाताओं के लिए पैमाने आधारित विनियमन के तहत 'ऊपरी परत' में शामिल पंद्रह एनबीएफसी की एक सूची जारी की।
सूची में LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पहले स्थान पर है, इसके बाद दूसरे नंबर पर बजाज फाइनेंस लिमिटेड और तीसरे नंबर पर श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड) है।
TMF बिजनेस सर्विसेज लिमिटेड (पूर्व में टाटा मोटर्स फाइनेंस लिमिटेड) को उसके चल रहे व्यवसाय पुनर्गठन के कारण अर्हता प्राप्त करने के बावजूद सूची में शामिल नहीं किया गया था।
RBI की 2023-24 की NBFC-UL सूची में शामिल अन्य NBFC HDB फाइनेंशियल सर्विसेज, आदित्य बिड़ला फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, मुथूट फाइनेंस, L&T फाइनेंस, पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस, टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस और बजाज हाउसिंग फाइनेंस हैं।

मुख्य विचार

RBI ने अक्टूबर 2021 में छाया बैंकिंग क्षेत्र पर कड़ी निगरानी रखने और समग्र वित्तीय प्रणाली के लिए जोखिमों को कम करने के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) के लिए चार-स्तरीय नियामक संरचना बनाने की घोषणा की।
मानदंडों का विस्तृत सेट एक स्केल आधारित विनियमन (SBR) ढांचे के लिए प्रदान करता है जो पूंजी आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है, शासन मानक, विवेकपूर्ण विनियमन और NBFC के अन्य पहलू।
ढांचा NBFC को बेस लेयर (NBFC-B;), मिडिल लेयर (NBFC-ML), अपर लेयर (NBFC-UL) और टॉप लेयर (NBFC-TL) में वर्गीकृत करता है।
ऊपरी परत में वे NBFC शामिल हैं, जिन्हें विशेष रूप से रिज़र्व बैंक द्वारा मापदंडों के एक सेट के आधार पर बढ़ी हुई नियामक आवश्यकताओं की गारंटी के रूप में पहचाना जाता है।
स्केल-आधारित ढांचा स्थापित करने का केंद्रीय बैंक का निर्णय 2018 में IL&FS और बाद में DHFL के पतन की पृष्ठभूमि में आया है, जिसका संपूर्ण वित्तीय प्रणाली पर, विशेष रूप से तरलता संकट के संदर्भ में, प्रभाव पड़ा।
आधार परत शामिल होगी (ए) ₹1000 करोड़ के परिसंपत्ति आकार से कम जमा न लेने वाली NBFC और (बी) निम्नलिखित गतिविधियां करने वाली NBFC- (i) NBFC-पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म (NBFC-P2P), (ii) NBFC-अकाउंट एग्रीगेटर

(NBFC-AA), (iii) नॉन-ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी (NOFHC) और (iv) NBFC जो सार्वजनिक धन का लाभ नहीं उठा रहे हैं और जिनके पास कोई ग्राहक इंटरफ़ेस नहीं है।
मध्य परत में (ए) सभी जमा स्वीकार करने वाली NBFC (NBFC-DS), संपत्ति के आकार की परवाह किए बिना, (बी) ₹1000 करोड़ और उससे अधिक की संपत्ति के आकार वाली गैर-जमा स्वीकार करने वाली NBFC और (सी) निम्नलिखित गतिविधियां करने वाली NBFC शामिल होंगी। (i) स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर्स (SPD), (ii) इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (IDF-NBFC), (iii) कोर इन्वेस्टमेंट कंपनियां (CIC), (iv) हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां (HFC) और (v)) इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनियां (NBFC-IFC)।
ऊपरी परत शामिल होगी: उन NBFC की जिन्हें रिज़र्व बैंक द्वारा विशेष रूप से इस परिपत्र के परिशिष्ट में दिए गए मापदंडों और स्कोरिंग पद्धति के एक सेट के आधार पर बढ़ी हुई नियामक आवश्यकता के रूप में पहचाना जाता है। अपनी संपत्ति के आकार के संदर्भ में शीर्ष दस पात्र एनबीएफसी किसी भी अन्य कारक के बावजूद हमेशा ऊपरी परत में रहेंगे।
शीर्ष परत आदर्श रूप से खाली रहेगी। यदि रिज़र्व बैंक की राय है कि ऊपरी परत में विशिष्ट NBFC से संभावित प्रणालीगत जोखिम में पर्याप्त वृद्धि हुई है तो यह परत आबाद हो सकती है। ऐसी NBFC ऊपरी परत से शीर्ष परत पर चली जाएंगी।
NBFC-ICC, NBFC-MFI और NBFC-फैक्टर्स के लिए नियामक न्यूनतम शुद्ध स्वामित्व निधि (NOF) मार्च 2027 तक बढ़ाकर ₹10 करोड़ कर दी जाएगी।
मौजूदा NBFC को ₹10 करोड़ का एनओएफ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित ग्लाइड पथ प्रदान किया गया है:
हालाँकि, NBFC-P2P, NBFC-AA और बिना सार्वजनिक फंड और बिना ग्राहक इंटरफेस वाले NBFC के लिए NOF ₹2 करोड़ बना रहेगा।
IPO फंडिंग की सीमा - आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) की सदस्यता के वित्तपोषण के लिए प्रति उधारकर्ता ₹1 करोड़ की सीमा होगी। NBFC अधिक रूढ़िवादी सीमाएं तय कर सकते हैं।
नियामक पूंजी की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, NBFC-UL जोखिम भारित परिसंपत्तियों का कम से कम 9 प्रतिशत सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी बनाए रखेगा।

RBI ने 4 सहकारी बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियामक अनुपालन में कमियों के लिए 4 सहकारी बैंकों पर मौद्रिक दंड लगाया है।

4 सहकारी बैंकों की सूची:

गुजरात के मेहसाणा में स्थित बेचाराजी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड पर ₹2.00 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
गुजरात के वडोदरा में स्थित वाघोडिया अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर ₹5.00 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
गुजरात के अहमदाबाद में स्थित वीरमगाम मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर भी ₹5.00 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
महाराष्ट्र के पुणे के बारामती में स्थित बारामती सहकारी बैंक लिमिटेड पर ₹2.00 लाख का जुर्माना लगाया गया है।

दंड के कारण:

बेचराजी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड को 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (UCB) द्वारा अन्य बैंकों में जमा राशि रखने' के संबंध में RBI के निर्देशों का पालन न करने और विवेकपूर्ण अंतरबैंक प्रतिपक्ष एक्सपोजर सीमा का उल्लंघन करने के लिए दंड का सामना करना पड़ा।
वाघोडिया अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को 'निदेशकों, रिश्तेदारों और फर्मों को ऋण और अग्रिम या चिंताओं, जिनमें वे रुचि रखते हैं' के साथ-साथ 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (UCB) द्वारा अन्य बैंकों में जमा राशि की नियुक्ति' से संबंधित निर्देशों का पालन न करने के लिए जुर्माना मिला।
वीरमगाम मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को 'निदेशकों आदि को ऋण और अग्रिम - निदेशकों को जमानती या गारंटर के रूप में - स्पष्टीकरण, 'प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (UCB) द्वारा अन्य बैंकों में जमा राशि की नियुक्ति' और पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (SAF) के तहत RBI द्वारा जारी विशिष्ट निर्देशों पर निर्देशों का पालन न करने के लिए दंडित किया गया था।

बारामती सहकारी बैंक लिमिटेड को 'जमा खातों के रखरखाव - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों' से संबंधित RBI के निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए दंड का सामना करना पड़ा क्योंकि इसने निष्क्रिय बचत बैंक खातों में ब्याज जमा नहीं किया था।

नवीनतम समाचार:

अगस्त 2023 में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 4 सहकारी बैंकों - मंगल को-ऑपरेटिव बैंक, द महाबलेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, द इस्लामपुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक और द तापिंदु अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया।

RBI के बारे में:

स्थापना: 1 अप्रैल 1935
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र, भारत
राज्यपाल: शक्तिकांत दाएस
उप राज्यपाल: महेश कुमार जैन, एम राजेश्वर राव, माइकल पात्रा और टी. रबी शंकर

LIC ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ₹1,831 करोड़ का लाभांश चेक सौंपा

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने वित्त मंत्री (FM) श्रीमती निर्मला सीतारमण को 1,831.09 करोड़ रुपये का लाभांश चेक प्रस्तुत किया।
22 अगस्त, 2023 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में LIC शेयरधारकों द्वारा लाभांश भुगतान को मंजूरी दी गई थी।
यह लाभांश राशि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लाभांश में केंद्र की हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व करती है।
जून 2023 तक, केंद्र के पास LIC में 96.5% की इक्विटी हिस्सेदारी थी।
मई 2022 में, LIC, जो देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है, ने अपना मेगा ₹21,000 करोड़ का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) लॉन्च किया।
यह IPO उस तारीख तक भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक निर्गम था।

LIC के बारे में:

स्थापना: 1956
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र
अध्यक्ष: सिद्धार्थ मोहंती
वर्तमान MD: आईपे मिनी, एम जगन्नाथ, तबलेश पांडे, सत पाल भानु

मोबिक्विक ने वित्तीय कल्याण में उपयोगकर्ताओं की सहायता के लिए 'लेंस' पेश किया

MobiKwik एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म, ने उपयोगकर्ताओं को उनके वित्तीय कल्याण में सहायता के लिए "लेंस" नामक एक नई सुविधा पेश की है।
MobiKwik लेंस अकाउंट एग्रीगेटर तकनीक का लाभ उठाता है, जो एक डेटा विज्ञान ढांचा है।
इस तकनीक का उपयोग जटिल वित्तीय डेटा को उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक समझने योग्य और कार्रवाई योग्य बनाने के लिए किया जाता है।
MobiKwik लेंस कई प्रकार की सुविधाएँ प्रदान करता है, जिनमें शामिल हैं:
उपयोगकर्ता का एक सिंहावलोकनविस्तृत लेनदेन जानकारी के साथ निवल मूल्य।
स्मार्ट वर्गीकरण इनकमिंग और आउटगोइंग वित्तीय लेनदेन।
बैंक खाते की शेष राशि, व्यय, निवेश और पुनर्भुगतान से संबंधित रुझानों की जानकारी।
उत्पाद में 'हाइलाइट' नामक एक सुविधा शामिल है, जिसे सही समय पर महत्वपूर्ण वित्तीय जानकारी पर उपयोगकर्ता का ध्यान आकर्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

नवीनतम समाचार:

अगस्त 2023 में, MobiKwik, वित्त वर्ष 23-24 की पहली तिमाही में 181% (वर्ष-दर-वर्ष) वृद्धि दर्ज करते हुए सकारात्मक PAT पोस्ट करने वाला देश का पहला फिनटेक बन गया।

मोबिक्विक के बारे में:
स्थापित: 2009
मुख्यालय: गुरुग्राम, हरियाणा
सह-संस्थापक और CEO: बिपिन प्रीत सिंह
MobiKwik एक भारतीय भुगतान सेवा प्रदाता है जो मोबाइल फोन-आधारित भुगतान प्रणाली और डिजिटल वॉलेट प्रदान करता है।

यस बैंक और ब्रिस्कपे ने भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए सीमा पार से भुगतान में बदलाव लाने के लिए सहयोग किया

गोब्रिस्क टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (ब्रिस्कपे) एक सीमा-पार भुगतान फिनटेक कंपनी, और यस बैंक ने निर्यातकों और आयातकों को सशक्त बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए समाधानों का एक अत्याधुनिक सूट, ब्रिस्कपे अकाउंट टू अकाउंट (A2A) पेश करने के लिए साझेदारी की है।
यह साझेदारी ब्रिस्कपे के ग्राहकों को 180 से अधिक देशों से 36 से अधिक विदेशी मुद्राओं में भुगतान एकत्र करने में सक्षम बनाती है।
विदेशी मुद्राओं में एकत्रित धनराशि को भारतीय रुपये (INR) में परिवर्तित किया जा सकता है और एक ही व्यावसायिक दिन के भीतर सीधे भारतीय व्यवसायों के स्थानीय बैंक खातों में जमा किया जा सकता है।
यह सहयोग सीमा पार से भुगतान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण छलांग का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को लाभ होता है।

साझेदारी के बारे में:
यह उत्पाद यस बैंक के ऑनलाइन पेमेंट गेटवे सर्विस प्रोवाइडर्स (OPGSP) एक्सपोर्ट API पर बनाया गया है और वास्तविक समय लेनदेन प्रसंस्करण और तत्काल EFIRA (इलेक्ट्रॉनिक फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस एडवाइस) जेनरेशन जैसी सुविधाएं प्रदान करता है।
यस बैंक का लक्ष्य इस साझेदारी के माध्यम से MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने और भारत को वैश्विक निर्यात पावरहाउस में बदलने के सरकार के उद्देश्य के साथ जुड़ना है।
यह साझेदारी सीमा पार भुगतान में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करती है, जो भारतीय निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जटिलताओं को नेविगेट करने और उनकी वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए एक सहज और कुशल मंच प्रदान करती है।

नवीनतम समाचार:
अगस्त 2023 में, यस बैंक ने व्यय प्रबंधन मंच ज़ैगल के सहयोग से व्यवसायों को अपनी भुगतान प्रक्रियाओं की फिर से कल्पना करने, सामंजस्य स्थापित करने और कंपनी के व्यय को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए सशक्त बनाने के लिए यस बैंक ज़ैगल कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड नाम से एक सह-ब्रांडेड कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया।
अगस्त 2023 में, निजी ऋणदाता यस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए डिजिटल बैंकिंग को फिर से परिभाषित करने के उद्देश्य से 'आईरिस' नाम से अपना अत्याधुनिक मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन पेश किया।

ब्रिस्कपे के बारे में:
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र
सह-संस्थापक और CEO: संजय त्रिपाठी
ब्रिस्कपे एक वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी है, जिसे छोटे से मध्यम आकार के व्यवसाय (SMB) के लिए सीमा पार B2B भुगतान समाधान प्रदान करने में एक वैश्विक खिलाड़ी और बाजार अग्रणी बनने के दृष्टिकोण से स्थापित किया गया है।

यस बैंक के बारे में:
स्थापना: 2004
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र

MD और CEO: प्रशांत कुमार
टैगलाइन: एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टीज़

इंडियन बैंक ने बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए 'आईबी साथी' लॉन्च किया

इंडियन बैंक ने "आईबी साथी" (समग्र समावेशन के लिए सतत पहुंच और संरेखित प्रौद्योगिकी) नामक एक वित्तीय समावेशन समाधान लॉन्च किया है।
यह पहल व्यवसाय संवाददाता (बीसी) चैनल के माध्यम से हितधारकों को बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने पर केंद्रित है।
आईबी साथी का लक्ष्य सेवाओं की डिलीवरी को सरल बनाना है और ग्राहकों को बुनियादी और मूल्य वर्धित दोनों सेवाएं प्रदान करना है
बैंक की योजना अपनी सभी शाखाओं में प्रतिदिन कम से कम 4 घंटे बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की है।
बैंकिंग संवाददाता (बीसी) भी ग्राहकों को सीधे उनके दरवाजे पर सेवाएं प्रदान करेंगे।
इंडियन बैंक ने ग्राहकों तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए मार्च 2024 तक लगभग 5,000 बैंकिंग संवाददाताओं को तैनात करने का लक्ष्य रखा है।
यह पहल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और वंचित क्षेत्रों और आबादी के लिए बैंकिंग सेवाओं को बढ़ाने के बैंक के प्रयासों का हिस्सा है।

इंडियन बैंक के बारे में:

स्थापना: 1907
मुख्यालय: चेन्नई, तमिलनाडु
MD और CEO: शांति लाल जैन
टैगलाइन: योर ओन बैंक/अपका अपना बैंक

इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) ने ऑनलाइन सुरक्षित जमा लॉकर आवंटन सेवा शुरू की

सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) ने अपने ग्राहकों और गैर-ग्राहकों के लिए सुरक्षित जमा लॉकर सुविधा का ऑनलाइन आवंटन शुरू किया है।
बैंक के मौजूदा और गैर-ग्राहक दोनों ग्राहक, बैंक के आधिकारिक पोर्टल पर लॉग इन करके इस नई सुविधा का उपयोग कर सकते हैं, जो है www.iob.in.
इस सेवा का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह IOB ग्राहकों और गैर-ग्राहकों दोनों को बैंक शाखा में जाने की आवश्यकता के बिना सुरक्षित जमा लॉकर सुविधा का लाभ उठाने की अनुमति देता है।

IOB के बारे में:

स्थापना: 10 फरवरी 1937
मुख्यालय: चेन्नई, तमिलनाडु, भारत
MD और CEO: अजय कुमार श्रीवास्तव
टैगलाइन: गुड पीपल टू ग्रो विथ

मारुति ने डीलरों को वित्तीय समाधान प्रदान करने के लिए इंडियन बैंक के साथ सहयोग किया

मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने अपने डीलरों को वित्तपोषण समाधान प्रदान करने के लिए इंडियन बैंक के साथ साझेदारी की है।
इस सहयोग को औपचारिक रूप देने के लिए दोनों पक्षों ने एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
इस साझेदारी का लक्ष्य देश भर में 4,000 से अधिक मारुति सुजुकी डीलरशिप को उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यापक इन्वेंट्री फंडिंग विकल्प प्रदान करके सशक्त बनाना है।

इस सहयोग में भारत भर में मारुति सुजुकी के डीलर भागीदारों की जरूरतों के अनुरूप व्यक्तिगत ऑफर और एंड-टू-एंड कार्यशील पूंजी समाधान का विकास शामिल है।

नवीनतम समाचार:

फरवरी 2023 में, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने साउथ इंडियन बैंक के साथ एमओयू (समझौता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर किए, जिसके माध्यम से कंपनी का लक्ष्य डीलर भागीदारों को वाहन इन्वेंट्री फंडिंग को सुव्यवस्थित करने और अपने ग्राहकों को व्यापक खुदरा वित्तपोषण समाधान प्रदान करने में मदद करना है।

मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के बारे में:

स्थापना: 24 फरवरी 1981
मुख्यालय: नई दिल्ली, दिल्ली, भारत
MD और CEO: हिसाशी टेकुची
मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड जापानी वाहन निर्माता सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन की भारतीय सहायक कंपनी है।

इंडियन बैंक के बारे में:

स्थापना: 1907
मुख्यालय: चेन्नई, तमिलनाडु
MD और CEO: शांति लाल जैन
टैगलाइन: योर ओन बैंक/अपका अपना बैंक

रिज़र्व बैंक की घर्षण रहित ऋण पहल से ऋणदाता ग्राहक अधिग्रहण लागत में 70% की कमी और उधारकर्ताओं के लिए 6% की बचत हुई

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) एक "घर्षण रहित ऋण पहल" चला रहा है जिसके परिणामस्वरूप ऋणदाताओं के लिए ग्राहक अधिग्रहण लागत में 70% की भारी कमी आई है, दूसरी ओर, उधारकर्ता ऋण राशि का 6% बचा रहे हैं।
पायलट की शुरुआत इस अप्रैल, 2023 में तमिलनाडु (टीएन) और मध्य प्रदेश (एमपी) में सार्वजनिक तकनीकी मंच पर आरबीआई इनोवेशन हब द्वारा विकसित एक ऑल-डिजिटल KCC (किसान क्रेडिट कार्ड) ऋण के साथ हुई।
पायलट कार्यक्रम को 17 अगस्त, 2023 से 4 अतिरिक्त राज्यों: महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात (डेयरी किसानों के लिए) तक बढ़ा दिया गया है।

मुख्य विचार:

यह मंच केंद्रीय बैंक की एक स्वतंत्र सहायक कंपनी रिजर्व बैंक इनोवेशन हब द्वारा बनाया गया था, जो उधारदाताओं को आवश्यक जानकारी के निर्बाध प्रवाह को सक्षम करता है।
इससे बदले में बाधा रहित ऋण वितरित करने में मदद मिलेगी।
17 अप्रैल,2023 को RBI ने मध्य प्रदेश में प्रति उधारकर्ता 1.6 लाख रुपये तक के किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ऋण, डेयरी ऋण, गैर-संपार्श्विक MSME ऋण, व्यक्तिगत ऋण और गृह ऋण जैसे शुद्ध खुदरा उत्पादों के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की।
प्लेटफ़ॉर्म एक खुला आर्किटेक्चर है, जो ओपन एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (API) और मानक प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित है, जहां सभी वित्तीय क्षेत्र के खिलाड़ी प्लग एंड प्ले मॉडल में निर्बाध रूप से जुड़ सकते हैं।
सीख के आधार पर, पायलट के दौरान अधिक उत्पादों, सूचना प्रदाताओं और ऋणदाताओं को शामिल करने के लिए दायरे और कवरेज का विस्तार किया जाएगा।

मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने एक संयुक्त जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी 'सेवा' योजना लॉन्च की

मैक्स लाइफ इंश्योरेंस एक निजी जीवन बीमा कंपनी ने "सिक्योर अर्निंग्स एंड वेलनेस एडवांटेज" (SEWA) नामक एक नई बीमा योजना लॉन्च करके स्वास्थ्य और कल्याण क्षेत्र में प्रवेश किया है।
यह योजना स्वास्थ्य और जीवन बीमा के लाभों को एक ही पॉलिसी में जोड़ती है।

SEWA योजना दो प्रकारों में उपलब्ध है - "एलीट" और "लाइट।"

सेवा योजना की अनूठी विशेषताएं:

यह स्वास्थ्य, सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता लाभों को जोड़ता है।

SEWA योजना का स्वास्थ्य घटक प्रीमियम पर रिटर्न प्रदान करता है।

यह पॉलिसी पारंपरिक गारंटीकृत योजना के माध्यम से आंशिक निकासी की अनुमति देती है।

पॉलिसी अवधि के दौरान भुगतान किए गए स्वास्थ्य दावों की परवाह किए बिना गारंटीशुदा रिटर्न परिपक्वता पर एकमुश्त राशि के रूप में देय होता है।

योजना में मौजूदा स्वास्थ्य बीमा के अलावा एक अंतर्निहित स्वास्थ्य कवर भी शामिल है।

कवरेज: SEWA योजना अस्पताल में भर्ती होने, ICU में रहने, सर्जरी, गंभीर बीमारी, विकलांगता और जीवन बीमा सहित विभिन्न पहलुओं को कवर करती है।

वित्तीय समावेशन प्रयासों के हिस्से के रूप में और महिलाओं और ट्रांसजेंडर ग्राहकों के बीच बीमा को बढ़ावा देने के लिए, SEWA योजना प्रथम वर्ष के प्रीमियम पर 5% की छूट प्रदान करती है।

सेवानिवृत्ति पर मैक्स लाइफ का शोध, जिसे "इंडिया रिटायरमेंट इंडेक्स स्टडी" के रूप में जाना जाता है, इंगित करता है कि 59% भारतीय सेवानिवृत्ति की योजना बनाते समय स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं।

यह योजना ग्राहकों को मैक्स फिट वेलनेस डिजिटल ऐप तक पहुंच भी प्रदान करती है, जो उन्हें बेहतर परिपक्वता लाभ प्रदान करके एक अनुशासित और स्वस्थ जीवन शैली जीने के लिए प्रोत्साहित करती है।

मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बारे में:

स्थापना: 2000 (कार्य प्रारंभ: 2001)

मुख्यालय: गुरुग्राम, हरियाणा

MD और CEO: प्रशांत त्रिपाठी

स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस ने बीमा खरीद के लिए UPI QR कोड भुगतान विकल्प पेश किया है

स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने पॉलिसी खरीद और नवीनीकरण के लिए एक UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस) QR कोड-आधारित भुगतान विकल्प पेश किया है।

इस अनुकूलित समाधान का उद्देश्य ग्राहक खरीदारी अनुभव को सरल बनाना है, इसे केवल कुछ क्लिक तक कम करना है।

कंपनी ने ग्राहकों की सुविधा बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत UPI पेमेंट इंटेंट लिंक भी लॉन्च किया है।

यह पहल भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के सहयोग से संभव हुई है और आधुनिक, प्रौद्योगिकी-संचालित भुगतान समाधानों को अपनाने का प्रतीक है।

मुख्य विचार:

डायनामिक UPI QR कोड को भुगतान अनुस्मारक ईमेल में एकीकृत किया गया है, जिससे ग्राहक सेकंड के भीतर लेनदेन पूरा कर सकते हैं।

QR कोड में प्रीमियम राशि सहित सभी आवश्यक भुगतान विवरण शामिल हैं, जिससे ग्राहकों को मैन्युअल रूप से प्रीमियम राशि दर्ज करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

ग्राहक परेशानी मुक्त, त्रुटि मुक्त और कुशल भुगतान अनुभव सुनिश्चित करते हुए अनुकूलित क्यूआर कोड को स्कैन करके सेकंड के भीतर भुगतान कर सकते हैं।

नवीनतम समाचार:

अगस्त 2023 में, निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य बीमा प्रदाता स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने ग्राहकों को अपने बीमा उत्पाद प्रदान करने के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ एक "रणनीतिक कॉर्पोरेट बैंकएश्योरेंस" पर हस्ताक्षर किए हैं।

स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बारे में:

स्थापना: 2006

मुख्यालय: चेन्नई, तमिलनाडु, भारत

MD और CEO: आनंद रॉय

IREDA ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (IREDA), नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार का एक मिनी रत्न (श्रेणी - I) उद्यम, ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र (BOM) के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
इस सहयोग का उद्देश्य पूरे देश में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विविध स्पेक्ट्रम के लिए सह-उधार और ऋण सिंडिकेशन को बढ़ावा देना और सुविधा प्रदान करना है।
समझौता ज्ञापन में सभी अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए सह-उधार और सह-उत्पत्ति समर्थन, ऋण सिंडिकेशन और अंडरराइटिंग की सुविधा, IREDA उधारकर्ताओं के लिए ट्रस्ट और प्रतिधारण खाते का प्रबंधन और IREDA उधारियों के लिए 3-4 वर्षों की अवधि में स्थिर निश्चित ब्याज दरों को स्थापित करने की प्रतिबद्धता सहित कई सेवाएं शामिल हैं।
इस समझौते के तहत, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पेशकश के निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार IREDA द्वारा जारी बांड में निवेश कर सकता है।
MoU पर IREDA के महाप्रबंधक (तकनीकी सेवाएं), श्री भरत सिंह राजपूत और महाप्रबंधक (खुदरा और MSME क्रेडिट), बैंक ऑफ महाराष्ट्र, श्री राजेश सिंह ने IREDA के बिजनेस सेंटर, नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए।
हस्ताक्षर समारोह IREDA के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, श्री प्रदीप कुमार दास और दोनों संगठनों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हुआ।

इरेडा के बारे में:

मुख्यालय: नई दिल्ली, दिल्ली
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक: प्रदीप कुमार दास
IREDA एक सार्वजनिक लिमिटेड सरकारी कंपनी और एक गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान है, जिसका गठन ऊर्जा के नए और नवीकरणीय स्रोतों और ऊर्जा दक्षता/संरक्षण से संबंधित परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए किया गया है, जिसका आदर्श वाक्य है: "हमेशा के लिए ऊर्जा"।
यह भारत सरकार का एक मिनी रत्न (श्रेणी - I) उद्यम है जिसका उद्देश्य वित्तीय सहायता को बढ़ावा देना, विकास करना और विस्तार करना है और यह नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

नवीनतम समाचार

मई 2023 में,सरकार ने भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (IREDA) के आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (IPO) के प्रबंधन के लिए IDBI कैपिटल, BOB कैपिटल और SBI कैपिटल को नियुक्त किया।
जून 2023 में, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (IREDA) ने नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में अपनी 36वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) आयोजित की।

BoM के बारे में:

स्थापना: 16 सितंबर 1935
मुख्यालय: पुणे, महाराष्ट्र भारत
MD और CEO: एएस राजीव
टैगलाइन: वन फैमिली वन बैंक

IRDAI ने साइबर सुरक्षा पर अंतःविषय स्थायी समिति की स्थापना की

भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने साइबर सुरक्षा पर एक स्थायी समिति का गठन किया है।

समिति का उद्देश्य:

बीमा उद्योग में मौजूदा या उभरती प्रौद्योगिकियों से जुड़े खतरों की नियमित समीक्षा करना।

समिति की भूमिका:
समिति बीमा उद्योग की साइबर सुरक्षा स्थिति और लचीलेपन को बढ़ाने के लिए ढांचे में उचित बदलाव की भी सिफारिश करेगी।
यह पहल अप्रैल, 2023 में सूचना और साइबर सुरक्षा दिशानिर्देश जारी होने के बाद की गई थी।
समिति की संरचना:
स्थायी समिति में पीएस जगन्नाथम की अध्यक्षता में 10 सदस्य शामिल हैं।
समिति में शिक्षा जगत के प्रौद्योगिकी पेशेवर, उद्योग विशेषज्ञ और बीमा ब्रोकिंग समुदाय के प्रतिनिधि शामिल हैं।
आवश्यकतानुसार समिति में शामिल होने के लिए बाहरी सदस्यों को भी आमंत्रित किया जा सकता है.
साइबर सुरक्षा मानदंडों का अधिदेश:
IRDAI द्वारा अनिवार्य किए गए साइबर सुरक्षा मानदंडों के तहत बीमाकर्ताओं और मध्यस्थों को जोखिम-आधारित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता होती है।
उन्हें साइबर खतरों के खिलाफ अपने सिस्टम और डेटा को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक उपाय लागू करने की आवश्यकता है।
IRDAI के बारे में:
स्थापना: 1999
मुख्यालय: हैदराबाद, तेलंगाना
अध्यक्ष: देबाशीष पांडा
IRDAI भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (MoF) के अधिकार क्षेत्र में एक वैधानिक निकाय है और इसे भारत में बीमा और पुनर्बीमा उद्योगों को विनियमित करने और लाइसेंस देने का काम सौंपा गया है।

उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने प्रीमियम ग्राहकों के लिए मैक्सिमा बचत खाता और बिजनेस मैक्सिमा चालू खाता लॉन्च किया

उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक (उज्जीवन SFB), एक अग्रणी लघु वित्त बैंक ने प्रीमियम ग्राहक वर्ग के लिए मैक्सिमा बचत खाता और बिजनेस मैक्सिमा चालू खाता पेश किया है।
इन नई पेशकशों का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की सेवाएँ और लाभ प्रदान करके नए और मौजूदा दोनों ग्राहकों के लिए बैंकिंग अनुभव को बेहतर बनाना है।
उत्पादों को ग्राहकों को उनकी विभिन्न वित्तीय और बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न लाभ, बेहतर सुविधाएँ और एक प्रीमियम अनुभव प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
मुख्य विचार:
मैक्सिमा बचत खाते पर वार्षिक ब्याज दर 7.5% तक है और ग्राहक 1 लाख रुपये से खाता खोल सकते हैं।
प्रीमियम ग्राहकों के पास रुपये बनाए रखने की सुविधा है। इस खाते के लिए शेष राशि पात्रता मानदंड को पूरा करने के लिए सावधि जमा में 15 लाख या उससे अधिक, एक अनूठी सुविधा आमतौर पर मानक बचत खातों के साथ उपलब्ध नहीं है।
मैक्सिमा बचत खाते की अतिरिक्त सेवाओं और लाभों में उच्च लेनदेन सीमा, चेक और डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) जारी करना, सभी चैनलों पर मुफ्त लेनदेन और किसी भी शाखा में असीमित नकद जमा और निकासी शामिल हैं।
मैक्सिमा बचत खाते के लागू ग्राहकों को एक मानार्थ हेल्थ प्राइम लाभ भी मिलता है।
बिजनेस मैक्सिमा चालू खाता:
उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने प्रीमियम बिजनेस ग्राहकों के लिए बिजनेस मैक्सिमा चालू खाता पेश किया है।
इस खाते में सुविधाजनक ऑनलाइन बैंकिंग, तत्काल फंड ट्रांसफर और नकद प्रबंधन विकल्प हैं।
व्यवसाय की मुख्य विशेषताएंमैक्सिमा चालू खाता शामिल है
व्यवसायों के लिए अपनी स्वयं की नकद जमा सीमा परिभाषित करने की क्षमता
प्रति दिन 5 लाख रुपये की उच्च दैनिक एटीएम निकासी सीमा

व्यापारियों के लिए खाता सेवाओं जैसी बैंकिंग सेवाओं से परे का प्रावधान, और पॉइंट-ऑफ-सेल (PoS) सेवाओं के लिए मुफ्त इंस्टॉलेशन और किराये की फीस।

उज्जीवन लघु वित्त बैंक के बारे में:

स्थापित: 1 फरवरी 2017
मुख्यालय: बैंगलोर, कर्नाटक, भारत
MD और CEO: श्री इत्तिरा डेविस

गुल्लक ने जसपे के साथ साझेदारी की और UPI प्लगइन SDK को लागू करने वाला भारत का पहला देश बन गया

गुल्लक एक प्रमुख फिनटेक ऐप, जसपे के UPI प्लगइन SDK को "हाइपरयूपीआई" नामक लागू करने वाला पहला ऐप बन गया है।

मुख्य विचार:

हाइपरयूपीआई के कार्यान्वयन से चेकआउट प्रक्रिया के दौरान भुगतान करते समय गुल्लक के ग्राहकों को दूसरे यूपीआई भुगतान ऐप पर स्विच करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
भुगतान अब पूरी तरह से गुल्लक के ऐप के भीतर पूरा किया जा सकता है।
इस एकीकरण के परिणामस्वरूप, UPI भुगतान में लगने वाला समय 22 सेकंड से घटकर 3 सेकंड से भी कम हो गया है।
हाइपरयूपीआई के एकीकरण से उपयोगकर्ताओं के लिए एक आसान भुगतान अनुभव होता है, जिसमें कम टैप की आवश्यकता होती है, लगभग शून्य भुगतान विफलता दर होती है, और बाहरी भुगतान ऐप्स पर पुनर्निर्देशन की 100% समाप्ति होती है।

सिडबी अगले वित्त वर्ष में राइट्स इश्यू से 10,000 करोड़ रुपये जुटाएगी

सिडबी ने अपने पूंजी आधार का विस्तार करने के लिए अगले वित्त वर्ष में राइट्स इश्यू से 10,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बनाई है।
सिडबी, जो SME ऋणों को पुनर्वित्त करता है, प्रत्येक अगले वित्तीय वर्ष में ₹5,000 करोड़ की दो किस्तों में राइट्स इश्यू आयोजित करने की योजना बना रहा है।
सिडबी को उम्मीद है कि मार्च 2023 में लगभग 4 लाख करोड़ रुपये से मार्च 2024 तक उसकी संपत्ति बढ़कर 5 लाख करोड़ रुपये हो जाएगी।
शेयरधारक प्रस्तावित राइट्स इश्यू की सदस्यता लेंगे।
केंद्र सरकार के पास SIDBI की 20.8% हिस्सेदारी है।
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की 15.65% और जीवन बीमा निगम की 13.33% हिस्सेदारी है।
शेष इक्विटी अन्य सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों और बैंकों के पास है।
सिडबी का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) वित्त वर्ष 2012 में 24.28% से घटकर वित्त वर्ष 2013 में 19.29% हो गया। जून 2023 तिमाही तक यह घटकर 15.63% रह गई।

मार्च 2023 तक ₹16.39 करोड़ मूल्य का ई-रुपया प्रचलन में था

सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) या ई-रुपया ₹16.39 करोड़ प्रचलन में है।
यह FY23 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था पर RBI की सांख्यिकी की हैंडबुक के आंकड़ों के अनुसार है।
आंकड़ों से पता चला कि कुल ई-रुपया सर्कुलेशन में से, ₹10.69 करोड़ थोक CBDC था और ₹5.70 करोड़ खुदरा CBDC था।
₹500 CBDC नोटों का प्रचलन सबसे अधिक ₹2.71 करोड़ था।
इसके बाद 1.16% पर ₹200 के नोट थे।
50 पैसे से ₹100 तक की अन्य सभी मुद्राओं का प्रचलन 1% से कम था। यह 0.01- 0.83% के बीच था।

Click Here to Subscribe Our Yearly Mock Test Package

वित्तीय वर्ष 2013 में वाणिज्यिक क्षेत्र में संसाधनों का कुल प्रवाह साल-दर-साल (वर्ष-दर-वर्ष) 31% बढ़ गया।
भारतीय अर्थव्यवस्था 2022-23 पर RBI की सांख्यिकी की हैंडबुक के अनुसार बैंकों की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2012 में 46% से बढ़कर कुल प्रवाह में 59% हो गई और गैर-बैंकों की हिस्सेदारी 54% से घटकर 41% हो गई।
वाणिज्यिक क्षेत्र में संसाधनों का कुल प्रवाह वित्त वर्ष 2013 में ₹29,49,176 करोड़ था, जो वित्त वर्ष 2012 में ₹22,51,703 करोड़ था।
गैर-बैंक श्रेणी के तहत, वित्त वर्ष 2013 में घरेलू स्रोतों से वाणिज्यिक क्षेत्र में संसाधन प्रवाह 70% से अधिक था।
विदेशी स्रोतों से प्रवाह तेजी से 52% से घटकर 30% हो गया।

सेबी ने REIT, InvIT धारकों के लिए बोर्ड सीटों की अनुमति देने की प्रक्रिया का विवरण दिया

सेबी ने उस ढांचे को अधिसूचित किया जो रियल एस्टेट निवेश ट्रस्टों और बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्टों के यूनिटधारकों को बोर्ड में प्रतिनिधियों को नामित करने की अनुमति देता है।
बाजार नियामक के एक परिपत्र में कहा गया है कि जिन यूनिटधारकों के पास व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से बकाया REIT या InvIT का कम से कम 10% हिस्सा है, वे REIT या InvIT के निवेश प्रबंधकों के बोर्ड में एक निदेशक को नामित कर सकते हैं।
पात्रता की हर माह समीक्षा की जाएगी।
अपनी जून बोर्ड बैठक में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने अपने कॉर्पोरेट प्रशासन मानदंडों को बढ़ाने के लिए यूनिटधारकों के लिए विशेष अधिकारों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
अधिसूचित ढांचे के अनुसार, नियमों के तहत पात्र यूनिट धारकों के पास अपने प्रतिनिधि के रूप में निवेश प्रबंधकों के बोर्ड में एक निदेशक को नामित करने या नामित करने से बचने का विकल्प होगा।
कोई भी आगामी सूचना प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 10 दिनों के भीतर दी जाएगी। सूचना प्राप्त होने पर, इच्छुक यूनिटधारक अगले 10 दिनों के भीतर अपने निवेश प्रबंधक को सूचित करेंगे।

REIT के बारे में

रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या REIT निवेश ट्रस्ट (म्यूचुअल फंड की तरह) हैं जो रियल एस्टेट संपत्तियों का स्वामित्व और संचालन करते हैं और अपने निवेश पर नियमित आय और पूंजीगत प्रशंसा अर्जित करते हैं।

InvITs के बारे में

इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या InvITs भी म्यूचुअल फंड की तरह हैं जो उन निवेशकों से पैसा इकट्ठा करते हैं जो राजमार्गों, सड़कों, पाइपलाइनों, गोदामों, बिजली संयंत्रों आदि जैसे परिचालन बुनियादी ढांचे की संपत्तियों के मालिक हैं और उनका संचालन करते हैं।

RBI ने बैंकों द्वारा निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण और मूल्यांकन के लिए संशोधित मानदंड जारी किए

RBI ने वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन के लिए संशोधित मानदंड जारी किए, उन्हें वैश्विक मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखित किया।
संशोधित 'भारतीय रिजर्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन) दिशानिर्देश, 2023' 1 अप्रैल, 2024 से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर सभी वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होंगे।

मुख्य विचार

संशोधित निर्देशों में निवेश पोर्टफोलियो का सिद्धांत आधारित वर्गीकरण, धारित से परिपक्वता (HTM) श्रेणी में स्थानान्तरण और HTM से बाहर बिक्री के बारे में नियमों को कड़ा करना, HTM में गैर-SLR (सांविधिक तरलता अनुपात) प्रतिभूतियों को शामिल करना शामिल है, बशर्ते कि कुछ शर्तों को पूरा किया जाए और लाभ और हानि की सममित मान्यता दी जाए।
संशोधित मानदंडों के अनुसार, बैंकों को अपने संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो को तीन श्रेणियों - परिपक्वता तक धारित (HTM), बिक्री के लिए उपलब्ध (AFS) और लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (FVTPL) के तहत वर्गीकृत करना होगा।
"ट्रेडिंग के लिए आयोजित (HFT) FVTPL के भीतर एक अलग निवेश उपश्रेणी होगी।

निवेश की श्रेणी अधिग्रहण से पहले या अधिग्रहण के समय बैंक द्वारा तय की जाएगी और इस निर्णय को उचित रूप से प्रलेखित किया जाएगा।
RBI ने हेल्ड फॉर ट्रेडिंग (HFT) श्रेणी के तहत प्रतिभूतियों की होल्डिंग अवधि पर 90 दिन की सीमा हटा दी है।
वर्तमान में, बैंकों को HTM के तहत कुल निवेश का 25% से अधिक अलग रखने की अनुमति है, बशर्ते वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश 18% पर सीमित है।
वर्तमान में बैंकों को निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण और मूल्यांकन पर विनियामक दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक है, जो अक्टूबर 2000 में तत्कालीन प्रचलित वैश्विक मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं पर आधारित एक रूपरेखा पर आधारित हैं।

ACKO ने अपने नए शुरू किए गए ACKO प्लैटिनम हेल्थ प्लान के लिए 'स्वास्थ्य बीमा की सुबह हो गई मामू' अभियान शुरू किया

ACKO ने अपना स्वास्थ्य बीमा उत्पाद लॉन्च किया है- ACKO प्लैटिनम स्वास्थ्य योजना।
कंपनी के अनुसार, योजना में 100% बिल भुगतान, नो रूम रेंट कैपिंग और शून्य प्रतीक्षा अवधि सहित अन्य सुविधाएं हैं।
कंपनी का दावा है कि विज्ञापन फिल्मों की श्रृंखला दर्शकों को शून्य प्रतीक्षा अवधि, 100% बिल भुगतान, तनाव मुक्त दावा प्रक्रिया के लिए बीमारियों का पूरा खुलासा प्रदान करने के लाभ और दावे दाखिल करने में आसानी के बारे में शिक्षित करने पर केंद्रित है।
अभियान की विज्ञापनों की श्रृंखला का उद्देश्य दर्शकों को ACKO प्लेटिनम स्वास्थ्य योजना की कई महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में सूचित करना है, जिनमें शामिल हैं:
शून्य प्रतीक्षा अवधि: अभियान योजना की शून्य प्रतीक्षा अवधि की विशेष सुविधा पर जोर देता है, जो पॉलिसीधारकों को त्वरित कवरेज की गारंटी देता है।
100% बिल भुगतान: ACKO चिकित्सा आपात स्थितियों के दौरान वित्तीय तनाव को कम करने के लिए चिकित्सा खर्चों का 100% भुगतान करने के अपने समर्पण पर प्रकाश डालता है।
तनाव-मुक्त दावों के लिए पूर्ण प्रकटीकरण: विज्ञापन अभियान पॉलिसीधारकों से उनकी सभी चिकित्सीय स्थितियों का खुलासा करने का आग्रह करता है। यह पारदर्शिता दावा प्रक्रिया को आसान और कम तनावपूर्ण बनाती है।
आसानीदावा दायर करने की संख्या: ACKO दावा दायर करने की सरलता पर ज़ोर देता है, जिससे यह ग्राहकों के लिए एक दर्द रहित प्रक्रिया बन जाती है।

वित्त मंत्रालय ने LIC एजेंटों और कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी उपायों को मंजूरी दी

वित्त मंत्रालय ने भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) एजेंटों और कर्मचारियों के लाभ के लिए कई कल्याणकारी उपायों को मंजूरी दी।
कल्याणकारी उपाय LIC (एजेंट) विनियम, 2017 में संशोधन, ग्रेच्युटी सीमा में वृद्धि और पारिवारिक पेंशन की समान दर सहित अन्य से संबंधित हैं।
13 लाख से अधिक एजेंट और 1 लाख से अधिक नियमित कर्मचारी, जो LIC के विकास और भारत में बीमा पैठ को गहरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इन कल्याणकारी उपायों से लाभान्वित होंगे।
LIC एजेंटों और कर्मचारियों के संबंध में निम्नलिखित कल्याणकारी उपायों को मंजूरी दी गई:
LIC एजेंटों के लिए ग्रेच्युटी की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की गई। यह LIC एजेंटों की कामकाजी स्थिति और लाभों में पर्याप्त सुधार लाएगा।
पुनर्नियुक्त एजेंटों को नवीनीकरण कमीशन के लिए पात्र बनाना, जिससे उन्हें बढ़ी हुई वित्तीय स्थिरता प्रदान की जा सके।
वर्तमान में, LIC एजेंट पुरानी एजेंसी के तहत पूरे किए गए किसी भी व्यवसाय पर नवीनीकरण कमीशन के लिए पात्र नहीं हैं।
एजेंटों के लिए टर्म इंश्योरेंस कवर को 3,000-10,000 रुपये की मौजूदा सीमा से बढ़ाकर 25,000-1,50,000 रुपये कर दिया गया है। टर्म इन्शुरन्स में यह वृद्धि मृतक एजेंटों के परिवारों को काफी लाभान्वित करेगी, जिससे उन्हें अधिक महत्वपूर्ण कल्याणकारी लाभ मिलेगा।

LIC कर्मचारियों के परिवारों के कल्याण के लिए @ 30% की एक समान दर पर पारिवारिक पेंशन।

ADB ने इस वर्ष (2023) भारत की GDP वृद्धि की उम्मीद को घटाकर 6.3% कर दिया

एशियाई विकास बैंक (ADB) ने गिरते निर्यात और अनियमित वर्षा पैटर्न के प्रभाव का हवाला देते हुए इस वर्ष के लिए भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अपने विकास पूर्वानुमान को घटाकर 6.3% कर दिया है, जो पहले अनुमानित 6.4% था, जिससे कृषि उत्पादन प्रभावित हो सकता है।
निजी निवेश और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की उम्मीदों से प्रभावित होकर, बैंक के अर्थशास्त्रियों ने भी वर्ष के लिए अपने मुद्रास्फीति पूर्वानुमान को अप्रैल में अनुमानित 5% से बढ़ाकर 5.5% कर दिया और 2024-25 के लिए अपने वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद विकास अनुमान को 6.7% पर बरकरार रखा।
इसके अतिरिक्त, एडीबी ने वित्त वर्ष 2014 के लिए भारत के लिए अपने मुद्रास्फीति अनुमान को पिछले 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 5.5 प्रतिशत कर दिया।
प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण जुलाई में खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई, जिससे दक्षिण एशिया की समग्र मुद्रास्फीति दर में वृद्धि हुई।
यदि भारत का कृषि उत्पादन कमजोर होता है और चावल निर्यात प्रतिबंध जारी रहता है, तो इससे विकासशील एशिया में खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति बढ़ सकती है

वित्त मंत्रालय FY24 के लिए 6.5% बेसलाइन GDP वृद्धि अनुमान को लेकर सहज है

चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक दृष्टिकोण को "उज्ज्वल" बताते हुए, वित्त मंत्रालय ने कहा कि वित्त वर्ष 2024 में GDP वृद्धि के लिए बेसलाइन अनुमान 6.5% है।
पिछले वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.2 प्रतिशत की दर से बढ़ी, लेकिन वैश्विक मंदी के कारण चालू वित्त वर्ष में विकास दर धीमी होने की आशंका है।
हालाँकि, अर्थव्यवस्था 2023-24 की पहली तिमाही में 7.8% की अनुमानित दर से अधिक बढ़ी, जिससे वित्तीय वर्ष के लिए निजी एजेंसियों द्वारा विकास अनुमान बढ़ गया।
हालाँकि, अधिकांश एजेंसियाँ अभी भी 6.5% से कम के पूर्वानुमान के साथ सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को लेकर सतर्क बनी हुई हैं।
हालाँकि, मासिक रिपोर्ट में अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक बातों पर प्रकाश डाला गया है और कहा गया है कि अगस्त में मानसून की कमी को सितंबर में आंशिक रूप से कम कर दिया गया है, जबकि चयनित खाद्य पदार्थों की कीमतें, जिन्होंने जुलाई में मुद्रास्फीति को 7% से अधिक कर दिया था, पीछे हट रही हैं।

GDP क्या है?

सकल घरेलू उत्पाद (GDP) किसी देश या देशों द्वारा एक विशिष्ट समय अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य का एक मौद्रिक माप है।

वित्त मंत्रालय के बारे में:

वित्त मंत्रालय भारत सरकार के भीतर भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित एक मंत्रालय है, जो भारत के खजाने के रूप में कार्य करता है।
गठन: 29 अक्टूबर 1946
मुख्यालय: नई दिल्ली
क्षेत्राधिकार: भारत सरकार
मंत्री जिम्मेदार: निर्मला सीतारमण

एक्सिस बैंक ने MSME के लिए 'एनईओ फॉर बिजनेस' बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया

एक्सिस बैंक ने भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए विशेष रूप से तैयार एक विशिष्ट लेनदेन बैंकिंग मंच 'नियो फॉर बिजनेस' के शुभारंभ की घोषणा की।
यह अपनी तरह का पहला व्यापक डिजिटल प्रस्ताव है जो एमएसएमई की वास्तविक, वर्तमान और उभरती लेनदेन बैंकिंग जरूरतों को पूरा करता है।
नीरज गंभीर- एक्सिस बैंक में ग्रुप एक्जीक्यूटिव और हेड - ट्रेजरी, मार्केट्स और होलसेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स ने कहा कि 'NEO बाय एक्सिस बैंक' को हमारे कॉर्पोरेट बैंकिंग ग्राहकों के लिए डिजिटल बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं की एक पूरी श्रृंखला की पेशकश करने वाले एक मंच के रूप में लॉन्च किया गया था।
इस प्लेटफॉर्म के भीतर, हमारा नया लॉन्च किया गया 'एनईओ फॉर बिजनेस' MSME की व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए वन-स्टॉप समाधान है," उन्होंने आगे कहा।

व्यवसाय के लिए एक्सिस बैंक के NEO के लाभ:

'NEO फॉर बिजनेस' प्लेटफॉर्म MSME के लिए एक गेम-चेंजर है, जो बैंकिंग और बियॉन्ड बैंकिंग सुविधाओं का एक व्यापक सूट पेश करता है जो सुविधा और उत्पादकता को बढ़ाता है।
इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं:

डिजिटल सेल्फ ऑन-बोर्डिंग
बिजनेस के लिए NEO के साथ, MSME आसानी से खुद को डिजिटल रूप से प्लेटफॉर्म पर जोड़ सकते हैं, जिससे बैंक शाखा में भौतिक दौरे की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

थोक भुगतान
प्लेटफ़ॉर्म थोक भुगतान की सुविधा देता है, उन व्यवसायों के लिए प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है जिन्हें बार-बार और बड़े पैमाने पर भुगतान लेनदेन की आवश्यकता होती है।

GST अनुरूप चालान
व्यवसाय के लिए NEO चालान-प्रक्रिया में GST अनुपालन सुनिश्चित करता है, जिससे व्यवसायों को अपने कर-संबंधी दस्तावेज़ों को सहजता से प्रबंधित करने में मदद मिलती है।

भुगतान गेटवे एकीकरण
भुगतान गेटवे के साथ एकीकरण MSME के लिए ऑनलाइन लेनदेन को सरल बनाता है, जिससे वे सुरक्षित रूप से भुगतान स्वीकार करने में सक्षम होते हैं।

360° ग्राहक दृश्य
उपयोगकर्ता अपने वित्तीय डेटा के व्यापक दृश्य तक पहुंच प्राप्त करते हैं, जिससे बेहतर निर्णय लेने और वित्तीय प्रबंधन संभव हो पाता है।

एंड टू एंड ट्रांजेक्शन ट्रैकिंग
पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए व्यवसाय शुरुआत से लेकर समापन तक अपने लेनदेन को ट्रैक कर सकते हैं।

ऑटो सुलह
व्यवसाय के लिए NEO समाधान प्रक्रिया को स्वचालित करता है, त्रुटियों को कम करता है और MSME के लिए मूल्यवान समय बचाता है।

आवर्ती संग्रह
उन व्यवसायों के लिए जो आवर्ती भुगतान पर निर्भर हैं, प्लेटफ़ॉर्म संग्रह को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए उपकरण प्रदान करता है।

नकदी प्रवाह रिपोर्ट और बहुत कुछ
विस्तृत नकदी प्रवाह रिपोर्ट और अतिरिक्त सुविधाओं की एक श्रृंखला MSME को अपने वित्तीय संचालन को अनुकूलित करने के लिए अंतर्दृष्टि के साथ सशक्त बनाती है।

एक्सिस बैंक के बारे में:

स्थापना: 3 दिसंबर 1993 को यूटीआई बैंक के रूप में

मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र
MD एवं CEO: श्री अमिताभ चौधरी
टैगलाइन: बढ़ती का नाम जिंदगी

जेपी मॉर्गन अपने उभरते बाजार सूचकांक में जी-सेक को शामिल करेगा

एक ऐसे विकास में जो भारत को अगले वित्तीय वर्ष से 21 बिलियन डॉलर (1.7 लाख करोड़ रुपये) का निवेश आकर्षित करने में मदद कर सकता है, वैश्विक वित्तीय फर्म जेपी मॉर्गन ने कहा कि वह भारत सरकार के बांड (IGB) या सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) को शामिल करने की योजना बना रही है। इसका बेंचमार्क इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है।
यह पहली बार है कि भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों को किसी प्रमुख वैश्विक बांड सूचकांक में जोड़ा गया है।
IGB का समावेश 28 जून, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक 10 महीने की अवधि में किया जाएगा।
1% से शुरू होकर, भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों का भार मार्च 2025 तक 10 महीनों में अधिकतम 10% तक बढ़ जाएगा।.
इससे उच्च विदेशी प्रवाह को आकर्षित करने में मदद मिलेगी, क्योंकि कई विदेशी फंडों को वैश्विक सूचकांकों पर नज़र रखना अनिवार्य है
इससे विदेशों से बड़े निष्क्रिय निवेश लाने में भी मदद मिलेगी, जिसके परिणामस्वरूप उद्योग के लिए अधिक घरेलू पूंजी उपलब्ध होगी
2021 में, जेपी मॉर्गन ने पहली बार भारतीय जी-सेक को 'इंडेक्स वॉच पॉजिटिव' मोड पर रखा था - जो इसके बॉन्ड इंडेक्स में शामिल करने के लिए एक अग्रदूत था।

जेपी मॉर्गन के बारे में:

जेपी मॉर्गन एंड कंपनी एक अमेरिकी वित्तीय संस्थान है जो निवेश बैंकिंग, परिसंपत्ति प्रबंधन और निजी बैंकिंग उद्योग में विशिष्ट है।
स्थापित: 1871
संस्थापक: जेपी मॉर्गन
मुख्यालय: न्यूयॉर्क शहर

RBI ने अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के लिए बेसल-III पूंजी ढांचा लागू किया

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (AIFI) के लिए निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण और मूल्यांकन पर बेसल III पूंजी ढांचे, धन उगाहने, एक्सपोजर दिशानिर्देशों और मानदंडों पर मानदंड पेश किए हैं, जो अप्रैल 2024 से लागू होंगे।
भारत में 5 AIFI हैं जो RBI द्वारा विनियमित हैं।
ये संस्थान भारतीय निर्यात-आयात बैंक (EXIM बैंक), नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड), नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (NaBFID), नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB), और स्मॉल भारतीय उद्योग विकास बैंक (सिडबी) हैं।

मुख्य विचार:

न्यूनतम पूंजी आवश्यकताएँ: AIFI को अप्रैल 2024 तक न्यूनतम 9% की कुल पूंजी बनाए रखने की आवश्यकता होगी। इसमें 7% की न्यूनतम टियर-I पूंजी आवश्यकता और 5.5% की न्यूनतम सामान्य इक्विटी टियर-I (CET-1) पूंजी आवश्यकता शामिल है।
NHB के लिए कार्यान्वयन तिथि: राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) इन मानदंडों को जुलाई 2024 में लागू करेगा, जो अपने लेखांकन वर्ष के कारण अन्य AIFI से अलग है, जो जुलाई से जून तक चलता है।
वित्तीय सहायक कंपनियों का एकीकरण: बीमा और गैर-वित्तीय गतिविधियों में लगी कंपनियों को छोड़कर, AIFI की सभी वित्तीय सहायक कंपनियों को पूंजी पर्याप्तता के उद्देश्य से पूरी तरह से समेकित किया जाना चाहिए।

निवेश सीमाएँ: RBI ने बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं के पूंजीगत उपकरणों में AIFI के निवेश पर उनकी पूंजी निधि के 10% की सीमा निर्धारित की है।
इसके अतिरिक्त, AIFI किसी बैंक या किसी अन्य AIFI के इक्विटी शेयरों में हिस्सेदारी हासिल नहीं कर सकता है यदि इससे निवेशिती की इक्विटी पूंजी के 5% से अधिक हिस्सेदारी हो जाएगी।
इक्विटी निवेश सीमाएँ: AIFI एक इकाई में 49% तक के इक्विटी निवेश तक सीमित हैं।
हालाँकि, यदि यह निवेश किसी दावे के विरुद्ध संपार्श्विक के रूप में रखा गया है, तो इसे 3 वर्षों के भीतर 10% से नीचे लाना होगा।

बेसल III दिशानिर्देशों के बारे में:

बेसल III दिशानिर्देश 2008 के वित्तीय संकट के जवाब में 2010 में वैश्विक स्तर पर पेश किए गए थे।
वे अधिक लचीली बैंकिंग प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख मापदंडों के रूप में पूंजी पर्याप्तता, उत्तोलन, वित्त पोषण और तरलता पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
पूंजी पर्याप्तता अनुपात: पूंजी पर्याप्तता अनुपात 12.9% पर बनाए रखा जाना है।
न्यूनतम टियर 1 पूंजी अनुपात और न्यूनतम टियर 2 पूंजी अनुपात को जोखिम-भारित परिसंपत्तियों के क्रमशः 10.5% और 2% पर बनाए रखना होगा। इसके अलावा, बैंकों को 2.5% का पूंजी संरक्षण बफर बनाए रखना होगा। प्रति-चक्रीय बफर को भी 0-2.5% पर बनाए रखा जाना है।
उपलब्ध साधन का अनुपात:बैंकों को कम से कम 3 प्रतिशत का उत्तोलन अनुपात बनाए रखना चाहिए, जो कि कुल समेकित परिसंपत्तियों के औसत के लिए टियर 1 पूंजी का अनुपात है।
तरलता अनुपात: बेसल III ने बैंकों के पास पर्याप्त तरलता सुनिश्चित करने के लिए दो तरलता अनुपात - तरलता कवरेज अनुपात (LCR) और नेट स्थिर फंड दर (NSFR) पेश किए।

LCR के बारे में:

तरलता कवरेज अनुपात (LCR) के लिए बैंकों को पर्यवेक्षकों द्वारा निर्दिष्ट तीव्र अल्पकालिक तनाव परिदृश्य में आने वाले नकदी बहिर्प्रवाह से निपटने के लिए पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्तियों का बफर रखने की आवश्यकता होगी।
लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि यदि ऐसा होता है तो बैंकों के पास 30-दिवसीय तनाव परिदृश्य के लिए पर्याप्त तरलता हो।

NSFR के बारे में:

नेट स्टेबल फंड रेट (NSFR) के लिए बैंकों को अपनी ऑफ-बैलेंस-शीट परिसंपत्तियों और गतिविधियों के संबंध में एक स्थिर फंडिंग प्रोफ़ाइल बनाए रखने की आवश्यकता होती है।
NSFR के लिए बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी गतिविधियों को वित्त के स्थिर स्रोतों (एक वर्ष की अवधि के लिए विश्वसनीय) से वित्तपोषित करें।
न्यूनतम NSFR आवश्यकता 100% है।

बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (BCBS) के बारे में:

बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (BCBS) अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग नियमों के लिए बेसल मानदंड जारी करती है।
इन मानदंडों का लक्ष्य दुनिया भर में बैंकिंग नियमों का समन्वय करके अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करना है।

RBI के बारे में:

स्थापना: 1 अप्रैल 1935
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र, भारत
राज्यपाल: शक्तिकांत दास
उप राज्यपाल: महेश कुमार जैन, एम राजेश्वर राव, माइकल पात्रा और टी. रबी शंकर

सेबी ने ऋण बाजार तक पहुंच रखने वाले बड़े निगमों के लिए नियमों को सरल बनाया

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बड़े कॉरपोरेट्स (LC) के लिए ऋण बाजार से उनकी वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई छूटें पेश की हैं।

प्रारंभ में, सेबी ने अनिवार्य किया था कि एलसी को अपनी वित्तपोषण आवश्यकताओं का 25% ऋण बाजार से जुटाना होगा। इस आवश्यकता का उद्देश्य भारत में कॉर्पोरेट बांड बाजार के विकास को बढ़ावा देना है।

मुख्य विचार:

निवेशकों के लिए समर्थन: नियमों को आसान बनाने के सेबी के फैसले से बीमा कंपनियों, पेंशन फंड और भविष्य निधि जैसे निवेशकों को फायदा होने की उम्मीद है।

इन इकाइयों को अपने वृद्धिशील धन का एक विशिष्ट प्रतिशत कॉर्पोरेट बॉन्ड में आवंटित करने की आवश्यकता होती है। बांड जारी करने में आपूर्ति की कमी इन निवेशकों के लिए चुनौतियां खड़ी कर सकती है।

LC द्वारा गैर-अनुपालन: सेबी ने पाया कि एलसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान ऋण प्रतिभूतियों के माध्यम से उनकी वृद्धिशील उधारी के लिए न्यूनतम 25% की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है।

सीमा संशोधन प्रस्ताव: जबकि सेबी की विज्ञप्ति में सटीक सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई थी, पिछले परामर्श पत्र में बकाया दीर्घकालिक उधारों में एलसी के रूप में संस्थाओं की पहचान के लिए सीमा को मौजूदा ₹100 करोड़ से बढ़ाकर कम से कम ₹500 करोड़ करने का सुझाव दिया गया था।

एलसी के लिए जुर्माना हटाना: सेबी के बोर्ड ने ऋण बाजार से वृद्धिशील उधार के एक विशिष्ट प्रतिशत को पूरा करने में विफल रहने वाले एलसी पर लगाए गए जुर्माने को खत्म करने का प्रस्ताव दिया है।

वर्तमान में, तीन साल के अंत में उधार ली गई राशि में कमी का 0.2 प्रतिशत मौद्रिक जुर्माना लगाया जाता है।

निवेश सलाहकार आवश्यकताओं के लिए विस्तार: सेबी ने निवेश सलाहकारों के लिए बढ़ी हुई योग्यता और अनुभव आवश्यकताओं के अनुपालन की समयसीमा दो साल बढ़ा दी है, समय सीमा 30 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी गई है।

दावा न की गई रकम की रूपरेखा: सेबी के बोर्ड ने सूचीबद्ध संस्थाओं (कंपनियों, REITS और InvITs को छोड़कर) में निवेशकों की दावा न की गई राशि को निवेशक सुरक्षा और शिक्षा कोष (IPEF) में जमा करने के लिए एक सुव्यवस्थित ढांचे को मंजूरी दे दी है।

सेबी के बारे में:

स्थापना: 12 अप्रैल 1988 एक कार्यकारी निकाय के रूप में और सेबी अधिनियम, 1992 के माध्यम से 30 जनवरी 1992 को वैधानिक शक्तियां दी गईं

मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र

अध्यक्ष: माधबी पुरी बुच (सेबी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला)

SEBI भारत में प्रतिभूति और कमोडिटी बाजारों के लिए नियामक निकाय है जो वित्त मंत्रालय (MoF), भारत सरकार के स्वामित्व के तहत है।

SBI ने 7.49% इन्फ्रास्ट्रक्चर बांड के माध्यम से ₹10,000 करोड़ जुटाए

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने 7.49% की ब्याज दर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बांड जारी करके सफलतापूर्वक ₹10,000 करोड़ जुटाए। यह SBI के चौथे बुनियादी ढांचा बांड जारी करने का प्रतीक है, जो बुनियादी ढांचे के विकास के लिए धन जुटाने के बैंक के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है।

मुख्य विचार:

इंफ्रास्ट्रक्चर बांड की परिपक्वता अवधि 15 वर्ष है और यह 7.49% की उपज प्रदान करता है।

इन बांडों ने निवेशकों के एक विविध समूह से महत्वपूर्ण रुचि आकर्षित की है।

बांड इश्यू को मजबूत मांग प्राप्त हुई, जिसमें कुल ₹21,045 करोड़ की 134 बोलियां आईं, जो कि ₹4,000 करोड़ के बेस इश्यू आकार से काफी अधिक थी।

इस जारी करने से पहले, SBI ने जुलाई 2023 में अतिरिक्त टियर-I (एटी-1) बांड के माध्यम से ₹3,101 करोड़ और दीर्घकालिक 15-वर्षीय बुनियादी ढांचा बांड के माध्यम से ₹10,000 करोड़ जुटाए थे।

कुल बकाया दीर्घकालिक बांड अब ₹39,718 करोड़ हैं।

अन्य बैंक बांड जारी: चालू वित्त वर्ष में कई अन्य बैंकों ने भी बांड जारी कर धन जुटाया है।

उदाहरण के लिए, कोटक महिंद्रा बैंक ने ₹1,895 जुटाए7-वर्षीय इन्फ्रास्ट्रक्चर बांड के माध्यम से 7.55% पर करोड़, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने 10-वर्षीय टियर-2 बांड के माध्यम से 8.40% पर ₹1,500 करोड़ जुटाए, और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने टियर-2 बांड के माध्यम से 7.74% पर ₹3,090 करोड़ जुटाए।

आगामी बांड जारी करना: आने वाले सप्ताह में, PNB को अतिरिक्त टियर-I (एटी-1) बांड के माध्यम से ₹3,000 करोड़ तक जुटाने की उम्मीद है, और केनरा बैंक को 10-वर्षीय बुनियादी ढांचा बांड के माध्यम से ₹5,000 करोड़ तक जुटाने की उम्मीद है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर बांड क्या हैं?

इन्फ्रास्ट्रक्चर बांड विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए विशेष रूप से समर्पित धन जुटाने के लिए सरकारों या निजी कंपनियों द्वारा जारी किए गए वित्तीय साधन हैं।

इन परियोजनाओं में सड़कों, पुलों, हवाई अड्डों, बिजली संयंत्रों, रेलवे और दूरसंचार नेटवर्क जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास सहित एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है।

नवीनतम समाचार:

अगस्त 2023 में, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने तीसरे बुनियादी ढांचा बांड जारी करने के माध्यम से 7.54% की कूपन दर पर 10,000 करोड़ रुपये जुटाए।

SBI के बारे में:

स्थापना: 1 जुलाई, 1955
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र
चेयरमैन दिनेश खारा

RBI ने जानबूझकर और बड़े डिफॉल्टरों से निपटने के लिए ड्राफ्ट मास्टर डायरेक्शन जारी किया

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक "ड्राफ्ट मास्टर डायरेक्शन" जारी किया है जो बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में जानबूझकर चूक करने वालों और बड़े चूककर्ताओं के इलाज पर केंद्रित है।

RBI ने इस ड्राफ्ट मास्टर डायरेक्शन पर टिप्पणियाँ और प्रतिक्रिया आमंत्रित की है, और हितधारकों के पास 31 अक्टूबर, 2023 तक इनपुट प्रदान करने का अवसर है।

मुख्य विचार:

RBI द्वारा प्रस्तावित मानदंडों का उद्देश्य जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों के इलाज के लिए सख्त दिशानिर्देश स्थापित करना है।

मसौदे के अनुसार, बैंकों और अन्य ऋणदाताओं को रुपये के बकाया शेष वाले सभी खातों की जांच करने की आवश्यकता है। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या उधारकर्ता जानबूझकर ऋण चुकौती से बच रहा है, 25 लाख या उससे अधिक।

मास्टर डायरेक्शन का मसौदा परिभाषा को व्यापक बनाता हैजान-बूझकर की गई चूक, संभावित रूप से चूक करने वाले व्यवहारों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करती है।

यह विनियमित संस्थाओं के दायरे को भी विस्तृत करता है जो उधारकर्ताओं को जानबूझकर चूक करने वालों के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं, जिसका अर्थ है कि विभिन्न वित्तीय संस्थान इन नियमों के अधीन होंगे।

मसौदे में कहा गया है कि किसी खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किए जाने के 6 महीने के भीतर जानबूझकर डिफ़ॉल्ट पहलुओं को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।

मसौदे के अनुसार, बड़े डिफॉल्टरों से संबंधित प्रावधान आरबीआई द्वारा विनियमित सभी संस्थाओं पर लागू होंगे। यह इस बात पर ध्यान दिए बिना होगा कि वे 'ऋणदाता' की परिभाषा में आते हैं या नहीं।

प्रस्तावित नियमों का उद्देश्य बैंकों, गैर-बैंक ऋणदाताओं (आवास वित्त कंपनियों सहित), सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (AIFI) सहित विभिन्न प्रकार की विनियमित संस्थाओं पर लागू करना है।

मास्टर डायरेक्शन के मसौदे में यह भी बताया गया है कि संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को बेचे गए जानबूझकर डिफ़ॉल्ट ऋणों का इलाज कैसे किया जाएगा और दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) के तहत उनकी स्थिति क्या होगी।

PhonePe ने भारत में Google Play को टक्कर देने के लिए इंडस ऐपस्टोर पेश किया

phonepe बेंगलुरु स्थित डिजिटल भुगतान कंपनी ने भारत में एंड्रॉइड डेवलपर्स को आकर्षित करने के लिए "इंडस ऐपस्टोर डेवलपर प्लेटफॉर्म" नामक अपना ऐप स्टोर प्लेटफॉर्म पेश किया है।

डेवलपर्स के लिए प्लेटफ़ॉर्म लाभ:

निःशुल्क पंजीकरण और अपलोड: प्लेटफ़ॉर्म मुफ़्त पंजीकरण प्रदान करता है और डेवलपर्स को पहले वर्ष के लिए ऐप्स अपलोड करने की अनुमति देता है।
कोई प्लेटफ़ॉर्म शुल्क नहीं: इंडस ऐपस्टोर डेवलपर प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करने से जुड़ा कोई प्लेटफ़ॉर्म शुल्क नहीं है।
इन-ऐप खरीदारी पर कोई कमीशन नहीं: Google Play जैसे अन्य ऐप स्टोर के विपरीत, PhonePe का प्लेटफ़ॉर्म इन-ऐप खरीदारी पर कोई कमीशन नहीं लेता है, जिससे यह डेवलपर्स के लिए एक आकर्षक विकल्प बन जाता है।

मुख्य विचार:

PhonePe ने एंड्रॉइड ऐप डेवलपर्स को निमंत्रण दिया है, जिससे उन्हें इंडस ऐपस्टोर डेवलपर प्लेटफॉर्म पर अपने ऐप को पंजीकृत करने और अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
प्लेटफ़ॉर्म पर अपलोड किए गए ऐप्स को 'मेड-इन-इंडिया' ऐप स्टोर पर सूचीबद्ध किया जाएगा, जिसे इंडस ऐपस्टोर के नाम से जाना जाता है।
यह स्टोर स्थानीय अनुभव प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और भारतीय दर्शकों को पूरा करने के लिए 12 भाषाओं में सामग्री का समर्थन करेगा।
इंडस ऐप स्टोर डेवलपर्स को भारतीय एंड्रॉइड बाजार तक पहुंचने के लिए एक वैकल्पिक वितरण चैनल प्रदान करता है।
यह विशेष रूप से हो सकता हैविविध भारतीय दर्शकों तक पहुंचने के इच्छुक डेवलपर्स के लिए फायदेमंद।
प्लेटफ़ॉर्म डेवलपर्स को बहुभाषी ऐप खोज के माध्यम से उच्च-गुणवत्ता वाले उपयोगकर्ता अधिग्रहण में सहायता करेगा, संभावित रूप से उन्हें अपने ऐप की पहुंच का विस्तार करने में मदद करेगा।
स्टार्टअप और नए ऐप लॉन्च के लिए, प्लेटफ़ॉर्म में 'लॉन्च पैड' नामक एक समर्पित अनुभाग है, जो नए ऐप्स के लिए बेहतर दृश्यता और खोज अनुकूलन प्रदान करता है, जिससे उनकी प्रारंभिक वृद्धि और पहचान में सहायता मिलती है।
CPO और इंडस ऐपस्टोर के सह-संस्थापक: आकाश डोंगरे

फ़ोनपे के बारे में:

स्थापित: 2015
मुख्यालय: बैंगलोर, कर्नाटक

ट्रूकैप और HDFC बैंक ने कम सेवा वाले MSME उधारकर्ताओं को समर्थन देने के लिए सह-ऋण के लिए सहयोग किया

सोने और व्यापार ऋण में विशेषज्ञता रखने वाली एक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी ट्रूकैप फाइनेंस लिमिटेड (TRU) और एचडीएफसी बैंक ने सह-उधार साझेदारी में प्रवेश किया है।
TRU वंचित उधारकर्ताओं को गुणवत्तापूर्ण क्रेडिट समाधान प्रदान करने के लिए इस साझेदारी के हिस्से के रूप में अपने लेंडिंग-ए-ए-सर्विस (LaaS) मॉडल का उपयोग करेगा।
साझेदारी का उद्देश्य गैर-शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उधारकर्ताओं पर विशेष ध्यान देने के साथ उधारकर्ताओं को MSME व्यवसाय ऋण और गोल्ड लोन प्रदान करना है।

मुख्य विचार:

उद्योग के अनुमान से संकेत मिलता है कि MSME क्षेत्र की कुल ऋण मांग 69.3 ट्रिलियन रुपये है, जो 11.5% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ रही है।

इस मांग का 15% से भी कम औपचारिक ऋण चैनलों द्वारा पूरा किया जाता है।
TRU, जो MSME ऋण देने में माहिर है, छोटे व्यवसायों के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किफायती ऋण समाधान पेश करने पर ध्यान केंद्रित करता है।
TRU के प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO): रोहन जुनेजा

HDFC बैंक के बारे में:

स्थापित: 1994
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र
MD और CEO: शशिधर जगदीशन
टैगलाइन: वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड

SBI ने योनो ऐप के माध्यम से डिजिटल NRE और NRO खाता खोलने की शुरुआत की

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अनिवासी भारतीयों (NRI) के लिए अपने मोबाइल के माध्यम से आसानी से गैर-आवासीय बाहरी (NRE) और अनिवासी साधारण (NRO) खाते (बचत और चालू खाते दोनों) खोलने के लिए एक डिजिटल सुविधा शुरू की है। यह सेवा NTB या 'बैंक में नए' ग्राहकों के लिए डिज़ाइन की गई है, जो उन्हें खाता खोलने की प्रक्रिया में आसानी और दक्षता प्रदान करती है।

मुख्य विचार:

इस डिजिटल सेवा के लॉन्च के साथ, NRI अपने घर बैठे ही अपने NRE/NRO खाते खोल सकते हैं, जिससे भारत में व्यक्तिगत यात्रा की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।
भारतीय स्टेट बैंक के NRI ग्राहक अपने खाता खोलने की प्रक्रिया के हर कदम पर वास्तविक समय में आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।
यह पहल भारत में अपने खाते खोलने और प्रबंधित करने के लिए परेशानी मुक्त तरीके से NRI ग्राहकों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करती है।

योनो के माध्यम से NRI/NRO खाता कैसे खोलें?

चरण 1: योनो SBI ऐप डाउनलोड करें
चरण 2: NRE/NRO खाता खोलने के लिए विकल्प चुनें
चरण 3: सफल सबमिशन पर ग्राहकों के पास अपना केवाईसी जमा करने के लिए दो विकल्प होते हैं
विकल्प ए) भारत में पसंद की SBI शाखा में दस्तावेज़ जमा करें
विकल्प बी) - KYC दस्तावेजों को नोटरी, भारतीय दूतावास, उच्चायोग, SBI विदेश कार्यालय, प्रतिनिधि कार्यालय, कोर्ट मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश द्वारा सत्यापित करें और उन्हें प्रसंस्करण के लिए केंद्रीय रूप से नामित शाखा में मेल करें।

NRE और NRO के बीच क्या अंतर है?

गैर-आवासीय बाहरी (NRE) खाता एक NRI के नाम पर भारत में अपनी विदेशी कमाई को जमा करने के लिए खोला गया एक बैंक खाता है; जबकि, भारत में एक अनिवासी साधारण (NRO) खाता एक NRI के नाम पर खोला जाता है, ताकि भारत में उसके द्वारा अर्जित आय का प्रबंधन किया जा सके।

SBI के बारे में:

स्थापना: 1955
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र, भारत
MD और CEO: दिनेश कुमार खारा
टैगलाइन: द बैंकर टू एवरी इंडियन

RBI ने मार्च 2023 तक ₹16.39 करोड़ मूल्य के ई-रुपये प्रचलन में होने की रिपोर्ट दी है

मार्च 2023 तक, वित्त वर्ष 2023 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था पर भारतीय रिज़र्व बैंक की हैंडबुक ऑफ़ स्टैटिस्टिक्स के डेटा से संकेत मिलता है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC), जिसे ई-रुपया भी कहा जाता है, कुल 16.39 करोड़ रुपये के मूल्य के साथ प्रचलन में थी।
कुल ई-रुपया सर्कुलेशन में से 10.69 करोड़ रुपये में थोक CBDC शामिल है, जबकि 5.70 करोड़ रुपये में खुदरा CBDC शामिल है।
ई-रुपया भारत की कानूनी निविदा के डिजिटल प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करता है, जो विभिन्न मूल्यवर्ग में भौतिक मुद्रा को प्रतिबिंबित करता है और बैंकों को वितरित किया जाता है।
विभिन्न मूल्यवर्गों में, 500 रुपये के CBDC नोटों का प्रचलन सबसे अधिक 2.71 करोड़ रुपये था, इसके बाद 200 रुपये के नोटों का 1.16 करोड़ रुपये था। अन्य मूल्यवर्ग 50 पैसे से लेकर 100 रुपये तक थे, जिसका प्रसार प्रतिशत 0.01 और 0.83 करोड़ रुपये के बीच था।

CBDC पहल:

भारतीय रिजर्व बैंक ने CBDC के लिए दो पायलट कार्यक्रम शुरू किए।
थोक CBDC पायलट, जिसे CBDC (डब्ल्यू) कहा जाता है, नवंबर 2022 में शुरू हुआ, शुरू में सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार लेनदेन के निपटान पर ध्यान केंद्रित किया गया।
खुदरा पायलट, जिसे CBDC (आर) के रूप में जाना जाता है, को दिसंबर 2022 में भाग लेने वाले ग्राहकों, बैंकों और व्यापारियों के एक बंद उपयोगकर्ता समूह के भीतर लॉन्च किया गया था।
खुदरा ई-रुपी को शुरुआत में 8 सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ पेश किया गया था और तब से इसे और अधिक बैंकों तक बढ़ा दिया गया है। इसे UPI QR कोड के साथ इंटरऑपरेबल भी बनाया गया है।
सितंबर में, RBI ने CBDC के साथ UPI इंटरऑपरेबिलिटी के सफल समापन और कार्यान्वयन की घोषणा की।
वर्तमान फोकस ई-रुपया लेनदेन की मात्रा बढ़ाने पर है, जिसका लक्ष्य दैनिक लेनदेन को लगभग 15,000 से 1 मिलियन (10 लाख) तक बढ़ाना है।

वित्त वर्ष 2023 के दौरान भारत की घरेलू बचत 5 दशकों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में घरेलू बचत दशकों में अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है।
वित्तीय वर्ष 2023 (FY23) में, घरेलू बचत सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 5.1% थी।
यह FY22 में दर्ज 7.2% से एक महत्वपूर्ण गिरावट है।
वित्त वर्ष 2023 में परिवारों की वार्षिक वित्तीय देनदारियां बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 5.8% हो गईं, जबकि वित्त वर्ष 22 में यह 3.8% थी।
भारत में परिवारों की शुद्ध संपत्ति में गिरावट देखी गई है।
वित्त वर्ष 2011 में, ये संपत्तियाँ 22.8 ट्रिलियन रुपये थीं, लेकिन वित्त वर्ष 2012 में ये घटकर 16.96 ट्रिलियन रुपये हो गईं और वित्त वर्ष 2013 में और गिरकर 13.76 ट्रिलियन रुपये हो गईं।
RBI के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2012 में वित्तीय देनदारियों में वृद्धि की दर उल्लेखनीय रूप से ऊंची और आजादी के बाद दूसरी सबसे ऊंची थी।
गिरावट के कारक: बचत में कमी और उधारी में वृद्धि में योगदान देने वाले प्राथमिक कारकों में स्थिर या घटती घरेलू आय और बढ़ती मुद्रास्फीति शामिल हैं
वित्त मंत्रालय ने घरेलू बचत और अर्थव्यवस्था पर इसके समग्र प्रभाव को लेकर संकट की रिपोर्टों को खारिज कर दिया है।
इसने इस बात पर प्रकाश डाला है कि घरेलू बचत ने 2013-14 और 2021-22 के बीच 9.2% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) दिखाई है।
परिवारों ने वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष) 23 में पिछले वर्षों की तुलना में कम मात्रा में शुद्ध वित्तीय संपत्ति जोड़ी है क्योंकि उन्होंने अब घरों सहित वास्तविक संपत्ति खरीदने के लिए ऋण लेना शुरू कर दिया है।

इसके अतिरिक्त, अप्रैल, 2022 से वाहन ऋण में दोहरे अंक की वृद्धि देखी गई है।

वित्त मंत्रालय के बारे में:

कैबिनेट मंत्री: निर्मला सीतारमण
राज्य मंत्री: भागवत कराड, पंकज चौधरी

RBI ने वाणिज्यिक और माइक्रोफाइनेंस क्षेत्रों के लिए डेटा गुणवत्ता सूचकांक पेश किया

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने क्रेडिट सूचना कंपनियों (CIC) को वाणिज्यिक और माइक्रोफाइनेंस दोनों क्षेत्रों के लिए एक सामान्य डेटा गुणवत्ता सूचकांक (DQI) स्थापित करने का निर्देश दिया।
RBI ने आदेश दिया कि CIC को 31 मार्च, 2024 तक सभी क्रेडिट संस्थानों (CI) को वाणिज्यिक और माइक्रोफाइनेंस सेगमेंट के लिए DQI प्रदान करना चाहिए।

क्रेडिट सूचना कंपनियों (CIC) के बारे में:

CIC अन्य लोगों के अलावा ऋण और क्रेडिट कार्ड के संबंध में सार्वजनिक डेटा, क्रेडिट लेनदेन और व्यक्तियों और कंपनियों के भुगतान इतिहास एकत्र करते हैं।
उनका प्राथमिक कार्य विभिन्न स्रोतों, जैसे बैंकों, वित्तीय संस्थानों, ऋणदाताओं और अन्य क्रेडिट देने वाली संस्थाओं से डेटा इकट्ठा करना है, और फिर इस डेटा को क्रेडिट रिपोर्ट में संकलित करना है।
भारत में CIC को RBI द्वारा विनियमित किया जाता है और क्रेडिट सूचना कंपनी विनियमन अधिनियम, 2005 (CICRA) और अन्य RBI नियमों और विनियमों द्वारा शासित किया जाता है।
CICRA की धारा 15 के अनुसार, प्रत्येक क्रेडिट संस्थान (बैंकों की तरह) को कम से कम एक CIC का सदस्य होना आवश्यक है।
CIC अपने सदस्य क्रेडिट संस्थानों से जानकारी मांगने और प्राप्त करने के लिए अधिकृत हैं।
वर्तमान में, 4 क्रेडिट सूचना कंपनियों को RBI द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र दिया गया है।
ये कंपनियां हैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड (CIBIL), इक्विफैक्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, एक्सपीरियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और CRIF हाई मार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड।

क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड (CIBIL) के बारे में:

क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड (CIBIL)- यह RBI द्वारा लाइसेंस प्राप्त अग्रणी क्रेडिट ब्यूरो और CIC है।
बेसिक कार्यक्रम: अपने ग्राहकों के लिए क्रेडिट रिपोर्ट और क्रेडिट स्कोर तैयार करने और प्रदान करने के लिए ऋणदाताओं द्वारा प्रदान किए गए वित्तीय डेटा को एकत्र करना और बनाए रखना।
यह 600 मिलियन व्यक्तियों और 32 मिलियन व्यवसायों की क्रेडिट फाइलें रखता है।
सिबिल इंडिया एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय समूह ट्रांसयूनियन का हिस्सा है।
इसलिए, भारत में क्रेडिट स्कोर को CIBIL ट्रांसयूनियन स्कोर के रूप में जाना जाता है।
CIBIL तीन अंकों का संख्यात्मक सारांश प्रदान करता है जिसे क्रेडिट स्कोर के रूप में जाना जाता है, जो पिछले 36 महीनों में किसी व्यक्ति के क्रेडिट इतिहास को दर्शाता है।
क्रेडिट स्कोर का मूल्य 300 से 900 के बीच हो सकता है।
ऋणदाता आवेदकों को ऋण देने के जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए CIBIL रिपोर्ट और CIBIL स्कोर/CIBIL रैंक की जांच कर सकते हैं और तदनुसार नए ऋण/क्रेडिट कार्ड आवेदनों को स्वीकृत या अस्वीकार कर सकते हैं।

RBI के बारे में:

स्थापना: 1 अप्रैल 1935
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र, भारत
राज्यपाल: शक्तिकांत दास
उप राज्यपाल: महेश कुमार जैन, एम राजेश्वर राव, माइकल पात्रा और टी. रबी शंकर

RBI ने द कपोल को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाओं को लेकर द कपोल को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है।

"बैंक का जारी रहना उसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण है, बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा, और यदि बैंक को अपने बैंकिंग व्यवसाय को आगे जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो सार्वजनिक हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि सहकारी समितियों के अतिरिक्त सचिव और केंद्रीय रजिस्ट्रार, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार से भी बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है।

नतीजतन, बैंक 25 सितंबर, 2023 को कारोबार बंद होने से बैंकिंग व्यवसाय करना बंद कर देता है।

RBI ने कहा कि लाइसेंस रद्द करने के बाद, सहकारी बैंक को जमा स्वीकार करने और जमा का पुनर्भुगतान सहित बैंकिंग व्यवसाय संचालित करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि परिसमापन पर, प्रत्येक जमाकर्ता DICGC अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अधीन जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) से 5 लाख रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमा राशि की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।

विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 96.09 प्रतिशत जमाकर्ता DICGC से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।

"24 जुलाई, 2023 तक, DICGC ने बैंक के संबंधित जमाकर्ताओं से प्राप्त इच्छा के आधार पर DICGC अधिनियम, 1961 की धारा 18A के प्रावधानों के तहत कुल बीमाकृत जमा का 230.16 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही कर दिया है।"

सितंबर तिमाही में अफगानिस्तान की मुद्रा वैश्विक स्तर पर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली इकाई बनकर उभरी है

अफगानिस्तान की मुद्रा सितंबर तिमाही में दुनिया की सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली इकाई के रूप में उभरी है, विदेशी सहायता प्रवाह और अमेरिका द्वारा युद्धग्रस्त देश को धन जारी करने के बीच तीन महीने की अवधि के दौरान 9 प्रतिशत और इस साल अब तक 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

अब तालिबान शासित अफगानिस्तान की ज्यादातर कृषि अर्थव्यवस्था लगभग 30% गिर गई थी, और 16 अगस्त, 2021 को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले इसकी मुद्रा गिरकर 124.2 पर आ गई थी।

14 अगस्त को, स्थानीय मुद्रा ग्रीनबैक के मुकाबले 80.96 पर बोली गई।

विश्लेषक नाम नहीं बताना चाहते क्योंकि ब्रोकरेज अफगान मुद्रा को ट्रैक नहीं करता है क्योंकि वर्तमान अफगानिस्तान शासन ने डेटा साझा करना बंद कर दिया है।

विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, बेरोजगारी और विशाल बहुमत की घोर गरीबी में डूबी अर्थव्यवस्था अब अपस्फीति का सामना कर रही है।

विदेशी मुद्रा प्रवाह के कारण, अफगानी अगस्त की शुरुआत में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 85 से बढ़कर 31 अगस्त, 2023 को 73.38 तक पहुंच गया है, जो तालिबान के अधिग्रहण के बाद से अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है।

HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार, तब से सितंबर में यूनिट की चमक 6.5% कम हो गई है।

गिरावट के बावजूद, अफगानी सितंबर तिमाही में दुनिया भर में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा रही, इस तिमाही में 9 प्रतिशत और साल-दर-साल 14% की बढ़त हुई।

अफगानी बाज़ार में कोई तरलता नहीं है, और रैली एक बार होने वाली घटना होनी चाहिए और ऐसा नहीं लगता कि यह टिकेगी।

सिडबी ने फिनटेक-संचालित लघु ऋण वितरण के लिए DLAI के साथ सहयोग किया

डिजिटल लेंडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (DLAI) और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने ऋण देने में डिजिटल अपनाने को बढ़ावा देने और उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए नीतियां विकसित करने के लिए सहयोग करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
गोवा में DLAI द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में सिडबी और DLAI के बीच सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन (MoU) को औपचारिक रूप दिया गया।
सिडबी का इरादा DLAI के सदस्य फिनटेक के माध्यम से सूक्ष्म उद्यमों को अपने क्रेडिट उत्पादों के वितरण का पता लगाने का है।

मुख्य विचार:

DLAI के उद्योग आचार संहिता (COC) का नवीनतम संस्करण सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक शिवसुब्रमण्यम रमन ने एक कार्यक्रम में लॉन्च किया, जिसमें भारतीय फिनटेक उद्योग के शीर्ष 100 अधिकारियों ने भाग लिया।
COC का नया संस्करण आरबीआई के डिजिटल ऋण दिशानिर्देशों के आसपास संरचित है।
MoU में डिजिटल ऋण साझेदारी को अपनाने में तेजी लाने के लिए मानक प्रोटोकॉल विकसित करने के लिए DLAI और सिडबी के बीच सहयोग की परिकल्पना की गई है, जिसमें बैंकों और ऋण सेवा प्रदाताओं (LSP) के बीच गठबंधन, सह-उधार सहयोग और मॉडल साझेदारी समझौते विकसित करना शामिल है।
विकास संस्थान अनौपचारिक उद्यमों, सह-उधार, GST सहाय, एक्सप्रेस ऋण, हरित वित्तपोषण और अन्य प्रत्यक्ष ऋण योजनाओं सिडबी के लिए अपनी "प्रयास" योजना के लिए साझेदारी भी तलाशेगा।

सिडबी के बारे में:

स्थापित: 2 अप्रैल 1990
मुख्यालय: लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत
अध्यक्ष और MD: शिवसुब्रमण्यम रामन
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम वित्त कंपनियों के समग्र लाइसेंसिंग और विनियमन के लिए शीर्ष नियामक निकाय है।

IREDA ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

राज्य के स्वामित्व वाली भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (IREDA) और बैंक ऑफ महाराष्ट्र (BOM) ने भारत में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए एक प्रारंभिक समझौता किया है।
सहयोग का उद्देश्य देश भर में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विविध स्पेक्ट्रम के लिए सह-उधार और ऋण सिंडिकेशन को बढ़ावा देना और सुविधा प्रदान करना है।
अनुबंध के तहत, बैंक ऑफ महाराष्ट्र (BOM) के पास पेशकश के निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार IREDA द्वारा जारी बांड में निवेश करने का अवसर है।
MoU पर IREDA के महाप्रबंधक (तकनीकी सेवाएं), श्री भरत सिंह राजपूत और महाप्रबंधक (खुदरा और MSME क्रेडिट), बैंक ऑफ महाराष्ट्र, श्री राजेश सिंह ने IREDA के बिजनेस सेंटर, नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए।

MoU के बारे में:

IREDA और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बीच समझौता ज्ञापन (Mou) में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए कई प्रमुख सेवाएं शामिल हैं, जिनमें शामिल हैं:
सह-उधार और सह-उत्पत्ति सहायता।
ऋण सिंडिकेशन और हामीदारी सुविधा।
पारदर्शिता के लिए ट्रस्ट और प्रतिधारण खातों का प्रबंधन।
3-4 वर्षों में IREDA उधारों के लिए स्थिर निश्चित ब्याज दरें।
यह साझेदारी वित्तीय संस्थानों और सरकारी निकायों के एक साथ काम करने के महत्व को रेखांकित करती है।

यह संरेखण माननीय प्रधान मंत्री के निर्देशानुसार 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य का समर्थन करता है।
इस समझौते के तहत, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पेशकश के निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार IREDA द्वारा जारी बांड में निवेश कर सकता है।

इरेडा के बारे में:

स्थापना: 1987
मुख्यालय: नई दिल्ली, दिल्ली
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक: प्रदीप कुमार दास
IREDA का गठन भारत सरकार के तहत एक मिनी रत्न सरकार उद्यम के रूप में किया गया है और प्रशासनिक रूप से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

BoM के बारे में:

स्थापना: 1935
मुख्यालय: पुणे, महाराष्ट्र
प्रबंध निदेशक एवं CEO: श्री. एएस राजीव
टैगलाइन: वन फैमिली वन बैंक

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के बारे में:

कैबिनेट मंत्री: राज कुमार सिंह
राज्य मंत्री: भगवंत खुबा

परियोजनाएं REC और PNB ने 3 वर्षों में 55,000 करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के सह-वित्तपोषण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

REC लिमिटेड ने पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि संयुक्त रूप से कंसोर्टियम व्यवस्था के तहत बिजली क्षेत्र और बुनियादी ढांचा और रसद क्षेत्र में परियोजनाओं के वित्तपोषण की संभावना का पता लगाया जा सके।
आरईसी और पीएनबी अगले 3 वर्षों में 55,000 करोड़ रुपये की राशि के ऋण को सह-वित्त पोषित करने के लिए एक-दूसरे के साथ सहयोग करेंगे।
कार्यकारी निदेशक (इन्फ्रा एंड लॉजिस्टिक्स), REC, श्री टीएससी बोश और CGM (कॉर्पोरेट क्रेडिट डिवीजन), PNB, श्री राजीव ने गुरुग्राम, हरियाणा में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में, कंपनी 2030 तक हरित परियोजनाओं के लिए अपने ऋण पोर्टफोलियो को ₹3 ट्रिलियन तक विस्तारित करने की भी योजना बना रही है।

REC लिमिटेड के बारे में:

स्थापना: 25 जुलाई 1969
मुख्यालय: गुरुग्राम, हरियाणा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक: विवेक कुमार देवागन
REC लिमिटेड, पूर्व में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसमें से पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PFC) होल्डिंग कंपनी है, जो बदले में भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के स्वामित्व में है।
REC बिजली क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक ऋण और अन्य वित्त उत्पाद प्रदान करता है, जिसमें उत्पादन, ट्रांसमिशन, वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी स्टोरेज और ग्रीन हाइड्रोजन जैसी नई प्रौद्योगिकियां शामिल हैं।

PNB के बारे में:

स्थापना: 19 मई 1894
मुख्यालय: नई दिल्ली, दिल्ली

MD एवं CEO: अतुल कुमार गोयल
टैगलाइन: द नेम यू कैन बैंक अपॉन

पूनावाला फिनकॉर्प को इंडसइंड बैंक के साथ सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड साझेदारी के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली

पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड (जिसे पहले मैग्मा फिनकॉर्प के नाम से जाना जाता था), साइरस पूनावाला समूह द्वारा प्रवर्तित गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (NBFC) को इंडसइंड बैंक के साथ सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी मिल गई है।
कंपनी की योजना इस क्रेडिट कार्ड को 3 महीने के भीतर लॉन्च करने की है।
यह साझेदारी पूनावाला फिनकॉर्प को लचीले और बहुमुखी खुदरा ऋण के एक नए युग की शुरुआत करने में सक्षम बनाएगी।

सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड क्या हैं?

सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड एक विशेष व्यापारी और क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता के बीच आपसी साझेदारी का उत्पाद हैं।
साथ में, वे एक क्रेडिट कार्ड बनाते हैं जिस पर व्यापारी का लोगो होता है और ब्रांड-वफादार उपभोक्ताओं को व्यापारी-विशिष्ट लाभ प्रदान करता है।

पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड के बारे में:

मुख्यालय: पुणे, महाराष्ट्र, भारत
अध्यक्ष: अदार पूनावाला

इंडसइंड बैंक लिमिटेड के बारे में:

स्थापना: अप्रैल 1994
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र, भारत
MD और CEO: सुमंत कठपालिया
टैगलाइन: वी मेक यू फील रिचर

RBI ने बैंकों से SARFAESI अधिनियम से जुड़े उधारकर्ताओं की जानकारी प्रदर्शित करने को कहा

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने एक निर्देश जारी किया है जिसमें बैंकों को उन उधारकर्ताओं के बारे में सार्वजनिक रूप से जानकारी प्रदर्शित करने की आवश्यकता है जो वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन (SARFAESI) अधिनियम, 2002 से जुड़े हैं।
बैंकों को इन उधारकर्ताओं के बारे में विस्तृत जानकारी अपलोड करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें शाखा का नाम, राज्य, उधारकर्ता का नाम और पंजीकृत पता, गारंटर का विवरण (जहां लागू हो), बकाया ऋण राशि, परिसंपत्ति वर्गीकरण और परिसंपत्ति वर्गीकरण की तारीख सहित अन्य डेटा शामिल हैं।
कुछ बैंकरों ने कार्य की जटिलता के बारे में चिंता व्यक्त की है, विशेष रूप से RBI द्वारा निर्धारित 6 महीने की समय सीमा के भीतर 2002 से पहले का ऐतिहासिक डेटा अपलोड करने के बारे में।
यह निर्देश वाणिज्यिक बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (NBFC), आवास वित्त कंपनियों और परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों सहित कई वित्तीय संस्थानों पर लागू होता है।
RBI का यह कदम वित्तीय क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने के उसके व्यापक प्रयासों का हिस्सा है।

मुख्य विचार:

SARFAESI अधिनियम बैंकों और वित्तीय संस्थानों को बकाया ऋण की वसूली के लिए वाणिज्यिक या आवासीय संपत्तियों की नीलामी करने का अधिकार देता है, जब उधारकर्ता उन्हें चुकाने में विफल रहते हैं।
यह बैंकों को पुनर्प्राप्ति विधियों और पुनर्निर्माण के माध्यम से अपनी गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) को कम करने में सक्षम बनाता है।

वित्तीय संस्थानों को सर्कुलर जारी होने की तारीख से 6 महीने के भीतर ऐसे उधारकर्ताओं की पहली सूची अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करनी होगी।
इसके बाद, उन्हें मासिक आधार पर इस सूची को अपडेट करना होगा।

RBI के बारे में:

स्थापना: 1 अप्रैल 1935
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र, भारत
राज्यपाल: शक्तिकांत दास
उप राज्यपाल: महेश कुमार जैन, एम राजेश्वर राव, माइकल पात्रा और टी. रबी शंकर

RBI ने 3 सहकारी बैंकों - सारस्वत सहकारी बैंक, बेसिन कैथोलिक सहकारी बैंक, राजकोट नागरिक सहकारी बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियामक अनुपालन में कमियों के कारण 3 सहकारी बैंकों - सारस्वत सहकारी बैंक लिमिटेड, बेसिन कैथोलिक सहकारी बैंक लिमिटेड और राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है।

सारस्वत सहकारी बैंक पर जुर्माना:

मुंबई स्थित सारस्वत सहकारी बैंक लिमिटेड पर ₹23 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) के विभिन्न प्रावधानों और RBI के 'निदेशकों, उनके रिश्तेदारों और फर्मों/संस्थाओं को ऋण और अग्रिम जिसमें वे रुचि रखते हैं' के निर्देशों के उल्लंघन के लिए लगाया गया था।
बैंक ने एक उधारकर्ता कंपनी को ऋण सुविधा नवीनीकृत की, जबकि बैंक के एक निदेशक ने उधारकर्ता कंपनी में एक स्वतंत्र निदेशक का पद संभाला था।

बेसिन कैथोलिक सहकारी बैंक पर जुर्माना:

महाराष्ट्र के वसई में स्थित बेसिन कैथोलिक को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को ₹25 लाख का आर्थिक दंड मिला।
यह जुर्माना बीआर अधिनियम की धारा 20 के प्रावधानों के साथ-साथ धारा 56 के प्रावधानों और 'एक्सपोज़र नॉर्म्स और वैधानिक / अन्य प्रतिबंधों' पर आरबीआई के निर्देशों के उल्लंघन के लिए लगाया गया था।
बैंक ने अपने एक निदेशक और उसकी स्वामित्व वाली फर्म को कई असुरक्षित ऋण दिए।

राजकोट नागरिक सहकारी बैंक पर जुर्माना:

राजकोट में स्थित राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड को ₹13 लाख के मौद्रिक दंड का सामना करना पड़ा।
यह जुर्माना 'जमा पर ब्याज दर' पर आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने पर लगाया गया था।
बैंक उन सावधि जमाओं पर पात्र ब्याज का भुगतान करने में विफल रहा जो रविवार/छुट्टी या गैर-व्यावसायिक कार्य दिवस पर परिपक्व होती थीं और अगले कार्य दिवसों पर भुगतान की जाती थीं।
इसके अतिरिक्त, इसने उस अवधि के लिए परिपक्व अवैतनिक सावधि जमा पर पात्र ब्याज का भुगतान नहीं किया, जब वे बैंक के पास दावा न किए गए थे।

RBI कार्यों का उद्देश्य:

RBI की कार्रवाई विनियामक अनुपालन में पहचानी गई कमियों के आधार पर की गई थी और इसका उद्देश्य बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता निर्धारित करना नहीं था।

RBI ने भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (आई) और 51 (1) के साथ भारतीय रिजर्व बैंक में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 3 बैंकों अर्थात भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया है।

SBI पर जुर्माना:

RBI ने 'ऋण और अग्रिम - वैधानिक और अन्य प्रतिबंधों' और 'अंतर-समूह लेनदेन और एक्सपोजर के प्रबंधन पर

दिशानिर्देशों' पर आरबीआई द्वारा जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक (बैंक) पर 1.30 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया।
वित्त वर्ष 2011 के लिए बैंकों के वैधानिक निरीक्षण में, यह पाया गया कि उन्होंने परियोजनाओं की व्यवहार्यता और बैंक योग्यता पर उचित परिश्रम किए बिना एक निगम को सावधि ऋण स्वीकृत किया था।
SBI ने 'इंट्रा-ग्रुप लेनदेन और एक्सपोजर के प्रबंधन' पर मानदंडों का भी उल्लंघन किया।

इंडियन बैंक पर जुर्माना:

RBI ने 'ऋण और अग्रिम - वैधानिक और अन्य प्रतिबंध', 'भारतीय रिजर्व बैंक [अपने ग्राहक को जानें (KYC)] निर्देश, 2016' और 'भारतीय रिजर्व बैंक (जमा पर ब्याज दर) निर्देश, 2016' पर RBI द्वारा जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए इंडियन बैंक (बैंक) पर 1.62 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया।

पंजाब एंड सिंध बैंक पर जुर्माना:

RBI ने पंजाब एंड सिंध बैंक (बैंक) पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 26 ए की उप-धारा (2) के प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए 1.00 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया, जिसे RBI द्वारा 'जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014-बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26 ए- परिचालन दिशानिर्देश' पर जारी निर्देशों के साथ पढ़ा गया है।
RBI ने NBFC (रिज़र्व बैंक) दिशा-निर्देश, 2016 में निगरानी धोखाधड़ी के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए मुंबई, महाराष्ट्र में एक गैर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज पर 8.80 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना भी लगाया।

वर्ल्डलाइन ने 2023 की पहली छमाही के लिए भारत डिजिटल भुगतान रिपोर्ट का अनावरण किया

Worldline भुगतान सेवाओं में वैश्विक नेता, ने 2023 की पहली छमाही (जनवरी से जून 2023) के लिए अपनी भारत डिजिटल भुगतान रिपोर्ट जारी की है, जो डिजिटल भुगतान परिदृश्य में महत्वपूर्ण रुझानों की जानकारी प्रदान करती है।
रिपोर्ट यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) की निरंतर सफलता पर प्रकाश डालती है और उम्मीद करती है कि यह भारतीय डिजिटल भुगतान क्षेत्र में अपना प्रभुत्व बनाए रखेगा।

मुख्य विचार:

रिपोर्ट से पता चलता है कि जनवरी 2018 में UPI लेनदेन की संख्या जो 151 मिलियन थी, जून 2023 में 9.3 बिलियन तक पहुंच गई है, जो मुख्य रूप से पर्सन-टू-मर्चेंट (पी2एम) लेनदेन में वृद्धि से प्रेरित है।
जनवरी 2022 में, पी2एम लेनदेन का हिस्सा सभी UPI लेनदेन का 40.3% था, जबकि जून 2023 में यह 57.5% था और इस प्रतिशत के बढ़ने की उम्मीद है।
वर्ल्डलाइन इंडिया के लिए 2022 में भौतिक टचप्वाइंट पर सबसे अधिक लेनदेन वाले शीर्ष 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, दिल्ली, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल थे।

शीर्ष UPI ऐप्स, प्रेषक और लाभार्थी बैंक:

वॉल्यूम और वैल्यू के मामले में 3 UPI ऐप्स का दबदबा; PhonePe, Google Pay और Paytm।
लेन-देन की मात्रा के संदर्भ में, जून 2023 में, 3 ऐप्स का सभी लेन-देन में 95.68% हिस्सा था, जबकि एक साल पहले यह 94.55% था।
लेनदेन मूल्य के संदर्भ में, जून 2022 में 93.38% की तुलना में जून 2023 में 3 का हिस्सा 93.65% था।
PhonePe का दबदबा कायम है और यह UPI लेनदेन के लिए बाजार में अग्रणी बना हुआ है, क्योंकि कुल मूल्य के मामले में अकेले इसकी बाजार हिस्सेदारी जून 2023 में 49.8% थी।
जून 2023 में 3,266.8 मिलियन लेनदेन के साथ Google Pay ने अपना दूसरा स्थान बरकरार रखा, इसके बाद 1,197.3 मिलियन लेनदेन के साथ Paytm दूसरे स्थान पर रहा।

क्रेडिट, डेबिट और प्रीपेड कार्ड:

पिछले 18 महीनों में प्रचलन में कार्डों की कुल संख्या में मामूली वृद्धि देखी गई है। जून 2023 में, कार्डों की कुल संख्या 1376

बिलियन थी, जो साल-दर-साल 9% की वृद्धि है।
जून 2023 में क्रेडिट कार्ड की संख्या 88.68 मिलियन, 975.8 मिलियन डेबिट कार्ड और 312.1 प्रीपेड कार्ड थी
क्रेडिट कार्ड के शीर्ष 5 जारीकर्ता क्रमशः HDFC, SBI, ICICI, एक्सिस और कोटक हैं और डेबिट कार्ड के शीर्ष 5 जारीकर्ता SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, HDFC और बैंक ऑफ इंडिया हैं।

वर्ल्डलाइन के बारे में:

मुख्यालय: बेज़ोन्स, फ्रांस
अध्यक्ष एवं CEO: गाइल्स ग्रेपिनेट

HDFC सिक्योरिटीज ने सभी निवेशकों और व्यापारियों के लिए ऑल-इन-वन डिस्काउंट ब्रोकिंग ऐप 'HDFC स्काई' लॉन्च किया

HDFC सिक्योरिटीज लिमिटेड ने "HDFC स्काई" नामक एक डिस्काउंट ब्रोकिंग ऑल-इन-वन मोबाइल ऐप पेश किया है। ऐप को सभी अनुभव स्तरों के निवेशकों और व्यापारियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया हैवित्तीय बाज़ारों में भाग लेने और अपने वित्तीय उद्देश्यों को प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए एक सहज अनुभव प्रदान करें।

HDFC स्काई के बारे में:

HDFC स्काई एक सरल और समान मूल्य निर्धारण संरचना को अपनाता है, जिसमें विभिन्न बाजार क्षेत्रों में इंट्राडे और डिलीवरी दोनों ट्रेडों के लिए ₹20 की एक समान दर होती है।
यह सीधा मूल्य निर्धारण दृष्टिकोण व्यापारियों के लिए लागत गणना को सरल बनाता है
ऐप 12% निर्धारित दर के साथ मार्जिन ट्रेडिंग सुविधा (MTF) प्रदान करता है, जो अपने निवेश का लाभ उठाने के इच्छुक व्यापारियों के लिए फायदेमंद हो सकता है।
HDFC स्काई पहले वर्ष के लिए शून्य खाता खोलने और रखरखाव शुल्क का लाभ प्रदान करता है।
यह इसे उपयोगकर्ताओं के लिए लागत प्रभावी बना सकता है।
HDFC स्काई, कई ट्रेडिंग ऐप्स की तरह, सभी निवेशकों और व्यापारियों के लिए खुला है, HDFC सिक्योरिटीज के विपरीत जो केवल एचडीएफसी बैंक के ग्राहकों के लिए है।

HDFC सिक्योरिटीज लिमिटेड के बारे में:

स्थापना: 2000
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र
MD एवं CEO: धीरज रेली
HDFC सिक्योरिटीज लिमिटेड भारत के अग्रणी वित्तीय प्रतिष्ठान, HDFC बैंक की सहायक कंपनी है।

RBI ने वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी छमाही के लिए सरकार के लिए अर्थोपाय अग्रिम (WMA) सीमा ₹50,000 करोड़ निर्धारित की

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्तीय वर्ष 2023-24 की दूसरी छमाही (अक्टूबर-मार्च) के लिए सरकार के लिए अर्थोपाय अग्रिम (WMA) की सीमा ₹50,000 करोड़ निर्धारित की है।
RBI बाजार ऋण जारी करने की शुरुआत तब करता है जब सरकार डब्ल्यूएमए सीमा का 75% उपयोग करती है।
ऐसा वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए किया जाता है

मुख्य विचार:

WMA पर ब्याज दरें: RBI प्रचलित रेपो दर को वेज एंड मीन्स एडवांस पर ब्याज के रूप में लेता है।
WMA सीमा से अधिक ओवरड्राफ्ट के लिए, रेपो दर से 2% अधिक ब्याज दर लागू होती है।
WMA का उद्देश्य: WMA भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेष विशेषता के रूप में कार्य करता है, जो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को उनकी प्राप्तियों और भुगतानों में किसी भी वित्तीय विसंगति को दूर करने के लिए RBI द्वारा अस्थायी अग्रिम प्रदान करता है।

WMA के बारे में:

इसे 1997 में पेश किया गया था और यह आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 17(5) के अंतर्गत आता है।
इसे केंद्र सरकार के घाटे को पूरा करने के लिए तदर्थ राजकोष बिल की चार दशक पुरानी प्रणाली को समाप्त करने के लिए पेश किया गया था।
इसे जरूरत पड़ने पर सरकार को तत्काल नकद सहायता प्रदान करने, घाटे को प्रबंधित करने और सुचारू वित्तीय संचालन सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।
सरकार को 90 दिनों के भीतर राशि चुकानी होगी।

व्यापार

ONGC 2038 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लिए 2 ट्रिलियन रुपये का निवेश करेगी

राज्य के स्वामित्व वाली ओएनजीसी ने 2038 तक अपने ऊर्जा परिवर्तन प्रयासों के लिए लगभग ₹2 ट्रिलियन का निवेश करने की योजना बनाई है।
कंपनी ने ऊर्जा संक्रमण पहल पर अगले 7 वर्षों में ₹1 ट्रिलियन का निवेश करने की अपनी योजना की घोषणा की थी।
इसने 2038 तक स्कोप 1 और स्कोप 2 बदलाव की घोषणा की।
इसके लिए ₹2 ट्रिलियन की आवश्यकता है जिसमें 2030 तक ₹1 ट्रिलियन का निवेश (निवेश) किया जाएगा और इसके विभिन्न भाग हैं।
मुख्य रूप से प्रारंभिक व्यय पहले स्कोप 1 को कम करने के लिए होगा और फिर हम स्कोप 2 पर जाते हैं और इसलिए दो भाग हैं।

मुख्य विचार

कंपनी हरित अमोनिया, हाइड्रोजन, सौर और अपतटीय पवन सहित कई हरित परियोजनाओं में निवेश करने की योजना बना रही है।
कंपनी के पास फिलहाल नवीकरणीय स्रोतों से बिजली पैदा करने की 189 मेगावाट क्षमता है।
इसका लक्ष्य 2030 तक 10 गीगावॉट का है।
कंपनी ने पहले ही राजस्थान में 5 गीगावॉट के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और समान आकार की परियोजनाओं की तलाश कर रही है।
इसके अलावा, यह 25 संपीड़ित बायोगैस संयंत्र स्थापित करना चाहता है जो कृषि-अवशेषों को गैस में परिवर्तित करेंगे जिनका उपयोग ऑटोमोबाइल (CNG) चलाने के लिए किया जा सकता है या उद्योगों में बिजली और उर्वरक उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।
ONGC 2 ग्रीन-फील्ड ऑयल-टू-केमिकल (O2C) संयंत्र स्थापित करने की भी योजना बना रही है।
पेट्रोकेमिकल कच्चे तेल से प्राप्त रासायनिक उत्पाद हैं और इनका उपयोग डिटर्जेंट, फाइबर (पॉलिएस्टर, नायलॉन, ऐक्रेलिक आदि), पॉलिथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक के निर्माण में किया जाता है।
फर्म के पास पहले से ही 2 सहायक कंपनियां हैं, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड और ओएनजीसी पेट्रो-एडिशंस लिमिटेड जो क्रमशः कर्नाटक के मैंगलोर और गुजरात के दाहेज में पेट्रोकेमिकल इकाइयां चलाती हैं।

ONGC के बारे में:

तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के स्वामित्व में एक भारतीय केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।
कंपनी का मुख्यालय नई दिल्ली में है।
ONGC की स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुई थी।
अरुण कुमार सिंह (अध्यक्ष एवं CEO)।

नवीनतम समाचार

जुलाई, 2023 में एअपने रिश्वत-विरोधी प्रबंधन प्रणाली (ABMS) के लिए प्रमाणन अर्जित करने वाला भारत का पहला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSE), तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) ने इतिहास रच दिया।
मई 2023 में, राज्य के स्वामित्व वाली तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) ने मुंबई अपतटीय क्षेत्र के 2 ब्लॉकों में कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस पाया था।

आठ प्रमुख उद्योगों का संयुक्त सूचकांक जुलाई 2022 के सूचकांक की तुलना में जुलाई 2023 में 8.0% (अनंतिम) बढ़ गया

आठ प्रमुख उद्योगों (ICI) का संयुक्त सूचकांक जुलाई 2022 के सूचकांक की तुलना में जुलाई 2023 में 8.0 प्रतिशत (अनंतिम) बढ़ गया।
कोयला, इस्पात, प्राकृतिक गैस, सीमेंट, बिजली, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक और कच्चे तेल का उत्पादन जुलाई 2023 में पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में बढ़ गया।
ICI आठ प्रमुख उद्योगों अर्थात कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली के उत्पादन के संयुक्त और व्यक्तिगत प्रदर्शन को मापता है।
आठ कोर उद्योगों में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में शामिल वस्तुओं का 40.27 प्रतिशत हिस्सा शामिल है।
अप्रैल 2023 के लिए आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक की अंतिम वृद्धि दर को इसके अनंतिम स्तर 3.5 प्रतिशत से संशोधित कर 4.6 प्रतिशत कर दिया गया है।
अप्रैल से जुलाई, 2023-24 के दौरान ICI की संचयी वृद्धि दर पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 6.4 प्रतिशत (अनंतिम) दर्ज की गई।

आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक का सारांश नीचे दिया गया है

कोयला - कोयला उत्पादन (भारांक: 10.33 प्रतिशत) जुलाई, 2023 में जुलाई, 2022 की तुलना में 14.9 प्रतिशत बढ़ गया। अप्रैल से जुलाई, 2023-24 के दौरान इसका संचयी सूचकांक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 10.1 प्रतिशत बढ़ गया।
कच्चा तेल - कच्चे तेल का उत्पादन (भारांक: 8.98 प्रतिशत) जुलाई, 2023 में जुलाई, 2022 की तुलना में 2.1 प्रतिशत बढ़ गया। अप्रैल से जुलाई, 2023-24 के दौरान इसका संचयी सूचकांक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 1.0 प्रतिशत कम हो गया।
प्राकृतिक गैस - प्राकृतिक गैस उत्पादन (भारांक: 6.88 प्रतिशत) जुलाई, 2023 में जुलाई, 2022 की तुलना में 8.9 प्रतिशत बढ़ गया। अप्रैल से जुलाई, 2023-24 के दौरान इसका संचयी सूचकांक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 2.3 प्रतिशत बढ़ गया।
पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद - पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादन (भारांक: 28.04 प्रतिशत) जुलाई, 2023 में जुलाई, 2022 की तुलना में 3.6 प्रतिशत बढ़ गया। अप्रैल से जुलाई, 2023-24 के दौरान इसका संचयी सूचकांक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 2.3 प्रतिशत बढ़ गया।
उर्वरक - उर्वरक उत्पादन (भारांक: 2.63 प्रतिशत) जुलाई, 2023 में जुलाई, 2022 की तुलना में 3.3 प्रतिशत बढ़ गया। अप्रैल से जुलाई, 2023-24 के दौरान इसका संचयी सूचकांक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 9.1 प्रतिशत बढ़ गया।
इस्पात - इस्पात उत्पादन (भारांक: 17.92 प्रतिशत) जुलाई, 2023 में जुलाई, 2022 की तुलना में 13.5 प्रतिशत बढ़ गया। अप्रैल से जुलाई, 2023-24 के दौरान इसका संचयी सूचकांक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 15.3 प्रतिशत बढ़ गया।
सीमेंट - सीमेंट उत्पादन (भारांक: 5.37 प्रतिशत) जुलाई, 2023 में जुलाई, 2022 की तुलना में 7.1 प्रतिशत बढ़ गया। अप्रैल से जुलाई, 2023-24 के दौरान इसका संचयी सूचकांक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 11.2 प्रतिशत बढ़ गया।
बिजली - बिजली उत्पादन (भारांक: 19.85 प्रतिशत) जुलाई, 2023 में जुलाई, 2022 की तुलना में 6.9 प्रतिशत बढ़ गया। अप्रैल से जुलाई, 2023-24 के दौरान इसका संचयी सूचकांक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 2.7 प्रतिशत बढ़ गया।

Click Here to Subscribe Our Yearly Mock Test Package

नवीनतम समाचार

मार्च 2022 के सूचकांक की तुलना में मार्च 2023 में आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में 3.6% की वृद्धि हुई।

Viacom18 ने ₹5,963 करोड़ के सौदे में BCCI टीवी और डिजिटल अधिकार हासिल किए

रिलायंस समर्थित Viacom18 ने ₹5,963 करोड़ के पांच साल के सौदे में BCCI टीवी और डिजिटल अधिकार हासिल किए हैं।
इससे वायाकॉम की OTT बोली और मजबूत हो गई, जिससे काउंटर पर डिज़्नी स्टार का डिजिटल वर्चस्व कम हो गया।
क्रिकेट संस्था ने भारत के घरेलू क्रिकेट प्रसारण के लिए टीवी और डिजिटल अधिकारों की नीलामी की।

मुख्य विचार:

IPL मीडिया अधिकार नीलामी की तरह, BCCI ने क्रिकेट घरेलू मैचों के टीवी और डिजिटल अधिकारों की अलग से नीलामी की।
भारत के तीन सबसे बड़े प्रसारकों, सोनी, डिज़्नी स्टार और वायाकॉम18 ने अधिकार जीतने के लिए कड़ा संघर्ष किया।
अपनी विजयी बोली के साथ, Viacom18 ने डिज़्नी स्टार द्वारा पिछले चक्र के प्रति मैच भुगतान किए गए ₹60 करोड़ से लगभग ₹7.76 करोड़ अधिक का भुगतान किया है।
क्रिकेट निकाय ने द्विपक्षीय अधिकारों के लिए आधार मूल्य ₹45 करोड़ प्रति मैच निर्धारित किया था।
वायाकॉम की बोली से BCCI को उनकी मांगी गई कीमत से 13 प्रतिशत अधिक प्रीमियम मिलता है।

नवीनतम समाचार

मई 2023 में, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड-नियंत्रित Viacom18 ने वार्नर ब्रदर्स के साथ तीन साल का करार किया है।
जून में, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने चेतन शर्मा की जगह अजीत अगरकर को सीनियर पुरुष चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया।
मार्च 2023 में, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भारतीय क्रिकेट टीम के किट प्रायोजक के रूप में जर्मन स्पोर्ट्सवियर प्रमुख एडिडास को शामिल किया है।

BCCI के बारे में:

स्थापना: दिसंबर 1928
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र, भारत
अध्यक्ष: रोजर बिन्नी
BCCI भारत में क्रिकेट की राष्ट्रीय शासी निकाय है।

Viacom18 के बारे में

Viacom18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड एक मुंबई स्थित मीडिया कंपनी है; यह नेटवर्क18 ग्रुप-रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी और पैरामाउंट ग्लोबल के बीच एक संयुक्त उद्यम है।
इसकी स्थापना 2007 में हुई थी और यह भारत में विभिन्न चैनलों के साथ-साथ कंटेंट प्रोडक्शन स्टूडियो का मालिक है।
CEO: ज्योति एस देशपांडे
स्थापित: नवंबर 2007

कृषि और वित्तीय क्षेत्रों ने अप्रैल-जून तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को 7.8% तक बढ़ा दिया है

सांख्यिकी कार्यालय ने बताया कि कृषि और वित्तीय क्षेत्रों के अच्छे प्रदर्शन ने वित्तीय वर्ष 2023-24 (Q1FY24) की अप्रैल-जून तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था को 7.8 प्रतिशत की वृद्धि करने में मदद की।
हालांकि सरकार गति को लेकर आशावादी है, लेकिन विशेषज्ञ इससे सहमत नहीं हैं।
GDP (सकल घरेलू उत्पाद) पर आधारित आर्थिक वृद्धि दर अप्रैल-जून तिमाही 2022-23 के दौरान 13.1 प्रतिशत और पिछले वित्त वर्ष (FY23) की जनवरी-मार्च तिमाही के दौरान 6.1 प्रतिशत थी।

मुख्य विचार

सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत के कृषि क्षेत्र में तीन महीनों में 3.5% की वृद्धि दर्ज की गई, जो पिछले साल अप्रैल-जून तिमाही में 2.4% थी।
वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाओं में वृद्धि 12.2% थी, जो पिछले साल अप्रैल-जून में 8.5% थी।
हालाँकि, आंकड़ों से पता चलता है कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि घटकर 4.7% रह गई, जबकि एक साल पहले यह 6.1% थी। भारत का वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च तक चलता है।
अप्रैल-जून तिमाही में खनन, बिजली, गैस, जल आपूर्ति और निर्माण में उत्पादन भी धीमा हो गया।
हालाँकि, विश्व बैंक ने कहा कि लगातार प्रतिकूल परिस्थितियों - बढ़ती उधार लागत, कड़ी वित्तीय स्थितियाँ और चल रहे मुद्रास्फीति दबाव - का इस वर्ष भारत की वृद्धि पर असर पड़ने की उम्मीद है।

नवीनतम समाचार

जुलाई 2023 में, RBI की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार, वैश्विक कमोडिटी और खाद्य कीमतों में नरमी और अच्छी रबी फसल की संभावनाओं के बीच, 2023-24 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि वित्त वर्ष 2024 के लिए 6.5% रहने का अनुमान है।
अप्रैल 2023 में, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MOSPI) के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने जनवरी से मार्च 2022-23 (Q4 2022-23) की अवधि के लिए सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के त्रैमासिक अनुमानों के साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमान (पीई) जारी किए।
जून 2023 में, वैश्विक क्रेडिट रेटिंग प्रमुख मूडी ने अनुमान लगाया कि जून तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में 6-6.3% की वृद्धि होने की उम्मीद है, और चालू वित्त वर्ष में उम्मीद से कम सरकारी राजस्व से उत्पन्न होने वाले राजकोषीय फिसलन के जोखिमों को चिह्नित किया।

अगस्त में भारत का कोयला उत्पादन 12.85% बढ़कर 67.65 मिलियन टन हो गया

कोयला उत्पादन देश में इस साल अगस्त महीने में 12.85 प्रतिशत बढ़कर 67.65 मिलियन टन हो गया, जबकि पिछले साल के इसी महीने में यह 59.95 मिलियन टन था।
कोयला मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उसने अगस्त 2023 के दौरान कुल कोयला उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हासिल की है। इसमें यह भी कहा गया है कि कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) का उत्पादन 13.21 प्रतिशत की वृद्धि के साथ अगस्त 2022 में 46.17 मिलियन टन की तुलना में अगस्त 2023 में 52.27 मिलियन टन हो गया है।
अगस्त 2023 तक संचयी कोयला उत्पादन भी चालू वित्त वर्ष के दौरान लगभग 349 मिलियन टन तक बढ़ गया है, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान यह 316 मिलियन टन से अधिक था।

CIL के बारे में:

कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) कोयला मंत्रालय के स्वामित्व में एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।

अप्रैल-जुलाई 2023 में केंद्र का राजकोषीय घाटा बजट अनुमान का 34% तक बढ़ गया

अग्रिम करचालू वित्त वर्ष (2023-24) की अप्रैल-जुलाई अवधि के दौरान हस्तांतरण और उच्च व्यय ने केंद्र के राजकोषीय घाटे को 6.1 लाख करोड़ रुपये या बजट अनुमान का 34 प्रतिशत तक पहुंचा दिया।
यह पिछले वित्त वर्ष से करीब 78 फीसदी ज्यादा है
पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में घाटा ₹3.4 लाख करोड़ या बजट अनुमान का 20.5 प्रतिशत था।
महालेखा नियंत्रक (CGA) द्वारा अपनी वेबसाइट पर डाले गए आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-जुलाई की अवधि के दौरान केंद्र द्वारा करों के हिस्से के हस्तांतरण के रूप में राज्य सरकारों को 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक हस्तांतरित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 1.08 लाख करोड़ रुपये अधिक है। 15 वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर, केंद्र के कर राजस्व का 41% 28 राज्यों को दिया जाता है।

शुद्ध-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने के लिए IOC ने ₹2.4 लाख करोड़ की योजना बनाई है

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) 2046 तक अपने शुद्ध-शून्य परिचालन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगभग ₹2.4 लाख करोड़ खर्च करने की योजना है।
इंडियन ऑयल कच्चे तेल को परिष्कृत करने और ईंधन में बदलने की क्षमता बढ़ाने में 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगा और परियोजनाओं में 2.4 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेगा जो उसे अपने परिचालन से शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने में मदद करेगा।
ओडिशा के पारादीप में एक विशाल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स स्थापित करने के लिए 60,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना है।
विस्तार में तमिलनाडु के नागापट्टिनम में 9 मिलियन टन प्रति वर्ष की नई तेल रिफाइनरी शामिल है।
इसके साथ ही, यह पेट्रोकेमिकल एकीकरण पर भी काम कर रहा है, जो कच्चे तेल को रसायनों में परिवर्तित करने में मदद करेगा जो प्लास्टिक से लेकर पेंट और सौंदर्य प्रसाधनों तक विभिन्न उत्पादों के लिए ब्लॉक बन रहे हैं।
कंपनी मौजूदा प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों को हाइड्रोजन परिवहन के लिए परिवर्तित करने की संभावना तलाशने के लिए इटली की स्नैम के साथ सहयोग कर रही है।
LPG में, इसने एक अद्वितीय QR कोड-आधारित 'ट्रैक एन ट्रेस' पायलट पहल शुरू की है।
उन्होंने कहा कि इंडियन ऑयल पानीपत रिफाइनरी में 10 किलो टन प्रति वर्ष का हरित हाइड्रोजन संयंत्र विकसित कर रहा है, कंपनी पानीपत में 86.8 हजार टन प्रति वर्ष क्षमता का एक सतत विमानन ईंधन (या SAF) संयंत्र भी स्थापित कर रही है।

IOCL के बारे में:

मुख्यालय: नई दिल्ली
स्थापना: 30 जून 1959
अध्यक्ष: श्रीकांत माधव वैद्य

नवीनतम समाचार

जून 2023 में, टेस्ला पावर यू.एस.ए ने सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी के पेट्रोल पंपों पर बैटरी बेचने और सर्विस करने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) के साथ एक समझौता किया है।
जुलाई 2023 में, रूसी ऊर्जा दिग्गज रोसनेफ्ट ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) के पूर्व निदेशक गोविंद कोट्टिएथ सतीश को अपने बोर्ड में नियुक्त किया।

TCS ने जीवन बीमा कंपनी एथोरा नीदरलैंड के साथ अनुबंध बढ़ाया

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने ग्राहक अनुभव, परिचालन लचीलापन और व्यावसायिक चपलता को बढ़ाने के लिए बेहतर आईटी ऑपरेटिंग मॉडल के साथ डच जीवन बीमा और पेंशन प्रदाता की मदद करने के लिए एथोरा नीदरलैंड्स (पूर्व में VIVAT) के साथ अपनी दीर्घकालिक साझेदारी का विस्तार किया है।
यह भारतीय आईटी सेवा प्रमुख के लिए एक बहु-वर्षीय सौदा होगा, जो इसे अनिश्चित मांग के माहौल के बीच अपने साथियों पर बढ़त देगा।
कंपनी ने सौदे के आकार या अवधि का खुलासा नहीं किया।
TCS ने सबसे पहले 2015 में एथोरा नीदरलैंड्स, जो उस समय VIVAT था, के साथ काम करना शुरू किया।
नवीनतम विस्तार के साथ, आईटी खिलाड़ी एक अग्रणी केंद्रित पेंशन और जीवन बीमा कंपनी बनने के लिए एथोरा नीदरलैंड के "एम्बिशन 2025" कार्यक्रम में योगदान देगा।
अनुबंध के हिस्से के रूप में, टीसीएस कंपनी के लिए एक हाइब्रिड क्लाउड आर्किटेक्चर स्थापित करेगी और एथोरा की जीवन बीमा पॉलिसियों की बंद किताब के लिए पॉलिसी सर्विसिंग, क्लेम हैंडलिंग और ग्राहक सेवा में फर्म के एंड-टू-एंड बिजनेस और आईटी संचालन को स्वचालित और प्रबंधित करेगी।

नीदरलैंड के बारे में:

राजधानी: एम्स्टर्डम
मुद्रा - यूरो

TCS के बारे में:

स्थापित: 1968
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र, भारत
अध्यक्ष: नटराजन चन्द्रशेखरन
MD और CEO: राजेश गोपीनाथन
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा संस लिमिटेड का एक प्रभाग, एक वैश्विक आईटी सेवा संगठन है जो विभिन्न उद्योगों में अपने ग्राहकों को आईटी सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है।

नवीनतम समाचार

जुलाई 2023 में, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) घोषणा की गई कि स्वीडन में इकानो बैंक एबी ने अपने पैन-यूरोप कोर बैंकिंग परिवर्तन के लिए TCS BANCS ग्लोबल बैंकिंग सास प्लेटफॉर्म का चयन किया है।
जून 2023 में, के. कृतिवासन ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी (IT) सेवा कंपनी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के नए प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के रूप में कार्यभार संभाला।

CCI ने भारती एयरटेल पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 6(2) के प्रावधानों का पालन करने में विफलता के लिए भारती एयरटेल पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
जुर्माना कंपनी द्वारा भारती टेलीमीडिया में वारबर्ग पिंकस की सहयोगी इकाई लायन मीडो इन्वेस्टमेंट लिमिटेड से हिस्सेदारी के अधिग्रहण से संबंधित है।
मार्च 2021 में, भारती एयरटेल ने अपनी DTH शाखा भारती टेलीमीडिया में लायन मीडो इन्वेस्टमेंट लिमिटेड से 20% हिस्सेदारी कुल 3,126 करोड़ रुपये में वापस खरीदी।
लायन मीडो ने दिसंबर 2017 में भारती टेलीमीडिया में 20% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया।
भारती एयरटेल लिमिटेड, जिसे आमतौर पर एयरटेल के नाम से जाना जाता है, नई दिल्ली में स्थित एक भारतीय बहुराष्ट्रीय दूरसंचार सेवा कंपनी है।

नवीनतम समाचार

जुलाई 2023 में, सरकार ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के महानिदेशक के रूप में अतुल वर्मा का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया।
अप्रैल 2023 में, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने जनरल अटलांटिक सिंगापुर एसीके पीटीई लिमिटेड (GASAC) को एको टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एको टेक) में अतिरिक्त हिस्सेदारी हासिल करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी।
जून 2023 में, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड (MHEPL) और मणिपाल एजुकेशन एंड मेडिकल ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (MEMG इंडिया) से जुड़े प्रस्तावित सौदे को मंजूरी दे दी।
जून 2023 में, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने दाइवा इंटरनेशनल होल्डिंग्स इंक (अधिग्रहणकर्ता) द्वारा एंबिट प्राइवेट लिमिटेड (लक्ष्य) में कुछ शेयरधारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी।

CCI के बारे में:

स्थापना: 14 अक्टूबर 2003
मुख्यालय: नई दिल्ली
अध्यक्ष: रवनीत कौर
CCI भारत में मुख्य राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नियामक है।
यह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है।
सीसीआई विभिन्न प्रतिस्पर्धा-विरोधी मामलों की जांच कर रही है, जिनमें प्रौद्योगिकी कंपनियों से संबंधित मामले भी शामिल हैं।

अमेज़ॅन एशिया-प्रशांत क्षेत्र में प्रकृति-आधारित परियोजनाओं में $15 मिलियन का निवेश करेगा

अमेज़ॅन ने एशिया-प्रशांत (APAC) क्षेत्र में प्रकृति-आधारित समाधानों के लिए $ 15 मिलियन के आवंटन की घोषणा की है। यह फंड भारत में परियोजनाओं में प्रारंभिक $3 मिलियन का निवेश करेगा, जिसकी शुरुआत पश्चिमी घाट में 300,000 पेड़ लगाने की पहली परियोजना से होगी।

यह आवंटन अमेज़न के 100 मिलियन डॉलर के राइट नाउ क्लाइमेट फंड से लिया गया है, जो 2019 में प्रकृति संरक्षण और पुनर्स्थापन परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए बनाया गया था, जो उन समुदायों में सामाजिक और पर्यावरणीय लाभ पहुंचाते हुए जलवायु लचीलापन और जैव विविधता को बढ़ाते हैं जहां वे काम करते हैं।

मुख्य विचार

फंड के APAC आवंटन से पहले $3 मिलियन भारत में प्रकृति-आधारित परियोजनाओं का समर्थन करेंगे।

अपने पहले प्रोजेक्ट के लिए, अमेज़ॅन पश्चिमी घाट में समुदायों और संरक्षण प्रयासों का समर्थन करने के लिए सेंटर फॉर वाइल्डलाइफ स्टडीज (CWS) के साथ काम करेगा, जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जो भारत की सभी वन्यजीव प्रजातियों में से 30 प्रतिशत से अधिक का घर है। जिसमें जंगली एशियाई हाथियों और बाघों की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी शामिल है।

अमेज़ॅन की $1 मिलियन की फंडिंग से CWS को "वाइल्ड कार्बन" कार्यक्रम स्थापित करने में मदद मिलेगी, जो 10,000 किसानों को दस लाख फलदार, लकड़ी और औषधीय पेड़ लगाने और बनाए रखने में सहायता करेगा।

2019 में, अमेज़ॅन ने द क्लाइमेट प्लेज की सह-स्थापना की, जो पेरिस समझौते से 10 साल पहले - 2040 तक शुद्ध-शून्य कार्बन तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध है।

नवीनतम समाचार

जून 2023 में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR), नई दिल्ली ने इष्टतम उपज और आय के लिए विभिन्न फसलों की वैज्ञानिक खेती पर किसानों का मार्गदर्शन करने के लिए दोनों संगठनों की ताकत को संयोजित करने और तालमेल बनाने के लिए अमेज़ॅन किसान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

अमेज़ॅन वेब सर्विसेज (AWS) ने 2030 तक भारत में क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में 12.7 बिलियन डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है।

पाइन लैब्स ने QR, कार्ड-आधारित भुगतान के लिए नया PoS डिवाइस पेश किया

डिजिटल भुगतान प्रदाता पाइन लैब्स ने अपने पॉइंट-ऑफ-सेल (PoS) डिवाइस का एक सस्ता संस्करण मिनी लॉन्च किया है, जो व्यापारियों को त्वरित प्रतिक्रिया (QR)-आधारित और कार्ड-आधारित भुगतान दोनों स्वीकार करने की अनुमति देगा। डिवाइस नियर फील्ड कम्युनिकेशन (NFC)-सक्षम है और केवल टैप-टू-पे मोड के माध्यम से कार्ड से भुगतान स्वीकार कर सकता है।

पाइन लैब्स का कदम ऐसे समय में आया है जब PoS बाजार में प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है, पेटीएम अपने ध्वनि-आधारित PoS, साउंडबॉक्स की स्वीकार्यता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

जुलाई में, पेटीएम ने अपने साउंडबॉक्स के विभिन्न वेरिएंट लॉन्च किए थे, जिसमें छोटे व्यापारियों के लिए डिवाइस का पोर्टेबल पॉकेट संस्करण भी शामिल था।

PhonePe जैसे अन्य उपभोक्ता भुगतान प्रदाताओं ने भी इसी तरह के व्यापारी भुगतान-स्वीकृति उपकरण लॉन्च किए हैं, जबकि Google Pay इस क्षेत्र में एक पायलट चला रहा है।

पाइन लैब्स ने कहा कि उसका मिनी डिवाइस नियमित PoS टर्मिनल की कीमत की लगभग एक तिहाई कीमत पर उपलब्ध है और इसका लक्ष्य छोटे व्यापारी हैं।

पाइन लैब्स के बारे में:

स्थापित: 1998

मुख्यालय: नोएडा, उत्तर प्रदेश, भारत

CEO: बी अमरीश राऊ

पाइन लैब्स एक भारतीय कंपनी है जो वित्तपोषण और खुदरा लेनदेन तकनीक प्रदान करती है।

नवीनतम समाचार

मई 2023 में, एक मर्चेंट कॉमर्स ओमनी चैनल प्लेटफॉर्म पाइन लैब्स ने ICICI बैंक के साथ साझेदारी में अपने PoS (पॉइंट ऑफ सेल) टर्मिनलों पर डिजिटल रुपया (ई रुपया) की स्वीकृति की घोषणा की है।

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2023-24 सीरीज II सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गई है

सॉवरेन गोल्ड बांड (SGB) सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है जो 15 सितंबर तक खरीदारी के लिए खुला रहेगा।
यह वित्तीय वर्ष 2023-24 में SGB योजनाओं की दूसरी श्रृंखला है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने घोषणा की कि सोने के बांड की कीमत 5,923 रुपये प्रति ग्राम होगी।
RBI ने योजना के लिए ऑनलाइन आवेदकों के लिए छूट की भी घोषणा की।
ऑनलाइन आवेदन करने वालों और डिजिटल मोड के माध्यम से आवेदन के विरुद्ध भुगतान करने वालों को अंकित मूल्य से 50 रुपये प्रति ग्राम कम की छूट दी जाएगी।
RBI की घोषणा के मुताबिक, ऑनलाइन निवेशकों के लिए गोल्ड बॉन्ड का निर्गम मूल्य 5,873 रुपये प्रति ग्राम सोना होगा।
सोने के बांड में कोई भी व्यक्ति न्यूनतम एक ग्राम निवेश कर सकता है।
प्रति वित्तीय वर्ष में सदस्यता की अधिकतम सीमा व्यक्तियों के लिए 4 किलोग्राम और ट्रस्टों और समान संस्थाओं के लिए 20 किलोग्राम निर्धारित की गई है।
SGB भौतिक सोने का एक सुरक्षित विकल्प और अतिरिक्त आय स्रोत प्रदान करता है।
यदि आप निवेश करने पर विचार कर रहे हैं, तो ध्यान में रखने योग्य पांच महत्वपूर्ण पहलू यहां दिए गए हैं।
सरकार ने नवंबर 2015 में स्वर्ण मौद्रीकरण योजना के तहत सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना शुरू की थी।

PSU सामान्य बीमाकर्ताओं की बाजार हिस्सेदारी उद्योग के एक तिहाई से कम

PSU सामान्य बीमाकर्ताओं की बाजार हिस्सेदारी पहली बार उद्योग के प्रीमियम के एक तिहाई से नीचे पहुंच गया।
चालू वित्त वर्ष के पहले पांच महीनों के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं की प्रीमियम आय 1% गिरकर ₹34,203 करोड़ हो गई है।
PSU बीमा कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी 33.4% से घटकर एक तिहाई से भी कम 32.5% रह गई।
प्रीमियम आय PSU की संख्या ₹37,100 करोड़ से घटकर ₹34,203 करोड़ हो गई।
जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के आंकड़ों के अनुसार, पहली बार, राज्य द्वारा संचालित सामान्य बीमाकर्ताओं का उद्योग प्रीमियम में एक तिहाई से भी कम 32.5% का योगदान है।
पहली बार, चालू वित्त वर्ष के पहले पांच महीनों के दौरान स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं की बाजार हिस्सेदारी 9.2% से बढ़कर 10.4% हो गई।
जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त तक पहले पांच महीनों के दौरान गैर-जीवन बीमा क्षेत्र में 11.7% की वृद्धि हुई।
इसने 1.14 लाख करोड़ रुपये की प्रीमियम आय दर्ज की।
FY23 में इसी अवधि में ₹1.02 लाख करोड़ की प्रीमियम आय दर्ज की गई थी।
देश में 26 परिचालन सामान्य बीमाकर्ता हैं।
केंद्र उनमें से छह का मालिक है।

उद्योग में पांच स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता हैं:

आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस, केयर हेल्थ इंश्योरेंस (पूर्व में रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस), मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस, स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस।

नवीनतम समाचार

मई 2023 में, 4 सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों - न्यू इंडिया एश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने अपने निजी समकक्षों के कारण पिछले 5 वर्षों में बाजार हिस्सेदारी में 800 आधार

अंक (BPS) खो दिए हैं, जैसा कि डेटा से पता चलता है। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने खुलासा किया।

अगस्त 2023 में CPI पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 6.83% हो गई

खुदरा मुद्रास्फीति, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) पर आधारित, इस साल अगस्त में गिरकर 6.83 प्रतिशत पर आ गया।
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में 7.02% की मुद्रास्फीति दर देखी गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में 6.59% थी।
सब्जियों की कीमतों में गिरावट के कारण पिछले महीने CPI जुलाई में 15 महीने के उच्च स्तर 7.44% से गिर गया।
उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (CFPI) अगस्त में 9.94 प्रतिशत रहा, जो जुलाई में 11.51 प्रतिशत था।
खुदरा मुद्रास्फीति अभी भी भारतीय रिजर्व बैंक की 6% की ऊपरी सहनशीलता सीमा से ऊपर बनी हुई है।
सरकार ने केंद्रीय बैंक को खुदरा मुद्रास्फीति को दोनों तरफ 2% के मार्जिन के साथ चार प्रतिशत पर बनाए रखने के लिए अनिवार्य किया था।

नवीनतम समाचार

भारत की वार्षिक खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल में 5.66 प्रतिशत से कम होकर 18 महीने के निचले स्तर 4.7% पर आ गई।
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल में घटकर 18 महीने के निचले स्तर 4.7% पर आ गई।
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति (CPI), जून 2023 में 4.81 प्रतिशत थी।

खुदरा मुद्रास्फीति के बारे में:

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI), जो खुदरा मुद्रास्फीति को ट्रैक करता है, खुदरा उपभोक्ताओं द्वारा देखी गई कीमतों में वृद्धि को ट्रैक करता है।
दूसरी ओर, थोक मूल्य सूचकांक (WPI) थोक मुद्रास्फीति को ट्रैक करता है और उत्पादक स्तर पर इसका आकलन करता है।

जुलाई 2023 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 5.7% बढ़कर पांच महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक उछलकर 5 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया।
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, इस साल जुलाई में IIP में 5.7% की वृद्धि हुई, जबकि जून 2023 में यह 3.7% थी।
जुलाई 2022 में यह 2.2% थी।
IIP में 77% वेटेज रखने वाले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ 4.6% रही।
जुलाई 2023 के लिए बेसिक मेटल सेक्टर 12.8%, माइनिंग आउटपुट 10.7% और इलेक्ट्रिसिटी 8% बढ़ा।

नवीनतम समाचार

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) अप्रैल 2023 के 4.2 प्रतिशत से बढ़कर मई 2023 में 5.2 प्रतिशत हो गया।

IIP के बारे में

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) एक सूचकांक है जो एक निर्धारित अवधि में अर्थव्यवस्था के विभिन्न उद्योग समूहों में विकास दर को दर्शाता है।
IIP सूचकांक की गणना और प्रकाशन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (CSO) द्वारा मासिक रूप से किया जाता है।

यूरोपीय संघ ने अल्फाबेट, अमेज़ॅन, मेटा और तीन अन्य तकनीकी दिग्गजों को सख्त प्रतिस्पर्धा नियमों के तहत 'द्वारपाल' के रूप में सूचीबद्ध किया है

यूरोपीय आयोग डिजिटल मार्केट एक्ट (DMA) के तहत छह प्रौद्योगिकी दिग्गजों - अल्फाबेट, अमेज़ॅन, ऐप्पल, बाइटडांस, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट को द्वारपाल के रूप में नामित किया गया है।)
कुल मिलाकर, द्वारपालों द्वारा प्रदान की जाने वाली 22 मुख्य प्लेटफ़ॉर्म सेवाओं को नामित किया गया है।
डिजिटल मार्केट एक्ट एक अभूतपूर्व यूरोपीय कानून है जिसका लक्ष्य बड़े ऑनलाइन प्लेटफार्मों को रोकना है जो उपभोक्ताओं को सामग्री, सामान और सेवाओं से जोड़ते हैं और उन्हें अपनी बाजार शक्ति का दुरुपयोग करने से रोकते हैं।

यूरोपीय आयोग का मानना है कि बड़ी इंटरनेट कंपनियों पर नियंत्रण रखने से अधिक प्रतिस्पर्धा और विकल्प, अधिक नवाचार, बेहतर गुणवत्ता और कम कीमतें हो सकती हैं।
नियमों के अनुसार, कंपनी द्वारा दी जाने वाली कोई भी सेवा जो दो मानदंडों को पूरा करती है, उसे गेटकीपर नामित किया जाता है।
ये हैं: उनका बाज़ार मूल्य कम से कम EUR 75 बिलियन (लगभग $82 बिलियन) है, और
या तो एक सोशल प्लेटफॉर्म या ऐप का मालिक हो जिसका उपयोग हर महीने कम से कम 45 मिलियन लोग करते हों या कम से कम 10,000 सक्रिय व्यावसायिक उपयोगकर्ता हों।
DMA का बड़ा हिस्सा 2023 के दौरान लागू हो जाएगा।

NSE के निफ्टी 50 ने 20,000 का आंकड़ा पार कर लिया है

NSE निफ्टी 50 हाल ही में पहली बार 20,000 का आंकड़ा पार करने में कामयाब रहा।
निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) द्वारा शुरू किया गया एक बाजार सूचकांक है।
यह एक मिश्रित शब्द है - नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और NSE द्वारा गढ़ा गया फिफ्टी।

निफ़्टी के बारे में

निफ्टी की स्थापना 1996 में CNX निफ्टी के नाम से की गई थी। इसके अलावा, 2015 में इसका नाम बदलकर निफ्टी 50 कर दिया गया।
निफ्टी 50 एक बेंचमार्क-आधारित सूचकांक और NSE का प्रमुख सूचकांक है।
यह NSE पर सूचीबद्ध 50 सबसे बड़े और सबसे सक्रिय रूप से कारोबार वाले शेयरों के प्रदर्शन का प्रतिनिधित्व करता है।
ये 50 सबसे बड़ी कंपनियां विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों से हैं और सामूहिक रूप से भारत के शेयर बाजार और आर्थिक रुझानों का प्रतिनिधित्व करती हैं।
यह भारत में दो मुख्य शेयर बाजार सूचकांकों में से एक है, दूसरा सेंसेक्स है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का एक उत्पाद है।
स्टॉक इंडेक्स शेयर बाज़ार में होने वाले परिवर्तनों का माप है।
यह मूल्य परिवर्तन और बाज़ार प्रदर्शन को मापता है।
एक सूचकांक बनाने के लिए, समान विशेषताओं वाले शेयरों की सूची में से कुछ शेयरों को समूहित करना होगा।
शेयरों का यह समूहन उद्योग के प्रकार, कुल बाजार पूंजीकरण या कंपनी के आकार पर आधारित हो सकता है।

₹100 करोड़ या उससे अधिक टर्नओवर वाले व्यवसायों को IRP पोर्टल पर चालान रिपोर्ट करने के लिए 30 दिन का समय मिलेगा

कम से कम ₹100 करोड़ के टर्नओवर वाले GST करदाता ई-चालान पोर्टल पर चालान का खुलासा करने के लिए अब 30 दिन तक का समय होगा।
नए नियम 1 नवंबर से प्रभावी हो जाएंगे
पहले यह समय सीमा 7 दिन रखी गई थी
GST प्राधिकरण ने ई-चालान पोर्टल पर चालान की तारीख से चालान की रिपोर्टिंग के लिए 30 दिनों की समय सीमा लगाने का निर्णय लिया है।
यह समय सीमा 100 करोड़ रुपये से अधिक या उसके बराबर कुल वार्षिक कारोबार (AATO) वाले करदाताओं के लिए लागू है।
GST के तहत समग्र वार्षिक कारोबार (AATO) इकाई का कुल वार्षिक कारोबार है जो विभिन्न राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में पंजीकृत हो सकता है।
₹100 करोड़ या उससे अधिक की श्रेणी के करदाताओं को रिपोर्टिंग की तारीख पर 30 दिनों से अधिक पुराने चालान की रिपोर्ट करने की अनुमति नहीं होगी।

Click Here to Subscribe Our Yearly Mock Test Package

CGST नियमों के नियम 48(4) के अनुसार, पंजीकृत व्यक्तियों के अधिसूचित वर्ग को चालान पंजीकरण पोर्टल (IRP) पर चालान तैयार करना होता है।

आदित्य बिड़ला फाइनेंस ने GeM सहाय पर MSME के लिए त्वरित खरीद ऑर्डर वित्तपोषण शुरू करने के लिए OCEN में भाग लिया

आदित्य बिड़ला फाइनेंस (ABFL), आदित्य बिड़ला कैपिटल (ABCL) की ऋण देने वाली शाखा, सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GEM) सहाय प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत MSME के लिए तत्काल खरीद ऑर्डर (PO) वित्तपोषण शुरू करके सार्वजनिक वित्तपोषण मंच ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क (OCEN) में शामिल हो गई है।
छोटे व्यवसाय सीधे-सीधे डिजिटल तरीके से खरीद ऑर्डर पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
OCEN एक विकेन्द्रीकृत ओपन क्रेडिट नेटवर्क है जिसकी कल्पना गैर-लाभकारी थिंक टैंक iSPIRT फाउंडेशन ने एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के रूप में की है।
यह मानकों के एक सामान्य सेट के तहत उधारकर्ताओं और ऋणदाताओं के बीच ऋण के प्रवाह की अनुमति देता है।
हाल के दिनों में MSME सेगमेंट में यह कंपनी की दूसरी बड़ी पहल है।
24 अगस्त, 2023 को कंपनी ने उद्योग प्लस लॉन्च किया, जो MSME ग्राहकों के लिए डिज़ाइन किया गया वन-स्टॉप बिजनेस प्लेटफॉर्म है।
यह नया बी2बी डिजिटल प्लेटफॉर्म MSME के लिए समाधानों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है, जिसमें उनके व्यवसाय के प्रबंधन और विकास के लिए वित्तपोषण, सुरक्षा, निवेश, सलाह और मूल्य वर्धित सेवाएं शामिल हैं।
राकेश सिंह, ABFL के MD और CEO।

स्टेबल मनी ने पहला सावधि जमा बाज़ार लॉन्च किया

निश्चित रिटर्न निवेश प्लेटफॉर्म स्टेबल मनी ने खुदरा निवेशकों के लिए देश का पहला फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) मार्केटप्लेस लॉन्च किया है।
यह प्लेटफॉर्म 200 से अधिक बैंकों और NBFC की ब्याज दरों की तुलना करते हुए FD की पेशकश करता है, और ग्राहकों को प्लेटफॉर्म पर अपनी एफडी को प्रबंधित और ट्रैक करने में सक्षम बनाता है।
अतिरिक्त सुविधाओं में 'ब्रेक एफडी' शामिल है जो रिटर्न का त्याग किए बिना परिपक्वता से पहले फंड तक पहुंचने की सुविधा देता है, और 'एफडी लैडरिंग' जो तरलता और रिटर्न दोनों पर विचार करके एक संतुलित पोर्टफोलियो बनाए रखने में मदद करता है।

स्थिर धन के बारे में

स्टेबल मनी एक निश्चित-रिटर्न निवेश मंच है जो उपयोगकर्ताओं को सावधि जमा, ऋण म्यूचुअल फंड और बांड तक पहुंचने की अनुमति देता है।
सौरभ जैन और हरीश रेड्डी, स्टेबल मनी के संस्थापक।

2022 में वैश्विक ऋण घटकर 235 ट्रिलियन डॉलर हो गया, लेकिन पूर्व-कोविड स्तर से ऊपर रहा: IMF

IMF ग्लोबल डेट डेटाबेस के नवीनतम अपडेट के अनुसार, वैश्विक ऋण का बोझ लगातार दूसरे वर्ष कम हुआ है, भले ही यह अपने पहले से ही उच्च महामारी-पूर्व स्तर से ऊपर बना हुआ है।
पिछले वर्ष कुल ऋण वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 238 प्रतिशत था, जो 2019 की तुलना में 9 प्रतिशत अंक अधिक है।
अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में, ऋण की राशि 235 ट्रिलियन डॉलर या 2021 में अपने स्तर से 200 बिलियन डॉलर अधिक है।
फिर भी, गिरावट महामारी की वृद्धि को मिटाने के लिए पर्याप्त नहीं थी।
महामारी से पहले, वैश्विक ऋण-से-जीडीपी अनुपात दशकों तक बढ़ा था।
1970 के दशक के मध्य से वैश्विक सार्वजनिक ऋण 2022 के अंत तक तीन गुना बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद के 92 प्रतिशत (या 91 ट्रिलियन डॉलर से थोड़ा ऊपर) तक पहुंच गया।

चीन ने हाल के दशकों में वैश्विक ऋण को बढ़ाने में केंद्रीय भूमिका निभाई है क्योंकि उधार ने आर्थिक विकास को पीछे छोड़ दिया है।
सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी के रूप में ऋण संयुक्त राज्य अमेरिका के समान स्तर तक बढ़ गया है, जबकि डॉलर के संदर्भ में चीन का कुल ऋण ($47.5 ट्रिलियन) अभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका (लगभग $70 ट्रिलियन) से काफी नीचे है।
जहाँ तक गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ऋण का सवाल है, चीन का 28% शेयर दुनिया में सबसे बड़ा है

IMF के बारे में:

स्थापित: 1990
मुख्यालय: उत्तरी हॉलीवुड, कैलिफ़ोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका
संस्थापक: ब्रायन नोविस, सूसी नोविस, और ब्रायन जीएम ड्यूरी
IMF एक अमेरिकी गैर-लाभकारी संगठन है जो अस्थि मज्जा में प्लाज्मा कोशिकाओं के कैंसर, मायलोमा के रोगियों की सेवा करता है।
फाउंडेशन की पहुंच दुनिया भर के 140 देशों में 525,000 से अधिक सदस्यों तक फैली हुई है।
क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक।

REC ने 1,440 मेगावाट पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए ग्रीनको को 6,075 करोड़ रुपये का ऋण दिया

REC लिमिटेड ने 1,440 मेगावाट स्टैंडअलोन पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए अक्षय ऊर्जा कंपनी ग्रीनको को 6,075 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया है।
देश की प्रमुख NBFC-IFC भी ग्रीनको के साथ उन्नत चर्चा में है और कई स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए तैयार है।
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की राष्ट्रीय विद्युत योजना का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2022 और वित्त वर्ष 2032 के बीच समग्र नवीकरणीय स्थापित क्षमता में लगभग 4 गुना वृद्धि होगी (सौर के तहत ~ 7 गुना, पंप भंडारण परियोजना के तहत ~ 5.5 गुना, पवन के तहत ~ 3 गुना)।
नवीकरणीय ऊर्जा के तहत वैश्विक जोर और राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के साथ मिलकर ये अनुमान न केवल REC के लिए एक व्यावसायिक अवसर पेश करेंगे, बल्कि कंपनी को ग्रीन फाइनेंसिंग वर्टिकल का नेतृत्व करके राष्ट्र निर्माण में योगदान करने की अनुमति भी देंगे।
एक दृढ़ दृष्टि और दृढ़ समर्पण के साथ, आरईसी वित्तीय वर्ष 2030 तक कुल 3 लाख करोड़ रुपये के ग्रीन फाइनेंस लोन पोर्टफोलियो को प्राप्त करने के मार्ग पर मजबूती से तैयार है।

नवीनतम समाचार

REC ने जुलाई 2023 में भारत की जी 20 अध्यक्षता के मौके पर ग्रीन फाइनेंस समिट की मेजबानी की, जहां आरई डेवलपर्स के साथ आमने-सामने की चर्चा आयोजित की गई, जिससे लगभग 2.86 लाख करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापनों (MoU) पर सफलतापूर्वक हस्ताक्षर किए गए।
जुलाई 2023 में, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम REC लिमिटेड ने बैंगलोर मेट्रो की चरण -2 परियोजना के तहत मेट्रो लाइनों की स्थापना और विकास के लिए बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BMRCL) को 3,045 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है।

REC लिमिटेड के बारे में

REC लिमिटेड एक NBFC है जो पूरे भारत में पावर सेक्टर के वित्तपोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित करती है।
BMRCL को वित्तीय सहायता बुनियादी ढांचे के विकास के वित्तपोषण में REC के प्रयास का हिस्सा है।
1969 में स्थापित, REC लिमिटेड ने संचालन के पचास वर्ष से अधिक पूरे कर लिए हैं।
यह संपूर्ण विद्युत क्षेत्र मूल्य श्रृंखला को वित्तीय सहायता प्रदान करता है; उत्पादन, पारेषण, वितरण और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के लिए।
REC की फंडिंग से भारत में हर चौथा बल्ब रोशन होता है।

चालू वित्त वर्ष में अब तक प्रत्यक्ष कर संग्रह में 23.5% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है

भारत का प्रत्यक्ष कर संग्रह आठ लाख 65 हजार करोड़ रुपये से अधिक (इस वित्तीय वर्ष के मध्य सितंबर तक) दर्ज किया गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 23.51 प्रतिशत अधिक है।
पिछले वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर संग्रह सात लाख 416 करोड़ रुपये रहा था
इस वित्तीय वर्ष में अब तक सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में भी 18.29 प्रतिशत की जोरदार वृद्धि देखी गई है, जो नौ लाख 87 हजार करोड़ रुपये से अधिक है।
पिछले वित्तीय वर्ष में आठ लाख 34 हजार करोड़ रुपये से अधिक का सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह दर्ज किया गया था
इस बीच, इस वित्त वर्ष के लिए एडवांस टैक्स कलेक्शन 20.73 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ तीन लाख 55 हजार करोड़ रुपये रहा
इसी अवधि के लिए अग्रिम कर संग्रह दो लाख 94 हजार 433 करोड़ रुपये दर्ज किया गया था।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक अब तक एक लाख 21 हजार करोड़ रुपये का रिफंड भी जारी किया जा चुका है

अगस्त में माल निर्यात 6.8% घटकर 34.48 अरब डॉलर रहा, लेकिन 'हरित अंकुर दिखाई दे रहे हैं'

भारत का माल निर्यात अगस्त में 6.8% घटकर $34.48 बिलियन हो गया।
अगस्त 2023 में भारत के माल निर्यात में लगातार सातवें महीने (वर्ष-दर-वर्ष) गिरावट आई।
पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न एवं आभूषण, रेडीमेड वस्त्र और रसायन जैसे क्षेत्रों ने वस्तुओं के निर्यात में गिरावट में योगदान दिया।
हालाँकि, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और कुछ कृषि वस्तुओं सहित शीर्ष तीस निर्यात वस्तुओं में से आधे में अगस्त 2023 के दौरान वृद्धि देखी गई है।
अगस्त 2023 में भारत का आयात 5.23% घटकर 58.64 बिलियन डॉलर हो गया है।
15 सितंबर 2023 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी त्वरित अनुमान के अनुसार पेट्रोलियम, कोयला और कोक, मोती, कीमती और अर्ध-कीमती पत्थरों और उर्वरकों के आयात में गिरावट आई है।
अगस्त 2023 में व्यापार घाटा 24.16 अरब डॉलर के दस महीने के उच्च स्तर पर था।

EPFO ने जुलाई, 2023 के दौरान 18.75 लाख शुद्ध सदस्यों के साथ उच्चतम पेरोल वृद्धि दर्ज की

EPFO का अनंतिम पेरोल जारी आंकड़ों से पता चलता है कि EPFO ने जुलाई 2023 के महीने में 18.75 लाख शुद्ध सदस्य जोड़े हैं।
सितंबर 2017 के बाद की अवधि को कवर करते हुए अप्रैल 2018 से EPFO पेरोल डेटा के पहले प्रकाशन के बाद से महीने के दौरान वृद्धि सबसे अधिक है।
जून, 2023 के पिछले महीने की तुलना में लगभग 85,932 शुद्ध सदस्यों की वृद्धि के साथ पिछले तीन महीनों से बढ़ती प्रवृत्ति जारी है।
डेटा बताता है कि जुलाई, 2023 के दौरान लगभग 10.27 लाख नए सदस्यों ने नामांकन किया है, जो जुलाई, 2022 के बाद से सबसे अधिक है।
EPFO में शामिल होने वाले अधिकांश नए सदस्य 18-25 वर्ष के आयु वर्ग में हैं, जो महीने के दौरान कुल नए सदस्यों का लगभग 58.45% है।
यह युवा नामांकन में बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है, जो ज्यादातर पहली बार नौकरी चाहने वाले देश के संगठित क्षेत्र के कार्यबल में शामिल हो रहे हैं।
पेरोल डेटा दर्शाता है कि लगभग 12.72 लाख सदस्य बाहर चले गए लेकिन EPFO में फिर से शामिल हो गए, जो पिछले 12 महीनों में सबसे अधिक है।

Click Here to Subscribe Our Yearly Mock Test Package

इन सदस्यों ने अपनी नौकरियां बदल लीं और EPFO के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों में फिर से शामिल हो गए और अंतिम निपटान के लिए आवेदन करने के बजाय अपनी जमा राशि को स्थानांतरित करने का विकल्प चुना, जिससे उनकी सामाजिक सुरक्षा सुरक्षा बढ़ गई।

एमक्योर फार्मा ने 2024 में 400-500 मिलियन डॉलर का IPO लॉन्च करने की योजना बनाई है, इसके लिए कोटक, जेफरीज को काम पर रखा है

एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स 2024 में आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) से $400-500 मिलियन जुटाने की योजना बना रही है।
यह विकास फार्मास्युटिकल कंपनी के लिए लिस्टिंग योजनाओं को पुनर्जीवित करता है, जिसे 2022 में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के कारण वैश्विक बाजारों में बाधा उत्पन्न होने के कारण स्थगित कर दिया गया था।
कंपनी ने IPO के लिए निवेश बैंकों जेपी मॉर्गन, जेफरीज और कोटक को काम पर रखा है और सूत्रों ने कहा कि इसका लक्ष्य लगभग 3 बिलियन डॉलर का मूल्यांकन है।
एमक्योर उन कंपनियों में से एक है जो दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश में दवाओं की बढ़ती जरूरत और नागरिकों के बीच बढ़ती स्वास्थ्य जागरूकता का फायदा उठाना चाहती है।
भारत का फार्मास्यूटिकल्स बाजार वर्तमान में 50 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2030 में 130 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, और इस क्षेत्र में सौदेबाजी तेजी से बढ़ रही है।

आदित्य बिड़ला फाइनेंस पहले NCD सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से ₹2,000 करोड़ जुटाएगा

आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड की सहायक कंपनी, गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (NCD) के अपने पहले सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से ₹2,000 करोड़ तक जुटाएगी।
NCD भारत में प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों (BSE और NSE) में सूचीबद्ध निश्चित आय वाली प्रतिभूतियां हैं।
ये NCD मध्यम जोखिम सहनशीलता वाले निवेशकों के लिए एक विकल्प हो सकते हैं जो बैंक और कॉर्पोरेट एफडी के विकल्प तलाश रहे हैं।
NCD को शेयर या इक्विटी में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है

गैर परिवर्तनीय डिबेंचर (NCD) के बारे में:

डिबेंचर दीर्घकालिक वित्तीय साधन हैं जिन्हें कंपनियां निवेशकों से अधिक धन जुटाने के लिए जारी करती हैं।

यह आम तौर पर किसी संपार्श्विक द्वारा समर्थित नहीं होता है और इस प्रकार जारीकर्ता की साख और प्रतिष्ठा पर अत्यधिक निर्भर होता है।
इस कारण से, बड़ी कंपनियों द्वारा बिना किसी सुरक्षा के निश्चित ब्याज दर पर धन जुटाने के लिए डिबेंचर जारी किए जाते हैं।
डिबेंचर विभिन्न प्रकार के होते हैं
ऐसी ही एक श्रेणी परिवर्तनीय डिबेंचर और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर है।
परिवर्तनीय डिबेंचर वे डिबेंचर होते हैं जो धारक को एक निश्चित अवधि के बाद इसे जारीकर्ता कंपनी के शेयर में परिवर्तित कराने का विकल्प देते हैं।
दूसरी ओर, एनसीडी का अर्थ यह है कि डिबेंचर परिपक्वता के समय धारक को ऐसा कोई विकल्प प्रदान नहीं करता है।

गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर क्या हैं?

गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर विशिष्ट शर्तों और ब्याज दरों के लिए निश्चित आय उपकरण हैं।
बड़ी कंपनियां इक्विटी में रूपांतरण का कोई विकल्प दिए बिना धन जुटाने के लिए इन्हें जारी करती हैं।
NCD डिबेंचर पर दी जाने वाली ब्याज दरें कमोबेश निश्चित होती हैं।
परिपक्वता पर, निवेशक को ब्याज सहित मूल राशि वापस मिल जाएगी।
चूंकि NCD संपार्श्विक द्वारा समर्थित नहीं हैं, बल्कि केवल जारीकर्ता की साख द्वारा समर्थित हैं, इसलिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों

द्वारा दी गई रेटिंग महत्वपूर्ण हो जाती है।
ऐसी रेटिंग निवेशकों को जारीकर्ता की साख के इतिहास और भविष्य में यह कैसी दिख सकती है, यह समझने में मदद करती है।

गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर के प्रकार: सुरक्षित और असुरक्षित

सुरक्षित NCD
सुरक्षित NCD वे NCD हैं जो जारीकर्ता कंपनी की संपत्ति द्वारा समर्थित हैं।

असुरक्षित NCD
जब NCD केवल जारीकर्ता की साख पर आधारित होते हैं और परिसंपत्तियों द्वारा समर्थित नहीं होते हैं, तो उन्हें असुरक्षित NCD कहा जाता है।

भारत में पेशेवरों के लिए ज़ेप्टो सबसे पसंदीदा स्टार्टअप: लिंक्डइन रैंकिंग

एक शीर्ष भर्ती मंच की सूची के अनुसार, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ज़ेप्टो, जो हाल ही में यूनिकॉर्न बन गया है, पेशेवरों के पसंदीदा कार्यस्थल के मामले में भारत में शीर्ष स्टार्टअप के रूप में उभरा है।
रैंकिंग में ई-किराना ऐप को फॉलो करने वाले स्टार्टअप में क्रमशः ईवी कैब एग्रीगेटर ब्लूस्मार्ट, फिनटेक कंपनी डिट्टो इंश्योरेंस, ऑडियो ओटीटी प्लेटफॉर्म पॉकेट एफएम और स्काईरूट एयरोस्पेस शामिल हैं।
लिंक्डइन ने अपनी 'टॉप 25 भारतीय स्टार्टअप सूची' जारी की, जो लगभग 1 करोड़ सदस्यों के हायरिंग प्लेटफॉर्म के डेटा के आधार पर उभरती कंपनियों की एक वार्षिक रैंकिंग है, जहां पेशेवर काम करना चाहते हैं।
कर्मचारी वृद्धि, नौकरी तलाशने वालों की रुचि, कंपनी और उसके कर्मचारियों के भीतर सदस्य जुड़ाव और लिंक्डइन की शीर्ष कंपनियों की सूची से प्रतिभा खींचने वाले स्टार्टअप के मामले में ज़ेप्टो पिछले साल नंबर 4 से तीन स्थान ऊपर चढ़ गया।

आदित्य बिड़ला फैशन ने TCNS क्लोदिंग में 51% हिस्सेदारी खरीदी

आदित्य बिड़ला फैशन रिटेल लिमिटेड (ABFRL) ने महिलाओं के परिधान ब्रांड का प्रमोटर बनने के लिए टीसीएनएस क्लोदिंग में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण पूरा कर लिया है।
TCNS कंपनी की एक सहायक कंपनी बन गई है, और सेबी लिस्टिंग विनियमों के अनुसार कंपनी की एक सामग्री सहायक कंपनी भी होगी।
5 मई को, आदित्य बिड़ला समूह की कंपनी ने घोषणा की थी कि वह 1,650 करोड़ रुपये के सौदे में TCNS क्लोदिंग में बहुमत हिस्सेदारी हासिल करेगी।
सौदे के अनुसार, इसने एक SPA (शेयर खरीद समझौते) के माध्यम से TCNS क्लोदिंग के संस्थापक प्रमोटर की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया, जिसके बाद एक खुली पेशकश की गई।
SPA के अनुसार, ABFRL ने कुल 1.41 करोड़ इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण किया, जो कंपनी की विस्तारित शेयर पूंजी का 22 प्रतिशत है।

बायजू ने व्हाइटहैट जूनियर को बायजू फ्यूचर स्कूल के रूप में नया नाम दिया है

बायजू ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी व्हाइटहैट जूनियर को रीब्रांड करने का निर्णय लिया है, जबकि कंपनी की संपत्ति को उसकी होल्डिंग इकाई थिंक एंड लर्न प्राइवेट सहित अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में पूरी तरह से एकीकृत किया गया है, जिसका उद्देश्य तत्काल तरलता संकट से निपटने के लिए लागत को कम करना है।
व्हाइटहैट जूनियर, जिसे बायजू ने तीन साल पहले $ 300 मिलियन नकद सौदे के लिए अधिग्रहित किया था, कंपनी की सबसे बड़ी घाटे वाली सहायक कंपनियों में से एक रही है, इसकी उच्च विपणन और कर्मचारी लाभ लागत के लिए धन्यवाद।
बायजू के अधिग्रहण के बाद से कंपनी के विस्तार के लिए इसमें 100 मिलियन डॉलर से अधिक का निवेश किया गया है।
इस प्रकार स्वयं के साथ विलय से कंपनी को अपने समग्र खर्च को कम करने में मदद मिलेगी, जो इसकी आसन्न नकदी जरूरतों को देखते हुए महत्वपूर्ण होगा।

सूत्रों ने कहा कि यह विस्तारित ऑफ़लाइन उपस्थिति के साथ व्हाइटहैट जूनियर को "बायजूज़ फ्यूचर स्कूल" के रूप में पुनः ब्रांड करने के लिए तैयार है।
बायजूज़ फ़्यूचर स्कूल भारत के बाहर के बच्चों को कोडिंग सिखाने के लिए डिज़ाइन किया गया एक मंच है और तीन साल पहले इसकी स्थापना के बाद से इसने व्हाइटहैट जूनियर के साथ तालमेल का आनंद लिया है।
बायजू ने अगस्त 2020 में व्हाइटहैट जूनियर अधिग्रहण के साथ सुर्खियां बटोरीं, जिसने संस्थापक और CEO करण बजाज को भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण निकास में से एक प्रदान किया।

वेदांता ने कार्डों पर परिचालन को अलग किया: एल्युमीनियम, स्टील, तेल व्यवसायों को अलग से सूचीबद्ध किया जा सकता है

वेदांता लिमिटेडधातु और खनन सम्राट अनिल अग्रवाल द्वारा नियंत्रित, कथित तौर पर अपने व्यवसायों को कई सूचीबद्ध संस्थाओं में विभाजित करने के लिए एक सौदा कर रहा है।
उम्मीद है कि कंपनी अपने धातु, बिजली, एल्युमीनियम और तेल एवं गैस कारोबार को अलग कर देगी।
वेदांता लिमिटेड की मूल कंपनी, वेदांता रिसोर्सेज, होल्डिंग कंपनी बनी रहेगी।

वेदांता लिमिटेड के बारे में:

वेदांता लिमिटेड एक भारतीय बहुराष्ट्रीय खनन कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई, भारत में है, जिसकी स्थापना 1979 में हुई थी।
इसका मुख्य परिचालन गोवा, कर्नाटक, राजस्थान और ओडिशा में लौह अयस्क, सोना और एल्यूमीनियम खानों में होता है।

TCS भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना हुआ है, लेकिन शीर्ष ब्रांडों का संयुक्त मूल्य 4% गिर गया

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कांतार ब्रांडज़ टॉप 75 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांडों की रिपोर्ट के अनुसार, (TCS) $43 बिलियन के साथ भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना हुआ है।
डेटा, इनसाइट्स और कंसल्टिंग कंपनी ने कहा कि सामान्य तौर पर बिजनेस टेक्नोलॉजी श्रेणी के लिए एक कठिन वर्ष के बावजूद, TCS ने डिजिटल परिवर्तन के लिए वैश्विक मांग का सफलतापूर्वक लाभ उठाना जारी रखा है।
भारत के शीर्ष 75 ब्रांडों का संयुक्त ब्रांड मूल्य $379 बिलियन है, जो 2022 से 4 प्रतिशत की गिरावट है।
TCS और इंफोसिस में 2023 में क्रमश: 6 प्रतिशत और 17 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।
कांतार ने एक रिपोर्ट में कहा कि HDFC बैंक, इंफोसिस और एयरटेल ने भी शीर्ष चार स्थान बरकरार रखे हैं, जबकि भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने सूची में प्रवेश किया है।
उन्होंने आगे कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत की GDP (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि 7 प्रतिशत CAGR (चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर) रही है जबकि ब्रांड वैल्यू वृद्धि 19 प्रतिशत है।
ऑटोमोटिव श्रेणी ने शीर्ष 75 में दो सबसे तेजी से उभरने वाले उत्पाद पेश किए - TVS जिसकी ब्रांड वैल्यू 1.90 बिलियन डॉलर और महिंद्रा की ब्रांड वैल्यू 2.01 बिलियन डॉलर है।
इस श्रेणी में 19 प्रतिशत की दूसरी उच्चतम श्रेणी वृद्धि दर्ज की गई।
TVS के मूल्य में 59 प्रतिशत की वृद्धि हुई और महिंद्रा के मूल्य में 48 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

नेशनल करेंट अफेयर्स

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने उत्केला हवाई अड्डे और उत्केला और भुवनेश्वर के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किया

नागरिक उड्डयन मंत्री, श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के राज्य मंत्री जनरल विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त) के साथ उत्केला हवाई अड्डे और उत्केला और भुवनेश्वर के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किया।
यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया गया।
उत्केला हवाई अड्डा ओडिशा सरकार के स्वामित्व में है।

इसे 31.07 करोड़ रुपये की लागत से नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार की उड़ान योजना के तहत एक क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया गया है।
उत्केला हवाई अड्डे की लंबाई 917 मीटर (2,995 फीट) है जिसकी चौड़ाई 30 मीटर है।
उत्केला हवाई अड्डे के जुड़ने के साथ, ओडिशा में अब 5 हवाई अड्डे होंगे।
नव उद्घाटन उत्केला -भुवनेश्वर- उत्केला उड़ान मार्ग क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ाएगा और क्षेत्र के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
IndiaOne 31 अगस्त, 2023 से इस रूट पर उड़ानें चलाएगा।
ऑपरेटर उड़ान योजना के तहत स्वीकृत 9-सीटर सेसना सी-208 विमान का उपयोग करेगा।

नवीनतम समाचार

नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में हेली शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया और उन्होंने इस कार्यक्रम के दौरान आरसीएस उड़ान 5.2 और हेलीसेवा-ऐप भी लॉन्च किया।
नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने खजुराहो, मध्य प्रदेश में 3 उड़ान प्रशिक्षण संगठनों (FTO) का उद्घाटन किया।

ओडिशा के बारे में:

राज्यपाल: गणेशी लाल
मुख्यमंत्री: नवीन पटनायक
राजधानी: भुवनेश्वर
राष्ट्रीय उद्यान: सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान
वन्यजीव अभयारण्य: उषाकोठी वन्यजीव अभयारण्य, टिकरपाड़ा वन्यजीव अभयारण्य

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रायपुर में "सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष" का शुभारंभ किया

अध्यक्ष द्रौपदी मुर्मू रायपुर, छत्तीसगढ़ में प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में "सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष" का राज्य स्तरीय कार्यक्रम शुरू किया।
इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उपस्थित थे।
राष्ट्रपति गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे।
इसके अलावा वह रायपुर में आदिम जनजाति समुदाय के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगी

नवीनतम समाचार

छत्तीसगढ़ स्थित कोल इंडिया की सहायक कंपनी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स (SECL), अगले 5 वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अपने परिचालन राज्यों में वृक्षारोपण पर 169 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री (सीएम) श्री भूपेश बघेल ने ग्रामीण आवास न्याय योजना नामक एक महत्वाकांक्षी ग्रामीण आवास योजना शुरू की
छत्तीसगढ़ सरकार ने 36 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) को उद्योग 4.0 प्रौद्योगिकी केंद्र में बदलने के लिए भारतीय बहुराष्ट्रीय उत्पाद इंजीनियरिंग कंपनी, टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ 1,188.36 करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

छत्तीसगढ़ के बारे में:

राज्यपाल: विश्वभूषण हरिचंदन
मुख्यमंत्री: भूपेश बघेल
राजधानी: रायपुर
राष्ट्रीय उद्यान: गुरु घासी दास (संजय) राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान
वन्यजीव अभयारण्य: अचानकमार वन्यजीव अभयारण्य, बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य

भारत अक्टूबर 2023 में 'ग्लोबल इंडियाएआई 2023' के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) अक्टूबर 2023 के लिए निर्धारित ग्लोबल इंडियाएआई 2023 का आयोजन किया जाएगा।
इसमें भारत और दुनिया भर के प्रमुख एआई खिलाड़ियों, शोधकर्ताओं, स्टार्टअप और निवेशकों की भागीदारी होगी।
सम्मेलन विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करने के लिए तैयार है, जिसमें अगली पीढ़ी की शिक्षा और मूलभूत एआई मॉडल, स्वास्थ्य देखभाल, शासन और अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रिक वाहनों में एआई अनुप्रयोग, भविष्य के एआई अनुसंधान रुझान, एआई कंप्यूटिंग सिस्टम, निवेश के अवसर और एआई का पोषण शामिल है।
केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी राज्य मंत्री, श्री राजीव चंद्रशेखर सम्मेलन की संचालन समिति की अध्यक्षता करते हैं, जिसे ग्लोबल इंडियाएआई 2023 की रूपरेखा को आकार देने का काम सौंपा गया है।
इसमें MeitY के डिजिटल इकोनॉमी सलाहकार समूह के सदस्य और AI के क्षेत्र के अन्य प्रमुख नेता शामिल हैं।

मुख्य विचार:

ग्लोबल इंडियाएआई 2023 सम्मेलन अस्थायी रूप से 14/15 अक्टूबर, 2023 के लिए योजनाबद्ध है और यह भारत और दुनिया भर से एआई में सर्वश्रेष्ठ और प्रतिभाशाली लोगों को एक साथ लाएगा।
इस शिखर सम्मेलन के विकसित होने और वैश्विक एआई उद्योग, स्टार्टअप, अभ्यासकर्ताओं, शोधकर्ताओं और छात्रों के वार्षिक कैलेंडर पर एक अवश्य भाग लेने वाला कार्यक्रम बनने की उम्मीद है।
अतीत की बड़ी सफलता2प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सेमीकॉनइंडिया सम्मेलन के संस्करणों ने भारत को वैश्विक सेमीकॉन मानचित्र पर मजबूती से स्थापित किया।
इसने भारत को इस क्षेत्र में निवेश और विकास के लिए उत्प्रेरक बनने में सक्षम बनाया।
ग्लोबल इंडियाएआई शिखर सम्मेलन भारत के एआई परिदृश्य और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को भी उत्प्रेरित करेगा।

नवीनतम समाचार

भारत नई दिल्ली में भारत-इराक संयुक्त आयोग की बैठक के 18वें सत्र की मेजबानी करता है।
भारत शंघाई सहयोग संगठनों के 23वें शिखर सम्मेलन की वर्चुअल मेजबानी की

ब्रिक्स+6 वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 30%, 46% जनसंख्या को नियंत्रित करेगा - SBI रिपोर्ट

BRICS समूह में 6 नए सदस्यों को जोड़ने से यह दुनिया की 46% आबादी और अपने आर्थिक उत्पादन के 30% को नियंत्रित करेगा।
जोहान्सबर्ग में नवीनतम ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में, वर्तमान सदस्यों - ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को समूह के नए सदस्यों के रूप में जोड़ने का फैसला किया।
नए सदस्य 1 जनवरी, 2024 से ब्रिक्स का हिस्सा बन जाएंगे।

मुख्य विचार

संक्षिप्त नाम ब्रिक्स मूल रूप से 2001 में जिम ओ'नील के नेतृत्व में गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्रियों द्वारा गढ़ा गया था।
बाद में दिसंबर 2010 में, दक्षिण अफ्रीका को 5 वें सदस्य के रूप में जोड़ा गया था।
वर्तमान में, 5 सदस्यीय समूह दुनिया की 40% आबादी का घर है जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 26% नियंत्रित करता है।
लेकिन 6 नए सदस्यों (ब्रिक्स + 6) के साथ, उनका सकल घरेलू उत्पाद का हिस्सा 30% तक बढ़ जाएगा और आबादी का हिस्सा 46% तक बढ़ जाएगा।
हालांकि, सबसे बड़ा प्रभाव वैश्विक तेल उत्पादन की हिस्सेदारी पर पड़ेगा जो वर्तमान 18% से बढ़कर 40% हो जाएगा, जबकि उनका तेल सेवन हिस्सा 27% से बढ़कर 36% हो जाएगा।
हालांकि, नए जोड़ के बाद भी, चीन और भारत समूह के समग्र सकल घरेलू उत्पाद का 74% योगदान देना जारी रखेंगे।
वर्तमान में, चीन ब्रिक्स जीडीपी का 70% नियंत्रित करता है जबकि भारत का हिस्सा 13% है।

Click Here to Subscribe Our Yearly Mock Test Package

नए सदस्यों के शामिल होने के बाद यह घटकर क्रमश: 62 और 12 प्रतिशत रह जाएगा।
ब्राजील का हिस्सा 7% पर अपरिवर्तित रहेगा।
ब्रिक्स +6 और जी-20 (20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह) की वैश्विक आबादी में हिस्सेदारी 3.7 अरब और 5.1 अरब है, जबकि GDP का हिस्सा क्रमश: 29,200 अरब डॉलर और 70,400 अरब डॉलर तथा विदेशी मुद्रा भंडार 5,500 अरब डॉलर और 9,400 अरब डॉलर है।

नवीनतम समाचार:

अल्जीरियाई राष्ट्रपति, अब्देलमदजीद तेब्बौ ने बताया कि अल्जीरिया ने ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है और 1.5 अरब डॉलर की राशि के साथ ब्रिक्स बैंक का शेयरधारक सदस्य बनने का अनुरोध प्रस्तुत किया है।

ब्रिक्स के बारे में:

मुख्यालय: शंघाई, चीन
ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ़्रीका ब्रिक्स देशों का समूह बनाते हैं।
यह दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 26% और दुनिया की 40% से अधिक आबादी का निर्माण करता है।

मंत्रिमंडल ने अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 5,000 करोड़ रुपये की PRIP योजना को मंजूरी दे दी है

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने फार्मा-मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान और विकास तथा नवाचार पर राष्ट्रीय नीति को हरी झंडी दे दी है।
यह निर्णय फार्मा-मेडटेक क्षेत्र (PRIP) में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए योजना की मंजूरी के साथ है, जिसमें वित्त वर्ष 2024 से वित्त वर्ष 2028 तक 5 साल की अवधि के लिए 5,000 करोड़ रुपये का पर्याप्त आवंटन किया गया है।
इस योजना को इस महीने की शुरुआत में सरकार द्वारा इस विश्वास के साथ शुरू किया गया था कि भारतीय दवा उद्योग में वर्ष 2030 तक वैश्विक बाजार में अपनी वर्तमान 3.4% हिस्सेदारी को 5% तक बढ़ाने की क्षमता है।

मुख्य विचार

राष्ट्रीय नीति 3 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है: नियामक ढांचे को मजबूत करना, नवाचार में निवेश को प्रोत्साहित करना और नवाचार और अनुसंधान के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम करना।
नीति का उद्देश्य दवा की खोज और विकास में तेजी लाना, उद्योग और शिक्षाविदों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और अनुसंधान संसाधनों को अनुकूलित करने के लिए मौजूदा नीतियों को कारगर बनाना है।
5,000 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ पीआरआईपी योजना, 2 घटकों पर केंद्रित है: अनुसंधान बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मौजूदा संस्थानों के भीतर उत्कृष्टता केंद्रों (CoE) की स्थापना, और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देना।
इन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में नई रासायनिक और जैविक इकाइयां, सटीक दवाएं, चिकित्सा उपकरण और रोगाणुरोधी प्रतिरोध समाधान जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं।
भारत मात्रा के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दवा उद्योग है, जिसका मूल्य लगभग 50 बिलियन डॉलर है।
यह योजना फार्मास्युटिकल कंपनियों, अनुसंधान संस्थानों और स्टार्ट-अप के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई है।

नवीनतम समाचार

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 17,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI 2.0) योजना के दूसरे संस्करण को मंजूरी दे दी है।
केंद्र सरकार ने पोषक तत्व-आधारित सब्सिडी (NBS) तंत्र के तहत खरीफ 2023 सीज़न (अप्रैल-सितंबर) के लिए फॉस्फेटिक और पोटाश (P&K) उर्वरकों के लिए 38,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) और मिस्र प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण (ECA) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी।

छठा राष्ट्रीय पोषण माह शुरू

छठा राष्ट्रीय पोषण माह शुरू और सरकार इस साल पूरे सितंबर में इसे मना रही है।
केंद्र सरकार की प्रमुख पहल, पोषण अभियान गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, किशोर लड़कियों और छह साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पोषण संबंधी परिणामों को व्यापक तरीके से आगे बढ़ाने में सहायक रही है।

मुख्य विचार:

इसका उद्देश्य जीवन-चक्र दृष्टिकोण के माध्यम से कुपोषण से व्यापक रूप से निपटना है और पोषण माह 2023 का केंद्र बिंदु महत्वपूर्ण मानव जीवन चरणों: गर्भावस्था, शैशवावस्था, बचपन और किशोरावस्था के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करना है।
इसका उद्देश्य सुपोषित भारत, साक्षर भारत और सशक्त भारत पर केंद्रित थीम के माध्यम से पूरे भारत में पोषण संबंधी समझ को बढ़ावा देना है।
एक महीने तक चलने वाले इस कार्यक्रम में विशेष स्तनपान और पूरक आहार के प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित करने वाले अभियानों के माध्यम से जमीनी स्तर पर पोषण संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में केंद्रित प्रयास किए जाएंगे।
स्वस्थ बाल प्रतियोगिता जैसी गतिविधियों का उद्देश्य पोषण और समग्र कल्याण के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना है।

ASI 4 सितंबर 2023 को "एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम" भारतीय विरासत ऐप और ई-अनुमति पोर्टल लॉन्च करेगा

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के संरक्षण में 3696 स्मारक हैं, जो पूरे देश में फैले हुए हैं।
ये स्मारक न केवल भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करते हैं बल्कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
इस उद्देश्य से और आगंतुकों के अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए, ASI समवेत ऑडिटोरियम, IGNCA, नई दिल्ली में "एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0" कार्यक्रम शुरू करेगा।
इस कार्यक्रम के तहत, ASI कॉर्पोरेट हितधारकों को अपने CSR फंड का उपयोग करके स्मारकों में सुविधाएं बढ़ाने के लिए आमंत्रित करता है।
यह कार्यक्रम 2017 में शुरू की गई पिछली योजना का एक नया संस्करण है और AMASR अधिनियम 1958 के अनुसार विभिन्न स्मारकों के लिए मांगी गई सुविधाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है।
हितधारक किसी स्मारक या विशिष्ट सुविधा/सुविधाओं को अपनाने के लिए यूआरएल www. Indianheritage.gov.in के साथ एक समर्पित वेब पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, जिसमें अंतराल विश्लेषण और सुविधाओं के वित्तीय अनुमान के साथ गोद लेने के लिए मांगे गए स्मारकों का विवरण शामिल है।

मुख्य विचार:

इसके अलावा, उसी दिन 'इंडियन हेरिटेज' नाम से एक उपयोगकर्ता-अनुकूल मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा, जो भारत के विरासत स्मारकों को प्रदर्शित करेगा।
ऐप में तस्वीरों के साथ-साथ स्मारकों का राज्यवार विवरण, उपलब्ध सार्वजनिक सुविधाओं की सूची, भू-टैग किए गए स्थान और नागरिकों के लिए फीडबैक तंत्र की सुविधा होगी।
लॉन्च चरणबद्ध तरीके से होगा, चरण । में टिकट वाले स्मारकों का लॉन्च होगा, उसके बाद शेष स्मारकों का लॉन्च होगा।
स्मारकों पर फोटोग्राफी, फिल्मांकन और विकासात्मक परियोजनाओं की अनुमति प्राप्त करने के लिए URL www.asipermissionportal.gov.in के साथ एक ई-अनुमति पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा।
पोर्टल विभिन्न अनुमतियाँ प्राप्त करने की प्रक्रिया को तेज़ करेगा और इसमें शामिल परिचालन और लॉजिस्टिक बाधाओं को हल करेगा।

ASI के बारे में

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एक भारतीय सरकारी एजेंसी है जो पुरातात्विक अनुसंधान और देश में सांस्कृतिक-ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण और संरक्षण के लिए जिम्मेदार है।
इसकी स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी जो इसके पहले महानिदेशक भी बने।
स्थापित: 1861
संस्थापक: अलेक्जेंडर कनिंघम
महानिदेशक: प्रो किशोर कुमार बासा
मुख्यालय: नई दिल्ली

केंद्रीय ऊर्जा और NRE मंत्री और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष ने युगांडा, कोमोरोस और माली में नौ सौर प्रदर्शन परियोजनाओं का उद्घाटन किया

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) ने रवांडा सरकार द्वारा समर्थित किगाली, रवांडा में अपनी 5वीं क्षेत्रीय बैठक की मेजबानी की, जिसमें 36 देशों और 15 देशों के मंत्रियों ने भाग लिया।
बैठक में, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और भारत सरकार के केंद्रीय विद्युत और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, श्री आरके सिंह, जो नई दिल्ली से वर्चुअल बैठक में शामिल हुए, ने युगांडा गणराज्य, कोमोरोस संघ और माली गणराज्य में कुल नौ सौर ऊर्जा प्रदर्शन परियोजनाओं का उद्घाटन किया।
इनमें से चार परियोजनाएं युगांडा में, दो कोमोरोस में और तीन माली में हैं।

मुख्य विचार

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा दिए गए अनुदान के माध्यम से, युगांडा में 48,835 अमरीकी डालर की लागत से 8.5 किलो-वाट पीक और 17.2 किलो-वाट घंटे की बैटरी भंडारण प्रणाली की क्षमता वाले एक ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र और तीन प्राथमिक स्कूलों का सौरकरण शुरू किया गया है।
इसी तरह, कोमोरोस में, 15 किलो-वाट पीक क्षमता और 33 किलो-वाट घंटे की बैटरी भंडारण प्रणाली के साथ बंगुओइकोनी और इवेम्बेनी में दो ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों का सौरीकरण, 49,999 अमेरिकी डॉलर की कुल लागत पर पूरा किया गया है। माली गणराज्य के कौला, सिंजानी और डौम्बा में 13 किलो-वाट पीक क्षमता और 43 किलो-वाट घंटे की बैटरी स्टोरेज की क्षमता वाले तीन ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों का सोलराइजेशन कुल 49,995 अमेरिकी डॉलर की लागत पर किया गया है। इनमें से किसी भी क्षेत्र में पहले ऊर्जा की पहुंच नहीं थी।

ISA के बारे में:

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 120 से अधिक हस्ताक्षरकर्ता देशों का गठबंधन है, जिनमें से अधिकांश सनशाइन देश हैं, जो पूरी तरह या आंशिक रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित हैं।
स्थापित: 30 नवंबर 2015
अध्यक्ष: आरके सिंह
संस्थापक: नरेंद्र मोदी, फ्रांस्वा ओलांद
मुख्यालय: गुरुग्राम, हरियाणा, भारत

रवांडा के बारे में:

राजधानी: किगाली
मुद्रा: रवांडा फ्रैंक
प्रधान मंत्री: एडौर्ड नगिरेंटे

श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में 'मेरी माटी-मेरा देश' अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा का शुभारंभ किया

केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में 'मेरी माटी-मेरा देश' अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा का शुभारंभ किया।

मुख्य विचार:

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर, केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल, विदेश राज्य मंत्री श्रीमती सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय की सचिव मीनाक्षी लेखी और सचिव उपस्थित थे।
देश के वीर शहीद पुरुषों और महिलाओं के सम्मान में इस अभियान की घोषणा 9 अगस्त 2023 को की गई थी।
अमृत कलश यात्रा पूरे देश में आयोजन किया जाएगा और इसके तहत देश के सभी क्षेत्रों से साढ़े सात हजार कलश की मिट्टी दिल्ली की अमृत वाटिका में लाई जाएगी।
एक भारत, श्रेष्ठ भारत के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास अमृत वाटिका बनाई जाएगी।
पिछले महीने पीएम मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि यह अभियान सितंबर में शुरू किया जाएगा और देश के हर गांव के हर घर से मिट्टी ली जाएगी

नवीनतम समाचार

मई 2023 में, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने असम में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (NFSU) के गुवाहाटी परिसर की आधारशिला रखी।
जुलाई 2023 में, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह नई दिल्ली में एक दिवसीय मेगा सम्मेलन "एफपीओ के माध्यम से पैक्स को मजबूत करना" का उद्घाटन करेंगे।
जुलाई 2023 में, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह नई दिल्ली में 'ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा' पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे।

श्री परषोत्तम रूपाला मुंबई में एक दिवसीय "मत्स्य पालन के लिए KCC पर राष्ट्रीय सम्मेलन" की अध्यक्षता करेंगे

केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, श्री परषोत्तम रूपाला महाराष्ट्र के मुंबई में यशवंतराव चव्हाण केंद्र में एक दिवसीय "मत्स्य पालन के लिए केसीसी पर राष्ट्रीय सम्मेलन" की अध्यक्षता करेंगे।
जमीनी मुद्दों को सुलझाने के लिए मत्स्य पालन विभाग (DOF) और पशुपालन डेयरी विभाग (DAHD) द्वारा संयुक्त रूप से सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है।

मुख्य विचार:

राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मत्स्य पालन विभाग, NFDB और अन्य संबंधित विभागों/मंत्रालयों के प्रतिनिधियों, केसीसी लाभार्थियों, मछुआरों, मछली किसानों, उद्यमियों और देश भर के अन्य हितधारकों के भाग लेने की उम्मीद है।
कार्यक्रम हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जा रहा है और इसमें लगभग 500 प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है।
किसान क्रेडिट कार्ड वित्तीय समावेशन और सहयोग के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है जहां कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी जैसी गतिविधियों को बड़ी संख्या में गरीब और सीमांत किसानों और मछुआरों के लिए आजीविका और आय सृजन के लिए महत्वपूर्ण घटक माना जाता है।
यह अपने किसानों को समर्थन देने और समान विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य संस्थाओं के दृढ़ संकल्प का प्रतिनिधित्व करता है।

नवीनतम समाचार

जुलाई 2023 में, आज़ादी का अमृत महोत्सव और G20 के कृषि कार्य समूह (AWG) के तत्वावधान में, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री परषोत्तम रूपाला ने NDDB, आनंद, गुजरात में सतत पशुधन परिवर्तन पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया।
जून 2023 में, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला और बंदरगाह शिपिंग और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने थोप्पमपाडी, समुद्रिका हॉल, विलिंगडन द्वीप, कोचीन पोर्ट अथॉरिटी, कोचीन में कोचीन मछली पकड़ने के बंदरगाह के आधुनिकीकरण और उन्नयन पर परियोजना की आधारशिला रखी है।

महाराष्ट्र के बारे में

राज्यपाल: रमेश बैस
मुख्यमंत्री: एकनाथ शिंदे

राजधानी: मुंबई
राष्ट्रीय उद्यान: ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान
वन्यजीव अभयारण्य: भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य, करनाला पक्षी अभयारण्य, नागज़ीरा वन्यजीव अभयारण्य
यूनेस्को विरासत स्थल: छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको पहनावा, अजंता गुफाएं, एलीफेंटा गुफाएं, एलोरा गुफाएं

श्री परषोत्तम रूपाला ने तमिलनाडु में बहुउद्देश्यीय समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना की आधारशिला रखी

सागर परिक्रमा चरण VIII के तीसरे दिन, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, श्री परषोत्तम रूपाला ने तमिलनाडु में बहुउद्देश्यीय समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना के लिए आधारशिला रखी।
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री, डॉ. एल. मुरुगन, भारत सरकार में पूर्व मंत्री, श्री पोन राधाकृष्णन, संयुक्त सचिव (मत्स्य पालन), भारत सरकार, श्रीमती नीतू कुमारी प्रसाद, मुख्य कार्यकारी, राष्ट्रीय मत्स्य पालन, विकास बोर्ड (NFDB), डॉ. एलएन मूर्ति, मत्स्य पालन आयुक्त, तमिलनाडु सरकार, डॉ. केएस पलानीसामी, रामनाथपुरम जिले के कलेक्टर, श्री थिरु बी. विष्णु चंद्रन और अन्य प्रमुख गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
यह एक नए अध्याय की शुरुआत करता है और इसे भारत में समुद्री शैवाल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक पहल के रूप में देखा जाता है।

मुख्य विचार:

कार्यक्रम की शुरुआत श्री पुरुषोत्तम रूपाला, डॉ. एल. मुरुगन और अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा वलावुर, थोंडी, रामनाथपुरम में बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क स्थल पर भूमि पूजन और आधारशिला रखने के साथ की गई।
समुद्री शैवाल पार्क में तमिलनाडु के 6 तटीय जिलों नागपट्टिनम, तंजावुर, तिरुवरुर, पुदुकोट्टई, रामनाथपुरम और थूथुकुडी में 136 तटीय मछली पकड़ने वाले गांवों में समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देना शामिल है।

नवीनतम समाचार

जून 2023 में, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, श्री पुरुषोत्तम रूपाला कृषि भवन में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन और डेयर, ICAR और NSPADD के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में रिपोर्ट मछली रोग (RFD) ऐप लॉन्च करेंगे।
जून 2023 में, भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री परषोत्तम रूपाला ने "रिपोर्ट मछली रोग" के रूप में एक एंड्रॉइड-आधारित मोबाइल ऐप लॉन्च किया।

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने MoCA और CII द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एयरोस्पेस सम्मेलन का उद्घाटन किया

श्री ज्योतिरादित्य एम.सिंधिया केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ने 'अंतर्राष्ट्रीय एयरोस्पेस सम्मेलन: समावेशी वैश्विक मूल्य श्रृंखला की ओर बढ़ना' का उद्घाटन किया।
यहथानागरिक उड्डयन मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) द्वारा संयुक्त रूप से 1 और 2 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित किया गया।
अंतर्राष्ट्रीय एयरोस्पेस सम्मेलन जी20 और बी20 प्राथमिकता के तहत एयरोस्पेस क्षेत्र में एक जी20 पहल है, जो वैश्विक व्यापार और निवेश के लिए समावेशी वैश्विक मूल्य श्रृंखला विकसित करने पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य जी20 देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना और मजबूत करना है।

मुख्य विचार:

बुनियादी ढांचे का विकास: नौ साल पहले भारतीय नागरिक उड्डयन क्षेत्र में केवल 74 हवाई अड्डे थे; अब यह हेलीपोर्ट और जल हवाई अड्डों सहित 148 हवाई अड्डों तक पहुंच गया है। सरकार आने वाले तीन से पांच वर्षों में इस संख्या को दो सौ से ऊपर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है;

विमान की उपलब्धता: पहले 2014 में 400 विमान थे अब यह संख्या लगभग 700 तक पहुंच गई है और लगभग 1000 और ऑर्डर पर हैं;
पारिस्थितिकी तंत्र विकास: एयर इंडिया के विनिवेश ने देश में नागरिक उड्डयन उद्योग में न केवल यात्रियों के लिए, न केवल हवाई अड्डों के लिए, बल्कि एमआरओ, विनिर्माण क्षेत्र और कार्गो के लिए भी परिवर्तन लाया है। एयर इंडिया और इंडिगो द्वारा दिए गए विमानों के भारी ऑर्डर और अकाशा जैसे नए खिलाड़ियों का उदय भारतीय नागरिक उड्डयन उद्योग में हो रहे बदलावों का एक और उदाहरण है;
क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पर जोर: उड़ान ने देश में 4 नई क्षेत्रीय एयरलाइनों को जन्म दिया है। हम दशकों से जिस हब और कनेक्टिविटी नेटवर्क की बात कर रहे हैं वह भारत में एक वास्तविकता है।

नवीनतम समाचार

अप्रैल 2023 में, भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) की राष्ट्रीय परिषद ने TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशंस के कार्यकारी उपाध्यक्ष आर दिनेश को 2023-24 के लिए CII के अध्यक्ष के रूप में चुना।
मई 2023 में, नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में हेली शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया।

CII के बारे में:

स्थापित: 1895
मुख्यालय: नई दिल्ली, दिल्ली, भारत
महानिदेशक: चंद्रजीत बनर्जी
CII एक गैर-सरकारी व्यापार संघ और वकालत समूह है।

जलवायु अनुकूल कृषि पर G20 तकनीकी कार्यशाला तेलंगाना के हैदराबाद में शुरू हुई

जलवायु लचीले कृषि पर तीन दिवसीय जी20 तकनीकी कार्यशाला का उद्घाटन केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री सुश्री शोबा करंदलाजे ने हैदराबाद के शमशाद में किया।
इस कार्यक्रम में भारत और विदेश से G20 देशों और आमंत्रित देशों सहित 100 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।

मुख्य विचार:

केंद्रीय मंत्री ने वैश्विक, जलवायु परिवर्तन पर चिंता व्यक्त की, जिससे वृद्धि और विकास में कई चुनौतियां पैदा हो रही हैं। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र सबसे संवेदनशील प्रतीत होता है और यह जलवायु परिवर्तन से काफी प्रभावित है और कृषि पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पहले से ही महसूस किया जा रहा है।
मंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दीर्घकालिक और एकीकृत रणनीतियों के साथ जलवायु परिवर्तन पर नेटवर्क प्रोजेक्ट (NPCC), जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) जैसी कई पहल देश द्वारा शुरू की गई हैं।
बैठक में कृषि अनुसंधान के विभिन्न मुद्दों, मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन और वैश्विक संदर्भ में कृषि के सतत विकास के लिए अन्य तकनीकों और तरीकों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।
गणमान्य व्यक्ति देश की उपलब्धियों और विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से कृषि और किसानों की चुनौतियों का समाधान करने के निरंतर प्रयासों को भी साझा करेंगे।
प्रारंभिक टिप्पणी एनआरएम के उप महानिदेशक डॉ. एसके चौधरी ने की, जबकि महानिदेशक डॉ. हिमांशु पाठक ने कृषि और बाजरा को बढ़ावा देने के लिए देश के प्रयासों के बारे में बताया।

तेलंगाना के बारे में:

राज्यपाल: तमिलिसाई सुंदरराजन
मुख्यमंत्री: के.चंद्रशेखर राव
पूंजी: हैदराबाद
राष्ट्रीय उद्यान: मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान, महावीर हरिणा वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान

नवीनतम समाचार

जून 2023 में, अमूल के विपणक गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड (GCMMF) ने 5 लाख लीटर प्रति दिन (LLPD) की क्षमता वाला दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए हैदराबाद के पास वर्गल में भूमि की पहचान की है।
जुलाई 2023 में, तेलंगाना सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नवाचार के लिए एक ग्रैंड चैलेंज शुरू किया है।
मई 2023 में, भारत में अपनी तरह की पहली नीति में, तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना राज्य रोबोटिक्स फ्रेमवर्क पेश किया है, जो तेलंगाना में रोबोटिक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए एक रोडमैप प्रदान करता है।

संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली में एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम लॉन्च किया

संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने विरासत स्थल पर आगंतुकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए नई दिल्ली में एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम लॉन्च किया।
इस कार्यक्रम की परिकल्पना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा निजी क्षेत्र की कंपनियों, ट्रस्टों और गैर सरकारी संगठनों के साथ सहयोग करने के लिए की गई है।
इसका उद्देश्य भारत की समृद्ध संस्कृति विरासत को प्रदर्शित करते हुए देश भर में फैले तीन हजार 697 संरक्षित स्मारकों में सुविधाएं बढ़ाने में कॉर्पोरेट हितधारकों को शामिल करना है।

मुख्य विचार:

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की प्राचीन विरासत को समृद्ध करने के लिए 2014 के बाद कई कदम उठाए हैं।
उन्होंने कहा, देश के विकास के साथ विरासत का संरक्षण भी जरूरी है।
इस अवसर पर संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम के माध्यम से भारत के इतिहास की विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। उन्होंने देश की विरासत और संस्कृति की रक्षा करने की आवश्यकता पर बल दिया।
श्रीमती लेखी ने कहा कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के माध्यम से विरासत पर अब तक मात्र 0.7 फीसदी ही काम हो रहा है

नवीनतम समाचार

जुलाई 2023 में, केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी, नई दिल्ली में प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने गुजरात में अमृता पटेल सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने गुजरात के आनंद में अमृता पटेल जन स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर संबोधित करते हुए, श्री मंडाविया ने कहा, भारत स्वास्थ्य क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है।
सरकार देश में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए समग्र स्वास्थ्य पर जोर दे रही है।
उन्होंने कहा कि पिछले नौ वर्षों के दौरान देश में MBBS सीटों और मेडिकल कॉलेजों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
उन्होंने कहा, सरकार सभी के लिए सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए व्यापक प्रयास कर रही है।

नवीनतम समाचार

अप्रैल 2023 में, भारत का स्वच्छ हाइड्रोजन मिशन गुजरात में हाइड्रोजन वैली परियोजना से बढ़ावा मिला।
जून 2023 में, गुजरात कैबिनेट ने स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए गुजरात के 13 जिलों में 21 नए औद्योगिक एस्टेट स्थापित करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी।
जून 2023 में, भारत की G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में, तीसरी व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक केवडिया, गुजरात में शुरू हुई।

गुजरात के बारे में:

राज्यपाल: आचार्य देवव्रत
मुख्यमंत्री: भूपेन्द्रभाई पटेल
राजधानी: गांधीनगर
राष्ट्रीय उद्यान: वंसदा राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, वेलावदर राष्ट्रीय उद्यान
वन्यजीव अभयारण्य: जम्बुघोड़ा वन्यजीव अभयारण्य, बरदा वन्यजीव अभयारण्य, शूलपनेश्वर वन्यजीव अभयारण्य

श्री धर्मेंद्र प्रधान ने मेटा के साथ 3 साल की साझेदारी शुरू की, शिक्षा से उद्यमिता तक: छात्रों, शिक्षकों और उद्यमियों की एक पीढ़ी को सशक्त बनाना

केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और मेटा के बीच 3 साल की साझेदारी "उद्यमिता के लिए शिक्षा: छात्रों, शिक्षकों और उद्यमियों की एक पीढ़ी को सशक्त बनाना" शुरू की।
मेटा और NIESBUD, AICTE और CBSE के बीच 3 आशय पत्रों (LOI) का आदान-प्रदान किया गया।
शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती. अन्नपूर्णा देवी और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री श्री राजीव चन्द्रशेखर भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

मुख्य विचार

श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि शुरू की गई पहल भारत को दुनिया की कौशल राजधानी बनाने और हमारी अमृत पीढी को सशक्त बनाने के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए है।
उन्होंने आगे कहा कि 'एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप' साझेदारी एक गेम-चेंजर है, जो डिजिटल स्किलिंग को जमीनी स्तर तक ले जाएगी।
यह हमारे प्रतिभा पूल की क्षमताओं का निर्माण करेगा, छात्रों, युवाओं, कार्यबल और सूक्ष्म-उद्यमियों को भविष्य की प्रौद्योगिकियों के साथ सहजता से जोड़ेगा और हमारी अमृत पीढी को नए युग के समस्या समाधानकर्ताओं और उद्यमियों में बदल देगा।
सचिव, उच्च शिक्षा, श्री के. संजय मूर्ति; स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव, श्री संजय कुमार; सचिव, MSDE श्री अतुल कुमार तिवारी; अध्यक्ष, AICTE, प्रोफेसर टीजी सीतारम; अध्यक्ष, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम NBA NAAC, प्रोफेसर अनिल सहस्रबुद्धे; फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) के अध्यक्ष, श्री सुभ्रकांत पांडा और मंत्रालयों, AICTE, CBSE, राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (NIESBUD) के वरिष्ठ अधिकारी; श्री शिवनाथ ठुकराल, निदेशक, सार्वजनिक नीति, भारत और दक्षिण एशिया, मेटा और संध्या देवनाथन, मेटा इंडिया के उपाध्यक्ष भी उपस्थित थे।

नवीनतम समाचार

मई 2023 में, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली से गैबॉन की पहली कृषि-SEZ परियोजना को हरी झंडी दिखाई।

ज्ञान साझा करने के लिए केंद्र का डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर शिक्षा मंच AI सहायता प्रदान करेगा

नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD) पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग (PAL) को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग (DIKSHA) प्लेटफॉर्म में एकीकृत करेगा।
व्यक्तिगत अनुकूली शिक्षण के तहत, प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत सीखने का अनुभव होगा।

मुख्य विचार:

शिक्षा मंत्रालय के तहत दीक्षा एक ऑनलाइन पोर्टल और एक मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से स्कूलों के लिए ई-सामग्री प्रदान करती है।
DIKSHA प्लेटफ़ॉर्म में दृश्य या श्रवण बाधित शिक्षार्थियों के लिए सहायक तकनीकें अंतर्निहित हैं।
इसने NCERT पाठ्यपुस्तकों को डिजिटल कर दिया है जिनका उपयोग राष्ट्रीय और राज्य बोर्डों में किया जाता है।

इस मंच पर कई शिक्षाविदों द्वारा योगदान किए गए शिक्षण वीडियो, व्याख्याकार और अभ्यास प्रश्न हैं।
NCERT ने दीक्षा के लिए PAL को सुविधा प्रदान करने के लिए MeitY की विशेषज्ञता मांगी।
PAL के लिए, विभिन्न विषयों की सामग्री को वर्गीकृत करना होगा और विभिन्न भागों को टैग करना होगा।

दीक्षा के बारे में

दीक्षा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की एक पहल है।
इसमें 33 भाषाओं में कक्षा 1-12 के लिए क्यूआर-कोडित पाठ्यपुस्तकें और विभिन्न विशिष्ट ई-सामग्री हैं।
इसे 5 सितंबर 2017 को लॉन्च किया गया था।

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की, NCERT को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला

सरकार ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया है।
यह घोषणा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में NCERT के 63वें स्थापना दिवस समारोह कार्यक्रम में भाग लेने के दौरान की।
शिक्षा मंत्री ने यह भी घोषणा की कि बाल भवन का जल्द ही NCERT में विलय कर दिया जाएगा।

मुख्य विचार

बाल भवन एक स्वायत्त संस्थान है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
प्रधान मंत्री, जवाहरलाल नेहरू ने 1956 में इसकी स्थापना की।
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संवर्धित वास्तविकता (AR) और आभासी वास्तविकता (VR) प्रयोगशाला का उद्घाटन किया।
AR और VR सुविधा से देश के हर कोने के अलग-अलग बोली वाले बच्चों को लाभ मिलेगा।
इस अवसर पर उन्होंने एक विद्या समीक्षा केंद्र का भी उद्घाटन किया।
उन्होंने NCERT को सभी 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं में चंद्रयान-3 की सफलता और निष्कर्षों पर एक संक्षिप्त अध्याय जोड़ने का निर्देश दिया।
डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दी गई एक मान्यता है।
मान्यता "विश्वविद्यालय की शैक्षणिक स्थिति और विशेषाधिकार" प्रदान करती है।

NCERT के बारे में

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) एक स्वायत्त संगठन है।
इसकी स्थापना 1961 में की गई थी।
डॉ. दिनेश प्रसाद सकलानी इसके निदेशक हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की दो दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया की दो दिवसीय यात्रा पर होंगे।
दोनों शिखर सम्मेलनों की मेजबानी आसियान के वर्तमान अध्यक्ष इंडोनेशिया द्वारा जकार्ता में की जाएगी।
नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्व) सौरभ कुमार ने कहा, 20वां आसियान-भारत शिखर सम्मेलन विशेष है क्योंकि पिछले साल भारत-आसियान संबंधों के व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचने के बाद यह पहला शिखर सम्मेलन है।
शिखर सम्मेलन के दौरान, प्रधान मंत्री आसियान-भारत संबंधों में प्रगति की समीक्षा करेंगे और उन्हें आगे की दिशा प्रदान करेंगे।
भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का संस्थापक सदस्य है।
उन्होंने कहा, कि शिखर सम्मेलन के दौरान, प्रधान मंत्री और अन्य नेता पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन तंत्र को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे और साथ ही क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हितों के मामलों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे।

इंडोनेशिया के बारे में:

राष्ट्रपति: जोको विडोडो
मुद्रा: इंडोनेशियाई रुपिया (आरपी)

नवीनतम समाचार

जुलाई 2023 में, प्रधान मंत्री (पीएम) श्री नरेंद्र मोदी पेरिस, फ्रांस में फ्रेंच बैस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि होंगे

G20 शिखर सम्मेलन से पहले 'भारत में ग्रीन हाइड्रोजन पायलट' सम्मेलन आयोजित किया गया

18वें G20 शिखर सम्मेलन के क्रम में, "भारत में ग्रीन हाइड्रोजन पायलट" पर एक दिवसीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।
सम्मेलन में भारत की सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न ग्रीन हाइड्रोजन पायलटों का प्रदर्शन किया गया।
राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन पायलट परियोजनाएं हैं, जिन्हें 1,466 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
NTPC लिमिटेड द्वारा आयोजित सम्मेलन में हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी में अग्रणी नवोन्मेषी पायलटों और प्रगति पर भी प्रस्तुति दी गई।

मुख्य विचार:

मंत्री ने चल रहे हरित हाइड्रोजन पायलटों और इस दिशा में भारत द्वारा उठाए जा रहे कदमों का अवलोकन दिया।
भारत और दुनिया भर में कई हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हमारे पास ग्रीन स्टील और हेवी-ड्यूटी परिवहन के लिए पायलट हैं।
लंबी दूरी की भारी गतिशीलता के लिए विद्युत गतिशीलता व्यवहार्य नहीं है; इसलिए हाइड्रोजन या अमोनिया उत्तर है।
शिपिंग के क्षेत्र में दुनिया भर के देश कुछ जहाज तैयार कर रहे हैं।
लगभग 10 वर्षों के भीतर विश्व शिपिंग हरित हो जाएगी।
सचिव ने बताया कि इस्पात के लिए 456 करोड़ रुपये, परिवहन के लिए 495 करोड़ रुपये, शिपिंग के लिए 115 करोड़ रुपये और अन्य परियोजनाओं के लिए 400 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।
पायलट परियोजनाओं का लक्ष्य इन क्षेत्रों में क्रांति लाना और स्थिरता और नवाचार के लिए नए मानक स्थापित करने का वादा करना है।
श्री भल्ला ने कहा कि एमएनआरई ने पहले ही संबंधित मंत्रालयों, अर्थात् सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय और बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय से संबंधित क्षेत्रों में पायलट परियोजनाओं के लिए अपने प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया था।

जल जीवन मिशन ने 13 करोड़ ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन का मील का पत्थर हासिल किया

जल जीवन मिशन (JJM) ने 13 करोड़ ग्रामीण घरों में नल का पानी कनेक्शन प्रदान करके एक और मील का पत्थर हासिल किया।
'गति और पैमाने' के साथ काम करते हुए, जीवन बदलने वाले मिशन ने ग्रामीण नल कनेक्शन कवरेज को अगस्त 2019 में मिशन की शुरुआत में केवल 3.23 करोड़ घरों से बढ़ाकर केवल 4 वर्षों में 13 करोड़ कर दिया है।
जल जीवन मिशन की घोषणा प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीर से की थी जब देश ने अपना 73 वां स्वतंत्रता दिवस मनाया था।

मुख्य विचार

6 राज्य अर्थात् गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात, पंजाब और हिमाचल प्रदेश) और 3 केंद्र शासित प्रदेशों - पुडुचेरी, D&D और D&NH और A&N द्वीप समूह ने 100% कवरेज की सूचना दी है। बिहार 96.39% पर, उसके बाद मिजोरम 92.12% पर, भी निकट भविष्य में संतृप्ति प्राप्त करने के लिए तैयार हैं।

गोवा, हरियाणा, पंजाब, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी, D&D और D&NH और A&N 'हर घर जल प्रमाणित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश हैं यानी इन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में, ग्रामीणों ने ग्राम सभाओं के माध्यम से पुष्टि की है कि 'गांव के सभी घरों और सार्वजनिक संस्थानों को पानी की पर्याप्त, सुरक्षित और नियमित आपूर्ति मिल रही है।
देश के 145 जिलों और 1,86,818 गांवों ने 100% कवरेज की सूचना दी है।
मिशन राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ साझेदारी में कार्यक्रम को कार्यान्वित करता है और यह विकास भागीदारों सहित सभी के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है कि परिवर्तनकारी परिवर्तन जमीन पर देखा जाता है।
हर सेकंड एक नल जल कनेक्शन स्थापित किया जा रहा है जिससे देश का ग्रामीण परिदृश्य बदल रहा है। 1 जनवरी 2023 से हर दिन औसतन 87,500 नल कनेक्शन दिए जा रहे हैं।
उत्तर प्रदेश जनवरी 2023 से 61.05 लाख कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) स्थापित करके चालू वित्त वर्ष में प्रगति चार्ट में शीर्ष पर है।

नवीनतम समाचार

मई 2023 में, आजादी का अमृत काल के तहत, जल जीवन मिशन (JJM) देश के 12 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में नल के माध्यम से सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने की एक नई उपलब्धि का जश्न मना रहा है।

G20 शिखर सम्मेलन स्थल पर विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा स्थापित की गई

दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल भारत मंडपम में दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा स्थापित की गई है।
20 टन वजनी 28 फुट ऊंची प्रतिमा को तमिलनाडु के तंजावुर जिले के स्वामीमलाई में मूर्तिकार राधाकृष्णन स्टापथी और उनकी टीम ने सात महीने के रिकॉर्ड समय में बनाया था।
मूर्ति का निर्माण पारंपरिक कास्टिंग विधि का उपयोग करके अष्टधातु (8 धातुओं) में किया गया था।
प्रतिमा को चार दिनों में राष्ट्रीय राजधानी तक पहुंचाया गया और इसके परिवहन के लिए एक विशेष हरित गलियारा बनाया गया।

आयकर रिटर्न की प्रोसेसिंग का औसत समय घटकर 10 दिन हो गया

आयकर रिटर्न का औसत प्रसंस्करण समय आकलन वर्ष 2023-24 में (ITR) को घटाकर दस दिन कर दिया गया है।
आकलन वर्ष 2019-20 में आईटीआर का औसत प्रसंस्करण समय 82 दिन था, और आकलन वर्ष 2022-23 में 16 दिन था।
आयकर विभाग ने कहा, वह करदाताओं के लिए ITR को त्वरित और कुशल तरीके से संसाधित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्य विचार:

विभाग के मुताबिक, आकलन वर्ष 2023-24 के लिए छह करोड़ 98 लाख ITR दाखिल किए गए, जिनमें से 6 करोड़ 84 लाख ITR सत्यापित हो चुके हैं।
विभाग ने बताया कि आकलन वर्ष 2023-24 के लिए दो करोड़ 45 लाख से अधिक रिफंड पहले ही जारी किए जा चुके हैं।
आयकर विभाग ने कहा, ऐसे कई मामले हैं जिनमें ITR संसाधित हो चुका है और रिफंड भी निर्धारित किया जा चुका है, लेकिन विभाग उन्हें जारी करने में असमर्थ है।
इसमें कहा गया है कि करदाताओं ने अभी तक अपने बैंक खाते को सत्यापित नहीं किया है जिसमें रिफंड जमा किया जाना है।
विभाग ने करदाताओं से रिफंड प्राप्त करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से अपने बैंक खातों को मान्य करने का आग्रह किया।

भारत ने दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल, आरोग्य मैत्री क्यूब का अनावरण किया

भारत ने दुनिया का पहला आपदा अस्पताल बनाया है जिसे हवाई मार्ग से 72 क्यूब्स में पैक करके ले जाया जा सकता है।
इसे 'आरोग्य मैत्री क्यूब' नाम दिया गया है.

आरोग्य मैत्री क्यूब क्या है?

आरोग्य मैत्री क्यूब दुनिया का पहला आपदा अस्पताल है जिसे हवाई मार्ग से ले जाया जा सकता है।
इसे प्रोजेक्ट भीष्म (सहयोग हित और मैत्री के लिए भारत स्वास्थ्य पहल) के तहत स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है।
इसे मित्र देशों को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने के लिए भारत की 'आरोग्य मैत्री' पहल के हिस्से के रूप में विकसित किया गया है।

प्रमुख विशेषताऐं:

आरोग्य मैत्री क्यूब 72 क्यूब्स में पैक किया गया है।
इन क्यूब्स में आवश्यक उपकरण और आपूर्ति होती है, जैसे एक ऑपरेशन थिएटर, एक मिनी-ICU, वेंटिलेटर, रक्त परीक्षण उपकरण, एक एक्स-रे मशीन, एक खाना पकाने का स्टेशन, भोजन, पानी, आश्रय, एक बिजली जनरेटर, और बहुत कुछ।
विशेष पिंजरे में 100 लोगों के दो दिनों तक जीवित रहने के लिए आवश्यक आपूर्ति से भरे 36 मिनी-क्यूब्स रखे जा सकते हैं।
इनमें से दो पिंजरे हैं, जिन्हें मास्टर क्यूब्स कहा जाता है, जिन्हें 200 जीवित बचे लोगों को सहारा देने के लिए जोड़ा जा सकता है।
इन क्यूब्स की प्रमुख विशेषताओं में से एक विभिन्न गंभीर चोटों को संभालने की उनकी क्षमता है, जिसमें गोली लगने की चोटें, बड़े रक्तस्राव आदि शामिल हैं।

भारत के तीन-चौथाई सिंचाई स्रोत बिजली से चलते हैं:

लघु सिंचाई जनगणना (MIC) के नवीनतम/छठे संस्करण से पता चलता है कि पानी निकालने के लिए डीजल, पवन चक्कियों और सौर पंपों की तुलना में बिजली प्रमुख स्रोत (3/4) है।
MIC किसानों के बोरवेल, ट्यूबवेल और अन्य निजी स्वामित्व वाले सिंचाई स्रोतों का एक संग्रह है।
कुल मिलाकर, देश में 695 जिलों से 23.14 मिलियन MI योजनाएं रिपोर्ट की गईं, जो पांचवें और छठे संस्करण के बीच लगभग 1.42 मिलियन की वृद्धि दर्शाती है।
अधिकांश योजनाएँ (96.6%) निजी स्वामित्व वाली थीं और छोटे और सीमांत किसान, जिनके पास दो हेक्टेयर से कम भूमि थी, अधिकांश एमआई योजनाओं के मालिक थे।
सभी MI योजनाओं में से, 21.93 मिलियन (94.8%) भूजल (GW) के लिए और 1.21 मिलियन (5.2%) सतही जल (SW) निष्कर्षण के लिए थे।
यूपी में देश में सबसे बड़ी MI योजनाएं (17.2 फीसदी) थीं, इसके बाद महाराष्ट्र (15.4 फीसदी) और एमपी (9.9 फीसदी) थे।
GW योजनाओं में अग्रणी राज्य यूपी, महाराष्ट्र, एमपी हैं; जबकि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, ओडिशा और झारखंड की SW में सबसे अधिक हिस्सेदारी है
भूजल या सतही जल का उपयोग करने वाली और व्यक्तिगत रूप से 2000 हेक्टेयर तक खेती योग्य कमांड क्षेत्र वाली सिंचाई योजनाओं को लघु सिंचाई योजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
लघु सिंचाई कृषि और आजीविका के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, विशेष रूप से सूखाग्रस्त क्षेत्रों और प्रमुख और मध्यम परियोजनाओं की कमान से बाहर के क्षेत्रों में।
योजनाओं को मोटे तौर पर 6 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है:
डगवेल (अधिकतम 15 मीटर की गहराई से पानी खींच सकता है),
उथला ट्यूबवेल (35 मीटर तक पानी खींचने में सक्षम),
मध्यम ट्यूबवेल (70 मीटर तक),
गहरा ट्यूबवेल (70 मीटर से अधिक),
भूतल प्रवाह योजनाएं और
भूतल लिफ्ट योजनाएं.
लघु सिंचाई योजनाओं की पहली जनगणना संदर्भ वर्ष 1986-87 के साथ आयोजित की गई थी।
यह छठा MIC है, जो दिल्ली, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली और लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में संदर्भ वर्ष 2017-18 के साथ आयोजित किया गया है।

जबकि 'खुदे हुए कुएं' या तालाब भूजल का प्रमुख स्रोत बने हुए हैं, 5वें और 6वें संस्करण के बीच उनकी संख्या 87 लाख से घटकर 82 लाख हो गई है।
'उथले' ट्यूबवेल 59 लाख से घटकर 55 लाख रह गए हैं।
हालाँकि, 'मध्यम आकार' के कुएं 31 लाख से बढ़कर 43 लाख हो गए और 'गहरे' कुएं 26 लाख से बढ़कर 37 लाख हो गए।

मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए औद्योगिक विकास योजना, 2017 के तहत अतिरिक्त धन की आवश्यकता को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए औद्योगिक विकास योजना (IDS), 2017 के लिए 1164.53 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी है।
भारत सरकार ने 2018 में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य के लिए अधिसूचना संख्या 2(2)/2018-SPS दिनांक 23 अप्रैल 2018 के माध्यम से औद्योगिक विकास योजना, 2017 की घोषणा की।
इस योजना के तहत कुल वित्तीय परिव्यय 131.90 करोड़ रुपये था।
यह आवंटित धनराशि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान समाप्त हो गई है।
इसके अलावा, 2028-2029 तक प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता 1164.53 करोड़ रुपये है।
मंत्रिमंडल ने आयोजित अपनी बैठक में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए औद्योगिक विकास योजना 2017 के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के प्रस्ताव पर विचार किया और 2028-29 तक योजना के तहत प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धन आवश्यकताओं के लिए मंजूरी दे दी।
हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य के लिए IDS, 2017 का वित्तीय परिव्यय केवल 131.90 करोड़ रुपये था, जो 2021-2022 के दौरान जारी किया गया था।
इसके अलावा, 2028-29 तक योजना के तहत धन की अतिरिक्त आवश्यकता के माध्यम से प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए, कैबिनेट ने योजना के तहत 1164.53 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय परिव्यय राशि को मंजूरी दे दी है।

ऋण तक पहुंच के लिए केंद्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन (CCIIAC):

हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में कहीं भी स्थित विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में पर्याप्त विस्तार करने वाली सभी पात्र नई औद्योगिक इकाइयों और मौजूदा औद्योगिक इकाइयों को 5.00 करोड़ रुपये की ऊपरी सीमा के साथ संयंत्र और मशीनरी में निवेश के लिए क्रेडिट तक पहुंच (CCIIAC) @ 30% के लिए केंद्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

केंद्रीय व्यापक बीमा प्रोत्साहन (CCII):

हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में कहीं भी स्थित सभी पात्र नई औद्योगिक इकाइयां और उनके पर्याप्त विस्तार पर मौजूदा औद्योगिक इकाइयां तिथि से अधिकतम 5 वर्षों की अवधि के लिए भवन और संयंत्र और मशीनरी के बीमा पर 100% बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगी।

एचपी के बारे में:

राज्यपाल: शिव प्रताप शुक्ला
मुख्यमंत्री: सुखविंदर सिंह सुक्खू
राजधानी: शिमला (ग्रीष्मकालीन), धर्मशाला (शीतकालीन)
वन्यजीव अभयारण्य: दारनघाटी अभयारण्य, कंवर अभयारण्य, रूपी भावा अभयारण्य

उत्तराखंड के बारे में:

राज्यपाल: गुरमित सिंह
मुख्यमंत्री: पुष्कर सिंह धामी
राष्ट्रीय उद्यान: कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान
वन्यजीव अभयारण्य: बिनसर वन्यजीव अभयारण्य, झिलमिल वन्यजीव अभयारण्य

नवीनतम समाचार

मई 2023 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) और मिस्र प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण (ECA) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी।
मई 2023 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन (CITIIS) 2.0 कार्यक्रम को अधिकृत किया, जो एक प्रतियोगिता के माध्यम से चुने गए 18 स्मार्ट शहरों में एक परिपत्र अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करेगा।

मंत्रिमंडल ने बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (BESS) के विकास के लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण नामक योजना को मंजूरी दी

माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) के विकास के लिए व्यवहार्यता गैप फंडिंग (VGF) योजना को मंजूरी दे दी है।
अनुमोदित योजना में 2030-31 तक 4,000 मेगावाट की BESS परियोजनाओं के विकास की परिकल्पना की गई है, जिसमें व्यवहार्यता गैप फंडिंग (VGF) के रूप में बजटीय सहायता के रूप में पूंजीगत लागत का 40% तक वित्तीय सहायता शामिल है।
सरकार द्वारा उठाए गए पर्यावरण-समर्थक उपायों की लंबी सूची में एक महत्वपूर्ण क्षण, इस कदम से बैटरी भंडारण प्रणालियों की लागत कम होने और उनकी व्यवहार्यता बढ़ने की उम्मीद है।
सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की क्षमता का दोहन करने के लिए बनाई गई इस योजना का उद्देश्य नागरिकों को स्वच्छ, विश्वसनीय और सस्ती बिजली प्रदान करना है।
3,760 करोड़ रुपये के बजटीय समर्थन सहित 9,400 करोड़ रुपये के प्रारंभिक परिव्यय के साथ BESS योजना के विकास के लिए VGF, स्थायी ऊर्जा समाधानों के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
VGF समर्थन की पेशकश करके, योजना का लक्ष्य भंडारण की एक स्तरीय लागत (LCOS) प्राप्त करना है। 5.50-6.60 प्रति किलोवाट-घंटा (kWh), जो देश भर में चरम बिजली की मांग के प्रबंधन के लिए संग्रहीत नवीकरणीय ऊर्जा को एक व्यवहार्य विकल्प बनाता है।
VGF को BESS परियोजनाओं के कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों से जुड़े पांच किश्तों में वितरित किया जाएगा।

नवीनतम समाचार

जून 2023 में, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने आज विपणन सीजन 2023-24 के लिए सभी अनिवार्य खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी।
जून 2023 में, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने 2021-22 से 2025-26 तक 2980 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय के साथ "कोयला और लिग्नाइट योजना की खोज" की केंद्रीय क्षेत्र की योजना को 15 वें वित्त आयोग चक्र के साथ 2021-22 से 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी।

NTPC लिमिटेड एक महीने में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन का उद्घाटन करेगा

NTPC लिमिटेड, एक राज्य के स्वामित्व वाली बिजली उत्पादक, आने वाले महीने के भीतर लद्दाख में भारत के पहले उद्घाटन ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन को चालू करने के लिए तैयार है।
हरित हाइड्रोजन का उत्पादन और उपयोग: यह परियोजना 99.97% शुद्धता पर मापते हुए प्रतिदिन 80 किलोग्राम असाधारण शुद्ध हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए डिज़ाइन की गई है।
यह हाइड्रोजन ईंधन भरने सहित विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए संपीड़न, भंडारण और वितरण से गुजरेगा।
लद्दाख में हाइड्रोजन ईंधन सेल बसें: NTPC का इरादा लद्दाख क्षेत्र में 5 हाइड्रोजन ईंधन सेल बसें शुरू करने का है।
एक मौजूदा NTPC हाइड्रोजन बस भी हाइड्रोजन ईंधन का उपयोग करने के लिए इसे ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन (FCEV) में बदल देगी।
ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन प्रक्रिया लेह में स्थापित सौर ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर निर्भर करेगी, जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग पर प्रकाश डालेगी।

NTPC विंध्याचल में एक और महत्वाकांक्षी हाइड्रोजन पायलट परियोजना चला रहा है, जिसका लक्ष्य प्रति दिन 10 टन हरित मेथनॉल का उत्पादन करना है।
यह परियोजना पहले से ही कमीशनिंग के उन्नत चरण में है और 31 दिसंबर 2023 तक पूरी तरह से चालू होने की उम्मीद है।

NTPC लिमिटेड के बारे में:

स्थापना: 7 नवंबर 1975
मुख्यालय: नई दिल्ली, दिल्ली, भारत
अध्यक्ष और MD: गुरदीप सिंह
NTPC लिमिटेड, जिसे पहले नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के नाम से जाना जाता था, एक भारतीय केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र हैविद्युत मंत्रालय और भारत सरकार के स्वामित्व वाला उपक्रम, जो बिजली उत्पादन और अन्य गतिविधियों में लगा हुआ है।

पर्यटन मंत्रालय 'कल के लिए पर्यटन' विषय पर राष्ट्रीय प्रतियोगिता शुरू करेगा

पर्यटन मंत्रालय जी20 गोवा रोडमैप की पांच प्राथमिकताओं के अनुरूप सर्वोत्तम प्रथाओं और केस अध्ययनों की पहचान करने के लिए 'कल के लिए पर्यटन' पर एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता शुरू की जाएगी।
प्रतियोगिता का शुभारंभ 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस पर किया जाएगा।
जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान अपनाई गई नई दिल्ली नेताओं की घोषणा ने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के माध्यम के रूप में 'पर्यटन के लिए गोवा रोडमैप' के महत्व को रेखांकित किया।

मुख्य विचार

नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन पर्यटन क्षेत्र को एक नई दिशा प्रदान करता है। G20 गोवा रोडमैप सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्यटन क्षेत्र के लिए चुनौतियों, उद्देश्यों, अवसरों और सिफारिशों की रूपरेखा तैयार करता है।
'GOA रोडमैप', भारत के G20 टूरिज्म ट्रैक का प्रमुख वितरण, एक अग्रणी पहल है जो टिकाऊ वैश्विक पर्यटन के लिए एक खाका प्रदान करता है।
भारत की जी20 प्रेसीडेंसी की थीम के अनुरूप गोवा का रोडमैप, समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण प्रबंधन में पर्यटन की भूमिका को रेखांकित करता है।
रोडमैप पांच प्राथमिकताओं पर केंद्रित है: हरित पर्यटन, डिजिटलीकरण, कौशल, पर्यटन MSME और गंतव्य प्रबंधन।
यह राष्ट्रों को अपनी पर्यटन नीतियों को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 2030 के साथ संरेखित करने के लिए एक व्यापक रणनीति प्रदान करता है।
जी20 नेताओं ने जिम्मेदार और टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा देने में इसकी परिवर्तनकारी क्षमता पर जोर देते हुए "जीवन के लिए यात्रा" पहल के शुभारंभ का भी समर्थन किया।
पर्यटन मंत्रालय का लक्ष्य शिक्षा और जागरूकता अभियानों के माध्यम से गोवा रोडमैप कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाना है।
इन अभियानों के माध्यम से, राज्य सरकारों और निजी हितधारकों को अधिक टिकाऊ, लचीला और समावेशी पर्यटन के निर्माण के लिए अपने संचालन में प्रमुख अनुशंसित कार्यों को शामिल करने के बारे में संवेदनशील बनाया जाएगा।

FSSAI आधिकारिक तौर पर मिथुन को एक खाद्य पशु के रूप में मान्यता देता है

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने हाल ही में अर्ध पालतू गोजातीय पशु मिथुन को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी है, जिससे पूर्वोत्तर की पहाड़ियों पर इसकी खपत और वाणिज्यिक पालन को बढ़ावा देने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
मिथुन को घरेलू पशु विविधता सूचना प्रणाली (DADIS) डेटाबेस में शामिल किया गया है।
300 से 3,000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाले मिथुन पारंपरिक रूप से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में विभिन्न जनजातियों की संस्कृति का हिस्सा रहे हैं।
हालाँकि, FSSAI द्वारा इसे खाद्य पशु के रूप में मान्यता दिए बिना मांस और उसके दूध की खपत को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है।

यह अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का राज्य पशु है और मुख्य रूप से सामुदायिक खेतों में मांस के लिए पाला जाता है।
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम वैश्विक मिथुन उत्पादन का लगभग 98% हिस्सा हैं।
2019 में एक अनुमान के अनुसार मिथुन की जनसंख्या 3.9 लाख थी, जिसमें से अकेले अरुणाचल प्रदेश में 3.50 लाख थी।
NRCM ने पहली बार 2017 में FSSAI की मान्यता के लिए आवेदन किया था।
FSSAI की मान्यता का जश्न मनाने के लिए, NCM ने नागालैंड के मेडजिफेमा में अपने परिसर में पहला राष्ट्रीय मिथुन दिवस (1 सितंबर) मनाया।
मिथुन मांस को एक ब्रांड नाम दिया गया था, वीशी, एक नागा शब्दावली।

FSSAI के बारे में

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। FSSAI की स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत की गई है, जो भारत में खाद्य सुरक्षा और विनियमन से संबंधित एक समेकित क़ानून है।
स्थापित: 5 सितंबर 2008
मुख्यालय: नई दिल्ली

नवीनतम समाचार

जून 2023 में, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के तहत असम में गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता, पौष्टिक भोजन प्रदान करने की मान्यता में FSSAI द्वारा 'ईट राइट स्टेशन' प्रमाणन से सम्मानित किया गया था।

केंद्र खरीदारों को गुमराह करने के लिए साइटों को 'अंधेरे पैटर्न' बुनने से रोकेगा

संघ सरकार ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म द्वारा उपयोग किए जाने वाले "डार्क पैटर्न" पर अंकुश लगाने के लिए मसौदा दिशानिर्देश जारी किए हैं।
उपभोक्ता मामले विभाग (DoCA) ने जून 2023 में 'डार्क पैटर्न' पर एक इंटरैक्टिव हितधारक परामर्श आयोजित किया।
उसके बाद, डार्क पैटर्न की पहचान और विनियमन पर सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था।
इस टास्क फोर्स की सिफारिशों और अन्य हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के आधार पर, डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन के लिए मसौदा दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं।

मुख्य विचार

इसका उद्देश्य रणनीति को डार्क पैटर्न के रूप में स्पष्ट रूप से पहचानना और परिभाषित करना है ताकि उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 18 के तहत इसमें शामिल प्लेटफार्मों के खिलाफ कार्रवाई कर सके।
दस्तावेज़ डार्क पैटर्न को इस प्रकार परिभाषित करता है:
किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर यूआई/यूएक्स (यूज़र इंटरफ़ेस/यूज़र अनुभव) इंटरैक्शन का उपयोग करने वाली कोई भी प्रथा या भ्रामक डिज़ाइन पैटर्न;
उपयोगकर्ताओं को कुछ ऐसा करने के लिए गुमराह करने या बरगलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो मूल रूप से उनका इरादा नहीं था या करना नहीं चाहते थे;
उपभोक्ता की स्वायत्तता, निर्णय लेने या पसंद को नष्ट या ख़राब करके;
भ्रामक विज्ञापन या अनुचित व्यापार व्यवहार या उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन।
उदाहरण के लिए, झूठी तात्कालिकता एक काला पैटर्न है जिसके तहत ऑनलाइन विक्रेता सीमित स्टॉक के झूठे दावे करता है ("जल्दी करें, केवल दो आइटम बचे हैं!")।
मसौदा दिशानिर्देशों में डार्क पैटर्न में शामिल होने पर प्रतिबंध का प्रस्ताव है।
मसौदा दिशानिर्देश, एक बार अधिसूचित होने के बाद, भारत में व्यवस्थित रूप से वस्तुओं या सेवाओं की पेशकश करने वाले सभी प्लेटफार्मों, विज्ञापनदाताओं और विक्रेताओं पर लागू होंगे।

दस्तावेज़ 10 प्रकार के डार्क पैटर्न निर्दिष्ट करता है।
झूठी अत्यावश्यकता का अर्थ है अत्यावश्यकता की भावना को ग़लत ढंग से बताना या आरोपित करना।
बास्केट स्नीकिंग का अर्थ है चेकआउट के समय उपयोगकर्ता की सहमति के बिना अतिरिक्त वस्तुओं को शामिल करना।
कन्फ़र्म शेमिंग का अर्थ है किसी वाक्यांश, वीडियो, ऑडियो या किसी अन्य माध्यम का उपयोग करके किसी के मन में डर, शर्म या उपहास या अपराध की भावना पैदा करना।
जबरन कार्रवाई का अर्थ है किसी उपयोगकर्ता को ऐसी कार्रवाई करने के लिए मजबूर करना जिसके लिए उपयोगकर्ता को आवश्यकता होगी
इंटरफ़ेस हस्तक्षेप का अर्थ डिज़ाइन तत्व है जो उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस में हेरफेर करता है।
बैट और स्विच उपयोगकर्ता की कार्रवाई के आधार पर किसी विशेष परिणाम का विज्ञापन करने की प्रथा है।
ड्रिप मूल्य निर्धारण ऐसी ही एक और प्रथा है जिससे तत्वकीमतों का खुलासा पहले नहीं किया गया है।
मंत्रालय की ओर से गाइडलाइंस में छद्म विज्ञापन और नैगिंग को परिभाषित किया गया है।
"डार्क पैटर्न" शब्द 2010 में एक उपयोगकर्ता अनुभव विशेषज्ञ हैरी ब्रिग्नुल द्वारा गढ़ा गया था।
इन पैटर्न का उपयोग अक्सर उपयोगकर्ताओं को सेवाओं के लिए साइन अप करने, खरीदारी करने या व्यक्तिगत जानकारी साझा करने सहित अन्य चीजों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है।

2025 तक 56% नए इंटरनेट उपयोगकर्ता ग्रामीण भारत से होंगे

ट्रांसयूनियन सिबिल की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 तक कुल नए इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में से लगभग 56 प्रतिशत ग्रामीण भारत से होंगे, जिसमें कहा गया है कि वर्तमान में, 36% डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता देश के ग्रामीण हिस्सों से हैं।

मुख्य विचार

बढ़ते गोद लेने को इस तथ्य से प्रेरित किया जा रहा है कि 52%देश की जनसंख्या 40 वर्ष से कम आयु की है, जो वैश्विक औसत 46 से अधिक है%
इसके अलावा, वित्त वर्ष 2023 में दाखिल किए गए 6.7 करोड़ आईटी रिटर्न में से 2 करोड़ से अधिक जेन जेड द्वारा दाखिल किए गए थे, रिपोर्ट में कहा गया है कि व्यक्तिगत EPFO खातों में भी पिछले 10 वर्षों में दोगुनी वृद्धि देखी गई है।
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल (FCC) की अंतर्दृष्टि से तैयार की गई रिपोर्ट, उभरते उपभोक्ता पर क्रेडिट और भुगतान के डिजिटलीकरण के परिवर्तनकारी प्रभावों पर केंद्रित है।
विशिष्ट पहचान कार्यक्रम के मामले में देश शीर्ष स्थान पर है, 130 करोड़ लोगों को आधार के तहत नामांकित किया गया है, और डिजिटल लेनदेन की मात्रा के मामले में, 2022 में 7,400 यूपीआई लेनदेन किए गए हैं।

केंद्र सरकार ने PMLA के तहत 'लाभार्थी मालिक' नियमों को कड़ा किया

केंद्र सरकार ने अंतिम लाभार्थी के लिए नियमों को और कड़ा कर दिया है और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत रिपोर्टिंग इकाई की परिभाषा को ठीक कर दिया है।
संशोधनों का उद्देश्य PMLA अधिनियम के तहत एजेंसी को अधिक शक्ति देना और अधिनियम के दायरे में आने वाले व्यक्तियों के प्रकार और प्रकृति का विस्तार करना है।
वित्त मंत्रालय ने धन शोधन रोकथाम (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 में बदलाव को अधिसूचित किया है। तदनुसार, किसी साझेदारी की पूंजी या मुनाफे के 10% से अधिक के स्वामित्व वाले व्यक्ति को 'लाभकारी स्वामी' के रूप में उप नियम 3 के दायरे में लाया जाएगा।

मुख्य विचार

पहले यह सीमा 15% थी
इसी प्रकार, एक व्यक्ति जिसके पास 15 से अधिक का कोई स्वामित्व या अधिकार नहीं है%(अब 10%) साझेदारी की पूंजी या मुनाफे का, लेकिन अन्य माध्यमों से साझेदारी पर नियंत्रण रखता है, उसे लाभकारी स्वामी माना जाएगा।
'रिपोर्टिंग इकाई के प्रधान अधिकारी' की परिभाषा में भी बदलाव किया गया है

मुख्य अधिकारी वित्तीय खुफिया इकाई को जानकारी प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है।
संशोधन से पहले, एक रिपोर्टिंग इकाई के पास किसी भी अधिकारी को 'प्रधान अधिकारी' के रूप में नियुक्त करने का विवेक था।
संशोधन के बाद प्रबंधन स्तर के किसी अधिकारी को ही 'प्रधान अधिकारी' नियुक्त किया जा सकेगा

नवीनतम समाचार

मई 2023 में, वित्त मंत्रालय ने एक कंपनी के निदेशकों को व्यवसाय के दौरान की गई कुछ गतिविधियों के लिए PMLA के तहत रिपोर्टिंग संस्थाओं के रूप में शामिल किया।

पीएम मोदी ने ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस के लॉन्च की घोषणा की

भारत ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने की घोषणा की और वैश्विक स्तर पर पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिश्रण को 20% तक ले जाने की दलील के साथ जी-20 देशों से इस पहल में शामिल होने का आग्रह किया।
गठबंधन की शुरुआत श्री मोदी ने जी-20 शिखर सम्मेलन के मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा, बांग्लादेश की प्रधान मंत्री शेख हसीना और इतालवी प्रधान मंत्री जियोर्जिया मेलोनी सहित कई वैश्विक नेताओं के साथ की थी।
भारत के अलावा, पहल करने वाले सदस्यों में अर्जेंटीना, बांग्लादेश, ब्राजील, इटली, मॉरीशस, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका शामिल हैं, जबकि कनाडा और सिंगापुर पर्यवेक्षक देश हैं।

मुख्य विचार

वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का उद्देश्य परिवहन सहित सभी क्षेत्रों में सहयोग को सुविधाजनक बनाना और टिकाऊ जैव ईंधन के उपयोग को तेज करना है।
इसका ध्यान मुख्य रूप से बाजारों को मजबूत करने, वैश्विक जैव ईंधन व्यापार को सुविधाजनक बनाने, ठोस नीति सबक-साझाकरण विकसित करने और दुनिया भर में राष्ट्रीय जैव ईंधन कार्यक्रमों के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने पर है।
इस तरह की पहल का उद्देश्य भारत को वैकल्पिक ईंधन की ओर संक्रमण में मदद करना और उसके आयात बिल में कटौती करना है, क्योंकि देश 2070 तक अपने शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है।
दूसरी ओर, ISA का लक्ष्य हैको जुटानेसौर ऊर्जा के बड़े पैमाने पर दोहन के लिए 2030 तक 1,000 अरब डॉलर से अधिक के निवेश की आवश्यकता है।
अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का अनुमान है कि 2050 तक दुनिया की ऊर्जा प्रणाली को शुद्ध-शून्य उत्सर्जन की दिशा में लाने के लिए वैश्विक टिकाऊ जैव ईंधन उत्पादन को 2030 तक तीन गुना करने की आवश्यकता होगी।
तरल जैव ईंधन ने 2022 में कुल परिवहन ऊर्जा आपूर्ति का चार प्रतिशत से अधिक प्रदान किया।

पीएम मोदी ने जकार्ता में आसियान-भारत शिखर सम्मेलन को संबोधित किया

पीएम मोदी इंडोनेशिया के जकार्ता में 20वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन को संबोधित किया।
उन्होंने भारत-आसियान सहयोग को मजबूत करने के लिए 12 सूत्री प्रस्ताव पेश किया
वह हमें सूचित किया कि भारत-आसियान साझेदारी चौथे दशक में पहुंच गई है
वह मुझे सूचित किया कि यह शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता करना उनके लिए सम्मान की बात है।
पीएम मोदी ने बताया कि आसियान भारत की एक्ट ईस्ट नीति का केंद्रीय स्तंभ है।
उन्होंने इतिहास और भूगोल के साथ-साथ साझा मूल्यों, क्षेत्रीय एकीकरण और शांति, समृद्धि और बहुध्रुवीय दुनिया में साझा विश्वास के बारे में बताया जो भारत और आसियान को एकजुट करता है।
पीएम मोदी 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी शामिल हुए
12 सूत्री प्रस्ताव में कनेक्टिविटी, डिजिटल परिवर्तन, व्यापार और आर्थिक जुड़ाव, समकालीन चुनौतियों का समाधान, लोगों से लोगों के बीच संपर्क और रणनीतिक जुड़ाव को गहरा करना शामिल है।

पीएम मोदी ने रखा प्रस्तावमल्टी-मॉडल की स्थापना कनेक्टिविटी और आर्थिक गलियारा जो दक्षिण-पूर्व एशिया-भारत-पश्चिम एशिया-यूरोप को जोड़ता है।
उन्होंने डिजिटल भविष्य के लिए आसियान-भारत फंड की घोषणा की।
उन्होंने आसियान देशों को ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। इसकी स्थापना भारत में WHO द्वारा की जा रही है।
पीएम मोदी ने आसियान देशों को आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया।
दो संयुक्त वक्तव्य अपनाये गये। एक समुद्री सहयोग पर था और दूसरा खाद्य सुरक्षा पर था।

नवीनतम समाचार

मई 2023 में, भारत ने पहले आसियान-भारत समुद्री अभ्यास (AIME-2023) में भाग लेने के लिए दो फ्रंटलाइन युद्धपोत भेजे।
मई 2023 में, एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशंस (आसियान) देशों में भारतीय नौसेना की तैनाती के एक हिस्से के रूप में, पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग रियर एडमिरल गुरचरण सिंह की कमान के तहत भारतीय नौसेना के जहाज INS दिल्ली और आईएनएस सतपुड़ा सिहानोकविले, कंबोडिया से रवाना हुए।
जुलाई 2023 में, भारत और आसियान (दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ) के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए, भारत "संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना (UNPK) संचालन में महिलाओं" पर एक पहल शुरू करेगा।

आसियान के बारे में:

दक्षिणपूर्व एशियाई देशों का संगठन (आसियान) एक क्षेत्रीय अंतरसरकारी संगठन है जिसमें 10 दक्षिणपूर्व एशियाई देश शामिल हैं।
इसकी स्थापना 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी।
सदस्य: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया और वियतनाम।
आसियान संघ की पहली शिखर बैठक 1976 में इंडोनेशिया के सबसे प्रमुख द्वीप बाली पर आयोजित की गई थी।

इंडोनेशिया के बारे में:

राष्ट्रपति: जोको विडोडो
मुद्रा: इंडोनेशियाई रुपिया (आरपी)

जी-20 शिखर सम्मेलन ने नई दिल्ली घोषणापत्र हासिल किया

नई दिल्ली नेताओं का ऐलान G20 शिखर सम्मेलन 2023 में अपनाया गया।
G20 नेताओं ने घोषणा के सभी 83 पैराग्राफों पर 100% सहमति दी है।
नई दिल्ली के नेताओं की घोषणा इस पर केंद्रित है: मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास, एसडीजी पर प्रगति में तेजी लाना, सतत भविष्य के लिए हरित विकास समझौता, 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थान और बहुपक्षवाद को पुनर्जीवित करना।
भारत के जी20 शेरपा अमिताभ कांत के अनुसार, हर एक देश हरित विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक साथ आया है।
सबसे बड़ी उपलब्धि हमने महिला नेतृत्व वाले विकास पर हासिल की है।
रूस-यूक्रेन युद्ध पर, दिल्ली घोषणापत्र में "सभी राज्यों से क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और शांति और स्थिरता की रक्षा करने वाली बहुपक्षीय प्रणाली सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों को बनाए रखने का आह्वान किया गया"।
परमाणु हथियारों का उपयोग या उपयोग की धमकी अस्वीकार्य है।
यूरोपीय आयोग ने जी20 देशों से वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तीन गुना करने और ऊर्जा दक्षता को दोगुना करने के वैश्विक लक्ष्यों पर सहमत होने का आग्रह किया।

निष्कर्ष में, कुछ व्यापक निष्कर्ष थे कि इस शिखर सम्मेलन ने 2026 में शुरू होने वाले नए चक्र सहित भविष्य के राष्ट्रपतियों के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता का अनुमान लगाया - 2024 में ब्राजील, 2025 में दक्षिण अफ्रीका और 2026 में अमेरिका।
भारत के G20 प्रेसीडेंसी के सभी सहभागिता समूहों और पहलों को मान्यता दी गई।
भारत भर के 60 शहरों में 200 से अधिक बैठकें आयोजित करके, नई दिल्ली ने जी20 को लोगों तक ले जाने के लिए एक नया खाका और एक उच्च मानक स्थापित किया है।
जनतंत्रीकरणकूटनीति इस सफल अभ्यास का एक महत्वपूर्ण परिणाम है।

कैबिनेट की मंजूरी: कैबिनेट ने 4 साल के लिए ई-कोर्ट चरण III को मंजूरी दी

प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7210 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ चार साल (2023 से आगे) के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में ई-कोर्ट प्रोजेक्ट चरण III को मंजूरी दे दी है।
माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के "सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास" के दृष्टिकोण के अनुरूप, ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके न्याय तक पहुंच में सुधार के लिए प्रमुख प्रस्तावक है।
राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के एक भाग के रूप में, भारतीय न्यायपालिका चरण-II के ICT सक्षमीकरण के लिए ई-न्यायालय परियोजना 2007 से कार्यान्वित की जा रही है, जो 2023 में समाप्त होगी।
भारत में ई-कोर्ट परियोजना का तीसरा चरण "पहुंच और समावेशन" के दर्शन पर आधारित है।
ई-कोर्ट चरण III की केंद्र प्रायोजित योजना को न्याय विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार और ई-कमेटी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संयुक्त साझेदारी के तहत संबंधित उच्च न्यायालयों के माध्यम से विकेंद्रीकृत तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है। न्यायिक प्रणाली जो सभी हितधारकों के लिए प्रणाली को अधिक सुलभ, किफायती, विश्वसनीय, पूर्वानुमानित और पारदर्शी बनाकर न्याय में आसानी को बढ़ावा देगी।

कैबिनेट ने मेसर्स सुवेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड में 9589 करोड़ रुपये तक के विदेशी निवेश को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने मेसर्स बरहयांडा लिमिटेड, साइप्रस द्वारा मेसर्स सुवेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड में 9589 करोड़ रुपये तक के विदेशी निवेश के लिए FDI प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
यह मंजूरी अनिवार्य खुली पेशकश के माध्यम से मौजूदा प्रमोटर शेयरधारकों और सार्वजनिक शेयरधारकों से शेयरों के हस्तांतरण के माध्यम से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड में सूचीबद्ध एक सार्वजनिक लिमिटेड भारतीय दवा कंपनी मेसर्स सुवेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के 76.1% इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण के लिए है।
मेसर्स सुवेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड में कुल विदेशी निवेश 90.1% तक बढ़ सकता है।
प्रस्ताव का मूल्यांकन सेबी, RBI, CCI और अन्य संबंधित एजेंसियों द्वारा किया गया है।
संबंधित विभागों, RBI और सेबी द्वारा प्रस्ताव की जांच के बाद मंजूरी दी गई है और यह इस संबंध में लागू सभी नियमों और विनियमों की पूर्ति के अधीन है।
मौजूदा FDI नीति के अनुसार, ग्रीनफील्ड फार्मास्युटिकल परियोजनाओं में स्वचालित मार्ग के तहत 100% विदेशी निवेश की अनुमति है।
ब्राउनफील्ड फार्मास्युटिकल परियोजनाओं में, स्वचालित मार्ग के तहत 74% तक FDI की अनुमति है और 74% से अधिक निवेश के लिए सरकार की मंजूरी आवश्यक है।
पिछले पांच वर्षों (2018-19 से 2022-23 तक) के दौरान फार्मास्युटिकल क्षेत्र में कुल FDI प्रवाह 43,713 करोड़ रुपये रहा है।
पिछले वित्तीय वर्ष में इस क्षेत्र में 58% की FDI में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है।

कैबिनेट ने डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या पैमाने पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और आर्मेनिया के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी

माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या पैमाने पर लागू सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और आर्मेनिया गणराज्य के उच्च तकनीक उद्योग मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी।
समझौता ज्ञापन का उद्देश्य दोनों देशों की डिजिटल परिवर्तनकारी पहलों के कार्यान्वयन में घनिष्ठ सहयोग और अनुभवों और डिजिटल प्रौद्योगिकियों-आधारित समाधानों (जैसे इंडिया स्टैक) के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है।
MoU में आईटी के क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने वाले बेहतर सहयोग की परिकल्पना की गई है।
समझौता ज्ञापन पार्टियों के हस्ताक्षर की तारीख से प्रभावी होगाबचा रहेगा3 वर्ष की अवधि के लिए लागू।
डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के क्षेत्र में G2G और B2B दोनों द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाया जाएगा।
इस समझौता ज्ञापन में विचार की गई गतिविधियों को उनके प्रशासन के नियमित संचालन आवंटन के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा।

आर्मेनिया के बारे में:

प्रधान मंत्री: निकोल पशिन्यान
राजधानी: येरेवान
मुद्रा: अर्मेनियाई ड्राम

कैबिनेट ने डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या पैमाने पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और एंटीगुआ और बारबुडा के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी

माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या पैमाने पर लागू सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और एंटीगुआ और बारबुडा के सूचना, संचार प्रौद्योगिकी, उपयोगिता और ऊर्जा मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी।
समझौता ज्ञापन का उद्देश्य दोनों की डिजिटल परिवर्तनकारी पहलों के कार्यान्वयन में घनिष्ठ सहयोग और अनुभवों और डिजिटल प्रौद्योगिकियों-आधारित समाधानों (जैसे इंडिया स्टैक) के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है।
MoU में आईटी के क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने वाले बेहतर सहयोग की परिकल्पना की गई है।
समझौता ज्ञापन पार्टियों के हस्ताक्षर की तारीख से प्रभावी होगा और 3 साल की अवधि तक लागू रहेगा।
G2G और B2B दोनों द्विपक्षीय सहयोग डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) के क्षेत्र में वृद्धि की जाएगी।
इस समझौता ज्ञापन में विचार की गई गतिविधियों को उनके प्रशासन के नियमित संचालन आवंटन के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा।

एंटीगुआ और बारबुडा के बारे में

प्रधान मंत्री: गैस्टन ब्राउन
राजधानी: सेंट जॉन्स
मुद्रा: पूर्वी कैरेबियाई डॉलर

कैबिनेट ने डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या पैमाने पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और सिएरा लियोन के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी

माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या पैमाने पर लागू सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सिएरा लियोन गणराज्य के सूचना और संचार मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी।
समझौता ज्ञापन का उद्देश्य दोनों की डिजिटल परिवर्तनकारी पहलों के कार्यान्वयन में घनिष्ठ सहयोग और अनुभवों और डिजिटल प्रौद्योगिकियों-आधारित समाधानों (जैसे इंडिया स्टैक) के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है।
MoU में आईटी के क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने वाले बेहतर सहयोग की परिकल्पना की गई है।

समझौता ज्ञापन पार्टियों के हस्ताक्षर की तारीख से प्रभावी होगा और 3 साल की अवधि तक लागू रहेगा।
डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के क्षेत्र में G2G और B2B दोनों द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाया जाएगा।
इस समझौता ज्ञापन में विचार की गई गतिविधियों को उनके प्रशासन के नियमित संचालन आवंटन के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा।

सिएरा लियोन के बारे में:

अध्यक्ष: जूलियस माडा बायो
राजधानी: फ्रीटाउन
मुद्रा: सिएरा लियोनियन लियोन

कैबिनेट ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को LPG कनेक्शन का समर्थन करने के लिए अनुदान जारी करने की योजना को मंजूरी दी

प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक तीन वर्षों में 75 लाख LPG कनेक्शन जारी करने के लिए प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के विस्तार को मंजूरी दे दी है।
निम्नलिखित दरों पर प्रति कनेक्शन कुल वित्तीय निहितार्थ 1650 करोड़ रुपये होगा:
14.2 किलोग्राम सिंगल बोतल कनेक्शन - 2200 रुपये प्रति कनेक्शन
5 किलो डबल बोतल कनेक्शन - 2200 रुपये प्रति कनेक्शन
5 किलो सिंगल बोतल कनेक्शन - 1300 रुपये प्रति कनेक्शन
उज्ज्वला 2.0 के मौजूदा तौर-तरीकों के अनुसार, उज्ज्वला लाभार्थियों को पहली रिफिल और स्टोव भी मुफ्त प्रदान किया जाएगा।
PMUY उपभोक्ताओं को प्रति वर्ष 12 रिफिल तक 14.2 किलोग्राम LPG सिलेंडर पर 200 रुपये की लक्षित सब्सिडी प्रदान की जा रही है।
PMUY को जारी रखे बिना पात्र गरीब परिवारों को योजना के तहत उचित लाभ नहीं मिल पाएगा।
गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन खाना पकाने के ईंधन के पारंपरिक स्रोतों जैसे जलाऊ लकड़ी, कोयला, गोबर आदि के उपयोग के कारण होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में मदद करने के लिए स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन तक पहुंच प्रदान करेगा।
इससे बदले में महिलाओं की उत्पादकता में वृद्धि होगी, लकड़ी के संग्रह से जुड़े कठिन परिश्रम को दूर करके उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा और कई बार खाना पकाने के ईंधन की अनुपलब्धता के खिलाफ उन्हें बीमा मिलेगा।

नवीनतम समाचार

मई 2023 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) और मिस्र प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण (ECA) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी।
जून 2023 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट, इंटीग्रेटेड एंड सस्टेन (CITIIS) 2.0 कार्यक्रम को अधिकृत किया, जो एक प्रतियोगिता के माध्यम से चुने गए 18 स्मार्ट शहरों में एक परिपत्र अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करेगा।
प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 अगस्त, 2022 को भारत सरकार (GoI) और गठबंधन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर (CDRI) के बीच मुख्यालय समझौते (HQA) के अनुसमर्थन को मंजूरी दे दी है।

प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में छह हजार करोड़ रुपये से अधिक की रेल क्षेत्र परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे:

छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेल क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे
रायगढ़ में सार्वजनिक कार्यक्रम में 6 हजार करोड़ रुपये से अधिक की महत्वपूर्ण रेल क्षेत्र की परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करने के साथ ही देश भर में कनेक्टिविटी में सुधार पर प्रधानमंत्री के जोर को बढ़ावा मिलेगा।

इन परियोजनाओं में छत्तीसगढ़ पूर्व रेल परियोजना चरण- I, चंपा से जमगा के बीच तीसरी रेल लाइन, पेंड्रा रोड से अनूपपुर के बीच तीसरी रेल लाइन और तलाईपल्ली कोयला खदान को NTPC लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन से जोड़ने वाली मेरी-गो-राउंड प्रणाली शामिल है।
रेल परियोजनाएं क्षेत्र में यात्रियों की आवाजाही के साथ-साथ माल ढुलाई को सुविधाजनक बनाकर सामाजिक-आर्थिक विकास को गति प्रदान करेंगी।
कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के नौ जिलों में 'क्रिटिकल केयर ब्लॉक' का शिलान्यास भी करेंगे
इसके अलावा, सिकल सेल रोग के कारण होने वाले स्वास्थ्य मुद्दों को संबोधित करने के उद्देश्य से, विशेष रूप से आदिवासी आबादी के बीच, प्रधान मंत्री स्क्रीनिंग की गई आबादी को एक लाख सिकल सेल परामर्श कार्ड भी वितरित करेंगे।

नवीनतम समाचार

मई 2023 में, छत्तीसगढ़ स्थित कोल इंडिया की सहायक कंपनी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स (SECL), अगले पांच वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अपने परिचालन राज्यों में वृक्षारोपण पर 169 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।
अप्रैल 2023 में, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री (सीएम) श्री भूपेश बघेल ने ग्रामीण आवास न्याय योजना नामक एक महत्वाकांक्षी ग्रामीण आवास योजना शुरू की।

छत्तीसगढ़ के बारे में:

राज्यपाल: विश्वभूषण हरिचंदन
मुख्यमंत्री: भूपेश बघेल
राजधानी: रायपुर
राष्ट्रीय उद्यान: गुरु घासी दास (संजय) राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान
वन्यजीव अभयारण्य: अचानकमार वन्यजीव अभयारण्य, बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य

तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन पुणे में आयोजित किया जाएगा

तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 14 और 15 सितंबर को पुणे में होगा।
गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के सचिव
अंशुली आर्य ने पुणे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी
इस अवसर पर राजभाषा विभाग की संयुक्त सचिव मीनाक्षी जॉली उपस्थित थीं।
सुश्री आर्य ने घोषणा की कि पुणे एक लोकप्रिय शहर है और इसकी एक ऐतिहासिक परंपरा है, इसलिए पुणे को तीसरे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के लिए चुना गया है।
सम्मेलन में हिंदी भाषा के विद्वान वक्ता और विद्वान भाग लेंगे।
सम्मेलन के दौरान चर्चा किए जाने वाले कुछ विषयों में राजभाषा@2047: विकसित भारत का भाषाई पैनोरमा (कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित), हिंदी के विकास में मीडिया की भूमिका और भारतीय सिनेमा और हिंदी शामिल हैं।
सम्मेलन के दौरान तीन लाख 51 हजार शब्दों का शब्दकोष हिंदी शब्दसिंधु और एक ई-ऑफिस ऐप लॉन्च किया जाएगा।
सुश्री आर्य ने मुझे बताया कि वर्तमान में, विभिन्न मंत्रालयों की वेबसाइटों पर जानकारी हिंदी और अन्य भाषाओं में उपलब्ध है।
उन्होंने बताया कि भविष्य में वेबसाइटों को इस तरह विकसित किया जा रहा है कि जानकारी के लिए पहला विकल्प हिंदी भाषा में उपलब्ध होगा।

महाराष्ट्र के बारे में:

राज्यपाल: भगत सिंह कोश्यारी
मुख्यमंत्री: एकनाथ शिंदे
पूंजी: मुंबई
राष्ट्रीय उद्यान: ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान
वन्यजीव अभयारण्य: भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य, करनाला पक्षी अभयारण्य, नागजीरा वन्यजीव अभयारण्य
यूनेस्को विरासत स्थल: छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको पहनावा, अजंता गुफाएं,

एलीफेंटा गुफाएं, एलोरा गुफाएं

पीएम ने एमपी में BPCL बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मध्य प्रदेश के बीना में BPCL की बीना रिफाइनरी में डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और रिफाइनरी विस्तार परियोजना की आधारशिला रखी।
लगभग 49,000 करोड़ रुपये की लागत से विकसित की जाने वाली यह अत्याधुनिक रिफाइनरी लगभग 1200 KTPA (किलो-टन प्रति वर्ष) एथिलीन और प्रोपलीन का उत्पादन करेगी, जो कपड़ा, पैकेजिंग, फार्मा जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है।
इससे देश की आयात निर्भरता कम होगी और प्रधानमंत्री के 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण को पूरा करने की दिशा में एक कदम होगा।
यह मेगा प्रोजेक्ट रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा और पेट्रोलियम क्षेत्र में डाउनस्ट्रीम उद्योगों के विकास को बढ़ावा देगा।
मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी सहित अन्य उपस्थित थे।
सभा को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि यह पेट्रोकेमिकल संयंत्र माननीय प्रधानमंत्री की ओर से न केवल बीना बल्कि बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश के लिए एक उपहार है।

एमपी के बारे में:

राज्यपाल: मंगूभाई सी. पटेल
मुख्यमंत्री: शिवराज सिंह चौहान
राजधानी: भोपाल
राष्ट्रीय उद्यान: सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान
वन्यजीव अभयारण्य: नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य, बोरी वन्यजीव अभयारण्य

नवीनतम समाचार

मई 2023 में मध्य प्रदेश (MP) की राजधानी भोपाल संयुक्त राष्ट्र (यूएन) द्वारा अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों (SDG) के स्थानीयकरण को स्वीकार करने वाला भारत का पहला शहर बन गया।
जून 2023 में, राज्य द्वारा संचालित भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPCL) मध्य प्रदेश (एमपी) के सागर जिले के बीना में एक एथिलीन क्रैकर (ईसी) परियोजना स्थापित करेगी, और लगभग 49,000 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय के साथ अपनी रिफाइनरी क्षमता का विस्तार करेगी।

कैबिनेट ने मेसर्स सुवेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड में 9589 करोड़ रुपये तक के विदेशी निवेश को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने मेसर्स बरहयांडा लिमिटेड, साइप्रस द्वारा मेसर्स सुवेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड में 9589 करोड़ रुपये तक के विदेशी निवेश के लिए FDI प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
यह मंजूरी अनिवार्य खुली पेशकश के माध्यम से मौजूदा प्रमोटर शेयरधारकों और सार्वजनिक शेयरधारकों से शेयरों के हस्तांतरण के माध्यम से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड में सूचीबद्ध एक सार्वजनिक लिमिटेड भारतीय दवा कंपनी मेसर्स सुवेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के 76.1% इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण के लिए है।
मेसर्स सुवेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड में कुल विदेशी निवेश 90.1% तक बढ़ सकता है।
प्रस्ताव का मूल्यांकन सेबी, RBI, CCI और अन्य संबंधित एजेंसियों द्वारा किया गया है।
संबंधित विभागों, RBI और सेबी द्वारा प्रस्ताव की जांच के बाद मंजूरी दी गई है और यह इस संबंध में लागू सभी नियमों और विनियमों की पूर्ति के अधीन है।

विदेशी निवेशक कंपनी, मेसर्स बरहयांदा लिमिटेड में संपूर्ण निवेश एडवेंट फंड्स के पास है, जो विभिन्न लिमिटेड पार्टनर्स (एलपी) से निवेश एकत्र करता है।

आगमन निधि के बारे में

एडवेंट फंड का प्रबंधन एडवेंट इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन द्वारा किया जाता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में शामिल एक इकाई है।

1984 में स्थापित एडवेंट इंटरनेशनल कॉरपोरेशन ने 42 देशों में लगभग 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है।

एडवेंट इंडिया ने भारत में निवेश शुरू कियामें2007 और अब तक इसने स्वास्थ्य सेवा, वित्तीय सेवाओं, औद्योगिक विनिर्माण, उपभोक्ता वस्तुओं और आईटी सेवा क्षेत्रों में 20 भारतीय कंपनियों में लगभग 34000 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

नवीनतम समाचार

मई 2023 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) और मिस्र प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण (ECA) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी।

शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों से सभी डेटा को एक मंच पर लाने को कहा

राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला (NDEAR) के तहत, शिक्षा मंत्रालय राज्यों को विद्या समीक्षा केंद्र (VSK) खोलने के लिए प्रेरित कर रहा है।

विद्या समीक्षा केंद्र (VSK) एक डेटा भंडार है जिसमें शिक्षा मंत्रालय (MoE) द्वारा संचालित सभी योजनाओं का डेटा होगा।

इन केंद्रों के नियंत्रण कक्ष प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों को ट्रैक करने के लिए डेटा एकत्र करेंगे और साथ ही AI और मशीन-लर्निंग का उपयोग करके सरकारी योजनाओं से एकत्र किए गए डेटा का विश्लेषण करेंगे।

इस भंडार में नियमित रूप से अद्यतन डेटा शामिल होगा

पीएम-पोषण मध्याह्न भोजन कार्यक्रम;

स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों के समग्र उन्नति पोर्टल के लिए राष्ट्रीय पहल से शिक्षक प्रशिक्षण डेटा;

ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर से पाठ्यपुस्तक सामग्री;

शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (UDISE+) पर स्कूल छोड़ने वालों और उपस्थिति से संबंधित डेटा;

छात्र राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण से परिणाम सीख रहे हैं;

प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक, जो राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर स्कूली शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन करता है।

केंद्र ने VSK को अपनाने और स्थापित करने के लिए प्रत्येक राज्य को 2 से 5 करोड़ रुपये तक की धनराशि आवंटित की है।

VSK विकसित करने का विचार सकल पहुंच अनुपात का आकलन करने के लिए जनसंख्या परत के साथ स्कूल स्थान परत को मैप करना भी है।

वर्तमान में, केंद्रीय स्तर पर, एक वीएसके केंद्र राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) परिसर में केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान भवन में स्थित है, जिसमें बहुराष्ट्रीय आईटी कंपनी अन्र्स्ट एंड यंग इसके संचालन का प्रबंधन कर रही है। यह सी-क्यूब सॉफ्टवेयर पर चलने वाला एक ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म है।

एकस्टेप फाउंडेशन, जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष नंदन नीलेकणि द्वारा सह-स्थापित एक गैर-लाभकारी संगठन है, VSK परियोजना को लागू करने के लिए एक सलाहकार की भूमिका में है।

NDEAR के बारे में

NDEAR एक शिक्षा पहल है जो संघीय, असंबद्ध, अंतरसंचालनीय, समावेशी, सुलभ और लगातार विकसित हो रही है।

इसका प्राथमिक उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों, समुदायों और प्रशासकों को लाभ पहुंचाने वाले नवीन समाधान तैयार करना और वितरित करना है, जिसके परिणामस्वरूप नीति लक्ष्यों का समय पर कार्यान्वयन हो सके।

NDEAR इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) के सहयोग से शिक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में संचालित होता है।

इसका लक्ष्य शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी के निर्माण, उपयोग और पुन: उपयोग के लिए सिद्धांतों और दृष्टिकोणों के एक सामान्य सेट को बढ़ावा देना है, जिससे शिक्षा प्रौद्योगिकी के लिए अधिक सुव्यवस्थित और प्रभावी दृष्टिकोण सक्षम हो सके।

नवीनतम समाचार

मई 2023 में, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 'शिक्षा पुरस्कार' और 'हिंदीतर भाषी हिंदी लेखक पुरस्कार' को बंद करने का निर्णय लिया।

सरकार ने मार्च 2024 तक पीएम-कुसुम के तहत सौर कोशिकाओं के लिए घरेलू सामग्री की आवश्यकता में छूट दी

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने मार्च 2024 तक पीएम कुसुम योजना के घटक सी के तहत सौर कोशिकाओं के लिए घरेलू सामग्री आवश्यकता (DCR) मानदंडों में ढील दी है।
पिछले साल अगस्त में, मंत्रालय ने 20 जून, 2023 को या उससे पहले सौंपी गई परियोजनाओं के लिए घरेलू आवश्यकता मानदंडों को माफ कर दिया था।
चालू बोली प्रक्रिया के कारण घटक सी (FLS) के तहत सौर कोशिकाओं के लिए DCR छूट के विस्तार के संबंध में इसे फिर से विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।
पीएम-कुसुम या प्रधानमंत्री ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान यह एक मांग-संचालित योजना है और इसलिए, राज्यों से प्राप्त मांग के आधार पर योजना के तीन घटकों के तहत मात्रा या क्षमता आवंटित की जाती है।

मुख्य विचार

पीएम कुसुम के तहत घटक सी का उद्देश्य व्यक्तिगत पंप सोलराइजेशन (IPS) और फीडर लेवल सोलराइजेशन (FLS) के माध्यम से 15 लाख ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सोलराइजेशन हासिल करना है।
घटक-सी के तहत लाभार्थी व्यक्तिगत किसान, जल उपयोगकर्ता संघ, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां और समुदाय या क्लस्टर-आधारित सिंचाई प्रणाली हो सकते हैं।
कृषि फीडर सौर्यीकरण के लिए, प्रति मेगावाट ₹1.05 करोड़ की केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) प्रदान की जाती है।
भाग लेने वाले राज्यों से वित्तीय सहायता की कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। फीडर सोलराइजेशन को CAPEX या RESCO (नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी) मोड में लागू किया जा सकता है।
इसके अलावा, घटक सी के तहत सीएफए बेंचमार्क लागत या निविदा लागत का 30 प्रतिशत, जो भी कम हो, है।
राज्य सरकार की सब्सिडी 30 प्रतिशत है, और शेष 40 प्रतिशत का भुगतान किसान को करना होता है।
जुलाई 2023 तक, घटक सी में, केंद्र ने व्यक्तिगत पंप सोलराइजेशन (IPS) के तहत 1,21,930 पंपों को मंजूरी दी है, जिनमें से 1,519 पंप स्थापित किए जा चुके हैं।
फीडर लेवल सोलराइजेशन (FLS) के तहत 22,05,279 पंप स्वीकृत किए गए हैं, जबकि अभी तक कोई पंप स्थापित नहीं किया गया है।
योजना के तहत धनराशि राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (SIA) द्वारा रिपोर्ट की गई स्थापना की प्रगति और योजना दिशानिर्देशों के प्रावधानों के आधार पर जारी की जाती है।

पीएम कुसुम के बारे में

पीएम कुसुम का लक्ष्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सेवा शुल्क सहित ₹34,422 करोड़ की कुल केंद्रीय वित्तीय सहायता के साथ 30,800 मेगावाट की सौर क्षमता जोड़ना है।
पीएम-कुसुम योजना 2019 में शुरू की गई थी।
इस योजना में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के साथ किसानों के लिए उनकी बंजर भूमि से आय सृजन की परिकल्पना की गई है।
योजना में तीन घटक शामिल हैं
घटक ए: 2 मेगावाट तक की क्षमता के व्यक्तिगत संयंत्रों के छोटे सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के माध्यम से 10,000 मेगावाट की सौर क्षमता।
घटक बी: 20 लाख स्टैंडअलोन सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंपों की स्थापना।
घटक सी: 15 लाख ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सौर्यीकरण
नोडल मंत्रालय: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE)

कोल इंडिया 61 पर्यावरण-अनुकूल परियोजनाओं में 24,750 करोड़ रुपये का निवेश करेगी

कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) ने लगभग रुपये के पूंजी निवेश की योजना बनाई है। अगले कुछ वर्षों में 61 फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी (FMC) परियोजनाओं पर 24,750 करोड़ रुपये।
तीन चरणों में पूरी होने वाली इन परियोजनाओं की कुल क्षमता पूरी होने पर 763.5 मिलियन टन प्रति वर्ष (MTPA) होगी।
FMC परियोजनाओं में उत्पादन बिंदु से कोयला प्रबंधन संयंत्रों/साइलो तक तेजी से लोडिंग प्रणाली के साथ मशीनीकृत पाइप कन्वेयर में कोयले का परिवहन शामिल होता है, जहां कोयले को सीधे रेल वैगनों में लोड किया जाता है।
पहले चरण के तहत 414.5 MTPA क्षमता वाली 35 FMC परियोजनाओं की लागत 10,750 करोड़ रुपये है।
दूसरे और तीसरे चरण की परियोजनाएं क्रमशः 9 और 17 हैं।
जबकि उनकी संबंधित निकासी क्षमता 57 MTPA और 292 MTPA है, क्रमिक रूप से निवेश लगभग 2,500 करोड़ रुपये और 11,500 करोड़ रुपये होगा।
दूसरे चरण के तहत, निर्माणाधीन 21.5 MTPA क्षमता की 5 परियोजनाएं वित्त वर्ष 2025 तक चालू होने की उम्मीद है। शेष परियोजनाएं प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं और निविदाएं जारी की गई हैं और बोली दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं।
तीसरे चरण के लिए 65 MTPA क्षमता की 3 परियोजनाओं के लिए निविदाएं जारी की गई हैं। 9 परियोजनाओं को खदान डेवलपर्स और ऑपरेटरों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाना है। चरण तीन परियोजनाओं के वित्त वर्ष 2029 तक चालू होने का अनुमान है।
जब वित्त वर्ष 2029 तक सभी 61 परियोजनाएं चालू हो जाएंगी, तो कुल पर्यावरण-अनुकूल कोयला निकासी 914.5 MTPA तक बढ़ जाएगी, जिसमें 151 MTPA की पिछली क्षमता भी शामिल है।

भारत 13वां देश बन गया जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत OIML प्रमाणपत्र जारी कर सकता है

भारत दुनिया का 13 वां देश बन गया है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत OIML (इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी) प्रमाण पत्र जारी कर सकता है।
नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए, उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि घरेलू निर्माता अब देश में अपने वजन और माप उपकरणों का परीक्षण करवा सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच सकते हैं।
यह दुनिया भर में स्वीकृत एकल प्रमाणपत्र है और अतिरेक को कम करता है, और संसाधनों की बचत करता है।
यह प्रणाली दुनिया भर में माप में एकरूपता और विश्वास सुनिश्चित करती है और बार-बार प्रमाणीकरण से बचकर संसाधनों की बचत करती है।
अब भारतीय निर्माता या उनके एजेंट अपने माप उपकरणों के लिए भारतीय OIML जारीकर्ता प्राधिकरण से OIML प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं जो उपभोक्ता मामलों के विभाग का कानूनी माप विज्ञान प्रभाग है।

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए विशेष अभियान 3.0 पोर्टल लॉन्च किया

केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में एक समारोह में एक विशेष अभियान 3.0 पोर्टल लॉन्च किया है।
इस समर्पित पोर्टल - scdpm.nic.in के माध्यम से विशेष अभियान 3.0 की निगरानी की जाएगी।
सरकार ने स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने और संतृप्ति दृष्टिकोण के साथ सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए इस वर्ष 2 से 31 अक्टूबर तक विशेष अभियान 3.0 आयोजित करने की घोषणा की है।
यह विशेष अभियान सेवा वितरण या सार्वजनिक इंटरफ़ेस वाले क्षेत्र और बाहरी कार्यालयों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग इस अभियान के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग है।
विशेष अभियान 3.0 से पहले इस महीने की 15 से 30 तारीख तक प्रारंभिक चरण शुरू किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की और कुछ ही महीनों में यह एक जन आंदोलन बन गया
उन्होंने बताया कि इस मिशन के तहत अब तक देशभर में 10 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है।

उन्होंने कहा कि इस प्रकार के विशेष अभियान से कार्य संस्कृति में सकारात्मक बदलाव आया है। इस अवसर पर, दिसंबर 2022-जुलाई 2023 तक विशेष अभियान 3.0 दिशानिर्देश और विशेष अभियान प्रगति और जून-जुलाई, 2023 के लिए सचिवालय सुधारों की मासिक रिपोर्ट भी जारी की गई।
इस अवसर पर डाक विभाग के सचिव विनीत पांडे, रेलवे बोर्ड के सचिव मिलिंद के.देउस्कर और भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के महानिदेशक अरुण सिंघल भी उपस्थित थे।

वित्तीय समावेशन के लिए जी-20 वैश्विक साझेदारी बैठक मुंबई में चल रही है

वित्तीय समावेशन के लिए चौथी G20 वैश्विक साझेदारी (GPFI) बैठक मुंबई में आयोजित की जा रही है।
बैठक में जी20 सदस्य देशों, विशेष आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 50 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।
GPFI सदस्य डिजिटल वित्तीय समावेशन के लिए जी20 GPFI उच्च-स्तरीय सिद्धांतों के कार्यान्वयन, राष्ट्रीय प्रेषण योजनाओं के अद्यतन और SME वित्तपोषण में आम बाधाओं को दूर करने के लिए SME सर्वोत्तम प्रथाओं और नवीन उपकरणों के संबंध में GPFI कार्य से संबंधित चर्चा कर रहे हैं।
MSME को सक्रिय करने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई।
एक अन्य संगोष्ठी "डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के माध्यम से वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाना: डिजिटल और वित्तीय साक्षरता और उपभोक्ता संरक्षण के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना" पर निर्धारित की गई है।

श्री परषोत्तम रूपाला ने नवसारी, गुजरात में ICAR-CIBA के झींगा किसान सम्मेलन-2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया

केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, श्री परषोत्तम रूपाला ने गुजरात के नवसारी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में ICAR-CIBA (ICAR-सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वॉटर एक्वाकल्चर) झींगा किसान कॉन्क्लेव-2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया।
सम्मेलन में गुजरात के तटीय जिलों के लगभग 410 जलीय किसानों ने भाग लिया।
पुरुषोत्तम रूपाला ने मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र के सतत विकास के लिए 20,050 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया।
इसने प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY) के तहत 25 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ "पेनियस इंडिकस (भारतीय सफेद झींगा) के आनुवंशिक सुधार कार्यक्रम - चरण- I" पर ICAR-CIBA द्वारा कार्यान्वित एक परियोजना विकसित करने का मार्ग प्रशस्त किया। झींगा प्रजनन के लिए एक राष्ट्रीय आनुवंशिक सुधार सुविधा स्थापित करें।
केंद्रीय मंत्री श्री रूपाला ने झींगा में EHP रोग के नियंत्रण के लिए चिकित्सीय EHP-क्यूरा-आई विकसित करने के लिए CIBA वैज्ञानिकों को बधाई दी और उन्हें जल्द से जल्द किसानों को उपलब्ध कराने के लिए कहा।
मंत्री ने इस अवसर पर AIC के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक श्रीमती की उपस्थिति में ICAR-CIBA के सहयोग से कृषि बीमा कंपनी (AIC) द्वारा विकसित झींगा फसल बीमा योजना भी लॉन्च की। ग्रिजा सुब्रमण्यन.
CIBA और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (NFDB) के बीच दो समझौता ज्ञापनों (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए; NFDB द्वारा दी जाने वाली प्रीमियम सब्सिडी और FFPO के लिए प्रौद्योगिकी सहायता के साथ जलीय कृषि के लिए फसल बीमा को लागू करने के लिए क्रमशः CIBA और गुजरात के मछली किसान उत्पादक संगठन (FFPO) हैं।
श्री रूपाला ने NGRC-CIBA वैज्ञानिकों द्वारा समर्थित आजीविका विकास के लिए CIBA प्रौद्योगिकियों को अपनाने के माध्यम से नवसारी क्षेत्र के SC, ST और केज कल्चर लाभार्थियों द्वारा अर्जित 40.05 लाख रुपये की राशि भी सौंपी।

सरकार ने कृषि सांख्यिकी के लिए एकीकृत पोर्टल UPAg शुरू किया

केंद्र ने कृषि सांख्यिकी के लिए एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया और इसे यूपीएजी (कृषि सांख्यिकी के लिए एकीकृत पोर्टल) नाम दिया और इसे भारत के कृषि क्षेत्र के सामने आने वाली जटिल शासन चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

पोर्टल वास्तविक समय, विश्वसनीय और मानकीकृत जानकारी के साथ हितधारकों को सशक्त बनाएगा, जिससे अधिक उत्तरदायी और कुशल कृषि नीतियों का मार्ग प्रशस्त होगा।
कृषि सचिव मनोज आहूजा दावा किया गया कि UPAg पोर्टल उपयोगकर्ताओं को विश्वसनीय, विस्तृत और वस्तुनिष्ठ डेटा तक पहुंच बनाने में मदद करेगा।
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (DA&FW) द्वारा विकसित कृषि सांख्यिकी के लिए एकीकृत पोर्टल नीति आयोग के सदस्यों द्वारा लॉन्च किया गया था।
यह कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का एक महत्वपूर्ण घटक है।
यह कृषि क्षेत्र में डेटा प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने के लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग की एक पहल है।

नवीनतम समाचार

मई 2023 में, केंद्रीय संचार मंत्री ने एक नागरिक-केंद्रित संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया।
मई 2023 में, हिमाचल प्रदेश (एचपी) मुख्यमंत्री (सीएम) श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी सरकारी निकायों के वास्तविक समय और सटीक डेटा को एकीकृत करके कल्याणकारी योजनाओं की डिलीवरी में सुधार करने के लिए एक सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म 'हिम' डेटा पोर्टल लॉन्च किया।

1 अक्टूबर, 2023 से सभी सूचित जन्म और मृत्यु को डिजिटल रूप से पंजीकृत किया जाएगा

एक सरकारी अधिसूचना के अनुसार, 1 अक्टूबर से देश में सभी सूचित जन्म और मृत्यु को केंद्र के पोर्टल पर डिजिटल रूप से पंजीकृत किया जाएगा।
जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र के लिए मार्ग प्रशस्त करता है
यह शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, ड्राइविंग के लिए आवेदन के लिए उपयोग किया जाने वाला एक एकल दस्तावेज होगालाइसेंस, सरकारी नौकरी, पासपोर्ट या आधार, मतदाता नामांकन, और विवाह का पंजीकरण, आदि।
केंद्रीकृत डेटाबेस राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR), राशन कार्ड, संपत्ति पंजीकरण और मतदाता सूची को भी अपडेट करेगा।
राज्यों के लिए केंद्र के नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) पोर्टल पर जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करना और भारत के रजिस्ट्रार जनरल (RGI) के साथ डेटा साझा करना अनिवार्य होगा।
केंद्रीकृत डेटाबेस राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR), राशन कार्ड, संपत्ति पंजीकरण और मतदाता सूची को भी अपडेट करेगा।

NPR के बारे में:

NPR, जिसे पहली बार 2010 में एकत्र किया गया था और 2015 में घर-घर जाकर गणना के माध्यम से अद्यतन किया गया था, में पहले से ही 119 करोड़ निवासियों का डेटाबेस है।
नागरिकता अधिनियम के अनुसार, एनपीआर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के निर्माण की दिशा में पहला कदम है।
राज्यों के लिए केंद्र के नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) पोर्टल पर जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करना और RGI के साथ डेटा साझा करना अनिवार्य होगा जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है।

वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण नवी मुंबई में शुरू हुआ

वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण (WSC) नवी मुंबई के वाशी में शुरू हुआ।
विश्व मसाला कांग्रेस (WSC) की योजना और कल्पना 1990 में मसालों के आयातकों और निर्यातकों के बीच चर्चा और बातचीत के एक मंच के रूप में की गई थी।
यह वैश्विक मसाला उद्योग का समूह है जो अपनी तीन दशक लंबी उपस्थिति के दौरान इस क्षेत्र की चिंताओं और विचारों पर विचार-विमर्श करने के लिए सबसे उपयुक्त मंच बन गया है।
अपनी स्थापना के बाद से, यह मसाला बोर्ड, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के नेतृत्व में आयोजित किया गया है।
WSC 2023 का विषय विज़न 2030: SPICES है, जो स्थिरता, उत्पादकता, नवाचार, सहयोग, उत्कृष्टता और सुरक्षा के लिए है।

भारतीय मसाला बोर्ड के बारे में

भारतीय मसाला बोर्ड का गठन 26 फरवरी 1987 को मसाला बोर्ड अधिनियम 1986 के तहत पूर्ववर्ती इलायची बोर्ड (1968) और मसाला निर्यात संवर्धन परिषद (1960) के विलय के साथ किया गया था।
यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

भारत में 15 रेंज-राज्यों में फैले 150 हाथी गलियारे हैं, पश्चिम बंगाल सूची में सबसे ऊपर है

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, भारत में चार हाथी-असर वाले क्षेत्रों में 15 रेंज-राज्यों में कम से कम 150 हाथी गलियारे हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल 26 ऐसी भूमि पट्टियों के साथ सूची में शीर्ष पर है।
केंद्र सरकार की 2010 की हाथी टास्क फोर्स रिपोर्ट (गजाह रिपोर्ट) में देश में 88 गलियारे सूचीबद्ध हैं।
"भारत के हाथी गलियारे" शीर्षक वाली नवीनतम रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इनमें से 59 गलियारों में हाथियों के उपयोग की तीव्रता बढ़ी है, 29 में स्थिर रही और 29 अन्य में कमी आई है।
कुल गलियारों में से 15 क्षतिग्रस्त हो गए हैं और कार्यक्षमता बहाल करने के लिए पुनर्स्थापन प्रयासों की आवश्यकता है।

मुख्य विचार

हाथियों द्वारा 18 गलियारों के वर्तमान उपयोग के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं थी।
हाथी गलियारा एक भूमि पट्टी है जो दो या दो से अधिक व्यवहार्य आवास क्षेत्रों के बीच हाथियों की आवाजाही की सुविधा प्रदान करती है।
2017 में किए गए अंतिम अनुमान के अनुसार, भारत में लगभग 30,000 हाथी हैं, जो जानवरों की वैश्विक आबादी का 60 प्रतिशत है।
नवीनतम रिपोर्ट भारतीय वन्यजीव संस्थान के तकनीकी सहयोग से केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के परियोजना हाथी और राज्य वन विभागों के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास का परिणाम है। 15 राज्यों में 150 हाथी गलियारों के जमीनी सत्यापन को पूरा होने में लगभग दो साल लग गए।
भारत में सबसे अधिक हाथी गलियारों के मामले में पश्चिम बंगाल सबसे आगे है, जो देश में कुल ऐसे भूमि भूखंडों का 17 प्रतिशत से अधिक है।

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे पर 'उड़ान भवन' का उद्घाटन किया

दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे पर एक एकीकृत कार्यालय परिसर 'उड़ान भवन' के उद्घाटन के साथ, जिसका उद्घाटन केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त) और MoCA सचिव श्री वुमलुनमांग वुअलनाम की गरिमामय उपस्थिति में किया।
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA), नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS), विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) और हवाईअड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण (AERA), नियामक प्राधिकरण होने के नाते, नागरिक उड्डयन क्षेत्र में निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मानकों के अनुसार नियम और विनियम भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) पूरे भारत में विभिन्न हवाई अड्डों पर निर्माण, संचालन, ATC और CNS सेवाएं प्रदान करने और रखरखाव के लिए जिम्मेदार प्रमुख हवाई अड्डा ऑपरेटर है।
नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे पर उड़ान भवन, नए एकीकृत कार्यालय परिसर का निर्माण किया गया है जो MoCA के तहत विभिन्न नियामक प्राधिकरणों के बीच बेहतर समन्वय की सुविधा प्रदान करेगा।

श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कौशल को बढ़ावा देने के लिए NSDC और इंडसइंड बैंक के साथ 'स्किल्स ऑन व्हील्स' पहल शुरू की

केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री, श्री धर्मेंद्र प्रधान और लोकसभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला ने एक हरी झंडी दिखाने वाले समारोह के साथ NSDC और इंडसइंड बैंक के साथ 'स्किल्स ऑन व्हील्स' पहल शुरू की।

साझेदारी के तहत, अपनी युवा आबादी को प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके ग्रामीण परिवारों की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से 60,000 युवाओं को पांच साल की अवधि में सशक्त बनाया जाएगा।
सहयोग के तहत, रेट्रोफिटेड उपकरणों के साथ एक अनुकूलित बस 'स्किल्स ऑन व्हील्स' के माध्यम से 'कौशल भारत मिशन' पहल को बढ़ावा देगी और आकांक्षी और पिछड़े जिलों की लंबाई और चौड़ाई में यात्रा करेगी।
इस पहल का उद्देश्य नि:शुल्क कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में जमीनी स्तर पर जागरूकता फैलाना है, जो युवाओं को मजबूत कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से अपने जीवन की दिशा को गहराई से बदलने में सक्षम बनाता है।
इस मिशन के अनुरूप, इंडसइंड बैंक के साथ इस साझेदारी का उद्देश्य 'स्किल्स ऑन व्हील्स' परियोजना के माध्यम से देश के युवाओं को सशक्त बनाना है।
स्किल्स ऑन व्हील्स का उद्देश्य बड़ी संख्या में युवाओं को उद्योग-प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण लेने में सक्षम बनाना है जो उनके सैद्धांतिक और साथ ही व्यावहारिक ज्ञान में सुधार करेगा और आवश्यक तालमेल, निरीक्षण और प्रभावी समन्वय लाकर उन्हें बेहतर आजीविका सुरक्षित करने में मदद करेगा।
इसका उद्देश्य उद्योग में आवश्यक कुशल लोगों और बेरोजगार युवाओं के बीच अंतर को पाटना है, यह सुनिश्चित करके कि किसी विशेष नौकरी के लिए जुनून रखने वाला सही उम्मीदवार अपनी शैक्षणिक पृष्ठभूमि, योग्यता और कौशल सेट के अनुसार सही पाठ्यक्रम चुनता है।

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया

सरकार ने महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश कर दिया है
इस विधेयक का नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम रखा गया है।
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस संबंध में 128वां संशोधन विधेयक, 2023 पेश किया।
बिल पेश करते हुए उन्होंने बताया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होने के बाद लोकसभा में महिलाओं के लिए सीटों की संख्या 181 हो जाएगी।
बिल पेश होने के बाद लोकसभा को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया है
पुराने संसद भवन का नाम बदलकर संविधान सदन कर दिया गया है।

रक्षा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उद्योग सहयोग पर भारत-मलेशिया संयुक्त उप-समिति की 10वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई

रक्षा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उद्योग सहयोग पर भारत-मलेशिया संयुक्त उप-समिति की 10वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई।
बैठक की सह-अध्यक्षता संयुक्त सचिव (नौसेना प्रणाली), रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय श्री राजीव प्रकाश और अवर सचिव, रक्षा उद्योग प्रभाग, रक्षा मंत्रालय, मलेशिया श्री एरिस जेमादी बिन ताजुद्दीन ने की।
रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा अनुसंधान और उद्योग सहयोग की समीक्षा की गई और आपसी हित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई
बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा अनुसंधान और उद्योग सहयोग की समीक्षा की गई और आपसी हित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई।
दोनों पक्षों ने रक्षा उद्योग क्षेत्र से संबंधित चल रही बातचीत को और विस्तारित करने के लिए प्रभावी और व्यावहारिक पहल की खोज की।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए 'पीएम विश्वकर्मा' योजना शुरू की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर नई दिल्ली में पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया।

हिंदू पौराणिक कथाओं में, विश्वकर्मा को देवताओं के वास्तुकार के रूप में देखा जाता है और वह दिव्य बढ़ई और मास्टर शिल्पकार थे।
यह योजना पारंपरिक शिल्प और कौशल में लगे श्रमिकों को सरकारी सहायता प्रदान करेगी।
इस योजना की घोषणा सबसे पहले पीएम मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान की थी
यह 13,000 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली एक नई योजना है और पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है।
इस योजना का उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों और सेवाओं की पहुंच के साथ-साथ गुणवत्ता में सुधार करना भी है।

पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में

मंत्रालयसूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) का नोडल मंत्रालय है।
जनजातीय कार्य मंत्रालय, विश्वकर्माओं की भलाई के लिए योजना के कार्यान्वयन के लिए सक्रिय सहायता प्रदान करेगा।
यह योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME), कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) और वित्तीय सेवा विभाग (DFS), वित्त मंत्रालय (MoF), भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से लागू की जाएगी।
इस सूची में बोट मेकर जैसे 18 पारंपरिक शिल्प शामिल थे; कवचधारी; लोहार; हथौड़ा और टूल किट निर्माता; वगैरह।
पहले वर्ष में पांच लाख परिवारों को और पांच वर्षों में 30 लाख परिवारों को कवर किया जाएगा।
उन्हें बुनियादी और उन्नत प्रशिक्षण सहित कौशल उन्नयन, 15,000 रुपये का टूलकिट प्रोत्साहन, 1 लाख रुपये तक संपार्श्विक-मुक्त क्रेडिट सहायता (पुनर्भुगतान की पहली किस्त अवधि 18 महीने) और 5% की रियायती ब्याज दर पर 2 लाख रुपये (पुनर्भुगतान की दूसरी किस्त की अवधि) 5% की रियायती ब्याज दर पर दी जाएगी।
वीडियो तत्व के साथ 12 भारतीय भाषाओं में एक टूलकिट पुस्तिका भी जारी की गई है।
प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को प्रति दिन ₹500 का वजीफा मिलेगा।
पंजीकरण की तिथि पर लाभार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
लाभार्थी को पंजीकरण की तारीख पर संबंधित ट्रेडों में संलग्न होना चाहिए और पिछले 5 वर्षों में स्वरोजगार / व्यवसाय विकास के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार की इसी तरह की क्रेडिट-आधारित योजनाओं के तहत ऋण का लाभ नहीं उठाना चाहिए, जैसे PMEGP, पीएम स्वनिधि, मुद्रा।
8% तक की संपूर्ण ब्याज छूट का लाभ MoMSME द्वारा बैंकों के माध्यम से लाभार्थियों को अग्रिम रूप से दिया जाएगा।
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, सहकारी बैंक, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां और सूक्ष्म वित्त संस्थान, इस योजना के तहत ऋण देने के पात्र हैं।
ऋण देने वाली संस्थाओं को योजना की अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए अपने क्षेत्रीय पदाधिकारियों यानी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स/एसोसिएट्स के नेटवर्क का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
इस योजना का उद्देश्य लाभार्थियों को डिजिटल लेनदेन अपनाने की सुविधा देकर डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है।
आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम (APBS) के माध्यम से DBT मोड में लाभार्थी के बैंक खाते में मासिक रूप से प्रति पात्र डिजिटल लेनदेन (अधिकतम 100 योग्य लेनदेन तक) 1 रुपये की राशि जमा की जाएगी।

शांतिनिकेतन यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल

विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान शांतिनिकेतन को सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया।
विश्व धरोहर समिति का 45वां सत्र इस समय सऊदी अरब में चल रहा है।

शांतिनिकेतन के बारे में

शांतिनिकेतन की स्थापना 1901 में नोबेल पुरस्कार विजेता रवीन्द्रनाथ टैगोर के पिता महर्षि देवेन्द्रनाथ टैगोर ने की थी।
शांतिनिकेतन पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है।

मुख्य विचार

केंद्र ने पहली बार 2010 में शांतिनिकेतन के लिए विश्व विरासत टैग प्राप्त करने का प्रयास किया।
शांतिनिकेतन में विश्वभारती एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय हैबंगाल. प्रधानमंत्री इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं।

ICOMOS ने कुछ महीने पहले शांतिनिकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की सिफारिश की थी।
शांतिनिकेतन भारत में 41 वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है।
सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान और दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे के बाद यह पश्चिम बंगाल में तीसरा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है।
पिछले साल, पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा को यूनेस्को के तहत "मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत" में रखा गया था।
एक 'विश्व विश्वविद्यालय' - विश्व भारती - की स्थापना 1921 में शांतिनिकेतन में की गई थी।
17 सितंबर 2023 को सूची में रखी गई अन्य साइटें हैं:
फ़िलिस्तीन में प्राचीन जेरिको,
ताजिकिस्तान में ज़राफशान-काराकुम सिल्क रोड कॉरिडोर,
तुर्कमेनिस्तान,
उज़्बेकिस्तान, इथियोपिया में गेडियो सांस्कृतिक परिदृश्य,
चीन के पुएर में जिंगमई पर्वत के पुराने चाय के जंगलों का सांस्कृतिक परिदृश्य।

ICOMOS के बारे में

स्मारकों और स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद (ICOMOS) फ्रांस स्थित एक अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संस्था है

यूनेस्को के बारे में

मुख्यालय: पेरिस, फ्रांस
स्थापित: 16 नवंबर 1945, लंदन, यूनाइटेड किंगडम
प्रमुख: ऑड्रे अज़ोले;

नवीनतम समाचार

मई 2023 में, मीडिया पेशेवरों की एक अंतर्राष्ट्रीय जूरी की सिफारिश के बाद, निलोफर हमेदी, इलाहेह मोहम्मदी और नरगेस मोहम्मदी को 2023 यूनेस्को / गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के विजेताओं के रूप में नामित किया गया था।
अप्रैल 2023 में, केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि शांतिनिकेतन, वह स्थान जहां नोबेल पुरस्कार विजेता कवि रवींद्रनाथ टैगोर ने एक सदी पहले विश्व-भारती का निर्माण किया था, को एक अंतरराष्ट्रीय सलाहकार निकाय द्वारा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है।

युवाओं को सशक्त बनाने और भविष्य बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण शुरू हो गया है

वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण दिल्ली में शुरू हो गया है।
दो दिवसीय शिखर सम्मेलन का विषय कौशल निर्माण, युवाओं को सशक्त बनाना और भविष्य बनाना है।
शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारत में उच्च गुणवत्ता वाले उद्योग-आधारित कौशल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक रोड मैप बनाने पर ध्यान केंद्रित करना है।
शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सचिव अतुल कुमार तिवारी ने बताया कि देश का गतिशील कार्यबल स्कूल के तुरंत बाद के अवसरों की तलाश करता है।
उन्होंने आगे कहा कि जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ती है, देश में शिक्षा, कौशल और उद्यमिता के पारिस्थितिकी तंत्र को युवाओं को कौशल और रोजगार के अवसरों से लैस करना चाहिए।
शिखर सम्मेलन में भारत के युवाओं को उद्योग के लिए कुशल बनाने और भारत में कौशल और शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को नेविगेट करने के तरीकों पर भविष्य में चर्चा और विचार-विमर्श किया जाएगा।

केंद्र ने कृषि-ऋण और फसल बीमा पर ध्यान केंद्रित करते हुए किसानों के लिए तीन गेम-चेंजिंग पहल शुरू की

सरकार नई दिल्ली में देश में कृषि में क्रांति लाने के उद्देश्य से परिवर्तनकारी पहलों की एक श्रृंखला शुरू करेगी।
परिवर्तनकारी पहलों में किसान ऋण पोर्टल (KRP), डोर टू डोर KCC अभियान और मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम (विंड्स) मैनुअल शामिल हैं।

इन पहलों की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर करेंगे।
कृषि और किसान कल्याण मंत्री के अनुसार, इन पहलों का उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ाना, डेटा उपयोग को सुव्यवस्थित करना, प्रौद्योगिकी का उपयोग करना और कृषि समुदाय की आजीविका को बढ़ाना है।
इसमें कहा गया है कि ये पहल किसानों के कल्याण को अपने मूल में रखते हुए कृषि-ऋण और फसल बीमा पर ध्यान केंद्रित करेंगी। इसमें कहा गया है कि ये प्रयास और नवाचार देश के कृषक समुदाय के लिए कृषि परिवर्तन और सतत आर्थिक विकास के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे।

किसान ऋण पोर्टल के बारे में

कई सरकारी विभागों के सहयोग से विकसित किसान ऋण पोर्टल (KRP), किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के तहत क्रेडिट सेवाओं तक पहुंच में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए तैयार है। यह डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म किसान डेटा, ऋण संवितरण विशिष्टताओं, ब्याज छूट दावों और कुशल कृषि ऋण का एक व्यापक दृश्य प्रदान करता है।

घर-घर किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में

घर-घर किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) अभियान पूरे भारत में प्रत्येक किसान तक किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना का लाभ पहुंचाने का एक महत्वाकांक्षी अभियान है। इस अभियान का उद्देश्य सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन प्राप्त करना है, यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक किसान को ऋण सुविधाओं तक निर्बाध पहुंच हो। मंत्रालय ने कहा कि मार्च 2023 तक सक्रिय KCC खातों की कुल संख्या 7.35 करोड़ है और कुल स्वीकृत सीमा 8.85 लाख करोड़ रुपये है।

मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम के बारे में

मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम (WINDS) पहल एक महत्वपूर्ण नवाचार है, जो हितधारकों को मौसम पर कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए उन्नत मौसम डेटा विश्लेषण का लाभ उठाता है।

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया 24 सितंबर 2023 को तेजू हवाई अड्डे पर नए बुनियादी ढांचे का उद्घाटन करेंगे

श्री ज्योतिरादित्य एम.सिंधिया नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू के साथ तेजू हवाई अड्डे के नव विकसित बुनियादी ढांचे का उद्घाटन करेंगे।
तेज़ू हवाई अड्डा तेज़ू शहर में स्थित एक घरेलू हवाई अड्डा है जो एकल रनवे के माध्यम से संचालित होता है।
हवाई अड्डा 212 एकड़ भूमि पर विकसित किया गया है और ATR 72 प्रकार के विमानों के संचालन को संभालने में सक्षम है।
AAI ने राज्य सरकार के अनुरोध पर तेजू हवाई अड्डे को चालू करने के लिए विकास और उन्नयन कार्य किया।
170 करोड़ रुपये के कार्यों में रनवे का विस्तार (1500 मीटर x 30 मीटर) और 02 मीटर के लिए एक नए एप्रन का निर्माण शामिल है।
ATR 72 प्रकार के विमान, एक नए टर्मिनल भवन का निर्माण, और एक फायर स्टेशन सह ATC टॉवर।
तेजू हवाई अड्डे को नागरिक उड्डयन मंत्रालय की RCS उड़ान योजना के तहत 2018 में चालू किया गया था। हवाई अड्डा वर्तमान में एलायंस एयर और फ्लाईबिग एयरलाइन द्वारा नियमित निर्धारित उड़ानों के माध्यम से डिब्रूगढ़, इंफाल और गुवाहाटी से जुड़ा हुआ है।

परियोजना के लाभ

अधिक यातायात को संभालने के लिए हवाई अड्डे की क्षमता का विस्तार।
देश के बाकी हिस्सों के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र की बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करें।
पर्यटन, व्यापार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना।
क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।

तेज़ू के बारे में

तेज़ू लोहित नदी के तट पर स्थित एक छोटा सा शहर है और अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले का मुख्यालय है। यह शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, जहां चारों ओर हरे-भरे जंगल और ऊंची-ऊंची पहाड़ियां हैं।

भारत ने सीमेंट रसायन विज्ञान पर 17वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की मेजबानी की बोली जीती

भारत ने 2027 में नई दिल्ली में सीमेंट के रसायन विज्ञान (ICCC) पर प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की मेजबानी के लिए बोली जीती है।
भारत के अग्रणी अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थान, नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मैटेरियल्स (NCCBM), और IIT दिल्ली ने बैंकॉक, थाईलैंड में चल रहे 16वें ICCC के दौरान सम्मेलन की संचालन समिति के सदस्यों के समक्ष भारत की बोली सफलतापूर्वक प्रस्तुत की।
भारत के अलावा, अन्य बोलीदाता स्विट्जरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात से थे।
इस निर्णय की घोषणा 20 सितंबर 2023 को बैंकॉक, थाईलैंड में 16वीं ICCC के दौरान की गई थी।
भारतीय बोली डॉ. एलपी सिंह, महानिदेशक, NCCBM, डॉ. एसके चतुर्वेदी, संयुक्त निदेशक, NCCBM और डॉ. शशांक बिश्नोई, प्रोफेसर (सिविल इंजीनियरिंग), IIT दिल्ली द्वारा प्रस्तुत की गई थी।
सीमेंट के रसायन विज्ञान पर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस अपनी तरह का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित आयोजन है जो सीमेंट और कंक्रीट के क्षेत्र में अनुसंधान की प्रगति की समीक्षा करता है।
1918 से कांग्रेस आम तौर पर चार से छह साल के अंतराल पर आयोजित की जाती रही है, जो अकादमिक जगत और सीमेंट उद्योग के बीच एक मजबूत और उपयोगी संबंध प्रदान करती है।
9वीं कांग्रेस का आयोजन 1992 में NCCBM द्वारा नई दिल्ली में किया गया था और वर्तमान 16वीं ICCC 18-22 सितंबर 2023 तक बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित की जा रही है।

पीएम नरेंद्र मोदी यूपी भर में बने 16 अटल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन करेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में बने 16 अटल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन करने के लिए वाराणसी जाएंगे।
इन्हें COVID-19 महामारी के कारण श्रमिकों, निर्माण श्रमिकों और अनाथ बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए 11 सौ करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनाया गया है।
प्रत्येक स्कूल 10 से 15 एकड़ के क्षेत्र में बनाया गया है जिसमें कक्षाएँ, खेल मैदान, मनोरंजक क्षेत्र, एक मिनी सभागार, एक छात्रावास परिसर, मेस और कर्मचारियों के लिए आवासीय फ्लैट हैं।
इन आवासीय विद्यालयों में प्रत्येक में अंततः 1000 छात्रों को समायोजित करने का इरादा है।
प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला भी रखेंगे
वाराणसी के गांजरी, राजातालाब में बनने वाला क्रिकेट स्टेडियम लगभग 450 करोड़ रुपये की लागत से 30 एकड़ से अधिक क्षेत्र में विकसित किया जाएगा।
स्टेडियम की क्षमता 30,000 दर्शकों की होगी
प्रधानमंत्री काशी संसद सांस्कृतिक महोत्सव 2023 के समापन समारोह में शामिल होंगे।
महोत्सव में 17 विधाओं में 37 हजार से अधिक लोगों ने भाग लिया, जिन्होंने गायन, वाद्य वादन, नुक्कड़ नाटक और नृत्य में अपने कौशल का प्रदर्शन किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में बने 16 अटल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन करेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे उत्तर प्रदेश में बने 16 अटल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन करने के लिए वाराणसी जाएंगे।
इन्हें COVID-19 महामारी के कारण श्रमिकों, निर्माण श्रमिकों और अनाथ बच्चों के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए 11 सौ करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनाया गया है।
प्रत्येक स्कूल 10 से 15 एकड़ के क्षेत्र में बनाया गया है जिसमें कक्षाएँ, खेल मैदान, मनोरंजक क्षेत्र, एक मिनी सभागार, छात्रावास परिसर, मेस और कर्मचारियों के लिए आवासीय फ्लैट हैं।
इन आवासीय विद्यालयों में प्रत्येक में अंततः 1000 छात्रों को समायोजित करने का इरादा है।
प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला भी रखेंगे
वाराणसी के गांजरी, राजातालाब में बनने वाला क्रिकेट स्टेडियम लगभग 450 करोड़ रुपये की लागत से 30 एकड़ से अधिक क्षेत्र में विकसित किया जाएगा।

स्टेडियम की क्षमता 30,000 दर्शकों की होगी.
प्रधानमंत्री काशी संसद सांस्कृतिक महोत्सव 2023 के समापन समारोह में शामिल होंगे।
महोत्सव में 17 विधाओं में 37 हजार से अधिक लोगों ने भाग लिया, जिन्होंने गायन, वाद्य वादन, नुक्कड़ नाटक और नृत्य में अपने कौशल का प्रदर्शन किया।

इंडिगो ने नवंबर 2023 से हैदराबाद और कोलंबो को जोड़ने वाली नई सीधी उड़ानों की घोषणा की

भारत की अग्रणी एयरलाइन इंडिगो ने इस साल नवंबर से हैदराबाद और कोलंबो को जोड़ने वाली नई सीधी उड़ानों की घोषणा की है।
यह विकास एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है क्योंकि इंडिगो दो जीवंत शहरों के बीच सीधा संपर्क स्थापित करने वाला पहला भारतीय वाहक बन गया है
स्थानीय समाचार पोर्टलों और अखबारों ने इंडिगो के वैश्विक बिक्री प्रमुख विनय मल्होत्रा के बयान की रिपोर्ट दी है, जिसमें असाधारण सेवाएं प्रदान करने और ग्राहकों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने पर उनकी कंपनी के फोकस पर जोर दिया गया है।
भारत और श्रीलंका के बीच कनेक्टिविटी जाफना और चेन्नई के बीच उड़ानें फिर से शुरू होने से पिछले एक साल में इसमें सुधार हुआ है, जिसे अब दैनिक कर दिया गया है।
इसके अलावा, मुंबई और कोलंबो के बीच उड़ान कनेक्टिविटी भी इस साल शुरू हो गई है।
नागपट्टिनम और कांकेसंथुराई के बीच नौका सेवाएं भी जल्द ही शुरू होने वाली हैं, जो लंबे समय से लंबित मांग रही है।
दूसरी ओर, द्वीप पर आने वाले पर्यटकों के लक्जरी वर्ग को पूरा करने के लिए, इस साल जून में चेन्नई, हंबनटोटा और त्रिंकोमाली को जोड़ने वाला एक अंतरराष्ट्रीय लक्जरी क्रूज भी शुरू किया गया है।
परंपरागत रूप से, श्रीलंका में पर्यटकों के आगमन की संख्या के मामले में भारत अग्रणी स्रोत बाजार रहा है।

भारत ने सुरक्षा खतरों का हवाला देते हुए कनाडाई नागरिकों के लिए ई-वीजा सहित वीजा सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है

भारत ने कनाडा में ई-वीजा सहित वीजा सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है।
नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि हिंसा भड़काने और कनाडाई प्राधिकरण की निष्क्रियता और कनाडा में भारतीय उच्चायोग और वाणिज्य दूतावासों के कार्यों को बाधित करने वाला माहौल बनाने के कारण यह निर्णय लिया गया है।
उन्होंने यह भी कहा कि किसी तीसरे देश में कनाडाई नागरिक भारतीय वीजा के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे।
हालांकि, प्रवक्ता ने बताया कि वैध वीजा या अन्य दस्तावेजों वाला कोई भी व्यक्ति भारत की यात्रा कर सकता है।
भारत में कनाडाई राजनयिकों की संख्या पर एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, श्री बागची ने कहा
कनाडा की ओर से राजनयिकों की कमी होगी क्योंकि भारत ने आपसी राजनयिक उपस्थिति में ताकत में समानता का आह्वान किया है।
हरदीप निज्जर विवाद पर जानकारी देते हुए प्रवक्ता ने कहा कि अब तक कनाडा ने इस मामले पर कोई विशेष जानकारी नहीं दी है, जबकि भारत ने कनाडा की धरती पर स्थित व्यक्तियों द्वारा आपराधिक गतिविधियों के बारे में कनाडा के साथ विशिष्ट सबूत साझा किए हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं की गई है।
श्री बागची ने इस मुद्दे पर कनाडाई सरकार द्वारा की गई टिप्पणियों को भी राजनीति से प्रेरित बताया।
उन्होंने आगे कहा कि कनाडा संगठित आतंकवाद के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह बन गया है और कनाडाई अधिकारियों से अब ऐसा न करने का आग्रह किया।
प्रवक्ता ने यह भी बताया कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने आतंकवाद के आरोपों वाले 25 व्यक्तियों के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया है या उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कनाडा से सहायता मांगी है, लेकिन प्रतिक्रिया मददगार नहीं रही है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस वर्ष सभी श्रेणियों में NEET PG काउंसलिंग के लिए क्वालीफाइंग परसेंटाइल को घटाकर शून्य कर दिया है

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने NEET PG काउंसलिंग 2023 के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों (मेडिकल/डेंटल) के लिए कट-ऑफ प्रतिशत कम कर दिया है।
अब, सभी श्रेणियों में क्वालीफाइंग परसेंटाइल को घटाकर 'शून्य' कर दिया गया है।
मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) द्वारा जारी एक अधिसूचना में इसकी घोषणा की गई।
NEET PG 2023 परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले सभी उम्मीदवार अब स्नातकोत्तर चिकित्सा परामर्श लिंग राउंड में भाग लेने के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे। मेडिकल उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर आधिकारिक नोटिस देख सकते हैं
MCC ने घोषणा की कि सामान्य वर्ग के लिए कट-ऑफ कुल 800 अंकों में से 291 से घटाकर 0 और आरक्षित वर्ग के लिए 257 कर दिया गया है।
NEET पीजी काउंसलिंग 2023 राउंड 3 के लिए नए पंजीकरण और विकल्प भरने की प्रक्रिया भी उन लोगों के लिए फिर से खोली जाएगी जो अब भाग लेने के लिए पात्र हैं।
MCC की वेबसाइट पर उम्मीदवारों को जल्द ही NEET पीजी राउंड 3 पंजीकरण तिथियों के बारे में सूचित किया जाएगा।

प्रधानमंत्री 23 सितंबर को नई दिल्ली में 'अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023' का उद्घाटन करेंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 'अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023' का उद्घाटन करेंगे।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूह को भी संबोधित करेंगे।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा 'न्याय वितरण प्रणाली में उभरती चुनौतियां' विषय पर अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का आयोजन किया जा रहा है।
सम्मेलन का उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न कानूनी विषयों पर सार्थक बातचीत और चर्चा के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना, विचारों और अनुभवों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना और कानूनी मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समझ को मजबूत करना है।
देश में पहली बार आयोजित हो रहे इस सम्मेलन में उभरते कानूनी रुझान, सीमा पार मुकदमेबाजी में चुनौतियां, कानूनी प्रौद्योगिकी, पर्यावरण कानून आदि विषयों पर चर्चा होगी।
कार्यक्रम में प्रतिष्ठित न्यायाधीशों, कानूनी पेशेवरों और वैश्विक कानूनी बिरादरी के नेताओं की भागीदारी देखी जाएगी।

श्री मनोज आहूजा ने खेती के तरीकों में क्रांति लाने के लिए सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण (GCES) के लिए इनोवेटिव मोबाइल एप्लिकेशन और वेब पोर्टल लॉन्च किया

श्री मनोज आहूजा कृषि और किसान कल्याण विभाग (DA&FW) के सचिव ने GCES (सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण) के लिए मोबाइल एप्लिकेशन और वेब पोर्टल लॉन्च किया।
यह क्रांतिकारी पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन पूरे देश में कृषि पद्धतियों को बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
श्री आहूजा ने कृषि में वास्तविक समय अनुमान और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता पर जोर दिया।
उन्होंने उल्लेख किया कि सच्चे और विश्वसनीय परिणाम उत्पन्न करने के लिए डेटा की सटीकता एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है और डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी डेटा प्रदाताओं की भी है।
इसलिए, उन्होंने सभी राज्यों से साख सुनिश्चित करने के लिए जीसीईएस पोर्टल और एप्लिकेशन को अपनाने का अनुरोध किया।

GCES वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन द्वारा संबोधित प्रमुख चुनौतियाँ:

रिपोर्टिंग में देरी- अब तक डेटा संग्रह, संकलन और उपज अनुमान पूरी तरह से मैन्युअल प्रक्रिया है जिसके कारण राज्यों द्वारा रिपोर्टिंग में देरी होती है। नई प्रक्रिया में, GPS सक्षम मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करके फ़ील्ड डेटा एकत्र किया जाएगा और सर्वर में संग्रहीत किया जाएगा जो फसल आंकड़ों की समय पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित करता है।

पारदर्शिता- GPS सक्षम डिवाइस डेटा संग्रह बिंदुओं के लिए सटीक अक्षांश और देशांतर निर्देशांक प्रदान करते हैं। यह जानकारी सुनिश्चित करती है कि डेटा विशिष्ट भौगोलिक स्थानों से जुड़ा हुआ है, जिससे डेटा को कहां एकत्र किया गया था, इसके बारे में अस्पष्टता या हेरफेर के लिए कोई जगह नहीं बचती है।

GCES वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन की मुख्य विशेषताएं:

व्यापक जानकारी- पोर्टल और ऐप गांववार जीसीईएस योजना और प्लॉट विवरण सहित उपज अनुमान का एक व्यापक भंडार प्रदान करते हैं जहां फसल काटने के प्रयोग किए जाते हैं, कटाई के बाद फसल का वजन और फसल का सूखा वजन।

जियो-रेफरेंसिंग- जियो-रेफरेंसिंग मोबाइल एप्लिकेशन की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, जो प्राथमिक कार्यकर्ता को प्रायोगिक भूखंड की सीमा खींचने और इसके माध्यम से भूखंड के साथ-साथ फसलों की तस्वीरें अपलोड करने में सक्षम बनाता है। यह सुविधा डेटा की पारदर्शिता और सटीकता भी सुनिश्चित करेगी।

श्री कैलाश चौधरी ने पीएम-किसान योजना के लिए एआई चैटबॉट लॉन्च किया

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के लिए एक एआई चैटबॉट लॉन्च किया।

एआई चैटबॉट का लॉन्च पीएम-किसान योजना की दक्षता और पहुंच बढ़ाने और किसानों को उनके प्रश्नों का त्वरित, स्पष्ट और सटीक उत्तर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

एआई चैटबॉट को लॉन्च करते हुए, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री, श्री कैलाश चौधरी ने कहा कि यह पहल प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने और शासन में सुधार लाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

श्री चौधरी ने कहा कि एआई चैटबॉट योजना की जानकारी तक पहुंचने और शिकायतों को हल करने में मदद करेगा। उन्होंने इस सेवा को मौसम की जानकारी, मिट्टी की स्थिति और बैंक भुगतान आदि जैसे अन्य संबंधित मुद्दों से जोड़ने के लिए इसे व्यापक बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

मंत्री ने कम समय में प्रौद्योगिकी को शामिल करने के लिए मंत्रालय के अधिकारियों की सराहना की और कहा कि इससे केंद्र और राज्यों के कृषि अधिकारियों के लिए बोझ कम हो जाएगा।

वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान, भारत सरकार और राज्य सरकार के गणमान्य व्यक्ति कृषि क्षेत्र में इस महत्वपूर्ण मील के पत्थर का जश्न मनाने के लिए एकत्र हुए।

पीएम किसान योजना के लिए एआई चैटबॉट का सफल लॉन्च किसानों के कल्याण के लिए तकनीकी प्रगति का लाभ उठाने की सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

पीएम-किसान के बारे में

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) भारत में भूमि-धारक किसानों की वित्तीय जरूरतों का समर्थन करने के लिए फरवरी 2019 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह योजना प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) मोड के माध्यम से पात्र किसानों के परिवारों को तीन समान किस्तों में 6,000 रुपये का वार्षिक वित्तीय लाभ प्रदान करती है। अपनी स्थापना के बाद से, अब तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को 2.61 लाख करोड़ रुपये से अधिक वितरित किए गए हैं, यह विश्व स्तर पर सबसे बड़ी DBT योजनाओं में से एक है।

प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टेडियम के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण पर 121 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जबकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने स्टेडियम के निर्माण के लिए 330 करोड़ रुपये का बजट रखा है।

इस स्टेडियम की विषयगत वास्तुकला भगवान शिव से प्रेरणा लेती है, जिसमें अर्धचंद्राकार छत के कवर, त्रिशूल के आकार की फ्लडलाइट्स, घाट सीढ़ियों पर आधारित बैठने की व्यवस्था और अग्रभाग पर बिल्वपत्र के आकार की धातु की चादरों के डिजाइन विकसित किए गए हैं।

स्टेडियम की क्षमता 30,000 दर्शकों की होगी

यूपी के बारे में:

राज्यपाल: आनंदीबेन पटेल
मुख्यमंत्री: योगी आदित्यनाथ
राजधानी: लखनऊ
राष्ट्रीय उद्यान: दुधुवा राष्ट्रीय उद्यान
वन्यजीव अभयारण्य: हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य।

वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ

वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण दिल्ली में शुरू हो गया है।
दो दिवसीय शिखर सम्मेलन का विषय कौशल निर्माण, युवाओं को सशक्त बनाना और भविष्य बनाना है।

शिखर सम्मेलन का उद्देश्य:

शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारत में उच्च गुणवत्ता वाले उद्योग-आधारित कौशल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक रोड मैप बनाने पर ध्यान केंद्रित करना है।
शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सचिव अतुल कुमार तिवारी ने कहा कि देश का गतिशील कार्यबल स्कूल के तुरंत बाद के अवसरों की तलाश करता है।
उन्होंने आगे कहा कि देश में शिक्षा, कौशल और उद्यमिता के पारिस्थितिकी तंत्र को अर्थव्यवस्था के बढ़ने के साथ युवाओं को कौशल और रोजगार के अवसरों से लैस करना चाहिए।
शिखर सम्मेलन में भारत के युवाओं को उद्योग के लिए कुशल बनाने और भारत में कौशल और शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को नेविगेट करने के तरीकों पर भविष्य में चर्चा और विचार-विमर्श किया जाएगा।

दिल्ली के बारे में:

राज्यपाल: विनय कुमार सक्सैना
मुख्यमंत्री: अरविंद केजरीवाल
राजधानी: दिल्ली
राष्ट्रीय उद्यान: राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, तितली पार्क
वन्यजीव अभयारण्य: असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य, अरावली जैव विविधता पार्क।

पीएम-किसान योजना के लिए AI चैटबॉट लॉन्च किया गया

भारत में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के लिए एक एआई चैटबॉट का अनावरण किया है, जो योजना की दक्षता और पहुंच को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
एआई चैटबॉट किसानों को उनके प्रश्नों के त्वरित, सटीक और स्पष्ट जवाब प्रदान करेगा, कार्यक्रम के साथ प्रभावी ढंग से जुड़ने के लिए एक उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफ़ेस प्रदान करेगा।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह पहल प्रौद्योगिकी के माध्यम से किसानों के जीवन और शासन को बेहतर बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

एआई चैटबॉट के बारे में:

चैटबॉट मौसम अपडेट, मिट्टी की स्थिति और बैंक लेनदेन को शामिल करने के लिए अपनी सेवाओं का विस्तार करने की योजना के साथ, योजना की जानकारी और शिकायत समाधान तक पहुंच की सुविधा प्रदान करेगा।
पीएम किसान मोबाइल ऐप के साथ एकीकृत एआई चैटबॉट पीएम-किसान लाभार्थियों के बीच भाषाई और क्षेत्रीय विविधता को पूरा करते हुए बहुभाषी समर्थन प्रदान करता है।

यह पहला एआई चैटबॉट है जो एक प्रमुख सरकारी फ्लैगशिप कार्यक्रम के साथ एकीकृत है और किसानों को सुलभ जानकारी, पारदर्शिता और सूचित निर्णय लेने के साथ सशक्त बनाने के लिए तैयार है।
वर्तमान में पांच भाषाओं में उपलब्ध है, जल्द ही इसका विस्तार देश की सभी 22 भाषाओं में हो जाएगा।
यह पहल किसानों और कृषि क्षेत्र के कल्याण के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

पीएम-किसान योजना के बारे में:

प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (PMKISAN) भारत सरकार की एक पहल है जो किसानों को न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रति वर्ष ₹6,000 तक देती है।
इस पहल की घोषणा पीयूष गोयल ने 1 फरवरी 2019 को भारत के 2019 अंतरिम केंद्रीय बजट के दौरान की थी।
इस योजना को पहली बार तेलंगाना सरकार द्वारा रायथू बंधु योजना के रूप में कल्पना और कार्यान्वित किया गया था, जहां एक निश्चित राशि सीधे पात्र किसानों को दी जाती है।

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव समिति की नई दिल्ली में बैठक हुई

एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति की नई दिल्ली में बैठक हुई।
इसने देश में एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर राजनीतिक दलों और विधि आयोग जैसे विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श करने का निर्णय लिया है।
समिति के मुताबिक, उन्होंने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टियों, राज्यों में सरकार वाली पार्टियों, जिन पार्टियों के प्रतिनिधि हैं, उन्हें आमंत्रित करने का फैसला किया हैसंसद, अन्य मान्यता प्राप्त राज्य दलों को "देश में एक साथ चुनाव के मुद्दे पर सुझाव/दृष्टिकोण मांगने के लिए"।
कानून मंत्रालय ने कहा कि इसके अलावा, समिति एक साथ चुनाव के मुद्दे पर अपने सुझाव और दृष्टिकोण के लिए विधि आयोग को भी आमंत्रित करेगी।
जाने-माने वकील हरीश साल्वे इस बैठक में वर्चुअली शामिल हुए।
बयान में कहा गया है कि लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बैठक में मौजूद नहीं थे।
बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष सी कश्यप और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी शामिल हुए

एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में:

सरकार ने सभी स्तरों पर एक साथ चुनाव कराने की जांच करने और सिफारिशें करने के लिए 2 सितंबर को 8 सदस्यीय समिति को अधिसूचित किया था।
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पहले यह कहते हुए समिति का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को पैनल से बाहर रखा गया है, जबकि कांग्रेस के पूर्व नेता श्री आज़ाद को शामिल किया गया है।
1967 तक पूरे देश में एक साथ चुनाव होते थे और इस तरह से चार चुनाव हुए।
1968-69 में कुछ राज्य विधानसभाओं को समय से पहले भंग कर दिए जाने के बाद यह प्रथा बंद हो गई।
1970 में लोकसभा भी अपने निर्धारित समय से एक साल पहले ही भंग कर दी गई थी - जो इसके इतिहास में पहली बार था।
2014 के चुनाव में एक साथ चुनाव कराना बीजेपी के घोषणा पत्र का हिस्सा था

रामनाथ कोविन्द के बारे में:

राम नाथ कोविंद एक भारतीय राजनीतिज्ञ और वकील हैं, जिन्होंने 2017 से 2022 तक भारत के 14 वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया।
वह भारत के राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने वाले उत्तर प्रदेश के पहले व्यक्ति हैं।
वह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं।

राष्ट्रपति पद से पहले, उन्होंने 2015 से 2017 तक बिहार के 26 वें राज्यपाल के रूप में कार्य किया।
उन्होंने 1994 से 2006 तक राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया।
राजनीति में प्रवेश करने से पहले, वह 16 साल तक एक वकील थे और 1993 तक दिल्ली उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अभ्यास किया।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन किया

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के हिंडन में भारतीय वायु सेना के एयरबेस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में पहले सी - 295 मेगावाट परिवहन विमान को औपचारिक रूप से शामिल किया गया।
प्रेरण समारोह के दौरान एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। इससे पहले श्री सिंह ने दो दिवसीय भारत ड्रोन शक्ति-2023 का उद्घाटन किया।
भारत ने भारतीय वायु सेना AVRO बेड़े को बदलने के लिए 56 एयरबस C-295 विमानों के अधिग्रहण को औपचारिक रूप दे दिया है।
अनुबंध संबंधी समझौते के अनुसार, एयरबस सेविले में अपनी अंतिम असेंबली लाइन से उड़ान भरने की स्थिति में पहले 16 विमान वितरित करेगा।
40 का निर्माण और असेंबलिंग टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स द्वारा भारत में दोनों कंपनियों के बीच एक औद्योगिक साझेदारी के हिस्से के रूप में की जाएगी।
सभी सी-295 विमान परिवहन विन्यास में सौंपे जाएंगे और स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट से सुसज्जित होंगे।
भारतीय वायु सेना को 13 तारीख को स्पेन के सेविले में पहला C-295 MW परिवहन विमान प्राप्त हुआसितंबर में एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने भाग लिया।
सी-295 का उपयोग 71 सैनिकों या 50 पैराट्रूपर्स तक के सामरिक परिवहन के लिए और उन स्थानों पर रसद संचालन करने के लिए किया जाता है जो भारी विमानों के लिए पहुंच योग्य नहीं हैं।

भारत ड्रोन शक्ति-2023 के बारे में:

भारत ड्रोन शक्ति - 2023 में 75 से अधिक ड्रोन स्टार्ट-अप और कंपनियों की भागीदारी देखी जा रही है।
इसमें केंद्र सरकार, राज्य विभागों, सार्वजनिक और निजी उद्योगों, सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और मित्र देशों के प्रतिनिधियों सहित लगभग पांच हजार प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है।
भारत ड्रोन शक्ति 2030 तक वैश्विक ड्रोन हब बनने की भारत की प्रतिबद्धता को बढ़ावा देगा।

यूपी के बारे में:

राज्यपाल: आनंदीबेन पटेल
मुख्यमंत्री: योगी आदित्यनाथ
राजधानी: लखनऊ
राष्ट्रीय उद्यान: दुधुवा राष्ट्रीय उद्यान
वन्यजीव अभयारण्य: हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य।

भारत में बिकने वाले 40% इलेक्ट्रिक वाहन तमिलनाडु में निर्मित होते हैं

तमिलनाडु सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के वाहन डैशबोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, इस साल बेचे गए इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक बन गया है।
इस वर्ष (2023) भारत में बेची गई 10 लाख ईवी में से 4 लाख से अधिक का निर्माण तमिलनाडु में किया गया था।
ईवी दो और चार पहिया वाहनों के साथ-साथ राज्य में दस कंपनियों द्वारा निर्मित कारें थीं।

वाहन डैशबोर्ड डेटा के अनुसार, जनवरी से 20 सितंबर तक RTO के साथ 10,44,600 ईवी पंजीकृत किए गए थे।

इसमें से, तमिलनाडु ने राज्य के आरटीओ में सभी ईवी के पंजीकरण के आधार पर निर्मित 4,14,802 ईवी बेचीं।
अग्रणी मूल उपकरण निर्माता (OEM) - ओला इलेक्ट्रिक, TVS मोटर, एथर एनर्जी और एम्पीयर व्हीकल्स की राज्य में अपनी ईवी विनिर्माण सुविधाएं हैं और अब उसे 2025 तक इस क्षेत्र में 50,000 करोड़ रुपये के निवेश और 150,000 नौकरियों के सृजन की उम्मीद है।
राज्य सरकार ने ईवी हब के रूप में विकसित करने के लिए 6 शहरों - कोयंबटूर, तिरुचि, तिरुनेलवेली, मदुरै, सलेम और चेन्नई की पहचान की है। इस क्षेत्र की सहायता करने वाले कुछ प्राकृतिक लाभों में एक प्रशिक्षित कार्यबल की उपलब्धता, सहायक आपूर्तिकर्ताओं की एक नेटवर्क और आपूर्ति श्रृंखला, एक जीवंत ऑटो और ऑटो घटक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र और बुनियादी ढांचे और रसद समर्थन प्रणाली शामिल हैं।

तमिलनाडु के बारे में:

राज्यपाल: आरएन रवि
मुख्यमंत्री: एमके स्टालिन
राजधानी: चेन्नई
राष्ट्रीय उद्यान: गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान
वन्यजीव अभयारण्य: अनामलाई टाइगर रिजर्व, इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान

बिजली, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने नई दिल्ली में 'भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023' का उद्घाटन किया

बिजली, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने आज नई दिल्ली में फिक्की फेडरेशन हाउस में 'भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023' का उद्घाटन किया।
दो दिवसीय शिखर सम्मेलन का उद्देश्य देश में एक सक्षम ग्रीन हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित करना है।
शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि जलवायु परिवर्तन दुनिया के लिए खतरा है।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत अगली पीढ़ी के लिए स्वस्थ और सुरक्षित पौधे के पीछे रहने के लिए प्रतिबद्ध है।
शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में बेल्जियम के किंडोम के राजदूत डिडियर वेंडरहासेल्ट और जर्मनी के राजदूत डॉ. फिलिप एकरमैन सहित वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन सेल बस लॉन्च की

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में इंडिया गेट से अपनी तरह की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस लॉन्च की।
इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि सरकार हरित वाहनों की नई पीढ़ी लाने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि ये बसें 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने के भारत के लक्ष्य की दिशा में एक सकारात्मक कदम हैं।
परियोजना के विवरण का उल्लेख करते हुए, इंडियन ऑयल के अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद्य ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वर्ष के अंत तक 13 और बसें लॉन्च की जाएंगी।

हरदीप सिंह पुरी के बारे में:

हरदीप सिंह पुरी (जन्म 15 फरवरी 1952) एक भारतीय राजनीतिज्ञ और पूर्व भारतीय राजनयिक हैं जो वर्तमान में भारत सरकार में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास और शहरी मामलों के मंत्री के रूप में कार्यरत हैं।
वह वर्तमान में इतिहास में आवास और शहरी मामलों के लिए सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मंत्री के रूप में भी रिकॉर्ड रखते हैं।

विदेश मंत्री एस जयशंकर, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत की जी20 अध्यक्षता, वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा की

विदेश मंत्री एस जयशंकर और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने न्यूयॉर्क में अपनी बैठक के दौरान भारत की जी20 अध्यक्षता के साथ-साथ अफगानिस्तान, म्यांमार की स्थिति और अन्य वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा की।
डॉ. जयशंकर के साथ संयुक्त राष्ट्र महासचिव की बैठक में श्री गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र के साथ भारत के सहयोग और जी20 के नेतृत्व के लिए सराहना व्यक्त की।
विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस से भी मुलाकात की.
डॉ. जयशंकर ने भारत की जी20 अध्यक्षता के परिणामों पर यूएनजीए अध्यक्ष की सराहना का स्वागत किया।
वे बहुपक्षवाद में सुधार और हमारे समय के महत्वपूर्ण मुद्दों पर ग्लोबल साउथ को उसका हक दिलाने के महत्व पर भी सहमत हुए।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे

पंजाब में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह अमृतसर में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ शामिल हैं।
बैठक का आयोजन भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत अंतर-राज्य परिषद सचिवालय द्वारा पंजाब सरकार के सहयोग से किया जा रहा है।
इस बैठक के सुचारू संचालन के लिए विस्तृत व्यवस्था की गई है।
मेहमानों को समृद्ध पंजाबी संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी।
बैठक में सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ-साथ प्रत्येक राज्य के दो वरिष्ठ मंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल/प्रशासक शामिल होंगे।
बैठक में राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव, अन्य वरिष्ठ अधिकारी और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेंगे।

मुद्दों पर चर्चा:

इस बैठक में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद कई मुद्दों पर चर्चा करेगी।
इन मुद्दों में भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड, पंजाब विश्वविद्यालय से संबद्धता, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना PMGSY के तहत सड़क निर्माण कार्य, नहर परियोजनाएं और पानी का बंटवारा, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित मुद्दे, बुनियादी ढांचे का विकास, भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण और वन संबंधी मंजूरी, उड़ान योजना के तहत क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय स्तर पर सामान्य हित के अन्य मुद्दे शामिल हैं।

ISAC 2022 के चौथे संस्करण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय मध्य प्रदेश के इंदौर में दो दिवसीय इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कर रहा है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड प्रतियोगिता (ISAC) 2022 के चौथे संस्करण के विजेताओं को सम्मानित करेंगी।
कॉन्क्लेव में उन सभी 100 स्मार्ट शहरों की भागीदारी देखी जाएगी जो शहरी नवाचार में सबसे आगे रहकर शहर के विकास के अभ्यास में एक आदर्श बदलाव का नेतृत्व कर रहे हैं।
यह आयोजन देश में भविष्य के शहरी परिवर्तन के रोडमैप को स्पष्ट करने में मदद करने के लिए मिशन के तहत किए गए उनके अनुकरणीय कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए शहरों को एक मंच प्रदान करेगा।

इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड प्रतियोगिता के बारे में:

इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड प्रतियोगिता (ISAC) का आयोजन भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत किया जाता है।
यह मिशन के तहत शुरू की गई महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक है, जहां अनुकरणीय प्रदर्शन को पुरस्कृत करने, सहकर्मी-सहकर्मी सीखने को सक्षम करने और सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रसार करने के लिए अग्रणी शहर रणनीतियों, परियोजनाओं और विचारों को मान्यता दी जाती है।
ISAC उन शहरों, परियोजनाओं और नवीन विचारों को मान्यता देता है और पुरस्कृत करता है जो 100 स्मार्ट शहरों में सतत विकास को बढ़ावा दे रहे हैं, साथ ही समावेशी, न्यायसंगत, सुरक्षित, स्वस्थ और सहयोगी शहरों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिससे सभी के लिए जीवन की गुणवत्ता बढ़ रही है।
अतीत में, ISAC ने 2018, 2019 और 2020 में तीन संस्करण देखे हैं।
ISAC का चौथा संस्करण अप्रैल 2022 में सूरत में 'स्मार्ट सिटीज़-स्मार्ट शहरीकरण' कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया गया था।
ISAC 2022 पुरस्कार में दो चरण की प्रस्तुति प्रक्रिया थी जिसमें 'योग्यता चरण' शामिल था, जिसमें शहर के प्रदर्शन का समग्र मूल्यांकन शामिल था, और 'प्रस्ताव चरण' जिसमें स्मार्ट शहरों को छह पुरस्कार श्रेणियों के लिए अपने नामांकन जमा करने की आवश्यकता थी:
परियोजना पुरस्कार: 10 अलग-अलग थीम,
इनोवेशन पुरस्कार: 2 अलग-अलग थीम,
राष्ट्रीय/क्षेत्रीय शहर पुरस्कार,
राज्य पुरस्कार,
यूटी पुरस्कार, और
पार्टनर्स पुरस्कार, 3 अलग-अलग थीम

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के बारे में:

आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय (MoHUA) भारत सरकार का एक मंत्रालय है जो भारत में आवास और शहरी विकास से संबंधित नियमों और विनियमों और कानूनों के निर्माण और प्रशासन पर कार्यकारी अधिकार रखता है।
मंत्रालय 2004 में आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय से स्वतंत्र हो गया, लेकिन बाद में 2017 में इसे फिर से इसमें मिला दिया गया।
गठन: 1952
जिम्मेदार मंत्री: हरदीप सिंह पुरी

संशोधित FCRA नियम: NGO को विदेशी फंड से बनाई गई संपत्ति का ब्योरा देना होगा

गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA के तहत पंजीकृत गैर-सरकारी संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों द्वारा वार्षिक रिटर्न दाखिल करने से संबंधित नियमों में संशोधन किया है और उनसे हर साल विदेशी धन का उपयोग करके बनाई गई चल और अचल संपत्तियों का विवरण प्रदान करने के लिए कहा है।
मंत्रालय ने एक गजट अधिसूचना में कहा कि विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार विदेशी अंशदान (विनियमन) नियम, 2011 में और संशोधन करने के लिए नियम बनाती है।
मंत्रालय ने विदेशी योगदान विनियमन नियमों में दो खंड जोड़कर बदलाव किया - वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को विदेशी योगदान से बनाई गई चल संपत्ति का विवरण और वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को विदेशी योगदान से बनाई गई अचल संपत्ति का विवरण। फॉर्म एफसी-4 में।
फॉर्म एफसी-4 अपने वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के लिए एफसीआरए लाइसेंस प्राप्त गैर सरकारी संगठनों द्वारा भरा जाता है।
गृह मंत्रालय ने उन संस्थाओं के FCRA लाइसेंस की वैधता बढ़ाने का भी फैसला किया, जिनके लाइसेंस इस महीने की 30 तारीख (सितंबर 2023) को समाप्त हो रहे थे और नवीनीकरण अगले साल 31 मार्च (2024) तक लंबित था।

देखे गए आंकड़ों के अनुसार, MHA ने 2019 और 2022 के बीच FCRA के तहत पंजीकृत या पूर्व अनुमति प्राप्त 335 NGO और संघों का निरीक्षण या ऑडिट किया, यह देखने के लिए कि क्या उनके द्वारा विदेशी फंडिंग नियमों का पालन किया जा रहा है।
सरकार ने विदेशी धन प्राप्त करने और उपयोग करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को जवाबदेह बनाकर FCRA अनुपालन को सख्त कर दिया है।
गृह मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि एनजीओ को पिछले तीन वर्षों में ₹55,449 करोड़ की विदेशी फंडिंग प्राप्त हुई है।
इस साल 17 जुलाई तक देश में वैध FCRA लाइसेंस वाले 16,301 NGO थे और कानून के उल्लंघन के लिए पिछले पांच वर्षों में 6,600 से अधिक NGO के FCRA लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं।
कुल मिलाकर, अब तक 20,693 NGO के FCRA लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं।
FCRA अधिनियम, जिसे सितंबर 2020 में संशोधित किया गया था, ने लोक सेवकों को विदेशी फंडिंग प्राप्त करने से रोक दिया और NGO के प्रत्येक पदाधिकारी के लिए आधार अनिवार्य बना दिया।
नए कानून में यह भी कहा गया है कि विदेशी फंड प्राप्त करने वाले संगठन प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए ऐसे फंड का 20% से अधिक उपयोग नहीं कर पाएंगे।
यह सीमा अब तक 50% थी.
नए FCRA नियमों के अनुसार, ऐसे संगठन जो सीधे तौर पर किसी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं हैं, लेकिन बंद, हड़ताल या रास्ता रोको (सड़क नाकेबंदी) जैसी राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हैं, उन्हें राजनीतिक प्रकृति का माना जाएगा।
इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले संगठनों में किसान संगठन, छात्र या श्रमिक संगठन और जाति-आधारित संगठन शामिल हैं।

विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010:

विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 2010 के 42वें अधिनियम द्वारा भारत की संसद का एक अधिनियम है।
यह एक समेकित अधिनियम है जिसका दायरा कुछ व्यक्तियों या संघों या कंपनियों द्वारा विदेशी योगदान या विदेशी आतिथ्य की स्वीकृति और उपयोग को विनियमित करना है और राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक किसी भी गतिविधि के लिए विदेशी योगदान या विदेशी आतिथ्य की स्वीकृति और उपयोग को प्रतिबंधित करना है।

गृह मंत्रालय के बारे में:

गृह मंत्रालय या केवल गृह मंत्रालय, भारत सरकार का एक मंत्रालय है।
यह मुख्य रूप से आंतरिक सुरक्षा और घरेलू नीति के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है।
इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री करते हैं।
गठन: 15 अगस्त 1947
जिम्मेदार मंत्री: अमित शाह

केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया फार्मा-मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास और नवाचार पर राष्ट्रीय नीति लॉन्च करेंगे

डॉ मनसुख मंडाविया, केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, भारत सरकार भारत में फार्मा-मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान और विकास और नवाचार पर राष्ट्रीय नीति लॉन्च करेंगे।
इसके अलावा, केंद्रीय मंत्री फार्मा मेडटेक सेक्टर (PRIP) में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए योजना का शुभारंभ करेंगे।
यह आयोजन 26 सितंबर, 2023 को फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया जाएगा।
राष्ट्रीय नीति और योजना केंद्रीय रसायन और उर्वरक और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री भगवंत खुबा और नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके पॉल की उपस्थिति में लॉन्च की जाएगी।

लॉन्च कार्यक्रम में नीति निर्माता, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के विशेषज्ञ और शिक्षा जगत, थिंक टैंक, उद्योग और मीडिया सहित अन्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। उद्योग विशेषज्ञों, विभिन्न विभागों के सरकारी अधिकारियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को भी आमंत्रित किया जाएगा।
इस सभा का उद्देश्य भारत की दवा और फार्मास्युटिकल निर्यात प्रवृत्ति, भारत की श्रेणी-वार निर्यात हिस्सेदारी, प्रस्तावना, नीति की आवश्यकता, इसके उद्देश्य, उद्देश्यों के फोकस क्षेत्रों और निगरानी और मूल्यांकन तंत्र को उजागर करना है।
इस लॉन्च इवेंट का उद्देश्य दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स के लिए भारत के निर्यात रुझानों के साथ-साथ श्रेणी, नीति की प्रस्तावना और उसके उद्देश्यों के अनुसार निर्यात हिस्सेदारी को प्रदर्शित करना है।
यह उन उद्देश्यों और इसकी निगरानी और मूल्यांकन पद्धति के क्षेत्रों पर और जोर देगा।

मुख्य विचार:

फार्मा-मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय नीति का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक दवाओं और फाइटोफार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरणों सहित फार्मास्यूटिकल्स में अनुसंधान एवं विकास को प्रेरित करना है।
यह नीति भारत को अगले दशक में फार्मा-मेडटेक सेक्टर को 120-130 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने में मदद करेगी, जिससे सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान लगभग 100 आधार अंकों तक बढ़ जाएगा।
यह पारंपरिक दवाओं और फाइटोफार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरणों सहित फार्मास्यूटिकल्स में अनुसंधान एवं विकास में सुधार करेगा।

केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने एम्स दिल्ली के 68वें स्थापना दिवस समारोह की अध्यक्षता की

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली ने परिसर के मैदान में 68वां स्थापना दिवस मनाया, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने भाग लिया।
एम्स दिल्ली के 68वें स्थापना दिवस समारोह में एम्स नई दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर एम श्रीनिवास, एम्स नई दिल्ली के डीन प्रोफेसर मीनू बाजपेयी और एम्स नई दिल्ली के रजिस्ट्रार प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद रथ ने भी भाग लिया।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने साझा किया कि भारत वर्तमान में अपने अत्यधिक कुशल मानव संसाधनों की बदौलत किसी भी विकसित देश के बराबर स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर सकता है। देश पहले से ही अपने वैक्सीन उत्पादन कौशल, फार्मास्युटिकल फर्मों और चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सफलताओं के लिए प्रसिद्ध है।
इस अवसर पर प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने "एम्स: भारत की स्वास्थ्य देखभाल सुरक्षा में अग्रणी" विषय पर आयोजित एआईआईएम की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसके बाद इस अवसर पर डॉ. वीके पॉल ने डायमंड जुबली ओरेशन दिया।
डॉ. वीके पॉल ने "आत्मनिर्भरता" और "आत्मविश्वास" की कहानी शीर्षक से कोविड-19 टीकाकरण यात्रा साझा की। भारत ने महामारी के दौरान प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के तहत स्वदेशी वैक्सीन और विदेशी वैक्सीन दोनों के निर्माण में सफलता हासिल की है।

एम्स दिल्ली के बारे में:

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, जिसे एम्स दिल्ली के रूप में भी जाना जाता है, नई दिल्ली, भारत में एक सार्वजनिक चिकित्सा अनुसंधान विश्वविद्यालय और अस्पताल है।
संस्थान एम्स अधिनियम, 1956 द्वारा शासित है और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्वायत्त रूप से संचालित होता है।
अध्यक्ष: मनसुख मंडाविया
स्थापना: 1956
आदर्श वाक्य: "द बॉडी इज इनडीड द प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट ऑफ़ धर्म"

सरकार की योजना दिल्ली और जयपुर के बीच इलेक्ट्रिक हाईवे विकसित करने की है

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, नितिन गडकरी ने कहा है कि इलेक्ट्रिक बसें बहुत लोकप्रिय हैं और सरकार दिल्ली से जयपुर तक एक इलेक्ट्रिक राजमार्ग बनाने की योजना बना रही है।

उन् होंने नई दिल्ली में 20वें भारत-अमरीका आर्थिक शिखर सम् मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही।
श्री गडकरी ने कहा कि सरकार लक्जरी सुविधाओं के साथ बसें लाने की योजना बना रही है और लोगों को विमानन श्रेणी के समान उपचार मिलेगा।
उन्होंने कहा कि डीजल बसों की तुलना में यह दर 30 प्रतिशत से कम होगी।
इन बसों को जयपुर और दिल्ली जाने में लगभग दो घंटे 50 मिनट का समय लगेगा।
केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि भारत-अमेरिका आर्थिक शिखर सम्मेलन में काफी संभावनाएं हैं जहां दोनों देश नए संयुक्त उद्यमों की दिशा में काम कर सकते हैं।
उन्होंने कहा भारत और अमेरिका परस्पर प्रौद्योगिकी साझा कर सकते हैं जिससे दोनों देशों के विकास में मदद मिलेगी।
श्री गड़करी ने 7वां बिजनेस लीडरशिप पुरस्कार भी दिया।

पीएम मोदी गुजरात के छोटा उदेपुर में परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के छोटा उदेपुर में 5200 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
इन परियोजनाओं में 'मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस' कार्यक्रम के तहत 4500 करोड़ रुपये से अधिक की स्कूल बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शामिल हैं।
प्रधानमंत्री वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन के दो दशक पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम की भी अध्यक्षता करेंगे।
हालिया रिपोर्टों में कहा गया है कि वर्ष 2003 में मात्र 300 अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों के साथ अहमदाबाद के टैगोर हॉल से शुरू हुई यात्रा 28 सितंबर 2023 को शानदार 20 साल पूरे कर रही है।
वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट, इस पहल की संकल्पना गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वैश्विक व्यवसायों को आकर्षित करने के लिए की गई थी जब राज्य अभी भी विनाशकारी भूकंप के दुष्प्रभावों से पीड़ित था।
सितंबर 2003 में शिखर सम्मेलन शुरू होने के समय मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
पिछले 20 वर्षों में, शिखर सम्मेलन ने गुजरात को व्यवसायों के लिए एक अग्रणी ब्रांड के रूप में सफलतापूर्वक स्थापित किया है।
2019 शिखर सम्मेलन, इसमें 135 से अधिक देशों के हजारों प्रतिनिधियों की जबरदस्त भागीदारी देखी गई।
शिखर सम्मेलन के दो दशक के जश्न को चिह्नित करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम, जो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित किया जाएगा, इसमें उद्योग संघ, व्यापार और वाणिज्य क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियां, युवा उद्यमी और शामिल होंगे।

गुजरात के बारे में:

पूंजी: गांधीनगर
मुख्यमंत्री: भूपेन्द्रभाई पटेल
राज्यपाल: आचार्य देवव्रत
राष्ट्रीय उद्यान: गिर राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, भावनगर ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान, वंसदा राष्ट्रीय उद्यान

भारत का पहला लाइटहाउस उत्सव गोवा में शुरू हुआ

भारत का पहला लाइटहाउस फेस्टिवल गोवा में शुरू हुआ।
केंद्रीय बंदरगाह मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत के साथ फोर्ट अगुआड़ा लाइटहाउस में उत्सव का उद्घाटन किया।
केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गोवा के प्रतिष्ठित किले अगुआड़ा में 'भारतीय प्रकाश स्तंभ उत्सव' या भारतीय प्रकाशस्तंभ महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया।

मुख्य विचार:

यह महोत्सव 23 सितंबर को शुरू हुआ और 25 सितंबर तक चलेगा।
इसे पर्यटन स्थलों के रूप में बढ़ावा देने के लिए देश भर के प्रकाशस्तंभों में मनाया जा रहा है।
75 ऐतिहासिक लाइटहाउसों को पर्यटन स्थलों में बदलने के लिए 'लाइटहाउस हेरिटेज टूरिज्म' अभियान शुरू किया गया था।
यह महोत्सव प्रकाशस्तंभों को पर्यटक आकर्षण के रूप में विकसित करने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
गोवा के फोर्ट अगुआड़ा में होने वाले उत्सव में नृत्य प्रदर्शन, भोजन स्टॉल, संगीत समारोह और समुद्री इतिहास पर चर्चा जैसी विभिन्न गतिविधियाँ शामिल होती हैं।

गोवा के बारे में:

राजधानी: पणजी
मुख्यमंत्री: प्रमोद सावंत
राज्यपाल: पीएस श्रीधरन पिल्लई
राष्ट्रीय उद्यान &वन्यजीव अभ्यारण्य: अंशी राष्ट्रीय उद्यान, भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य, बोंडला वन्यजीव अभयारण्य, नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य, कोटिगाओ वन्यजीव अभयारण्य, म्हादेई वन्यजीव अभयारण्य

पीएम मोदी ने लता मंगेशकर को उनकी जयंती पर याद किया:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर को उनकी 94वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी।
28 सितंबर 1929 को जन्मीं 'भारत कोकिला' का संगीत में योगदान अविस्मरणीय है।

मंगेशकर द्वारा जीते गए पुरस्कार:

अपने पूरे करियर में, उन्होंने कई पुरस्कार और सम्मान जीते।
उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला।
उन्हें 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।
2007 में, फ्रांस ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर का अधिकारी बनाया।
वह तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 15 बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुरस्कार, चार फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्वगायक पुरस्कार, दो फिल्मफेयर विशेष पुरस्कार, फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार सहित अन्य पुरस्कारों की प्राप्तकर्ता थीं।
1974 में, वह लंदन, इंग्लैंड में रॉयल अल्बर्ट हॉल में प्रदर्शन करने वाली पहली भारतीय पार्श्व गायिका बनीं।
हालाँकि लता मंगेशकर का बहु-अंग विफलता के कारण 6 फरवरी को निधन हो गया, लेकिन वह 'अजीब दास्तां है ये', 'ऐ मेरे वतन के लोगो', 'लुक्का छुपी' जैसे अपने भावपूर्ण गीतों के साथ हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगी।

ICCR द्वारा आयोजित इंडो-लैटिन अमेरिकी सांस्कृतिक महोत्सव का चौथा संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) द्वारा आयोजित इंडो-लैटिन अमेरिकी सांस्कृतिक महोत्सव का चौथा संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ।
दो दिवसीय महोत्सव में तीन देशों - कोलंबिया, इक्वाडोर और चिली के कुल 34 कलाकार भाग ले रहे हैं।
ICCR के अध्यक्ष डॉ. विनय सहस्रबुद्धे ने कहा कि संस्कृति और कला के जीवंत उत्सव का उद्देश्य लैटिन अमेरिका की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना है।
उन्होंने कहा कि यह महोत्सव सांस्कृतिक और शैक्षिक सहयोग की संभावनाओं पर विचार-विमर्श करने के लिए भारत और लैटिन अमेरिका के प्रमुख हितधारकों को एक साथ ला रहा है।
आकाशवाणी संवाददाता की रिपोर्ट है कि इंडो-लैटिन अमेरिकी सांस्कृतिक महोत्सव भारत और लैटिन अमेरिका के बीच स्थायी सांस्कृतिक संबंधों के प्रमाण के रूप में कार्य करता है, जो दोनों क्षेत्रों की समृद्ध परंपराओं और कलात्मक अभिव्यक्तियों की आपसी समझ और सराहना को बढ़ावा देता है।

Click Here to Subscribe Our Yearly Mock Test Package

पीएम मोदी आकांक्षी ब्लॉकों के लिए सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रम 'संकल्प सप्ताह' का शुभारंभ करेंगे

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में देश में आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह नामक एक सप्ताह तक चलने वाले कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे।
उद्घाटन कार्यक्रम में भारत मंडपम में देश भर से लगभग 3,000 पंचायत और ब्लॉक स्तर के जन प्रतिनिधि और पदाधिकारी भाग लेंगे।
इसके अलावा, ब्लॉक और पंचायत स्तर के पदाधिकारियों, किसानों और जीवन के अन्य क्षेत्रों के व्यक्तियों सहित लगभग 2 लाख लोग कार्यक्रम से वस्तुतः जुड़ेंगे।
संकल्प सप्ताह आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (ABP) के प्रभावी कार्यान्वयन से जुड़ा है।
ब्लॉक स्तर पर शासन में सुधार और नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रधान मंत्री द्वारा इस वर्ष 7 जनवरी (2023) को राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू किया गया था।
इसे 329 जिलों के 500 आकांक्षी ब्लॉकों में लागू किया जा रहा है।
आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम को लागू करने और एक प्रभावी ब्लॉक विकास रणनीति तैयार करने के लिए, देश भर में गांव और ब्लॉक स्तर पर चिंतन शिविर आयोजित किए गए।
संकल्प सप्ताह चिंतन शिविरों की परिणति है
विषय पहले छह दिनों में संपूर्ण स्वास्थ्य, सुपोषित परिवार, स्वच्छता, कृषि, शिक्षा और समृद्धि दिवस शामिल हैं।
सप्ताह के अंतिम दिन 9 अक्टूबर को पूरे सप्ताह के दौरान किए गए कार्यों का जश्न मनाया जाएगा, संकल्प सप्ताह के रूप में - समावेश समारोह।

1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST दर

भारत 1 अक्टूबर, 2023 से ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर लागू करने के लिए तैयार है।
यह घोषणा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने की।
यह घोषणा लोकसभा द्वारा दो GST कानूनों में संशोधन को ध्वनिमत से पारित करने के लगभग दो महीने बाद की गई है।
ये संशोधन कैसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग में आपूर्ति के कराधान पर स्पष्टता प्रदान करने के लिए CGST अधिनियम, 2017 की तीसरी अनुसूची में प्रावधान शामिल करने से संबंधित हैं।
दूसरी ओर, IGST अधिनियम में संशोधन ऑफशोर संस्थाओं द्वारा प्रदान किए गए ऑनलाइन मनी गेमिंग पर जीएसटी देयता लगाने का प्रावधान डालने से संबंधित है।
ऐसी संस्थाओं को भारत में GST पंजीकरण प्राप्त करना आवश्यक होगा। GST की समीक्षा अगले वित्त वर्ष में ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो पर कदम उठाए जाने की संभावना है।
केंद्र ने कहा है कि ये संशोधन कैसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग में आपूर्ति के कराधान के संबंध में बहुत जरूरी स्पष्टता प्रदान करेंगे।

इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स

काठमांडू-कलिंग साहित्य महोत्सव नेपाल के ललितपुर में संपन्न हुआ

3 दिनों तक चलने वाला काठमांडू-कलिंग साहित्य महोत्सव नेपाल के ललितपुर में संपन्न हुआ।
महोत्सव का उद्घाटन नेपाल के विदेश मंत्री एनपी सऊद ने किया।
भाग लेने वाले देश: महोत्सव के दौरान भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका सहित कई दक्षिण एशियाई देशों के साहित्य का प्रदर्शन किया गया।
महोत्सव में साहित्य, संगीत, नृत्य, कविता और अन्य कला रूपों का प्रदर्शन किया गया।
मुख्य विचार:
प्रोफेसर अवधेश प्रधान, अभिनेत्री और लेखिका दिव्या दत्ता, प्रोफेसर माधव प्रसाद

पोखरेल और अभिनेत्री मनीषा कोइराला को 'यशस्वी साहित्य सम्मान' मिला।
इस वर्ष 'यशस्वी पुस्तक पुरस्कार' नामक एक नया पुरस्कार शुरू किया गया, जो विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्यों को मान्यता देता है।
बिबेक ओझा को उनकी पुस्तक 'ऐथन' के लिए कथा साहित्य का पुरस्कार मिला।
डॉ. नवराज केसी को 'सुन्याको मुल्या' के लिए क्रिएटिव नॉन-फिक्शन के लिए सम्मानित किया गया।
रेणुका जीसी को उनकी कहानी पुस्तक 'सनेश' के लिए मान्यता मिली।
डॉ. महेंद्र मल्ल को उनके काव्य संग्रह 'भासको बकपात्र' के लिए सराहा गया।
गोविंदा गिरी प्रेरणा को 'सुश्री पारिजात' के लिए जीवनी श्रेणी का पुरस्कार मिला।
'छमछको छमछमी' के लिए अनुराधा को बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

'यशस्वी पुस्तक' के अन्य प्राप्तकर्तापुरस्कार' में शामिल हैं:

रीमा केसी को 'सेलेक्टेड पोयम्स ऑफ अमृता प्रीतम' के अनुवाद के लिए पुरस्कृत किया गया।
नारायण घिमिरे को 'रायठाणे खानपण रा चाडपरवा' के लिए खाद्य एवं औषधि श्रेणी में मान्यता मिली।
लाक्पा डेंडी शेरपा को उनकी आत्मकथा 'हिमालयन मेवरिक' के लिए सम्मानित किया गया।
सुशांत थापा को 'मीन्स ऑफ मेरिट' शीर्षक वाली कविताओं के संकलन के लिए अंग्रेजी कविता लेखन की श्रेणी में पुरस्कार मिला।

नेपाल के बारे में:

अध्यक्ष: राम चंद्र पौडेल
प्रधान मंत्री: पुष्प कमल दहल
पूंजी: काठमांडू
मुद्रा: नेपाली रुपया

इंडोनेशिया ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए 'गोल्डन वीज़ा' कार्यक्रम शुरू किया

इंडोनेशिया ने विदेशी व्यक्तियों और कॉर्पोरेट निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से एक 'गोल्डन वीज़ा' कार्यक्रम शुरू किया हैअपनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करें।
गोल्डन वीज़ा 5 से 10 वर्षों की अवधि के लिए विस्तारित निवास परमिट प्रदान करता है, जो पात्र आवेदकों के लिए दीर्घकालिक प्रवास का विकल्प प्रदान करता है।

व्यक्तिगत निवेशक पात्रता:

5-वर्षीय गोल्डन वीज़ा के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, किसी व्यक्ति को इंडोनेशिया में न्यूनतम $2.5 मिलियन के निवेश के साथ एक कंपनी स्थापित करनी होगी।
10 साल के वीज़ा के लिए, आवश्यक निवेश बढ़कर $5 मिलियन हो जाता है।

कॉर्पोरेट निवेशक पात्रता:

कॉर्पोरेट निवेशक, जैसे निदेशक और आयुक्त, $25 मिलियन का निवेश करके 5 साल के गोल्डन वीज़ा के लिए पात्र हैं।
10-वर्षीय वीज़ा प्राप्त करने के लिए, उन्हें अपना निवेश दोगुना करना होगा, जो कुल $50 मिलियन होगा।
संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और स्पेन सहित कई अन्य देश भी निवेशकों के लिए इसी तरह के 'गोल्डन वीज़ा' कार्यक्रम पेश करते हैं।
ये कार्यक्रम इन देशों में पूंजी को आकर्षित करने और उद्यमशीलता निवास को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

इंडोनेशिया के बारे में:

राष्ट्रपति: जोको विडोडो
पूंजी: जकार्ता
मुद्रा: इंडोनेशियाई रुपया

G20 शिखर सम्मेलन में भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए

नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका (US), सऊदी अरब, यूरोपीय संघ (EU), संयुक्त अरब अमीरात (UAE), फ्रांस, की सरकारों के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। जर्मनी और इटली भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) स्थापित करेंगे।

मुख्य विचार:

IMEC परियोजना PGII (पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट) का हिस्सा है, जो एक पश्चिमी नेतृत्व वाली पहल है जिसका उद्देश्य दुनिया भर में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित करना है।
इसे चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) का जवाब माना जा रहा है।
PGII को पारदर्शिता और लिंग समानता और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के विकास के लक्ष्यों को संबोधित करते हुए जलवायु-लचीला बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने की विशेषता है, जैसा कि जी 7 देशों द्वारा रेखांकित किया गया है।
PGII वैश्विक दक्षिण देशों में बुनियादी ढांचे के अंतराल को कम करने में योगदान दे सकता है।

विशिष्ट पहल:

इंडोनेशिया में परियोजनाएं: PGII ने इंडोनेशिया में कई परियोजनाओं की घोषणा की है, जिनमें स्वच्छ ऊर्जा और दूरसंचार से संबंधित परियोजनाएं भी शामिल हैं।
अमेरिकी निवेश: अमेरिकी सरकार का अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम (DFC) भारत के स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में 15 मिलियन डॉलर से अधिक का निवेश करेगा।
ईयू ग्लोबल गेटवे कार्यक्रम: यूरोपीय संघ, अपने ग्लोबल गेटवे कार्यक्रम के माध्यम से, 2021 से 2027 तक महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी परियोजनाओं में 300 बिलियन यूरो के निवेश को सक्रिय करने की योजना बना रहा है, इस फंडिंग का आधा हिस्सा अफ्रीका के लिए नामित है।

यूनाइटेड किंगडम ने यूरोपीय संघ के €95.5 बिलियन होराइजन अनुसंधान कार्यक्रम में फिर से प्रवेश किया

यूनाइटेड किंगडम (यूके) सरकार ने आधिकारिक तौर पर € 95 बिलियन के बजट के साथ यूरोपीय संघ के अनुसंधान वित्त पोषण कार्यक्रम क्षितिज यूरोप में फिर से शामिल होने के अपने फैसले की घोषणा की है।
इस कदम से, ब्रिटेन के वैज्ञानिकों को अब वित्त पोषण के एक महत्वपूर्ण स्रोत तक पहुंच प्राप्त होगी।
ब्रिटेन ने 2020 की शुरुआत में EU छोड़ दिया।

मुख्य विचार:

होराइजन यूरोप में यूके की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए यूरोपीय आयोग और यूनाइटेड किंगडम के बीच एक "सैद्धांतिक समझौते" पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
होराइज़न यूरोप यूरोपीय संघ और "संबद्ध" गैर-यूरोपीय संघ देशों के भीतर व्यक्तिगत शोधकर्ताओं और अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग का समर्थन करता है।
ये संबद्ध देश कार्यक्रम में योगदान करते हैं और अनुदान सुरक्षित करने और सीमा पार वैज्ञानिक परियोजनाओं में शामिल होने के अवसर प्राप्त करते हैं।
2016 के जनमत संग्रह में ब्रिटेन के यूरोपीय संघ छोड़ने के फैसले ने शुरुआत में होराइजन यूरोप में उसकी भागीदारी को खतरे में डाल दिया।
हालाँकि 2020 ब्रेक्सिट वापसी समझौते के हिस्से के रूप में होराइजन यूरोप के साथ सहयोग पर बातचीत की गई थी, उत्तरी आयरलैंड से संबंधित व्यापार विवादों ने यूके-ईयू संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया, जिससे समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर में देरी हुई।
2024 में शुरू होकर, यूके एक संबद्ध देश के रूप में क्षितिज यूरोप में फिर से शामिल हो जाएगा, कार्यक्रम तक पहुंचने के लिए सालाना लगभग € 2.6 बिलियन का योगदान देगा।

होराइजन यूरोप के अलावा, यूके यूरोपीय संघ के पृथ्वी अवलोकन कार्यक्रम, जिसे कोपरनिकस के नाम से जाना जाता है, में भी फिर से शामिल होगा।

G20 नेताओं ने पर्यटन क्षेत्र को महत्वपूर्ण बढ़ावा देने के लिए गोवा रोडमैप और "ट्रैवल फॉर लाइफ" कार्यक्रम को मंजूरी दी

बीस का समूह (जी20) नेताओं ने सतत विकास लक्ष्यों (SDG) को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में "पर्यटन के लिए गोवा रोडमैप" का सर्वसम्मति से समर्थन किया है।
"गोवा रोडमैप" भारत के G20 पर्यटन ट्रैक का परिणाम है और स्थायी वैश्विक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक ब्लूप्रिंट के रूप में कार्य करता है।
यह रोडमैप भारत की जी20 प्रेसीडेंसी की थीम के अनुरूप है और समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यावरणीय स्थिरता में पर्यटन की भूमिका पर जोर देता है।

5 प्राथमिकता वाले क्षेत्र:

रोडमैप 5 परस्पर जुड़ी प्राथमिकताओं पर प्रकाश डालता है:
हरित पर्यटन
डिजिटाइजेशन
गंतव्य प्रबंधन
कौशल विकास
पर्यटन सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों (MSME) के लिए सहायता।
इन प्राथमिकताओं का सभी G20 देशों ने समर्थन किया है, जिसमें टिकाऊ, लचीला और समावेशी पर्यटन प्राप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया है।

जीवन भर के लिए यात्रा:

भारत के "जीवन के लिए यात्रा" (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) के दृष्टिकोण को गोवा रोडमैप में एकीकृत किया गया है, जिसमें टिकाऊ जीवन शैली पर जोर दिया गया है।

G20 पर्यटन और SDG डैशबोर्ड:

G20 पर्यटन और SDG डैशबोर्ड को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (UNWTO) के सहयोग से केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।
यह डैशबोर्ड एक वैश्विक भंडार के रूप में कार्य करता है, जो G20 देशों की स्थायी पर्यटन प्रथाओं और नीतियों की सर्वोत्तम प्रथाओं और केस अध्ययनों को प्रदर्शित करता है।

मिशन लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवन शैली):

मिशन LiFE या पर्यावरण के लिए जीवन शैली पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से व्यक्तिगत और सामुदायिक कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत द्वारा शुरू किया गया एक वैश्विक पर्यावरण आंदोलन है।
इसे नवंबर 2021 में ग्लासगो में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP26) में भारतीय प्रधान मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था।
मिशन LiFE का लक्ष्य भारत और अन्य देशों में 1 अरब व्यक्तियों को स्थायी जीवन शैली अपनाने और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने के लिए प्रेरित करना है।
यह "पी3 मॉडल" की भावना का प्रतीक है, जिसका अर्थ है "प्रो प्लैनेट पीपल।"
यह कार्यक्रम स्थायी जीवन पद्धतियों को बढ़ावा देते हुए 'ग्रह की जीवन शैली, ग्रह के लिए और ग्रह द्वारा' के सिद्धांतों पर संचालित होता है।

पर्यटन मंत्रालय के बारे में:

कैबिनेट मंत्री: जी किशन रेड्डी
राज्य मंत्री: श्रीपद नाइक,अजय भट्ट

इटली कथित तौर पर चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से हटने पर विचार कर रहा है

इटली के प्रधान मंत्री श्री जियोर्जिया मेलोनी ने कथित तौर पर 2023 में जी20 शिखर सम्मेलन में एक निजी बैठक के दौरान चीनी प्रधान मंत्री के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) से हटने के इटली के इरादे पर चर्चा की।
मेलोनी ने स्पष्ट किया कि BRI से इटली की वापसी के संबंध में अंतिम निर्णय अभी तक नहीं किया गया है।

मुख्य विचार:

इटली एकमात्र G7 देश है जो 2019 में BRI में शामिल हुआ, जिसने इसे अन्य प्रमुख पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं से अलग कर दिया।
G7 में उन्नत अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, जिनमें अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान शामिल हैं, जबकि यूरोपीय संघ "गैर-प्रगणित" सदस्य है।
चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (जिसे वन बेल्ट, वन रोड (OBOR) के रूप में भी जाना जाता है) कई देशों के माध्यम से सड़क, रेल और बंदरगाह परियोजनाओं के चक्रव्यूह के निर्माण की परिकल्पना करती है।
इसका उद्देश्य चीन के पड़ोसी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के निर्माण के एक विशाल कार्यक्रम के माध्यम से बीजिंग के आर्थिक नेतृत्व को मजबूत करना है।
कनेक्टिविटी और व्यापार मार्गों को बढ़ाने के उद्देश्य के कारण BRI को अक्सर "21वीं सदी का सिल्क रोड" कहा जाता है।
भारत ने मुख्य रूप से इस चिंता के कारण BRI में भाग लेने से इनकार कर दिया है कि चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC), जो BRI का एक घटक है, भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र से होकर गुजरता है।
CPEC चीन के शिनजियांग क्षेत्र से पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक चलता है, जो गिलगित-बाल्टिस्तान सहित भारत द्वारा दावा किए गए क्षेत्रों से होकर गुजरता है।
इटली ऐसे समय में BRI में शामिल हुआ जब उसने निवेश और बुनियादी ढांचे के विकास की मांग की, खासकर आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के बाद।
वैश्विक बुनियादी ढांचा निवेश के लिए भागीदारी (PGII) को पश्चिमी देशों द्वारा BRI के विकल्प के रूप में पेश किया गया है, जिसका उद्देश्य वैश्विक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित करना है।

इटली के बारे में:

अध्यक्ष: सर्जियो मैटरेल्ला
प्रधान मंत्री: जियोर्जिया मेलोनी
राजधानी: रोम
मुद्रा: यूरो

नई दिल्ली में जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली के नेताओं की घोषणा में जलवायु परिवर्तन पर प्रकाश डाला गया

G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर, 2023 को नई दिल्ली में हुआ।
शिखर सम्मेलन के दौरान अपनाए गए नई दिल्ली नेताओं की घोषणा ने वैश्विक भूराजनीतिक एजेंडे पर जलवायु परिवर्तन को प्रमुखता से उजागर किया।
नई दिल्ली घोषणापत्र में जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने में अपर्याप्तताओं को भी रेखांकित किया गया है, जिसमें वैश्विक महत्वाकांक्षा और पेरिस के कार्यान्वयन पर चिंता व्यक्त की गई है।
जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए समझौते की प्रतिबद्धताएँ अपर्याप्त हैं।
जी20 नेताओं ने सदी के मध्य तक या उसके आसपास वैश्विक शुद्ध-शून्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन या कार्बन तटस्थता प्राप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

मुख्य विचार:

नई दिल्ली घोषणा उच्च वित्तीय आंकड़ों पर ध्यान केंद्रित करके और शमन के लिए वित्त से लचीलापन और अनुकूलन की ओर संक्रमण करके वित्तीय चर्चाओं में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है।
घोषणा में कहा गया है कि विकासशील देशों को अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) हासिल करने के लिए 2030 से पहले 5.8-5.9 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता है।
इसके अतिरिक्त, यह विकासशील देशों के लिए 2050 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने के लिए 4 ट्रिलियन डॉलर के वार्षिक व्यय का अनुमान लगाता है।
घोषणापत्र बहुपक्षीय विकास बैंकों (MDB) के लिए सुधारों का समर्थन करता है, जिसमें मिश्रित वित्त और जोखिम-साझाकरण तंत्र का विस्तार करने के लिए सतत वित्त कार्य समूह (SFWG) की सिफारिशें शामिल हैं।
SFWG की सिफारिशें विशेष रूप से रियायती संसाधनों के माध्यम से जलवायु वित्त जुटाने में MDB की बढ़ती भूमिका पर जोर देती हैं।
घोषणा 2030 तक (2019 के स्तर की तुलना में) वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को 43% तक कम करने की आवश्यकता को पहचानती है और इस बात पर जोर देती है कि वैश्विक शिखर 2025 से पहले होना चाहिए।
नई दिल्ली घोषणा में कुछ विवादास्पद मुद्दों जैसे कि अधिक महत्वपूर्ण उत्सर्जन में कटौती, जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना और वित्तीय संसाधनों को बड़े पैमाने पर जुटाना शामिल नहीं था।
इसने काफी हद तक पहले बताए गए पदों का पालन किया।

पीएम मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का अनावरण किया

प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन (GBA) की स्थापना की घोषणा की।
यह भारत के नेतृत्व वाली एक पहल है जिसका उद्देश्य जैव ईंधन को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और उद्योग के खिलाड़ियों के बीच एक गठबंधन बनाना है।·

सदस्यता और संस्थापक देश:

GBA को G20 सदस्यों और गैर-सदस्य देशों सहित 19 देशों से समर्थन प्राप्त हुआ है।
अब तक कुल 19 देश और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन गठबंधन में शामिल होने के लिए सहमत हुए हैं, जिनमें G20 सदस्य और गैर-सदस्य देश दोनों शामिल हैं।
गठबंधन के संस्थापक सदस्यों में भारत, ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।

उद्देश्य:

GBA का उद्देश्य विशेष रूप से परिवहन क्षेत्र में सहयोग को सुविधाजनक बनाना और टिकाऊ जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना है।
यह बाजारों को मजबूत करने, वैश्विक जैव ईंधन व्यापार को सुविधाजनक बनाने, नीति सबक साझा करने और दुनिया भर में राष्ट्रीय जैव ईंधन कार्यक्रमों के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है।

जैव ईंधन के बारे में:

यह एक ईंधन है जो जीवाश्म ईंधन, जैसे तेल के निर्माण में शामिल बहुत धीमी प्राकृतिक प्रक्रियाओं के बजाय बायोमास से थोड़े समय की अवधि में उत्पादित होता है।

जैव ईंधन की विभिन्न पीढ़ियाँ:

पहली पीढ़ी: इसका उत्पादन उपभोज्य खाद्य पदार्थों से किया जाता है जिनमें बायोअल्कोहल के लिए स्टार्च (चावल और गेहूं), चीनी (चुकंदर और गन्ना), या बायोडीजल के लिए वनस्पति तेल शामिल होते हैं।
दूसरी पीढ़ी: यह मुख्य रूप से गैर-खाद्य फीडस्टॉक जैसे वन/उद्योग/कृषि अपशिष्ट और अपशिष्ट या प्रयुक्त वनस्पति तेलों से प्राप्त होता है।
तीसरी पीढ़ी: इसे 'शैवाल ईंधन' के रूप में जाना जाता है और यह बायोडीजल और बायोअल्कोहल दोनों के रूप में शैवाल से प्राप्त होता है।

चौथी पीढ़ी: तीसरी पीढ़ी की तरह, 4जी जैव ईंधन गैर-कृषि योग्य भूमि का उपयोग करके बनाया जाता है। हालाँकि, तीसरे के विपरीत, उन्हें बायोमास के विनाश की आवश्यकता नहीं है।

GBA में महत्वपूर्ण सदस्य देश:

GBA में अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कनाडा, भारत, इटली, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे G20 देशों का समर्थन शामिल है।

G20 द्वारा आमंत्रित देशों में GBA का समर्थन करने वाले बांग्लादेश, सिंगापुर, मॉरीशस और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं।

8 गैर-जी20 देश आइसलैंड, केन्या, गुयाना, पैराग्वे, सेशेल्स, श्रीलंका, युगांडा और फिनलैंड सहित, GBA का भी हिस्सा हैं।

अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भागीदारी:

12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल हुए हैं, जिसमें विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, विश्व आर्थिक मंच, विश्व एलपीजी संगठन, यूएन एनर्जी फॉर ऑल, यूनिडो, बायोफ्यूचर्स प्लेटफॉर्म, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, आईईए, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी और विश्व बायोगैस एसोसिएशन शामिल हैं।

इथेनॉल के प्रमुख उत्पादक और उपभोक्ता:

GBA सदस्य जैव ईंधन के प्रमुख उत्पादक और उपभोक्ता हैं।

USA (52%), ब्राज़ील (30%) और भारत (3%), उत्पादन में लगभग 85% हिस्सेदारी और इथेनॉल की खपत में लगभग 81% योगदान देता है।

भारत के जैव ईंधन कार्यक्रमों पर प्रभाव:

GBA से पीएम-जीवन योजना, सतत और गोबरधन योजना सहित भारत के मौजूदा जैव ईंधन कार्यक्रमों में तेजी लाने की उम्मीद है।

इन पहलों का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, रोजगार के अवसर पैदा करना और भारत के पारिस्थितिकी तंत्र के समग्र विकास में योगदान करना है।

जैव ईंधन में विकास की संभावनाएँ:

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के अनुसार, जैव ईंधन क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास क्षमता है, जो 2050 तक इसके वर्तमान आकार का 3.5-5 गुना होने का अनुमान है।

इस वृद्धि का श्रेय शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने के वैश्विक प्रयासों को दिया जाता है, जो भारत के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है।

इथेनॉल-पेट्रोल सम्मिश्रण सफलता:

भारत ने नवंबर 2022 की मूल नियोजित समयसीमा से पहले ही पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिश्रण करने का अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है।

इस सफलता ने भारत सरकार को 2030 के पिछले लक्ष्य से 2025-26 तक 20% इथेनॉल के साथ अखिल भारतीय ई20-पेट्रोल के रोलआउट को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है।

भारत ने स्थायी ऊर्जा प्रथाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए जी-20 देशों से वैश्विक स्तर पर पेट्रोल के साथ 20% तक इथेनॉल मिश्रण को अपनाने पर विचार करने का आग्रह किया है।

भारत टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों के तहत उपयुक्त जैव ईंधन के साथ डीजल के मिश्रण और बायोगैस के साथ प्राकृतिक गैस के उपयोग की भी खोज कर रहा है।

भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत-मध्य पूर्व-यूरोप मेगा आर्थिक गलियारे का अनावरण किया

भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत-मध्य पूर्व-यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर (IMEC) की शुरुआत की घोषणा की है।

भाग लेने वाले देश:

IMEC परियोजना में भारत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई देश शामिल हैं।

उद्देश्य:
परियोजना का प्राथमिक लक्ष्य ऊर्जा उत्पादों के व्यापार पर विशेष ध्यान देने के साथ भाग लेने वाले देशों के बीच बढ़ते व्यापार को सुविधाजनक बनाना है।
IMEC के घटक:
IMEC में 2 मुख्य गलियारे हैं: एक पूर्वी गलियारा जो भारत को खाड़ी क्षेत्र से जोड़ता है और एक उत्तरी गलियारा जो खाड़ी क्षेत्र को यूरोप से जोड़ता है।
इसमें रेलवे, जहाज-रेल पारगमन नेटवर्क और सड़क परिवहन मार्गों सहित परिवहन के विभिन्न तरीके शामिल हैं।
मुख्य विचार:
गलियारे में रेलवे लिंक, बिजली केबल, हाइड्रोजन पाइपलाइन और हाई-स्पीड डेटा केबल जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे के तत्व शामिल होंगे।
उम्मीद है कि IMEC भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
रेल और शिपिंग कॉरिडोर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट (PGII) के लिए साझेदारी का हिस्सा है, जो विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए जी 7 देशों द्वारा एक सहयोगात्मक प्रयास है।
PGII का लक्ष्य विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे की कमी को पाटना और वैश्विक स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों (SDG) को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति में तेजी लाना है।
बुनियादी ढांचे की योजना की शुरुआत जून 2021 में यूके में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी।
सामूहिक रूप से, PGII का लक्ष्य 2027 तक जी7 देशों से लगभग 600 बिलियन डॉलर जुटाना है ताकि महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश किया जा सके जिससे जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो और दुनिया भर में लोगों को लाभ हो।

भारत और यूके ने नई दिल्ली में 12वीं आर्थिक और वित्तीय वार्ता (EFD) बैठक आयोजित की

मंत्रिस्तरीय भारत-यूनाइटेड किंगडम (यूके) आर्थिक और वित्तीय वार्ता का 12वां दौर नई दिल्ली में हुआ।
भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने किया और ब्रिटेन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ब्रिटेन के राजकोष के चांसलर माननीय श्री जेरेमी हंट, सांसद, ब्रिटेन के राजकोष के चांसलर ने किया।
भारत औरयूके ने वित्तीय समावेशन और सतत विकास पर ध्यान देने के साथ वित्तीय सेवाओं पर सहयोग को गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
बातचीत का फोकस बुनियादी ढांचे के विकास की प्राथमिकताओं, मजबूत फिनटेक साझेदारी और दीर्घकालिक विकास उद्देश्यों के लिए सतत वित्त को आगे बढ़ाने के लिए भारत और यूके के बीच ज्ञान के आदान-प्रदान, सहयोग और समर्थन को बढ़ाने पर भी था।
दोनों पक्षों ने व्यापक आर्थिक और बहुपक्षीय मुद्दों पर आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की।
मुख्य विचार:
भारत और यूके ने यूके इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज के लॉन्च की घोषणा की, जो नीति आयोग और सिटी ऑफ लंदन कॉरपोरेशन के सह-नेतृत्व में एक सहयोगी उद्यम है, जिसका उद्देश्य प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाना और उन्हें लागू करना है।
चर्चा में सुरक्षित और समावेशी वित्तीय मध्यस्थता को बढ़ावा देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग और भारत के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग के अवसरों पर प्रकाश डाला गया।
ब्रिटेन के राजकोष के चांसलर ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज (LSE) में भारतीय कंपनियों की सीधी लिस्टिंग की सुविधा के प्रयासों की सराहना की।
टिप्पणी:

11वीं भारत-यूनाइटेड किंगडम आर्थिक और वित्तीय वार्ता (EFD) 02 सितंबर, 2021 को भारतीय केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और यूनाइटेड किंगडम ट्रेजरी चांसलर श्री ऋषि सुनक की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी।

यूनाइटेड किंगडम के बारे में:

कैबिनेट मंत्री: निर्मला सीतारमण
राज्य मंत्री: भागवत कराड, पंकज चौधरी

यूके के बारे में:

प्रधान मंत्री: ऋषि सुनक
पूंजी: लंडन
मुद्रा: पौंड स्टर्लिंग

अफ्रीकी संघ को G20 में स्थायी सदस्यता प्रदान की गई

अफ्रीकी संघ आधिकारिक तौर पर G20 समूह का सदस्य बन गया है, और यह समावेश भारतीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर किया गया था, जो G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे थे।
18वें जी20 शिखर सम्मेलन के समापन पर एक नेता घोषणापत्र को अपनाए जाने की उम्मीद है, जो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अत्याधुनिक भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जा रहा है।
भारत की G20 अध्यक्षता का विषय "वसुधैव कुटुंबकम - एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य" है।

मुख्य विचार:

अफ्रीकी संघ में अफ्रीकी महाद्वीप के 55 देश शामिल हैं।
जी20 के भीतर अफ्रीकी संघ को पूर्ण सदस्यता देने का विचार पीएम मोदी ने जी20 नेताओं के साथ चर्चा के दौरान प्रस्तावित किया था।
इस विचार को जनवरी 2023 में 'वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ' शिखर सम्मेलन के बाद गति मिली, जिसमें कई अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों ने भाग लिया।
इस समावेशन से पहले, अफ्रीकी संघ का केवल एक देश, दक्षिण अफ्रीका, G20 का हिस्सा था।
अफ्रीकी एकता संगठन को प्रतिस्थापित करने के उद्देश्य से 9 सितंबर, 1999 को लीबिया में सिर्ते घोषणा में अफ्रीकी संघ की घोषणा की गई थी।
इसे आधिकारिक तौर पर 2001 में इथियोपिया में स्थापित किया गया था और 9 जुलाई 2002 को दक्षिण अफ्रीका में लॉन्च किया गया था।
अफ्रीकी संघ को संयुक्त राष्ट्र महासभा में स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है।

अफ्रीकी संघ के बारे में:

मुख्यालय: अदीस अबाबा, इथियोपिया
वर्तमान अध्यक्ष: अज़ाली असौमानी
आधिकारिक भाषा: किस्वाहिली

UNDP इंडिया ने डेटा-संचालित कृषि नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड के साथ सहयोग किया है

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) ने 5 साल के समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

उद्देश्य:

टिकाऊ कृषि पद्धतियों के निर्माण और विशेष रूप से महिलाओं सहित छोटे कृषकों के लिए आजीविका सुरक्षित करने पर ध्यान देने के साथ DiCRA (क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर में डेटा) सहित डेटा-संचालित डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं का सह-निर्माण करना।

MoU पर नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक श्री संजीव रोहिल्ला और UNDP के उप-निवासी प्रतिनिधि सुश्री इसाबेल सचान ने हस्ताक्षर किए।

मुख्य विचार:

इस समझौता ज्ञापन के तहत, दोनों संगठन उत्पाद विकास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और कृषि नीतियों के निर्माण का समर्थन करने के लिए ओपन-सोर्स डेटा साझा करके छोटे किसानों के जीवन और आजीविका को बेहतर बनाने के लिए सहयोग करेंगे।

UNDP कृषि निवेश में डेटा-संचालित निर्णय लेने को बढ़ावा देने के नाबार्ड के एजेंडे का समर्थन करने के लिए खुले नवाचारों, डेटा सहयोगी, डेटा विज्ञान दृष्टिकोण और वैश्विक ज्ञान में अपनी विशेषज्ञता का लाभ उठाएगा।

DiCRA (जलवायु लचीली कृषि में डेटा) के बारे में:

DiCRA एक सहयोगी डिजिटल सार्वजनिक वस्तु है जो जलवायु-लचीले कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण भू-स्थानिक डेटासेट तक खुली पहुंच प्रदान करती है।

UNDP और साझेदार संगठन भारत भर में 50 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि को कवर करते हुए कृषि में सार्वजनिक निवेश की जानकारी देने के लिए DiCRA का प्रबंधन करते हैं।

DiCRA उन खेतों की पहचान करने के लिए अत्याधुनिक डेटा विज्ञान और मशीन लर्निंग का उपयोग करता है जो जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीले हैं और जो अत्यधिक असुरक्षित हैं।

इस तरह के खुले डेटा नवाचार सर्वोत्तम प्रथाओं को उजागर कर सकते हैं, कृषि निवेश को अनुकूलित कर सकते हैं और आबादी को जोखिम से बचा सकते हैं।

नाबार्ड DiCRA प्लेटफ़ॉर्म की मेजबानी और रखरखाव करेगा और UNDP के तकनीकी सहयोग से नीति निर्माण, अनुसंधान और विकास गतिविधियों के लिए प्रमुख भू-स्थानिक डेटासेट का उपयोग करेगा।

साझेदारी के लाभ:

साझेदारी समय के साथ कृषि रुझानों के विश्लेषण को सक्षम करेगी ताकि वाटरशेड प्रबंधन, सूक्ष्म सिंचाई, गोदाम अनुकूलन और जलवायु से संबंधित पहल जैसे क्षेत्रों में निवेश के बारे में निर्णय को सूचित किया जा सके।

यह सहयोग UNDP और नाबार्ड दोनों के लिए डेटा संसाधनों को बढ़ाता है, कृषि में डेटा-संचालित समाधानों को बढ़ावा देता है।

नवीनतम समाचार:

अगस्त 2023 में, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने भारत के सतत विकास लक्ष्यों (SDG) को गति देने के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (MDoNER) को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता जताई।

नाबार्ड के बारे में:

मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र, भारत

अध्यक्ष: श्री. शाजी के.वी

इसकी स्थापना राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 को लागू करने के लिए 12 जुलाई 1982 को बी शिवरामन समिति (संसद के अधिनियम 61, 1981 द्वारा) की सिफारिशों पर की गई थी।

नाबार्ड भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और शीर्ष सहकारी बैंकों के समग्र विनियमन के लिए एक शीर्ष नियामक निकाय है।

यह वित्त मंत्रालय (MoF), भारत सरकार (GoI) के अधिकार क्षेत्र में है।

UNDP के बारे में:

स्थापना: 22 नवंबर 1965

मुख्यालय: न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका

प्रशासक :अचिम स्टीनर

UNDP संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जिसे देशों को गरीबी को खत्म करने और सतत आर्थिक विकास और मानव विकास प्राप्त करने में मदद करने का काम सौंपा गया है।

इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र विस्तारित तकनीकी सहायता कार्यक्रम (EPTA) और विशेष कोष के विलय के साथ की गई थी।

यूनाइटेड किंगडम ने ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए $2 बिलियन का योगदान दिया

यूनाइटेड किंगडम (यूके) ने जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने और विकसित देशों को विकासशील देशों के लिए जलवायु निधि में योगदान सुनिश्चित करने के लिए जी20 नेताओं की प्रतिबद्धता के मद्देनजर ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF) को 2 बिलियन डॉलर देने का वादा किया है।

इस प्रतिबद्धता को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए यूके द्वारा की गई सबसे बड़ी फंडिंग प्रतिज्ञाओं में से एक माना जाता है।

यह प्रतिबद्धता पार्टियों के सम्मेलन (COP27) में यूके के प्रधान मंत्री की घोषणा के बाद है कि यूके जलवायु अनुकूलन के लिए अपनी फंडिंग को तीन गुना कर देगा।

मुख्य विचार:

यूके GCF में £1.62 बिलियन का योगदान देगा, जो 2 बिलियन डॉलर के बराबर है।

COP15 में कोपेनहेगन समझौते के बाद 194 देशों द्वारा GCF की स्थापना की गई थी।

GCF दुनिया का सबसे बड़ा वैश्विक कोष है जो वैश्विक उत्सर्जन को कम करने में विकासशील देशों का समर्थन करने और समुदायों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल बनाने में मदद करने के लिए समर्पित है।

2 बिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता 2020 से 2023 की अवधि के लिए GCF में यूके के पिछले योगदान में 12.7% की वृद्धि दर्शाती है।

यह पिछला योगदान ही 2014 में फंड की स्थापना के लिए उनकी शुरुआती फंडिंग को दोगुना करना था।

यूनाइटेड किंगडम ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि उसने किसी भी अन्य G7 देश की तुलना में तेज़ दर से उत्सर्जन कम किया है।

इसके अतिरिक्त, कम-कार्बन ऊर्जा स्रोत अब यूके के आधे से अधिक बिजली उत्पादन के लिए जिम्मेदार हैं।

2011 के बाद से, यूके जलवायु सहायता खर्च ने 95 मिलियन से अधिक लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में सहायता की है और 68 मिलियन टन से अधिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम किया है या टाला है।

यूके के बारे में:

प्रधान मंत्री: ऋषि सुनक

राजधानी: लंदन

मुद्रा: पाउंड स्टर्लिंग

म्यांमार को 2026 एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशंस (आसियान) की बैठक की अध्यक्षता करने की अनुमति नहीं दी गई

दक्षिण पूर्व एशियाई नेताओं ने निर्णय लिया कि म्यांमार देश में सत्ता पर सैन्य कब्जे के कारण दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) 2026 की बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा।

आसियान शिखर सम्मेलन के बारे में:

आसियान शिखर सम्मेलन आसियान में सर्वोच्च नीति-निर्धारक निकाय है जिसमें आसियान सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होते हैं।

आसियान शिखर सम्मेलन की बैठकें सालाना दो बार आयोजित की जाती हैं, जिसका निर्धारण आसियान शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष द्वारा अन्य सदस्य राज्यों के परामर्श से किया जाता है।

आसियान शिखर सम्मेलन की मेजबानी सदस्य देशों के बीच घूमती रहती है, आसियान सदस्य राज्य आसियान की अध्यक्षता में इस आयोजन की मेजबानी करते हैं।

पहला आसियान शिखर सम्मेलन 1976 में बाली, इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था।

आसियान के बारे में:

स्थापना: 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक, थाईलैंड में आसियान घोषणा (बैंकॉक घोषणा) पर हस्ताक्षर के साथ।

मुख्यालय: जकार्ता, इंडोनेशिया
महासचिव: काओ किम होर्न
आसियान दक्षिण पूर्व एशिया के 10 सदस्य देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है।
संस्थापक: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड।
अन्य सदस्य ब्रुनेई, वियतनाम, लाओ पीडीआर (पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक), म्यांमार और कंबोडिया हैं।

जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान-नीति मंच का 10वां सत्र बॉन, जर्मनी में आयोजित हुआ

जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं (IPBES) पर अंतर सरकारी विज्ञान-नीति मंच के पूर्ण सत्र का 10वां सत्र 28 अगस्त से 2 सितंबर, 2023 तक बॉन, जर्मनी में आयोजित किया जा रहा है।

IPBES क्या है?

IPBES जैव विविधता के संरक्षण और टिकाऊ उपयोग, दीर्घकालिक मानव कल्याण और सतत विकास के लिए जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए विज्ञान-नीति इंटरफ़ेस को मजबूत करने के लिए राज्यों द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र अंतर-सरकारी निकाय है।
IPBES की स्थापना 21 अप्रैल 2012 को 94 सरकारों की भागीदारी के साथ पनामा सिटी में की गई थी।
भारत IPBES के संस्थापक सदस्यों में से एक है।
यह संयुक्त राष्ट्र की संस्था नहीं है
हालाँकि, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) IPBES को सचिवालय सेवाएं प्रदान करता है
IPBES ने अपना नया प्रकाशन - "आक्रामक विदेशी प्रजातियों और उनके नियंत्रण पर मूल्यांकन रिपोर्ट" जारी किया है।
IPBES के 143 सदस्य राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा बॉन, जर्मनी में अनुमोदित, मूल्यांकन रिपोर्ट जैव विविधता पर विदेशी प्रजातियों के प्रभाव का विश्लेषण करती है।
यह अध्ययन, जो 4 वर्षों की अवधि में हुआ है, 49 देशों के 86 प्रमुख विशेषज्ञों द्वारा 13,000 से अधिक संदर्भों पर आधारित है।
पौधों और जानवरों सहित 37,000 विदेशी प्रजातियाँ हैं, जिन्हें कई मानवीय गतिविधियों द्वारा दुनिया भर के क्षेत्रों और बायोम में लाया गया है।
37,000 में से 3,500 से अधिक विदेशी प्रजातियाँ प्रकृति, अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा और मानव स्वास्थ्य के लिए बड़े वैश्विक खतरे पैदा करती हैं।
अधिकांश देशों (80%) ने अपनी राष्ट्रीय जैव विविधता योजनाओं में आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रबंधन से संबंधित लक्ष्यों को शामिल किया है।
केवल 17% ही राष्ट्रीय कानून में इस मुद्दे को विशेष रूप से संबोधित करते हैं। सभी देशों में से लगभग आधे (45%) जैविक आक्रमणों के प्रबंधन में निवेश नहीं करते हैं।
दिसंबर 2022 में, सरकारें कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे के लक्ष्य 6 के तहत 2030 तक आक्रामक विदेशी प्रजातियों के परिचय और स्थापना की दर को कम से कम 50% कम करने पर सहमत हुईं।
IPBES 9 के पूर्ण सत्र का 9वां सत्र 3 से 9 जुलाई 2022 तक बॉन, जर्मनी में आयोजित किया गया था।

जर्मनी के बारे में:

राष्ट्रपति: फ्रैंक-वाल्टर स्टीनमीयर
राजधानी: बर्लिन
मुद्रा: यूरो

यूनेस्को ने शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (GenAI) के अनुप्रयोग पर उद्घाटन मार्गदर्शन जारी किया

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने शिक्षा में जेनरेटिव एआई (GenAI) के उपयोग पर अपना पहला मार्गदर्शन प्रकाशित किया है, जिसमें इस तकनीक को विनियमित करने के महत्व पर जोर दिया गया है।

यूनेस्को ने सरकारी एजेंसियों से शिक्षा में GenAI के उपयोग को विनियमित करने का आह्वान किया है।
इसमें डेटा गोपनीयता की सुरक्षा के उपाय और उपयोगकर्ताओं के लिए आयु सीमा का कार्यान्वयन शामिल है।

मुख्य विचार:

मार्गदर्शन में चैटजीपीटी जैसे जेनएआई चैटबॉट्स के उद्भव पर प्रकाश डाला गया है, जिसे नवंबर में माइक्रोसॉफ्ट समर्थित ओपनएआई द्वारा लॉन्च किया गया था।
इन चैटबॉट्स ने महत्वपूर्ण लोकप्रियता हासिल की है और Google के बार्ड जैसे प्रतिद्वंद्वी सिस्टम के विकास को प्रेरित किया है।
छात्रों ने GenAI को भी पसंद किया है, जो संकेतों की कुछ पंक्तियों के साथ निबंध से लेकर गणितीय गणना तक कुछ भी उत्पन्न कर सकता है।
64 पेज की रिपोर्ट में दिशानिर्देशों की एक श्रृंखला के बीच, यूनेस्को ने तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में स्कूली शिक्षा के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत AI पाठ्यक्रम की आवश्यकता पर जोर दिया।
यूनेस्को ने 64 पन्नों की अपनी रिपोर्ट में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में स्कूली शिक्षा के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत एआई पाठ्यक्रम की आवश्यकता पर जोर दिया है।
जबकि चीन जैसे कुछ देशों ने पहले ही GenAI पर नियम बना लिए हैं, यूरोपीय संघ के AI अधिनियम को बाद में 2023 में मंजूरी मिलने की उम्मीद है।
हालाँकि, कई अन्य देश अभी भी अपने स्वयं के एआई कानूनों का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में हैं।

यूनेस्को के बारे में:

स्थापना: 16 नवंबर 1945
मुख्यालय: पेरिस, फ्रांस
महानिदेशक: ऑड्रे अज़ोले
मूल संगठन: संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद
यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र (UN) की एक विशेष एजेंसी है जिसका उद्देश्य शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है।

विश्व बैंक और यूनिसेफ के आकलन से पता चलता है कि भारत में 52 मिलियन बच्चे अत्यधिक गरीबी में हैं

विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष (यूनिसेफ) ने "अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखाओं के अनुसार बाल मौद्रिक गरीबी में वैश्विक रुझान" नामक एक मूल्यांकन किया।
आकलन के अनुसार, भारत में लगभग 52 मिलियन बच्चे अत्यधिक गरीबी में जी रहे हैं।
रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि विश्व स्तर पर अत्यधिक गरीबी में रहने वाला हर दूसरा व्यक्ति बच्चा है।

मुख्य विचार:

सितंबर 2022 के मध्य में विश्व बैंक द्वारा अपने गरीबी और असमानता प्लेटफ़ॉर्म पर डेटा अपडेट करने के साथ एक नई वैश्विक गरीबी रेखा को अपनाया गया था।
दुनिया भर में अत्यधिक गरीब आबादी 2.15 डॉलर (लगभग 178.38 रुपये) की अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है।
2022 में, कुल वैश्विक अत्यधिक गरीब आबादी में बच्चों की हिस्सेदारी 5% थी।
मूल्यांकन से पता चलता है कि अधिकांश गरीब बच्चे दो क्षेत्रों में केंद्रित हैं: उप-सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया।
उप-सहारा अफ्रीका में गरीबी में रहने वाले बच्चों की दर सबसे अधिक है, इस क्षेत्र के 40% बच्चे अत्यधिक गरीबी का सामना कर रहे हैं।
इसके बाद दक्षिण एशिया का नंबर आता है जहां 9.7% बच्चे गरीबी में जी रहे हैं।
ये दो क्षेत्र, उप-सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया, मिलकर दुनिया के 90% बेहद गरीब बच्चों का हिस्सा हैं।

आकलन से पता चलता है कि 2020 में, महामारी की शुरुआत के वर्ष में, बाल गरीबी में वृद्धि हुई, जिससे लगातार गिरावट की प्रवृत्ति टूट गई।
बच्चों में सबसे अधिक गरीबी दर 0-5 वर्ष आयु वर्ग में देखी जाती है।
इस आयु वर्ग में, लगभग 18.3% 99 मिलियन बच्चों के बराबर, बेहद गरीब घरों में रहते थे।
आकलन के मुताबिक, भारत में 5% बच्चे बेहद गरीब घरों में रहते हैं।

विश्व बैंक के बारे में:

स्थापना: 7 जुलाई, 1944
मुख्यालय: वाशिंगटन, डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका
अध्यक्ष: अजय बंगा

यूनिसेफ के बारे में:

स्थापना: 1946
मुख्यालय: न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका
कार्यकारी निदेशक: कैथरीन एम. रसेल

ADB ने वित्त वर्ष 2024 में बांग्लादेश के लिए 6.5 प्रतिशत GDP वृद्धि की भविष्यवाणी की है

एशियाई विकास बैंक (ADB) ने वित्तीय वर्ष 2024 में बांग्लादेश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि 6.5 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है, जबकि वित्तीय वर्ष 2023 में अनुमानित वृद्धि 6 प्रतिशत है।
यह अनुमान ADB की नवीनतम रिपोर्ट, 'एशियाई विकास आउटलुक (ADO) सितंबर 2023' में जारी किया गया था।
ADB ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि थोड़ी तेज वृद्धि का पूर्वानुमान घरेलू मांग में सुधार और यूरो क्षेत्र में आर्थिक सुधार के कारण बेहतर निर्यात वृद्धि को दर्शाता है।
ADB ने यह भी भविष्यवाणी की है कि बांग्लादेश में मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2023 में 9.0% से घटकर वित्त वर्ष 2024 में 6.6% हो जाएगी।
हालाँकि, बांग्लादेश सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार अगस्त 2023 में खाद्य मुद्रास्फीति 12.54 प्रतिशत थी जो 12 साल का उच्चतम स्तर है।
ADB को यह भी उम्मीद है कि प्रेषण वृद्धि में सुधार के कारण चालू खाता घाटा वित्त वर्ष 2023 में सकल घरेलू उत्पाद के 0.7% से थोड़ा कम होकर वित्त वर्ष 2024 में सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% हो जाएगा।
इस विकास अनुमान का मुख्य जोखिम निर्यात वृद्धि में और गिरावट है यदि वैश्विक मांग अपेक्षा से कमजोर है

पाकिस्तान के आम चुनाव जनवरी 2024 में होंगे:

पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने घोषणा की कि देश में आम चुनाव जनवरी 2024 के आखिरी सप्ताह में होंगे।
एक बयान में, चुनावी निकाय ने कहा कि उसने निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर काम की समीक्षा की और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए प्रारंभिक सूची पिछले सप्ताह सितंबर में प्रकाशित की जाएगी।
इसमें कहा गया है कि सूची के संबंध में आपत्तियों और सुझावों को सुनने के बाद अंतिम सूची 30 नवंबर को जारी की जाएगी।
आयोग ने कहा कि चुनाव जनवरी 2024 के अंतिम सप्ताह में होंगे।
पाकिस्तान में नेशनल असेंबली के विघटन के 90 दिनों के भीतर आम चुनाव होने हैं, जिसे 9 अगस्त, 2023 को समय से पहले भंग कर दिया गया था।
पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल की समाप्ति से कुछ ही दिन पहले घोषणा की थी कि चुनाव नई जनगणना पूरी होने और नई निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएँ तय होने के बाद ही हो सकते हैं।

पाकिस्तान के बारे में:

राजधानी: इस्लामाबाद
मुद्रा: रुपये

राष्ट्रपति: आरिफ अल्वी

सिंगापुर अब दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था है

कनाडा के थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, सिंगापुर ने हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था बन गई है।
1970 में विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक शुरू होने के बाद पहली बार हांगकांग पहले स्थान से खिसक कर दूसरे स्थान पर आ गया है और उसका स्कोर और भी गिरने वाला है।

स्वतंत्रता सूचकांक पर आधारित:

आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ सिद्धांतों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार में आसानी, बाजारों में प्रवेश करने और प्रतिस्पर्धा करने की स्वतंत्रता, साथ ही व्यावसायिक नियमों के साथ-साथ अन्य मानदंडों के आधार पर मापा जाता है।
2023 की रिपोर्ट के निष्कर्ष 2021 के डेटा पर आधारित हैं, जो 165 न्यायक्षेत्रों में उपलब्ध तुलनीय आंकड़ों के साथ सबसे हालिया वर्ष है। यह व्यक्तियों की आर्थिक स्वतंत्रता - या स्वयं आर्थिक निर्णय लेने की उनकी क्षमता को मापता है।

अन्य स्थानों के बारे में:

सिंगापुर पिछले वर्ष दूसरे स्थान से शीर्ष स्थान पर पहुंच गया।
स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड और अमेरिका क्रमशः तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर हैं।
अन्य उल्लेखनीय उल्लेखों में यूनाइटेड किंगडम का नौवें स्थान पर आना शामिल है, जबकि जापान और जर्मनी ने क्रमशः 20वें और 23वें स्थान का दावा किया है।

सिंगापुर के बारे में:

राजधानी: सिंगापुर
मुद्रा: डॉलर
अध्यक्ष: थरमन शन्मुगरत्नम

क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर मुलाकात

क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों - जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं - ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) सत्र के मौके पर मुलाकात की।
बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के नए विदेश मंत्री योको कामिकावा शामिल हुए।
एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि क्वाड स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक के हमारे साझा दृष्टिकोण के लिए महत्वपूर्ण है।

क्वाड ने इस पर जताई चिंता:

क्वाड ने यूक्रेन में युद्ध पर चिंता व्यक्त की और यूक्रेन में "व्यापक, न्यायपूर्ण और स्थायी शांति" का आह्वान किया।
चारों देशों ने उत्तर कोरिया के "बैलिस्टिक मिसाइल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अस्थिर करने वाले प्रक्षेपणों और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन करते हुए परमाणु हथियारों की निरंतर खोज की निंदा की।
समूह ने म्यांमार में राजनीतिक, मानवीय और आर्थिक संकट पर भी चिंता व्यक्त की और हिंसा को समाप्त करने का आह्वान किया।

क्वाड के बारे में:

स्थापना: 2007
सदस्य: भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका

भारतीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन को गणतंत्र दिवस 2024 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया

भारतीय प्रधान मंत्री (पीएम) श्री नरेंद्र मोदी ने 26 जनवरी, 2024 को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि बनने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) के राष्ट्रपति जो बिडेन को निमंत्रण दिया है।
यह निमंत्रण दिल्ली में जी 20 शिखर सम्मेलन के मौके पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति बिडेन के बीच द्विपक्षीय बैठक के दौरान दिया गया था, जो 8 सितंबर, 2023 को हुआ था।

मुख्य विचार:

यदि राष्ट्रपति बिडेन निमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं, तो वह भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सेवा देने वाले दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपति बन जाएंगे।
इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति 2015 में बराक ओबामा थे।
2022 के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सिसी थे।
भारत पारंपरिक रूप से अंतरराष्ट्रीय सहयोग और मित्रता के प्रतीक के रूप में विश्व नेताओं को अपने गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है।
2021 और 2022 दोनों में, COVID-19 महामारी के कारण गणतंत्र दिवस समारोह में कोई मुख्य अतिथि नहीं था, जिससे कई अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम बाधित हुए।

यूएसए के बारे में:

राजधानी: वाशिंगटन, डी.सी
मुद्रा: डॉलर
राष्ट्रपति: जो बिडेन

ब्रिटेन के प्रधान मंत्री ऋषि सनक ने नेट जीरो रीसेट में नई पेट्रोल और डीजल कारों पर प्रतिबंध 5 साल तक बढ़ा दिया

ऋषि सुनक, ब्रिटिश प्रधान मंत्री (पीएम) ने 2035 तक पेट्रोल और डीजल कारों पर प्रतिबंध में 5 साल की देरी की घोषणा की है।
इस देरी को ब्रिटेन में जीवन-यापन की लागत के संकट के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, और सुनक ने इसे अधिक "व्यावहारिक, आनुपातिक और यथार्थवादी मार्ग" की ओर बदलाव के रूप में वर्णित किया है।
देरी के बावजूद, यूके 2050 तक शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के अपने लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है।

शुद्ध शून्य उत्सर्जन क्या है?

'शुद्ध शून्य उत्सर्जन' का तात्पर्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (GHG) उत्पादन और वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के बीच एक समग्र संतुलन प्राप्त करना है।
सुनक ने कहा कि इस संशोधित दृष्टिकोण का उद्देश्य उन परिवारों पर वित्तीय बोझ को कम करना है जो पहले से ही संघर्ष कर रहे हैं।
पेट्रोल और डीजल कारों पर प्रतिबंध में देरी के अलावा, तेल और LPG बॉयलरों पर प्रतिबंध के साथ-साथ ऑफ-गैस-ग्रिड घरों के लिए नए कोयला हीटिंग पर भी देरी हो रही है।
यह प्रतिबंध मूल रूप से 2026 तक इन हीटिंग विधियों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन अब इसे 2035 तक बढ़ा दिया गया है।

यूके के बारे में:

प्रधान मंत्री: ऋषि सुनक
पूंजी: लंडन
मुद्रा: पौंड स्टर्लिंग

दुबई ने 21वें अरब मीडिया फोरम में मीडिया में जेनरेटिव एआई के लिए व्यापक गाइड का अनावरण किया

मीडिया परिदृश्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की शक्ति का उपयोग करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में, यूएई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इकोनॉमी और रिमोट वर्क एप्लिकेशन मंत्रालय ने दुबई मीडिया काउंसिल के सहयोग से आधिकारिक तौर पर 'मीडिया में जेनरेटिव एआई के 100 व्यावहारिक उपयोग मामले' नामक एक ग्राउंडब्रेकिंग गाइड लॉन्च किया है।
यह अनावरण दुबई में 21वें अरब मीडिया फोरम के उद्घाटन दिवस पर हुआ, जो 26 सितंबर को शुरू हुआ था।
यह व्यापक मार्गदर्शिका विभिन्न उद्योग क्षेत्रों में एआई प्रौद्योगिकियों की परिवर्तनकारी क्षमता की खोज करने के इच्छुक मीडिया पेशेवरों के लिए अंतर्दृष्टि और अनुप्रयोगों का खजाना दर्शाती है।
एक व्यापक रोडमैप की पेशकश करते हुए, गाइड मीडिया में जेनरेटिव एआई के 100 व्यावहारिक अनुप्रयोगों की सावधानीपूर्वक रूपरेखा तैयार करता है, जिसमें दृश्य कला से लेकर ऑडियो सामग्री निर्माण तक डोमेन की एक श्रृंखला शामिल है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल अर्थव्यवस्था और रिमोट वर्क एप्लिकेशन राज्य मंत्री उमर सुल्तान अल ओलामा ने संयुक्त अरब अमीरात में विकास की नई लहरों को शुरू करने और प्रौद्योगिकी-समृद्ध भविष्य तैयार करने के उद्देश्य से अत्याधुनिक प्रगति को अपनाने के लिए मंत्रालय की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
एक सूचनात्मक संसाधन के रूप में काम करने से परे, यह मार्गदर्शिका UAE के चैंपियन नवाचार-संचालित परिवर्तनों के दृष्टिकोण का प्रतीक है।
यह एक केंद्र के रूप में अपना वैश्विक कद ऊंचा करने की देश की आकांक्षा को भी रेखांकित करता है, एआई अनुप्रयोग विकास, सतत विकास को बढ़ावा देने, उत्पादकता और दक्षता बढ़ाने और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रतिमान बदलाव को उत्प्रेरित करने के लिए ऐसे नवाचारों का लाभ उठाता है।
डिजिटल प्रौद्योगिकियों के एक स्पेक्ट्रम के प्रबंधन के लिए जेनरेटर एआई सिद्धांतों और इष्टतम रणनीतियों की गहन खोज की पेशकश करके गाइड और भी आगे बढ़ता है। यह डेटा गोपनीयता संबंधी विचारों पर प्रमुखता से जोर देता है और एआई प्रौद्योगिकियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के सर्वोपरि महत्व को रेखांकित करता है।
गाइड में निहित परिवर्तनकारी अंतर्दृष्टि और ज्ञान से लैस, रचनाकारों, नवप्रवर्तकों और मीडिया पेशेवरों को अपने संबंधित क्षेत्रों में अपनी दक्षता, प्रदर्शन, रचनात्मकता और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सशक्त बनाया गया है।
इसके अलावा, यह गाइड नीति-निर्माताओं, उद्यमियों, उद्योग के नेताओं और निर्णय निर्माताओं के लिए एक अनिवार्य संसाधन के रूप में खड़ा है जो सक्रिय रूप से मीडिया नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए एआई को एकीकृत करना चाहते हैं।
ऐसे युग में जहां जेनेरिक एआई मानव रचनात्मकता को प्रतिबिंबित करने वाली सामग्री उत्पन्न करने के लिए तैयार है, यह मार्गदर्शिका न केवल संयुक्त अरब अमीरात में बल्कि व्यापक क्षेत्र और उससे परे दर्शकों के साथ गहराई से गूंजने वाली उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार है।
जैसा कि रचनात्मक सामग्री निर्माण के लिए एआई की क्षमता लगातार बढ़ रही है, गाइड का लॉन्च भविष्य की ओर एक उल्लेखनीय छलांग का संकेत देता है जहां एआई और मीडिया कहानी कहने और सामग्री निर्माण को फिर से परिभाषित करने के लिए एकजुट होते हैं।

भारत-अमेरिका 2 प्लस 2 अंतरसत्रीय वार्ता वाशिंगटन में आयोजित हुई

भारत-अमेरिका 2 प्लस 2 अंतरसत्रीय वार्ता वाशिंगटन में आयोजित किया गया था
भारत-अमेरिका संबंधों में परिवर्तनकारी गति को रेखांकित करते हुए, दोनों देशों ने अंतरसंचालनीयता और लॉजिस्टिक्स सहयोग को और मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा की।
भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव वाणी राव और रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव विश्वेश नेगी ने किया।
अमेरिकी पक्ष का नेतृत्व भारत-प्रशांत सुरक्षा मामलों के सहायक रक्षा सचिव डॉ. एली रैटनर और दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के सहायक सचिव डोनाल्ड लू ने किया।
अधिकारियों ने पूरे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय सुरक्षा विकास और रणनीतिक प्राथमिकताओं पर भी चर्चा की।

2 प्लस 2 इंटरसेशनल डायलॉग ने रक्षा और सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों, लोगों से लोगों के बीच संबंध, स्वच्छ ऊर्जा और आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन सहित अमेरिका-भारत साझेदारी के दायरे में महत्वाकांक्षी पहलों की एक विस्तृत श्रृंखला को आगे बढ़ाया।
दोनों पक्षों ने पुष्टि की कि भारत-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और समृद्धि बनाए रखने के लिए दोनों देशों के बीच मजबूत साझेदारी आवश्यक है।

भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और इज़राइल ने पर्यावरणीय मुद्दों और जलवायु परिवर्तन के समाधान के लिए संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम पर सहयोग किया

इज़राइल, भारत, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), और संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त रूप से न्यूयॉर्क में 78 वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान एक नए अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है।
ये देश I2U2 समूह के सदस्य हैं, जिन्हें पश्चिम एशिया क्वाड के नाम से भी जाना जाता है।
जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इन देशों के विदेश मंत्रियों द्वारा अक्टूबर 2021 में समूह की स्थापना की गई थी।
भाग लेने वाले देश आर्टेमिस समझौते के भी हस्ताक्षरकर्ता हैं, जो नासा की भागीदारी के साथ, विशेष रूप से चंद्रमा और मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सिद्धांतों का एक गैर-बाध्यकारी सेट है।
संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम मुख्य रूप से चार भागीदार देशों के अंतरिक्ष-आधारित अवलोकन डेटा और क्षमताओं का उपयोग करता है।
इसका उद्देश्य एक अद्वितीय अंतरिक्ष-आधारित उपकरण बनाना है जिसका उपयोग नीति निर्माताओं, संस्थानों और उद्यमियों द्वारा पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन चुनौतियों का समाधान करने के लिए किया जा सकता है।
4 देशों के विदेश मंत्रियों ने अक्टूबर 2021 में I2U2 समूह की स्थापना की।
समूह ने एक नया डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म भी लॉन्च किया, जिसमें निजी क्षेत्र के नेताओं को विभिन्न वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए परियोजनाओं के लिए अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया।
समूह ने अपना पहला आभासी शिखर सम्मेलन जुलाई 2022 में आयोजित किया।

US के बारे में:
अध्यक्ष: जो बिडेन
पूंजी: वाशिंगटन डीसी
मुद्रा: अमेरिकी डॉलर

UAE के बारे में:
अध्यक्ष: मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान
प्रधान मंत्री: मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम
पूंजी: आबू धाबी
मुद्रा: संयुक्त अरब अमीरात दिरहम

इज़राइल के बारे में:
अध्यक्ष: इसहाक हर्ज़ोग
प्रधान मंत्री: बेंजामिन नेतन्याहू
पूंजी: यरूशलेम
मुद्रा: न्यू शेकेल

ICMR अध्ययन से पता चला है कि भारतीय प्रतिदिन 8 ग्राम नमक खाते हैं, जो WHO के मानकों से 3% अधिक है

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, भारतीयों में औसत दैनिक नमक की खपत 8 ग्राम है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मानक से 3% अधिक है।

मुख्य विचार:

अध्ययन से पता चलता है कि पुरुष प्रतिदिन औसतन 8.9 ग्राम नमक का अधिक सेवन करते हैं।
नौकरीपेशा व्यक्ति भी अपेक्षाकृत अधिक नमक का सेवन करते हैं, प्रतिदिन 8.6 ग्राम।
मोटे व्यक्तियों (9.2 ग्राम) और उच्च रक्तचाप (8.5 ग्राम) वाले लोगों में नमक की खपत उल्लेखनीय रूप से अधिक है।
इसके विपरीत, महिलाओं का औसत दैनिक नमक सेवन 7.9 ग्राम है।
स्वस्थ जीवन बनाए रखने के लिए WHO प्रतिदिन 5 ग्राम नमक खाने की सलाह देता है।
इस स्तर तक नमक का सेवन कम करने से संभावित रूप से उच्च रक्तचाप को 25% तक कम किया जा सकता है।
अत्यधिक नमक के सेवन से उच्च रक्तचाप या उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ जाता है।
यह स्थिति दिल के दौरे और स्ट्रोक जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकती है।
विश्व स्तर पर, आहार में सोडियम की खपत में प्रतिदिन कम से कम 1.2 ग्राम की कमी आई है, उच्च रक्तचाप के लिए उपचार की आवश्यकता वाले व्यक्तियों की संख्या में उल्लेखनीय रूप से कमी आ सकती है, संभावित रूप से इसे 50% तक कम किया जा सकता है।

ICMR के बारे में:

मुख्यालय: नई दिल्ली, दिल्ली, भारत
महानिदेशक: राजीव बहल
ICMR, सर्वोच्च संस्थाभारतके निर्माण, समन्वयन एवं संवर्धन हेतुजैव चिकित्सा अनुसंधान, दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े चिकित्सा अनुसंधान निकायों में से एक है।

WHO के बारे में:

स्थापना: 7 अप्रैल 1948
मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्जरलैंड
महानिदेशक: टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस
WHO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है।

SDG शिखर सम्मेलन 2023 न्यूयॉर्क में सतत विकास लक्ष्यों (SDG) की दिशा में त्वरित प्रगति की शुरुआत करता है

SDG शिखर सम्मेलन 2023 न्यूयॉर्क में आयोजित एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम था।
शिखर सम्मेलन ने सतत विकास लक्ष्यों (SDG) को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति में तेजी लाने पर केंद्रित एक नए चरण की शुरुआत को चिह्नित किया।

मुख्य विचार:

महासभा के अध्यक्ष ने वैश्विक मंच पर इसके महत्व को रेखांकित करते हुए शिखर सम्मेलन बुलाया।
शिखर सम्मेलन 2030 एजेंडा और SDG को प्राप्त करने के लिए निर्धारित समय-सीमा के आधे बिंदु के साथ मेल खाता है।
2015 में, दुनिया भर के देशों ने सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के हिस्से के रूप में SDG को अपनाया।
SDG का प्राथमिक उद्देश्य वैश्विक समृद्धि को बढ़ावा देना, असमानताओं को दूर करना और सतत विकास को आगे बढ़ाते हुए पर्यावरण की रक्षा करना है।
कुल 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, प्रत्येक लक्ष्य वैश्विक चुनौतियों के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करते हैं, जिनमें गरीबी, असमानता, जलवायु परिवर्तन और बहुत कुछ शामिल हैं।
SDG को विभिन्न वैश्विक मुद्दों, जैसे गरीबी में कमी, हिंसक संघर्षों की रोकथाम, मानवाधिकारों की सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला और पर्यावरणीय गिरावट को संबोधित करने के लिए एक व्यावहारिक और प्रभावी मार्ग के रूप में पहचाना जाता है।
वर्तमान में, केवल 12% SDG को उपलब्धि के रास्ते पर माना जाता है।
यह इंगित करता है कि SDG को पूरा करने की दिशा में वैश्विक प्रगति लक्ष्य से कम हो रही है, विशेष रूप से यह देखते हुए कि यह आकलन वर्ष 2030 के आधे रास्ते पर किया गया था।

Click Here to Subscribe Our Yearly Mock Test Package

घोषणा में विकासशील देशों के लिए वित्तपोषण के लिए एक दृढ़ प्रतिबद्धता, कम से कम $500 बिलियन के वार्षिक SDG प्रोत्साहन के प्रस्ताव का समर्थन, साथ ही एक प्रभावी ऋण-राहत तंत्र शामिल है।

स्टेट करेंट अफेयर्स

दिल्ली सरकार ने नागरिकों को वनों, वन्यजीवों की रक्षा के लिए सशक्त बनाने के लिए 'ई-वनलेख' पोर्टल लॉन्च किया

दिल्ली के पर्यावरण एवं वन मंत्री गोपाल राय संरक्षण की आवश्यकता वाले वन और वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्रों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए एक पोर्टल evanlekh.eForest.delhi.gov.in लॉन्च किया।
यह डेटा को प्रभावी ढंग से देखने के लिए एक भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) प्लेटफॉर्म का उपयोग करता है, जिसका लक्ष्य दिल्ली में व्यापार करने और रहने में आसानी को बढ़ाना है।
इसके अलावा, उपयोगकर्ता पोर्टल पर KML (जिसे पहले कीहोल मार्कअप लैंग्वेज के नाम से जाना जाता था) फ़ाइलें जेनरेट कर सकते हैं।

KML क्या है?

KML, Google Earth जैसे Earth ब्राउज़र में भौगोलिक संदर्भ में जानकारी प्रदर्शित करने के लिए एक XML (एक्स्टेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज) आधारित फ़ाइल स्वरूप है।

मुख्य विचार:

यह वर्तमान में संरक्षित वन क्षेत्रों, आरक्षित वन क्षेत्रों, रूपात्मक विवरण, वन्यजीव अभयारण्यों, वन्यजीव अभयारण्यों के बफर क्षेत्रों और वन और वन्यजीव विभाग की प्रशासनिक सीमाओं सहित विभिन्न पहलुओं पर जानकारी प्रदान करता है।
पोर्टल के भविष्य के संवर्द्धन में अवर्गीकृत वन क्षेत्र, पेड़ काटने की अनुमति वाले क्षेत्र, प्रतिपूरक वृक्षारोपण और वनीकरण के लिए लक्षित क्षेत्र, हरित एजेंसियों द्वारा वृक्षारोपण स्थल, गैर-वानिकी गतिविधियों के लिए अनुमोदन की आवश्यकता वाले स्थान, मिट्टी की नमी संरक्षण विवरण और भारतीय वन रिपोर्ट आधारित हरित आवरण की जानकारी शामिल होगी।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन बहुभाषी 'स्पीकिंग फॉर इंडिया' पॉडकास्ट पेश करेंगे

द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ अपने अभियान के हिस्से के रूप में "स्पीकिंग फॉर इंडिया" शीर्षक से पॉडकास्ट की एक श्रृंखला शुरू की है।
ये पॉडकास्ट अनुवाद के माध्यम से अंग्रेजी और विभिन्न भारतीय भाषाओं सहित कई भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा।
ऑडियो श्रृंखला का उद्देश्य इस बात पर प्रकाश डालना है कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार, जिसके 2024 में समाप्त होने की उम्मीद है, ने भारत को कैसे प्रभावित किया है।
यह अधिक समाजवादी और समावेशी भारत बनाने में विपक्षी दलों के दृष्टिकोण पर भी जोर देगा।

नवीनतम समाचार:

अगस्त, 2023 में तमिलनाडु सरकार ने 31,000 स्कूलों में नाश्ता योजना शुरू की।

तमिलनाडु के बारे में:

राज्यपाल: आरएन रवि
मुख्यमंत्री: एमके स्टालीएन
पूंजी: चेन्नई
नृत्य: भरतनाट्यम, करकट्टम
राष्ट्रीय उद्यान: मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान
वन्यजीव अभयारण्य: कलाकाड वन्यजीव अभयारण्य, कारिकिली पक्षी अभयारण्य, वेदांथंगल पक्षी अभयारण्य
टाइगर रिजर्व: अनामलाई टाइगर रिजर्व
बायोस्फीयर रिजर्व: अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने स्टार्टअप मिशन द्वारा LEAP सदस्यता कार्ड पेश किया

केरल के मुख्यमंत्री (सीएम) श्री पिनाराई विजयन ने केरल स्टार्टअप मिशन (KSUM) 'लीप (लॉन्च, एम्पावर, एक्सिलरेट, प्रॉस्पर) कोवर्क्स' का राज्यव्यापी सदस्यता कार्ड लॉन्च किया है और केरल के तिरुवनंतपुरम में टेक्नोपार्क फेज 1 के थेजस्विनी बिल्डिंग में केएसयूएम के नवीनीकृत मुख्यालय का भी उद्घाटन किया है।
यह सदस्यता कार्ड स्टार्टअप को समर्थन देने और नवाचार को बढ़ावा देने की सरकार की पहल का हिस्सा है।
इसके अलावा उन्होंने देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क के पहले चरण का भी उद्घाटन किया

लीप कोवर्क्स के बारे में:

LEAP कोवर्क्स एक अग्रणी सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य उद्योग इनक्यूबेटरों को सह-कार्यशील स्थानों में बदलना है। प्राथमिक लक्ष्य एक सफल स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देते हुए नवाचार और सहयोग के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना है।

बुनियादी ढाँचा और सुविधाएँ:

LEAP कोवर्क्स अत्याधुनिक बुनियादी ढाँचा प्रदान करता है, जिसमें अच्छी तरह से शामिल है-उत्पादक कार्य वातावरण बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए कार्यस्थान, बैठक कक्ष, हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी और आवश्यक सुविधाएं।

केएसयूएम द्वारा ऊष्मायन सहायता:

KSUM स्टार्टअप्स को मेंटरशिप प्रोग्राम, बिजनेस डेवलपमेंट सहायता, फंडिंग के अवसरों तक पहुंच और विशेषज्ञ मार्गदर्शन सहित मूल्यवान इन्क्यूबेशन सहायता सेवाएं प्रदान करना जारी रखता है।

स्टार्टअप्स के लिए अवसर खोलना:

LEAP कोवर्क्स सदस्यता कार्ड के लॉन्च से स्टार्टअप, पेशेवरों, एन्जिल्स और उद्यम पूंजीपतियों को KSUM की प्रीमियम सुविधाओं तक अद्वितीय पहुंच प्रदान करने की उम्मीद है।

सब्सिडीयुक्त पहुंच और फ्लेक्सी वर्कस्टेशन:

सदस्यता कार्ड न केवल प्रीमियम सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करता है बल्कि सभी LEAP केंद्र सुविधाओं तक रियायती पहुंच की सुविधा भी प्रदान करता है।
यह उपयोगकर्ताओं को फ्लेक्सी वर्कस्टेशन बुक करने और केरल भर में KSUM के भागीदार इनक्यूबेशन केंद्रों तक पहुंचने की अनुमति देता है

नवीनतम समाचार:

अगस्त, 2023 में केरल को तिरुवनंतपुरम के शांतिगिरी विद्याभवन में अपना पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्कूल मिला।

KSUM के बारे में:

स्थापित: 2006
मुख्यालय: तिरुवनंतपुरम, केरल, भारत
CEO: अनूप अंबिका

केरल के बारे में:

राज्यपाल: आरिफ मोहम्मद खान
मुख्यमंत्री: पिनाराई विजयन
राजधानी: तिरुवनंतपुरम
राष्ट्रीय उद्यान: पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, मथिकेट्टन राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान

उत्तर प्रदेश सबसे अधिक संख्या के साथ इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकरण में अग्रणी है

उत्तर प्रदेश (यूपी) राज्य में 1,70,269 इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकृत होने के साथ, यह देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की उच्चतम दर के साथ उभरा है।

वाहन पंजीकरण पर नज़र रखने वाले वाहन के आंकड़ों के अनुसार, भारत में पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल संख्या में 4.9% की वृद्धि हुई है।
CY23 के जनवरी और सितंबर के बीच, भारत में कुल 10,24,781 इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत किए गए।

मुख्य विचार:

आंकड़ों के अनुसार, यूपी के बाद, महाराष्ट्र में 1,24,558 और कर्नाटक में 1,00,235 के साथ सबसे अधिक इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हुए।
जबकि मौलिक उपकरण निर्माता (OEM) अपने इलेक्ट्रिक वाहन पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहे हैं, कंपनियां शहर और राष्ट्रीय राजमार्गों पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए विकास और साझेदारी कर रही हैं।
क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2025 तक इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की नई वाहन बिक्री में 10-12% की प्रवेश दर हासिल होने की उम्मीद है।
इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों और इलेक्ट्रिक बसों में भी वित्त वर्ष 2025 तक क्रमश: 14-16 फीसदी और 11-13 फीसदी की पहुंच दर के साथ पर्याप्त वृद्धि होने की उम्मीद है।

असम सरकार ने बहुविवाह विरोधी कानून का मसौदा तैयार करने के लिए 3 सदस्यीय समिति की स्थापना की

असम सरकार ने असम के भीतर बहुविवाह को समाप्त करने के उद्देश्य से एक कानून का मसौदा तैयार करने के लिए 3 सदस्यीय समिति की स्थापना की है।
समिति में प्रमुख व्यक्ति शामिल हैं, जिनमें महाधिवक्ता देवजीत सैकिया, कानूनी सलाहकार कुंतल शर्मा पाठक और पुलिस महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह शामिल हैं।
नवगठित समिति को 45 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर बहुविवाह विरोधी विधेयक का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा गया है।
इससे पहले, असम सरकार ने बहुविवाह विरोधी कानून के अधिनियमन के संबंध में राज्य विधायिका की विधायी क्षमता का आकलन करने के लिए न्यायमूर्ति रूमी फूकन (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में एक और समिति का गठन किया था।
न्यायमूर्ति रूमी फूकन के पैनल ने समान नागरिक संहिता की स्थापना से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के उद्देश्य से मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) अधिनियम, 1937 के प्रावधानों की जांच की और अनुच्छेद 25 पर भी विचार किया।

असम के बारे में:

राज्यपाल: गुलाब चंद कटारिया
मुख्यमंत्री: हिमंत बिस्वा सरमा
राजधानी: गुवाहाटी
राष्ट्रीय उद्यान: काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान
वन्यजीव अभयारण्य: गरमपानी वन्यजीव अभयारण्य, लाओखोवा वन्यजीव अभयारण्य, बोर्नाडी वन्यजीव अभयारण्य

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए 'सबल' योजना की शुरुआत की

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर के नादौन से मुख्यमंत्री खेल क्षमता, पुनर्निर्माण आकांक्षाएं और आजीविका योजना (SABAL) का शुभारंभ किया।
उद्देश्य: हिमाचल प्रदेश में दिव्यांग बच्चों के जीवन को बेहतर बनाना।
कवरेज: इस योजना में हमीरपुर, सोलन और शिमला जिलों के लगभग 400 स्कूल शामिल हैं।

अन्य लॉन्च:

अभ्यास हिमाचल' और 'शिक्षक सहायता' चैटबॉट:
स्विफ्ट चैट ऐप के माध्यम से सुलभ चैटबॉट व्हाट्सएप के समान आसानी प्रदान करते हैं और संवादी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) द्वारा संचालित होते हैं।
ये चैटबॉट छात्रों को अपने मोबाइल फोन से किसी भी स्थान से अपनी सुविधानुसार पाठों को संशोधित करने में सक्षम बनाएंगे।

यह सुविधा एक प्रश्नोत्तरी-आधारित प्रारूप पेश करती है और शैक्षिक वीडियो प्रदान करती है जिसका उपयोग छात्र और शिक्षक दोनों कक्षा में सीखने और सिखाने के अनुभव को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं।

संपर्क विज्ञान टीवी कार्यक्रम:

"संपर्क विज्ञान टीवी कार्यक्रम" सामान्य टीवी को स्मार्ट टीवी में बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

इस नवाचार का उद्देश्य बच्चों के सीखने के अनुभवों को बढ़ाना है, खासकर गणित और अंग्रेजी जैसे विषयों में।

यह उपकरण शैक्षिक सामग्री के साथ पहले से लोड किया हुआ आता है, जिससे इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

'राज्य चयन आयोग' की स्थापना:

उन्होंने उम्मीदवारों के चयन मानदंडों में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अगले 2 महीनों के भीतर हमीरपुर में अब भंग हो चुके हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के स्थान पर 'राज्य चयन आयोग' स्थापित करने की भी घोषणा की।

HPSSC विघटन:

23 दिसंबर, 2022 को पेपर लीक की खोज के बाद, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग (HPSSC) को फरवरी 2023 में भंग कर दिया गया था।

एचपी के बारे में:

राज्यपाल: शिव प्रताप शुक्ला

मुख्यमंत्री: सुखविंदर सिंह सुक्खू

राष्ट्रीय उद्यान: ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, खिरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान

वन्यजीव अभयारण्य: किब्बर वन्यजीव अभयारण्य, चंद्रताल वन्यजीव अभयारण्य (रामसर साइट)

झारखंड कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1000 रुपये की पेंशन और पिछड़ा वर्ग श्रेणी में शामिल करने को मंजूरी दी

मुख्यमंत्री (सीएम) हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मंत्रिमंडल ने राज्य की सार्वभौमिक पेंशन योजना में ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल करने को मंजूरी दे दी है, जिसे "मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना" के नाम से जाना जाता है।

इस योजना के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को 1,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी।

पात्रता मापदंड:

पेंशन योजना के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को उपायुक्त कार्यालय से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

पात्रता मानदंड में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र होना और मतदाता पहचान पत्र होना शामिल है।

OBC श्रेणी में शामिल करना:

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आधिकारिक तौर पर "अन्य पिछड़ा वर्ग" (OBC) की श्रेणी में शामिल किया गया है।

प्रस्ताव में दो प्रमुख पहलू शामिल हैं:

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को "तीसरे लिंग" के रूप में मान्यता।

ऐसे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को OBC श्रेणी में शामिल करना जो किसी अन्य आरक्षण श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं, विशेष रूप से OBC सूची में क्रम संख्या 46 पर।

महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग (WCDSS) के अनुसार, ट्रांसजेंडर 2011 में झारखंड की जनसंख्या लगभग 11,900 थी, जो वर्तमान में लगभग 14,000 होगी।

नवीनतम समाचार:

अगस्त 2023 में, झारखंड के मुख्यमंत्री (सीएम) श्री हेमंत सोरेन ने रांची, झारखंड में मानव-हाथी संघर्ष को कम करने के लिए रांची में 74वें वन महोत्सव के अवसर पर एक मोबाइल एप्लिकेशन-आधारित हाथी आंदोलन ट्रैकिंग प्रणाली, झारखंड हाथी ट्रैकर लॉन्च किया।

झारखंड के बारे में:

राज्यपाल: सीपी राधाकृष्णन
मुख्यमंत्री: हेमन्त सोरेन
पूंजी: रांची
टाइगर रिजर्व: पलामू टाइगर रिजर्व
वन्यजीव अभयारण्य: दलमा वन्यजीव अभयारण्य, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, उधवा झील पक्षी वन्यजीव अभयारण्य

उत्सर्जन व्यापार योजना लागू करने वाला अहमदाबाद भारत का दूसरा शहर बन गया

गुजरात सरकार ने घोषणा की है कि औद्योगिक उत्सर्जन को प्रभावी ढंग से विनियमित करने और गुजरात में प्रदूषण के स्तर को कम करने में योगदान देने के उद्देश्य से कण प्रदूषण के लिए उत्सर्जन व्यापार योजना (ETS) अपनाने वाला अहमदाबाद भारत का दूसरा शहर बन गया है।
ऐसी योजना लागू करने वाला पहला भारतीय शहर सूरत था, जो गुजरात राज्य में स्थित है।
ETS योजना के भीतर लाइव ट्रेडिंग 1 सितंबर, 2023 को शुरू हुई।
इसने योजना के अंतर्गत कार्यरत 118 उद्योगों को शामिल करते हुए व्यापार प्रक्रिया की शुरुआत को चिह्नित किया।
गुजरात के वन और पर्यावरण मंत्री, मुलुभाई बेरा ने अहमदाबाद ETS बाजार के लिए पहली समान नीलामी का उद्घाटन किया, जिसमें सभी भाग लेने वाले उद्योगों को ऑनलाइन प्रदूषण परमिट वितरित किए गए।

ETS के बारे में:

अहमदाबाद में ETS विशेष रूप से पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) उत्सर्जन को लक्षित करता है और यह पीएम उत्सर्जन के लिए समर्पित दुनिया का पहला ETS है।
यह मुख्य रूप से नारोल और वटवा औद्योगिक समूहों के भीतर कपड़ा क्षेत्र के उद्योगों पर केंद्रित है।
ETS, जिसे "कैप-एंड-ट्रेड" प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है, विनियमित उद्योगों से अनुमत प्रदूषण की मात्रा पर एक सीमा निर्धारित करता है और उत्सर्जन के लिए परमिट जारी करता है।

कार्यान्वयन और तकनीकी विशेषज्ञता:

ETS गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लागू किया जाता है और शिकागो विश्वविद्यालय, येल विश्वविद्यालय और वारविक विश्वविद्यालय जैसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों द्वारा प्रदान की गई तकनीकी विशेषज्ञता से लाभान्वित होता है।
अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब (जे-PAL) और एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट शिकागो जैसे संगठन भी इस पहल में योगदान देते हैं।
ETS के लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म NCDEX ई मार्केट्स लिमिटेड (NEML) द्वारा विकसित किया गया है, जो कमोडिटी एक्सचेंज क्षेत्र में एक मान्यता प्राप्त इकाई है।
ETS एक अभिनव बाजार-आधारित प्रणाली है जिसमें पर्यावरणीय गुणवत्ता और विकास के बीच व्यापार-बंद को बदलने, उद्योग के अनुपालन की कम लागत के साथ वायु गुणवत्ता में सुधार करने की क्षमता है।
इसके अलावा, निरंतर उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (CEMS) के उपयोग से उद्योग की निगरानी के लिए नियामकों की जानकारी और क्षमता में काफी सुधार होता है।

गुजरात के बारे में:

राज्यपाल: आचार्य देवव्रत
मुख्यमंत्री: भूपेन्द्रभाई पटेल
राजधानी: गांधीनगर
राष्ट्रीय उद्यान: वंसदा राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, वेलावदर राष्ट्रीय उद्यान
वन्यजीव अभयारण्य: जम्बुघोड़ा वन्यजीव अभयारण्य, बरदा वन्यजीव अभयारण्य, शूलपनेश्वर वन्यजीव अभयारण्य

ओडिशा के 'कोरापुट कालाजीरा चावल' को भौगोलिक संकेत (GI) दर्जा प्राप्त हुआ

ओडिशा का 'कोरापुट कालाजीरा चावल,'अपनी अनूठी सुगंध और पोषण मूल्य के लिए प्रसिद्ध, को आधिकारिक तौर पर भौगोलिक संकेत (GI) का दर्जा दिया गया है।
चावल की यह सुगंधित किस्म, जिसे अक्सर 'चावल का राजकुमार' कहा जाता है, दिखने में धनिये के बीज जैसा दिखता है।
ओडिशा के कोरापुट जिले के पुजारीपुट में जैविक श्री फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड द्वारा जनवरी 2022 में 'कोरापुट कालाजीरा चावल' के जीआई पंजीकरण के लिए आवेदन शुरू किया गया था।
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और ओडिशा सरकार के कृषि और किसान सशक्तिकरण विभाग के सहयोग से, किसान संगठन को 'कोरापुट कालाजीरा चावल' के लिए GI टैग प्राप्त हुआ।

कालाजीरा चावल के बारे में:

चावल की खेती के उद्गम केंद्र, ओडिशा के कोरापुट जिले के किसानों ने पीढ़ियों से कालाजीरा चावल की खेती की है।

कालाजीरा चावल की विशेषताएं:

'कालाजीरा चावल' अपने काले रंग, असाधारण सुगंध, स्वाद और बनावट के लिए जाना जाता है।
चावल उपभोक्ताओं के बीच इसे अत्यधिक माना जाता है।
इस चावल में औषधीय गुण हो सकते हैं, जिनमें याददाश्त बढ़ाना, मधुमेह नियंत्रण, हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाना और चयापचय में सुधार शामिल है।

बढ़ते क्षेत्र:

कालाजीरा चावल प्रमुख रूप से होता हैकोरापुट जिले के अंतर्गत तोला, पात्रापुट, पुजारीपुट, बालीगुडा और मोहुली जैसे क्षेत्रों में उगाया जाता है।
इसके अलावा, नयागढ़ जिले की एक बैंगन प्रजाति 'नयागढ़ कांटेईमुंडी बैंगन' को भी GI टैग प्राप्त हुआ।

GI टैग के बारे में:

GI, एक प्रकार का बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR), मुख्य रूप से एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाला कृषि, प्राकृतिक या निर्मित उत्पाद (हस्तशिल्प और औद्योगिक सामान) है।
GI एक लेबल है जो उन उत्पादों पर लगाया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और जिनमें किसी विशेष स्थान से संबंधित विशेषताएं होती हैं।
यह टैग 10 वर्ष की अवधि के लिए वैध होता है जिसके बाद इसे नवीनीकृत किया जाता है।

ओडिशा के बारे में:

राज्यपाल: गणेशी लाल
मुख्यमंत्री: नवीन पटनायक
पूंजी: भुवनेश्वर
राष्ट्रीय उद्यान: सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान
वन्यजीव अभयारण्य: टिकरपाड़ा वन्यजीव अभयारण्य, चिल्का वन्यजीव अभयारण्य, सुनाबेड़ा वन्यजीव अभयारण्य।

महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने बढ़ते साइबर अपराधों से निपटने के लिए 837 करोड़ रुपये की साइबर सुरक्षा पहल को मंजूरी दी

महाराष्ट्र में साइबर अपराध के बढ़ते मामलों के कारण महाराष्ट्र कैबिनेट ने 837 करोड़ रुपये की साइबर सुरक्षा परियोजना लागू करने का निर्णय लिया है।
इस परियोजना में नागरिकों को समर्पित 24 घंटे का कॉल सेंटर है, जो उन्हें साइबर अपराधों की तुरंत रिपोर्ट करने के लिए एक सुविधाजनक अवसर प्रदान करता है।

मुख्य विचार:

नागरिकों के पास शिकायत दर्ज करने के लिए कई विकल्प हैं, जिनमें एक समर्पित मोबाइल ऐप या एक ऑनलाइन पोर्टल शामिल है, जो इसे अधिक सुलभ और कुशल बनाता है।

कार्यान्वयन के बाद, नागरिकों को फोन कॉल के माध्यम से शिकायत दर्ज करने की अतिरिक्त सुविधा मिलेगी, जिससे पीड़ितों के लिए पहुंच में आसानी सुनिश्चित होगी।
यह परियोजना सभी रिपोर्ट की गई शिकायतों की पूरी तरह से जांच करने के लिए उन्नत साइबर तकनीक के उपयोग पर जोर देती है, जिससे साइबर अपराधियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने की राज्य की क्षमता में वृद्धि होती है।
परियोजना का कार्यान्वयन और निरीक्षण विशेष पुलिस महानिरीक्षक (साइबर) द्वारा किया जाएगा, जो साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक केंद्रित और कुशल दृष्टिकोण सुनिश्चित करेगा।
इस परियोजना में एक कमांड और कंट्रोल सेंटर, प्रौद्योगिकी सहायता प्राप्त जांच क्षमताएं, एक उत्कृष्टता केंद्र, एक क्लाउड-आधारित डेटा सेंटर और एक सुरक्षा संचालन केंद्र जैसे महत्वपूर्ण घटक शामिल हैं, जो सामूहिक रूप से राज्य की साइबर सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाते हैं।
इस पहल का एक केंद्रीय उद्देश्य एक अत्याधुनिक नागरिक-केंद्रित मंच बनाना है जो शिकायतकर्ताओं और प्रौद्योगिकी के बीच समन्वय को सुव्यवस्थित करता है, रिपोर्टिंग और समर्थन प्रक्रिया को बढ़ाता है।
इस परियोजना में पूरे महाराष्ट्र में पुलिस आयुक्त और अधीक्षक कार्यालयों के भीतर स्थित सभी साइबर पुलिस स्टेशनों का एकीकरण शामिल है।

महाराष्ट्र के बारे में:

राज्यपाल: रमेश बैस
मुख्यमंत्री: एकनाथ शिंदे
राजधानी: मुंबई
राष्ट्रीय उद्यान: ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान
वन्यजीव अभयारण्य: भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य, करनाला पक्षी अभयारण्य, नागज़ीरा वन्यजीव अभयारण्य
यूनेस्को विरासत स्थल: छत्रपतिशिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको पहनावा, अजंता गुफाएं, एलीफेंटा गुफाएं, एलोरा गुफाएं

तमिलनाडु के सलेम सागो को भौगोलिक संकेत (GI) टैग प्रदान किया गया

सेलम स्टार्च और सागो मैन्युफैक्चरर्स सर्विस इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, जिसे आमतौर पर सागोसर्व के नाम से जाना जाता है, को सेलम सागो के लिए भौगोलिक संकेत (GI) टैग से सम्मानित किया गया है।
जिला कलेक्टर एस कर्मेगाम ने एक आधिकारिक कार्यक्रम के दौरान सागोसर्व के प्रशासक ललितादित्य नीलम को आधिकारिक तौर पर GI प्रमाण पत्र प्रदान किया।

साबूदाना के बारे में:

तमिलनाडु के सेलम जिले को भारत में कुटीर पैमाने के आधार पर साबूदाना उत्पादन के प्राथमिक केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त है।
साबूदाना टैपिओका जड़ों से निकाले गए गीले स्टार्च पाउडर से प्राप्त होता है।
साबूदाना आमतौर पर छोटे, कठोर ग्लोब्यूल्स या मोती के रूप में पाया जाता है, जिसका रंग मोती-सफेद होता है।
टैपिओका से प्राप्त सूखा पाउडर विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए मौलिक कच्चे माल के रूप में कार्य करता है।
तमिलनाडु के सेलम जिले ने पहले कच्चे रेशम और मालगोआ आम के लिए GI टैग अर्जित किया है, जिससे इस क्षेत्र की अद्वितीय उत्पादों के लिए पहचान बढ़ी है।

जीआई टैग के बारे में:

भौगोलिक संकेत (GI) एक विशिष्ट प्रकार का बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) है जो मुख्य रूप से हस्तशिल्प और औद्योगिक वस्तुओं सहित कृषि, प्राकृतिक या निर्मित मूल के उत्पादों पर लागू होता है। यह एक सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र से उनकी उत्पत्ति का प्रतीक है।
GI टैग उन उत्पादों को दिए जाते हैं जिनमें उनके मूल स्थान से जुड़ी विशिष्ट विशेषताएं या गुण होते हैं।
GI टैग आमतौर पर 10 साल की अवधि के लिए वैध होता है और बाद में इसे नवीनीकृत किया जा सकता है।

नवीनतम समाचार:
अगस्त 2023 में, अपनी अनूठी सुगंध और पोषण मूल्य के लिए प्रसिद्ध ओडिशा के 'कोरापुट कालाजीरा चावल' को आधिकारिक तौर पर भौगोलिक संकेत (GI) का दर्जा दिया गया था।
जुलाई 2023 में, तमिलनाडु के 3 प्रसिद्ध उत्पादों - जडेरी नमककट्टी, कन्याकुमारी मैटी केला, चेदिबुट्टा साड़ी - को जीआई टैग मिला।
सागोसर्वा के बारे में:
स्थापना: 1981
यह एक सहकारी समिति है जिसमें सेलम, नामक्कल, धर्मपुरी, इरोड, पेरम्बलुर, त्रिची, तिरुवन्नामलाई और विल्लुपुरम सहित विभिन्न जिलों के 374 सदस्य हैं।

नागालैंड आधार-लिंक्ड जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य बन गया है

नगालैंड आधार लिंक्ड जन्म पंजीकरण (ALBR) शुरू करने वाला उत्तर पूर्वी क्षेत्र का पहला राज्य बन गया है।
यह अभिनव पहल जन्म पंजीकरण प्रक्रिया के भीतर 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आधार नामांकन को एकीकृत करती है।
उद्देश्य:
बच्चों के कल्याण के लिए विशेष रूप से तैयार की गई विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं तक निर्बाध पहुंच की सुविधा प्रदान करना।
लॉन्च की शुरुआत औपचारिक रूप से कमिश्नर टी म्हाबेमो यानथन के नेतृत्व में की गई।
मुख्य विचार:
नागालैंड के जिलों में इस सेवा की पहुंच बढ़ाने के लिए, आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, नागालैंड, जो राज्य के लिए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करता है, ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के साथ साझेदारी की है।
UIDAI ALBR प्रक्रिया के माध्यम से बच्चों के नामांकन के लिए एक रजिस्ट्रार सह नामांकन एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है।
UIDAI कार्यशालाओं, डोर-टू-डोर नामांकन और दूरदराज के क्षेत्रों में पहुंच के माध्यम से राज्यों को सक्रिय रूप से समर्थन दे रहा है, जिससे उन्हें आधार पारिस्थितिकी तंत्र के लाभों का उपयोग करने में सहायता मिल रही है।
नवीनतम समाचार:
जुलाई 2023 में, नागालैंड को आधिकारिक तौर पर "जानवरों में संक्रामक और संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम, 2009" के अनुसार गांठदार त्वचा रोग (LSD) सकारात्मक राज्य घोषित किया गया था।
नागालैंड के बारे में:
राज्यपाल: श्री ला गणेशन
मुख्यमंत्री: नेफ्यू रियो
राजधानी: कोहिमा

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर, गुजरात में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में आयोजित 26वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की।
मुख्य उपस्थितगण:
बैठक में पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल।
मुख्य विचार:
बैठक के दौरान राज्यों और केंद्र के बीच कुल 17 मुद्दों पर चर्चा हुई, इनमें से 9 मुद्दों का समाधान कर लिया गया, जबकि बाकी को गहन चर्चा के बाद निगरानी के लिए रखा गया।

क्षेत्रीय परिषदें बनाने की अवधारणा 1956 में प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित की गई थी।
इसका उद्देश्य सहकारी कामकाज को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को 4 या 5 क्षेत्रों में पुनर्गठित करने के लिए समूह बनाना है, जिनमें से प्रत्येक में एक सलाहकार परिषद होगी।

5 क्षेत्रीय परिषदें:

राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 15-22 के तहत 1957 में 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी।
प्रत्येक परिषद की एक विशिष्ट संरचना और भौगोलिक कवरेज होती है।
उत्तरी क्षेत्रीय परिषद: इसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़ शामिल हैं।
मध्य क्षेत्रीय परिषद: इसमें छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश शामिल हैं।
पूर्वी क्षेत्रीय परिषद: इसमें बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।
पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद: इसमें गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और दमन एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली शामिल हैं।
दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद: इसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी शामिल हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री 5 क्षेत्रीय परिषदों में से प्रत्येक के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।

पूर्वोत्तर राज्यों का बहिष्कार:

पूर्वोत्तर राज्य (असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड) क्षेत्रीय परिषदों में शामिल नहीं हैं।
उनके विशेष मुद्दों को उत्तर पूर्वी परिषद द्वारा संबोधित किया जाता है, जिसे उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम, 1972 के तहत स्थापित किया गया है।
सिक्किम भी उत्तर पूर्वी परिषद का हिस्सा है।

नवीनतम समाचार:

जुलाई 2023 में भारत का स्वच्छ हाइड्रोजन मिशन गुजरात में हाइड्रोजन वैली प्रोजेक्ट से बढ़ावा मिला।
मई 2023 में, गुजरात कैबिनेट ने स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, गुजरात के 13 जिलों में 21 नए औद्योगिक एस्टेट स्थापित करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी।

गुजरात के बारे में:

राज्यपाल: आचार्य देवव्रत
मुख्यमंत्री: भूपेन्द्रभाई पटेल
पूंजी: गांधीनगर
राष्ट्रीय उद्यान: वंसदा राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, वेलावदर राष्ट्रीय उद्यान
वन्यजीव अभयारण्य: जम्बुघोड़ा वन्यजीव अभयारण्य, बरदा वन्यजीव अभयारण्य, शूलपनेश्वर वन्यजीव अभयारण्य

कौशल विकास मामले में आंध्र के पूर्व सीएम और TDP प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू गिरफ्तार

एन. चंद्रबाबू नायडू, तेलुगू देशम पार्टी (TDP) के प्रमुख और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री (CM) को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
नायडू की गिरफ्तारी उनके सीएम कार्यकाल के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य कौशल विकास निगम में 317 करोड़ रुपये के कथित घोटाले से जुड़ी है।
एपी राज्य कौशल विकास निगम की स्थापना टीडीपी शासन के दौरान युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए की गई थी, जिसने 2014 से 2019 तक आंध्र प्रदेश पर शासन किया था।
नायडू पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करने और भारतीय दंड संहिता की धारा 465 से संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।
साथ ही इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भी लगाया गया है.
आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी हैं, जो YSR कांग्रेस पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष भी हैं।

गिग श्रमिकों के लिए सरकार की नई बीमा योजना 4 लाख रुपये का कवर प्रदान करती है

कर्नाटक गिग श्रमिकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला राजस्थान के बाद दूसरा राज्य है।
राज्य सरकार ने राज्य भर में गिग श्रमिकों के लिए 4 लाख रुपये के कवर के साथ एक बीमा योजना शुरू की।
राज्य इस योजना के लिए पूरे प्रीमियम का भुगतान करेगा जिसके तहत श्रमिकों को 2 लाख रुपये का जीवन बीमा कवर और 2 लाख रुपये का दुर्घटना कवर मिलेगा।
इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने जुलाई में राज्य के बजट में की थी।
सरकार कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) फंडिंग और "राज्य सरकार द्वारा ऐसे किसी भी अनुमोदित तंत्र" के अलावा योजना के लिए नियोक्ताओं और कर्मचारियों से भी धन की मांग कर सकती है।
आदेश में यह भी कहा गया है कि कर्नाटक के पास इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कितने गिग वर्कर काम कर रहे हैं, लेकिन उसने नीति आयोग की रिपोर्ट-2022 पर भरोसा किया है।
रिपोर्ट का अनुमान है कि भारत में 7.7 मिलियन गिग श्रमिक हैं और इस दशक के अंत तक यह लगभग 23.5 मिलियन हो जाएंगे।

ओडिशा ने बैंक रहित ग्राम पंचायतों में बैंकिंग सेवाएं देने के लिए छह बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

ओडिशा सरकार ग्राहक सेवा बिंदु (CSP) प्लस बैंकिंग आउटलेट के माध्यम से राज्य के सभी बैंक रहित ग्राम पंचायतों (जीपी) में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए छह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
ये बैंक थे भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा।
6,798 ग्राम पंचायतों में से 4,373 में ईंट और मोर्टार शाखाएँ नहीं हैं। इसका मतलब है कि लगभग 65 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में ऐसी बैंक शाखाएँ नहीं हैं।
यह योजना चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के भीतर राज्य के बैंक रहित ग्राम पंचायतों को कवर करने के लिए चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी।
राज्य सरकार पांच साल के लिए किराया मुक्त बैंकिंग स्थान प्रदान करेगी।
यह तीन साल की अवधि के लिए निश्चित लागत और आवर्ती खर्चों के लिए एकमुश्त खर्च भी वहन करेगा।
योजना के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है
सभी ग्राम पंचायतों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए इस तरह का मॉडल अपनाने वाला ओडिशा पूरे देश में पहला राज्य है।

असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने 'सरपंच संवाद' मोबाइल ऐप पेश किया

असम के राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया ने असम के गुवाहाटी में राजभवन में 'सरपंच संवाद' मोबाइल ऐप लॉन्च किया।
'सरपंच संवाद' ऐप को क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (QCI) द्वारा विकसित किया गया है।
उद्देश्य: सरपंचों (ग्राम प्रधानों) को व्यापक समर्थन प्रदान करना और नेताओं के रूप में उनके विकास को बढ़ावा देना।
उद्देश्य: पूरे भारत में लगभग 2.5 लाख सरपंचों को जोड़ना और सरपंचों के बीच नेटवर्किंग, ज्ञान प्रसार और सहयोग के लिए एक समग्र मंच के रूप में कार्य करता है।

QCI के बारे में:

स्थापना: 1997
मुख्यालय: नई दिल्ली, दिल्ली, भारत
अध्यक्ष: जक्सय शाह
महासचिव: डॉ.रवि पी. सिंह

भारत सरकार (GoI) और भारतीय उद्योग द्वारा स्थापित QCI, तीसरे पक्ष की राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली की स्थापना और संचालन, सभी क्षेत्रों में गुणवत्ता में सुधार और गुणवत्ता से संबंधित मामलों पर सरकार और अन्य हितधारकों को सलाह देने के लिए जिम्मेदार शीर्ष संगठन है।

घटक बोर्ड: QCI ने विभिन्न घटक बोर्ड स्थापित किए हैं, जिनमें से प्रत्येक विशिष्ट क्षेत्रों में मान्यता के लिए जिम्मेदार है:

NABL (राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड): परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं को मान्यता देता है।

NABH (अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड): अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को मान्यता देता है।

NABCB (प्रमाणन निकायों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड): प्रमाणीकरण और निरीक्षण निकायों को मान्यता देता है

NABET (राष्ट्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड): शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता देता है।

QCI का राष्ट्रीय गुणवत्ता संवर्धन बोर्ड विभिन्न क्षेत्रों में गुणवत्ता के महत्व पर जोर देते हुए राष्ट्रीय गुणवत्ता अभियान चलाने के लिए जिम्मेदार है।

असम के बारे में:

राज्यपाल: गुलाब चंद कटारिया
मुख्यमंत्री: हिमंत बिस्वा सरमा
राजधानी: गुवाहाटी
राष्ट्रीय उद्यान: काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान
वन्यजीव अभयारण्य: गरमपानी वन्यजीव अभयारण्य, लाओखोवा वन्यजीव अभयारण्य, बोर्नाडी वन्यजीव अभयारण्य
नृत्य: बिहू, झुमुर नृत्य, बगुरुम्बा

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कलैगनार महिला अधिकार निधि योजना का अनावरण किया

तमिलनाडु (TN) के मुख्यमंत्री (सीएम) श्री एमके स्टालिन ने 'कलैगनार मगलीर उरीमाई थिट्टम' (कलैगनार महिला अधिकार सहायता योजना) का उद्घाटन किया है, जो तमिलनाडु में महिलाओं को 1,000 रुपये की मासिक सहायता प्रदान करता है।
यह योजना 15 सितंबर, 2023 को सीएन अन्नादुरई की जयंती के अवसर पर शुरू की जाएगी।
लॉन्च की तारीख का चुनाव ऐतिहासिक महत्व रखता है, क्योंकि यह तमिलनाडु के पहले मुख्यमंत्री और प्रमुख द्रविड़ नेता सीएन अन्नादुराई की जयंती है।
अन्नादुराई ने द्रविड़ आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और डीएमके पार्टी की स्थापना की और 1967 से 1969 तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे।
अन्नादुरई की जयंती पर योजना शुरू करना उनकी विरासत और राज्य के राजनीतिक इतिहास में योगदान के लिए एक श्रद्धांजलि है।
वर्ष 2023 सीएन अन्नादुराई की 115वीं जयंती है

कलैगनार महिला अधिकार सहायता के बारे में योजना:

यह पहल तमिलनाडु में महिलाओं की कड़ी मेहनत को स्वीकार करने और समर्थन करने के लिए बनाई गई है।
तमिलनाडु सरकार ने योजना के तहत लाभार्थियों के रूप में लगभग 1.06 करोड़ महिलाओं की पहचान की है।
1,000 रुपये की सहायता प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणाली के माध्यम से लाभार्थियों को वितरित की जाती है।

तमिलनाडु के बारे में:

राज्यपाल: आरएन रवि
मुख्यमंत्री: एमके स्टालिन
राजधानी: चेन्नई
नृत्य: भरतनाट्यम, करकट्टम
राष्ट्रीय उद्यान: मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान

वन्यजीव अभयारण्य: कलाकाड वन्यजीव अभयारण्य, कारिकिली पक्षी अभयारण्य, वेदांथंगल पक्षी अभयारण्य
टाइगर रिजर्व: अनामलाई टाइगर रिजर्व
बायोस्फीयर रिजर्व: अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व

उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष उपहार विलेख योजना शुरू की

उत्तर प्रदेश (यूपी) सरकार ने एक विशेष उपहार विलेख योजना शुरू की है।
योगी आदित्यनाथ सरकार ने सद्भाव को बढ़ावा देने और संपत्ति संबंधी पारिवारिक विवादों को सुलझाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की।
लाभार्थी: 5 अगस्त 2023 से 12 सितंबर 2023 तक इस योजना से 43,574 से अधिक लोगों को लाभ हुआ है।

योजना के बारे में:

वित्तीय प्रभाव: इस योजना के तहत जनता को कुल 1,807.31 करोड़ रुपये का लाभ मिला है
स्टाम्प शुल्क में कटौती: नई योजना रक्त संबंधियों को संपत्ति दान के लिए स्टांप शुल्क को घटाकर 5,000 रुपये की निश्चित राशि कर देती है।
पहले, व्यक्तियों को उपहार विलेख निष्पादित करते समय प्रचलित सर्कल दर के आधार पर स्टांप शुल्क का भुगतान करना पड़ता था।
जून 2023 से दिसंबर 2023 तक लागू की गई इस योजना का 2022 में 2.56 लाख से ज्यादा लोगों ने फायदा उठाया

नवीनतम समाचार:

अगस्त 2023 में, उत्तर प्रदेश (यूपी) सरकार ने राज्य के सभी 74 विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही पैदा करने के उद्देश्य से 'मानव सम्पदा पोर्टल' पेश किया।
अगस्त 2023 में, 5,000 बच्चों तक पहुंचने के लिए, उत्तर प्रदेश (यूपी) सरकार ने सभी 75 जिलों में 'बाल श्रमिक विद्या योजना' का विस्तार करने का निर्णय लिया।

यूपी के बारे में:

राज्यपाल: आनंदीबेन पटेल
मुख्यमंत्री: योगी आदित्यनाथ
राजधानी: लखनऊ
राष्ट्रीय उद्यान: दुधवा राष्ट्रीय उद्यान
वन्यजीव अभयारण्य: बखिरा वन्यजीव अभयारण्य, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गृहिणियों और उद्यमियों को सशक्त बनाने की पहल का खुलासा किया

गोवा की गृहणियों को सशक्त बनाने के लिए गृह आधार योजना शुरू की गई है।
गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत ने कई लाभार्थियों को गृह आधार स्वीकृति आदेश वितरित किए।
यह पहल महिला एवं बाल विकास निदेशालय द्वारा गृहणियों को उनके जीवन स्तर को बढ़ाने और उनकी स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित की गई है।

मुख्य विचार:

उन्होंने गोवा में उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए एक पहल, चावथ ई बाज़ार भी लॉन्च किया।
चावथ ई बाज़ार एक ऑनलाइन पोर्टल है जो स्विगी ऐप के साथ एकीकृत है, जो एक सहज ऑर्डरिंग अनुभव प्रदान करता है।
गृह आधार का गोवा राज्य में काफी प्रभाव पड़ा है, 11,500 नए स्वीकृत ऑर्डर लाभार्थियों को वितरित किए गए हैं।
स्वयंपूर्ण गोवा 2.0 पहल के तहत, महिलाओं को उनकी संबंधित पंचायतों में मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

गोवा के बारे में:

राज्यपाल: पीएस श्रीधरन पिल्लई
मुख्यमंत्री: प्रमोद सावंत
राजधानी: पणजी

हवाई अड्डे: डाबोलिमहवाई अड्डा, मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भूमि खरीद के लिए 'ई-भूमि' पोर्टल लॉन्च किया

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने भूस्वामियों की सहमति से सरकारी परियोजनाओं के लिए भूमि खरीद प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से ई-भूमि पोर्टल लॉन्च किया।
सरकार का लक्ष्य जमीन मालिकों की सहमति से पारदर्शी तरीके से जमीन खरीदना है

ई-भूमि पोर्टल के बारे में:

नए पोर्टल पर जमीन का ऑफर 6 महीने तक वैध रहेगा
किसान स्वतंत्र रूप से या सूचीबद्ध एग्रीगेटर्स के माध्यम से अपनी जमीन की पेशकश कर सकते हैं।
एग्रीगेटर्स द्वारा किए गए स्वैच्छिक प्रस्तावों के लिए न्यूनतम 10 एकड़ की पेशकश अनिवार्य कर दी गई है।

अन्य लॉन्च:

नो-लिटिगेशन पॉलिसी-2023 पोर्टल:
खट्टर ने औद्योगिक मॉडल टाउनशिप (IMT) मानेसर के विस्तार के लिए 2011 से भूमि अधिग्रहण के मुद्दों को हल करने के लिए 'नो-लिटिगेशन पॉलिसी -2023 पोर्टल' का भी उद्घाटन किया।
यह नीति गुरुग्राम जिले की मानेसर तहसील के कसान, कुकरोला और सहरावन गांवों में भूमि संबंधी मुद्दों को संबोधित करती है।
इसका उद्देश्य उन भूस्वामियों को लाभ प्रदान करना है जिनके नाम 16 अगस्त, 2022 को पुरस्कार संख्या 1, 2 और 3 में घोषित पुरस्कारों की तारीख तक इन गांवों की राजस्व संपत्ति में दर्ज हैं।

HMJIS पोर्टल:
उन्होंने हरियाणा में अवैध खनन से निपटने के लिए पहले लॉन्च किए गए ई-रावण पोर्टल की जगह HMJIS पोर्टल लॉन्च किया।

परिवार पहचान पत्र (PPP) के माध्यम से OBC प्रमाणपत्र सेवा:
हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र (PPP) प्रणाली के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) प्रमाण पत्र जारी करने की शुरुआत की।
नागरिक अब सिटीजन सरल पोर्टल के माध्यम से अपने OBC प्रमाणपत्र ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।
PPP के भीतर OBC श्रेणी में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर ओबीसी प्रमाणपत्रों के लिए पात्रता की पुष्टि की जाती है।
कुल 397 योजनाएँ और सेवाएँ PPP से जुड़ी हुई हैं।

'मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना पोर्टल':
उन्होंने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के पोर्टल का भी अनावरण किया, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आवास प्रदान करना है।
इस योजना में पंचकुला, गुरुग्राम, सोनीपत और फरीदाबाद में फ्लैटों का निर्माण शामिल है, जबकि अन्य शहरों में प्लॉट और फ्लैट दोनों विकल्प उपलब्ध होंगे।
यह योजना हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित की जाएगी, जिससे आवास कॉलोनियों में आवश्यक सुविधाओं का प्रावधान सुनिश्चित किया जा सके।

किसानों के लिए मुआवज़ा:
हरियाणा सरकार ने उन किसानों के लिए ₹7,000 प्रति एकड़ मुआवजे की घोषणा की, जिन्हें जुलाई 2023 में भारी बारिश और बाढ़ के कारण धान की दोबारा रोपाई करनी पड़ी।
एक ई-क्षतिपूर्ति द्वारा बारिश, बाढ़ और दंगों जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण संपत्ति, पशुधन या मानव हानि से संबंधित मुद्दों को संभालने के लिए लॉन्च किया गया था।

हरियाणा के बारे में:

राज्यपाल: बंडारू दत्तात्रेय
मुख्यमंत्री: मनोहर लाल खटटर

राजधानी: चंडीगढ़
वन्यजीव अभयारण्य: कालेसर वन्यजीव अभयारण्य, बीर शिकारगाह वन्यजीव अभयारण्य

कुर्मी समाज द्वारा बुलाया गया अनिश्चितकालीन रेल-रोको आंदोलन झारखंड में शुरू हो गया

कुर्मी समाज द्वारा बुलाया गया अनिश्चितकालीन रेल-रोको आंदोलन झारखंड में शुरू हो गया
कुर्मी समुदाय के लोग खुद को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं
कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पश्चिम बंगाल में आंदोलन पर प्रतिबंध लगाने के बाद, कुर्मी समुदाय ने पश्चिम बंगाल में आंदोलन वापस ले लिया।
इसके अलावा झारखंड के गोमो, मुरी और नीमडीह रेलवे स्टेशनों के पास भी आंदोलनकारी बड़ी संख्या में जमा हो गए हैं
टोटेमिक कुर्मी विकास मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शीतल ओहदार ने कहा कि झारखंड में रेल रोको आंदोलन तय कार्यक्रम के अनुसार है
उन्होंने दावा किया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय का आंदोलन प्रतिबंध आदेश झारखंड के लिए नहीं है
फिलहाल आंदोलन के कारण झारखंड में चलने वाली चार ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जिनमें रक्सौल-सिकंदराबाद एक्सप्रेस, भागलपुर-रांची एक्सप्रेस, गोरखपुर-हटिया एक्सप्रेस और कामाख्या-रांची एक्सप्रेस शामिल हैं
इस बीच, दक्षिण पूर्व रेलवे डिवीजन ने हाल ही में जारी अपने प्रेस बयान में तत्काल प्रभाव से सामान्य ट्रेन सेवाओं को बहाल करने की बात कही है।
जो रेलगाड़ियाँ रद्द की गई थीं, मार्ग परिवर्तन किया गया था, शॉर्ट-टर्मिनेट किया गया था, या शॉर्ट-ऑरिजिनेट किया गया था, वे अब अपने निर्धारित समय के अनुसार चलेंगी।
आंदोलन को देखते हुए रांची और धनबाद जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये हैं

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ग्रेटर नोएडा में पहले उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का उद्घाटन करेंगी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में पहले उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन करेंगे।
ट्रेड शो 21 से 25 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा।
उद्घाटन अवसर पर राज्य की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और औद्योगिक मंत्री नंद गोपाल नंदी भी उपस्थित रहेंगे।

मुख्य विचार

मुंबई डब्बावाला के साथ राज्य सरकार के विभाग और संस्थान विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों पर जानकारीपूर्ण सत्र आयोजित करेंगे।
साथ ही शो में 108 नए स्टार्टअप भी हिस्सा लेंगे।
व्यापार शो में अंतरराष्ट्रीय उपस्थित लोगों सहित पांच लाख से अधिक आगंतुकों के शामिल होने की उम्मीद है।
पांच दिवसीय कार्यक्रम ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित किया जाएगा।
उम्मीद है कि यह राज्य के उत्पादों, विशिष्टताओं, व्यंजनों और संस्कृति के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन और बाजार के अवसर प्राप्त करने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा।
अब तक 60 से अधिक देशों के लगभग 400 प्रतिभागियों ने इस आयोजन के लिए पंजीकरण कराया है।
2000 से अधिक प्रदर्शक समारोह सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे।
2000 से अधिक प्रदर्शक ऑटोमोबाइल, हस्तशिल्प, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल, हस्तशिल्प, स्वास्थ्य देखभाल, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मास्यूटिकल्स, डेयरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और ई-कॉमर्स सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। शो में आम जनता के लिए प्रवेश निःशुल्क रहेगा।

जी-20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक मध्य प्रदेश में शुरू

भारत की जी-20 अध्यक्षता के तहत जी-20 इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की दो दिवसीय चौथी बैठक मध्य प्रदेश के खजुराहो में शुरू हुई।
यह भारतीय जी20 प्रेसीडेंसी के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की आखिरी बैठक है।
इसने G20 सदस्य देशों, अतिथि देशों और भारत द्वारा आमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 54 से अधिक प्रतिनिधियों को एक साथ लाया है।
यह मंच पिछली तीन IWG बैठकों के दौरान हुई चर्चाओं को जारी रखते हुए प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श कर रहा है।
बैठक की मेजबानी और अध्यक्षता भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील द्वारा सह-अध्यक्ष के रूप में की जा रही है।
बैठक के विभिन्न सत्रों में शहरी बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को बढ़ावा देने के साथ-साथ वित्तीय संसाधन जुटाने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की गई।

चौथा नदी उत्सव नई दिल्ली में IGNCA में शुरू होगा

चौथा नदी उत्सव नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA) में शुरू होगा।
नदी थीम पर आधारित यह कार्यक्रम इस साल यमुना पर केंद्रित होगा।
तीन दिवसीय कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रदर्शन, एक पुस्तक मेला, एक वृत्तचित्र फिल्म महोत्सव और एक कठपुतली शो सहित कई प्रकार के कार्यक्रम शामिल होंगे।
इसमें नदी संरक्षण की थीम पर आधारित चित्र, सांझी कला और स्कूली बच्चों की पेंटिंग्स की प्रदर्शनी भी प्रदर्शित की जाएगी।
राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के सहायक निदेशक अभय मिश्रा उन्होंने युवाओं और जनता के बीच जल निकायों के संबंध में भारी मतदान और जागरूकता बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की।

असम के बिश्वनाथ घाट को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 चुना गया

बिश्वनाथ घाट पर्यटन मंत्रालय, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा असम को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 के रूप में चुना गया है।
बिश्वनाथ घाट को 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 791 आवेदनों में से चुना गया है।

बिस्वनाथ घाट के बारे में:

बिश्वनाथ घाट ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है और बिश्वनाथ चरियाली टाउन से दक्षिण की ओर स्थित है।
गुप्तों के स्वर्णिम शासन के दौरान काशी की तुलना में घाट को "गुप्त काशी' के नाम से भी जाना जाता है।
इसका नाम प्राचीन बिस्वनाथ मंदिर के नाम पर रखा गया है।
बिश्वनाथ घाट में विभिन्न देवी-देवताओं के मंदिरों का एक समूह है।
भगवान शिव का एक मंदिर ब्रह्मपुत्र के साथ बृहदंगा (बुरीगोंगा) नदी के संगम पर स्थित था।

असम के बारे में:

राज्यपाल: गुलाब चंद कटारिया
मुख्यमंत्री: हिमंत बिस्वा सरमा
राजधानी: दिसपुर
राष्ट्रीय उद्यान: मानस राष्ट्रीय उद्यान, खजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी नेशन पार्क, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान
वन्यजीव अभयारण्य: गरमपानी वन्यजीव अभयारण्य, लाओखोवा वन्यजीव अभयारण्य, बोरनाडी वन्यजीव अभयारण्य, चक्रशिला वन्यजीव अभयारण्य

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एकता के प्रतीक के रूप में ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री (सीएम) शिवराज सिंह चौहान आदि शंकराचार्य को 12 साल के बच्चे के रूप में चित्रित करने वाली 108 फुट ऊंची 'स्टैच्यू ऑफ वननेस' का अनावरण किया।
यह प्रतिमा ओंकारेश्वर में स्थित है।
ओंकारेश्वर खंडवा जिले के मांधाता द्वीप पर स्थित मंदिरों का शहर है।
ओंकारेश्वर में इस प्रतिमा के अनावरण से एक महत्वपूर्ण पर्यटन सर्किट बनने की उम्मीद है, जो इसे उज्जैन, महेश्वर और मांडू सहित क्षेत्र के अन्य धार्मिक शहरों से जोड़ेगा।

आदि शंकराचार्य के बारे में:

पेरियार नदी के तट पर केरल के कलाडी में जन्मे आदि शंकराचार्य का जीवन 788 और 820 ईस्वी के बीच था।
उन्हें अद्वैत वेदांत के समर्थक के रूप में जाना जाता है, जो हिंदू दर्शन का एक स्कूल है जो गैर-द्वैत पर जोर देता है।
आदि शंकराचार्य की बहु-धातु प्रतिमा मांधाता पर्वत पहाड़ी पर स्थित है, जो दक्षिण की ओर नर्मदा नदी की ओर है।
आदि शंकराचार्य बौद्ध धर्म और जैन धर्म सहित प्रचलित दार्शनिक परंपराओं को चुनौती देते हुए अद्वैत वेदांत के समर्थक बन गए
यह क्षेत्र उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के करीब है, जो उत्तर पश्चिम में 110 किमी दूर स्थित है।
बहु-धातु आदि शंकराचार्य की प्रतिमा मांधाता पर्वत पहाड़ी के ऊपर स्थापित है, जो दक्षिण की ओर नर्मदा नदी की ओर है।
यह प्रतिमा 54 फीट के शिखर पर खड़ी है, जो 27 फीट के कमल की पंखुड़ी के आधार पर टिकी हुई है, जो लाल पत्थर से बनी है।
मूर्ति का वजन 100 टन है और इसे 75 फुट ऊंचे मंच पर स्थापित किया गया है।
यह कांस्य से बना है जिसमें 88% तांबा, 4% जस्ता और 8% टिन होता है और इसकी आंतरिक संरचना उच्च गुणवत्ता वाले स्टील से बनी होती है।
प्रतिमा के आधार पर शंकर स्तंभ है, जिसमें लकड़ी के गुंबद और पत्थर के खंभे हैं, जिन पर नक्काशी के साथ आचार्य शंकर से संबंधित 32 कहानियों को दर्शाया गया है।
आसपास का क्षेत्र, जिसे एकात्म धाम के नाम से जाना जाता है, नागर, द्रविड़, उड़िया, मारू-गुर्जरा, होयसला, उत्तर भारतीय-हिमालयी और केरल शैलियों सहित स्थापत्य शैलियों की एक पच्चीकारी प्रदर्शित करता है।
अद्वैत वेदांत के अध्ययन और समझ को बढ़ावा देने के लिए एक आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान का निर्माण किया जा रहा है।

एमपी के बारे में:

राज्यपाल: मंगूभाई सी. पटेल
मुख्यमंत्री: शिवराज सिंह चौहान
पूंजी: भोपाल
राष्ट्रीय उद्यान: सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान
वन्यजीव अभयारण्य: नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य, बोरी वन्यजीव अभयारण्य

मध्य प्रदेश ने 'वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व' को अपना 7वां बाघ अभयारण्य नामित किया है

मध्य प्रदेश (एमपी) सरकार ने "वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व" के निर्माण की घोषणा की है, जो एमपी में 7वां बाघ रिजर्व बन गया है।
मध्य प्रदेश में मौजूदा बाघ अभयारण्य: मध्य प्रदेश पहले से ही अपने 6 मौजूदा बाघ अभयारण्यों, अर्थात् कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, संजय डुबरी और सतपुड़ा के लिए प्रसिद्ध है।
वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के जुड़ने से बाघ संरक्षण के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता और मजबूत होती है।
इस वृद्धि के साथ, भारत में अब देश भर में कुल 54 बाघ अभ्यारण्य हो गए हैं।

वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के बारे में:

वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिलों में स्थित है, जो 2,339 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र को कवर करता है।
इस नए बाघ अभयारण्य में नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य और दुर्गावती वन्यजीव अभयारण्य के क्षेत्र शामिल होंगे।
नए रिजर्व में बाघों की प्राकृतिक आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए, पन्ना टाइगर रिजर्व (PTR) को वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व से जोड़ने के लिए एक हरित गलियारा विकसित किया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड (HPSEB) का एकीकृत उपभोक्ता पोर्टल लॉन्च किया

हिमाचल प्रदेश (एचपी) के मुख्यमंत्री (सीएम) ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड (HPSEBL) का एकीकृत बिजली उपभोक्ता पोर्टल लॉन्च किया।

उद्देश्य:

संगठन के भीतर कागज रहित कार्य संस्कृति की शुरुआत करना, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और सेवाओं में तेजी लाने की उम्मीद है।
यह 31 मार्च, 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य में बदलने का एक हिस्सा है।

पोर्टल की विशेषताएं:

उपभोक्ताओं को अब अपना बिजली बिल जमा करने के लिए लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा और वे इसे ऑनलाइन जमा कर सकेंगे।
इसके अलावा, नए बिजली कनेक्शन चाहने वाले भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इस पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन की प्रगति को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं।
पोर्टल HPSEBL द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं, जैसे नाम में बदलाव और लोड समायोजन आदि को कवर करने के लिए अपनी सेवाओं का विस्तार करता है।
पोर्टल में ऊर्जा उत्पादन डेटा होगा और संबंधित कार्यालयों का दौरा किए बिना स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (IPP) द्वारा ऑनलाइन चालान जमा करने की सेवा प्रदान की जाएगी।

एचपी के बारे में:

राज्यपाल: शिव प्रताप शुक्ला
मुख्यमंत्री: सुखविंदर सिंह सुक्खू
राष्ट्रीय उद्यान: पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान
वन्यजीव अभयारण्य: कालाटोप खजियार अभयारण्य,

अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने 'मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना' की शुरुआत की

अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री (सीएम) पेमा खांडू ने राज्य के श्रम बल के कल्याण के लिए 'मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना' नामक एक नई योजना शुरू करने की घोषणा की है।

मुख्य विचार:

इस योजना के तहत श्रमिकों के परिवारों के लिए मातृत्व लाभ 1,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दिया गया है
योजना के तहत प्राकृतिक मृत्यु पर मुआवजा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है।
दुर्घटना में मौत पर मुआवजा भी 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दिया गया है
यह योजना श्रमिकों के बच्चों के बीच खेल भागीदारी को प्रोत्साहित करती है।
यह राज्य-स्तरीय टूर्नामेंट या प्रतियोगिताओं में उपलब्धियों के लिए नकद प्रोत्साहन प्रदान करता है: स्वर्ण के लिए 15,000 रुपये, रजत के लिए 10,000 रुपये और कांस्य के लिए 8,000 रुपये।

खेल में राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों को योजना के तहत और भी अधिक प्रोत्साहन मिलेगा: स्वर्ण के लिए 30,000 रुपये, रजत के लिए 20,000 रुपये और कांस्य के लिए 15,000 रुपये।

अरुणाचल प्रदेश के बारे में:

राज्यपाल: कैवल्य त्रिविक्रम पर्णाईक
मुख्यमंत्री: पेमा खांडू
पूंजी: ईटानगर
राष्ट्रीय उद्यान: नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान
वन्यजीव अभयारण्य: टाल वैली वन्यजीव अभयारण्य, कमलांग वन्यजीव अभयारण्य

तमिलनाडु चेन्नई के बाहर डिज़्नी जैसा 100 एकड़ का मनोरंजन पार्क बनाने की योजना बना रहा है

तमिलनाडु अपनी नई पर्यटन नीति के अनुसार, निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से चेन्नई के बाहरी इलाके में डिज़्नी और यूनिवर्सल स्टूडियो द्वारा संचालित पार्क की तर्ज पर एक बड़े प्रारूप वाले 100 एकड़ के थीम पार्क को विकसित करने की योजना है।

राज्य सरकार के पर्यटन विभाग ने अपनी पर्यटन नीति जारी की, जिसके तहत उसने 12 प्राथमिकता वाले पर्यटन खंडों की रूपरेखा तैयार की है - साहसिक पर्यटन, मनोरंजन पर्यटन, कारवां पर्यटन, ग्रामीण और वृक्षारोपण पर्यटन, तटीय पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा और कल्याण पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, पर्यावरण पर्यटन, MICE पर्यटन, विरासत पर्यटन और फिल्म पर्यटन।

भारतीय मनोरंजन पार्क क्षेत्र का अनुमान $500 मिलियन है, जो $49 बिलियन के वैश्विक उद्योग का केवल 1% है।

IBEF के अनुसार, केवल 15-20 मनोरंजन पार्क हैं जिनमें प्रति वर्ष 0.5 मिलियन से अधिक लोग आते हैं।

कुछ प्रमुख में इमेजिका एडलैब्स (लोनावाला), किंगडम ऑफ ड्रीम्स (गुड़गांव), वंडरला (बैंगलोर और कोच्चि) शामिल हैं।

यह पर्यटन नीति, जो नीति अधिसूचना की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए या नई नीति की घोषणा होने तक वैध होगी, ने मनोरंजन पर्यटन के तहत रुचि के एक अन्य क्षेत्र के रूप में गोल्फ पर्यटन पर भी प्रकाश डाला है।

इसके अलावा, दक्षिणी राज्य सभी क्षेत्रों - बॉलीवुड, कॉलीवुड, वृत्तचित्र, टीवी प्रोडक्शंस, विदेशी फिल्में और शो और अन्य क्षेत्रीय फिल्मों - में फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने की भी योजना बना रहा है।

"एक फिल्म पर्यटन योजना तमिलनाडु में फिल्म शूटिंग के लिए दिशानिर्देशों और प्रोत्साहनों की रूपरेखा अलग से लॉन्च की जाएगी।"

इसी तरह की फिल्म पर्यटन योजनाओं की घोषणा राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों द्वारा पहले ही की जा चुकी है।

झारखंडवासी करमा पूजा मनाते हैं

कर्म पूजा झारखंड में मनाया जाता था, जो फसल, प्रकृति की पूजा, भाई-बहन के बीच बंधन और करम वृक्ष को श्रद्धांजलि से संबंधित सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है।

त्योहार के दौरान, करमा नर्तक गाते और नृत्य करते हुए करम पेड़ की शाखा ले जाते हैं।

दूध और चावल की बीयर से सजाए गए करम पेड़ की शाखा को उस स्थान के बीच में रखा जाता है जहां समूह नृत्य करता है।

दूसरे दिन करम देव को उखाड़ा जाता हैऔर गांव के सभी घरों में घुमाकर विधि विधान से विसर्जन किया गया।

नवीनतम समाचार:

जुलाई 2023 में, झारखंड के मुख्यमंत्री (सीएम) श्री हेमंत सोरेन ने रांची, झारखंड में मानव-हाथी संघर्ष को कम करने के लिए रांची में 74वें वन महोत्सव के अवसर पर एक मोबाइल एप्लिकेशन-आधारित हाथी आंदोलन ट्रैकिंग प्रणाली, झारखंड हाथी ट्रैकर लॉन्च किया।

झारखंड के बारे में:

राज्यपाल: सीपी राधाकृष्णन
मुख्यमंत्री: हेमन्त सोरेन

पूंजी: रांची
टाइगर रिजर्व: पलामू टाइगर रिजर्व
वन्यजीव अभयारण्य: दलमा वन्यजीव अभयारण्य, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, उधवा झील पक्षी वन्यजीव अभयारण्य

बिहार सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों के बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए नए कार्यक्रम की शुरुआत की

बिहार सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवाओं के लिए 'मुख्यमंत्री अल्पसंख्या उद्यमी योजना' शुरू कर रही है। इस योजना को लागू करने का निर्णय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक के दौरान किया गया।

योजना के बारे में:

योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र बेरोजगार व्यक्तियों को नया उद्योग स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये मिलेंगे।
कुल राशि में से 5 लाख रुपये सब्सिडी के रूप में दिए जाएंगे, जबकि शेष रुपये 5 लाख का ऋण प्रदान किया जाएगा।
ऋण राशि किश्तों में चुकाए जाने की उम्मीद है।
नई योजना मुख्यमंत्री SC/ST/EBC उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना (MMUY) और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना (MYUY) जैसी मौजूदा योजनाओं के समान ही लागू की जाएगी।
बिहार सरकार ने इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (IGIMS, पटना) में मुफ्त चिकित्सा परीक्षण और उपचार की पेशकश करने का भी निर्णय लिया है।
मरीजों को सिर्फ रजिस्ट्रेशन और बेड चार्ज देना होगा।
यातायात प्रबंधन में सुधार के प्रयास में, राज्य सरकार ने 23 शहरों में 28 समर्पित यातायात पुलिस स्टेशनों की स्थापना को मंजूरी दी है।

बिहार के बारे में:

राज्यपाल: राजेंद्र आर्लेकर
मुख्यमंत्री: नीतीश कुमार
पूंजी: पटना
राष्ट्रीय उद्यान: वाल्मिकी राष्ट्रीय उद्यान
वन्यजीव अभयारण्य: वाल्मिकी वन्य प्राणी अभयारण्य, भीमबांध अभयारण्य, पंत वन्य प्राणी अभयारण्य, कंवर झील पक्षी अभयारण्य

मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में जीवन कौशल शिक्षा कार्यक्रम के लिए मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के साथ सहयोग किया है

मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन शिक्षा और कौशल पर ध्यान केंद्रित करने वाले एक गैर-लाभकारी संगठन ने सरकारी स्कूलों में जीवन कौशल शिक्षा कार्यक्रम "प्रोजेक्ट सक्षम" शुरू करने के लिए मध्य प्रदेश (MP) सरकार के साथ सहयोग किया है।
मैजिक बस मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण प्रदान करेगी, जो तब 18,000 सरकारी शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे, जिसमें सीएम राइज स्कूल, मिडिल स्कूल, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS), कन्या शिक्षा परिसर (KSP), मॉडल आवासीय विद्यालय (MRS) छात्रावास और आश्रम सहित 9,000 सरकारी स्कूलों में लगभग दस लाख किशोरों को जीवन कौशल प्रदान किया जाएगा।

मुख्य विचार:

प्रोजेक्ट 'सक्षम' एक जीवन कौशल शिक्षा कार्यक्रम है।
मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य विभाग ने मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है।
यह साझेदारी राज्य के 20 जिलों और 89 ब्लॉकों में किशोरों को जीवन कौशल शिक्षा देने के लिए सरकारी स्कूल के शिक्षकों को सक्षम बनाने के लिए है।
प्रारंभिक चरण में 20 जिले और 53 ब्लॉक शामिल होंगे।

कार्यक्रम दूसरे वर्ष तक 89 आदिवासी ब्लॉकों के सभी स्कूलों को कवर करेगा।
मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के वैश्विक CEO: जयंत रस्तोगी

एमपी के बारे में:

राज्यपाल: मंगूभाई सी. पटेल
मुख्यमंत्री: शिवराज सिंह चौहान
पूंजी: भोपाल
राष्ट्रीय उद्यान: बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान
वन्यजीव अभयारण्य: नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य, बोरी वन्यजीव अभयारण्य कूनो वन्यजीव अभयारण्य
टाइगर रिजर्व: बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व

कांग्रेस नेता राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में ग्रामीण आवास योजना शुरू करेंगे

राहुल गांधी, एक कांग्रेस नेता, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में "मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना (MGANY)" ग्रामीण आवास योजना शुरू करने के लिए तैयार हैं।
लॉन्च इवेंट बिलासपुर जिले के तखतपुर विकास खंड के भीतर परसदा (सकरी) गांव में होगा।
MGANY का प्राथमिक लक्ष्य उन व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो बेघर हैं या जिनके पास ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे घर हैं।
"आवास न्याय सम्मेलन" कार्यक्रम के दौरान, राहुल गांधी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 1,30,000 लाभार्थियों को उनके घरों के निर्माण के लिए 25,000 रुपये की पहली किस्त हस्तांतरित करेंगे।

मुख्य विचार:

आयोजन के हिस्से के रूप में, सरकार मई 2022 में शुरू की गई "मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना" के तहत 500 लाभार्थियों के खातों में 5 करोड़ रुपये भी हस्तांतरित करेगी।
यह योजना छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को आवास निर्माण के लिए 1 लाख रुपये की सहायता प्रदान करती है।
राहुल गांधी और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल बिलासपुर जिले में 524.33 करोड़ रुपये की विकास और निर्माण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे
कार्यक्रम के दौरान, वे 2,594 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे।
MGANY के तहत, छत्तीसगढ़ सरकार उन बेघर परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जो सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना -2011 (SECC-2011) की सर्वेक्षण सूची से बाहर हो गए थे।

छत्तीसगढ़ के बारे में:

राज्यपाल: विश्वभूषण हरिचंदन
मुख्यमंत्री: भुपेश बघेल
राष्ट्रीय उद्यान: इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान
वन्यजीव अभयारण्य: सीतानदी वन्यजीव अभयारण्य, बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य

रैंकिंग और रिपोर्ट

जमीनी स्तर पर क्रिप्टो अपनाने में भारत पहले स्थान पर है

भारत चैनालिसिस के 2023 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स के अनुसार, कठिन नियामक माहौल के बीच भी, जमीनी स्तर पर क्रिप्टो अपनाने में पहले स्थान पर है।
केंद्रीकृत सेवा मूल्य प्राप्त, खुदरा सहित चार मापदंडों में देश पहले स्थान पर रहाकेंद्रीकृतसेवा मूल्य प्राप्त हुआ, DeFi मूल्य प्राप्त हुआ और खुदरा DeFi मूल्य प्राप्त हुआ।
2022 में, रिपोर्ट के आधार पर भारत चौथे स्थान पर रहा।

रिपोर्ट यह मापने के लिए ऑन-चेन डेटा और वास्तविक दुनिया डेटा को जोड़ती है कि कौन से देश जमीनी स्तर पर क्रिप्टो अपनाने में दुनिया में अग्रणी हैं।
जमीनी स्तर पर क्रिप्टो को अपनाना इस बारे में नहीं है कि किन देशों में कच्चे लेनदेन की मात्रा सबसे अधिक है, इसके बजाय, यह वे देश हैं जहां औसत, रोजमर्रा के लोग क्रिप्टो को सबसे अधिक अपना रहे हैं।
सूचकांक में नाइजीरिया दूसरे स्थान पर है, इसके बाद वियतनाम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूक्रेन हैं।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कम आय वाले देशों में FTX के पतन के कारण 2022 के अंत में गिरावट के बाद क्रिप्टो अपनाने में नाटकीय वृद्धि देखी गई।
लाभ पर 30% कर के साथ, भारत ने क्रिप्टो ट्रेडों पर 1% टीडीएस भी पेश किया है, इस प्रकार व्यापार की मात्रा को नुकसान पहुंचा रहा है।
हालांकि, भारत हाल ही में देश द्वारा आयोजित जी 20 शिखर सम्मेलन में दुनिया भर में क्रिप्टो कानून की वकालत कर रहा है।

फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2023 में मुकेश अंबानी, गौतम अडानी शीर्ष पर हैं

मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) के संस्थापक, 99.7 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट में शीर्ष पर हैं।
गौतम अडानी, अडानी ग्रुप के चेयरमैन 63.71 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ सूची में दूसरे स्थान पर हैं।
शापूरजी पालोनजी ग्रुप का मिस्त्री परिवार 34.6 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ तीसरे स्थान पर है।
सीरम इंस्टीट्यूट का मालिक पूनावाला परिवार 32.9 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ चौथे स्थान पर है।
राधाकिशन दमानी स्टॉकब्रोकर और डी-मार्ट-ब्रांडेड किराना स्टोर के संस्थापक, 23.4 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ 5वें स्थान पर हैं।
शिव नादर परिवार, अजीम प्रेमजी, गोदरेज, बजाज और कुमार मंगलम बिड़ला सहित इंडिया इंक के दिग्गजों ने शीर्ष 10 अमीरों की सूची में जगह बनाई है।

धन आकलन पद्धति:

पत्रिका बताता है कि भारतीय अरबपतियों की संपत्ति का अनुमान 14 जुलाई, 2023 तक स्टॉक की कीमतों और दिसंबर 2022 तक शेयरधारिता पर आधारित है।
14 जुलाई, 2023 तक रुपया-डॉलर विनिमय दर 82.17 रुपये प्रति डॉलर मानी गई है।
फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध दोनों कंपनियों के उद्यमियों को उनकी संपत्ति के आधार पर रैंक करती है।

सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2023: स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान पर बरकरार, भारत एक स्थान चढ़कर 30वें स्थान पर

स्विट्जरलैंड नवीनतम यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की वार्षिक सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग के अनुसार, डी ने एक बार फिर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब अपने नाम किया है।
यह स्विट्जरलैंड के लगातार दूसरे वर्ष शिखर पर रहने और कुल मिलाकर छठी बार सूची में नंबर 1 देश बनने का प्रतीक है।
हाल ही में जारी की गई रैंकिंग स्विट्जरलैंड की सर्वोच्चता की पुष्टि करती है, जिसका बारीकी से अनुसरण किया जाता है
कनाडा नंबर 2 पर,
स्वीडन तीसरे नंबर पर,
ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पर,
और संयुक्त राज्य अमेरिका 5वें स्थान पर है।
यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के सर्वश्रेष्ठ देश 2023 के 8वें संस्करण के अनुसार, भारत 30वें स्थान पर था।

मुख्य विचार

संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी 2022 रैंकिंग की तुलना में एक स्थान नीचे खिसक गया है।
2023 रैंकिंग में, यूरोपीय देश शीर्ष 25 में से 16 स्थान हासिल करके शीर्ष स्तर पर हावी हैं।

उल्लेखनीय बदलावों में जर्मनी शामिल है, जो 2022 के बाद से पांच स्थान नीचे गिर गया है, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, दोनों साल दर साल तीन स्थान ऊपर चढ़ रहे हैं।
मध्य पूर्व का प्रतिनिधित्व संयुक्त अरब अमीरात द्वारा किया जाता है, जबकि एशिया में शीर्ष 25 में जापान, सिंगापुर, चीन और दक्षिण कोरिया शामिल हैं।
रैंकिंग वैश्विक विपणन संचार कंपनी WPP और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के व्हार्टन स्कूल के सहयोग से विकसित की गई है।
विशेष रूप से, साइप्रस, होंडुरास और ज़िम्बाब्वे ने रैंकिंग में अपनी शुरुआत की है, जबकि अल साल्वाडोर 2022 में अनुपस्थित रहने के बाद सूची में फिर से शामिल हो गया है।
'मूवर्स' श्रेणी, जिसमें राष्ट्रों को भविष्य के विकास की उनकी क्षमता के आधार पर रखा जाता है, जिसमें यह भी शामिल है कि वे वैश्विक अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पन्न कठिनाइयों को संभालने के लिए कितनी अच्छी तरह तैयार हैं, भारत ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। संयुक्त अरब अमीरात, कतर, मिस्र और सऊदी अरब के बाद, भारत सूची में पांचवें स्थान पर था। संस्कृति और विरासत के मामले में भारत को आठवां दर्जा दिया गया। भारत दुनिया का 12वाँ सबसे शक्तिशाली देश है।

TIME की 2023 की शीर्ष 100 विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में इंफोसिस एकमात्र भारतीय कंपनी है

आईटी प्रमुख इंफोसिस टाइम मैगजीन और ऑनलाइन डेटा प्लेटफॉर्म स्टेटिस्टा द्वारा जारी 2023 की विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की शीर्ष 100 सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी है।
माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और अल्फाबेट (गूगल मालिक) सूची में शीर्ष 3 पर हैं, जबकि भारत की इंफोसिस 100 में से 88.38 के कुल स्कोर के साथ 64 वें स्थान पर है।
स्थिरता के मामले में इंफोसिस 135वें स्थान पर है जबकि कर्मचारियों की संतुष्टि के मामले में कंपनी की रैंक 103वीं है।

मुख्य विचार

टाइम मैगजीन के मुताबिक कंपनी की ग्रोथ रेट ऊंची रही है।
इन्फोसिस दुनिया की शीर्ष 3 पेशेवर सेवा कंपनियों में से एक थी।
माइक्रोसॉफ्ट, ऐप्पल, अल्फाबेट (कंपनी जो Google का मालिक है) और मेटा प्लेटफॉर्म्स (पूर्व में फेसबुक) स्टेटिस्टा और टाइम द्वारा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में से 750 की एक नई सांख्यिकीय रैंकिंग में शीर्ष चार कंपनियां थीं, जो राजस्व वृद्धि, कर्मचारी संतुष्टि सर्वेक्षण और कठोर पर्यावरण, सामाजिक और कॉर्पोरेट प्रशासन (ESG, या स्थिरता) डेटा के सूत्र पर आधारित हैं।
750 कंपनियों की सूची में इंफोसिस के अलावा 7 कंपनियां भी सूचीबद्ध थीं। सूची में बिग टेक प्रमुख विप्रो 174वें स्थान पर था जबकि आनंद महिंद्रा के नेतृत्व वाला महिंद्रा समूह 210वें स्थान पर था।
रिलायंस इंडस्ट्रीज 248वें रैंक पर, HCL टेक्नोलॉजीज 262वें रैंक पर, HDFC बैंक 418वें रैंक पर, WNS ग्लोबल सर्विसेज 596वें रैंक पर और अंत में ITC 672वें रैंक पर रही।
वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सबसे हालिया वित्तीय वर्ष में 72 बिलियन डॉलर कमाए, जो 2020 से 63% की वृद्धि है, जबकि कुल उत्सर्जन में 0.5% की कमी आई है।
टाइम न्यूयॉर्क शहर में स्थित एक अमेरिकी समाचार पत्रिका है।

इंफोसिस के बारे में:

स्थापना: 2 जुलाई 1981
मुख्यालय: बैंगलोर, कर्नाटक, भारत
MD और CEO: सलिल पारेख
इंफोसिस लिमिटेड एक भारतीय बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है जो व्यवसाय परामर्श, सूचना प्रौद्योगिकी और आउटसोर्सिंग सेवाएं प्रदान करती है।

नवीनतम समाचार

मई 2023 में, आईटी प्रमुख इंफोसिस लिमिटेड ने जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के लिए 'इन्फोसिस टोपाज' नामक एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया।

Click Here to Subscribe Our Yearly Mock Test Package

समझौता और समझौता ज्ञापन

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार पैदा करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर रक्षा मंत्रालय के पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के तहत महानिदेशालय पुनर्वास (DGR) और नई दिल्ली में मेसर्स जेनपैक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच हस्ताक्षर किए गए।
DGR और कॉर्पोरेट्स के बीच समझौता ज्ञापन का उद्देश्य रक्षा सेवाओं के सम्मानित पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कॉर्पोरेट कंपनियों और पूर्व सैनिकों को एक मंच पर लाना है।
जेनपैक्ट, पेशेवर सेवाओं में एक वैश्विक नेता, दिग्गजों के लिए सार्थक कैरियर के अवसर प्रदान करेगा।
"यह साझेदारी हमारे पूर्व सैनिकों को उद्योग में अधिक दृश्यता प्रदान करेगीनिगमऔर कुशल जनशक्ति प्रदान करने और हमारे पूर्व सैनिकों को एक सम्मानजनक दूसरा करियर देने के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करें।

नवीनतम समाचार

जून 2023 में, नई दिल्ली में पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, रक्षा मंत्रालय के तहत महानिदेशालय पुनर्वास (DGR) और मेसर्स कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (NSKFDC) ने वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे एक महत्वपूर्ण सहयोग मजबूत हुआ है।
इस रणनीतिक साझेदारी का उद्देश्य सफाई कर्मचारियों, मैला ढोने वालों, कचरा बीनने वालों और उनके सामाजिक-आर्थिक उत्थान को बढ़ाना है।
NSKFDC सफाई कर्मचारियों, शहरी स्थानीय निकायों को कम ब्याज दरों पर सॉफ्ट लोन प्रदान करके सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई कार्यों के पूर्ण मशीनीकरण पर केंद्रित है।
पूंजीगत सब्सिडी 50 से 32 तक%स्वच्छता उद्यमी योजना (SUY) के तहत मशीनीकृत सफाई कार्य करने वाले सफाई कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है।
स्वच्छता कर्मियों को सुरक्षा सावधानियों, पीपीई किटों के उपयोग और सफाई मशीनों के संचालन और रखरखाव के संबंध में पर्याप्त प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदान किया जाता है।

मुख्य विचार

NSKFDC अपनी महिला समृद्धि योजना और माइक्रो क्रेडिट फाइनेंस योजना के तहत 1.00 लाख रुपये तक का ऋण भी प्रदान करता है।
कुल ब्याज दर क्रमशः 4% और 5% है।
अन्य ऋण योजनाएं सामान्य सावधि ऋण और हरित व्यवसाय योजनाएं हैं जिनके तहत क्रमशः 15.00 लाख रुपये और 30.00 लाख रुपये तक के ऋण पर 6% की ब्याज दर और महिला लाभार्थियों के लिए 1% की छूट प्रदान की जाती है।
वित्त वर्ष 2022-23 में, NSKFDC ने 43862 लाभार्थियों को कवर करते हुए कुल 261.49 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया है।
लगभग 80% लाभार्थी महिलाएं हैं।
NSKFDC ने वित्त वर्ष 2023-24 में 52634 नए लाभार्थियों को कवर करने का लक्ष्य रखा है और वित्त वर्ष 2024-25 में 63161 नए लाभार्थी।
NSKFDC ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान SRMS और पीएम दक्ष योजना के तहत 20686 स्वच्छता कर्मचारियों और उनके आश्रितों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया है।

सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए भारत सरकार की पहल को मजबूत करने के लिए, MoU के अनुसार NSKFDC पीएम दक्ष योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 में क्रमशः 11000 और 12500 लाभार्थियों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

भारत और केन्या हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने और उग्रवाद विरोधी संयुक्त प्रशिक्षण पर सहमत हुए

भारत और केन्या हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा में सहयोग को और गहरा करने पर सहमत हुए।
नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केन्या के कैबिनेट रक्षा सचिव अदन बेयर डुएले के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई।
भारत और केन्या हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी संयुक्त प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए।
वे रक्षा उद्योग और उपकरणों में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमत हुए।

मुख्य विचार

क्षमता निर्माण के क्षेत्र में और जहाज डिजाइन और निर्माण में सहयोग के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और केन्या शिपयार्ड लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए।
श्रीराजनाथ सिंह ने केन्याई बलों के लिए ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित 15 जोड़ी पैराशूट प्रस्तुत किए।
भारत केन्या में एक उन्नत सीटी स्कैन सुविधा की स्थापना का भी समर्थन करेगा।
केन्या के रक्षा मामलों के कैबिनेट सचिव भारत की तीन दिवसीय यात्रा पर हैं।
वह गोवा और बेंगलुरु, कर्नाटक में भारतीय शिपयार्ड और रक्षा उद्योगों का भी दौरा करेंगे।

केन्या के बारे में:

राजधानी: नैरोबी
मुद्रा: केन्याई शिलिंग

MSME निर्यातकों के लिए डिजिटल असिस्टेंट अपनाने के लिए अमेज़न ने इंडिया पोस्ट के साथ साझेदारी की

अमेज़न ने MSME निर्यातकों के लिए सीमा पार लॉजिस्टिक्स को सरल बनाने के लिए इंडिया पोस्ट के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने ई-कॉमर्स कंपनी के संभव शिखर सम्मेलन 2023 में इंडिया पोस्ट और अमेज़ॅन के बीच साझेदारी के एक दशक के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट का अनावरण किया।
अमेज़ॅन के ई-कॉमर्स SMBHAV शिखर सम्मेलन 2023 में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इंडिया पोस्ट और अमेज़ॅन के बीच एक दशक लंबी साझेदारी की स्मृति में एक पोस्ट स्टांप का अनावरण किया।
अमेज़ॅन ने साह-एआई पेश किया, जो एक जनरेटिव एआई-आधारित व्यक्तिगत डिजिटल सहायक है जो अपने बाज़ार में नए और मौजूदा विक्रेताओं को व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने के लिए भारत और विश्व स्तर पर लाखों विक्रेताओं के साथ काम करने के अमेज़ॅन के अनुभव का लाभ उठाता है।
अमेज़ॅन ने भारतीय रेलवे के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (DFC) के साथ अपनी भागीदारी की भी घोषणा की, जो अमेज़ॅन को भारत में माल रेलवे मार्गों के माध्यम से ग्राहक पैकेजों की शिपिंग के लिए डीएफसी का लाभ उठाने वाली देश की पहली ई-कॉमर्स कंपनी बनाती है।
अमेज़न ने 10 मिलियन MSME को डिजिटल बनाने, संचयी ई-कॉमर्स निर्यात में 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर उत्पन्न करने और 2025 तक भारत में 2 मिलियन नौकरियां पैदा करने का वादा किया है।

नवीनतम समाचार

मई 2023 में, अमेज़ॅन वेब सर्विसेज (AWS) ने 2030 तक भारत में क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में 12.7 बिलियन डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है।

अप्रैल 2023 में, टाटा पावर कंपनी भारत के सबसे 'आकर्षक नियोक्ता ब्रांड' के रूप में उभरी है, इसके बाद अमेज़ॅन और टाटा स्टील हैं, रैंडस्टैड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च (REBR) 2023 के निष्कर्षों का खुलासा करता है
जून 2023 में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR), नई दिल्ली ने इष्टतम उपज और आय के लिए विभिन्न फसलों की वैज्ञानिक खेती पर किसानों का मार्गदर्शन करने के लिए दोनों संगठनों की ताकत को संयोजित करने और तालमेल बनाने के लिए अमेज़ॅन किसान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
इंडिया पोस्ट ने मई 2023 में लॉजिस्टिक सेवा के लिए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) और तृप्ता टेक्नोलॉजीज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

इंडिया पोस्ट के बारे में:

स्थापना: 1 अक्टूबर 1854
मुख्यालय: नई दिल्ली, दिल्ली, भारत
इंडिया पोस्ट भारत में सरकार द्वारा संचालित डाक प्रणाली है, जो संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग का हिस्सा है।

NTPC और OIL नवीकरणीय ऊर्जा और डीकार्बोनाइजेशन में सहयोग के लिए एक साथ आए हैं

NTPC लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड ने नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव और भू-तापीय ऊर्जा के उपयोग सहित डीकार्बोनाइजेशन पहल के क्षेत्रों में सहयोग का पता लगाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
MoU कार्बन पृथक्करण जैसी आगामी डीकार्बोनाइजेशन प्रौद्योगिकियों पर ज्ञान और अनुभव साझा करने की सुविधा भी प्रदान करेगा।
MoU के माध्यम से, दो महारत्न दिग्गज अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अपने पदचिह्न को बढ़ाने और वर्ष 2070 तक देश के नेट ज़ीरो प्राप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में स्थायी समाधान में प्रवेश करने का इरादा रखते हैं।

मुख्य विचार:

NTPC के CMD श्री गुरदीप सिंह की उपस्थिति में नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए; CMD, OIL, डॉ. रंजीत रथ; और उनके कार्यात्मक निदेशक।
NTPC 73,024 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता के साथ बिजली क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला में मौजूद है।
ऑयल इंडिया लिमिटेड एक सरकारी स्वामित्व वाली तेल कंपनी है जो कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज, विकास और उत्पादन के व्यवसाय में लगी हुई है।
NTPC वर्ष 2032 तक 60 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।
इसका लक्ष्य ग्रीन हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी और ऊर्जा भंडारण क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी बनना है।
कंपनी डीकार्बोनाइजेशन की दिशा में हाइड्रोजन मिश्रण, कार्बन कैप्चर और ईंधन जैसी कई पहल कर रही हैसेल बसेंदूसरों के बीच में।

नवीनतम समाचार

जुलाई 2023 में, भारत की अग्रणी एकीकृत बिजली उत्पादक NTPC लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2023 - 2024 की पहली तिमाही के दौरान अपनी कैप्टिव खानों से कोयला उत्पादन को पिछले वर्ष की पहली तिमाही के दौरान उत्पादन की तुलना में लगभग दोगुना कर दिया।
जून 2023 में, NTPC को "लर्निंग और अपस्किलिंग में AI/AR/VR का सर्वोत्तम उपयोग" और "एक्सटेंडेड एंटरप्राइज लर्निंग प्रोग्राम बनाने में सर्वश्रेष्ठ एडवांस" के लिए प्रतिष्ठित इकोनॉमिक टाइम्स (ET) HR वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स अवार्ड्स 2023 प्राप्त हुआ।

NTPC के बारे में

स्थापना: 7 नवंबर 1975
मुख्यालय: नई दिल्ली, भारत
गुरदीप सिंह NTPC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं

NCDEX, महाराष्ट्र हल्दी उत्पादकों को विकल्प व्यापार में भाग लेने के लिए सब्सिडी देने में मदद करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा

NCDEX भारत के प्रमुख भविष्य एक्सचेंजों में से एक, हल्दी उत्पादकों को विकल्प ट्रेडिंग में भाग लेने के लिए सब्सिडी देने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करेगा।
किसान विशेष रूप से किसान उत्पादक संगठनों (FPO) के माध्यम से "पुट" विकल्प व्यापार में भाग लेंगे।
NCDEX ने बाजार नियामक सेबी से FPO को एक्सचेंज में विकल्प डालने में भाग लेने में मदद करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की।

NCDEX के बारे में

नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड भारत में स्थित एक भारतीय ऑनलाइन कमोडिटी और डेरिवेटिव एक्सचेंज है।
यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के स्वामित्व में है।
MD एवं CEO: अरुण रस्ते

महाराष्ट्र के बारे में

राज्यपाल: रमेश बैस
मुख्यमंत्री: एकनाथ शिंदे
राजधानी: मुंबई
राष्ट्रीय उद्यान: ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान
वन्यजीव अभयारण्य: भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य, करनाला पक्षी अभयारण्य, नागज़ीरा वन्यजीव अभयारण्य
यूनेस्को विरासत स्थल: छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको पहनावा, अजंता गुफाएं, एलीफेंटा गुफाएं, एलोरा गुफाएं

नवीनतम समाचार

जून 2023 में, महाराष्ट्र राज्य में पंप स्टोरेज योजनाओं और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत परियोजनाओं के विकास के लिए NHPC लिमिटेड और महाराष्ट्र सरकार के ऊर्जा विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

IREDA ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के सह-वित्तपोषण के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (IREDA) ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (UBI) और बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
ये समझौते इरेडा को स्थापित और उभरती दोनों आरई प्रौद्योगिकियों सहित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए सह-उधार और ऋण सिंडिकेशन में यूबीआई और बीओबी के साथ सहयोग करने के लिए सशक्त बनाएंगे।

सहभागी

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर औपचारिक रूप से महाप्रबंधक (तकनीकी सेवाएं), IREDA, श्री भरत सिंह राजपूत और महाप्रबंधक (बड़े कॉर्पोरेट वर्टिकल), यूबीआई, श्री धीरेंद्र जैन द्वारा हस्ताक्षर किए गए।
हस्ताक्षर समारोह में IREDA के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री प्रदीप कुमार दास, UBI की प्रबंध निदेशक और सीईओ सुश्री ए. मणिमेखलाई और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ समझौता ज्ञापन महाप्रबंधक (तकनीकी सेवाएं), IREDA, श्री भरत सिंह राजपूत और महाप्रबंधक, BOB, श्री धीरेन लालई द्वारा निष्पादित किया गया।
हस्ताक्षर समारोह में कार्यकारी निदेशक श्री ललित त्यागी के साथ IREDA के CMD और BoB के MD और CEO, श्री देबदत्त चंद की उपस्थिति देखी गई। इस अवसर पर BOB के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, हेड-लार्ज कॉरपोरेट रिलेशनशिप, श्री सुमित सचदेवा और हेड-क्रेडिट, श्री मनोज चयानी भी उपस्थित थे।

मुख्य विचार

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों की शाखाओं के विशाल नेटवर्क के साथ देश भर में व्यापक उपस्थिति है।
इस सहयोग का उद्देश्य विशेष रूप से टियर-2 और टियर-3 शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी पहुंच का विस्तार करना है, जिससे हम मौजूदा और नए ग्राहकों को अद्वितीय और अभिनव वित्तीय सहायता प्रदान कर सकें।
हाल के वर्षों में, IREDA नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए अपनी तकनीकी-वित्तीय विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए विभिन्न केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के साथ-साथ वित्तीय संस्थानों के साथ साझेदारी को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित कर रहा है।

इरेडा के बारे में:

मुख्यालय: नई दिल्ली, दिल्ली
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक: प्रदीप कुमार दास
IREDA एक सार्वजनिक लिमिटेड सरकारी कंपनी और एक गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान है, जिसका गठन ऊर्जा के नए और नवीकरणीय स्रोतों और ऊर्जा दक्षता/संरक्षण से संबंधित परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए किया गया है, जिसका आदर्श वाक्य है: "हमेशा के लिए ऊर्जा"।
यह भारत सरकार का एक मिनी रत्न (श्रेणी - I) उद्यम है जिसका उद्देश्य वित्तीय सहायता को बढ़ावा देना, विकास करना और विस्तार करना है और यह नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

BOB के बारे में:

स्थापना: 20 जुलाई 1908
मुख्यालय: वडोदरा, गुजरात, भारत
MD और CEO: देबदत्त चंद
टैगलाइन: इंडियाज इंटरनेशनल बैंक
बैंक ऑफ बड़ौदा पूरे भारत में 11,000 से अधिक ATM संचालित करता है

UBI के बारे में:

स्थापना: 11 नवंबर 1919
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र, भारत
MD और CEO: ए मणिमेखलाई
टैगलाइन: गुड पीपल टू बैंक विथ

नवीनतम समाचार

मई 2023 में, सरकार ने भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (IREDA) के आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (IPO) के प्रबंधन के लिए IDBI कैपिटल, BOB कैपिटल और SBI कैपिटल को नियुक्त किया है।
जुलाई 2023 में, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (IREDA) ने नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में अपनी 36वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) आयोजित की।

नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए IREDA और IIFCL ने मिलकर काम किया

भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (IREDA) ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (IIFCL) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
यह समझौता ज्ञापन IREDA और IIFCL को लघु जलविद्युत परियोजनाओं सहित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की सभी श्रेणियों के लिए सह-ऋण/सह-उत्पत्ति और ऋण सिंडिकेशन में संलग्न होने के लिए सशक्त बनाएगा।
दोनों संगठन तीन से चार साल की अवधि के लिए IREDA उधार के लिए ब्याज दरें भी तय करने का प्रयास करेंगे।
इसके अलावा, IIFCL इश्यू के नियमों और शर्तों के अनुसार, IREDA द्वारा जारी बांड में निवेश कर सकता है।

MoU पर IREDA के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री प्रदीप कुमार दास और IIFCL के प्रबंध निदेशक, श्री पीआर जयशंकर ने हस्ताक्षर किए।
आरई क्षेत्र में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए IREDA ने दो साल पहले एक विशेष व्यवसाय विकास और परामर्श प्रभाग की स्थापना की।
अतीत में, IREDA ने अन्य केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
यह समझौता ज्ञापन IREDA की हरित वित्तपोषण विशेषज्ञता और IIFCL की इंफ्रा वित्तपोषण विशेषज्ञता के तालमेल को सक्षम करेगा।

इरेडा के बारे में:

भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (IREDA) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) के तहत एक पीएसयू है और इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (IIFCL) व्यवहार्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 2006 में स्थापित भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है।

संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के सहयोग से पर्यटन मंत्रालय ने G20 पर्यटन और SDG डैशबोर्ड का अनावरण किया

पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (UNWTO) के सहयोग से जी20 पर्यटन और SDG डैशबोर्ड का अनावरण किया।
पर्यटन, संस्कृति और डोनर मंत्री, श्री जी. किशन रेड्डी ने एक आभासी समारोह में डैशबोर्ड लॉन्च किया।
भारत की जी20 प्रेसीडेंसी के नेतृत्व में और UNWTO की विशेषज्ञ ज्ञान साझेदारी के साथ विकसित, डैशबोर्ड टिकाऊ पर्यटन के लिए भारत की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है।
यह G20 देशों की सर्वोत्तम प्रथाओं, केस अध्ययनों और अंतर्दृष्टि को प्रदर्शित करता है, जो सभी सतत विकास लक्ष्यों (SDG) को प्राप्त करने के लिए तैयार किए गए हैं।
यह डैशबोर्ड भारत की जी20 प्रेसीडेंसी की एक स्थायी विरासत है, जो वैश्विक पर्यटन उद्योग में वैश्विक सहयोग और सतत विकास के प्रति इसके समर्पण को दर्शाता है।

मुख्य विचार:

G20 पर्यटन और SDG डैशबोर्ड एक व्यापक ऑनलाइन सार्वजनिक मंच के रूप में कार्य करता है, जो G20 पर्यटन कार्य समूह के सामूहिक ज्ञान को समाहित करता है।
यह GOA रोडमैप, सर्वेक्षण परिणाम, केस अध्ययन और G20 देशों की सर्वोत्तम प्रथाओं को समेकित करता है।
डैशबोर्ड स्थायी पर्यटन प्रथाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और ज्ञान के आदान-प्रदान, सहयोग और विकास के लिए एक मंच भी प्रदान करता है।
वर्चुअल लॉन्च में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और उद्योग हितधारकों की भागीदारी देखी गई।

UNWTO के बारे में

स्थापित: 1946
मुख्यालय: मैड्रिड, स्पेन
प्रमुख: महासचिव; ज़ुराब पोलोलिकाश्विली

ई-कॉमर्स निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए इंडिया पोस्ट और शिपरॉकेट ने साझेदारी की

डाक विभाग ने देश में ई-कॉमर्स के लिए एक निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की अपनी चल रही पहल के हिस्से के रूप में, प्रमुख ई-कॉमर्स सक्षम प्लेटफार्मों में से एक, बिगफुट रिटेल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड (शिपरॉकेट) के साथ एक समझौता किया है।

इस सहयोग का उद्देश्य इंडिया पोस्ट की व्यापक उपस्थिति और विश्वसनीय शिपिंग समाधानों का लाभ उठाकर ई-कॉमर्स निर्यात को बढ़ाना है।
नई दिल्ली में डाक सेवाओं के महानिदेशक श्री आलोक शर्मा, दिल्ली की मुख्य पोस्टमास्टर जनरल सुश्री मंजू कुमार और शिपरॉकेट के CEO श्री साहिल गोयल की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जो भारत के सीमा पार ई-कॉमर्स परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

मुख्य विचार:

इंडिया पोस्ट ने हाल के दिनों में विदेशी विस्तार जैसे कई कदम उठाए हैं
डाकघर, डाकघरों के माध्यम से वाणिज्यिक निर्यात को सक्षम करने के लिए निर्यात के डाक बिल की शुरूआत, एक प्रतिस्पर्धी अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ड पैकेट सेवा का शुभारंभ और देश भर में डाक घर निर्यात केंद्र (DNK) की स्थापना।
इस समझौते से डाक घर निर्यात केंद्र और शिपरॉकेट के बीच तकनीकी एकीकरण होगा और शिपरॉकेट का उपयोग करने वाले भारत-आधारित विक्रेताओं को सीधे शिपरॉकेट प्लेटफॉर्म से ई-PBE और शिपिंग लेबल उत्पन्न करने में सक्षम बनाया जाएगा।
निर्यातक पैकेजिंग, लेबल प्रिंटिंग, पिकअप सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं और देश के किसी भी हिस्से में अपने शिपमेंट को निकटतम DNK में भेज सकते हैं।

नवीनतम समाचार

इंडिया पोस्ट ई-कॉमर्स निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए दोनों देशों के बीच इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट सर्विस (ITPS) शुरू करने के लिए कनाडा पोस्ट के साथ एक समझौता किया है।
इंडिया पोस्ट ने लॉजिस्टिक सेवा के लिए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) और तृप्ता टेक्नोलॉजीज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने में मदद करने के लिए केंद्र ने Adobe के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एडोब एक्सप्रेस एप्लिकेशन का उपयोग करके कक्षाओं में बच्चों को रचनात्मक अभिव्यक्ति विकसित करने में मदद करने के लिए वैश्विक सॉफ्टवेयर प्रमुख एडोब के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
एडोब एक्सप्रेस-आधारित पाठ्यक्रम का उपयोग करके 2027 तक लगभग 20 मिलियन छात्रों और 5,00,000 शिक्षकों को रचनात्मकता और डिजिटल साक्षरता में प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान किया जाएगा।

मुख्य विचार

कार्यक्रम के तहत, एडोब देश भर के स्कूलों को एडोब एक्सप्रेस प्रीमियम तक मुफ्त पहुंच और शिक्षकों के व्यावसायिक विकास की सुविधा प्रदान करेगा।
छात्रों और शिक्षकों को रचनात्मकता, जनरेटिव एआई, डिजाइन, एनीमेशन, वीडियो और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों को कवर करने वाले विषयों के साथ सशक्त बनाने के लिए एडोब एक्सप्रेस टूल और क्षमताओं पर आधारित पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण और प्रमाणन शुरू किया जाएगा।
छात्र और शिक्षक एक्सप्रेस का उपयोग करने में सक्षम होंगे, जो एडोब के अनुसार, जेनरेटिव एआई क्षमताओं के साथ एक आसान सामग्री निर्माण एप्लिकेशन है।

एडोब के बारे में:

CEO: शांतनु नारायण
मुख्यालय: सैन जोस, कैलिफ़ोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका
संस्थापक: चार्ल्स गेश्के, जॉन वार्नॉक
स्थापना: दिसंबर 1982

TCS ने £800 मिलियन डिजिटल परिवर्तन सौदे के लिए JLR के साथ साझेदारी की

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) और जगुआर लैंड रोवर (JLR) ने JLR की डिजिटल संपत्ति को बदलने और एक नया, भविष्य के लिए तैयार डिजिटल कोर बनाने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है।
अगले पांच वर्षों में इस साझेदारी का मूल्य £800 मिलियन आंका गया है।
साझेदारी के तहत TCS JLR को अपनी डिजिटल क्षमता बढ़ाने और अपनी डिजिटल संपत्ति को बदलने और सरल बनाने में मदद करने के लिए अपनी गहरी डोमेन विशेषज्ञता, मालिकाना प्लेटफॉर्म और विशाल भागीदार पारिस्थितिकी तंत्र का लाभ उठाएगी।
यह साझेदारी जेएलआर की रीइमेजिन रणनीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जिसका उद्देश्य कंपनी को अधिक चुस्त, कुशल और ग्राहक-केंद्रित संगठन बनाना है।
साझेदारी JLR को अपने डिजिटल परिवर्तन लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने ग्राहकों के लिए एक आधुनिक लक्जरी अनुभव प्रदान करने में मदद करेगी।
जगुआर लैंड रोवर ऑटोमोटिव पीएलसी, जगुआर लैंड रोवर लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी है, जिसे जेएलआर के नाम से भी जाना जाता है, और यह एक ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय ऑटोमोबाइल निर्माता है जो लक्जरी वाहन और स्पोर्ट यूटिलिटी वाहन बनाती है।

TCS के बारे में:

संस्थापक: फकीर चंद कोहली, जेआरडी टाटा
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र
CEO: के. कृतिवासन
स्थापित: 1 अप्रैल 1968

नवीनतम समाचार

मई 2023 में, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने घोषणा की कि प्रमुख आईटी कंपनी के नेतृत्व वाले एक संघ को सरकारी स्वामित्व वाली BSNL द्वारा ₹15,000 करोड़ से अधिक का अग्रिम खरीद ऑर्डर दिया गया है।
जून 2023 में, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) घोषणा की गई कि स्वीडन में इकानो बैंक एबी ने अपने पैन-यूरोप कोर बैंकिंग परिवर्तन के लिए TCS BANCS ग्लोबल बैंकिंग सास प्लेटफॉर्म का चयन किया है।

REC ने EXIM के साथ 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विदेशी मुद्रा सावधि ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किएकिनारा

REC लिमिटेड, विद्युत मंत्रालय के अधीन महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम ने भारतीय निर्यात-आयात बैंक (EXIM बैंक) के साथ 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विदेशी मुद्रा सावधि ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
ऋण की आय का उपयोग पूंजीगत उपकरणों के आयात के लिए बिजली, बुनियादी ढांचे और रसद क्षेत्रों में आरईसी के उधारकर्ताओं को पुनर्वित्त के लिए किया जाएगा।
यह धनराशि REC के रुपये के बाजार उधार कार्यक्रम के हिस्से के रूप में जुटाई जाएगी। वर्ष 2023-24 के लिए 1.20 लाख करोड़।
यह EXIM बैंक द्वारा REC को दिया जाने वाला पहला सावधि ऋण है।
ऋण को 5 साल की अवधि के लिए बांधा गया है और इसे SOFR (सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट) पर बेंचमार्क किया गया है, जो USD में मूल्यवर्गित ऋण के लिए बेंचमार्क दर है।

REC के बारे में:

REC लिमिटेड एक NBFC है जो पूरे भारत में पावर सेक्टर के वित्तपोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। 1969 में स्थापित, आरईसी लिमिटेड ने संचालन के पचास वर्ष से अधिक पूरे कर लिए हैं।

निर्यात-आयात बैंक भारत के बारे में:

स्थापना: 1982.
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र
प्रबंध निदेशक: हर्षा बंगारी

यह पूरी तरह से भारत सरकार (GoI) के स्वामित्व में है और इसकी स्थापना भारत के अंतर्राष्ट्रीय को वित्तपोषित करने, सुविधा प्रदान करने और बढ़ावा देने के लिए की गई थी।

नवीनतम समाचार

अप्रैल 2023 में, EXIM (निर्यात-आयात) बैंक चालू वित्त वर्ष (FY24) की तीसरी तिमाही (Q3) तक व्यापार वित्त के लिए अपनी प्रस्तावित GIFT सिटी सहायक कंपनी के चालू होने की उम्मीद है।

NVIDIA ने भारत में AI इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए रिलायंस और टाटा समूह के साथ सहयोग किया है

संयुक्त राज्य अमेरिका (US) स्थित चिप निर्माता NVIDIA ने भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) बुनियादी ढांचे को स्थापित करने और देश के कार्यबल के कौशल सेट को बढ़ाने के लिए भारत के दो सबसे बड़े समूह, रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाटा समूह के साथ रणनीतिक साझेदारी बनाई है।

रिलायंस के सहयोग से, NVIDIA भारत का अपना मूलभूत बड़ा भाषा मॉडल विकसित करेगा, जो विशेष रूप से देश की विविध भाषाओं पर प्रशिक्षित होगा, जो भारत की विशाल आबादी के लिए जेनेरिक एआई अनुप्रयोगों को पूरा करेगा।

NVIDIA इस पहल के हिस्से के रूप में AI सुपरकंप्यूटिंग सेवाएं और प्रौद्योगिकियां प्रदान करेगा।

मुख्य विचार:

रिलायंस ने अपने 450 मिलियन Jio ग्राहकों के लिए AI एप्लिकेशन और सेवाएं बनाने के लिए इस AI बुनियादी ढांचे का लाभ उठाने की योजना बनाई है।

इसके अतिरिक्त, रिलायंस पूरे भारत में वैज्ञानिकों, डेवलपर्स और स्टार्टअप्स को ऊर्जा-कुशल एआई बुनियादी ढांचे की पेशकश करेगा।

एआई बुनियादी ढांचे को एआई-तैयार कंप्यूटिंग डेटा केंद्रों में होस्ट किया जाएगा, जो अंततः 2,000 मेगावाट तक बढ़ जाएगा। इस बुनियादी ढांचे के निष्पादन और कार्यान्वयन की देखरेख Jio द्वारा की जाएगी।

टाटा समूह के साथ साझेदारी में, NVIDIA का लक्ष्य स्थानीय अर्थव्यवस्था को समर्थन देने और भारत में AI नवाचार को बढ़ावा देने के लिए AI बुनियादी ढांचे की स्थापना करना है।

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) 6 लाख से अधिक लोगों के अपने कार्यबल के साथ, AI में पुनः कौशल से गुजरना होगा। केवल बैकरूम बिजनेस ऑपरेशंस एप्लिकेशन पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, TCS अब फ्रंट-ऑफिस कार्यों के लिए एआई एप्लिकेशन विकसित करेगा।

NVIDIA विज़ुअलाइज़ेशन, डिज़ाइन, स्टाइलिंग, इंजीनियरिंग और स्वायत्त वाहन में AI को एकीकृत करने के लिए टाटा मोटर्स के साथ भी सहयोग करेगा।

NVIDIA के बारे में:

स्थापना: 5 अप्रैल, 1993
मुख्यालय: सांता क्लारा, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका
अध्यक्ष और CEO: जेन्सेन हुआंग

भारतीय रेलवे के गति शक्ति विश्वविद्यालय (GSV) वडोदरा और एयरबस ने एयरोस्पेस शिक्षण और अनुसंधान के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

भारतीय रेलवे का गति शक्ति विश्वविद्यालय (GSV) वडोदरा और एयरबस ने एक समझौता ज्ञापन (MoU) के माध्यम से भारतीय विमानन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सहयोग किया है।

रेल भवन, नई दिल्ली में श्री रेमी मिलार्ड (अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, एयरबस इंडिया और दक्षिण एशिया) और प्रोफेसर मनोज चौधरी (कुलपति, गति शक्ति विश्वविद्यालय) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह नई दिल्ली में रेल भवन में हुआ और इसमें रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने भाग लिया, जो गति शक्ति विश्वविद्यालय के पहले चांसलर के रूप में भी कार्यरत हैं।

इस अवसर पर रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष एवं CEO सुश्री जया वर्मा सिन्हा सहित रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

साझेदारी का उद्देश्य:

इस साझेदारी का उद्देश्य विभिन्न माध्यमों से भारतीय विमानन क्षेत्र को बढ़ाना है, जिनमें शामिल हैं:
छात्रों और कामकाजी पेशेवरों के लिए एयरोस्पेस उद्योग से संबंधित कौशल पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों का सह-विकास और सह-वितरण।
संयुक्त अनुसंधान पहल.
संकाय के लिए उद्योग अनुभव प्रदान करना।
छात्रों के लिए इंटर्नशिप और प्लेसमेंट की पेशकश।
छात्रवृत्ति कार्यक्रम स्थापित करना।

गति शक्ति विश्वविद्यालय (GSV) वडोदरा के बारे में:

गति शक्ति विश्वविद्यालय (GSV) वडोदरा की स्थापना 2022 में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से संपूर्ण परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों के लिए सर्वोत्तम जनशक्ति और प्रतिभा तैयार करने के लिए की गई थी।
यह भारत सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा प्रायोजित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जिसके पहले चांसलर श्री अश्विनी वैष्णव, रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री हैं।
GSV एक "अपनी तरह का पहला" विश्वविद्यालय है जिसका लक्ष्य रेलवे, शिपिंग, बंदरगाह, राजमार्ग, सड़क, जलमार्ग और विमानन आदि में राष्ट्रीय विकास योजनाओं (पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान 2021 और राष्ट्रीय रसद नीति 2022) के जनादेश को पूरा करना है।

एयरबस के बारे में:

एयरबस वाणिज्यिक विमानों का दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता है और हेलीकॉप्टर, रक्षा और अंतरिक्ष उपकरणों का एक महत्वपूर्ण उत्पादक है।
इसके अलावा, एयरबस और टाटा ने भारत में C295 विमान के डिजाइन, नवाचार, निर्माण और विकास के लिए एक साझेदारी की घोषणा की है, जिसकी सुविधा वडोदरा, गुजरात में स्थित है।

भारत 6जी एलायंस और नेक्स्ट जी एलायंस ने सहयोग के अवसर तलाशने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में 6जी वायरलेस प्रौद्योगिकियों पर सहयोग के अवसरों का पता लगाने के लिए भारत 6जी एलायंस और नेक्स्ट जी एलायंस, एलायंस फॉर टेलीकम्युनिकेशंस इंडस्ट्री सॉल्यूशंस (ATIS) पहल के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।
MoU पर भारत 6जी अलायंस के अध्यक्ष एनजी सुब्रमण्यम और ATIS के नेक्स्ट जी अलायंस के अध्यक्ष और CEO सुसान मिलर ने हस्ताक्षर किए।
MoU अनुसंधान और विकास प्राथमिकताओं को संरेखित करने की सुविधा प्रदान करेगा जो एक सामान्य 6जी दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं और सुरक्षित और विश्वसनीय दूरसंचार के साथ-साथ लचीली आपूर्ति श्रृंखलाएं बनाते हैं।
भारत के पास बड़े पैमाने पर समाज के सशक्तिकरण का दृष्टिकोण था और अगली पीढ़ी 6जी जीवन की गुणवत्ता को और बढ़ाएगी।
ATIS द्वारा शुरू किया गया, नेक्स्ट जी एलायंस 6 जी पर प्रारंभिक ध्यान देने के साथ निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाले प्रयासों के माध्यम से अगले दशक में उत्तरी अमेरिकी वायरलेस प्रौद्योगिकी नेतृत्व को आगे बढ़ाने की एक पहल है।
एप्लीकेशन, ग्रीन जी, नेशनल 6जी रोडमैप, सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताएं, स्पेक्ट्रम और प्रौद्योगिकी में इसके कार्य समूहों के प्रयास 6जी और उससे आगे के क्षेत्र में उत्तर अमेरिकी नेतृत्व की नींव तैयार कर रहे हैं।

भारत 6जी एलायंस के बारे में

भारत 6 जी एलायंस भारतीय उद्योग, शिक्षाविदों और राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों की एक पहल है और प्रौद्योगिकी और नवाचारों को डिजाइन, विकसित और तैनात करने के लिए भारत 6 जी मिशन के साथ संरेखित है जो भारत और बाहर के नागरिकों के उच्च गुणवत्ता वाले जीवन अनुभव के लिए एक बुद्धिमान और सुरक्षित समाधान प्रदान करता है।

Click Here to Subscribe Our Yearly Mock Test Package

गठबंधन का उद्देश्य दूरसंचार उत्पादों और समाधानों के अनुसंधान, डिजाइन, विकास, क्षेत्र परीक्षण, सुरक्षा, प्रमाणन और विनिर्माण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है।

भारत और सऊदी अरब ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किये

भारत और सऊदी अरब ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
भारत सरकार और सऊदी अरब की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर नई दिल्ली में भारत सरकार की ओर से केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत मंत्री श्री आर. के. सिंह और सऊदी अरब साम्राज्य के ऊर्जा मंत्री, सऊदी पक्ष के लिए महामहिम अब्दुलअजीज बिन सलमान अल-सऊद ने हस्ताक्षर किए।
इस MoU से भारत और सऊदी अरब के बीच ऊर्जा के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी विकसित होगी।
यह समझौता ज्ञापन जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में ऊर्जा परिवर्तन और वैश्विक ऊर्जा प्रणाली में बदलाव के लिए भारत के प्रयासों का समर्थन करेगा।

समझौता ज्ञापन के अनुसार, भारत और सऊदी अरब निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग करेंगे:

नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, हाइड्रोजन, बिजली और दोनों देशों के बीच ग्रिड इंटरकनेक्शन, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सामरिक पेट्रोलियम भंडार और ऊर्जा सुरक्षा।
नवीकरणीय ऊर्जा, बिजली, हाइड्रोजन और भंडारण के क्षेत्र में द्विपक्षीय निवेश को प्रोत्साहित करना; और तेल और गैस.
जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए सर्कुलर इकोनॉमी और इसकी प्रौद्योगिकियां, जैसे कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण।
ऊर्जा के क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन, नवाचार साइबर-सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देना।
ऊर्जा, आपूर्ति श्रृंखलाओं और प्रौद्योगिकियों के सभी क्षेत्रों से संबंधित सामग्रियों, उत्पादों और सेवाओं को स्थानीयकृत करने के लिए दोनों देशों के बीच गुणात्मक साझेदारी विकसित करने पर काम करना।
ऊर्जा के क्षेत्र में विशेषज्ञता वाली कंपनियों के साथ सहयोग को मजबूत करना।
ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित कोई अन्य क्षेत्र जिस पर दोनों देश सहमत हों।

सऊदी अरब के बारे में:

प्रधान मंत्री: मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद
राजधानी: रियाद
मुद्रा: सऊदी रियाल

NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए नायरा एनर्जी के साथ सहयोग करेगा

NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (NGEL), जो भारत की अग्रणी एकीकृत बिजली उत्पादक NTPC लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, और अंतरराष्ट्रीय स्तर की नए जमाने की डाउनस्ट्रीम ऊर्जा कंपनी नायरा एनर्जी ने हरित क्षेत्र में अवसरों का पता लगाने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) में प्रवेश किया है।
समझौता ज्ञापन में नायरा एनर्जी के कैप्टिव उपयोग के लिए ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने, डीकार्बोनाइजेशन में तेजी लाने और कार्बन फुटप्रिंट में कमी को उत्प्रेरित करने के लिए सहयोग की परिकल्पना की गई है।
यह सहयोग भारत में हाइड्रोजन परियोजनाओं को विकसित करने के लिए NTPC की पहल के अनुरूप है और प्रधान मंत्री द्वारा निर्धारित आत्मनिर्भर भारत (आत्मनिर्भर भारत) के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह में एनजीईएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री मोहित भार्गव और नायरा एनर्जी के तकनीकी प्रमुख श्री अमर कुमार के साथ-साथ NTPC, NGEL और नायरा एनर्जी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

NTPC के बारे में:

NTPC भारत की सबसे बड़ी विद्युत उपयोगिता है जिसकी कुल स्थापित क्षमता 73 गीगावॉट से अधिक है। अपने नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो को बढ़ाने के हिस्से के रूप में, ग्रीन हाइड्रोजन, एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज और राउंड-द-क्लॉक आरई पावर के क्षेत्र में व्यवसायों सहित नवीकरणीय ऊर्जा पार्क और परियोजनाओं को शुरू करने के लिए एक पूर्ण स्वामित्व वाली

सहायक कंपनी NGEL का गठन किया गया है। NTPC समूह की वर्ष 2032 तक 60 गीगावॉट आरई क्षमता की योजना है और वर्तमान में वह 20+ गीगावॉट की पाइपलाइन पर काम कर रहा है, जिसमें से 3 गीगावॉट से अधिक परिचालन क्षमता है।
स्थापना: 7 नवंबर 1975
मुख्यालय: नई दिल्ली, भारत
गुरदीप सिंह NTPC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं

नायरा एनर्जी के बारे में

नायरा एनर्जी अंतरराष्ट्रीय स्तर की एक एकीकृत डाउनस्ट्रीम कंपनी है, जिसकी रिफाइनिंग से लेकर रिटेल तक हाइड्रोकार्बन मूल्य श्रृंखला में मजबूत उपस्थिति है। नायरा एनर्जी 20 MMTPA की क्षमता के साथ वाडिनार, गुजरात में भारत की दूसरी सबसे बड़ी सिंगल-साइट रिफाइनरी का मालिक है। यह 11.8 की जटिलता के साथ दुनिया की सबसे आधुनिक और जटिल रिफाइनरियों में से एक है, जो विश्व स्तर पर सबसे अधिक है। कंपनी के पूरे भारत में 6,000 से अधिक परिचालन खुदरा आउटलेट हैं।

नवीनतम समाचार

जून 2023 में, भारत की अग्रणी एकीकृत बिजली उत्पादक एनटीपीसी लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2023 - 2024 की पहली तिमाही के दौरान अपनी कैप्टिव खानों से कोयला उत्पादन को पिछले वर्ष की पहली तिमाही के दौरान उत्पादन की तुलना में लगभग दोगुना कर दिया।
जुलाई 2023 में, NTPC को "लर्निंग और अपस्किलिंग में एआई/एआर/वीआर का सर्वोत्तम उपयोग" और "एक्सटेंडेड एंटरप्राइज लर्निंग प्रोग्राम बनाने में सर्वश्रेष्ठ एडवांस" के लिए प्रतिष्ठित इकोनॉमिक टाइम्स (ईटी) एचआर वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स अवार्ड्स 2023 प्राप्त हुआ।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने विभिन्न निजी नौकरी पोर्टलों/नियोक्ताओं के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने यहां मंत्रालय के राष्ट्रीय करियर सेवा (NCS) पोर्टल के साथ एकीकृत करने के लिए प्रमुख निजी नौकरी पोर्टलों, कंपनियों/ नियोक्ताओं और कौशल प्रदाताओं के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
MoU का उद्देश्य NCS पोर्टल पर नौकरी चाहने वालों के लिए रोजगार के अवसरों और सेवाओं को बढ़ाना है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय के साथ साझेदारी करने वाले निजी नौकरी पोर्टल NCS पर अपनी रिक्तियों को साझा करेंगे ताकि NCS पंजीकृत नौकरी चाहने वाले ऐसी रिक्तियों के लिए निर्बाध रूप से आवेदन कर सकें।
श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से श्रम और रोजगार मंत्रालय में सचिव श्रीमती आरती आहूजा और अपर सचिव (श्रम एवं रोजगार) श्री रमेश कृष्णमूर्ति की उपस्थिति में उप महानिदेशक (रोजगार) श्री अमित निर्मल ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।
समझौता ज्ञापन पर टीमलीज एचआरटेक, Monster.com इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, क्वेस कॉर्प लिमिटेड, डिलीवरी ट्रैक (VSS टेक), करपागा एसेसमेंट एपीपी मैट्रिक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (हायरमी), क्विकर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, टीसीएस आईओएन और एनसीएस पोर्टल के साथ अपनी रिक्तियों को साझा करने वाली पहली job.co.in के साथ हस्ताक्षर किए गए। ये रिक्तियां NCS पंजीकृत नौकरी चाहने वालों के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाएंगी।
असंगठित क्षेत्र के 30 लाख से अधिक ईश्रम पंजीकृत श्रमिक जो अब तक NCS में शामिल हो चुके हैं, उन्हें भी इस साझेदारी से लाभ होगा।
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने NCS पोर्टल पर पंजीकृत नौकरी चाहने वालों को अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में मुफ्त ऑनलाइन सॉफ्ट कौशल रोजगार प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए TCS iON के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
यह रोजगारपरक प्रशिक्षण नौकरी चाहने वालों के रोजगारपरक कौशल को बढ़ाने में बहुत उपयोगी पाया गया।
इस तरह के प्रशिक्षण से उनके चयन पर कार्यबल की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी।

IICA और यूनिसेफ संयुक्त रूप से व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्टिंग (BRSR) पर कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स (IICA) ने यूनिसेफ और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सहयोग से मुंबई, महाराष्ट्र में NSE परिसर में बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग (BRSR) पर एक कार्यशाला का आयोजन किया।
कार्यशाला में प्रमुख कॉर्पोरेट घरानों के 50 से अधिक स्थिरता, CSR (कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी), ESG (पर्यावरण, सामाजिक और शासन) और BHR (बिजनेस ह्यूमन राइट्स) पेशेवरों ने भाग लिया।
कार्यशाला का उद्देश्य बीआरएसआर ढांचे की व्यापक समझ प्रदान करना है, जो जिम्मेदार व्यवसाय आचरण के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश (NGRBC) के नौ सिद्धांतों पर आधारित है।
BRSR ढांचा शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपनियों या व्यवसायों के लिए पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) पहलुओं पर अपने प्रदर्शन की रिपोर्ट करने और जिम्मेदार व्यावसायिक प्रथाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने के लिए एक अनिवार्य प्रकटीकरण तंत्र है।
कार्यशाला में जिम्मेदार ब्रांडों की स्थापना के लिए उपकरण के रूप में CSR और ESG, प्रभावी BRSR प्रकटीकरण, डिजिटल उपकरण, BRSR के लिए आईटी पोर्टल/सॉफ्टवेयर और व्यवसाय में परिवार के अनुकूल नीतियों के अनुप्रयोग जैसे विभिन्न विषयों को भी शामिल किया गया।
कार्यशाला ने प्रतिभागियों को बीआरएसआर और इसके कार्यान्वयन में अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाने में सक्षम बनाया।

नवीनतम समाचार

जुलाई 2023 में, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तत्वावधान में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स (IICA) ने अपने ग्रेजुएट इन्सॉल्वेंसी प्रोग्राम (GIP) के लिए अपने वार्षिक सप्ताह भर के सम्मेलन - 'वीक विद लीजेंड्स, 2023' की शुरुआत की, जिसमें दिवाला प्रथा के दिग्गजों को भारत में दिवाला और दिवालियापन शासन के विभिन्न पहलुओं पर अपने प्रमुख जीआईपी के छात्रों के साथ एक गोलमेज चर्चा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है।
जून 2023 में, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स (IICA) ने NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद के सहयोग से नई दिल्ली में दिवाला और दिवालियापन कानूनों में LLM नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया।
जून 2023 में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स (IICA) और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (RRU) के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।
जून 2023 में, रक्षा मंत्रालय के पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के तहत महानिदेशालय पुनर्वास (DGR) और नई दिल्ली में मेसर्स कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।

IICA के बारे में:

IICA भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) द्वारा एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित एक संस्था है जो एक एकीकृत और बहु-प्रक्रिया के माध्यम से भारत में कॉर्पोरेट क्षेत्र के विकास का समर्थन करने के लिए एक थिंक-टैंक और उत्कृष्टता केंद्र के रूप में कार्य करती है।
RRU गृह मंत्रालय के अधीन एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है।
यह भारत का एक अग्रणी राष्ट्रीय सुरक्षा और पुलिस विश्वविद्यालय है।

यूनिसेफ के बारे में:

मुख्यालय: न्यूयॉर्क,
स्थापना: 11 दिसंबर 1946
संस्थापक: संयुक्त राष्ट्र महासभा, लुडविक राजचमन
प्रमुख: कैथरीन एम. रसेल

DMRC और BEL ने स्वदेशी संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड स्वदेशी संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
यह साझेदारी भारत में रेल परिवहन को बदल देगी, नवाचार को बढ़ावा देगी, लागत को कम करेगी, और ट्रेन नियंत्रण सिग्नलिंग सिस्टम के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगी।
यह मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप है।
संचार-आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली रेल बुनियादी ढांचे का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हुए ट्रेन संचालन का अनुकूलन करेगी, आवृत्ति बढ़ाएगी और यात्री सेवाओं को बढ़ाएगी।
प्रोटोटाइप आई-CBTC उत्पाद को जल्द ही परीक्षण ट्रैक पर तैनात किया जाएगा।

नवीनतम समाचार

मई 2023 में, नौसेना एंटी-ड्रोन सिस्टम (NADS) जिसे भारतीय नौसेना के सहयोग से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है, का निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) द्वारा किया जा रहा है।

BEL के बारे में:

मुख्यालय: बेंगलुरु
स्थापित: 1954, बेंगलुरु
प्रमुख लोग: भानु प्रकाश श्रीवास्तव; (कार्यवाहक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)

AWS ने भारत में क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से अंतरिक्ष-तकनीकी नवाचारों का समर्थन करने के लिए इसरो और IN-SPACe के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

अमेज़न वेब सेवाएँ (AWS) भारत ने क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से अंतरिक्ष-तकनीकी नवाचारों का समर्थन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) के साथ एक रणनीतिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
यह सहयोग अंतरिक्ष स्टार्ट-अप, अनुसंधान संस्थानों और छात्रों को उन्नत क्लाउड प्रौद्योगिकियों तक पहुंच प्रदान करेगा जो अंतरिक्ष क्षेत्र में नए समाधानों के विकास को गति देगा।
इसरो, इन-स्पेस, और AWS अंतरिक्ष-तकनीक क्षेत्र में स्टार्ट-अप समुदाय के पोषण और विकास के लिए सहयोगात्मक रूप से काम करेंगे।
AWS, AWS एक्टिवेट प्रोग्राम के माध्यम से योग्य स्पेस स्टार्ट-अप को बिना किसी लागत के उपकरण, संसाधन और विशेषज्ञ तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।
इसके अलावा, स्टार्ट-अप को AWS तक पहुंच और AWS स्पेस एक्सेलेरेटर कार्यक्रम के माध्यम से एयरोस्पेस और उपग्रह समाधान बनाने के इसके वैश्विक अनुभव से भी लाभ होगा।
तीनों संगठन AWS शिक्षा कार्यक्रमों का लाभ उठाकर छात्रों और शिक्षकों को क्लाउड कंप्यूटिंग, AI, ML, एनालिटिक्स और सुरक्षा में प्रशिक्षित करने के लिए एक नई पहल पर भी सहयोग करेंगे।
अमेज़ॅन वेब सर्विसेज, इंक. अमेज़ॅन की एक सहायक कंपनी है जो व्यक्तियों, कंपनियों और सरकारों को मीटर के आधार पर भुगतान के आधार पर ऑन-डिमांड क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफ़ॉर्म और API प्रदान करती है।

जहाजों की न्यायिक बिक्री में कानूनी निश्चितता को बढ़ावा देने के लिए 15 देश संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में शामिल हुए

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, चीन, सऊदी अरब, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड सहित 15 देशों ने जहाजों की न्यायिक बिक्री के अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए।
समुद्री परिवहन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अग्रणी भूमिका निभाता है, और यह अनुमान लगाया गया है कि वैश्विक व्यापार का 90 प्रतिशत से अधिक सामान समुद्र के द्वारा ले जाया जाता है। यह जहाज को एक महत्वपूर्ण संपत्ति बनाता है।
हालाँकि, अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग से संबंधित मामले अक्सर अंतर्राष्ट्रीय सामंजस्य की कमी के कारण उत्पन्न होने वाली कानूनी कठिनाइयों से ग्रस्त होते हैं।

इसका उद्देश्य जहाजों की 'न्यायिक' बिक्री के अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों के लिए एक समान व्यवस्था बनाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी निश्चितता और पूर्वानुमान को बढ़ावा देना है।
जहाजों की न्यायिक बिक्री पर बीजिंग कन्वेंशन, जैसा कि अब ज्ञात है, था
संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग (UNCITRAL) द्वारा वास्तविक नए मालिकों की समस्या का समाधान करने के लिए विकसित किया गया है, जो ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में जहाज पर दावा करने वाले पिछले लेनदारों से निपटते हैं।
यह सम्मेलन न्यायिक बिक्री को अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव देने के लिए एक सामंजस्यपूर्ण शासन स्थापित करता है।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यात्रा करते समय क्रेता द्वारा जहाज में हासिल किए जाने वाले शीर्षक के लिए कानूनी निश्चितता सुनिश्चित करके, कन्वेंशन को उस कीमत को अधिकतम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जिसे जहाज बाजार में आकर्षित करने में सक्षम है और लेनदारों के बीच वितरण के लिए उपलब्ध आय, और अंतरराष्ट्रीय को बढ़ावा देने के लिए व्यापार।
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) ने कहा कि वह इन नोटिसों और न्यायिक बिक्री के प्रमाणपत्रों के भंडार के रूप में कार्य करके सम्मेलन की स्थापना का समर्थन कर रहा है।
जहाजों की लंबित और पूर्ण न्यायिक बिक्री की जानकारी IMO के ग्लोबल इंटीग्रेटेड शिपिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम (GISIS) प्लेटफॉर्म पर एक समर्पित मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध होगी।
जहाजों की न्यायिक बिक्री के अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों पर कन्वेंशन को अब अपनाए जाने के साथ, IMO सदस्य राज्यों को समझौते की पुष्टि करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।

IMO के बारे में

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो शिपिंग को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है।
IMO की स्थापना 1948 में जिनेवा में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में समझौते के बाद की गई थी और IMO दस साल बाद अस्तित्व में आया, 17 मार्च 1958 में पहली बार बैठक हुई।
मुख्यालय: लंदन, यूनाइटेड किंगडम.

डीलरों को वित्तपोषण समाधान प्रदान करने के लिए मारुति सुजुकी ने इंडियन बैंक के साथ साझेदारी की

मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने अपने डीलरों को वित्तपोषण समाधान प्रदान करने के लिए इंडियन बैंक के साथ साझेदारी की है।
दोनों पक्षों ने एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं, जो देश भर में 4,000 से अधिक मारुति सुजुकी डीलरशिप को उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए व्यापक इन्वेंट्री फंडिंग विकल्पों के साथ सशक्त बनाएगा।
हमारा लक्ष्य पूरे देश में हमारे डीलर भागीदारों के लिए वैयक्तिकृत ऑफ़र और एंड-टू-एंड कार्यशील पूंजी समाधान विकसित करने में इंडियन बैंक के साथ मिलकर काम करना है।
मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड जापानी वाहन निर्माता सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन की भारतीय सहायक कंपनी है।
इंडियन बैंक एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, जिसकी स्थापना 1907 में हुई और इसका मुख्यालय चेन्नई में है।

एयर इंडिया ने बैंकॉक एयरवेज के साथ इंटरलाइन साझेदारी की

अपने वैश्विक नेटवर्क का विस्तार करने के प्रयास के तहत, एयर इंडिया ने थाईलैंड और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों में अधिक कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए बैंकॉक एयरवेज के साथ एक इंटरलाइन साझेदारी में प्रवेश किया है।
इस समझौते में बैंकॉक एयरवेज के रूट नेटवर्क पर थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया के 10 गंतव्यों के लिए एयर इंडिया के बैंकॉक, हांगकांग और सिंगापुर गेटवे के माध्यम से निर्बाध कनेक्शन के साथ-साथ केबिन क्लास की परवाह किए बिना उपलब्ध हवाई अड्डों पर मानार्थ लाउंज का उपयोग शामिल है।
बैंकॉक गेटवे के अलावा, एयर इंडिया के यात्री सिंगापुर और हांगकांग के रास्ते कोह समुई तक उड़ान भरने का विकल्प भी चुन सकते हैं।

Click Here to Subscribe Our Yearly Mock Test Package

दोनों एयरलाइनों के बीच समझौते के दायरे में इंटर एयरलाइन थ्रू चेक-इन (IATCI) कार्यान्वयन शामिल है, जो मेहमानों को एक ही टिकट पर सभी यात्रा क्षेत्रों के लिए प्रस्थान के पहले बिंदु पर अपने बोर्डिंग पास प्राप्त करने और उनके सामान की जांच करने में सक्षम बनाता है।

एयर इंडिया के बारे में

एयर इंडिया भारत का ध्वज वाहक है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
एयर इंडिया लिमिटेड के पूर्व मालिक, भारत सरकार द्वारा बिक्री पूरी करने के बाद, इसका स्वामित्व टैलेस प्राइवेट लिमिटेड के पास है, जो टाटा संस की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।
CEO: कैंपबेल विल्सन

नवीनतम समाचार

जून 2023 में, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, मुंबई द्वारा आयोजित 'महाराजा का खजाना: प्रसिद्ध एयर इंडिया संग्रह से कला के चुनिंदा कार्य' नामक एक कला प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने किया था।

टाटा पावर, सिडबी ने एमएसएमई द्वारा सौर ऊर्जा अपनाने की सुविधा के लिए समझौता किया

टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (TPREL) ने सौर समाधान अपनाने के इच्छुक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को सुलभ वित्तपोषण विकल्प प्रदान करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
योजना के तहत, MSME रूफटॉप सोलर पीवी प्लांट या टाटा पावर या उससे जुड़ी सेवाओं का विकल्प चुन रहे हैंअधिकार दिया गयापूरे भारत में चैनल भागीदारों को सिडबी से वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।
इस सहयोग का उद्देश्य सिडबी की 4ई (एंड-टू-एंड एनर्जी एफिशिएंसी) योजना के माध्यम से अनुरूप और अभिनव वित्तपोषण समाधान प्रदान करके MSME के बीच सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देना है, जो MSME क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करते हुए प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों और लचीली ऋण सीमा प्रदान करता है।
इसके अतिरिक्त, TPSSL और सिडबी ने ग्लोबल SME फाइनेंस फोरम 2023 में 'द बिग सोलर फेस्ट' पेश किया है, जो आगामी त्योहारी सीजन के दौरान शून्य प्रोसेसिंग शुल्क की पेशकश करता है।
इस पहल का उद्देश्य बिना प्रसंस्करण शुल्क के प्रतिस्पर्धी वित्तपोषण विकल्पों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, जिससे MSME क्षेत्र में हरित ऊर्जा की ओर संक्रमण में तेजी आएगी।

सिडबी के बारे में:

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) की स्थापना 1990 में संसद के एक अधिनियम के तहत की गई थी।
मुख्यालय: लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत।
स्थापना: 2 अप्रैल 1990
मुख्यालय: लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक: शिवसुब्रमण्यम रमन
सिडबी भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम वित्त कंपनियों के समग्र लाइसेंसिंग और विनियमन के लिए शीर्ष नियामक निकाय है।
यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (MoF) के अधिकार क्षेत्र में है।

MSME के बारे में:

MSME शब्द भारत सरकार (GoI) द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (MSMED) अधिनियम, 2006 के समझौते के तहत पेश किया गया था।

नवीनतम समाचार

जून 2023 में, राज्य के स्वामित्व वाले भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को वित्तीय समाधान प्रदान करने के लिए HDFC बैंक के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) में प्रवेश किया।

जुलाई 2023 में, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) दो चरणों में ₹700 करोड़ के कुल लक्ष्य कोष के साथ विवृति एसेट मैनेजमेंट द्वारा प्रबंधित प्रॉमिसिंग लेंडर्स फंड (PLF) में एक एंकर निवेशक के रूप में भाग लिया है।

REC ने कर्नाटक के गडग में 560 मेगावाट ग्रीनफील्ड सौर-पवन परियोजना के लिए सेरेंटिका को 3081 करोड़ रुपये का ऋण वित्तपोषण किया

REC लिमिटेड ने कर्नाटक के गडग जिले में अपनी 560 मेगावाट पीक ग्रीनफील्ड सौर-पवन हाइब्रिड परियोजना के लिए नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी सेरेंटिका रिन्यूएबल्स को 3,081 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण वित्तपोषण को मंजूरी दी है।
ऋण दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं और धनराशि का वितरण किया जा रहा है।
REC लिमिटेड, एक महारत्न कंपनी, देश की COP26 प्रतिबद्धताओं और भारत की G20 प्रेसीडेंसी के तहत हाल ही में G20 प्रतिज्ञाओं के अनुरूप, भारत के ऊर्जा परिवर्तन को उत्प्रेरित करने में अग्रणी बनकर उभरी है।
दृढ़ दृष्टि और अटूट प्रतिबद्धता के साथ, REC वित्तीय वर्ष 2030 तक 3 लाख करोड़ रुपये की ग्रीन फाइनेंस लोन बुक हासिल करने के पथ पर है।
जैसा कि भारत और दुनिया एक स्वच्छ और हरित ऊर्जा परिदृश्य की दिशा में प्रयास कर रहे हैं, हरित वित्त पहल को बढ़ावा देने के लिए आरईसी का समर्पण और भारत के ऊर्जा परिवर्तन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका एक टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल भविष्य बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करती है।

REC के बारे में:

REC लिमिटेड एक NBFC है जो पूरे भारत में पावर सेक्टर के वित्तपोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। 1969 में स्थापित, आरईसी लिमिटेड ने अपने परिचालन के क्षेत्र में चौवन वर्ष से अधिक पूरे कर लिए हैं।
यह पूर्ण बिजली क्षेत्र मूल्य श्रृंखला को वित्तीय सहायता प्रदान करता है; उत्पादन, पारेषण और वितरण और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के लिए।
हाल ही में, REC ने हवाई अड्डों, मेट्रो, रेलवे, बंदरगाहों, पुलों आदि जैसे क्षेत्रों को कवर करने के लिए गैर-बिजली बुनियादी ढांचे और रसद क्षेत्र में भी विविधता लाई है।

कर्नाटक के बारे में:

राज्यपाल: थावर चंद गहलोत
मुख्यमंत्री: सिद्धारमैया
राजधानी: बेंगलुरु
राष्ट्रीय उद्यान: बांदीपुर एनपी, कुद्रेमुख एनपी
वन्यजीव अभयारण्य: बीआर हिल्स वन्यजीव अभयारण्य, कावेरी वन्यजीव अभयारण्य, गुडवी पक्षी अभयारण्य, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य
टाइगर रिजर्व: नागरहोल टाइगर रिजर्व, भद्रा टाइगर रिजर्व
त्यौहार: हम्पी, महामस्तकाभिषेक (श्रवणबेलगोला)
नृत्य: यक्षगान, डोल्लू कुनिथा, बोलक-आट (बोलक नृत्य)

नवीनतम समाचार

मई 2023 में, REC लिमिटेड ने राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक ग्रीन फील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स स्थापित करने के लिए HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (HRRL) को 4,785 करोड़ रुपये का ऋण दिया।
मई 2023 में, REC लिमिटेड एक महारत्न पावर फाइनेंस कंपनी ने अपने 7 बिलियन डॉलर के ग्लोबल मीडियम टर्म प्रोग्राम के तहत GIFT IFSC स्टॉक एक्सचेंजों में हाल ही में जारी किए गए 750 मिलियन डॉलर के ग्रीन बांड को विशेष रूप से सूचीबद्ध किया है।

NHAI ने बेंगलुरु में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए

NHAI की 100% स्वामित्व वाली कंपनी राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड (NHLML) ने बेंगलुरु में मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क (MMLP) के विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे 1,770 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर सार्वजनिक निजी भागीदारी (DBFOT) मॉडल के तहत विकसित करने का प्रस्ताव है।
MMLP को कर्नाटक के बेंगलुरु ग्रामीण जिले के मुदेलिंगनहल्ली में 400 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है।
यह परियोजना पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत देश में लागू की गई पहली और सबसे बड़ी MMLP बनने की ओर अग्रसर है।
निर्बाध रसद आवाजाही की सुविधा के लिए, यह साइट रणनीतिक रूप से पूर्व की ओर आगामी KIADB औद्योगिक क्षेत्र के निकट स्थित है, जो NH 648, उत्तर की ओर डब्बास्पेट से होसुर के साथ-साथ सैटेलाइट टाउन रिंग रोड और दक्षिण में बेंगलुरु - हुबली - मुंबई रेल लाइन से सटी हुई है। बेंगलुरु MMLP बेंगलुरु हवाई अड्डे से 58 किमी और बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन से 48 किमी की दूरी पर स्थित है।

MMLP के बारे में

MMLP को तीन चरणों में विकसित किया जाएगा। पहला चरण दो साल में पूरा होने की उम्मीद है। एमएमएलपी 45 वर्षों की रियायती अवधि के अंत तक लगभग 30 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) कार्गो को पूरा करेगा और बेंगलुरु और तुमकुर जैसे जलग्रहण क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्रों को भारी बढ़ावा देगा।
राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड (NHLML), रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) और कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (KIADB) के बीच एक सरकारी SPV शामिल है।
MMLP का विकास समग्र माल ढुलाई लागत और समय को कम करने, कुशल भंडारण प्रदान करने, माल की ट्रैकिंग और ट्रेसबिलिटी में सुधार करने, जिससे माल ढुलाई की दक्षता में वृद्धि के लिए कुशल अंतर-मोडल माल ढुलाई को सक्षम करके देश के माल लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में सुधार करने के लिए भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए तीन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने 3 अलग-अलग समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए, और स्वतंत्र भारत के अमृतकाल में 'नए भारत की आधुनिक खादी' की आधारशिला रखी।
खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार की उपस्थिति में प्रसार भारती, NBCC (इंडिया) लिमिटेड और डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के साथ इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।
इन समझौता ज्ञापनों का उद्देश्य प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुसार खादी और ग्रामोद्योग आयोग को आधुनिक बनाने और युवाओं के बीच अपने उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक रोडमैप तैयार करना है।

मुख्य विचार

इस अवसर पर श्री कुमार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को 150 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी सब्सिडी वितरित की।
प्रसार भारती के साथ हुए MoU के मुताबिक, बहुत जल्द डीडी न्यूज और डीडी इंटरनेशनल चैनलों के एंकर खादी परिधानों में नजर आएंगे।
श्री कुमार ने दोहराया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में खादी अब आत्मनिर्भर भारत की पहचान बन गयी है।
ऐसे में प्रसार भारती के साथ यह समझौता होगासिद्ध करनायुवाओं के बीच खादी को लोकप्रिय बनाने में एक मील का पत्थर साबित होगा।
इसके साथ ही, NBCC (इंडिया) लिमिटेड देश भर में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के लिए नए आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करेगा और केवीआईसी को नवीनतम तकनीक के साथ अद्यतन रखने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, KVIC ने डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के साथ हाथ मिलाया है।

उपस्थितगण:

प्रसार भारती के उप महानिदेशक श्री संजय प्रसाद और KVIC के प्रचार निदेशक श्री संजीव पोसवाल ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर NBCC (इंडिया) लिमिटेड के मुख्य महाप्रबंधक श्री प्रदीप शर्मा और KVIC के संपदा एवं

सेवाओं के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री राजन बाबू और डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के मुख्य तकनीकी अधिकारी श्री देबरत नायक और केवीआईसी के सूचना प्रौद्योगिकी के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री राजन बाबू उपस्थित थे।

नवीनतम समाचार

अप्रैल 2023 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर तहसील के नानपुर गांव में ग्राम विकास योजना वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया था।
मई 2023 में, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) ने तवांग, अरुणाचल प्रदेश की हस्तनिर्मित कागज बनाने की कला को संरक्षित और पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

KVIC के बारे में:

स्थापना: 1957
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र
अध्यक्ष: मनोज कुमार
KVIC एक वैधानिक निकाय है जिसका गठन अप्रैल 1957 में भारत सरकार (भारत सरकार) द्वारा संसद के अधिनियम, 'खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956' के तहत किया गया था।
यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत एक शीर्ष संगठन है

ओडिशा सरकार ने विस्तार के लिए गोपालपुर बंदरगाह के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

ओडिशा सरकार ने गंजम जिले में सुविधा के आगे विकास और विस्तार के लिए गोपालपुर बंदरगाह के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
MoU पर हस्ताक्षर के बाद ओडिशा सरकार ने गोपालपुर बंदरगाह को 119 एकड़ से अधिक जमीन सौंप दी।
समझौता ज्ञापन पर वाणिज्य और परिवहन मंत्री तुकुनी साहू की उपस्थिति में निदेशक बंदरगाह और अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन, वाणिज्य और परिवहन विभाग, पद्मलोचन रौ और गोपालपुर पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के CEO ने हस्ताक्षर किए।
गोपालपुर बंदरगाह को 1986-87 तक ओडिशा सरकार द्वारा मौसमी लाइटरेज बंदरगाह के रूप में संचालित किया गया था।
बंदरगाह को PPP मोड में सभी मौसम के लिए प्रत्यक्ष बर्थिंग बंदरगाह में बदलने के लिए गोपालपुर पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किया गया था।

ओडिशा के बारे में:

राज्यपाल: गणेशी लाल
मुख्यमंत्री: नवीन पटनायक
पूंजी: भुवनेश्वर
राष्ट्रीय उद्यान: सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान
वन्यजीव अभयारण्य: उषाकोठी वन्यजीव अभयारण्य, टिकरपाड़ा वन्यजीव अभयारण्य

नवीनतम समाचार

जून 2023 में, ओडिशा सरकार और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (QCI), उद्योग संघों - एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (ASSOCHAM), फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI), इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स के सहयोग से प्रमोशन काउंसिल (EEPC), ओडिशा असेंबली ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (OASME), PHD चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI), सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (CIPET), फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्तरां एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FHRAI) - ओडिशा के भुवनेश्वर में ओडिशा गुणवत्ता संकल्प (ओडिशा गुणवत्ता मिशन) का शुभारंभ किया।

NHAI ने पुलों और अन्य संरचनाओं के डिजाइन और निर्माण को मजबूत करने के लिए DMRC के साथ सहयोग किया है

राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क, NHAI विभिन्न पुलों/संरचनाओं के डिजाइन, NHAI परियोजनाओं के सुरक्षा पहलुओं और NHAI अधिकारियों की क्षमता निर्माण की समीक्षा के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
NHAI के अध्यक्ष श्री संतोष कुमार यादव और DMRC के प्रबंध निदेशक डॉ. विकास कुमार के साथ-साथ NHAI और DMRC के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
यह पहल NHAI के 'डिज़ाइन डिवीजन' को मजबूत करेगी जो देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों, संरचनाओं, सुरंगों और आरई दीवारों की योजना, डिजाइन, निर्माण और रखरखाव की समीक्षा करता है।
इस समझौते के तहत, DMRC चल रही परियोजनाओं में सभी पुलों/संरचनाओं के डिजाइन की समीक्षा के लिए NHAI को सेवाएं प्रदान करेगी।
समझौते में बेतरतीब ढंग से चयनित पुलों, संरचनाओं, सुरंगों, आरई दीवारों और अन्य विशेष संरचनाओं के डिजाइन की समीक्षा भी शामिल है।
DMRC विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) चरण में स्टैंड-अलोन पुलों और विशेष संरचनाओं की समीक्षा में भी NHAI का समर्थन करेगा।
DMRC यादृच्छिक आधार पर निर्माण पद्धतियों, अस्थायी संरचनाओं, उठाने और लॉन्च करने के तरीकों, और चुनिंदा पुलों और संरचनाओं और विशेष संरचनाओं के पूर्व-तनाव के तरीकों की समीक्षा करने में भी NHAI की मदद करेगी।
इसके अलावा, DMRC NHAI अधिकारियों के क्षमता निर्माण के लिए अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसमें ऊंचे ढांचे और पुलों में डिजाइन, निर्माण, पर्यवेक्षण, रखरखाव और सुरक्षा पहलू शामिल होंगे।
यह समझौता दो वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा।
यह पहल राष्ट्र-निर्माण के लक्ष्य की दिशा में योगदान देने वाले परिवहन बुनियादी ढांचे के नेटवर्क को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और मिलकर काम करने के लिए दो सरकारी संगठनों के बीच सहयोग पर प्रकाश डालती है।

सी-डॉट और CSIR-राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ने दूरसंचार क्षेत्र के लिए NavIC आधारित IST ट्रेस करने योग्य प्राथमिक संदर्भ समय घड़ी के विकास के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए:

टेलीमैटिक्स के विकास केंद्र (सी-डॉट), दूरसंचार विभाग (DoT) के प्रमुख दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र और CSIR-राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (NPL) ने दूरसंचार के लिए 'NavIC-आधारित IST ट्रेसेबल प्राइमरी रेफरेंस टाइम क्लॉक (PRTC) के विकास' के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
ग्रामीण और ग्रामीण क्षेत्रों में किफायती ब्रॉडबैंड और मोबाइल सेवाओं को सक्षम करने के लिए दूरसंचार उत्पादों और समाधानों के प्रौद्योगिकी डिजाइन, विकास और व्यावसायीकरण में शामिल घरेलू कंपनियों और संस्थानों को वित्त पोषण सहायता प्रदान करने के लिए दूरसंचार विभाग की दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास निधि (TTDF) योजना के तहत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
यह परियोजना एक ऐसे उपकरण के विकास पर केंद्रित है जो ± 20 एनएस के भीतर सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (TSP) और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISP) को सीधे भारतीय मानक समय (IST) ट्रेसबिलिटी प्रदान करेगा।
इससे भारत को GPS पर निर्भरता कम करने, IRNSS/NavIC पर स्विच करने, लेनदेन के डिजिटल फोरेंसिक विश्लेषण, साइबर सुरक्षित नेटवर्क, कॉल ड्रॉप को कम करने और सभी दूरसंचार सेवाओं को एक संदर्भ समय स्रोत IST के साथ सिंक्रनाइज़ करने से लेकर कई तरीकों से लाभ होगा, जिसे द्वारा विकसित किया गया है।
दूरसंचार नेटवर्क का समय सिंक्रनाइज़ेशन एक मजबूत साइबर-सुरक्षित राष्ट्र की नींव होगी, क्योंकि प्रत्येक बैंक लेनदेन, शेयर बाजार लेनदेन और सूचना का आदान-प्रदान TSP और ISP के माध्यम से होता है।
NavIC-आधारित IST ट्रेसेबल प्राइमरी रेफरेंस टाइम क्लॉक (PRTC) का विकास एक पहल है जिसका उद्देश्य "एक राष्ट्र एक समय" के उद्देश्य को प्राप्त करना है।

इंडिया ग्लोबल फोरम और वर्ल्ड गवर्नमेंट्स समिट ने उभरती अर्थव्यवस्था कार्यक्रम विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

भारत वैश्विक मंच और विश्व सरकार शिखर सम्मेलन ने एक उभरती अर्थव्यवस्था कार्यक्रम विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
यह कार्यक्रम सतत आर्थिक विकास, भू-आर्थिक दृष्टिकोण और नवीन समाधानों पर उच्च स्तरीय चर्चा को बढ़ावा देने के लिए सरकारी अधिकारियों, व्यापारिक नेताओं, अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों सहित प्रमुख हितधारकों को बुलाएगा।
साझेदारी वैश्विक दक्षिण से संबंधित उभरते रुझानों, चुनौतियों और अवसरों पर शोध करने, विचार नेतृत्व को विकसित करने और बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित करेगी।
यह कार्यक्रम भविष्य की सरकारों के लिए क्षेत्र के डेटा को भी उत्तरोत्तर बढ़ाएगा।
समझौता ज्ञापन पर इंडिया ग्लोबल फोरम के संस्थापक और अध्यक्ष मनोज लाडवा और विश्व सरकार शिखर सम्मेलन के प्रबंध निदेशक मोहम्मद अल शरहान ने संयुक्त अरब अमीरात के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल अर्थव्यवस्था और दूरस्थ कार्य अनुप्रयोगों के राज्य मंत्री उमर सुल्तान अल ओलेमा की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।
विश्व सरकार शिखर सम्मेलन संगठन एक वैश्विक, तटस्थ, गैर-लाभकारी संगठन है जो सरकारों के भविष्य को आकार देने के लिए समर्पित है।
शिखर सम्मेलन, अपनी विभिन्न गतिविधियों में, मानवता के सामने आने वाली सार्वभौमिक चुनौतियों को हल करने के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए, अगली पीढ़ी की सरकारों के एजेंडे की पड़ताल करता है।

नॉर्वे के वित्तीय बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए TCS, बैंकआईडी बैंकएक्सेप्ट ने मिलकर काम किया

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने ओस्लो, नॉर्वे में एक ऑपरेशन कमांड सेंटर स्थापित करने और प्रबंधित करने के लिए नॉर्वे के वित्तीय बुनियादी ढांचे की धुरी BankID BankAxept AS के साथ एक रणनीतिक साझेदारी बनाई है।
इस सौदे का उद्देश्य देश के महत्वपूर्ण वित्तीय बुनियादी ढांचे की लचीलापन, सुरक्षा और उपलब्धता को बढ़ाना है।
नॉर्वे के वित्तीय बुनियादी ढांचे में अनुपालन और सुरक्षा संबंधी चिंताओं को संबोधित करना

BankID BankAxept की भूमिका:

BankID BankAxept AS नॉर्वे के वित्तीय परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, देश के 80% कार्ड भुगतान BankAxept कार्ड का उपयोग करके किए जाते हैं और 90% से अधिक आबादी इलेक्ट्रॉनिक पहचान के लिए BankID पर निर्भर है।
डिजिटल पहचान प्रमाणीकरण के आसपास विकसित हो रहे नियमों के साथ, मजबूत, विश्वसनीय और सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक पहचान समाधानों की अत्यधिक आवश्यकता है।
BankID BankAxept AS ने राष्ट्रीय भुगतान और इलेक्ट्रॉनिक पहचान सत्यापन प्रणालियों के प्रबंधन और निगरानी के लिए 24×7 संचालन कमांड सेंटर स्थापित करने के लिए TCS की सेवाओं को सूचीबद्ध किया है।

TCS की भूमिका:

24×7 परिचालन लचीलापन के लिए TCS की निगरानी ढांचा।
TCS कमांड सेंटर में एक समर्पित निगरानी ढांचा लागू करेगा जिसमें सक्रिय समस्या पहचान और समाधान के लिए उन्नत तंत्र शामिल होंगे।
यह ढांचा विशेषज्ञों और विक्रेताओं के साथ कुशल डेटा साझा करने में सक्षम होगा, जिससे त्वरित समस्या की पहचान और समाधान हो सकेगा।
केंद्र टीमों और विक्रेताओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में भी सक्षम होगा, जिससे भागीदारों से मूल्यवर्धित सेवाओं को एकीकृत करते हुए व्यवधानों, सुरक्षा अलर्ट या घटनाओं पर त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सकेगी।

BankAxept ने TCS क्यों चुना?

BankID BankAxept AS के सीईओ, ओयविंड वेस्टबी ब्रेके ने कहा, "वर्तमान में BankID का उपयोग नॉर्वे भर में 4.4 मिलियन उपयोगकर्ताओं द्वारा किया जाता है, और BankAxept 10 में से लगभग 8 इन-स्टोर भुगतान संभालता है। इन

प्रणालियों के किसी भी डाउनटाइम का देश के सार्वजनिक संस्थानों, व्यवसायों और नागरिकों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। हमने एक मिशन क्रिटिकल कमांड सेंटर बनाने के लिए एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी भागीदार के रूप में टीसीएस की ओर रुख किया, जो हमें किसी भी तकनीकी समस्या या सेवाओं में व्यवधान को तुरंत हल करने में मदद करेगा, और यह नॉर्वे की महत्वपूर्ण वित्तीय सेवाओं के बुनियादी ढांचे की लचीलापन और विश्वसनीयता सुनिश्चित करेगा।

BankID BankAxept के बारे में:

परिचय: 1991

देश: नॉर्वे

BankAxept नॉर्वे में राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली है, जिसमें 80% कार्ड भुगतान BankAxept कार्ड का उपयोग करके किया जाता है।

BankID नॉर्वेजियन ईआईडी सत्यापन समाधान है, जिस पर देश की 90% से अधिक आबादी, बैंक, सार्वजनिक संस्थान और वाणिज्यिक उद्यम निर्भर हैं।

TCS के बारे में:

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एक आईटी सेवा, परामर्श और व्यापार समाधान संगठन है जो 55 वर्षों से अधिक समय से दुनिया के कई सबसे बड़े व्यवसायों के साथ उनकी परिवर्तन यात्रा में साझेदारी कर रहा है।

हेमाकिरण गुप्ता, प्रमुख, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा - कॉन्टिनेंटल यूरोप, TCS

ONGC ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए NTPC ग्रीन के साथ समझौता किया

राज्य के स्वामित्व वाली तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) ने हरित हाइड्रोजन और अपतटीय पवन परियोजनाओं की स्थापना का पता लगाने के लिए NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ एक प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

MoU पर ONGC के कार्यकारी निदेशक देबदुलाल अधिकारी और NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (NGEL) के CEO मोहित भार्गव ने ONGC के अध्यक्ष और CEO अरुण कुमार सिंह और NTPC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

ONGC भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादक है जबकि NGEL देश की सबसे बड़ी बिजली उपयोगिता NTPC की सहायक कंपनी है।

ONGC के बारे में:

तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के स्वामित्व के तहत एक भारतीय केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।

कंपनी का मुख्यालय नई दिल्ली में है।

ONGC की स्थापना 14 अगस्त 1956 को भारत सरकार द्वारा की गई थी।

यह देश में सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाला तेल और गैस खोजकर्ता और उत्पादक है और कच्चे तेल के भारत के घरेलू उत्पादन का लगभग 70 प्रतिशत और प्राकृतिक गैस का लगभग 84 प्रतिशत उत्पादन करता है।

नवंबर 2010 में, भारत सरकार ने ONGC को महारत्न का दर्जा दिया।

NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में:

NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड भारत सरकार की एक असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी है।

स्थापित: 07 अप्रैल, 2022

मुख्यालय: नई दिल्ली

CEO: मोहित भार्गव

ONGC ने MRPL के साथ कच्चे तेल का समझौता किया

तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) लिमिटेड ने कच्चे तेल की बिक्री और खरीद के लिए मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (MRPL) के साथ कच्चे तेल की बिक्री समझौते (COSA) पर हस्ताक्षर किए हैं।

ONGC और MRPL के बीच मौजूदा समझौता 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगा।
MRPL के एक बयान में कहा गया है कि दोनों समूह की कंपनियों के बीच समझौते से तालमेल आने की उम्मीद है और मुंबई हाई में ONGC के क्षेत्रों से कच्चे तेल की बिक्री और खरीद लेनदेन को सुव्यवस्थित करने की उम्मीद है।
संजय कुमार, ONGC के कार्यकारी निदेशक (विपणन) और MRPL के समूह महाप्रबंधक (इम्पेक्स और शिपिंग) चंद्रमणि ने मैंगलोर में दोनों संस्थाओं की ओर से समझौते पर हस्ताक्षर किए।
MRPL के प्रबंध निदेशक संजय वर्मा, निदेशक (वित्त), बीएचवी प्रसाद, कार्यकारी निदेशक (परियोजनाएं), और श्यामप्रसाद कामथ कार्यकारी निदेशक (रिफाइनरी) उपस्थित थे।

MRPL के बारे में:

मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (MRPL), तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) का एक प्रभाग है जो भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के स्वामित्व में है।
1988 में स्थापित, रिफाइनरी मैंगलोर के केंद्र से उत्तर में कटिपल्ला में स्थित है।
रिफाइनरी की स्थापना पांच गांवों, अर्थात् बाला, कलावर, कुठेतूर, कतीपल्ला और आद्यापदी को विस्थापित करने के बाद की गई थी।

ब्रुकफील्ड एक्सिस एनर्जी के साथ संयुक्त उद्यम में $845 मिलियन तक का निवेश करेगी

ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट ने नवीकरणीय ऊर्जा विकास मंच स्थापित करने के लिए हैदराबाद स्थित एक्सिस एनर्जी वेंचर्स इंडिया के साथ एक संयुक्त उद्यम में प्रवेश किया है, जिसमें निवेश प्रबंधन कंपनी 845 मिलियन डॉलर तक का निवेश करेगी।
भारतीय फर्म पवन और सौर ऊर्जा परियोजनाओं की अपनी मौजूदा पाइपलाइन प्रदान करेगी जो देश में विकास के विभिन्न चरणों में हैं।
ब्रुकफील्ड अपने ब्रुकफील्ड ग्लोबल ट्रांज़िशन फंड II (BGTF II) के माध्यम से निवेश करेगा।

ऊर्जा सेवाएँ प्रदान की गईं:

साझेदारी के तहत, कंपनियां संयुक्त रूप से सरकारी संस्थाओं, कॉर्पोरेट ग्राहकों और उभरते उद्योगों जैसे ग्रीन हाइड्रोजन सहित विभिन्न उद्योग प्रतिभागियों को ऊर्जा समाधान प्रदान करेंगी।

ऊर्जा सुरक्षा का उद्देश्य:

उन्होंने कहा, 'सरकार के 2030 तक 500 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य और ऊर्जा सुरक्षा के घोषित उद्देश्य के कारण हम भारत में मजबूत वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं। ब्रुकफील्ड के प्रबंध निदेशक नवल सैनी ने कहा, "सौर, पवन और भंडारण जैसी कई प्रौद्योगिकियों के संयोजन से अक्षय परिसंपत्तियों को बढ़ाकर इस मांग को तेजी से पूरा किया जाएगा।
ब्रुकफील्ड के पास पूरे भारत में 16 गीगावॉट से अधिक पवन और सौर संपत्ति परिचालन में है या पाइपलाइन में है।
यह ब्रुकफील्ड का दूसरा संयुक्त उद्यम हैएक्सिस एनर्जी, और 2019 के बाद से, ब्रुकफील्ड और एक्सिस एनर्जी ने 1.8 गीगावॉट से अधिक सौर और पवन संपत्ति विकसित की है।

2022 में एक्सिस के साथ ब्रुकफील्ड:

इससे पहले 2022 में, ब्रुकफील्ड रिन्यूएबल इंडिया ने राजस्थान के जोधपुर में 445 मेगावाट क्षमता वाली अपनी पहली ग्रीनफील्ड सौर परियोजना शुरू की थी।
यह प्रोजेक्ट एक्सिस एनर्जी के साथ साझेदारी में विकसित किया गया था।
कंपनियों ने मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी और पुडुचेरी बिजली विभाग को बिजली बेचने के लिए एनटीपीसी के साथ 25 साल के बिजली खरीद समझौते पर भी हस्ताक्षर किए थे।

HP ने भारत में Chromebook बनाने के लिए Google के साथ सहयोग की घोषणा की

एचपी, कंप्यूटर और प्रिंटर के लिए एक प्रसिद्ध ब्रांड ने 'मेक इन इंडिया' पहल का समर्थन करते हुए, यहीं भारत में Chromebook बनाने के लिए Google के साथ मिलकर काम किया है।

ये क्रोमबुक डिवाइस चेन्नई के पास फ्लेक्स फैसिलिटी में बनाए जाएंगे, जहां एचपी अगस्त 2020 से लैपटॉप और डेस्कटॉप बना रहा है।
एचपी क्रोमबुक का यह उत्पादन 2 अक्टूबर से शुरू होगा, जो मुख्य रूप से भारत में शिक्षा क्षेत्र के लिए किफायती पीसी उपलब्ध कराने पर केंद्रित है।
विक्रम बेदी एचपी इंडिया के सीनियर डायरेक्टर-पर्सनल सिस्टम्स ने कहा कि भारत में क्रोमबुक लैपटॉप बनाने से भारतीय छात्रों के लिए बजट-अनुकूल पीसी प्राप्त करना आसान हो जाएगा।
यह कदम भारत सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल के अनुरूप भी है।

क्रोम के बारे में:

कंपनी के अनुसार, क्रोमबुक का शिक्षा में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, जिससे दुनिया भर में 50 मिलियन से अधिक छात्र और शिक्षक लाभान्वित होते हैं।
वे ChromeOS पर चलते हैं, आसान पहुंच और मजबूत सुरक्षा के लिए सुविधाएँ प्रदान करते हैं, जो शैक्षिक सेटिंग्स में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

एचपी के बारे में:

दिसंबर 2021 से, HP भारत में विभिन्न प्रकार के लैपटॉप का उत्पादन कर रहा है, जिसमें HP EliteBooks, HP ProBooks और HP G8 श्रृंखला नोटबुक शामिल हैं।
उन्होंने स्थानीय रूप से निर्मित वाणिज्यिक डेस्कटॉप के अपने लाइनअप का भी विस्तार किया है, जो ग्राहकों की विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न मॉडल पेश करता है, जिसमें इंटेल और एएमडी प्रोसेसर दोनों के विकल्प शामिल हैं।
एचपी और गूगल के बीच यह सहयोग न केवल 'मेक इन इंडिया' पहल को बढ़ावा देता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि भारत में छात्रों के पास किफायती और विश्वसनीय पीसी तक आसान पहुंच हो, जो आज के डिजिटल युग में उनकी शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

पुरस्कार और सम्मान

2023 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के विजेताओं में असम स्थित ऑन्कोलॉजिस्ट भी शामिल हैं

ऑन्कोलॉजिस्ट रवि कन्नन भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म श्री के प्राप्तकर्ता और असम के कछार कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र (CCHRC) के निदेशक को एशिया के नोबेल पुरस्कार के समकक्ष, 2023 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के चार विजेताओं में से एक नामित किया गया है।

मुख्य विचार

डॉ. कन्नन चेन्नई के रहने वाले हैं, जहां उन्होंने 2007 में सिलचर जाने से पहले कैंसर संस्थान, अड्यार में काम किया था।
वह उस वर्ष CCHRC के निदेशक बने।
रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन की वेबसाइट के उद्धरण के अनुसार, डॉ. कन्नन के नेतृत्व में, CCHRC एक पूर्ण विकसित व्यापक कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र बन गया।
जब वह बोर्ड में आए थे तब सीमित सुविधाओं के बाद, अस्पताल में अब 28 विभाग हैं जिनमें ऑन्कोलॉजी, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, महामारी विज्ञान, ट्यूमर रजिस्ट्री और उपशामक देखभाल शामिल हैं।
23 कर्मियों से, अस्पताल अब 451 व्यक्तियों को रोजगार देता है।
उद्धरण में कहा गया है कि सीसीएचआरसी अब सालाना औसतन 5,000 नए रोगियों को मुफ्त या रियायती कैंसर देखभाल उपचार प्रदान करता है, लगभग 20,000 गरीब रोगियों को उपचार और फॉलो-अप प्रदान करता है।

नवीनतम समाचार

जून 2023 में, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के तहत असम में गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता, पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए FSSAI द्वारा 'ईट राइट स्टेशन' प्रमाणन से सम्मानित किया गया।

असम के बारे में:

राज्यपाल: गुलाब चंद कटारिया

मुख्यमंत्री: हिमंत बिस्वा सरमा
राजधानी: दिसपुर
राष्ट्रीय उद्यान: काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान
वन्यजीव अभयारण्य: चक्रशिला वन्यजीव अभयारण्य, बोरनाडी वन्यजीव अभयारण्य

विजयवाड़ा को प्लैटिनम रेटिंग के साथ IGBC का 'ग्रीन रेलवे स्टेशन' प्रमाणन मिला

विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (IGBC) द्वारा प्लैटिनम की उच्चतम रेटिंग के साथ 'ग्रीन रेलवे स्टेशन' प्रमाणन से सम्मानित किया गया।
यह स्टेशन की रेटिंग का अपग्रेड है, 2019 में गोल्ड से 2023 में प्लैटिनम तक।
इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (IGBC) भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) का हिस्सा है और इसका गठन वर्ष 2001 में किया गया था।
यह भारत की प्रमुख प्रमाणन संस्था है।
परिषद सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है, जिसमें नए हरित भवन रेटिंग कार्यक्रम, प्रमाणन सेवाएँ और हरित भवन प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करना शामिल है।
परिषद ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस का भी आयोजन करती है, जो हरित भवनों पर अपना वार्षिक प्रमुख कार्यक्रम है।
यह उन 5 देशों में से एक है जो वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के बोर्ड में शामिल हैं, जो सीओपी और इसी तरह के वैश्विक मंचों पर वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करते हैं।
रेटिंग छह पर्यावरण श्रेणियों पर आधारित है, जिसमें टिकाऊ स्टेशन सुविधा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और स्वच्छता, ऊर्जा दक्षता, जल दक्षता, स्मार्ट और हरित पहल और नवाचार और विकास शामिल हैं।

2022 में 12 प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किए गए हैं

देश के शीर्ष वार्षिक विज्ञान पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कारों की घोषणा दो साल के अंतराल के बाद की गई थी।
इस वर्ष 12 वैज्ञानिकों को सात श्रेणियों में पुरस्कार मिलेंगे।
CSIR के महानिदेशक डॉ. एन. कलैसेल्वी केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में वर्ष 2022 के पुरस्कारों की घोषणा की।
ये पुरस्कार CSIR के पहले निदेशक शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर हैंमें दियासात वैज्ञानिकअनुशासन: भौतिकी, जीव विज्ञान, इंजीनियरिंग, गणित, चिकित्सा, रसायन विज्ञान और पृथ्वी विज्ञान।
CSIRNIScPR में 'वन वीक वन लैब' कार्यक्रम शुरू हुआ जो 16 सितंबर तक जारी रहेगा।
यह एक अभियान है जिसके दौरान CSIR की प्रत्येक प्रयोगशाला एक सप्ताह के दौरान देश के लोगों के सामने अपने विशिष्ट विचारों और तकनीकी सफलताओं का प्रदर्शन करती है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि भविष्य में 'वन वीकवन लैब' की तर्ज पर CSIR 'वन मंथ वन थीम' अभियान के माध्यम से अपनी इकाइयों के योगदान को आम जनता तक फैलाने का अवसर लेगा।
पुस्तकें'संग्रह' नाम दिया गया हैविज्ञान प्रगति पत्रिका' और 'CSIR@80 एक फोटो यात्रा' के 80 लेखों में सेथेइस अवसर पर केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च किया गया।

नोबेल फाउंडेशन ने इस वर्ष के नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की, जिन्हें अतिरिक्त दस लाख मुकुट मिलेंगे

नोबेल फाउंडेशन ने घोषणा की है कि इस साल के नोबेल पुरस्कार विजेताओं को अतिरिक्त दस लाख मुकुट मिलेंगे।
इसका मतलब है कि 2023 के पुरस्कार विजेताओं को कुल 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन का वित्तीय पुरस्कार मिलेगा जो लगभग 986,000 डॉलर (8.1 करोड़) के बराबर है
इस वृद्धि ने इस साल के नकद पुरस्कार को नोबेल पुरस्कार के 100 से अधिक वर्षों के इतिहास में दिया जाने वाला सबसे मूल्यवान पुरस्कार बना दिया है।

हाल के वर्षों में पुरस्कार राशि को ऊपर-नीचे समायोजित किया गया है।
2012 में, फाउंडेशन ने अपने वित्त को मजबूत करने के लिए पुरस्कार राशि को 10 मिलियन क्राउन से घटाकर 8 मिलियन कर दिया।
हालाँकि, दशक के अंत में पुरस्कार राशि को धीरे-धीरे बढ़ाकर 10 मिलियन क्राउन कर दिया गया।
पुरस्कार देने वालों के अनुसार, इस वर्ष राशि में और वृद्धि फाउंडेशन की मजबूत वित्तीय स्थिति को दर्शाती है।
इस साल के नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा अगले महीने की जाएगी।
पुरस्कार विजेता होंगेतो हो10 दिसंबर को पुरस्कार समारोहों में अपने पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जो 1896 में पुरस्कार संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु की सालगिरह है।
प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार ओस्लो में दिया जाता है, जबकि अन्य पुरस्कार समारोह स्टॉकहोम में आयोजित किए जाते हैं।

84 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रदर्शन कला के विभिन्न क्षेत्रों के 84 कलाकारों को एक बार का संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान किया।
नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदर्शन कला के क्षेत्र में प्रदर्शन करने वाले कलाकारों के साथ-साथ शिक्षकों और विद्वानों को दिया जाने वाला एक राष्ट्रीय सम्मान है।
प्राप्तकर्ताओं का चयन अकादमी की सामान्य परिषद द्वारा किया जाता है।

मुख्य विचार

अकादमी की सामान्य परिषद में इन विषयों के प्रतिष्ठित संगीतकार, नर्तक, थिएटर कलाकार और विद्वान और भारत सरकार, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के नामांकित व्यक्ति शामिल थे।
इस सम्मान में 1,00,000 रुपये (एक लाख रुपये) की पर्स राशि के अलावा एक ताम्रपत्र और अंगवस्त्र शामिल हैं।
यह पुरस्कार 75 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय कलाकारों को सम्मानित करने के लिए गठित किया गया था, जिन्हें अब तक अपने करियर में कोई राष्ट्रीय सम्मान नहीं दिया गया है।
इसे शिक्षा मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष पीवी राजमन्नार थे।
इसकी स्थापना 1953 में संगीत, नृत्य और नाटक के रूपों में व्यक्त भारत की विविध संस्कृति की विशाल अमूर्त विरासत के संरक्षण और प्रचार के लिए की गई थी।
वर्तमान में, यह संस्कृति मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय है।
अकादमी के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा पाँच वर्ष की अवधि के लिए की जाती है।
यह अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित है।

ओडिशा की वैज्ञानिक स्वाति नायक ने नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जीता

विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा स्थापित इस पुरस्कार का नाम नोबेल पुरस्कार विजेता और हरित क्रांति के मुख्य वास्तुकार डॉ नॉर्मन ई बोरलॉग के सम्मान में रखा गया है।
ओडिशा की वैज्ञानिक डॉ. स्वाति नायक को भोजन और पोषण के क्षेत्र में उनके काम के लिए क्षेत्रीय अनुसंधान और अनुप्रयोग के लिए नॉर्मन ई. बोरलॉग पुरस्कार के 2023 प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया है।

स्वाति नायक के बारे में:

अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (IRRI) में बीज प्रणाली और उत्पाद प्रबंधन के लिए एक वैज्ञानिक और दक्षिण एशिया प्रमुख डॉ. नायक को किसानों को मांग-संचालित चावल बीज प्रणालियों में शामिल करने के उनके अभिनव दृष्टिकोण के लिए पुरस्कार के लिए चुना गया था।
वह यह पुरस्कार पाने वाली तीसरी भारतीय और पहली ओडिशा हैं।
उन्होंने अब तक एशिया और अफ्रीका के विविध पारिस्थितिकी तंत्रों में हजारों छोटे किसानों के साथ काम करते हुए, 500 से अधिक चावल की किस्मों के लिए 10,000 से अधिक व्यापक ऑन-फार्म परीक्षणों का आयोजन किया है।

ओडिशा में, नायक और उनकी टीम ने सूखा-सहिष्णु चावल की किस्म 'शाहभागी धन' पेश करने की रणनीति बनाई, जो हर किसान परिवार के आहार और फसल चक्र का एक अभिन्न अंग बनी हुई है। इसके लिए, उन्हें स्थानीय समुदायों द्वारा 'बिहाना दीदी' के नाम से जाना जाता है।

ओडिशा के बारे में:

राज्यपाल: गणेशी लाल
मुख्यमंत्री: नवीन पटनायक
राजधानी: भुवनेश्वर
राष्ट्रीय उद्यान: सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान
वन्यजीव अभयारण्य: उषाकोठी वन्यजीव अभयारण्य, टिकरपाड़ा वन्यजीव अभयारण्य

वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने घोषणा की है कि इस वर्ष के दादा साहेब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्तकर्ता अनुभवी अभिनेत्री वहीदा रहमान होंगे।
महान अभिनेता ने गाइड और रेशमा और शेरा जैसी फिल्मों में काम किया है।
वहीदा ने अपने अभिनय की शुरुआत तेलुगु फिल्म रोजुलु मराई (1955) से की थी। उन्होंने प्यासा (1957), गाइड (1965), खामोशी (1969), फागुन (1973), कभी कभी (1976), चांदनी (1989), लम्हे (1991), रंग दे बसंती (2006), और दिल्ली 6 (2009) जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया है।
पिछले साल इसे आशा पारेख को प्रस्तुत किया गया था।
इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के पिछले प्राप्तकर्ताओं में रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, गुलज़ार, प्राण, पृथ्वीराज कपूर, मनोज कुमार, शशि कपूर, मन्ना डे और विनोद खन्ना (मरणोपरांत) शामिल हैं।

दादा साहब फाल्के के बारे में:

दादा साहब फाल्के, जिन्हें 'भारतीय सिनेमा के पितामह' के रूप में जाना जाता है, ने अपने लगभग दो दशक लंबे फिल्म निर्माण करियर के दौरान 27 लघु फिल्मों और 90 से अधिक पूर्ण लंबाई वाली फिल्मों का निर्देशन किया।
उनके निधन के दो दशक बाद, भारत सरकार ने 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत की, जिसमें कला और सिनेमा में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए व्यक्तियों को सम्मानित किया गया।

नीता अंबानी को प्रतिष्ठित सिटीजन ऑफ मुंबई अवॉर्ड मिला

रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति में उनके योगदान के लिए रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा 'सिटीजन ऑफ मुंबई' पुरस्कार 2023-24 से सम्मानित किया गया।

नीता अंबानी की उपलब्धियां:

अंबानी इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे सफल क्रिकेट टीमों में से एक मुंबई इंडियंस के मालिक हैं।
इसके अतिरिक्त, अंबानी फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड के संस्थापक और अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, जिसने इंडियन सुपर लीग की शुरुआत की।
वह 'सभी के लिए शिक्षा और खेल' पहल की भी प्रमुख हैं, जो बच्चों के विकास का समर्थन करती है।
इसके अलावा, अंबानी एमआई न्यूयॉर्क के मालिक हैं, जिसने एक पेशेवर अमेरिकी टी20 लीग, मेजर लीग क्रिकेट (MLC) का उद्घाटन संस्करण जीता था।
वह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला हैं।
नीता अंबानी ने न्यूयॉर्क में मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के बोर्ड के मानद ट्रस्टी के रूप में चुनी जाने वाली पहली भारतीय बनकर भी इतिहास रचा है, जो व्यवसायी और परोपकारी व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
कला में अपने काम के अलावा, नीता अंबानी मुंबई में सर एचएन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के माध्यम से सभी भारतीयों को सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए भी समर्पित हैं।

Click Here to Subscribe Our Yearly Mock Test Package

सांस्कृतिक केंद्र, नीता मुकेश अंबानी सांस्कृतिक केंद्र, जिसकी स्थापना और अध्यक्षता नीता अंबानी ने की, का उद्देश्य भारतीय कलाओं को संरक्षित और बढ़ावा देना है।
इसके पीछे का दृष्टिकोण एक ऐसा मंच बनाना था जहां भारत और दुनिया भर के समुदाय एक साथ आ सकें, अपनी प्रतिभा दिखा सकें और एक-दूसरे की संस्कृतियों के बारे में जान सकें।

सिंगापुर के मैडम तुसाद संग्रहालय में विराट कोहली की मोम की प्रतिमा का उद्घाटन किया जाएगा

भारतीय क्रिकेट के दिग्गज विराट कोहली एक प्रतिष्ठित सम्मान पाने के लिए तैयार हैं क्योंकि सिंगापुर के मैडम तुसाद संग्रहालय में उनकी मोम की प्रतिमा स्थापित की जाएगी।
यह उल्लेखनीय उपलब्धि कोई आश्चर्य की बात नहीं है, यह देखते हुए कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान के पास पहले से ही दिल्ली के मैडम तुसाद में एक मोम प्रतिकृति है, जिसका 2018 में अनावरण किया गया था।
कोहली की मोम की प्रतिमा के निर्माण में एक जटिल प्रक्रिया शामिल थी, जिसमें एक समर्पित बैठक सत्र के दौरान ली गई 200 से अधिक मापों और तस्वीरों के उपयोग के माध्यम से उनकी समानता को सावधानीपूर्वक कैप्चर किया गया था।

अन्य किंवदंतियों की मोम की मूर्ति:

सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, लियोनेल मेस्सी और उसेन बोल्ट जैसे अन्य खेल दिग्गज भी अपने मोम समकक्षों के साथ मैडम तुसाद के हॉल की शोभा बढ़ाते हैं।
हालाँकि, यह उल्लेखनीय है कि केवल तीन क्रिकेटरों, अर्थात् कोहली, तेंदुलकर और कपिल को मैडम तुसाद टीम द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार की गई मोम की मूर्तियों से सम्मानित किया गया है।

मैडम तुसाद के बारे में:

विश्व स्तर पर प्रसिद्ध मोम संग्रहालय श्रृंखला मैडम तुसाद की जड़ें 18वीं सदी के फ्रांस में हैं।
प्रतिभाशाली मैरी तुसाद द्वारा स्थापित, इस प्रतिष्ठित आकर्षण ने दुनिया भर के दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है।
उत्साही पर्यटक मशहूर हस्तियों, ऐतिहासिक शख्सियतों और सांस्कृतिक प्रतीकों की सजीव मोम की आकृतियों को देखकर आश्चर्यचकित होने के लिए मैडम तुसाद संग्रहालय में आते हैं।
प्रत्येक आकृति को बड़ी मेहनत से बनाया गया है, यहां तक कि सबसे जटिल विवरण और अभिव्यक्तियों को भी उल्लेखनीय सटीकता के साथ कैप्चर किया गया है।
लंदन, न्यूयॉर्क और हांगकांग सहित दुनिया भर के प्रमुख शहरों में शाखाओं के साथ, मैडम तुसाद ने खुद को दृढ़ता से उन लोगों के लिए एक जरूरी गंतव्य के रूप में स्थापित किया है जो समय के साथ हमेशा के लिए जमी हुई प्रसिद्धि की एक झलक पाने के लिए उत्सुक हैं।

गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के जनसंपर्क अधिकारी निखिल वाघ को पुरस्कार से सम्मानित किया गया

निखिल मुकुंद वाघ भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन कंपनी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के जनसंपर्क अधिकारी को नई दिल्ली में "प्रोमिसिंग पीआर पर्सन ऑफ द ईयर" पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
यह पुरस्कार दिल्ली में पब्लिक रिलेशंस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में दिया गया।
यह पुरस्कार रक्षा मामलों की संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष और सांसद जुएल ओराम द्वारा दिया गया और इस अवसर पर पर्यटन विभाग के पूर्व सचिव विनोद जुत्शी, PRCI के मुख्य मार्गदर्शक जयराम और PRCI की राष्ट्रीय अध्यक्ष गीता शंकर ने कार्यक्रम में भाग लिया।
वाघ को जनसंपर्क, कॉर्पोरेट संचार और मीडिया पेशेवरों की उपस्थिति में पुरस्कार प्रदान किया गया।

निखिल मुकुंद वाघ के बारे में:

डॉ. वाघ, जो मूल रूप से बार्शी के रहने वाले हैं।
बाबासाहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, छत्रपति संभाजीनगर से जनसंचार में स्नातक की उपाधि प्राप्त की।
लोकमत और ABP माझा में कार्यकाल के बाद, उन्होंने 2011 में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL) के PRO-जनसंपर्क अधिकारी के रूप में पदभार संभाला।

वाघ ने समय के कदमों को पहचानते हुए गोवा शिपयार्ड को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ला दिया, जिससे गोवा शिपयार्ड के काम को लाखों लोगों तक पहुंचने में मदद मिली।

'2018-हर कोई हीरो है' ऑस्कर 2024 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि

भारतीय फिल्म उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, मलयालम फिल्म "2018 - एवरीवन इज ए हीरो" को 2024 में होने वाले 96वें अकादमी पुरस्कार, जिसे ऑस्कर के रूप में भी जाना जाता है, के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है।
निर्देशित प्रतिभाशाली फिल्म निर्माता जूड एंथनी जोसेफ द्वारा, फिल्म "2018 - एवरीवन इज ए हीरो" ने अपनी सम्मोहक कहानी, उल्लेखनीय प्रदर्शन और 2018 में केरल में आई भीषण बाढ़ के आसपास की घटनाओं की विचारशील खोज के लिए आलोचकों की प्रशंसा और बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल की है, जिसने इस क्षेत्र को तबाह कर दिया था।
यह फिल्म आम लोगों के जीवन और इस आपदा के सामने उनकी वीरता के इर्द-गिर्द घूमती है, इस विचार पर जोर देती है कि नायक सबसे अप्रत्याशित स्थानों से भी उभर सकते हैं।
भारत की ओर से आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में, यह फिल्म ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए नामांकन सूची में शामिल होने के लिए प्रतिस्पर्धा करेगी।
यह मलयालम फिल्म उद्योग के लिए एक जबरदस्त सम्मान है और इस क्षेत्र में पाई जाने वाली असाधारण सिनेमाई प्रतिभा का प्रमाण है।

समाचार में आवेदन

गीतिका श्रीवास्तव को पाकिस्तान में मिशन का नेतृत्व करने वाली भारत की पहली महिला राजनयिक नियुक्त किया गया

भारतीय विदेश सेवा (IFS) की 2005 बैच की अधिकारी गीतिका श्रीवास्तव ने इस्लामाबाद, पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग में पहली महिला चार्ज डी'अफेयर्स (CDA) बनकर इतिहास रच दिया है।
श्रीवास्तव की नियुक्ति के बाद सुरेश कुमार का कार्यकाल होगा, जो जल्द ही नई दिल्ली लौटने वाले हैं।
साद वाराइच, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय में अफगानिस्तान, ईरान और तुर्की डेस्क के वर्तमान महानिदेशक, नई दिल्ली में नए प्रभारी डी'एफ़ेयर की भूमिका निभाएंगे।

गीतिका श्रीवास्तव के बारे में:

श्रीवास्तव ने 2007-09 के दौरान चीन में भारतीय दूतावास में सेवा की है।
वह कोलकाता में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय और विदेश मंत्रालय में हिंद महासागर क्षेत्र प्रभाग के निदेशक के रूप में भी काम कर चुकी हैं।
अपने नए कार्यभार से पहले, उन्होंने विदेश मंत्रालय (MEA) के इंडो-पैसिफिक डिवीजन में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य किया।

मुख्य विचार:

श्रीवास्तव का कार्यभार एक चुनौतीपूर्ण समय में आया है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच राजनयिक संबंध पाकिस्तानी धरती से पनप रहे आतंकवाद सहित विभिन्न कारकों के कारण तनावपूर्ण हो गए हैं।
अगस्त 2019 में भारत द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने, जिसने जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप इस्लामाबाद ने नई दिल्ली के साथ राजनयिक संबंधों को कम कर दिया।
पिछले 76 वर्षों में पाकिस्तान में भारत का प्रतिनिधित्व हमेशा पुरुष राजनयिकों ने किया है।
1947 से, जब नई दिल्ली ने श्री प्रकाश को इस्लामाबाद में पहले भारतीय उच्चायुक्त के रूप में भेजा, तब से 22 मिशन प्रमुख हो चुके हैं।
अजय बिसारिया इस्लामाबाद में अंतिम भारतीय उच्चायुक्त को भारत के साथ राजनयिक संबंधों को कम करने के पाकिस्तान के फैसले के बाद वापस ले लिया गया था।

पाकिस्तान के बारे में:
पूंजी: इस्लामाबाद
मुद्रा: रुपया
अध्यक्ष: आरिफ अल्वी

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना को सिंगापुर के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया

न्यायमूर्ति रमण ने सिंगापुर के कानून मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग (UNCITRAL) और 20 से अधिक भागीदार संगठनों द्वारा आयोजित वार्षिक सम्मेलन 'सिंगापुर कन्वेंशन वीक' में भाग लिया।

एनवी रमना के बारे में:
एनवी रमन्ना एक पूर्व भारतीय न्यायाधीश और पत्रकार हैं जिन्होंने भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया।
वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे।
वह आंध्र प्रदेश न्यायिक अकादमी के अध्यक्ष भी रहे हैं।

SIMC के बारे में:
स्थापना: 2014
अध्यक्ष: जॉर्ज लिम
CEO: वी मेंग चुआन
SIMC सिंगापुर में एक स्वतंत्र गैर-लाभकारी संगठन है जो अपने अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थों के पैनल के माध्यम से अपने सीमा पार वाणिज्यिक विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के इच्छुक पक्षों को मध्यस्थता सेवाएं प्रदान करता है।

इंडियन ऑयल ने शेफ संजीव कपूर को इंडेन XTRATEJ LPG के लिए ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (इंडियन ऑयल - IOCL) रणनीतिक रूप से वाणिज्यिक और औद्योगिक एलपीजी क्षेत्र में अपनी उपस्थिति का विस्तार कर रहा है और इसके लिए इंडियन ऑयल ने सेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर को अपने इंडेन XTRATEJ एलपीजी ब्रांड के ब्रांड एंबेसडर के रूप में चुना है।
इस सहयोग के संबंध में घोषणा कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित 'इंडेन एक्स्ट्रातेज होटलियर हार्मनी मीट' के दौरान हुई।
वी.सतीश कुमार, इंडियन ऑयल के निदेशक (विपणन) ने इंडेन XTRATEJ एलपीजी ब्रांड के लिए बिल्कुल नए वीडियो विज्ञापन का अनावरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
इंडियनऑयल ने एक नया नियामक और LPG नली पेश करने की योजना बनाई है, जो होटल और आतिथ्य जैसे क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है।

IOCL के बारे में:
स्थापना: 30 जून 1959
मुख्यालय: नई दिल्ली, दिल्ली
अध्यक्ष: श्रीकांत माधव वैद्य
IOCL भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के स्वामित्व में एक भारतीय बहुराष्ट्रीय तेल और गैस कंपनी है।

श्रीमती जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया गया

कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने श्रीमती की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त की गईं।
1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना के बाद से वह भारतीय रेलवे में यह प्रतिष्ठित पद संभालने वाली पहली महिला हैं।

वह अनिल कुमार लाहोटी का स्थान लेंगी, जिनका कार्यकाल 31 अगस्त, 2023 को समाप्त हुआ।
उनकी नियुक्ति 31 अगस्त, 2024 तक प्रभावी है।

जया वर्मा सिन्हा के बारे में:

जया वर्मा सिन्हा ने 1988 में भारतीय रेलवे यातायात सेवा (IRTS) में अपना करियर शुरू किया।
भारतीय रेलवे में अपने 35 साल के करियर में, उन्होंने सदस्य (संचालन और व्यवसाय विकास) रेलवे बोर्ड और अतिरिक्त सदस्य, यातायात परिवहन, रेलवे बोर्ड सहित विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है।
विशेष रूप से, वह दक्षिण पूर्व रेलवे की प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला थीं।
उन्होंने बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायोग में रेलवे सलाहकार के रूप में काम किया था, जिसके दौरान कोलकाता से ढाका तक प्रसिद्ध मैत्री एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया था।
उसकी नियुक्ति के समयवह रेलवे बोर्ड में सदस्य (संचालन और व्यवसाय विकास) के रूप में कार्यरत थीं।

रेल मंत्रालय के बारे में:

कैबिनेट मंत्री: अश्विनी वैष्णव
राज्य मंत्री: रावसाहेब दानवे, दर्शना जरदोश

ब्रिस ओलिगुई न्गुएमा गैबॉन के संक्रमणकालीन राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे

ब्रिगेडियर जनरल ब्राइस क्लोटायर ओलिगुई न्गुएमा, गैबोनीज़ रिपब्लिकन गार्ड के कमांडर-इन-चीफ को गैबॉन के "संक्रमणकालीन राष्ट्रपति" के रूप में शपथ दिलाई जाएगी।
वह संस्थानों के परिवर्तन और बहाली के लिए समिति के अध्यक्ष का पद भी संभालेंगे।
ट्रांज़िशन के राष्ट्रपति, ब्राइस क्लोटायर ओलिगुई न्गुएमा का शपथ ग्रहण समारोह 4 सितंबर, 2023 को निर्धारित है।
समारोह गणतंत्र के प्रेसीडेंसी में संवैधानिक न्यायालय के समक्ष होगा।
यह विकास गैबोनीज़ इलेक्शन सेंटर की पुष्टि के बाद हुआ है कि निवर्तमान राष्ट्रपति बोंगो ने आधिकारिक तौर पर 64.27% वोट के साथ जीतकर राष्ट्रपति के रूप में तीसरा कार्यकाल हासिल कर लिया है।
2022 में नाइजर और माली में इसी तरह की घटनाओं के बाद गैबॉन सैन्य तख्तापलट का अनुभव करने वाला नवीनतम अफ्रीकी देश बन गया है।

गैबॉन के बारे में:

पूंजी: लिब्रेविल
मुद्रा: मध्य अफ़्रीकी CFA फ़्रैंक

CCI महानिदेशक अतुल वर्मा को कार्यकाल में 3 महीने का विस्तार मिला

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने अपने महानिदेशक (DG) अतुल वर्मा को 1 सितंबर, 2023 से प्रभावी 3 महीने का विस्तार दिया है।
अब वह 30 नवंबर 2023 तक पद पर रहेंगे।
यह दूसरी बार है जब अतुल वर्मा का प्रतिनियुक्ति कार्यकाल बढ़ाया गया है।
मई, 2023 में CCI ने उनकी प्रतिनियुक्ति को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया था, शुरुआत में अगस्त के अंत तक।

अतुल वर्मा के बारे में:

हिमाचल प्रदेश कैडर के 1991 बैच के IPS अधिकारी अतुल वर्मा ने जून 2020 में 3 साल के कार्यकाल के लिए डीजी का पद संभाला।
महानिदेशक CCI के भीतर स्वतंत्र जांच प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है।
विशेष रूप से, महानिदेशक की नियुक्ति की शक्ति पहले कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) के पास थी।
हालाँकि, प्रतिस्पर्धा अधिनियम में हाल के संशोधनों ने इस अधिकार को CCI को स्थानांतरित कर दिया।

जुलाई, 2023 में सरकार ने भर्ती नियमों, विशेष रूप से "भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (महानिदेशक) भर्ती नियम, 2009" में संशोधन किया।
इन परिवर्तनों ने महानिदेशक की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार चयन समिति की संरचना में भी बदलाव किया।
पहले, समिति की अध्यक्षता कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) के सचिव करते थे।

CCI के बारे में:

स्थापना: 14 अक्टूबर 2003
मुख्यालय: नई दिल्ली, दिल्ली
अध्यक्ष: रवनीत कौर
CCI भारत में मुख्य राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नियामक है।
यह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के भीतर एक वैधानिक निकाय है और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और भारत में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।

भारतीय मूल के अर्थशास्त्री शनमुगरत्नम ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की

भारतीय मूल के सिंगापुर के अर्थशास्त्री और पूर्व वरिष्ठ मंत्री थर्मन शनमुगरत्नम (66 वर्ष) को सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है।
वह सिंगापुर की पहली महिला राष्ट्रपति हलीमा याकूब का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 13 सितंबर, 2023 को समाप्त होगा।
यह जीत विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि यह दस वर्षों के अंतराल के बाद आई है, जो 2011 के बाद से देश का पहला राष्ट्रपति चुनाव है।
थर्मन शनमुगरत्नम ने दो चीनी मूल के दावेदारों, एनजी कोक सॉन्ग (15.7%) और टैन किन लियान (13.88%) को हराकर 70.4% वोट हासिल किए।
सेल्लापन रामनाथन और चेंगारा वीटिल देवन नायर के बाद थर्मन सिंगापुर के तीसरे भारतीय मूल के राष्ट्रपति होंगे।

थर्मन शनमुगरत्नम के बारे में:

थर्मन शनमुगरत्नम 2001 में राजनीति में शामिल हुए।
उन्होंने 2011 से 2014 तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की नीति सलाहकार समिति, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय समिति (IMFC) की अध्यक्षता की, और पहले एशियाई अध्यक्ष बने।
उन्होंने 2011 से 2019 तक सिंगापुर के उप प्रधान मंत्री के रूप में कार्य किया था।
2017 में, उन्हें वैश्विक वित्तीय प्रशासन पर G20 प्रख्यात व्यक्ति समूह की अध्यक्षता के लिए नियुक्त किया गया था।
उन्होंने 2019 और 2023 के बीच सिंगापुर के वरिष्ठ मंत्री, 2015 और 2023 के बीच सामाजिक नीतियों के समन्वय मंत्री और 2011 और 2023 के बीच सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।
उन्होंने 2014 और 2023 के बीच आर्थिक विकास बोर्ड (EDB) की अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (IAC) की अध्यक्षता की।

सिंगापुर के बारे में:

प्रधान मंत्री: ली सीन लूंग
राजधानी: सिंगापुर
मुद्रा: सिंगापुर डॉलर

उदय कोटक ने कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO पद से इस्तीफा दिया; दीपक गुप्ता ने अंतरिम नेतृत्व संभाला

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड (KMBL) के संस्थापक और लंबे समय से प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) उदय कोटक ने 31 दिसंबर, 2023 तक अपना कार्यकाल समाप्त होने से पहले 1 सितंबर, 2023 को अपनी भूमिका से इस्तीफा दे दिया।
उन्होंने 38 वर्षों में बैंक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 5 वर्षों तक गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में बने रहेंगे।
दीपक गुप्ता संयुक्त प्रबंध निदेशक, 31 दिसंबर, 2023 तक अंतरिम MD और CEO के रूप में कार्यरत हैं।

उनकी नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और बैंक के सदस्यों द्वारा अनुमोदन के अधीन है।

उदय कोटक के बारे में:

उदय कोटक कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक और प्रमोटर हैं।

वह 1 अगस्त 2002 से कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड (पहले कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के प्रबंध निदेशक और CEO रहे हैं।

वह वर्तमान में इंडो-यूके फाइनेंशियल पार्टनरशिप (IUKFP) के सह-अध्यक्ष और कॉर्पोरेट दिवाला और परिसमापन (भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड) पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं।

वह सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार पैनल, सिंगापुर सरकार के निवेश निगम के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड और भारत के आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड की निवेश सलाहकार समिति में भी हैं।

उन्होंने IL&FS बोर्ड के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया और NBFC के गहरे संकट को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

1 अक्टूबर, 2018 से 2 अप्रैल, 2022 तक, उन्होंने NBFC को गहरे संकट से बाहर निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित IL&FS बोर्ड के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।

दीपक गुप्ता के बारे में:

दीपक गुप्ता, जो जनवरी 1999 से KMBL के पूर्णकालिक निदेशक हैं।

उन्हें 1 जनवरी 2012 को संयुक्त प्रबंध निदेशक के रूप में नामित किया गया था।

उन्होंने आईटी, साइबर सुरक्षा, डिजिटल पहल, आंतरिक लेखा परीक्षा, मानव संसाधन, विपणन, अनुपालन, प्रशासन, बुनियादी ढांचे, संचालन और अन्य सहित विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों की देखरेख की है।

वह KMFL-फोर्ड क्रेडिट संयुक्त उद्यम, कोटक महिंद्रा प्राइमस लिमिटेड के पहले CEO थे।

1992 में कोटक ग्रुप में शामिल होने से पहले, उन्होंने एएफ फर्ग्यूसन के कंसल्टेंसी डिवीजन के साथ काम किया।

KMBL के बारे में:

स्थापना: 1985

मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र

टैगलाइन: लेट्स मेक मनी सिंपल

मनीष देसाई ने प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला

मनीष देसाई भारतीय सूचना सेवा (IIS) के एक वरिष्ठ अधिकारी को प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है।

वह निवर्तमान राजेश मल्होत्रा का स्थान लेंगे, जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

मनीष देसाई सरकार के प्रमुख प्रवक्ता के रूप में भी काम करेंगे।

अन्य उल्लेखनीय नियुक्तियाँ:

भारत में समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार में वर्तमान प्रेस रजिस्ट्रार धीरेंद्र ओझा को केंद्रीय संचार ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

वरिष्ठ IIS अधिकारी और PIB गुवाहाटी के अतिरिक्त महानिदेशक जेन नामचू को PIB कोलकाता के प्रमुख के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

IIS के एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी, भूपेन्द्र कैंथोला को भारत में समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार (RNI) के प्रेस रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किया गया है।

मनीष देसाई के बारे में:

श्री मनीष देसाई, 1989 बैच के भारतीय सूचना सेवा अधिकारी।

उन्होंने 2012 से 2018 तक छह वर्षों तक PIB में अतिरिक्त महानिदेशक (ADG) के रूप में कार्य किया और मुंबई में पश्चिम क्षेत्र PIB के महानिदेशक के रूप में भी कार्य किया।

नवंबर 2019 से जनवरी 2020 तक वह आरएनआई के महानिदेशक थे।
अपने तीन दशक के करियर के दौरान, उन्होंने फिल्म प्रभाग में महानिदेशक (डीजी), भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) में प्रशासन और प्रशिक्षण में जिम्मेदारियों के साथ अतिरिक्त महानिदेशक और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सहित विभिन्न महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं।
अपनी वर्तमान भूमिका से पहले, उन्होंने केंद्रीय संचार ब्यूरो में प्रधान महानिदेशक का पद संभाला, जहाँ उन्होंने सरकारी विज्ञापन और आउटरीच गतिविधियों की देखरेख की।

PIB के बारे में:

स्थापना: जून 1919
मुख्यालय: नई दिल्ली
प्रधान सूचना अधिकारी के रूप में ब्यूरो का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय: जे नटराजन (1941)
PIB सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है।
PIB जून, 2023 में अपनी सौवीं वर्षगांठ के अवसर पर सरकारी योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रम पहलों और उपलब्धियों पर प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और वेब मीडिया में जानकारी प्रसारित करता है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के बारे में:

कैबिनेट मंत्री: अनुराग ठाकुर
राज्य मंत्री: एल. मुरुगन

अभिनेता आर माधवन को भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया

सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने अभिनेता आर माधवन को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (FTII) सोसाइटी का अध्यक्ष और गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया।
माधवन ने अभिनेता और फिल्म निर्माता शेखर कपूर का स्थान लिया, जिनका FTII अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल मार्च, 2023 में समाप्त हो गया।
माधवन की नियुक्ति उनकी फिल्म 'रॉकेट्री: द नांबी इफेक्ट' की सफलता के मद्देनजर की गई है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार सहित इस फिल्म की राष्ट्रीय मान्यता का माधवन के करियर और प्रतिष्ठा पर प्रभाव का विश्लेषण करें।
विशेष रूप से, 'रॉकेट्री' के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 24 अगस्त, 2023 को इसरो द्वारा चंद्रयान -3 के चंद्रमा की सतह के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के बाद इतिहास रचने के एक दिन बाद मिला।
यह फिल्म इसरो के पूर्व वैज्ञानिक एस नांबी नारायणन के जीवन और भारत की अंतरिक्ष एजेंसी में उनके योगदान के बारे में है।

FTII के बारे में:

स्थापना: 1960
मुख्यालय: पुणे, महाराष्ट्र, भारत
FTII भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन और भारत की केंद्र सरकार द्वारा सहायता प्राप्त एक फिल्म संस्थान है।

कॉग्निजेंट इंडिया के अध्यक्ष और MD राजेश नांबियार को नैसकॉम चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया

राजेश नांबियार, कॉग्निजेंट इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (CMD) को नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज (नैसकॉम) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
राजेश नांबियार ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के पूर्व अध्यक्ष अनंत माहेश्वरी का स्थान लिया।
नांबियार पहले नैसकॉम के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं।

नांबियार, अध्यक्ष देबजानी घोष के साथ, नैसकॉम के साथ काम करना जारी रखेंगेकार्यकारी परिषद, उद्योग और सरकार वर्तमान अस्थिर वृहद वातावरण से निपटते हुए एक वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने में लगे हुए हैं।

नैसकॉम के बारे में:

स्थापित: 1988
मुख्यालय: नोएडा, उत्तर प्रदेश
अध्यक्ष: देबजानी घोष
नैसकॉम एक भारतीय गैर-सरकारी व्यापार संघ और वकालत समूह है जो मुख्य रूप से भारतीय प्रौद्योगिकी उद्योग को सेवा प्रदान करता है।

सातो किल्मन को वानुअतु का नया प्रधान मंत्री चुना गया

चार बार वानुअतु के प्रधान मंत्री (PM) सातो किलमैन को रिकॉर्ड 5 वीं बार शीर्ष पद के लिए चुना गया है, जिससे सरकार के नेता के रूप में अलातोई इश्माएल कलसाकाऊ के 9 महीने के शासनकाल का अंत हो गया है।
किल्मन को कुल 27 वोट मिले, जबकि कलसाकाऊ को 23 वोट मिले।
इससे पहले, वह दिसंबर 2010 से अप्रैल 2011, मई से जून 2011, जून 2011 से मार्च 2013, जून 2015 से फरवरी 2016 तक 4 मौकों पर वानूआतू के प्रधान मंत्री थे।

वानुअतु के बारे में:

अध्यक्ष: निकेनिके वुरोबारवु
पूंजी: पोर्ट विला
मुद्रा: वातु

सुदर्शन वेणु ने तिरुमाला तिरूपति देवस्थानम के सदस्य-न्यासी के रूप में शपथ ली

सुदर्शन वेणु, चेन्नई स्थित TVS मोटर कंपनी के प्रबंध निदेशक ने तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) ट्रस्ट बोर्ड के सदस्य-ट्रस्टी के रूप में शपथ ली है।
एन. नागा सत्यम और चेविरेड्डी मोहित रेड्डी ने भी शपथ ली।
TTD के संयुक्त कार्यकारी अधिकारी वीरब्रह्मम ने सुदर्शन वेणु को शपथ दिलाई।
यह समारोह बंगारू वकीली में हुआ, जो भगवान वेंकटेश्वर मंदिर के गर्भगृह के अंदर स्थित है।
TTD बोर्ड के सदस्य-न्यासी के रूप में सुदर्शन वेणु की नियुक्ति उल्लेखनीय है क्योंकि उन्हें हाल के दशकों में इस पद को संभालने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्तियों में से एक माना जाता है।

स्वराज ट्रैक्टर्स ने एमएस धोनी को ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया

स्वराज ट्रैक्टर्स भारतीय स्वदेशी ट्रैक्टर निर्माता कंपनी ने पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को अपना नया ब्रांड एंबेसडर चुना है।
इस साझेदारी की आधिकारिक घोषणा स्वराज की नवीनतम पेशकश, "स्वराज टारगेट", एक कॉम्पैक्ट और हल्के ट्रैक्टर मॉडल के लॉन्च इवेंट के दौरान हुई।
स्वराज ट्रैक्टर्स का लक्ष्य एमएस धोनी के साथ इस सहयोग के माध्यम से भारत भर के किसानों को नवीन और भरोसेमंद मशीनीकरण समाधान प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करना है।

एमएस धोनी की भूमिका:

स्वराज ट्रैक्टर के नए विज्ञापन अभियान में महेंद्र सिंह धोनी केंद्रीय भूमिका निभाएंगे।
यह अभियान स्वराज ट्रैक्टरों की असाधारण विशेषताओं और फायदों पर प्रकाश डालेगा।जो किसानों की उत्पादकता और दक्षता बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

स्वराज ट्रैक्टर्स के बारे में:

स्वराज ट्रैक्टर्स महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की सहायक कंपनी है जिसके अध्यक्ष श्री आनंद महिंद्रा हैं

महावीर लुनावत को AIBI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया

भारतीय निवेश बैंकरों का संघ (AIBI) सेबी और विभिन्न वैधानिक प्राधिकरणों के लिए निवेश बैंकरों के एकमात्र प्रतिनिधि निकाय ने पैंटोमैथ कैपिटल एडवाइजर्स के प्रबंध निदेशक (MD) महावीर लुनावत को सितंबर 2023 से 2 साल के लिए अपना अध्यक्ष नियुक्त किया।

AIBI का अध्यक्ष एक महत्वपूर्ण पद रखता है, जो सेबी की प्राथमिक बाजार सलाहकार समिति (PMAC) में निवेश बैंकरों का प्रतिनिधित्व करता है।

इस भूमिका में पूंजी बाजार से संबंधित नियामक सुधारों पर सदस्यों के विचारों, टिप्पणियों और सुझावों की सक्रिय रूप से वकालत करना शामिल है।

AIBI ने जेएम फाइनेंशियल के प्रबंध निदेशक अर्जुन मेहरा और ICICI सिक्योरिटीज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और ECM निष्पादन के प्रमुख प्रेम डी'कुन्हा को अपने उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की भी घोषणा की।

महावीर लुनावत के बारे में:

महावीर लुनावत 20 वर्षों से अधिक अनुभव वाले उद्योग के अनुभवी हैं, जिन्होंने भारत में प्रमुख व्यावसायिक घरानों के साथ काम किया है।

वह पैंटोमैथ कैपिटल एडवाइजर्स के संस्थापक और समूह प्रबंध निदेशक हैं।

उन्होंने महत्वपूर्ण M&A (विलय और अधिग्रहण) और कॉर्पोरेट पुनर्गठन परियोजनाओं का नेतृत्व किया है और 100 से अधिक आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) का प्रबंधन किया है।

उन्होंने TIE मुंबई में निदेशक, PHD चैंबर की पूंजी बाजार समिति के सदस्य और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर कोटक समिति के सदस्य सहित विभिन्न विचार नेतृत्व भूमिकाएं निभाई हैं।

वर्तमान में, महावीर लुनावत सेबी वैकल्पिक निवेश नीति सलाहकार समिति (AIPAC) में AIBI का प्रतिनिधित्व करते हैं।

वह प्रतिष्ठित भारतीय संस्थानों में विजिटिंग फैकल्टी सदस्य के रूप में भी कार्य करते हैं और ज्ञान प्रसार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए नियमित रूप से लेख प्रकाशित करते हैं।

AIBI के बारे में:

स्थापना: AIBI को मूल रूप से 1993 में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में शामिल किया गया था।

2010 में, संगठन का नाम AMBI से बदलकर एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ऑफ इंडिया (AIBI) कर दिया गया।

AIBI निवेश बैंकिंग उद्योग का सभी वैधानिक प्राधिकरणों, विशेषकर सेबी का एकमात्र प्रतिनिधि है।

RBI ने कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO के रूप में दीपक गुप्ता की अंतरिम नियुक्ति को मंजूरी दे दी

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2 सितंबर, 2023 से शुरू होने वाली 2 महीने की अवधि के लिए कोटक महिंद्रा बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के रूप में दीपक गुप्ता की नियुक्ति को अपनी मंजूरी दे दी है।

यह निर्णय बैंक के पिछले MD और CEO उदय कोटक के शीघ्र इस्तीफे के बाद लिया गया, जिन्होंने अपना कार्यकाल समाप्त होने से 3 महीने पहले पद छोड़ दिया था।

विश्लेषक इस अल्पकालिक नियुक्ति को एक संकेतक के रूप में व्याख्या करते हैं कि केंद्रीय बैंक उदय कोटक के स्थायी उत्तराधिकारी के चयन के संबंध में निर्णय के करीब है।

इससे पहले, उदय कोटक ने खुलासा किया था कि बैंक ने उम्मीदवारों के नाम जमा करने की निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर आरबीआई को दो उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश की थी।

कोटक महिंद्रा बैंक में सीईओ पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले दो प्रमुख आंतरिक उम्मीदवार हैं:

शांति एकंबरम: वर्तमान में, शांति एकंबरम बैंक के उपभोक्ता प्रमुख हैं

KVS मणियन: 1994 से बैंक में लंबे कार्यकाल के साथ, KVS मनियन कॉर्पोरेट, संस्थागत और निवेश बैंकिंग से संबंधित जिम्मेदारियां संभालते हैं।

दीपक गुप्ता के बारे में:

दीपक गुप्ता, जो जनवरी 1999 से KMBL के पूर्णकालिक निदेशक हैं।
उन्हें 1 जनवरी 2012 को संयुक्त प्रबंध निदेशक के रूप में नामित किया गया था।
उन्होंने आईटी, साइबर सुरक्षा, डिजिटल पहल, आंतरिक लेखा परीक्षा, मानव संसाधन, विपणन, अनुपालन, प्रशासन, बुनियादी ढांचे, संचालन और अन्य सहित विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों की देखरेख की है।
वह कोटक महिंद्रा प्राइमस लिमिटेड, KMFL-फोर्ड क्रेडिट संयुक्त उद्यम के पहले CEO थे।
1992 में कोटक ग्रुप में शामिल होने से पहले, उन्होंने एएफ फर्ग्यूसन के कंसल्टेंसी डिवीजन के साथ काम किया।

KMBL के बारे में:

स्थापना: 1985
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र
टैगलाइन: लेट्स मेक मनी सिंपल

RBI ने ICICI बैंक के MD और CEO के रूप में संदीप बख्शी की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दे दी

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भारत के दूसरे सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक, ICICI बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (MD और CEO) के रूप में संदीप बख्शी की फिर से नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।
संदीप बख्शी की पुनर्नियुक्ति 3 वर्ष की अवधि के लिए है, जो 4 अक्टूबर, 2023 से 3 अक्टूबर, 2026 तक प्रभावी है।
यह उनका दूसरा कार्यकाल विस्तार है।
इससे पहले, 2021 में, उन्हें 2 साल की अवधि के लिए फिर से नियुक्त किया गया था, जिसे अक्टूबर 2023 तक बढ़ाया गया था।
संदीप बख्शी अक्टूबर 2018 से MD और CEO के पद पर रहते हुए ICICI बैंक का नेतृत्व कर रहे हैं।

संदीप बख्शी के बारे में:

संदीप बख्शी का ICICI समूह के साथ लंबे समय से जुड़ाव रहा है, जो 1986 से इसका हिस्सा रहे हैं।
अपने पूरे करियर के दौरान, बख्शी ने ICICI लिमिटेड, ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, ICICI बैंक और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस सहित ICICI समूह के भीतर विभिन्न संस्थाओं में विभिन्न प्रमुख पदों पर कार्य किया है।
MD और CEO बनने से पहले, बख्शी ने ICICI बैंक के पूर्णकालिक निदेशक और मुख्य परिचालन अधिकारी (COO) के रूप में कार्य किया।

ICICI बैंक लिमिटेड के बारे में:

स्थापना: 5 जनवरी 1994
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र, भारत
MD एवं CEO: संदीप बख्शी
टैगलाइन: हम हैं ना, ख्याल आपका

श्रीनिवासन के स्वामी को 2023-24 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया

श्रीनिवासन के स्वामी, आरके स्वामी हंसा समूह के कार्यकारी अध्यक्ष को वर्ष 2023-2024 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन (ABC) के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है।

अन्य नियुक्तियाँ:

श्री रियाद मैथ्यू, परिषद में प्रकाशक सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले मलयाला मनोरमा के मुख्य सहयोगी संपादक और निदेशक को सर्वसम्मति से वर्ष 2023-2024 के लिए ब्यूरो के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया।
परिषद में प्रकाशक सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक श्री मोहित जैन को सर्वसम्मति से वर्ष 2023-2024 के लिए ब्यूरो के माननीय सचिव के रूप में चुना गया।

परिषद में विज्ञापन एजेंसियों के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले मैडिसन कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के पार्टनर और ग्रुप CEO मीडिया और OOH श्री विक्रम सखूजा को सर्वसम्मति से वर्ष 2023-2024 के लिए ब्यूरो के माननीय कोषाध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया।

परिषद के सदस्य:

प्रकाशक प्रतिनिधि:

श्री रियाद मैथ्यू - मलयाला मनोरमा कंपनी लिमिटेड - डिप्टी अध्यक्ष
श्री प्रताप जी. पवार - सकाल पेपर्स प्रा. लिमिटेड
श्री शैलेश गुप्ता - जागरण प्रकाशन लिमिटेड
श्री प्रवीण सोमेश्वर - एचटी मीडिया लिमिटेड।
श्री मोहित जैन - बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड - माननीय। सचिव
श्री ध्रुबा मुखर्जी - एबीपी प्रा. लिमिटेड
करण जी. दर्डा - लोकमत मीडिया प्रा. लिमिटेड
श्री गिरीश अग्रवाल - डीबी कॉर्प लिमिटेड

विज्ञापनदाता प्रतिनिधि

श्री करुणेश बजाज, ITC लिमिटेड
श्री अनिरुद्ध हलधर, TVS मोटर कंपनी लिमिटेड।
श्री शशांक श्रीवास्तव, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड।

सचिवालय

श्री होर्मुज़द मसानी - महासचिव

श्रीनिवासन के स्वामी के बारे में:

श्री स्वामी विज्ञापन और व्यावसायिक संघों में विभिन्न नेतृत्व पदों पर कार्यरत हैं।
वह वर्तमान में एशियन फेडरेशन ऑफ एडवरटाइजिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं।
उन्होंने पहले इंटरनेशनल एडवरटाइजिंग एसोसिएशन (IAA), IAA इंडिया चैप्टर, कन्फेडरेशन ऑफ एशियन एडवरटाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन, एडवरटाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एडवरटाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, मद्रास चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष/अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।
उन्हें एडवरटाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया (AAAI) द्वारा लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था।

ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन (ABC) के बारे में:

स्थापना: 1948
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र, भारत
भारत का ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन (ABC) एक गैर-लाभकारी परिसंचरण-ऑडिटिंग संगठन है।
यह भारत में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं सहित प्रमुख प्रकाशनों के प्रसार को प्रमाणित और ऑडिट करता है।

आईआरएस अधिकारी राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय के अंतरिम निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया

राहुल नवीन, 1993-बैच के भारतीय राजस्व सेवा (IRS) अधिकारी को मौजूदा संजय कुमार मिश्रा के स्थान पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के प्रभारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
वह वर्तमान में विशेष निदेशक-मुख्य सतर्कता अधिकारी (ईडी मुख्यालय) के रूप में कार्यरत हैं।

संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल:

संजय कुमार मिश्रा को शुरुआत में दो साल के कार्यकाल के लिए ईडी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था जो नवंबर 2020 में समाप्त होने वाला था।
बाद में उन्हें एक साल का विस्तार दिया गया, जिसे कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ा।

27 जुलाई, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने संजय कुमार मिश्रा को 15 सितंबर, 2023 तक ईडी के निदेशक पद पर बने रहने की अनुमति दी।

ईडी के बारे में:

स्थापित: 1 मई 1956
मुख्यालय: नई दिल्ली, दिल्ली, भारत
ईडी एक घरेलू कानून प्रवर्तन और आर्थिक खुफिया एजेंसी है जो भारत में आर्थिक कानूनों को लागू करने और आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए जिम्मेदार है।
यह राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय (MoF), भारत सरकार (GoI) के तहत संचालित होता है।
यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 2019 (फेमा), भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 और धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कुछ प्रावधानों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
प्रवर्तन निदेशालय का प्राथमिक ध्यान मनी लॉन्ड्रिंग, विदेशी मुद्रा उल्लंघन और आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों की जांच और मुकदमा चलाना है।

मास्टरकार्ड इंडिया ने SBI के पूर्व प्रमुख रजनीश कुमार को अपना गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है

मास्टर कार्ड भुगतान उद्योग की वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को मास्टरकार्ड इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया है।
मास्टरकार्ड इंडिया के अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका में, रजनीश कुमार एक गैर-कार्यकारी सलाहकार क्षमता में काम करेंगे।
वह मास्टरकार्ड की दक्षिण एशिया कार्यकारी नेतृत्व टीम को मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, जिसका नेतृत्व दक्षिण एशिया के डिवीजन अध्यक्ष और भारत के कंट्री कॉर्पोरेट अधिकारी गौतम अग्रवाल करेंगे।
यह मार्गदर्शन गतिशील घरेलू भुगतान परिदृश्य को नेविगेट करने में विशेष रूप से मूल्यवान होगा।

रजनीश कुमार के बारे में:

रजनीश कुमार के पास एसबीआई में लगभग चार दशकों का अनुभव है, जहां उन्होंने विभिन्न नेतृत्व पदों पर कार्य किया।
उन्होंने पूरे भारत, यूनाइटेड किंगडम (यूके) और कनाडा में बैंक के महत्वपूर्ण कार्यों का प्रबंधन किया।
उन्हें YONO (यू ओनली नीड वन) प्लेटफॉर्म का नेतृत्व करने के लिए व्यापक रूप से पहचाना जाता है।
कुमार ने अक्टूबर 2020 में एसबीआई के अध्यक्ष के रूप में अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा किया।
जबकि उनकी विशेषज्ञता कॉर्पोरेट क्रेडिट और प्रोजेक्ट फाइनेंस में निहित है, रजनीश कुमार के पास एचएसबीसी एशिया पैसिफिक, लार्सन एंड टुब्रो (L&T), और ब्रुकफील्ड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट जैसे कॉर्पोरेट दिग्गजों के बोर्ड में सीटों सहित कई निदेशक पद भी हैं।
इसके अतिरिक्त, वह भारतपे के बोर्ड के अध्यक्ष हैं और अग्रणी प्रबंधन संस्थान, एमडीआई, गुड़गांव में गवर्नर बोर्ड में कार्यरत हैं।

मास्टरकार्ड के बारे में:

स्थापना: 1966
मुख्यालय: न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका
CEO: माइकल माइबैक
यह भुगतान लेनदेन प्रसंस्करण और अन्य संबंधित-भुगतान सेवाओं (जैसे यात्रा-संबंधी भुगतान और बुकिंग) की एक श्रृंखला प्रदान करता है।
कंपनी के 210 देशों में कनेक्शन हैं।

यूएई की एतिहाद एयरवेज ने अभिनेत्री कैटरीना कैफ को ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया है

इतिहाद एयरवेज संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की राष्ट्रीय एयरलाइन ने बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया है।
यह एक दशक से अधिक समय में एतिहाद एयरवेज और कैटरीना कैफ के बीच दूसरा सहयोग है।
एतिहाद के ब्रांड एंबेसडर के रूप में कैटरीना कैफ को एयरलाइन को बढ़ावा देने के लिए रचनात्मक और आकर्षक अभियान वीडियो की एक श्रृंखला में दिखाया जाएगा।
एतिहाद एयरवेज वर्तमान में 8 प्रमुख भारतीय शहरों से उड़ानें संचालित करता है, जो भारतीय बाजार में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति को उजागर करता है।
कैटरीना कैफ के साथ नई साझेदारी 2010 में पिछले सहयोग पर आधारित है जब उन्हें एतिहाद के यात्रा अनुभव को प्रदर्शित करते हुए एक समझदार यात्री के रूप में चित्रित किया गया था।

एतिहाद एयरवेज के बारे में:

स्थापित: जुलाई 2003 (कार्य प्रारंभ: नवंबर 2003)
मुख्यालय: अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात
अध्यक्ष: मोहम्मद अली अल शोरफ़ा
सीईओ: एंटोनोआल्डो नेव्स

वरिष्ठ राजनयिक संतोष झा को श्रीलंका में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया

संतोष झा, एक वरिष्ठ राजनयिक को श्रीलंका में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है।
वह गोपाल बागले का स्थान लेंगे, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नामित किया गया है।
राजदूत संतोष झा ने 17 जुलाई, 2020 को बेल्जियम, लक्ज़मबर्ग और यूरोपीय संघ में भारत के राजदूत के रूप में अपनी वर्तमान भूमिका ग्रहण की।

नवीनतम समाचार:

जुलाई, 2023 में भारत और श्रीलंका ने अपनी आर्थिक साझेदारी को गहरा करने के उद्देश्य से एक 'विज़न दस्तावेज़' को औपचारिक रूप दिया।

संजीव कपूर को सऊदी लो-कॉस्ट कैरियर फ्लाईडील के CEO के रूप में नियुक्त किया गया

प्रसिद्ध विमानन और यात्रा दिग्गज संजीव कपूर को सऊदी अरब स्थित कम लागत वाली वाहक (LCC) फ्लाईडील एयरलाइंस का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया गया है।
संजीव कपूर, जो संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) के नागरिक हैं, कॉन कोर्फियाटिस की जगह लेंगे, जिन्होंने 2017 में लॉन्च होने के बाद से फ्लाईडील के CEO के रूप में कार्य किया था।
फ्लाईडील में शामिल होने से पहले, संजीव कपूर ने जेट एयरवेज के CEO के रूप में कार्य किया और सऊदी की राष्ट्रीय एयरलाइन सऊदी के महानिदेशक के सलाहकार के रूप में भी काम किया।
कपूर की नियुक्ति भारतीय मूल के नेताओं वाली पश्चिम एशियाई एयरलाइनों की सूची में शामिल हो गई है।
उदाहरण के लिए, कुवैत की जजीरा एयरवेज का नेतृत्व सीईओ रोहित रामचंद्रन द्वारा किया जाता है।

फ्लाईडील के बारे में:

स्थापित: 2016 (कार्य प्रारंभ: 23 सितंबर 2017)
मुख्यालय: जेद्दा, सऊदी अरब
फ्लाईएडील एक सऊदी कम लागत वाली एयरलाइन है जो जेद्दा में किंग अब्दुलअज़ीज़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्थित है।
सीट क्षमता में 11% हिस्सेदारी के साथ यह सऊदी अरब की तीसरी सबसे बड़ी एयरलाइन है।

विवेक भसीन ने BARC के 14वें निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला

वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक विवेक भसीन ने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) के 14वें निदेशक की भूमिका संभाली है।

वह अजीत कुमार मोहंती का स्थान लेंगे, जिन्हें 2023 की शुरुआत में परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था।

विवेक भसीन के बारे में:

विवेक भसीन का करियर तीन दशकों से अधिक का है और उन्होंने परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों की दीर्घायु और रखरखाव से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
प्रसिद्धजिन परियोजनाओं में वह शामिल रहे हैं उनमें राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन-1, तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन इकाइयां 1 और 2 और 3 और 4, मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन और अन्य जैसे परमाणु ऊर्जा स्टेशनों का पुनर्वास और संरचनात्मक अखंडता मूल्यांकन शामिल है।
उन्होंने अप्सरा-यू रिएक्टर के लिए ईंधन के निर्माण की सुविधाओं और स्वास्थ्य देखभाल में व्यापक अनुप्रयोगों के साथ रेडियोधर्मी आइसोटोप विखंडन-मोली के उत्पादन के लिए एक संयंत्र स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
उन्हें कई सम्मान और पुरस्कार मिले हैं, जिनमें इंडियन न्यूक्लियर सोसाइटी मेडल, डीएई विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुरस्कार और होमी भाभा विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुरस्कार शामिल हैं।
वह भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकादमी के फेलो हैं और उन्होंने परमाणु विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 300 से अधिक प्रकाशन लिखे हैं।

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) के बारे में:

स्थापना: 3 जनवरी 1954
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र, भारत
BARC भारत की प्रमुख परमाणु अनुसंधान सुविधा है।
यह परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) के तहत संचालित होता है, जिसकी देखरेख सीधे भारत के प्रधान मंत्री करते हैं।
होमी जहांगीर भाभा भारत में परमाणु कार्यक्रम की कल्पना की।
भाभा ने 1945 में परमाणु विज्ञान अनुसंधान करने के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) की स्थापना की।
राष्ट्र के लाभ के लिए परमाणु ऊर्जा के दोहन के प्रयास को तेज करने के लिए, डॉ. भाभा ने भारत के महत्वाकांक्षी परमाणु कार्यक्रम के लिए आवश्यक बहु-विषयक अनुसंधान कार्यक्रम के लिए जनवरी 1954 में परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान, ट्रॉम्बे (AEET) की स्थापना की।
1966 में भाभा के निधन के बाद, AEET का नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) कर दिया गया।

न्यायमूर्ति काजी फ़ैज़ ईसा ने पाकिस्तान के 29वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली

इस्लामाबाद के ऐवान-ए-सद्र में आयोजित एक समारोह में न्यायमूर्ति काजी फ़ैज़ ईसा ने पाकिस्तान के 29वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।
राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने उन्हें पद की शपथ दिलाई।
सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल 13 महीने का होगा, जो 25 अक्टूबर 2024 को समाप्त होगा।
उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब पाकिस्तान गंभीर संवैधानिक, कानूनी और राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहा है।
उनकी प्रारंभिक चुनौती संसद भंग होने के 90 दिनों के भीतर पारदर्शी तरीके से आम चुनाव कराना होगा।
मुख्य न्यायाधीश के लिए सबसे बड़ा काम शीर्ष अदालत की प्रतिष्ठा और निष्पक्षता को बहाल करना होगा।
जस्टिस ईसा के लिए एक और मुख्य चुनौती सुप्रीम कोर्ट में 56,000 से अधिक लंबित मामलों को सुलझाना होगा।
हाल ही में, वह सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के गैर-कार्यान्वयन के खिलाफ अपने विरोध के लिए खबरों में थे, जो शाहबाज शरीफ सरकार के कार्यकाल के दौरान बनाया गया था।

क़ाज़ी फ़ैज़ ईसा के बारे में

जस्टिस ईसा का जन्म 26 अक्टूबर 1959 को क्वेटा में हुआ था।

उन्होंने 1985 में बलूचिस्तान उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में अपना कानूनी करियर शुरू किया और बाद में 1998 में सुप्रीम कोर्ट के वकील बन गए।

भार्गव दासगुप्ता ने ICICI लोम्बार्ड के MD और CEO पद से इस्तीफा दिया, ADB में मार्केट सॉल्यूशंस के उपाध्यक्ष के रूप में शामिल होने के लिए तैयार

भार्गव दासगुप्ता ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के रूप में कार्यरत, ने कंपनी के साथ लगभग 14 साल के कार्यकाल के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।
दासगुप्ता 3 साल की अवधि के लिए एशियाई विकास बैंक (ADB) में उपाध्यक्ष के रूप में शामिल होंगे।
ADB में अपनी नई स्थिति में, दासगुप्ता ADB के निजी क्षेत्र संचालन विभाग और बाजार विकास और सार्वजनिक-निजी भागीदारी कार्यालय के संचालन के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होंगे।

भार्गव दासगुप्ता के बारे में:

भार्गव दासगुप्ता ने 1992 में पूर्ववर्ती ICICI लिमिटेड के साथ अपने करियर की शुरुआत की।
अपने पूरे करियर के दौरान, उन्होंने ICICI समूह के भीतर विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रमुख नेतृत्व भूमिकाएँ निभाई हैं। इन भूमिकाओं में परियोजना वित्त, कॉर्पोरेट बैंकिंग, ई-कॉमर्स, प्रौद्योगिकी प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग और जीवन बीमा शामिल हैं।
ICICI लोम्बार्ड में भार्गव दासगुप्ता के 14 साल के नेतृत्व के दौरान, कंपनी ने महत्वपूर्ण वित्तीय वृद्धि देखी। उनके नेतृत्व में कंपनी का राजस्व छह गुना बढ़ गया और शुद्ध लाभ 78 गुना बढ़ गया।
मौजूदा नियमों के मुताबिक, 15 साल पूरे होने के बाद अप्रैल 2024 में भार्गव को अपना पद छोड़ना होगा।

ADB के बारे में:

स्थापना: 19 दिसंबर 1966
मुख्यालय: मांडलुयॉन्ग, फिलिपींस
राष्ट्रपति: मासात्सुगु असकावा
सदस्यता: 68 देश

अभिनेता सुरेश गोपी को सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान (SRFTI) के अध्यक्ष के रूप में नामांकित किया गया

मलयालम अभिनेता और राजनीतिज्ञ सुरेश गोपी को कोलकाता स्थित सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान (SRFTI) के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था।
वह इसकी संचालन परिषद के अध्यक्ष की जिम्मेदारियों को भी निभाएंगे।
उन्हें 3 साल की अवधि के लिए नामांकित किया गया है।

सुरेश गोपी के बारे में:

सुरेश गोपी एक मलयालम अभिनेता-राजनेता हैं।
उन्हें "कलियाट्टम", "कमिश्नर" और "पाप्पन" जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है।
अक्टूबर 2016 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद उन्होंने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया।
2019 में, उन्होंने त्रिशूर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव भी लड़ा, जिसमें वह कांग्रेस के टीएन प्रतापन से हार गए।
वह पूर्व राज्यसभा सांसद (सांसद) हैं।
कलियाट्टम में उनकी भूमिका के लिए उन्हें 1997 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।

SRFTI के बारे में:

स्थापना: 1995
मुख्यालय: कोलकाता, पश्चिम बंगाल

लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस ने पराग वेद को नामित निदेशक और CEO नियुक्त किया है

लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस, एक निजी सामान्य बीमा कंपनी ने पराग वेद को अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) और बोर्ड में एक निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है।
रूपम अस्थाना की सेवानिवृत्ति के बाद पराग वेद ने CEO की भूमिका संभाली है, जो संगठन के भीतर नेतृत्व परिवर्तन का संकेत है।
लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस में शामिल होने से पहले, पराग वेद ने बीमा उद्योग में अपने व्यापक अनुभव को प्रदर्शित करते हुए, टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस में कंज्यूमर लाइन्स के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।

लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस के बारे में:

स्थापित: 2013
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र, भारत
यह अमेरिकी संपत्ति दुर्घटना बीमाकर्ता लिबर्टी म्यूचुअल इंश्योरेंस ग्रुप, भारतीय निजी निवेश कोष एनाम सिक्योरिटीज और भारतीय औद्योगिक समूह डीपी जिंदल ग्रुप के बीच एक संयुक्त उद्यम है।

RBI के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव को एक साल का कार्यकाल विस्तार मिला

केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के डिप्टी गवर्नर के रूप में एम राजेश्वर राव का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया।
पुनर्नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दे दी है.
राव को अक्टूबर 2020 में तीन साल की अवधि के लिए केंद्रीय बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था।

कौन हैं एम राजेश्वर राव?

कोचीन विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक और व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर राव 1984 में RBI में शामिल हुए।
नवंबर 2016 में उन्हें RBI के कार्यकारी निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया था।
एक कैरियर केंद्रीय बैंकर के रूप में, उन्हें आरबीआई के कामकाज के विभिन्न पहलुओं का अनुभव है।
वह पहले जोखिम निगरानी विभाग का प्रभार संभाल चुके हैं।
उन्होंने नई दिल्ली में बैंकिंग लोकपाल और अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई और राष्ट्रीय राजधानी में रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में भी काम किया है।

RBI ने 3 साल के लिए HDFC बैंक के MD और CEO के रूप में शशिधर जगदीशन की पुनः नियुक्ति को मंजूरी दी

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 27 अक्टूबर, 2023 से 3 साल के लिए एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के रूप में शशिधर जगदीशन की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दे दी।
मार्च 2023 में, HDFC बैंक बोर्ड ने 3 साल की अवधि के लिए जगदीशन की पुनर्नियुक्ति की सिफारिश की थी।
शशिधर जगदीशन ने अक्टूबर 2020 में आदित्य पुरी की सेवानिवृत्ति के बाद HDFC बैंक के MD और CEO का पद संभाला।
उनका विस्तार HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक के बीच विलय के मद्देनजर आया है, जिसने भारतीय स्टेट बैंक के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा बैंक बनाया।

शशिधर जगदीशन के बारे में:

उद्योग में 31 वर्षों का समग्र अनुभव रखने वाले जगदीशन 1996 में वित्त कार्य में प्रबंधक के रूप में बैंक में शामिल हुए।
वह पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और उन्होंने यूनाइटेड किंगडम के शेफ़ील्ड विश्वविद्यालय से धन, बैंकिंग और वित्त के अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री प्राप्त की है।
MD और CEO के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले, उन्होंने वित्त, मानव संसाधन, कानूनी और सचिवीय, प्रशासन आदि कार्यों की देखरेख करने के अलावा, बैंक के समूह प्रमुख के रूप में कार्य किया।
अप्रैल 2022 में, जगदीशन के नेतृत्व में HDFC बैंक ने HDFC के साथ विलय की घोषणा की।
विलय 1 जुलाई, 2023 से प्रभावी हुआ।

HDFC बैंक के बारे में:

स्थापित: 1994
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र
MD और CEO: शशिधर जगदीशन
टैगलाइन: वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड

मृणाल मोहित के इस्तीफे के बाद BYJU'S ने अर्जुन मोहन को भारत का CEO नियुक्त किया

एडटेक दिग्गज BYJU'S ने अपने भारतीय परिचालन के लिए अर्जुन मोहन को मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया है।
अर्जुन मोहन ने मृणाल मोहित का स्थान लिया, जो BYJU's के संस्थापक भागीदार और भारतीय व्यवसाय के निवर्तमान प्रमुख थे।
मृणाल मोहित ने BYJU's में भारतीय परिचालन के सीईओ के रूप में कार्य किया और व्यक्तिगत आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कंपनी छोड़ दी।
मृणाल मोहित मई 2022 से BYJU के भारत परिचालन का नेतृत्व कर रहे थेकंपनी के सह-संस्थापक और सीईओ BYJU रवीन्द्रन ने अपना ध्यान कंपनी के अंतर्राष्ट्रीय परिचालन की ओर स्थानांतरित कर दिया।
अर्जुन मोहन ने पहले BYJU के मुख्य व्यवसाय अधिकारी के रूप में कार्य किया था, लेकिन 2020 में रॉनी स्क्रूवाला की अपस्किलिंग यूनिकॉर्न अपग्रेड के सीईओ बनने के लिए कंपनी छोड़ दी।

नवीनतम समाचार:

जुलाई 2023 में बायजूस ने अपग्रेड के पूर्व CEO अर्जुन मोहन को अपने अंतरराष्ट्रीय कारोबार का CEO बनाया था।

वरिष्ठ नौकरशाह पीयूष गोयल का नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड प्रमुख के रूप में कार्यकाल बढ़ा दिया गया

केंद्र ने नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (NATGRID) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के रूप में वरिष्ठ नौकरशाह पीयूष गोयल के कार्यकाल को विस्तार दिया है।

पीयूष गोयल के बारे में:

पीयूष गोयल नागालैंड कैडर से संबंधित 1994-बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी हैं।
उन्होंने अगस्त 2022 में NATGRID CEO की भूमिका ग्रहण की।
कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने NATGRID के CEO के रूप में गोयल के कार्यकाल को 25 मार्च, 2024 से आगे 19 नवंबर, 2025 तक की अवधि के लिए विस्तार को मंजूरी दे दी है।
सरकार ने अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार के रूप में सुकृति लिखी के कार्यकाल के विस्तार को भी मंजूरी दे दी है।
वह हरियाणा कैडर से 1993-बैच की IAS अधिकारी हैं और उनका कार्यकाल 19 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दिया गया है।

नेटग्रिड के बारे में:

नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (NATGRID) आतंकवाद विरोधी उद्देश्यों के लिए एक एकीकृत इंटेलिजेंस मास्टर डेटाबेस संरचना है
NATGRID की परिकल्पना और विकास 2008 के मुंबई हमलों के बाद किया गया था।
इसका उद्देश्य विभिन्न खुफिया और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच निर्बाध सूचना साझाकरण और विश्लेषण को सक्षम करके राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाना है।

RBI ने केएन मधुसूदनन को धनलक्ष्मी बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दी

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने केएन मधुसूदनन को 3 साल की अवधि के लिए धनलक्ष्मी बैंक का अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया है।
इस नियुक्ति से पहले, मधुसूदनन वर्ष 2022 से धनलक्ष्मी बैंक में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यरत थे।
केएन मधुसूदनन की नियुक्ति RBI द्वारा जी राजगोपालन नायर को बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को खारिज करने के बाद हुई है।

राजगोपालन नायर ने पहले अगस्त 2020 से धनलक्ष्मी बैंक में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य किया था।

धनलक्ष्मी बैंक के बारे में:

स्थापना: 14 नवंबर 1927
मुख्यालय: त्रिशूर, केरल, भारत
MD और CEO: जेके शिवन

डिफेन्स करेंट अफेयर्स

भारतीय नौसेना का महेंद्रगिरि युद्धपोत मुंबई में सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ

भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी पत्नी डॉ. सुदेश के साथधनखड़ ने महाराष्ट्र के मुंबई में मेसर्स मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) में निर्मित युद्धपोत 'महेंद्रगिरि' का शुभारंभ किया।

'महेंद्रगिरि' के बारे में:

'महेंद्रगिरि' भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17ए के तहत 7वां स्टील्थ फ्रिगेट और MDL द्वारा निर्मित चौथा युद्धपोत है।
इसका नाम उड़ीसा राज्य में स्थित पूर्वी घाट की एक पर्वत चोटी के नाम पर रखा गया है।
जहाज का नाम उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ की पत्नी डॉ. सुदेश धनखड़ ने रखा, जो इस अवसर पर मुख्य अतिथि थीं।
महेंद्रगिरि को एकीकृत निर्माण पद्धति का उपयोग करके बनाया गया है जिसमें समानांतर आउटफिटिंग के साथ पतवार ब्लॉक शामिल हैं।
निर्माण विभिन्न भौगोलिक स्थानों पर किया गया है और MDL में स्लिपवे पर एकीकरण / निर्माण किया गया है।
महेंद्रगिरि की आधारशिला 28 जून 2022 को रखी गई थी।
जहाज का अनुमानित प्रक्षेपण वजन 3450 टन है।

प्रोजेक्ट 17A:

भारतीय रक्षा बलों द्वारा स्टील्थ गाइडेड-मिसाइल फ्रिगेट बनाने की परियोजना शुरू की गई।
प्रोजेक्ट 17ए कार्यक्रम के तहत, मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) द्वारा 4 और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (GRSE) द्वारा 3 जहाज बनाए जा रहे हैं।

प्रोजेक्ट 17ए युद्धपोतों की मुख्य विशेषताएं:

ये युद्धपोत प्रोजेक्ट 17 क्लास फ्रिगेट्स (शिवालिक क्लास) का अनुसरण करते हैं और उन्नत स्टील्थ सुविधाओं, उन्नत हथियारों, सेंसर और प्लेटफ़ॉर्म प्रबंधन प्रणालियों का दावा करते हैं।
प्रोजेक्ट 17-ए के तहत कुल 7 जहाज बनाए गए थे।
ये हैं
भारतीय नौसेना जहाज (INS) नीलगिरि
INS हिमगिरी
INS उदयगिरि
INS दुनागिरी
INS तारागिरी
INS विंध्यगिरि
INS महेंद्रगिरि
युद्धपोतों को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा इन-हाउस डिजाइन किया गया है
प्रोजेक्ट 17ए जहाजों के उपकरणों और प्रणालियों के लिए 75% ऑर्डर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) सहित स्वदेशी फर्मों से हैं।

नवीनतम समाचार:

अगस्त 2023 में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता में हुगली नदी के तट पर स्थित गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (GRSE) सुविधा में भारतीय नौसेना के उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट भारतीय नौसेना जहाज (INS) विंध्यगिरि, 6 वें प्रोजेक्ट 17 ए युद्धपोत का उद्घाटन किया।

रक्षा मंत्रालय के बारे में:

रक्षा मंत्री: राजनाथ सिंह
राज्य मंत्री: रक्षा मंत्रालय
रक्षा सचिव: गिरिधर अरमाने

चीन के साथ LAC विवाद के बीच IAF मेगा ड्रिल करेगी

भारतीय वायु सेना (IAF) अपनी लड़ाकू तत्परता का परीक्षण करने के लिए "त्रिशूल" नामक एक प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित कर रही है।
इस अभ्यास में देश के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में लड़ाकू विमान, परिवहन विमान, हेलीकॉप्टर और अन्य संपत्तियां शामिल होंगी।
यह अभ्यास वायु सेना की पश्चिमी वायु कमान (WAC) द्वारा 4 से 14 सितंबर, 2023 तक आयोजित किया जाएगा।

WAC के बारे में:

मुख्यालय: दिल्ली में सुब्रतो पार्क
WAC IAF की सबसे बड़ी ऑपरेशनल कमांड है।
यह लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, पंजाब और हरियाणा में बेस से संचालित होता है।

मुख्य विचार:

यह अभ्यास भारत द्वारा 9-10 सितंबर,2023 को दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के साथ मेल खाता है जो महत्वपूर्ण राजनयिक घटनाओं के दौरान भी युद्ध की तैयारी बनाए रखने के लिए भारतीय वायुसेना की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
10 दिवसीय अभ्यास में जिन लड़ाकू विमानों के हिस्सा लेने की उम्मीद है उनमें राफेल, सुखोई-30 और मिग-29 शामिल हैं।

अन्य अभ्यास:

भारतीय वायुसेना 2024 की शुरुआत में होने वाले एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय अभ्यास, "तरंग शक्ति" की तैयारी कर रही है। इसमें अंतरसंचालनीयता बढ़ाने, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और सैन्य सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान देने के साथ 12 वैश्विक वायु सेनाएं शामिल होंगी।
इस अभ्यास में लड़ाकू जेट, सैन्य परिवहन विमान, मध्य हवा में ईंधन भरने वाले विमान और हवाई चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली (AWACS) विमान शामिल होंगे।

नवीनतम समाचार:

जनवरी 2023 में, भारतीय वायु सेना (IAF) दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के संबंध में अलग-अलग धारणाओं से संबंधित चीन के साथ अनसुलझे सीमा विवाद के बीच देश के उत्तरपूर्वी क्षेत्र में अभ्यास प्रलय आयोजित करने के लिए तैयार है।

भारतीय वायुसेना के बारे में:

स्थापना: 1932
मुख्यालय: नई दिल्ली, दिल्ली
वायु सेना प्रमुख: एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी

हुगली नदी पर टीटागढ़, कोलकाता (WB) में फाइव-शिप डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट (DSC) परियोजना में पहले जहाज, DSC A 20' (यार्ड 325) का शुभारंभ

DSC A 20' (यार्ड 325) फाइव (05) डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट (DSC) परियोजना का पहला जहाज, टीटागढ़, कोलकाता (WB) में हुगली नदी पर लॉन्च किया गया था।

DSC A 20 के बारे में:

DSC A 20' का निर्माण मेसर्स टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड (TRSL) द्वारा किया गया है।
इन जहाजों में कैटामरन पतवार का डिज़ाइन है और इनकी लंबाई लगभग 30 मीटर है।
उनका विस्थापन लगभग 300 टन होने का अनुमान है।
DSC A 20' सहित सभी 5 DSC, वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारतीय नौसेना को सौंपे जाने वाले हैं।
इन शिल्पों को गोताखोरी संचालन करने के लिए अत्याधुनिक गोताखोरी उपकरण और उपकरणों से सुसज्जित किया जा रहा है।
इन जहाजों को बंदरगाहों और तटीय जल में परिचालन/प्रशिक्षण गोताखोरी संचालन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
यह उल्लेखनीय है कि ये जहाज पूरी तरह से स्वदेशी हैं, जो भारतीय शिपिंग रजिस्टर (IRS) के प्रासंगिक नौसेना नियमों और विनियमों का पालन करते हैं।
हाइड्रोडायनामिक विश्लेषण/ डिजाइन चरण के दौरान जहाजों का मॉडल परीक्षण नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला (NSTL), विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश (एपी) में किया गया था।
गोताखोरी सहायता पोत, जैसा कि नाम से पता चलता है, एक जहाज है जिसका उपयोग महासागरों में गोता लगाने के उद्देश्य से किया जाता है।
पेशेवर गोताखोरी प्रक्रिया के एक भाग के रूप में समुद्र के बीच में गोता लगाने वाले गोताखोरों को उचित गोताखोरी सहायता की आवश्यकता होती है।

रक्षा मंत्रालय के बारे में:

रक्षा मंत्री: राजनाथ सिंह
राज्य मंत्री: रक्षा मंत्रालय
रक्षा सचिव: गिरिधर अरमाने

भारतीय सेना का थल सेना भवन गृह-IV हरित मानकों का पालन करेगा

भारतीय सेना के आगामी थल सेना भवन (TSB) का निर्माण गृह-IV (एकीकृत आवास मूल्यांकन के लिए ग्रीन रेटिंग) मानदंडों के अनुपालन में किया जा रहा है।
सीपी कुकरेजा आर्किटेक्ट्स, जिन्हें इस परियोजना से सम्मानित किया गया है, के अनुसार इसे लगभग 100 वर्षों के भवन जीवन के लिए डिज़ाइन किया गया है, और यह भूकंप प्रतिरोधी है।
मई-जून 2025 तक भवन बनकर तैयार हो जाएगा।

गृह के बारे में:

गृह (एकीकृत पर्यावास मूल्यांकन के लिए ग्रीन रेटिंग), इसका नाम संस्कृत शब्द 'निवास' से लिया गया है।
इसे TERI (द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट) द्वारा विकसित किया गया है और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अपनाया गया है।
यह एक रेटिंग टूल के रूप में कार्य करता है जो राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत बेंचमार्क के विरुद्ध किसी भवन के प्रदर्शन का आकलन करने में सहायता करता है।
GRIHA किसी भवन के पूरे जीवन चक्र के दौरान उसके पर्यावरणीय प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है, और 'हरित भवन' के गठन के लिए एक निश्चित मानक स्थापित करता है।

रेटिंग प्रणाली और मानदंड:

स्वीकृत ऊर्जा और पर्यावरण सिद्धांतों पर आधारित रेटिंग प्रणाली, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्थापित प्रथाओं और उभरती अवधारणाओं के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करेगी।
इस उपकरण को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अपनाया गया है।

GRIHA रेटिंग प्रणाली 34 मानदंडों के आधार पर किसी इमारत का मूल्यांकन करती है और 100 के पैमाने पर अंक प्रदान करती है।
GRIHA प्रमाणन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, एक परियोजना को न्यूनतम 50 अंक प्राप्त करने होंगे।
रेटिंग के लिए पात्र होने के लिए किसी परियोजना के लिए कुछ मानदंड और उप-मानदंड अनिवार्य हैं और उन्हें पूरा किया जाना चाहिए।

गृह प्रमाणन स्तर:

परियोजना का GRIHA प्रमाणन स्तर उसके स्कोर के आधार पर निर्धारित किया जाता है:
50-60 अंक: 1-सितारा गृह रेटेड इमारत के रूप में प्रमाणित
61-70 अंक: 2-सितारा गृह रेटेड इमारत के रूप में प्रमाणित
71-80 अंक: 3 सितारा गृह रेटेड इमारत के रूप में प्रमाणित
81-90 अंक: 4 सितारा गृह रेटेड इमारत के रूप में प्रमाणित
91-100 अंक: 5 सितारा गृह रेटेड इमारत के रूप में प्रमाणित

भारतीय वायु सेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत ड्रोन शक्ति 2023 की सह-मेजबानी करेंगे

भारतीय वायु सेना (IAF) 'भारत ड्रोन शक्ति 2023' की मेजबानी के लिए ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ सहयोग कर रही है।
यह कार्यक्रम 25 और 26 सितंबर, 2023 को निर्धारित है, और यह गाजियाबाद में स्थित हिंडन में भारतीय वायुसेना के एयरबेस पर होगा, जहां भारतीय ड्रोन उद्योग लाइव हवाई प्रदर्शन देगा।
'भारत ड्रोन शक्ति 2023' का उद्देश्य भारतीय ड्रोन उद्योग की क्षमता का प्रदर्शन करना है।

भारत ड्रोन शक्ति 2023 के बारे में:

'भारत ड्रोन शक्ति 2023' 50 से अधिक लाइव हवाई प्रदर्शनों की प्रभावशाली लाइनअप के साथ भारतीय ड्रोन उद्योग की पूरी क्षमता प्रस्तुत करेगा।
प्रदर्शनों में ड्रोन अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होगी, जिसमें सर्वेक्षण ड्रोन, कृषि ड्रोन, अग्नि शमन ड्रोन, सामरिक निगरानी ड्रोन, ड्रोन झुंड और काउंटर-ड्रोन समाधान शामिल हैं।

भागीदारी:

इस आयोजन में भारत से 75 से अधिक ड्रोन स्टार्ट-अप और कॉर्पोरेट इकाइयाँ भाग लेंगी।
यह भारतीय ड्रोन उद्योग में उभरते और स्थापित दोनों खिलाड़ियों की मजबूत रुचि और भागीदारी को इंगित करता है।

स्वदेशी ड्रोन विकास के लिए IAF का समर्थन:

भारतीय ड्रोन संघ के साथ भारतीय वायुसेना का सहयोग देश में ड्रोन के स्वदेशी डिजाइन और विकास के लिए अपने समर्थन को दर्शाता है।
मेहर बाबा स्वार्म ड्रोन प्रतियोगिता जैसी पहल भारत की घरेलू ड्रोन क्षमताओं का दोहन करने के भारतीय वायुसेना के प्रयासों को दर्शाती है।

रक्षा मंत्रालय के बारे में:

रक्षा मंत्री: राजनाथ सिंह
राज्य मंत्री: रक्षा मंत्रालय
रक्षा सचिव: गिरिधर अरमाने

भारतीय वायुसेना के बारे में:

स्थापना: 1932
मुख्यालय: नई दिल्ली, दिल्ली
वायुसेनाध्यक्ष: एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी

भारत-फ्रांस द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास 'वरुण' 2023 का 21वां संस्करण अरब सागर में आयोजित किया गया

भारतीय-फ्रांसीसी द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास, वरुण 2023 का दूसरा चरण अरब सागर में हुआ।
इस अभ्यास में दोनों पक्षों के निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट, टैंकर, समुद्री गश्ती विमान और अभिन्न हेलीकॉप्टरों की भागीदारी देखी गई।
वरुणा अभ्यास का पहला चरण 16 जनवरी से 20 जनवरी, 2023 तक भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर हुआ।
वरुण 2023 भारत और के बीच इस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का 21वां संस्करण हैफ्रांस.
यह अभ्यास भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के 25वें वर्ष का भी जश्न मनाता है।

मुख्य विचार:

भारतीय-फ्रांसीसी द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 1993 में शुरू हुआ।
2001 में इसे आधिकारिक तौर पर "वरुण" नाम दिया गया।
वरुणा दोनों नौसेनाओं को नौसेना संचालन में एक-दूसरे की सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रक्रियाओं का आदान-प्रदान करने और सीखने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

भारतीय नौसेना और उबर ने भारत में नौसेना कर्मियों और उनके परिवारों की निजी यात्रा के लिए सहयोग किया

भारतीय नौसेना ने भारत भर में नौसेना कर्मियों और परिवारों की व्यक्तिगत यात्रा और आवागमन के लिए विश्वसनीय, सुविधाजनक, सुरक्षित और किफायती गतिशीलता समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से एक कैब एग्रीगेटर सेवा के साथ हाथ मिलाया है।
समुद्री सेना नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार और कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में उबर के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

उद्देश्य:

'शिप फर्स्ट' पहल के तहत "खुश कर्मियों" को सुनिश्चित करने के नौसेना स्टाफ प्रमुख के दृष्टिकोण के अनुरूप, भारतीय नौसेना कर्मियों को व्यापक लाभ प्रदान करना।
यह साझेदारी भारत सरकार की महत्वाकांक्षी 'डिजिटल इंडिया' दृष्टि के अनुरूप भी है, जो प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी क्षमता पर जोर देती है।
उबर भारतीय नौसेना के कर्मियों और उनके परिवारों को कई लाभ प्रदान करेगा, जिनमें शामिल हैं
Uber ऐप पर एक वैयक्तिकृत प्रोफ़ाइल।
प्रीमियर एक्जीक्यूटिव कैब श्रेणी व्यस्ततम कार्यालय समय के दौरान बढ़ती कीमतों से सुरक्षा प्रदान करती है।
टॉप-रेटेड ड्राइवरों की उपलब्धता।
सभी उबर यात्राओं पर शून्य रद्दीकरण शुल्क।
24x7 प्रीमियम व्यवसाय सहायता।

भारतीय नौसेना के बारे में:

स्थापना: 26 जनवरी 1950
मुख्यालय: नई दिल्ली, दिल्ली
नौसेना स्टाफ के प्रमुख (CNS): एडमिरल आर. हरि कुमार

उबर टेक्नोलॉजीज, इंक. के बारे में:

स्थापित: मार्च 2009
मुख्यालय: सैन फ्रांसिस्को, कैलिफ़ोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका।
अध्यक्ष: रोनाल्ड शुगर
CEO: दारा खोसरोशाही
उबर टेक्नोलॉजीज, इंक. एक अमेरिकी परिवहन समूह है जो मुख्य रूप से राइड-हेलिंग सेवाएं प्रदान करता है जहां व्यक्ति अपने फोन पर उबर ऐप का उपयोग करके वाहन चला सकते हैं।

सीमा सड़क संगठन लद्दाख में दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र बनाएगा

सीमा सड़क संगठन (BRO) लद्दाख के न्योमा क्षेत्र में दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र बनाने के लिए तैयार है।
यह हवाई क्षेत्र 13,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित होगा, जो इसे लड़ाकू विमानों के लिए विश्व स्तर पर सबसे ऊंचे हवाई क्षेत्रों में से एक बना देगा।
इस परियोजना की आधारशिला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 12 सितंबर, 2023 को देवक ब्रिज पर रखी जानी थी।
भारत चीन के साथ लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के 3,488 किलोमीटर के दायरे में बुनियादी ढांचे के विकास पर सक्रियता से काम कर रहा है।
सीमा सड़क संगठन के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने विश्वास जताया कि भारत इस मामले में अगले 2 से 3 वर्षों में चीन से आगे निकल जाएगा।

मुख्य विचार:

उच्च ऊंचाई वाले लड़ाकू हवाई क्षेत्र के निर्माण का बजट ₹219 करोड़ है।
इस अवसर पर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बीआरओ द्वारा शुरू की गई 90 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया।
चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थित इन परियोजनाओं का संचयी मूल्य ₹2,941 करोड़ है।
कार्यक्रम के दौरान, रक्षा मंत्री ने सांबा के रामगढ़ सेक्टर में भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगभग 3.5 किमी दूर स्थित देवक नदी पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पुल का उद्घाटन किया।
423 मीटर लंबे इस पुल का निर्माण ₹20 करोड़ की लागत से किया गया था।

BRO के बारे में:

स्थापना: 7 मई 1960
मुख्यालय: नई दिल्ली, दिल्ली
महानिदेशक: लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी
आदर्श वाक्य: श्रमेण सर्वम् साध्यम् (कड़ी मेहनत से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है)

भारतीय तटरक्षक बल ने इस्तांबुल, तुर्की में एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 19वीं बैठक (HACGAM) में भाग लिया

भारतीय तटरक्षक (ICG) ने एशियाई तटरक्षक एजेंसियों की बैठक (HACGAM) के 19वें प्रमुखों में भाग लिया, जो 5 सितंबर से 8 सितंबर, 2023 तक इस्तांबुल, तुर्की में हुई थी।
4 सदस्यीय ICG प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ICG के महानिदेशक डीजी राकेश पाल ने किया।
HACGAM में 23 सदस्य तटरक्षक एजेंसियां और 2 सहयोगी सदस्य शामिल हैं: एशिया में जहाजों के खिलाफ समुद्री डकैती और सशस्त्र डकैती से निपटने पर क्षेत्रीय सहयोग समझौता (ReCAAP) और ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNODC)।)

मुख्य विचार:

3 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक के दौरान, जिसमें सभी सदस्य देशों के तट रक्षकों के प्रमुखों ने भाग लिया, समुद्री कानून प्रवर्तन, समुद्र में जीवन की सुरक्षा और सुरक्षा, समुद्री पर्यावरण संरक्षण, ड्रग्स, हथियारों और समुद्र में मनुष्यों की अवैध तस्करी आदि सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई, और एजेंडा तैयार करने के माध्यम से आगे के सहयोग के अवसरों का पता लगाया गया।
मंच ने एशियाई तट रक्षकों के बीच समुद्री सहयोग को और मजबूत करने का संकल्प लिया।

HACGAM के बारे में:

HACGAM एक जापानी पहल का परिणाम है जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय तट रक्षकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है।

इसकी शुरुआत नवंबर 1999 में भारतीय तट रक्षक द्वारा समुद्री डाकू जहाज एमवी अलोंद्रा रेनबो को पकड़ने के बाद की गई थी।
HACGAM मुख्य रूप से क्षेत्र में सुरक्षित, संरक्षित और स्वच्छ समुद्र को सुनिश्चित करने और बढ़ावा देने के लिए सदस्य एशियाई राज्यों के तट रक्षकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
HACGAM में 4 कार्य समूह शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक विशिष्ट समुद्री मुद्दों पर केंद्रित है।
इन समूहों में खोज और बचाव (SAR), पर्यावरण संरक्षण, समुद्र में गैरकानूनी कृत्यों को नियंत्रित करना और सूचना साझा करना शामिल है।
भारतीय तटरक्षक खोज और बचाव (SAR) कार्य समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है और अन्य कार्य समूहों में सक्रिय रूप से भाग लेता है।
HACGAM का पिछला संस्करण 2022 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था

ICG के बारे में:

मुख्यालय: नई दिल्ली, दिल्ली
महानिदेशक: राकेश पाल
आदर्श वाक्य: वयम रक्षाम (हम रक्षा करते हैं)

रक्षा मंत्रालय के बारे में:

रक्षा मंत्री: राजनाथ सिंह
राज्य मंत्री: रक्षा मंत्रालय
रक्षा सचिव: गिरिधर अरमाने

भारतीय वायु सेना को स्पेन में एयरबस से अपना पहला C-295 विमान प्राप्त हुआ

भारतीय वायु सेना (IAF) को स्पेन के सेविले में एयरबस से पहला C-295MW परिवहन विमान प्राप्त हुआ है।
IAF ने ₹21,935 करोड़ की परियोजना के तहत कुल 56 C-295MW विमानों का ऑर्डर दिया है।

C-295MW के बारे में:

C-295MW 5-10 टन की क्षमता वाला एक परिवहन विमान है।
नया C-295MW विमान भारतीय वायु सेना में पुराने एवरो विमान की जगह लेगा, जो 1960 के दशक में खरीदे गए थे।
अनुबंध के तहत, 16 विमान सेविले से उड़ान भरने की स्थिति में वितरित किए जाएंगे, जबकि शेष 40 का निर्माण एयरबस द्वारा टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (T)ASL के साथ साझेदारी में किया जाएगा।
C-295MW विमान की उड़ान क्षमता 11 घंटे तक है और यह सभी मौसम की स्थिति में बहु-भूमिका संचालन कर सकता है।
यह शॉर्ट टेक-ऑफ और लैंडिंग (STOL) में सक्षम है और छोटी, बिना तैयारी वाली हवाई पट्टियों पर काम कर सकता है।
विमान को एक एयर टैंकर में परिवर्तित किया जा सकता है, जो एक अलग करने योग्य ईंधन भरने वाली किट जोड़कर फिक्स्ड और रोटरी-विंग रिसीवर्स को 6,000 किलोग्राम तक गैसोलीन पहुंचाने में सक्षम है।
दूसरा सी-295 मई 2024 में वितरित किया जाएगा, इसके बाद 2024 में प्रति माह एक की दर से सात और विमान दिए जाएंगे।
सितंबर 2021 में, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने एयरबस डिफेंस एंड स्पेस एसए, स्पेन से 56 C-295MW परिवहन विमान की खरीद को मंजूरी दी।
C-295MW इंटेलिजेंस सर्विलांस और रिकोनाइसेंस (ISR) क्षमताओं का उपयोग करके क्लोज़-एयर-सपोर्ट ऑपरेशन से लैस है, जो इसे विभिन्न मिशनों के लिए उपयुक्त बनाता है।
इसका उपयोग हताहत या चिकित्सा निकासी, हवाई भार गिराने, पैराट्रूपिंग, विशेष मिशन, आपदा राहत संचालन और समुद्री गश्ती जिम्मेदारियों के लिए किया जा सकता है।

भारतीय वायुसेना के बारे में:

स्थापना: 1932

मुख्यालय: नई दिल्ली, दिल्ली
वायुसेनाध्यक्ष: एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी

स्पेन के बारे में:

राजा: स्पेन के फेलिप VI
प्रधान मंत्री: पेड्रो सांचेज़
राजधानी: मैड्रिड
मुद्रा: यूरो

रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने 45,000 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें भारतीय वायु सेना (IAF) के लिए 12 Su-30MKI की खरीद भी शामिल है

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए 45,000 करोड़ रुपये के कुल 9 अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें भारतीय वायु सेना (IAF) के लिए 12 Su-30MKI की खरीद भी शामिल है।
इन अधिग्रहणों का उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों की क्षमताओं को मजबूत करना है।

मुख्य विचार:

12 Su-30MKIभारतीय वायु सेना (IAF) के लिए इसका निर्माण भारत में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा किया जाएगा।
Su-30MKI 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री से लैस होंगे।
ये IAF के सबसे आधुनिक Su-30 MKI विमान होंगे
संचालन की सटीकता और विश्वसनीयता में सुधार के लिए भारतीय वायुसेना को डोर्नियर विमान का उन्नत संस्करण भी मिलेगा।
ध्रुवास्त्र कम दूरी की हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का इस्तेमाल स्वदेश निर्मित ALH Mk-IV हेलिकॉप्टरों में किया जाएगा।
DAC ने हल्के बख्तरबंद बहुउद्देशीय वाहन (LAMV) और एकीकृत निगरानी और लक्ष्यीकरण प्रणाली (ISAT-S) की खरीद के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी।
डीएसी ने भारतीय नौसेना के लिए अगली पीढ़ी के सर्वेक्षण जहाजों की खरीद को भी मंजूरी दे दी।

नवीनतम समाचार:

अगस्त 2023 में, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) की बैठक में लगभग 7,800 करोड़ रुपये के पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति (AON) दी गई।
16 मार्च, 2023 को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) की बैठक में खरीद {भारतीय-IDDM (स्वदेशी डिजाइन, विकसित और निर्मित)} के तहत 70,500 करोड़ रुपये से अधिक की पूंजी अधिग्रहण के लिए आवश्यकता की स्वीकृति (AON) को मंजूरी दी गई है।

DAC के बारे में:

DAC की स्थापना फरवरी 2001 में राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली में सुधार पर मंत्रियों के समूह की सिफारिश पर की गई थी।
DAC सेना, नौसेना, वायु सेना और भारतीय तटरक्षक बल के लिए नई नीतियों और पूंजी अधिग्रहण पर निर्णय लेने के लिए रक्षा मंत्रालय में सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है।
केंद्रीय रक्षा मंत्री परिषद के अध्यक्ष हैं।

INS सुमेधा मिस्र, इटली और ग्रीस की नौसेनाओं के साथ अभ्यास ब्राइट स्टार 2023 में शामिल हुई

भारतीय नौसेना जहाज (INS) सुमेधा ने भूमध्य सागर में कई अन्य नौसेनाओं के साथ अभ्यास ब्राइट स्टार-23 में भाग लिया।
INS सुमेधा ने मिस्र, इटली, ग्रीस, साइप्रस और कतर की नौसेनाओं के साथ अभ्यास किया।

INS सुमेधा के बारे में:
आईएनएस सुमेधा स्वदेश निर्मित सरयू श्रेणी के नौसेना अपतटीय गश्ती जहाज (NOPV) का तीसरा जहाज है।
इसका डिज़ाइन और निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया था।
इस जहाज को 7 मार्च 2014 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था।
यह भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का हिस्सा है और विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश (एपी) में स्थित है।

अभ्यास ब्राइट स्टार-23 के बारे में:
अभ्यास ब्राइट स्टार-23 एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय त्रि-सेवा अभ्यास है।
यह उत्तरी मिस्र में होता है और इसका नेतृत्व अमेरिका और मिस्र के सशस्त्र बल संयुक्त रूप से करते हैं।
इस अभ्यास को मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े संयुक्त सैन्य अभ्यास के रूप में मान्यता प्राप्त है।
1980 में अपनी स्थापना के बाद से, अभ्यास ब्राइट स्टार 18 बार हो चुका है, जिसमें यह संस्करण सबसे नया है।
इसमें भारत समेत 34 देशों की भागीदारी थी।

अभ्यास के चरण:
अभ्यास ब्राइट स्टार-23 में दो मुख्य चरण होते हैं: हार्बर चरण और समुद्री चरण।
हार्बर चरण में क्रॉस-डेक विज़िट, पेशेवर आदान-प्रदान, खेल फिक्स्चर और समुद्री चरण की योजना जैसी विभिन्न गतिविधियाँ शामिल हैं।
समुद्री चरण में जटिल और उच्च तीव्रता वाले अभ्यास शामिल हैं, जिनमें क्रॉस-डेक उड़ान, सतह-रोधी और हवा-रोधी अभ्यास और लाइव हथियार फायरिंग अभ्यास शामिल हैं।

भागीदारी के उद्देश्य:
ब्राइट स्टार-23 अभ्यास में आईएनएस सुमेधा की भागीदारी से भारतीय नौसेना को साझेदार देशों के साथ अंतरसंचालनीयता को बढ़ाने और प्रदर्शित करने की अनुमति मिलती है।
यह भारतीय नौसेना को अपने साझेदार देशों से समुद्री सुरक्षा अभियानों में सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखने और लागू करने का अवसर भी प्रदान करता है।

श्री राजनाथ सिंह ने 2,900 करोड़ रुपये ($350 मिलियन) से अधिक की 90 सीमा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 11 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में फैली 2,900 करोड़ रुपये ($350 मिलियन) से अधिक की सीमा सड़क संगठन (BRO) की 90 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है।
परियोजनाओं का उद्घाटन रक्षा मंत्री द्वारा जम्मू और कश्मीर (J&K) में एक कार्यक्रम में किया गया।
कार्यक्रम का आयोजन देवक ब्रिज पर किया गया थाबिश्नाह-कौलपुर-फूलपुर रोड पर, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री ने किया।

मुख्य विचार:
422.9 मीटर लंबा क्लास 70 आरसीसी देवक पुल रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, जो सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को बढ़ाता है और क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है।
उद्घाटन की गई एक और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना अरुणाचल प्रदेश में बालीपारा-चारदुआर-तवांग रोड पर 500 मीटर लंबी नेचिफू सुरंग थी।
उन्होंने पश्चिम बंगाल (WB) में पुनर्निर्मित बागडोगरा और बैरकपुर एयरफील्ड को भी समर्पित किया।
उन्होंने वर्चुअली पूर्वी लद्दाख में न्योमा एयरफील्ड की आधारशिला रखी।
लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत वाला यह हवाई क्षेत्र, लद्दाख में हवाई बुनियादी ढांचे को बढ़ाएगा और उत्तरी सीमा पर भारतीय वायु सेना की क्षमताओं को बढ़ाएगा।
यह दुनिया के सबसे ऊंचे हवाई क्षेत्रों में से एक होगा।
BRO 15,855 फीट की ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग शिनकुन ला सुरंग का निर्माण करने के लिए तैयार है।
यह सुरंग हिमाचल प्रदेश में लाहौल-स्पीति को लद्दाख में जास्कर घाटी से जोड़ेगी, जिससे हर मौसम में कनेक्टिविटी मिलेगी।

BRO के बारे में:
स्थापना: 7 मई 1960
मुख्यालय: नई दिल्ली, दिल्ली, भारत
महानिदेशक: लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी
BRO भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के स्वामित्व में एक वैधानिक निकाय है।
इसकी प्राथमिक भूमिका भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों और मित्रवत पड़ोसी देशों में सड़क नेटवर्क का विकास और रखरखाव करना है।

13वां इंडो-पैसिफिक सेना प्रमुख सम्मेलन (IPACC) 26 से 27 सितंबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा

13वां इंडो-पैसिफिक आर्मीज़ चीफ्स कॉन्फ्रेंस (IPACC) इस महीने की 26 से 27 तारीख तक नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में आयोजित किया जाएगा।
दो दिवसीय सम्मेलन में 30 हिंद-प्रशांत क्षेत्र के सेना प्रमुख भाग लेंगे और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग और सामूहिक रणनीतियों पर चर्चा करेंगे।
सम्मेलन में क्षेत्र में आपसी हित के मुद्दों और क्षेत्र में संकट को कम करने में सैन्य कूटनीति की भूमिका पर भी चर्चा होगी।
यह 13वां द्विवार्षिक कार्यक्रम होगा जिसकी मेजबानी भारतीय सेना और अमेरिकी सेना प्रशांत द्वारा की जाएगी।
अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ, जनरल जेम्स सी मैककॉनविले, अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ, उन दो कार्यक्रमों के लिए उपस्थित रहेंगे, जिनकी वह भारतीय सेना स्टाफ के प्रमुख जनरल मनोज पांडे के साथ सह-मेजबानी करेंगे।
क्षेत्र में बहुपक्षीय सुरक्षा साझेदारी सुनिश्चित करने के लिए दो अन्य सम्मेलन, इंडो-पैसिफिक आर्मीज़ मैनेजमेंट सेमिनार (IPAMS), और सीनियर एनलिस्टेड लीडर्स फोरम (SELF) भी मानेकशॉ सेंटर में अलग से आयोजित किए जाएंगे।
सम्मेलन के दौरान इंडो-पैसिफिक सेनाओं के प्रमुख संकटों को कम करने में सैन्य कूटनीति की भूमिका, सहयोग और अंतरसंचालनीयता बढ़ाने और आधुनिक सेनाओं द्वारा आत्मनिर्भरता की आवश्यकता के मुद्दों को संबोधित करेंगे।
इंडो-पैसिफिक दुनिया की 64 प्रतिशत आबादी को कवर करता है और सकल घरेलू उत्पाद में 63 प्रतिशत का योगदान देता है, जिसमें विश्व व्यापारिक व्यापार का 46 प्रतिशत भी शामिल है।
इंडो-पैसिफिक निर्विवाद रूप से विश्व अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने AAI उड़ान निरीक्षण बेड़े में दो नए B-360 प्रकार के विमान शामिल किए

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने AAI उड़ान निरीक्षण बेड़े में उन्नत राज्य उड़ान निरीक्षण प्रणाली से सुसज्जित दो नए बी-360 प्रकार के विमान जोड़े हैं।
सफदरजंग हवाई अड्डे पर नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री श्री विजय कुमार सिंह की उपस्थिति में प्रेरण समारोह हुआ।
नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यह पहल हवाई अड्डों पर नौवहन सहायता उपकरणों की सटीकता में सुधार करने में काफी मदद करेगी।
यह भारतीय नागरिक उड्डयन को आधुनिक बनाने की दिशा में एक कदम आगे है, जो अंतर्राष्ट्रीय विमानन में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार है।
मंत्रालय के अनुसार, इन नए विमानों के शामिल होने से AAI को देश के सभी हवाई अड्डों पर ग्राउंड रेडियो नेविगेशन और दृश्य सहायता के समय पर उड़ान अंशांकन को पूरा करने में मदद मिलेगी।
AAI पड़ोसी देशों में उड़ान अंशांकन करके आवश्यक सहायता भी प्रदान करेगा, जिससे राजस्व सृजन भी होगा।

रक्षा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उद्योग सहयोग पर भारत-मलेशिया संयुक्त उप-समिति की 10वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई

रक्षा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उद्योग सहयोग पर भारत-मलेशिया संयुक्त उप-समिति की 10वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई।
रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा अनुसंधान और उद्योग सहयोग की समीक्षा की गई और आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा हुई।
इसमें कहा गया है कि रक्षा उद्योग क्षेत्र से संबंधित चल रही बातचीत को और विस्तारित करने के लिए प्रभावी और व्यावहारिक पहल की खोज की गई।

3 पश्चिमी अफ्रीकी देशों के सैन्य नेताओं ने एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए

साहेल सुरक्षा समझौता माली, बुर्किना फासो और नाइजर के सैन्य नेताओं द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं।
माली, बुर्किना फासो और नाइजर के सैन्य नेताओं ने एक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए।
इन तीन साहेल देशों के मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने माली की राजधानी बमाको में इस समझौते की घोषणा की
लिप्टाको-गौरमा चार्टर ने साहेल राज्यों के गठबंधन (AES) की स्थापना की।
इसका मुख्य उद्देश्य सामूहिक रक्षा और पारस्परिक सहायता की वास्तुकला स्थापित करना है।
लिप्टाको-गौरमा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां माली, बुर्किना फासो और नाइजर की सीमाएं मिलती हैं।
यह गठबंधन तीन देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य और आर्थिक प्रयास है।
तीनों देश अल कायदा और इस्लामिक स्टेट से जुड़े इस्लामिक विद्रोहियों को रोकने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
इस समझौते से पश्चिम अफ्रीकी साहेल के तीनों देश किसी भी विद्रोह या बाहरी आक्रमण की स्थिति में एक-दूसरे की मदद करेंगे।
ये तीनों देश क्षेत्र में इस्लामी समूहों से निपटने के लिए फ्रांस समर्थित जी5 साहेल गठबंधन संयुक्त बल के सदस्य हैं।
सहेल उत्तर में सहारा और दक्षिण में सूडानी सवाना के बीच अफ्रीका में संक्रमण का पारिस्थितिकीय और जैव-भौगोलिक क्षेत्र है।
अफ्रीका के साहेल भाग में उत्तरी सेनेगल के पश्चिम से पूर्व भाग, दक्षिणी मॉरिटानिया, मध्य माली, उत्तरी बुर्किना फासो, अल्जीरिया के चरम दक्षिण, नाइजर, नाइजीरिया के चरम उत्तर, कैमरून और मध्य अफ्रीकी गणराज्य के चरम उत्तर, मध्य चाड, मध्य और दक्षिणी सूडान, दक्षिण सूडान के चरम उत्तर, इरिट्रिया और इथियोपिया के चरम उत्तर शामिल हैं।

सिंगापुर - भारतीय नौसेना और सिंगापुर गणराज्य की नौसेना के बीच वार्षिक नौसेना समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास शुरू

भारतीय नौसेना और सिंगापुर गणराज्य की नौसेना के बीच सिंगापुर-भारत वार्षिक नौसेना समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास इस महीने की 24 तारीख तक आयोजित किया जा रहा है।
SIMBEX दो नौसेनाओं के बीच अंतरसंचालनीयता और आपसी समझ को बढ़ाता है।
अभ्यास दो चरणों में आयोजित किया जाता है।
हार्बर चरण में पेशेवर बातचीत, क्रॉस-डेक दौरे, विषय वस्तु विशेषज्ञ आदान-प्रदान और खेल फिक्स्चर की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है।
SIMBEX के समुद्री चरण में वायु रक्षा, तोप फायरिंग, पनडुब्बी रोधी और अन्य समुद्री अभियानों के अभ्यास शामिल हैं।
रणविजय, कवरत्ती, और सिंधुकेसरी, लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान P81 ने अभ्यास में भाग लिया।
SIMBEX भारतीय नौसेना का किसी अन्य देश के साथ किया गया सबसे लंबा नौसैनिक अभ्यास है। दोनों नौसेनाओं की इकाइयां समुद्री क्षेत्र में संयुक्त रूप से बहु-अनुशासनात्मक संचालन के साथ अपने युद्ध-लड़ने के कौशल को निखारेंगी।

भारत-अमेरिकी सेना 25 सितंबर से इंडो-पैसिफिक सेना प्रमुखों के सम्मेलन की मेजबानी करेगी

रक्षा मंत्रालय, भारतीय सेना और संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना 25 से 27 सितंबर 2023 तक नई दिल्ली में एक संयुक्त सैन्य सम्मेलन की सह-मेजबानी करेगी।

पैंतीस देशों की सेनाओं के प्रमुख और प्रतिनिधि 13वें इंडो-पैसिफिक आर्मी चीफ्स कॉन्फ्रेंस IPACC, 47वें इंडो-पैसिफिक आर्मीज मैनेजमेंट सेमिनार IPAMS और 9वें सीनियर एनलिस्टेड लीडर्स फोरम SELF में भाग लेंगे।
मंत्रालय, इसमें मुख्य रूप से भारत-प्रशांत क्षेत्र की भूमि सेनाओं के सेना प्रमुख और वरिष्ठ स्तर के नेता शामिल होंगे।
इसमें कहा गया है कि सम्मेलन सुरक्षा और समसामयिक मुद्दों पर विचारों और विचारों के आदान-प्रदान की अनुमति देगा।
मंच का मुख्य प्रयास तटीय साझेदारों के बीच आपसी समझ, संवाद और मित्रता के माध्यम से भारत-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना होगा।
इस मंच का केंद्रीय विषय "शांति के लिए एक साथ: भारत-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना" है।
यह कार्यक्रम दिल्ली कैंट के मानेकशॉ सेंटर में आयोजित किया जाएगा और इसमें 150 से अधिक प्रतिनिधि विभिन्न पूर्ण और गोलमेज सत्रों में भाग लेंगे।
इसमें तीन स्तरों पर पूर्ण सत्र और अनौपचारिक बैठकें होंगी।

युद्ध अभ्यास सैन्य अभ्यास का 19वां संस्करण अलास्का में होगा

"अभ्यास युद्ध अभ्यास" का 19 वां संस्करण 25 सितंबर से 8 अक्टूबर, 2023 तक फोर्ट वेनराइट, अलास्का, संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) में आयोजित किया जाएगा।
अभ्यास का विषय संयुक्त राष्ट्र शासनादेश के अध्याय VII के तहत 'पर्वतीय/चरम जलवायु परिस्थितियों में एक एकीकृत युद्ध समूह का नियोजन' है।

टिप्पणी:

अभ्यास का 18वां संस्करण नवंबर 2022 में औली, उत्तराखंड, भारत में हुआ।
अभ्यास का पहला संस्करण 2002 में भारत के आगरा उत्तर प्रदेश (UP) में हुआ था।

युद्ध अभ्यास के बारे में:

यह भारतीय सेना और संयुक्त राज्य अमेरिका सेना द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक वार्षिक अभ्यास है।

प्रतिभागी:

भारतीय सेना की टुकड़ी: इस संस्करण में भाग लेने वाले भारतीय सेना दल में 350 कर्मी शामिल हैं।
लीड बटालियन: भारत की ओर से प्रमुख बटालियन मराठा लाइट इन्फैंट्री रेजिमेंट से संबद्ध है।
अमेरिकी सेना: अमेरिका की ओर से प्रथम ब्रिगेड कॉम्बैट टीम की 1-24 इन्फेंट्री बटालियन भाग लेगी।

उद्देश्य:

दोनों सेनाओं के बीच अंतरसंचालनीयता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान चलाने पर ध्यान केंद्रित करना।
इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सामरिक अभ्यास का अभ्यास किया जाएगा।
"पूर्व युद्ध अभ्यास-23" दोनों सेनाओं को एक-दूसरे से पारस्परिक रूप से सीखने की सुविधा प्रदान करेगा और दोनों सेनाओं के बीच संबंधों को और मजबूत करेगा।

मुख्य विचार:

दोनों पक्षों के कार्मिक सैन्य अभियानों के विभिन्न पहलुओं से संबंधित अपने अनुभवों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए विस्तृत चर्चा में शामिल होंगे।
इस अभ्यास में ब्रिगेड स्तर पर एकीकृत युद्ध समूहों का सत्यापन, ब्रिगेड/बटालियन स्तर पर एकीकृत निगरानी ग्रिड, हेलीबोर्न/एयरबोर्न तत्वों की तैनाती, रसद और हताहत प्रबंधन, निकासी, लड़ाकू चिकित्सा सहायता, और उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों और चरम जलवायु परिस्थितियों से संबंधित अन्य पहलू शामिल हैं।
युद्ध कौशल के व्यापक स्पेक्ट्रम में विचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान अभ्यास का एक हिस्सा होगा, जिसमें लड़ाकू इंजीनियरिंग, बाधा निवारण, खदान युद्ध और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) युद्ध जैसे क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा।

रक्षा मंत्रालय के बारे में:

रक्षा मंत्री: राजनाथ सिंह

राज्य मंत्री: रक्षा मंत्रालय
रक्षा सचिव: गिरिधर अरमाने

भारतीय सेना में 600 स्वदेशी निर्मित 'विभव' एंटी-टैंक माइंस शामिल किए गए

भारतीय सेना ने 600 स्वदेश निर्मित स्व-निष्क्रिय एंटी-टैंक बारूदी सुरंगों को शामिल किया है जिन्हें "विभव" के नाम से जाना जाता है।

विभव के बारे में:

विभव एक स्व-निष्क्रिय एंटी-टैंक माइन है, अर्थात इसमें एक निश्चित अवधि के बाद खुद को निष्क्रिय करने की क्षमता है।
इन एंटी-टैंक खदानों को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) के सहयोग से पूरी तरह से भारत के भीतर डिजाइन और विकसित किया गया था।
विभव'' को प्वाइंट-अटैक एंटी-टैंक युद्ध सामग्री के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसे विशेष रूप से दुश्मन के बख्तरबंद वाहनों को स्थिर करने या नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
भारतीय सेना के लिए "विभव" खानों का उत्पादन कल्याणी समूह द्वारा किया जा रहा है।
इन खदानों में ऑपरेटरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत विस्फोटक, यांत्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा सुविधाएँ शामिल हैं।
विभव'' एक इलेक्ट्रॉनिक एंटी-हैंडलिंग और एंटी-लिफ्ट डिवाइस (EAHALD) से लैस है, जो हथियारबंद होने के बाद 120 दिनों तक सक्रिय रहता है।
खदानों में यांत्रिक टाइमर हैं, और 120 दिनों के बाद, उन्हें अनपेक्षित विस्फोटों के जोखिम को कम करते हुए, स्वयं-निष्प्रभावी करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
विभव'' का भंडारण जीवन 10 वर्ष है और इसके लिए विशेष भंडारण स्थितियों की आवश्यकता नहीं होती है।

भारतीय सेना के बारे में:

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS): जनरल अनिल चौहान
थल सेनाध्यक्ष (CoAS): जनरल मनोज पांडे

भारतीय नौसेना जहाज सह्याद्री ने पहले भारत-इंडोनेशिया-ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया

भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित युद्धपोत भारतीय नौसेना जहाज (INS) सह्याद्री, इंडो-पैसिफिक में तैनात मिशन, ने रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना (RAN) और इंडोनेशियाई नौसेना के जहाजों और विमानों के साथ पहले त्रिपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया।
INS सह्याद्रि, स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रोजेक्ट-17 क्लास मल्टीरोल स्टील्थ फ्रिगेट्स का तीसरा जहाज, मझगांव डॉक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र में बनाया गया था और इसकी कमान कैप्टन राजन कपूर के पास है।

उद्देश्य:

त्रिपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के समुद्री देशों के बीच साझेदारी को मजबूत करना है। इसने एक स्थिर, शांतिपूर्ण और सुरक्षित भारत-प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने के लिए उनकी सामूहिक क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया।
इस अभ्यास ने भाग लेने वाली नौसेनाओं को समुद्री क्षेत्र में सहयोग और सहयोग को बढ़ावा देने, अनुभव और विशेषज्ञता साझा करने का अवसर प्रदान किया।
अभ्यास के दौरान, जटिल सामरिक और युद्धाभ्यास अभ्यास हुए।
इसमें इंटीग्रल हेलीकॉप्टरों की क्रॉस-डेक विज़िट और क्रॉस-डेक लैंडिंग शामिल थी, जिसने चालक दल के प्रशिक्षण में योगदान दियासदस्यों और भाग लेने वाली नौसेनाओं के बीच अंतरसंचालनीयता में वृद्धि।

नवीनतम समाचार:

सितंबर 2023 को, भारतीय नौसेना के जहाज रणविजय और कवरत्ती और पनडुब्बी INS सिंधुकेसरी सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास (SIMBEX) के 30 वें संस्करण में भाग लेने के लिए सिंगापुर पहुंचे, जो भारतीय नौसेना और सिंगापुर गणराज्य नौसेना (RSN) के बीच एक वार्षिक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है, जो 1994 से संचालित किया जा रहा है।

रक्षा मंत्रालय के बारे में:

रक्षा मंत्री:-राजनाथ सिंह
राज्य मंत्री: अजय भट्ट

भारतीय वायु सेना ने हिंडन वायु सेना स्टेशन पर पहला C-295 परिवहन विमान शामिल किया

भारतीय वायु सेना (IAF) ने अपना पहला C-295 परिवहन विमान उत्तर प्रदेश (UP) के हिंडन वायु सेना स्टेशन में शामिल किया।
विमान को IAF स्क्वाड्रन नंबर 11 को सौंपा जाएगा, जिसे "द राइनोस" के नाम से जाना जाता है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने प्रेरण समारोह में भाग लिया, जिसमें 'सर्व धर्म पूजा' (बहु-विश्वास प्रार्थना) शामिल थी।
सी-295 परिवहन विमान एचएस-748 एवरो विमान की जगह लेगा, जो भारतीय वायुसेना की मध्यम-लिफ्ट सामरिक क्षमता को बढ़ाएगा।
सितंबर 2021 में, भारत ने 21,935 करोड़ रुपये की लागत से 56 एयरबस C295 विमानों के अधिग्रहण को औपचारिक रूप दिया।

मुख्य विचार:

ऑर्डर पर मौजूद 56 विमानों में से पहले 16 C295 को सेविले में सैन पाब्लो सुर साइट पर असेंबल किया जाएगा।
ऑर्डर के शेष 40 सी295 का निर्माण और संयोजन वडोदरा में फाइनल असेंबली लाइन (FAL) में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (TASL) के साथ साझेदारी में किया जाएगा।
इन विमानों के लिए घटकों का उत्पादन हैदराबाद में मुख्य संविधान सभा (MCA) सुविधा में शुरू हो गया है।
ये विमान निजी क्षेत्र के पहले 'मेक इन इंडिया' एयरोस्पेस कार्यक्रम का हिस्सा हैं।
पहला भारत-निर्मित C295 सितंबर 2026 में वडोदरा कारखाने से तैयार होने की उम्मीद है, और अंतिम विमान अगस्त 2031 तक IAF को डिलीवरी के लिए निर्धारित है।

भारतीय वायुसेना के बारे में:

मुख्यालय: नई दिल्ली, दिल्ली
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ: सामान्य अनिल चौहान
वायुसेनाध्यक्ष: एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी
वायु सेना उप प्रमुख: वायुमार्शल अमर प्रीत सिंह

स्पोर्ट्स करेंट अफेयर्स

ज्यूरिख डायमंड लीग में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहे:

नव-विजेता विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा ज्यूरिख में डायमंड लीग मीटिंग के पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 85.71 मीटर के अंतिम राउंड थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर रहे।
25 वर्षीय चोपड़ा, जो मौजूदा ओलंपिक चैंपियन भी हैं, ने 80.79 मीटर, 85.22 मीटर और 85.71 मीटर के तीन कानूनी थ्रो किए।
वह चेक गणराज्य के जैकब वाडलेज्च से पीछे रहे, जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था।
भारतीय सुपरस्टार, जो इस सीज़न में अजेय रहे, ने तीन मुकाबलों में 23 अंकों के साथ 17 सितंबर को यूजीन, यूएसए में होने वाले डायमंड लीग फाइनल के लिए क्वालीफाई किया।
उन्होंने पिछले साल डायमंड लीग ट्रॉफी जीती थी

नवीनतम समाचार

जुलाई 2023 में, स्टार भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 87.66 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ लॉज़ेन डायमंड लीग 2023 का खिताब जीता।

जर्मनी के बारे में:

राष्ट्रपति: फ्रैंक-वाल्टर स्टीनमीयर
राजधानी: बर्लिन
मुद्रा- यूरो

ग्रैंडमास्टर डी गुकेश अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी बन गए

किशोर ग्रैंडमास्टर डी. गुकेश तीन दशक से अधिक समय के बाद भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी के रूप में महान विश्वनाथन आनंद की जगह ले ली है।
आनंद जुलाई 1986 से भारत के नंबर 1 रहे हैं।
17 वर्षीय चेन्नई ग्रैंडमास्टर, जो हाल ही में बाकू में फिडे विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में मैग्नस कार्लसन से हार गए थे, आनंद से आगे निकलकर विश्व में 8वें नंबर पर पहुंच गए।
FIDE रेटिंग सूची के शीर्ष 10 में गुकेश का प्रवेश एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
वह 1 अगस्त से अब तक रेटिंग सूची में तीन पायदान ऊपर चढ़े हैं
नवीनतम FIDE रेटिंग के अनुसार, गुकेश की रेटिंग 2758 है, जबकि आनंद की रेटिंग 2754 है।
गुकेश ने जीत हासिल की और लाइव रेटिंग में विश्वनाथन आनंद को पछाड़ दिया।

FIDE के बारे में

मुख्यालय: लॉज़ेन, स्विट्जरलैंड
स्थापना: 20 जुलाई 1924
राष्ट्रपति: अर्कडी ड्वोरकोविच
सदस्यता: 200 राष्ट्रीय संघ

नवीनतम समाचार

मई 2023 में, चीन के ग्रैंडमास्टर डिंग लिरेन फिडे विश्व चैम्पियनशिप 2023 के अंतिम रैपिड टाईब्रेक गेम में रूसी ग्रैंडमास्टर इयान नेपोमनियाची को हराकर नए विश्व चैंपियन थे।

पेनल्टी शूटआउट में भारत ने पाकिस्तान पर जीत हासिल कर पुरुष हॉकी 5एस एशिया कप जीत लिया:

भारत फाइनल में पेनल्टी शूटआउट के बाद पाकिस्तान को 6-4 से हराकर एशियाई हॉकी 5एस चैंपियन का ताज पहनाया गया।
तीन मुकाबलों में यह पहली बार है कि भारत ने हॉकी 5एस प्रारूप में पाकिस्तान को हराया है।
दूसरे हाफ में 2-4 से पिछड़ने के बाद मोहम्मद राहील के दो गोल के बाद भारत खेल को शूटआउट में ले गया।
शूटआउट में पाकिस्तान ने अपने सारे मौके गँवा दिए जबकि मनिंदर सिंह ने ताबूत में हथौड़ा मारकर शूटआउट में भारत के लिए दूसरा गोल किया।
इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में मलेशिया को 10-4 से हराया था।
ओमान को 7-3 से हराकर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा

नवीनतम समाचार

जून 2023 में, भारत ने जापान के काकामिघारा में अपना पहला महिला जूनियर हॉकी एशिया कप जीतने के लिए चार बार के चैंपियन दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराया।

FIH के बारे में

मुख्यालय: लॉज़ेन, स्विट्जरलैंड

संस्थापक: पॉल लेउटी
स्थापित: 7 जनवरी 1924, पेरिस, फ्रांस
CEO: थिएरी वेइल

डेनिएल मैकगेही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनने जा रही हैं

डेनिएल मैकगैही 29 वर्षीया अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला खिलाड़ी बनने जा रही हैं।
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पहली बार, एक ट्रांसजेंडर महिला खिलाड़ी ICC से संबंधित टूर्नामेंट में भाग लेगी।
ऑस्ट्रेलिया के दाएं हाथ के बल्लेबाज, जो 2020 में कनाडा चले गए थे, ने ICC के अनुसार, पुरुष-से-महिला (MTF) संक्रमण के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा किया था।
मैकगेही को महिला टी20 अमेरिका क्वालीफायर के लिए कनाडा की टीम में नामित किया गया है, जो टी20 विश्व कप 2024 का मार्गदर्शक टूर्नामेंट है।
मैकगेही सितंबर में चार-टीम अमेरिका क्वालीफायर के लिए चुना गया है, जिसमें कनाडा का सामना ब्राजील, अर्जेंटीना और USA से होगा, जिसमें विजेता बांग्लादेश में 2024 टी20 विश्व कप के लिए वैश्विक क्वालीफायर में आगे बढ़ेंगे।

कनाडा के बारे में

राजधानी: ओटावा
प्रधान मंत्री: जस्टिन ट्रूडो
कैनेडियन डॉलर कनाडा की मुद्रा है।

फुटबॉल में, मोहन बागान ने कोलकाता में डूरंड कप 2023 जीतने के लिए ईस्ट बंगाल को 1-0 से हराया

मोहन बागान ने कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में ईस्ट बंगाल को 1-0 से हराकर डूरंड कप 2023 ट्रॉफी जीती।
मोहन बागान ने 23 वर्षों में पहली बार 132वां डूरंड कप जीता। इस जीत को दर्ज करते हुए, मोहन बागान एसजी डूरंड कप के इतिहास में 17 खिताब जीतने वाली पहली टीम बन गई है।
ईस्ट बंगाल डूरंड कप में दूसरी सबसे सफल टीम है और उसके नाम 16 खिताब हैं।
इससे पहले, मोहन बागान ने 2004, 2009 और 2019 में डूरंड कप फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन, तब जीत दर्ज नहीं कर सके थे।

नवीनतम समाचार

ओडिशा एफसी ने कोझीकोड के EMS कॉर्पोरेशन स्टेडियम में सुपर कप के फाइनल में बेंगलुरु एफसी को हराकर अपना पहला खिताब जीता।
अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय फुटबॉल आइकन प्रदीप कुमार बनर्जी के सम्मान में 23 जून को 'AIFF ग्रासरूट दिवस' के रूप में मनाने का फैसला किया है।

पहला 'क्लाइमेट कप' फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 लेह, लद्दाख में शुरू हुआ

क्लाइमेट फुटबॉल कप 2023 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पहला पेशेवर फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू हुआ।
सात दिवसीय कार्यक्रम लेह के स्पितुक में ओपन एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा।
प्रतियोगिता में चार टीमें भाग ले रही हैं।
ये हैं - दिल्ली फुटबॉल क्लब, तिब्बती नेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, लद्दाख प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब और लद्दाख स्टेट टीम।
ओपन स्टेडियम लद्दाख की अत्याधुनिक खेल सुविधा है।
यह स्टेडियम समुद्र तल से 11 हजार फीट की ऊंचाई पर बना है।
इसमें कृत्रिम घास लगाई गई है जो चरम मौसम की स्थिति का सामना कर सकती है।
यह स्टेडियम हाल ही में खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत बनाया गया है।
इसमें 30 हजार दर्शकों के बैठने की सुविधा है।

यह दुनिया के सबसे ऊंचे स्टेडियमों में से एक है।

लद्दाख के बारे में:

उपराज्यपाल: बीडी मिश्रा
राजधानियाँ: लेह, कारगिल

नवीनतम समाचार

जून 2023 में, महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में, लद्दाख पुलिस विभाग ने कारगिल जिले में पहले महिला पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया।

थाईलैंड महिला क्रिकेट टीम की नट्टाया बूचाथम एसोसिएट नेशन की ओर से टी-20 में 100 विकेट लेने वाली पहली गेंदबाज बनीं

थाईलैंड की स्पिनर नट्टाया बूचाथम ने कुवैत के खिलाफ आईसीसी महिला टी20 विश्व कप एशिया क्षेत्र क्वालीफायर गेम के दौरान तीन विकेट लेकर इतिहास रच दिया।

मैच में, बूचाथम ने टी20ई में 100 विकेट पूरे करने के लिए 3/3 के आंकड़े के साथ समापन किया, और टी20ई में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने वाले एसोसिएट राष्ट्र के पुरुष और महिला दोनों वर्ग के पहले खिलाड़ी बन गए।

36 वर्षीय स्पिन ऑलराउंडर ने अब 73 एकदिवसीय मैचों में 9.96 की औसत से 101 विकेट लिए हैं, जिससे वह दस से कम गेंदबाजी औसत के साथ इस मुकाम तक पहुंचने वाले एकमात्र गेंदबाज बन गए हैं।

वह न केवल 100 T20I विकेट लेने वाली दुनिया की एकमात्र महिला क्रिकेटर बन गईं, बल्कि सूची में उनका गेंदबाजी औसत भी सबसे अधिक है।

अगर वह 6 सितंबर को हांगकांग के खिलाफ थाईलैंड के आगामी मैच में एक विकेट लेती हैं, तो वह मौजूदा नंबर 1 गेंदबाज सोफी एक्लेस्टोन के 102 विकेट के कुल आंकड़े को पीछे छोड़ देंगी।

अमूल XIX एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल का आधिकारिक प्रायोजक होगा

अमूल चीन के हांगझोउ में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक होने वाले एशियाई खेलों 2022 के लिए भारतीय दल का आधिकारिक प्रायोजक होगा।

लंदन 2012 ओलंपिक के बाद से अमूल ने सभी भारतीय दलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के माध्यम से एक भारतीय खिलाड़ी के साथ साझेदारी की है।ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल और हम अपने एक दशक पुराने रिश्ते को और मजबूत करके प्रसन्न हैं।

इस सहयोग के हिस्से के रूप में, अमूल खिलाड़ी के प्रयासों का जश्न मनाने के लिए अपने संचार में एकीकृत लोगो का उपयोग करेगा।

भारतीय दल हांग्जो में एशियाई खेलों 2022 में 38 विभिन्न खेलों में 634 एथलीटों को मैदान में उतारेगा, जिसमें एथलेटिक्स में 65 का सबसे बड़ा दल होगा।

अमूल के बारे में

संस्थापक: वर्गीस कुरियन, त्रिभुवनदास किशिभाई पटेल;
स्थापना: 14 दिसंबर 1946
मुख्यालय: आनंद, गुजरात
प्रबंध निदेशक: जयेन मेहताजयेन मेहता

अमूल, पश्चिमी राज्य गुजरात में स्थित एक डेयरी सहकारी समिति, दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादकों में से एक है।

यह गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ लिमिटेड (GCMMF), सहकारिता विभाग, गुजरात सरकार के स्वामित्व में है।

चीन के बारे में:

राष्ट्रपति: शी जिनपिंग
राजधानी: बीजिंग

मुद्रा: रॅन्मिन्बी

नवीनतम समाचार

मई 2023 में, राज्य के स्वामित्व वाले पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने मुद्रा योजना के तहत पूरे भारत में अमूल के आपूर्ति नेटवर्क को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ लिमिटेड (GCMMFL), जिसे अमूल के नाम से जाना जाता है, के साथ साझेदारी की है।

जून 2023 में, विज्ञापन उद्योग अनुभवी और 1960 के दशक में शुरू हुए प्रतिष्ठित 'अमूल गर्ल' अभियान के निर्माता सिल्वेस्टर दाकुन्हा का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

ICC, इंडसइंड बैंक बहु-वर्षीय प्रायोजन समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे

इंडसइंड बैंक भारत में पुरुष क्रिकेट विश्व कप से शुरुआत करते हुए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के साथ एक बहु-वर्षीय प्रायोजन समझौते पर सहमति व्यक्त की है।

बहु-वर्षीय सौदे का मूल्य $20-$24 मिलियन (लगभग 160-200 करोड़ रुपये) है।

यह पता चला है कि इंडसइंड बैंक और मास्टरकार्ड ने डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म भारतपे और एड-टेक कंपनी बायजू की जगह ले ली है, जिन्होंने वित्तीय संकट के कारण समय से पहले ICC के साथ अपना जुड़ाव खत्म करने का फैसला किया है।

भारतपे और बायजू Unacademy, MPL और Paytm जैसे अन्य तकनीकी स्टार्टअप में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने निजी इक्विटी फंडिंग में गिरावट और लाभप्रदता पर ध्यान केंद्रित करने के बीच अपने प्रायोजन निवेश में कटौती की है।

ICC के अन्य शीर्ष स्तरीय प्रायोजकों में MRF टायर्स, बुकिंग.कॉम, अरामको और एमिरेट्स शामिल हैं।

ICC के बारे में

मुख्यालय: दुबई, संयुक्त अरब अमीरात
स्थापना: 15 जून 1909
CEO: ज्योफ एलार्डिस
अध्यक्ष: ग्रेग बार्कले

इंडसइंड बैंक के बारे में:

CEO: सुमंत कठपालिया
मुख्यालय: मुंबई
संस्थापक: एसपी हिंदुजा
स्थापित: अप्रैल 1994, मुंबई

एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारतीय पुरुष टीम ने कांस्य पदक के साथ समापन किया

टेबल टेनिस में, भारतीय पुरुष टीम कोरिया गणराज्य के प्योंगचांग में चीनी ताइपे से सेमीफाइनल में हार के बाद एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक के साथ समाप्त हुई।

शरथ कमल, हरमीत देसाई और साथियान ज्ञानसेकरन की भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम अपने अंतिम चार मैचों में 0-3 से हार गई।

प्रतियोगिता में हारने वाले दो सेमीफाइनलिस्टों को कांस्य पदक से सम्मानित किया जाता है।

एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए क्वालीफायर भी थी।

भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के बारे में

अध्यक्ष: मेघना अहलावत
स्थापित: 1926
सचिव: कमलेश मेहता
मुख्यालय: दिल्ली
सदस्यता: 32 राज्य इकाइयाँ और 37 संस्थाएँ

दक्षिण कोरिया के बारे में:

राष्ट्रपति: यूं सुक येओल
प्रधान मंत्री: हान डक-सू
राजधानी: सियोल
मुद्रा: दक्षिण कोरियाई वोन

नवीनतम समाचार

जून 2023 में, सुतीर्था मुखर्जी और अयहिका मुखर्जी की भारतीय महिला युगल जोड़ी ने मियु किहारा और मिवा हरिमोटो की जापानी जोड़ी को हराकर ट्यूनिस में विश्व टेबल टेनिस (WTT) कंटेंडर टूर्नामेंट जीता।

डीडी स्पोर्ट्स को डीडी स्पोर्ट्स एचडी के रूप में पुनः ब्रांड किया गया

प्रसार भारती, देश के सार्वजनिक प्रसारक ने डीडी स्पोर्ट्स को डीडी स्पोर्ट्स एचडी के रूप में पुनः ब्रांडेड किया है।
यह जुड़ाव इसके प्रसारण लाइनअप में एक और हाई-डेफिनिशन चैनल को शामिल करने का प्रतीक है।
डीडी स्पोर्ट्स एचडी ने मौजूदा एशिया कप क्रिकेट मैचों का प्रसारण करके अपनी शुरुआत की।
उम्मीद है कि डीडी स्पोर्ट्स एचडी अपने हाई-डेफिनिशन कंटेंट और खेल प्रेमियों के देखने के अनुभव को बेहतर बनाने के कारण खेल प्रेमियों के लिए पसंदीदा विकल्प बन जाएगा।
डीडी स्पोर्ट्स ने चैनल पर ताजा और रोमांचक सामग्री लाने के लिए NBA (नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन) और PGTA (प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया) जैसे प्रमुख खेल संगठनों के साथ साझेदारी की है।
ये सहयोग उपलब्ध खेल सामग्री की विविधता को बढ़ाना।
अब डीडी स्पोर्ट्स एचडी लॉन्च करने के निर्णय के साथ, चैनल प्रमुख अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों और खेलो इंडिया गेम्स, शीतकालीन खेलों और दिव्यांगों के लिए खेल जैसे जमीनी स्तर के परिवर्तनकारी आयोजनों के लिए वन-स्टॉप डेस्टिनेशन बन जाएगा।

डीडी स्पोर्ट्स का इतिहास:

डीडी स्पोर्ट्स को मूल रूप से 18 मार्च 1998 को लॉन्च किया गया था।
प्रारंभ में, यह दिन में 6 घंटे खेल कार्यक्रम प्रसारित करता था, जिसे बाद में 1999 में 12 घंटे तक बढ़ा दिया गया।
1 जून 2000 से, डीडी स्पोर्ट्स चौबीसों घंटे चलने वाला सैटेलाइट चैनल बन गया।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के बारे में:

कैबिनेट मंत्री: अनुराग ठाकुर
राज्य मंत्री: एल मुरुगन

नोवाक जोकोविच ने यूएस ओपन फाइनल में डेनियल मेदवेदेव को हराकर अपना रिकॉर्ड 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता:

यूएस ओपन टेनिस में नोवाक जोकोविच ने 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतकर इतिहास रच दिया।
सर्बियाई स्टार जोकोविच ने न्यूयॉर्क शहर के आर्थर ऐश स्टेडियम में यूएस ओपन 2023 पुरुष एकल फाइनल जीतने के लिए रूस के डेनियल मेदवेदेव को 63, 76, 63 से हराया।
इस के साथ,36 साल काजोकोविच ने मार्गरिट कोर्ट के 24 ग्रैंड स्लैम टेनिस खिताब के रिकॉर्ड की बराबरी की, जो इतिहास में किसी भी खिलाड़ी द्वारा सबसे अधिक है।
जोकोविच, जो पहले से ही सबसे उम्रदराज फ्रेंच ओपन एकल चैंपियन हैं, प्रो युग में सबसे उम्रदराज यूएस ओपन एकल चैंपियन बन गए।
महिला युगल में 16वीं वरीयता प्राप्त न्यूजीलैंड-कनाडाई जोड़ी एरिन राउटलिफ और गैब्रिएला डाब्रोव्स्की ने 12वीं वरीयता प्राप्त जर्मन, रूसी जोड़ी लौरा सीगमुंड और वेरा ज्वोनारेवा की जोड़ी को 76, 63 से हराकर खिताब जीता।

इससे पहले, अमेरिकी किशोर टेनिस सनसनी कोको गॉफ ने बेलारूसी आर्यना सबालेंका को 26, 63, 62 से हराकर अपना पहला महिला एकल खिताब हासिल किया।

नवीनतम समाचार

जून 2023 में, टेनिस में, सर्बियाई नोवाक जोकोविच ने पेरिस में फ्रेंच ओपन 2023 के पुरुष एकल फाइनल में कैस्पर रूड पर सीधे सेटों की जीत के साथ प्रतिष्ठित 23 ग्रैंड स्लैम खिताब तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बनकर इतिहास रच दिया।
जुलाई 2023 में, विंबलडन टेनिस में, विश्व के नंबर एक कार्लोस अलकराज ने फाइनल में 16 76(6) 61 36 64 की जीत के साथ अपना पहला विंबलडन 2023 खिताब और अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के लिए ऑलइंग्लैंड क्लब में नोवाक जोकोविच के लंबे शासन को समाप्त कर दिया।

अमेरिकी किशोरी कोको गॉफ ने आर्यना सबालेंका के खिलाफ रोमांचक मैच में पहला यूएस ओपन महिला एकल खिताब जीता:

यूएस ओपन टेनिस में, अमेरिकी किशोर टेनिस सनसनी कोको गॉफ ने न्यूयॉर्क में खिताबी मुकाबले में आर्यना सबालेंका को हराकर अपना पहला महिला एकल खिताब हासिल किया।
गॉफ ने आर्थर ऐश स्टेडियम कोर्ट पर दमदार प्रदर्शन करते हुए 26, 63, 62 से जीत दर्ज की।
मिक्स्ड डबल्स में कजाखस्तान की अन्ना दानिलिना और फिनलैंड की हैरी हेलियोवारा की जोड़ी ने जेसिका पेगुला और ऑस्टिन क्राइसेक की नंबर एक वरीयता प्राप्त जोड़ी को हराकर खिताब जीता।
महिला युगल में न्यूजीलैंड, कनाडाई जोड़ी एरिन राउटलिफ और गैब्रिएला
अंतिम मुकाबले में डाब्रोवस्की का मुकाबला जर्मनी की रूसी जोड़ी लॉरा सीजमंड और वेरा ज्वोनारेवा से होगा।
पुरुष एकल में विश्व नंबर 2 नोवाक जोकोविच प्रतिस्पर्धा करेंगे न्यूयॉर्क के आर्थर ऐश स्टेडियम में यूएस ओपन 2023 टेनिस फाइनल में दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव से मुकाबला

गॉफ़ के बारे में:

40 दिनों की अवधि में, गॉफ़ ने तीन बड़े खिताब जीते हैं और अपने पिछले 19 मैचों में से कुल 18 जीते हैं।
उन्होंने इससे पहले अगस्त में वाशिंगटन ओपन और सिनसिनाटी ओपन जीता था।
वह इस सदी में यूएस ओपन एकल खिताब जीतने वाली पहली अमेरिकी किशोरी हैं और कुल मिलाकर केवल तीसरी हैं।

मैक्स वेरस्टैपेन ने मोंज़ा में लगातार 10वीं जीत दर्ज करके F1 इतिहास रचा

मैक्स वेरस्टैपेन और रेड बुल इटालियन ग्रां प्री 2023 में इतिहास रच दिया, क्योंकि डच सनसनी ने अपनी लगातार 10वीं फॉर्मूला 1 जीत हासिल की।
ऐसा करते हुए, वेरस्टैपेन ने 2009 से सेबस्टियन वेट्टेल की लगातार नौ जीत को पीछे छोड़ दिया, और रेड बुल ने अपनी जीत की लय को उल्लेखनीय 15 रेसों तक बढ़ा दिया।
वेरस्टापेन ने सात मई को मियामी ग्रां प्री के बाद से हर रेस जीती है और वह चैंपियनशिप की हैट्रिक जीतने वाले ड्राइवरों में जुआन मैनुअल फांगियो, माइकल शूमाकर, सेबेस्टियन वेटेल और लुईस हैमिल्टन के साथ शामिल होंगे।
मोंजा सर्किट इस रिकॉर्ड-ब्रेकिंग प्रदर्शन के लिए मंच था, जहां वेरस्टापेन ने शुरू में फेरारी के पोल-सिटिंग कार्लोस सैंज के पीछे लाइन लगाई।

नवीनतम समाचार

जुलाई 2023 में, मैक्स वेरस्टैपेन ने लगातार तीसरे विश्व खिताब की ओर एक और कदम बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रियाई ग्रांड प्रिक्स जीता।
जुलाई 2023 में, रेड बुल के रहते हुए मैक्स वेरस्टैपेन ने ब्रिटिश ग्रां प्री जीता
फॉर्मूला वन सीज़न के लिए अजेय रहे और मैकलेरन के 1988 में लगातार 11 जीत के रिकॉर्ड की बराबरी की।
जून 2023 में, मैक्स वेरस्टैपेन ने मोनाको जीपी जीता, का सामना करना पड़समापन चरण में ट्रैक पर बारिश की बौछार के कारण चुनौतीपूर्ण स्थितियाँ थीं।

F1 ग्रांड प्रिक्स विजेताओं की सूची सूची: 2023

1.	**बहरीन ग्रांड प्रिक्स**	**मैक्स वेरस्टैपेन (रेड बुल - नीदरलैंड)**
2.	सऊदी अरब ग्रां प्री	सर्जियो पेरेज़ (रेड बुल - मेक्सिको)
3	ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री	मैक्स वेरस्टैपेन (रेड बुल - नीदरलैंड)
4.	अज़रबैजान ग्रां प्री	सर्जियो पेरेज़ (रेड बुल - मेक्सिको)
5.	मियामी ग्रां प्री	मैक्स वेरस्टैपेन (रेड बुल - नीदरलैंड)
6	एमिलिया रोमाग्ना ग्रांड प्रिक्स	रद्द
7	मोनाको ग्रैंड प्रिक्स	मैक्स वेरस्टैपेन (रेड बुल - नीदरलैंड)
8	स्पैनिश ग्रां प्री	मैक्स वेरस्टैपेन (रेड बुल - नीदरलैंड)
9	कैनेडियन ग्रां प्री	मैक्स वेरस्टैपेन (रेड बुल - नीदरलैंड)
10	ऑस्ट्रियाई ग्रां प्री	मैक्स वेरस्टैपेन (रेड बुल - नीदरलैंड)
11	ब्रिटिश ग्रां प्री	मैक्स वेरस्टैपेन (रेड बुल - नीदरलैंड)
12	हंगेरियन ग्रां प्री	मैक्स वेरस्टैपेन (रेड बुल - नीदरलैंड)
13	बेल्जियम ग्रां प्री	मैक्स वेरस्टैपेन (रेड बुल - नीदरलैंड)
14	डच ग्रां प्री	मैक्स वेरस्टैपेन (रेड बुल - नीदरलैंड)
15	इटालियन ग्रां प्री	मैक्स वेरस्टैपेन (रेड बुल - नीदरलैंड)

सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का 62वां संस्करण 19 सितंबर को होगा

सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट का 62वां संस्करण इस साल 19 सितंबर से आयोजित किया जाएगा।
टूर्नामेंट में 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 109 टीमें भाग लेंगी।
अंडर-17 जूनियर लड़कों और लड़कियों के टूर्नामेंट दिल्ली और गुरुग्राम में आयोजित किए जाएंगे, जबकि अंडर-14 सब जूनियर लड़कों की प्रतियोगिता बेंगलुरु में आयोजित की जाएगी।
एयर मार्शल आरके आनंद और उपाध्यक्ष सुब्रतो मुखर्जी खेल शिक्षा सोसायटीबताया किइस टूर्नामेंट का उद्देश्य जमीनी स्तर पर फुटबॉल को बढ़ावा देना है।
सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट एक प्रतिष्ठित अंतर-स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट है जो हर साल आयोजित किया जाता है। इस टूर्नामेंट का नाम एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने का विचार रखा था।
यह एक वार्षिक आयोजन है जो 1960 में शुरू हुआ था।

यह एक अनोखा टूर्नामेंट है जहां सभी राज्यों और विदेशी देशों की चैंपियन स्कूल टीमें इस टूर्नामेंट में भाग लेती हैं।

नवीनतम समाचार

मई 2023 में, भारतीय फुटबॉल टीम के मिडफील्डर लालियानजुआला चांग्ते 2022-23 के लिए AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर नामित किया गया, जबकि मनीषा कल्याण ने लगातार दूसरी बार महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता।

विराट कोहली सबसे तेज 13,000 वनडे रन बनाने वाले खिलाड़ी बने, शतक जड़ा

भारत के बल्लेबाज विराट कोहली कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप सुपर 4 मुकाबले के दौरान सबसे तेज 13,000 वनडे रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए।

34 वर्षीय खिलाड़ी ने केवल 277 पारियों में यह उपलब्धि हासिल करके साथी भारतीय दिग्गज सचिन तेंदुलकर (321 पारी) के रिकॉर्ड को बेहतर बनाया।

कोहली ने शाहीन अफरीदी की गेंद पर डबल रन लेकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की।

कोहली ने शतक के साथ शीर्ष पर एक चेरी जोड़ी।

अगली गेंद पर उन्होंने वनडे में अपना 47वां शतक पूरा किया।

इसके अतिरिक्त, इस शतक के साथ, कोहली ने अब इस स्टेडियम में लगातार चार शतक बनाए हैं, जो दक्षिण अफ्रीका के महान हाशिम अमला के साथ एक ही स्थान पर संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा शतक हैं।

अन्य तीन शतक श्रीलंका के खिलाफ थे- जिनमें से दो 2017 में और एक 2012 में आया था।

नवीनतम समाचार

टीम इंडिया के बल्लेबाज विराट कोहली ने त्रिनिदाद के पोर्ट ऑफ स्पेन में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दौरान अपने 500वें अंतरराष्ट्रीय मैच में शतक बनाने वाले पहले क्रिकेटर बनकर इतिहास रच दिया।

भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा अमेरिका के यूजीन में डायमंड लीग फाइनल में पुरुषों की स्पर्धा में दूसरे स्थान पर रहे

भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा अमेरिका के ओरेगॉन के यूजीन में डायमंड लीग फाइनल में पुरुषों की स्पर्धा में दूसरे स्थान पर रहे।

भारतीय का सर्वश्रेष्ठ 83.80 मीटर का थ्रो उनके दूसरे प्रयास में आया।

हालाँकि, चेक गणराज्य के जैकब वाडलेज्च ने 84.24 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ अपना तीसरा खिताब जीता।

ओलिंपिक राज कर रहा है और विश्व चैंपियन चोपड़ा, जिनके पास 89.94 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड है, ने पिछले साल उसी स्थान पर 88.13 मीटर के प्रयास के साथ विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था।

इस महीने की शुरुआत में, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले चोपड़ा, अपने डायमंड लीग खिताब का बचाव करने में असफल रहे, और जैकब वाडलेज्च से 85.86 मीटर पीछे रह गए, जिन्होंने ट्रॉफी घर ले ली।

इसके बाद, वह इस महीने के अंत में हांगझू में शुरू होने वाले एशियाई खेल 2023 में अपने खिताब का बचाव करेंगे।

नवीनतम समाचार

अगस्त 2023 में, ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने दूसरे प्रयास में 88.17 मीटर थ्रो के साथ विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रचा, जो उनका सर्वश्रेष्ठ था और उन्हें शीर्ष पर बनाए रखा।

जर्मनी ने सर्बिया को हराकर पहली बार FIBA बास्केटबॉल विश्व कप जीता

जर्मनी ने मनीला में दो यूरोपीय पावरहाउस के मुकाबले में सर्बिया को 83-77 से हराकर अपना पहला FIBA बास्केटबॉल विश्व कप खिताब जीता।

टूर्नामेंट के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी डेनिस श्रोडर ने जर्मनी को गेम-सर्वोच्च 28 अंकों के साथ आगे बढ़ाया, जो उनके प्रति गेम 17.9 अंक के औसत से काफी ऊपर था, और उन्होंने दो रिबाउंड और दो सहायता जोड़ीं।

जर्मनी 2006 में स्पेन के बाद अपने अंतिम पदार्पण में FIBA विश्व कप का ताज जीतने वाली पहली टीम बन गई।
पुरुष विश्व कप में जर्मनी का पिछला सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2002 में था, जब एमवीपी डर्क नोविट्ज़की ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ (FIBA) प्रतियोगिता में कांस्य पदक दिलाया था।
इससे पहले, कनाडा ने एक दिलचस्प, रिकॉर्ड-सेटिंग कांस्य-पदक खेल में शॉर्ट-हैंड संयुक्त राज्य अमेरिका को ओवरटाइम में 127-118 से हराकर अपना पहला विश्व कप पोडियम फिनिश हासिल किया।
FIBA बास्केटबॉल विश्व कप 2023 25 अगस्त से 10 सितंबर तक फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया में हुआ।

FIBA के बारे में:

इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन राष्ट्रीय संगठनों का एक संघ है जो दुनिया भर में बास्केटबॉल के खेल को नियंत्रित करता है।
राष्ट्रपति: हमाने नियांग
स्थापना: 18 जून 1932
मुख्यालय: मिज़, स्विट्ज़रलैंड

भारतीय निशानेबाज इलावेनिल वलारिवान ने ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता

भारतीय निशानेबाज इलावेनिल वलारिवन ने ब्राजील के रियो डी जनेरियो में ISSF विश्व कप 2023 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है।
ओलंपियन एलावेनिल वलारिवन ने फाइनल में 24 शॉट्स की अपनी श्रृंखला में 252.2 का स्कोर किया और फ्रांस की ओसिएने मुलर को मामूली अंतर से हराया।
कुल आठ निशानेबाजों ने फाइनल के लिए क्वालीफाई किया।
यह एलावेनिल वलारिवान का दूसरा व्यक्तिगत ISSF विश्व कप पदक था।
इससे पहले एलावेनिल वलारिवन क्वालिफिकेशन राउंड में 630.5 अंक के साथ 9वें स्थान पर रहीं।
रियो प्रतियोगिता 2023 का आखिरी राइफल और पिस्टल ISSF विश्व कप है।
ब्राजील के शहर में चल रहे कार्यक्रम के बाद 18 से 27 नवंबर तक दोहा, कतर में फाइनल होगा। भारत ने ISSF विश्व कप के लिए 16 सदस्यीय टीम भेजी है।

ISSF के बारे में:

स्थापित: 1907
मुख्यालय: म्यूनिख, जर्मनी
सदस्यता: 150 क्षेत्र
सचिव: विली ग्रिल (महासचिव)

भारत ने कोलंबो में श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर एशिया कप 2023 का खिताब जीता

क्रिकेट में, भारत ने कोलंबो में एशिया कप जीतने के लिए फाइनल में 10 विकेट से जीत दर्ज करके मेजबान श्रीलंका को ध्वस्त कर दिया।
बल्लेबाजी करने उतरी मेजबान टीम महज 15.2 ओवर में 50 रन के मामूली स्कोर पर ढेर हो गई।
भारत के मोहम्मद सिराज ने छह विकेट लेकर श्रीलंका को घुटनों पर ला दिया।
उनके बाद हार्दिक पंड्या ने तीन विकेट लिए, साथ ही एक विकेट जसप्रित बुमरा ने लिया।
जवाब में भारत ने 51 रन का लक्ष्य महज 6.1 ओवर में ही हासिल कर लिया
ईशान किशन 23 रन और शुबमन गिल 27 रन बनाकर नाबाद रहे।
मोहम्मद सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच और कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया।

ICC ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप के लिए आधिकारिक एंथम 'दिल जश्न बोले' जारी किया, जिसमें रणवीर सिंह और प्रभावशाली कलाकार शामिल हैं

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद अगले महीने की 5 तारीख से शुरू होने वाले पुरुष क्रिकेट विश्व कप के लिए आधिकारिक गान जारी किया।
एंथम का विषय दिल जश्न बोले है और इसमें बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह और अन्य लोकप्रिय सोशल मीडिया प्रभावशाली लोग शामिल हैं।
ICC ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया, एक्स, आधिकारिक गान अब प्लेटफॉर्म 2023 पर आ रहा है, वन डे एक्सप्रेस पर बोर्ड करें और अब तक के सबसे महान क्रिकेट जश्न में शामिल हों!
गान का संगीत प्रीतम द्वारा तैयार किया गया है, और गायक हैं - प्रीतम, नकाश अजीज, श्रीराम चंद्रा, अमित मिश्रा, जोनिता गांधी, अकासा और चरण।
वीडियो में दिखाया गया है कि रणवीर सिंह ट्रेन के डिब्बे में दिल जश्न जश्न बोले गाने पर डांस कर रहे हैं और फिर यात्री भी उनके साथ डांस करने लगते हैं।
ICC के महाप्रबंधक - विपणन और संचार, क्लेयर फर्लांग ने कहा, यह गान शानदार ढंग से भारत और प्रशंसकों के जुनून और ऊर्जा को दर्शाता है जो इस कार्यक्रम को इतना खास बना देगा।
12 साल बाद भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन हो रहा है। यह 10 शहरों में खेला जाएगा।
5 अक्टूबर को उद्घाटन मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत अपना पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई में खेलेगा।

भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने आईसीसी गेंदबाजों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है

भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ICC की ताजा गेंदबाज़ों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है।
एशिया कप फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ उनके नवीनतम मैच विजेता प्रदर्शन ने उन्हें शीर्ष पर पहुंचाने के लिए आठ स्थान की छलांग लगाई।
कुलदीप यादव एक अन्य भारतीय गेंदबाज हैं जिन्होंने शीर्ष दस में जगह बनाई है।
जसप्रित बुमरा लंबे चोट के बाद वापसी करने वाले 2 स्थान ऊपर चढ़कर 27वें स्थान पर पहुंच गए हैं।
हार्दिक पंड्या आठ पायदान ऊपर 50वें स्थान पर पहुंच गये
बल्लेबाजों में सलामी बल्लेबाज शुबमन गिल ने पाकिस्तान के बाबर आजम के बाद अपना दूसरा स्थान बरकरार रखा है।
रोहित शर्मा ने भी अपना 10वां स्थान बरकरार रखा है जबकि स्टार बल्लेबाज विराट कोहली एक पायदान ऊपर आठवें स्थान पर पहुंच गए हैं।

हरमनप्रीत, लवलीना एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक होंगी

भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान और टोक्यो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता उद्घाटन समारोह में दल का नेतृत्व करेंगे।
पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन 19वें एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी।
यह पहली बार है कि ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों की तर्ज पर लैंगिक समानता के लिए एशियाई खेलों में दो ध्वजवाहक होंगे।
हांग्जो पहुंचने वाली टीमों में मुक्केबाजी, हॉकी और टेबल टेनिस सबसे महत्वपूर्ण खेल हैं, इसलिए हमने हॉकी और मुक्केबाजी से सर्वश्रेष्ठ को चुना।
जकार्ता और पालेमबांग में 2018 एशियाई खेलों में, उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व नीरज चोपड़ा ने किया था।
तब से एक ओलंपिक और विश्व चैंपियन, भाला इक्का एक स्वचालित पसंद रहा होगा, लेकिन वह खेल शुरू होने के एक सप्ताह बाद ही आता है।
एथलेटिक्स 29 सितंबर से ही शुरू हो रहा है

BCCI ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सीज़न 2023-26 के लिए SBI लाइफ को आधिकारिक भागीदार घोषित किया

SBI लाइफ ने BCCI घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सत्र 2023-2026 के लिए आधिकारिक भागीदारों में से एक के रूप में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के साथ हाथ मिलाया है।
SBI लाइफ ने BCCI के साथ 3 साल का करार किया है और उनकी साझेदारी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 22 सितंबर, 2023 से शुरू होने वाली आगामी तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला से शुरू होगी।
इसमें BCCI और SBI लाइफ की अच्छी-खासी साझेदारी है।
SBI लाइफ भारत में एक शीर्ष स्तरीय जीवन बीमा प्रदाता है, और BCCI दुनिया के सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण खेल संगठनों में से एक है।
यह गठबंधन भारत में हर स्तर पर क्रिकेट को समर्थन और बढ़ावा देगा।
क्रिकेट के लिए BCCI का दृष्टिकोण और उत्कृष्टता के लिए SBI लाइफ की प्रतिबद्धता आदर्श रूप से संगत है।
यह साझेदारी सभी स्तरों पर क्रिकेट को आगे बढ़ाने और सहायता करने के प्रति हमारे समर्पण को दर्शाती है।
BCCI के आधिकारिक भागीदार के रूप में SBI लाइफ की संबद्धता, इसकी निर्विवाद पहुंच और पूर्ण विश्वसनीयता के साथ, उपभोक्ता के साथ वास्तविक संबंध बनाने के लिए प्रतिबद्ध एक ब्रांड के रूप में एक विपणक का सपना है।

SBI लाइफ के बारे में:

भारत में शीर्ष जीवन बीमा प्रदाताओं में से एक SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, जिसे SBI लाइफ के नाम से भी जाना जाता है।
यह फ्रांस स्थित BNP पारिबा कार्डिफ़ और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के बीच एक संयुक्त उद्यम है, जो भारत के सबसे बड़े और सबसे प्रतिष्ठित बैंकों में से एक है।
इस साझेदारी में मुख्य स्वामित्व SBI के पास है।

कुश्ती में, भारत के अंतिम पंघाल ने सर्बिया में विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता

युवा भारतीय पहलवान अंतिम पंघाल ने सर्बिया के बेलग्रेड में चल रही विश्व चैंपियनशिप में महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया।
उन्होंने भारत के लिए पेरिस ओलंपिक 2024 का कोटा भी हासिल किया।
19 वर्षीय अंतिम ने कांस्य पदक के मुकाबले में दो बार की यूरोपीय चैंपियन एम्मा जोना डेनिस माल्मग्रेन को 16-6 से हराया।
टूर्नामेंट के मौजूदा संस्करण में यह भारत का पहला पदक है।
अंतिम ने विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए अब तक का 23वां पदक हासिल किया है, जिसमें एक स्वर्ण, पांच रजत और 17 कांस्य पदक शामिल हैं।
इससे पहले, अंतिम पंघाल ने शुरुआती दौर में 2022 विश्व चैंपियन USA की डोमिनिक ओलिविया पैरिश को 3-2 से हराया था।
भारतीय पहलवान ने क्वार्टर फाइनल में रूस की नतालिया मालिशेवा के खिलाफ 9-6 से जीत हासिल करने से पहले राउंड 16 में पोलैंड की रोक्साना मार्टा ज़सीना पर जीत दर्ज की।
हालाँकि, विश्व चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं के 53 किग्रा फ्रीस्टाइल सेमीफाइनल में बेलारूस की वेनेसा कलादज़िंस्काया ने एंटीम को 5-4 के अंतर से हरा दिया।

ICC प्लेयर ऑफ द मंथ (अगस्त 2023): बाबर ने तीसरा सम्मान हासिल किया

पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने इस साल अपना तीसरा ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता क्योंकि उन्होंने अगस्त 2023 के महीने के लिए पुरस्कार जीता।
अनुभवी बल्लेबाज ने अपने असाधारण प्रदर्शन से प्रभावित करना जारी रखा और इसलिए, वह ICC वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर हैं।

उन्होंने शादाब खान और वेस्टइंडीज के दाशेर निकोलस पूरन को पछाड़ते हुए पुरस्कार जीता।

यह कहानी क्यों मायने रखती है?

प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसी विशेष महीने में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुरुष और महिला क्रिकेटरों को दिया जाता है।

दोनों श्रेणियों के लिए तीन नामांकन की घोषणा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद 2021 की शुरुआत से ही यह पुरस्कार वितरित कर रहा है।

वोटिंग पैनल में जाने-माने पत्रकार और पूर्व क्रिकेटर शामिल हैं।

मतदान में आम जनता की हिस्सेदारी 10% है।

सबसे तेज 19 वनडे शतक:

बाबर ने 2023 एशिया कप में नेपाल के खिलाफ 151 रनों की पारी खेलकर अपना 19वां वनडे शतक जड़कर इतिहास रच दिया।

वह सबसे तेज 19 वनडे शतक लगाने वाले क्रिकेटर बन गए।

बाबर ने 102 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की और दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज हाशिम अमला का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 104 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की थी।

बाबर सबसे तेज़ 18 वनडे शतक भी लगाने वाले खिलाड़ी थे

बाबर ने अपना 31वां अंतरराष्ट्रीय शतक लगाया

नेपाल के खिलाफ बाबर का 31वां अंतर्राष्ट्रीय शतक था और उन्होंने दिग्गजों जावेद मियांदाद और सईद अनवर की बराबरी कर ली।

पाकिस्तानी बल्लेबाजों में बाबर शतकों के मामले में सिर्फ यूनिस खान (41), मोहम्मद यूसुफ (39) और इंजमाम उल हक (35) से पीछे हैं।

कुल मिलाकर, बाबर ने 107 वनडे मैचों में 58.47 की शानदार औसत से 5,380 रन बनाए हैं।

उन्होंने 19 शतकों के अलावा 28 अर्धशतक लगाए हैं

ICC महिला प्लेयर ऑफ़ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता?

आयरलैंड की तेज गेंदबाज अर्लीन केली ने अगस्त के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता।

केली ने नीदरलैंड की आइरिस ज्विलिंग और मलेशिया की आइना हामिजा हाशिम से आगे बढ़कर यह पुरस्कार हासिल किया।

नीदरलैंड के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 विकेट झटके।

उनका 4.30 का औसत किसी द्विपक्षीय श्रृंखला में चौथा सर्वश्रेष्ठ है, जहां किसी गेंदबाज ने महिला टी20ई में 10 से अधिक विकेट लिए हैं।

हांग्जो में एशियाई खेलों में भारत की कुल पदक संख्या 11 है

चीन के हांगझू में एशियाई खेलों में अब तक भारत की कुल पदक संख्या ग्यारह हो गई है - दो स्वर्ण, तीन रजत और छह कांस्य।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल मैच में श्रीलंका को 19 रन से हराकर देश के लिए दूसरा स्वर्ण पदक जीता।

स्मृति मंधाना ने 46 रन बनाकर अपना दमखम दिखाया और भारत के स्कोर को 116 रन तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया।

इसके बाद पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भारतीय तिकड़ी रुद्राक्ष पाटिल, दिव्यांग पंवार और ऐश्वर्या तोमर की स्वर्ण पदक जीत भी हुई।

भारतीय पुरुष क्वाड्रपल स्कल टीम और रोइंग में पुरुषों की चार टीम ने कांस्य पदक जीता, जबकि ऐश्वर्या तोमर ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल-व्यक्तिगत- स्पर्धा में कांस्य पदक जीता।

25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल टीम पुरुष स्पर्धा में अनीश भानवाला, विजयवीर सिद्धू और आदर्श सिंह की भारतीय टीम ने भी कांस्य पदक हासिल किया है।
इससे पहले, भारत ने निशानेबाजी में अपना पहला पदक जीता था जब रमिता जिंदल, मेहुली घोष और आशी चौकसे की तिकड़ी ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में रजत पदक जीता था।
पहले पदक के तुरंत बाद, भारतीय जोड़ी अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह ने रोइंग अनुशासन में पुरुषों की लाइटवेट डबल स्कल्स में रजत पदक जीता।
रोइंग ने भारत को और पदक दिलाए, पुरुषों की आठ टीम ने एक और रजत पदक जीता, जबकि बाबू लाल यादव और लेख राम ने पुरुषों की जोड़ी में कांस्य पदक हासिल किया।
महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल फाइनल में, भारत की रमिता ने कांस्य पदक जीता, जिससे कुल पदक 11 हो गए।

फॉर्मूला वन: मैक्स वेरस्टैपेन ने जापानी ग्रां प्री जीता

रेड बुल के मैक्स वेरस्टैपेन ने जापानी ग्रां प्री में आसान जीत हासिल की और अपनी लगातार तीसरी फॉर्मूला वन चैंपियनशिप अर्जित करने के करीब एक कदम आगे बढ़ गए।
सुज़ुका सर्किट में जीत ने वेरस्टैपेन को इस सीज़न में अब तक 16 रेसों में अपनी 13वीं जीत हासिल करने में मदद की।
हालाँकि, जापानी ग्रां प्री वेरस्टैपेन के रेड बुल टीम के साथी सर्जियो पेरेज़ के लिए बहुत यादगार नहीं रही, जिन्हें लुईस हैमिल्टन के साथ टक्कर का सामना करना पड़ा और उन्हें पांच-सेकंड बार पेनल्टी खानी पड़ी।
मैक्स एमिलियन वर्स्टापेन (जन्म 30 सितंबर 1997), एक बेल्जियम-डच रेसिंग ड्राइवर और 2021 और 2022 फॉर्मूला वन विश्व चैंपियन हैं।
वह रेड बुल रेसिंग के साथ फॉर्मूला वन में डच ध्वज के तहत प्रतिस्पर्धा करता है।
जापानी ग्रां प्री में वेरस्टैपेन के शानदार प्रदर्शन ने रेड बुल को लगातार दूसरे वर्ष कंस्ट्रक्टर्स का खिताब दिलाया।
2005 में खेल में प्रवेश करने के बाद से यह रेड बुल का छठा खिताब था।
उन्होंने छह ग्रां प्री और तीन स्प्रिंट स्पर्धाओं के अभी बाकी होने पर भी खिताब का दावा किया।
कुल मिलाकर, यह रेड बुल का छठा खिताब था। इसके अलावा, रेड बुल ने 2023 में 16 रेसों में से अपनी 15वीं जीत दर्ज की।

हांग्जो एशियाई खेल: भारत की नेहा ठाकुर ने रजत पदक जीता

भारतीय नाविक नेहा ठाकुर ने लड़कियों की डोंगी ILCA-4 स्पर्धा में रजत पदक जीतकर हांग्जो में एशियाई खेलों 2023 के खेल में देश के लिए पदकों की गिनती शुरू की।
नेशनल सेलिंग स्कूल भोपाल की एक उभरती हुई नाविक, नेहा कुल 32 अंकों के साथ समाप्त हुई, लेकिन उसके 27 के नेट स्कोर ने उसे थाईलैंड की स्वर्ण पदक विजेता नोपासोर्न खुनबूनजान के बाद दूसरा स्थान हासिल करने में मदद की।
सिंगापुर की कीरा मैरी कार्लाइल को 28 के नेट स्कोर के साथ कांस्य पदक मिला।
नौकायन में, नेट स्कोर निर्धारित करने के लिए सभी दौड़ों में से प्रतिस्पर्धी के सबसे खराब स्कोर को कुल अंकों से घटा दिया जाता है। सबसे कम नेट स्कोर वाले को विजेता माना जाता है।

कौन हैं नेहा ठाकुर?

मध्य प्रदेश के देवास जिले के अमलताज गांव में जन्मी नेहा एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती हैं। उनके पिता मुकेश कुमार ठाकुर एक किसान हैं जबकि उनकी मां रीना ठाकुर एक गृहिणी हैं।
पिछले साल, नेहा ने अबू धाबी में एशियाई सेलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता और एशियाई खेलों के लिए क्वालीफाई किया।
नेहा ने बहुत कम उम्र में नौकायन करना शुरू कर दिया था और उन्हें नेशनल सेलिंग स्कूल भोपाल द्वारा पहचाना और तैयार किया गया था।

SAFF अंडर-19: सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला मेजबान नेपाल से होगा

काठमांडू में SAFF अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला मेजबान नेपाल से होगा।
भारत लगातार दो जीत के साथ ग्रुप बी विजेता के रूप में सेमीफाइनल में पहुंचा।
दूसरी ओर, नेपाल ने ग्रुप ए में पाकिस्तान के बाद दूसरा स्थान हासिल किया।
इससे पहले पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला भूटान से होगा
पहले मैच में बांग्लादेश को 3-0 से हराने के बाद, भारत को भूटान के खिलाफ थोड़ा संघर्ष करना पड़ा और 2-1 से जीत हासिल की।

2023 SAFF U-19 के बारे में:

2023 सैफ अंडर -19 चैम्पियनशिप सैफ अंडर -19 चैम्पियनशिप का 5 वां संस्करण है, जो दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ (SAFF) द्वारा आयोजित पुरुषों की अंडर -19 राष्ट्रीय टीमों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है।
यह 21-30 सितंबर 2023 से काठमांडू, नेपाल में हो रहा है।
भारत गत चैंपियन है, जिसने 2022 में फाइनल में बांग्लादेश को हराकर अपना दूसरा खिताब जीता था।

एशियाई खेल 2023 में महिलाओं की 50 मीटर राइफल स्पर्धा में भारत की सिफ्त कौर समरा ने स्वर्ण पदक जीता

भारत की सिफ्त कौर समरा ने एशियाई खेल 2023 में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3-पी व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर भारत को हांगझू में पांचवां स्वर्ण दिलाया।
महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल शूटिंग स्पर्धा में मनु भाकर, रिदम सांगवान और ईशा सिंह की भारतीय टीम ने भी स्वर्ण पदक जीता।
इस जीत के साथ भारत के कुल पदकों की संख्या 21 हो गई है जिसमें पांच स्वर्ण, छह रजत और 10 कांस्य पदक शामिल हैं।
इस बीच, ईशा सिंह ने महिलाओं की व्यक्तिगत 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में चीन की रुई लियू को पीछे छोड़ते हुए रजत पदक जीता।
विष्णु सरवनन ने एशियन गेम्स 2023 में ILCA- 7 इवेंट में कांस्य हासिल कर एक और पदक अपने नाम कर लिया है।
50 मीटर राइफल टीम स्पर्धा में सिफ्ट समरा कौर, आशी चौकसे और मानिनी कौशिक की भारतीय तिकड़ी ने रजत पदक जीता, जबकि 50 मीटर राइफल की व्यक्तिगत स्पर्धा में आशी चौकसे ने कांस्य पदक जीता।

एशियाई खेल 2023 के बारे में:

हांग्जो को आधिकारिक तौर पर 16 सितंबर, 2015 को मेजबान शहर के रूप में सम्मानित किया गया था।
खेलों का प्रतीक, हांग्जो में एक समारोह के दौरान 'सर्जिंग टाइड्स' की घोषणा की गई थी, और इसे एक हाथ के पंखे, एक रनिंग ट्रैक और कियानतांग नदी और रेडियो तरंगों (वायरलेस कनेक्टिविटी का प्रतीक) जैसा डिज़ाइन किया गया है।

हांग्जो में एशियाई खेलों में भारत की रोशिबिना देवी नाओरेम ने रजत पदक जीता

अत्यधिक प्रतिभाशाली रोशिबिना देवी ने चल रहे एशियाई खेलों 2023 में वुशु प्रतियोगिता के 60 किलोग्राम में रजत पदक जीता।
फाइनल में अपने चीनी प्रतिद्वंद्वी शियाओवेई वू से 2-0 से हारने के बाद वह स्वर्ण जीतने का मौका चूक गईं।
मौजूदा एशियाई खेलों में रोशिबिना के प्रदर्शन में समग्र सुधार देखा गया।
उन्होंने अपने पदक का रंग कांस्य से उन्नत किया, जो उन्होंने 2018 जकार्ता एशियाई खेलों में जीता था।
उन्होंने वियतनाम की थी थू न्गुयेन के खिलाफ दमदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया
उन्होंने क्वार्टरफाइनल में भी शानदार प्रदर्शन किया और कजाकिस्तान की ऐमान करश्यागा को पीछे छोड़ दिया।
एशियाई खेलों के पिछले संस्करण में, भारत का 13 सदस्यीय वुशु दल चार कांस्य पदक लेकर लौटा था।
इस जीत के साथ, भारत ने एशियाई खेलों 2010 में वांगखेम संध्यारानी देवी की रजत जीत के बाद से एशियाई खेलों में वुशु में अपना सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्रदर्शित किया है।

स्वप्निल-ऐश्वर्य-अखिल की तिकड़ी ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता, पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3पी टीम में विश्व रिकॉर्ड तोड़ा

हांग्जो में चल रहे एशियाई खेलों में भारतीय निशानेबाजी दल का दबदबा कायम है, स्वप्निल कुसल, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर और अखिल श्योराण की पुरुष तिकड़ी ने 50 मीटर राइफल पुरुष 3पी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता।
1769 अंकों के साथ टीम इंडिया ने गोल्ड पर कब्ज़ा जमाया
रजत पदक चीन ने 1763 अंकों के साथ जीता और कांस्य पदक दक्षिण कोरिया ने 1748 अंकों के साथ जीता।
अपने स्कोर के साथ, भारत ने पिछले वर्ष से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा बनाए गए 1761 अंकों के विश्व रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया।

एशियाई खेल: नेपाल ने तोड़ा टी-20 रिकॉर्ड; युवी का सबसे तेज 50 रन का रिकॉर्ड टूटा

नेपाल के कुशल मल्ला ने 27 सितंबर को मंगोलिया के खिलाफ चल रहे एशियाई खेलों के पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता में ग्रुप A के पहले मैच में सनसनीखेज शतक बनाकर टी20ई में बल्लेबाजी के कई सर्वकालिक रिकॉर्ड तोड़ दिए।
मल्ला के शतक ने उन्हें रोहित शर्मा के लंबे समय से चले आ रहे रिकॉर्ड को तोड़ दिया।
मल्ला ने मंगोलिया के खिलाफ तीन अंकों तक पहुंचने के लिए केवल 34 गेंदों का समय लिया और टी 20 आई प्रारूप में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए और रोहित शर्मा के टी 20 आई में 35 गेंदों में 100 रन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया।
इस बीच, उनके साथी दीपेंद्र सिंह ऐरी ने सिर्फ नौ गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और युवराज सिंह के 12 गेंदों में 50 रन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया।
नेपाल ने मंगोलिया के खिलाफ मैच में कई रिकॉर्ड तोड़ दिए क्योंकि उन्होंने 273 रन की जीत हासिल की।
टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इससे पहले किसी भी टीम ने 300 का स्कोर नहीं बनाया था और नेपाल का 314 का स्कोर टी20 में सबसे अधिक है।
पिछला सर्वोच्च टीम स्कोर अफगानिस्तान द्वारा बनाया गया था जब उन्होंने देहरादून (2019) में आयरलैंड के खिलाफ 278 रन बनाए थे।
मल्ला अब T20I प्रारूप में सबसे तेज़ शतकवीर हैं।
उन्होंने चेक गणराज्य के सुदेश विक्रमसेकरा, दक्षिण अफ्रीका के डेविड मिलर और भारत के रोहित शर्मा के संयुक्त रिकॉर्ड को तोड़ दिया।
सुदेश, मिलर और रोहित क्रमशः 35 गेंदों में मील के पत्थर तक पहुंच गए थे।
नेपाल की मंगोलिया पर 273 रनों से जीत T20I क्रिकेट में जीत का सबसे बड़ा अंतर है।
पिछली सर्वोच्च जीत 2021 में पनामा पर चेक गणराज्य की चौंका देने वाली जीत थी।

एशियाई खेल 2023 भारत की पदक तालिका: सभी खेलों में भारत द्वारा जीते गए पदकों की पूरी सूची

भारतीय दल एक बार फिर इस आयोजन के 19वें संस्करण में शानदार प्रदर्शन करने के लिए उत्साहित है, जो वर्तमान में चीन के हांगझू में चल रहा है।
इस तरह के आश्चर्यजनक प्रदर्शन से प्रेरणा लेते हुए, भारतीय एथलीट फिर से अधिक से अधिक पदक जीतने और इंडोनेशिया में स्थापित रिकॉर्ड को पार करने का प्रयास करेंगे।
हालाँकि यह एक कठिन काम होगा, लेकिन यह निश्चित रूप से संभव है क्योंकि हांग्जो में भारतीय दल में कुछ प्रतिष्ठित और आशाजनक नाम हैं।
हांग्जो एशियाई खेलों में भारत के लिए पदक और पदक विजेताओं की पूरी सूची यहां दी गई है:

क्र.सं	पदक	खेल/अनुशासन

1.	चाँदी	महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम (शूटिंग)
2.	चाँदी	पुरुषों की लाइटवेट डबल स्कल्स (रोइंग)
3.	पीतल	पुरुषों की जोड़ी (रोइंग)
4.	चाँदी	पुरुषों की आठ (रोइंग)
5.	पीतल	महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल (शूटिंग)
6.	सोना	पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम (शूटिंग)
7.	पीतल	पुरुष चार (रोइंग)
8.	पीतल	पुरुषों की चतुर्भुज (रोइंग)
9.	पीतल	पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल (शूटिंग)
10.	पीतल	पुरुषों की 25 मीटर रैपिड पिस्टल टीम (शूटिंग)
11।	सोना	महिला क्रिकेट
12.	चाँदी	लड़कियों की डोंगी (ILCA4) (नौकायन)
13.	पीतल	पुरुष विंडसर्फर आरएस:एक्स (सेलिंग)
14.	सोना	ड्रेसेज टीम (घुड़सवारी)
15.	चाँदी	महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम (शूटिंग)
16.	सोना	महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम (शूटिंग)
17.	सोना	महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन (शूटिंग)
18.	पीतल	महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन (शूटिंग)
19.	पीतल	पुरुषों की स्कीट टीम (शूटिंग)
20.	पीतल	पुरुषों की डोंगी ICLA7 (नौकायन)
21.	चाँदी	महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल (शूटिंग)
22.	चाँदी	पुरुषों की स्कीट (शूटिंग)
23.	चाँदी	महिला 60 किग्रा (वुशु)
24.	सोना	पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम (शूटिंग)
25.	पीतल	घुड़सवारी व्यक्तिगत ड्रेसेज घटना
26.	चाँदी	महिलाओं की 10 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा
27.	सोना	पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3पी टीम स्पर्धा
28.	चाँदी	पुरुष टेनिस युगल
29.	चाँदी	महिलाओं की 10 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा

30.	सोना	महिलाओं की 10 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा
31.	पीतल	महिला स्कैश टीम
32.	चाँदी	पुरुषों की 50 मीटर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

चंद्रयान-3 के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर, ऑक्सीजन, आयरन और टाइटेनियम की मौजूदगी की पुष्टि की

चंद्रयान-3 के 'प्रज्ञान' रोवर पर लगे लेजर-प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी (LIBS) उपकरण ने पहली बार इन-सीटू माप के माध्यम से, दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्र सतह पर सल्फर की उपस्थिति की "स्पष्ट रूप से पुष्टि" की है।
सल्फर के अलावा, LIBS उपकरण ने प्रत्याशित रूप से विभिन्न अन्य तत्वों का भी पता लगाया है, जिनमें चंद्रमा पर एल्यूमीनियम (अल), सल्फर (एस), कैल्शियम (सीए), आयरन (Fe), क्रोमियम (Cr), और टाइटेनियम (Ti) शामिल हैं।
आगे के मापों से मैंगनीज (एमएन), सिलिकॉन (सी), और ऑक्सीजन (ओ) की उपस्थिति का पता चला है।

LIBS के बारे में:

LIBS उपकरण पीन्या में इलेक्ट्रो-ऑप्टिक्स सिस्टम प्रयोगशाला में विकसित किया गया हैइंडस्ट्रियल एस्टेट, बेंगलुरु जहां 1975 में पहला भारतीय उपग्रह बनाया गया था।
इसने चंद्रमा की सतह पर, विशेष रूप से दक्षिणी ध्रुव के पास, मौलिक संरचना के उद्घाटन-इन-सीटू माप को सक्षम किया है।

चंद्रयान-3 की चंद्र लैंडिंग उपलब्धि:

23 अगस्त 2023 को भारत ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की जब चंद्रयान-3 का लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा।
इस उपलब्धि ने भारत को अमेरिका, चीन और रूस के बाद इतिहास में चौथे राष्ट्र के रूप में स्थापित किया, जिसने एक नरम चंद्र लैंडिंग हासिल की और विशेष रूप से, पृथ्वी के चंद्रमा के अज्ञात दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया।

लैंडिंग स्थलों का नामकरण और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस:

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उस स्थान का नाम 'शिव शक्ति बिंदु' रखने के निर्णय की घोषणा की जहां चंद्रयान -3 विक्रम लैंडर ने सॉफ्ट लैंडिंग की थी और जिस स्थान पर चंद्रयान -2 लैंडर 2019 में चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, उसे 'तिरंगा पॉइंट' के नाम से जाना जाएगा।
अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए, 23 अगस्त, चंद्रयान -3 की चंद्र लैंडिंग की तारीख, को 'राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस' के रूप में घोषित किया गया था।

इसरो ने चंद्रयान-3 के पेलोड द्वारा मापी गई चंद्र सतह पर तापमान भिन्नता का एक ग्राफ जारी किया

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने चंद्रमा की सतह और लगभग 8 सेमी नीचे एक बिंदु के बीच तापमान भिन्नता का एक ग्राफ जारी किया, जिसे ChaSTE जांच नामक उपकरण द्वारा मापा गया था।
यह महत्वपूर्ण डेटा उस स्थान पर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के उतरने के ठीक 4 दिन बाद जारी किया गया है, जिसे 'शिव शक्ति' बिंदु कहा जाता है, यह नाम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया है।

ChaSTE जांच के बारे में:

चंद्रा का सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट (ChaSTE) एक तापमान जांच के रूप में खड़ा है।
यह 10 सेंसरों से सुसज्जित है और इसे मोटर का उपयोग करके चंद्रमा की सतह पर यंत्रवत् चलाया जा सकता है, जो 10 सेमी गहराई तक पहुंच सकता है।

उद्देश्य:

ChaSTE का प्राथमिक कार्य इसके थर्मल व्यवहार को समझने के लिए दक्षिणी ध्रुव के आसपास चंद्र ऊपरी मिट्टी के तापमान प्रोफ़ाइल को मापना है।

डेवलपर्स:

विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (VSSC) में इसरो की अंतरिक्ष भौतिकी प्रयोगशाला द्वारा विकसित, ChaSTE जांच अहमदाबाद, गुजरात में स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (PRL) के सहयोग से बनाई गई थी।

मुख्य विचार:

ChaSTE का एकत्रित डेटा चंद्रमा की सतह और उसके लगभग 10 सेमी नीचे एक बिंदु के बीच एक उल्लेखनीय भिन्नता दर्शाता है।

चंद्रमा की दृश्य सतह पर (वह क्षेत्र जहां लैंडर स्थित है, मैन्ज़िनस सी और सिम्पेलियस एन क्रेटर के बीच), तापमान 40-50 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जाता है।

हालाँकि, सतह से लगभग 80 मिमी की गहराई पर, तापमान में भारी गिरावट का अनुभव होता है, जो लगभग -10 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है।

इसरो के बारे में:

स्थापना: 15 अगस्त 1969
मुख्यालय: बैंगलोर, कर्नाटक
अध्यक्ष: श्रीधर सोमनाथ

जापान दोहरे उद्देश्य वाले अंतरिक्ष प्रक्षेपण की तैयारी कर रहा है: चंद्र लैंडर और एक्स-रे जांच की एक साथ तैनाती

जापान एक रॉकेट से दोहरे उद्देश्य वाले मिशन को लॉन्च करने की तैयारी है, जिसमें चंद्रमा की जांच के लिए SLIM या स्मार्ट लैंडर को तैनात किया जाएगा ताकि सटीक चंद्रमा लैंडिंग तकनीकों और उन्नत खगोलीय विश्लेषण के लिए XRISM का प्रदर्शन किया जा सके।

XRISM के बारे में:

एक्स-रे इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन (XRISM) जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (JAXA) और नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) का एक संयुक्त मिशन है, जिसमें यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी का योगदान भी शामिल है।

उद्देश्य:

गहरे अंतरिक्ष से आने वाली एक्स-रे का निरीक्षण करना और अभूतपूर्व सटीकता के साथ उनकी तरंग दैर्ध्य की पहचान करना।

यह विभिन्न तरंग दैर्ध्य पर आकाशीय पिंडों की चमक में परिवर्तन को मापने के लिए अत्याधुनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करेगा।

यह 400 से 12,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की ऊर्जा वाले एक्स-रे का पता लगाता है। (तुलना के लिए, दृश्य प्रकाश की ऊर्जा 2 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है।)

यह रेंज खगोल भौतिकीविदों को ब्रह्मांड के कुछ सबसे गर्म क्षेत्रों, सबसे बड़ी संरचनाओं और सबसे मजबूत गुरुत्वाकर्षण वाली वस्तुओं के बारे में नई जानकारी प्रदान करेगी।

स्लिम के बारे में:

SLIM एक कॉम्पैक्ट रोबोटिक मून लैंडर है जिसमें कोई अंतरिक्ष यात्री सवार नहीं है।

जापानी भाषा में 'मून स्निपर' कहा जाता है, इसमें उन्नत अवलोकन और संसाधन-दुर्लभ ग्रहों पर अनुकूलनीय लैंडिंग, अन्वेषण रणनीतियों को आगे बढ़ाने के लिए हल्के उपकरण हैं।

लैंडर का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य सटीक टचडाउन के साथ सटीक चंद्र लैंडिंग तकनीकों का प्रदर्शन करना है।

मिशन योजना में चंद्रमा के शिओली क्रेटर के अंदर एक लक्ष्य से 328 फीट (100 मीटर) से अधिक की दूरी पर उतरने का आह्वान किया गया है।

नवीनतम समाचार:

जापान की जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (JAXA) के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण में, एक्स-रे इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन (XRISM) अंतरिक्ष यान, चंद्रमा की जांच के लिए स्मार्ट लैंडर (SLIM) के साथ, 26 अगस्त, 2023 को लॉन्च के लिए निर्धारित है।

BHEL ने NOX उत्सर्जन को कम करने के लिए यदाद्री पावर स्टेशन के लिए पहला स्वदेशी SCR उत्प्रेरक बनाया

एक सरकारी इंजीनियरिंग फर्म, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) ने थर्मल पावर प्लांटों से नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) उत्सर्जन को सीमित करने के लिए चयनात्मक उत्प्रेरक रिएक्टरों (SCR) के लिए भारत के उत्प्रेरक के पहले सेट का निर्माण किया।

तेलंगाना में 5x800 मेगावाट यदाद्री थर्मल पावर स्टेशन के लिए स्वदेशी रूप से निर्मित SCR उत्प्रेरक के पहले सेट को बीएचईएल की निदेशक (औद्योगिक प्रणाली और उत्पाद) रेणुका गेरा ने बेंगलुरु, कर्नाटक में कंपनी के सोलर बिजनेस डिवीजन (SBD) इकाई से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

कोयला जलाने से इसकी नाइट्रोजन सामग्री नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) में परिवर्तित हो जाती है, जो एक प्रमुख वायु प्रदूषक है जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड (NO), नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO2), और नाइट्रस ऑक्साइड (N2O) जैसे पदार्थ शामिल हैं।

NOx कटौती की मान्यता प्राप्त आवश्यकता:

BHEL ने थर्मल पावर स्टेशनों में NOX कमी को पूरा करने के लिए अपनी SBD इकाई में एक अत्याधुनिक SCR उत्प्रेरक विनिर्माण सुविधा स्थापित की है।

NOx के दीर्घकालिक गंभीर प्रभावों को स्वीकार करते हुए और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना पर विचार करते हुए तेलंगाना राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (TSGENCO) ने 5x800 मेगावाट यादाद्री थर्मल पावर स्टेशन (TPS), महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी (महाजेनको) के लिए 1x660 मेगावाट भुसावल टीपीएस, पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम (WBPDCL) के लिए 1x660 मेगावाट सागरदिघी टीपीएस और नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी (नालको) के लिए 1x660 मेगावाट सागरदिघी टीपीएस के लिए एससीआर का ऑर्डर दिया था।

BHEL के बारे में:

स्थापना: 1956

मुख्यालय: नई दिल्ली, दिल्ली

BHEL एक भारतीय केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम और सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाली बिजली उत्पादन उपकरण निर्माता है।

यह भारत सरकार के स्वामित्व और भारी उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

भारत का पहला सौर मिशन, आदित्य एल1, सूर्य अध्ययन के लिए श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (SDSC) के दूसरे लॉन्च पैड (SLP) से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV-C 57) रॉकेट का उपयोग करके भारत के पहले सौर मिशन आदित्य-एल 1 (लैग्रेंज पॉइंट 1) ऑर्बिटर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया।

उद्देश्य:

सौर हवाओं का अध्ययन करना, जो पृथ्वी पर व्यवधान पैदा कर सकती हैं, जिसमें ऑरोरा जैसी घटनाएं भी शामिल हैं।

आदित्य-एल1 PSLV-XL कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग करने वाला 25वां मिशन है।

मिशन समयरेखा:

आदित्य एल-1 ने अंतरिक्ष में अपनी 125 दिन की यात्रा शुरू कर दी है।

आदित्य-एल1 के परियोजना निदेशक तमिलनाडु (टीएन) से निगार शाजी हैं।

मिशन बजट:

इसरो आदित्य एल 1 मिशन का बजट 400 करोड़ रुपये है और इसरो ने दिसंबर 2019 से आदित्य एल 1 पर काम करना शुरू कर दिया था।

आदित्य-एल1 के बारे में:

आदित्य-एल1, जिसका नाम सूर्य के लिए हिंदी शब्द पर रखा गया है, एक विशिष्ट सौर मिशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका लक्ष्य अंतरिक्ष में एक विशिष्ट स्थान तक पहुंचने के लिए 4 महीने की अवधि में लगभग 1.5 मिलियन किमी की यात्रा करना है जिसे लैग्रेंज प्वाइंट के रूप में जाना जाता है।

लैग्रेंज पॉइंट्स के बारे में:

लैग्रेंज पॉइंट अंतरिक्ष में स्थित वे स्थान हैं जहां दो खगोलीय पिंडों, इस मामले में, पृथ्वी और सूर्य, से गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित होते हैं।
लैग्रेंज पॉइंट, जिसका नाम इतालवी-फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफ-लुई लैग्रेंज के नाम पर रखा गया है।
लैग्रेंज बिंदु L1 पृथ्वी-सूर्य प्रणाली में 5 लैग्रेंज बिंदुओं में से एक है।
यह एक छोटी वस्तु द्वारा महसूस किए गए केन्द्रापसारक बल को संतुलित करता है और उन्हें एक स्थिर बल में "होवर" करने की अनुमति देता है।
लैग्रेंज बिंदु L1 अंतरिक्ष यान को बिना किसी ग्रहण या प्रच्छादन के सूर्य का निरंतर दृश्य प्राप्त करने का लाभ देगा।
4 अन्य बिंदु हैं- L2, L3, L4 और L5

मुख्य विचार:

आदित्य-एल1 पृथ्वी की कक्षाओं में 16 दिन बिताता है, जिसके दौरान यह अपनी लंबी यात्रा के लिए आवश्यक वेग प्राप्त करने के लिए पांच महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं से गुजरता है।
अपनी आरंभिक पृथ्वी-बद्ध कक्षाओं के बाद, आदित्य-एल1 एक ट्रांस-लैग्रेन्जियन1 सम्मिलन पैंतरेबाज़ी को क्रियान्वित करता है।
यह एल1 लैग्रेंज बिंदु पर निर्दिष्ट गंतव्य तक पहुंचने के लिए इसके 110-दिवसीय प्रक्षेप पथ की शुरुआत का प्रतीक है।
आदित्य एल 1 पेलोड के सूट से कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इजेक्शन, प्री-फ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियों की समस्याओं और उनकी विशेषताओं, अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता, कणों के प्रसार का अध्ययन और इंटरप्लेनेटरी माध्यम में क्षेत्रों आदि को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने की उम्मीद है।

पेलोड:

इसरो के अनुसार, आदित्य एल-1 मिशन के 7 पेलोड हैं जिन्हें 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है: रिमोट सेंसिंग पेलोड और इन-सीटू पेलोड।

रिमोट सेंसिंग पेलोड (4):

दृश्यमान उत्सर्जन रेखा कोरोनाग्राफ (VELC):
विकसित: भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, बैंगलोर
कार्य: दृश्यमान उत्सर्जन रेखाओं का उपयोग करके सूर्य की सबसे बाहरी परतों (कोरोना) का अवलोकन करता है।
सौर पराबैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप (SUIT):
विकसित: इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, पुणे, महाराष्ट्र
कार्य: पराबैंगनी स्पेक्ट्रम में सूर्य की छवियां कैप्चर करता है।
सौर निम्न ऊर्जा एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर (SoLEXS):
विकसित: भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद, गुजरात
कार्य: सूर्य से कम ऊर्जा वाले एक्स-रे को मापता है, सौर अध्ययन में सहायता करता है।
उच्च ऊर्जा L1 ऑर्बिटिंग एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर (HEL1OS):
विकसित: यूआर राव सैटेलाइट सेंटर, बैंगलोर, कर्नाटक
कार्य: सूर्य से उच्च-ऊर्जा एक्स-रे का विश्लेषण करता है, सौर अवलोकन में योगदान देता है।

इन-सीटू पेलोड (3):

आदित्य सौर पवन कण प्रयोग (ASPEX):
विकसित: अंतरिक्ष भौतिकी प्रयोगशाला (SPL), विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तिरुवनंतपुरम, केरल
कार्य: सूर्य से उत्पन्न होने वाले सौर पवन कणों का अध्ययन।
आदित्य (PAPA) के लिए प्लाज्मा विश्लेषक पैकेज:
विकसित: SPL, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तिरुवनंतपुरम, केरल
कार्य: अंतरिक्ष में प्लाज्मा का विश्लेषण करता है, अंतरिक्ष के मौसम को समझने में योगदान देता है।
उन्नत त्रि-अक्षीय उच्च-रिज़ॉल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर:
यहां विकसित: इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम प्रयोगशाला, बैंगलोर
कार्य: अंतरग्रहीय माध्यम में चुंबकीय क्षेत्र को मापता है।
ये पेलोड सूर्य की सबसे बाहरी परतों के अध्ययन से लेकर सौर पवन कणों और चुंबकीय क्षेत्रों का विश्लेषण करने तक, सौर अवलोकनों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करते हैं। इन्हें देश भर के विभिन्न इसरो केंद्रों के सहयोग से विकसित किया गया है, जो इसे एक व्यापक और स्वदेशी मिशन बनाता है।

नवीनतम समाचार:

अगस्त, 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के PSLV-C56 रॉकेट ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले लॉन्च-पैड (FLP) से सिंगापुर के DS-SAR उपग्रह और 6 सह-यात्री पेलोड को सफलतापूर्वक लॉन्च किया।

इसरो के बारे में:

स्थापना: 15 अगस्त 1969
मुख्यालय: बैंगलोर, कर्नाटक, भारत
अध्यक्ष: एस. सोमनाथ

इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV-C56 रॉकेट पर 7 सिंगापुरी उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के PSLV-C56 रॉकेट ने आंध्र प्रदेश (AP) के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले लॉन्च-पैड (FLP) से सिंगापुर के DS-SAR उपग्रह और 6 सह-यात्री पेलोड को सफलतापूर्वक लॉन्च किया।
यह मिशन, PSLV-C56 / DS-SAR, एसटी इंजीनियरिंग, सिंगापुर के लिए न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) द्वारा संचालित एक समर्पित वाणिज्यिक मिशन है।
यह PSLV की 58वीं और कोर अलोन कॉन्फ़िगरेशन में PSLV की 17वीं उड़ान है।

6 सह-यात्रियों की सूची:

VELOX-AM, एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन माइक्रोसैटेलाइट (23 किग्रा)
आर्केड एटमॉस्फेरिक कपलिंग एंड डायनेमिक्स एक्सप्लोरर (आर्केड), एक प्रायोगिक उपग्रह
SCOOB-II, एक 3U नैनो उपग्रह जो एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक पेलोड उड़ा रहा है
NuSpace द्वारा NuLIoN, एक उन्नत 3U नैनोसैटेलाइट जो शहरी और दूरस्थ दोनों स्थानों में निर्बाध IoT कनेक्टिविटी को सक्षम करता है।
गैलासिया-2, एक 3यू नैनो उपग्रह जो पृथ्वी की निचली कक्षा में परिक्रमा करेगा।
ORB-12 STRIDER, उपग्रह एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के तहत विकसित किया गया है
सभी उपग्रहों को 5-डिग्री कक्षीय झुकाव के साथ 535 किमी गोलाकार कक्षा में स्थापित किया गया।

DS-SAR के बारे में:

DS-SAR, एक रडार इमेजिंग पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, मिशन के लिए एक प्राथमिक उपग्रह है।
इसे रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी एजेंसी (सिंगापुर सरकार का प्रतिनिधित्व) और एसटी इंजीनियरिंग के बीच साझेदारी के तहत विकसित किया गया था।

DS- SAR एक सिंथेटिक एपर्चर रडार (SAR) पेलोड वहन करता है, जो लोद, इज़राइल में स्थित इज़राइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (IAI) द्वारा संचालित है।
SAR पेलोड DS-SAR को मौसम की स्थिति की परवाह किए बिना उच्च गुणवत्ता वाली इमेजरी प्रदान करने में सक्षम बनाता है, जो सभी मौसम में दिन और रात की कवरेज प्रदान करता है।

मुख्य विचार:

सह-यात्री पेलोड VELOX-AM एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग (AM) पेलोड के प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के लिए नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (NTU), सिंगापुर द्वारा विकसित एक माइक्रोसैटेलाइट है।
ARCADE एक 27यू माइक्रोसैटेलाइट है जिसे नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (NTU), सिंगापुर द्वारा इंस्पायर (इंटरनेशनल सैटेलाइट प्रोग्राम इन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी) कंसोर्टियम के सहयोग से डिजाइन और निर्मित किया गया है, आर्केड में आयोडीन आधारित ठोस प्रणोदक प्रणोदन मॉड्यूल है, जो कम ऊंचाई वाले मिशन के दौरान कक्षा के रखरखाव के लिए हॉल इफेक्ट थ्रस्टर पर आधारित है।

इसरो के बारे में:

स्थापना: 15 अगस्त 1969
मुख्यालय: बैंगलोर, कर्नाटक, भारत
अध्यक्ष: एस. सोमनाथ

हैदराबाद की कंपनी ग्रेन रोबोटिक्स ने भारत का पहला AI-संचालित एंटी-ड्रोन सिस्टम 'इंद्रजाल' पेश किया

हैदराबाद स्थित कंपनी ग्रेने रोबोटिक्स ने हैदराबाद में अपने हथियार मंच 'इंद्रजाल', दुनिया के एकमात्र स्वायत्त विस्तृत क्षेत्र एंटी-ड्रोन, काउंटर-मानवरहित विमान प्रणाली (C-UAS) का प्रदर्शन शुरू किया है।
इंद्रजाल का प्रदर्शन भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
यह एंटी-ड्रोन सिस्टम सूक्ष्म, मिनी, छोटे, बड़े और अतिरिक्त-बड़े ड्रोन सहित विभिन्न ड्रोन वर्गीकरणों से सुरक्षा करने में सक्षम है, जो भविष्य के लिए सुरक्षा उपायों को बढ़ाता है।

इंद्रजाल के बारे में:

इंद्रजाल का डिज़ाइन सिद्धांत दुनिया में पहली बार कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित प्रौद्योगिकी की 12 अद्वितीय परतों के लेगो ब्लॉक-जैसे संयोजन तंत्र का लाभ उठाता है।
यह डिज़ाइन सिस्टम को वास्तविक समय में ड्रोन खतरों का पता लगाने, पहचानने, वर्गीकृत करने, ट्रैक करने और तेजी से बेअसर करने में सक्षम बनाता है।
इंद्रजाल 360-डिग्री सुरक्षा प्रदान करता है और 4000 वर्ग किमी तक फैले विशाल क्षेत्र को कवर कर सकता है।
यह स्वायत्त ड्रोन के सभी वर्गीकरणों और स्तरों से बचाव के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है, जिसमें कम रडार क्रॉस सेक्शन (RCS) खतरों से लेकर मध्यम और उच्च ऊंचाई वाले लंबे समय तक चलने वाले (HALE) यूएवी, लोइटरिंग गोला-बारूद, स्मार्ट बम, रॉकेट शावर, नैनो और माइक्रो ड्रोन और झुंड ड्रोन शामिल हैं।

मछुआरों की सुरक्षा के लिए इसरो द्वारा विकसित उपकरण का नींदकारा में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया

'नभमित्र' मछुआरों की सुरक्षा के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो)-अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (अहमदाबाद, गुजरात) द्वारा विकसित एक उपकरण का केरल के कोल्लम शहर के तटीय क्षेत्र नींदकारा में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया।

नभमित्र डिवाइस की मुख्य विशेषताएं:

यह मछुआरों की सुरक्षा के लिए समुद्र से और समुद्र तक दो-तरफ़ा संदेश सेवाएँ सक्षम बनाता है।
यह उपकरण मछुआरों को उनकी स्थानीय भाषा में मौसम और चक्रवात की चेतावनियाँ बताने, उनकी समझ और सुरक्षा बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
मछुआरे नाव पलटने या आग लगने जैसी आपातकालीन स्थिति में अधिकारियों को संकट संदेश भेजने के लिए इस उपकरण का उपयोग कर सकते हैं।

यह उपकरण एक आपातकालीन बटन से सुसज्जित है जिसे गंभीर परिस्थितियों में मछुआरों द्वारा दबाया जा सकता है।
जब आपातकालीन बटन दबाया जाता है, तो उपकरण मछुआरों को निर्दिष्ट नियंत्रण केंद्र के साथ संचार स्थापित करने की अनुमति देता है।
नियंत्रण केंद्र को डिवाइस से अलर्ट प्राप्त होता है, जिसमें संकटग्रस्त नाव का सटीक स्थान, त्वरित बचाव कार्यों में सहायता शामिल है।
'नाभमित्र' मछुआरों की मदद भी करता हैवे उपयुक्त मछली पकड़ने के क्षेत्रों की पहचान करते हैं, जिससे उनकी पकड़ने की दक्षता में सुधार होता है।
इसके अतिरिक्त, यह उपकरण शिपिंग चैनलों और समुद्री सीमाओं के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है, जो सुरक्षित नेविगेशन में योगदान देता है।

जापान ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति की जांच के लिए रॉकेट ले जाने वाले चंद्र लैंडर और एक्स-रे टेलीस्कोप को सफलतापूर्वक लॉन्च किया

जापान "मून स्नाइपर" नामक मिशन के हिस्से के रूप में एक चंद्र लैंडर और एक एक्स-रे टेलीस्कोप ले जाने वाला एक रॉकेट लॉन्च किया गया।
मून स्नाइपर मिशन जापान का तीसरा मून मिशन है और पूरे मिशन का बजट 100 मिलियन डॉलर है।
HII-A नाम के इस रॉकेट को जापान के तनेगाशिमा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था।
प्रक्षेपण का जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (JAXA) द्वारा सीधा प्रसारण किया गया।

पेलोड:

रॉकेट ने एक्स-रे इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन (XRISM) को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया।
XRISM अंतरिक्ष पदार्थ की संरचना और गति को मापेगा।
इसके अतिरिक्त, जहाज पर एक चंद्र लैंडर भी है जिसे स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून (SLIM) कहा जाता है।
फरवरी 2024 तक XRISM और SLIM के चंद्रमा पर पहुंचने की उम्मीद है।
JAXA भविष्य में चंद्र जांच और अन्य ग्रहों पर लैंडिंग की तैयारी के लिए "पिनपॉइंट लैंडिंग तकनीक" विकसित कर रहा है।
जापान का पहला चंद्र अन्वेषण मिशन, हितेन, 24 जनवरी 1990 को अंतरिक्ष और अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया था।
जापान का दूसरा चंद्र अन्वेषण कागुया (सेलीन) था, जिसे 14 सितंबर, 2007 को तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था।
चंद्रमा की जांच के लिए स्मार्ट लैंडर या SLIM, चंद्रमा पर नरम लैंडिंग का प्रयास करेगा।
यदि SLIM चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल हो जाता है, तो जापान चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश बन जाएगा, भारत, जो चंद्रयान-3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के साथ चंद्रमा पर किसी अंतरिक्ष यान की सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बन गया है।

स्लिम के बारे में:

SLIM एक छोटे पैमाने का अन्वेषण लैंडर है जिसे न केवल चंद्र सतह पर पिनपॉइंट लैंडिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है, बल्कि चंद्रमा लैंडिंग में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के आकार और वजन में कमी को प्रदर्शित करने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है।
SLIM का उद्देश्य एक छोटे खोजकर्ता द्वारा सटीक लैंडिंग तकनीकों का प्रदर्शन, चंद्रमा की उत्पत्ति की जांच, चंद्रमा के अध्ययन में तेजी लाना है।

मुख्य विचार:

JAXA ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) और NASA के सहयोग से XRISM विकसित किया।
चूंकि ESA ने XRISM के लिए हार्डवेयर उपलब्ध कराया है और JAXA को वैज्ञानिक सलाह भी देगा, इसलिए अंतरिक्ष एजेंसी को दूरबीन के उपलब्ध अवलोकन समय का 8% आवंटित किया जाएगा।

ब्रह्मांड के विकास और अंतरिक्ष-समय की संरचना जैसे रहस्यों को जानने के लिए XRISM ब्रह्मांड में सबसे ऊर्जावान घटनाओं और वस्तुओं का निरीक्षण करेगा।
यह कदम ऐसे समय में आया है जब दुनिया फिर से चंद्रमा पर जाने की चुनौती की ओर बढ़ रही है।
केवल 4 राष्ट्र अमेरिका, रूस, चीन और भारत चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतर चुके हैं।
अगस्त 2023 में, भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास एक अंतरिक्ष यान उतारा।
ऐसा कुछ ही दिनों बाद हुआ जब रूस लगभग आधी सदी में पहली बार चंद्रमा पर लौटने के अपने प्रयास में विफल रहा।
जापान की एक निजी कंपनी, जिसे आईस्पेस कहा जाता है, ने अप्रैल, 2023 में चंद्रमा पर उतरने की कोशिश करते समय एक लैंडर को दुर्घटनाग्रस्त कर दिया।
चंद्रमा पर नासा का आखिरी मानव मिशन 1972 में था, और चंद्रमा पर मनुष्यों को भेजने पर ध्यान कम होता दिखाई दिया, मिशन रोबोटों पर सिमट गए।

जापान के बारे में:

प्रधान मंत्री: फुमियो किशिदा
राजधानी: टोक्यो
मुद्रा: जापानी येन

चीन हल्के अंतरिक्ष संकेतों का पता लगाने के लिए वाइड फील्ड सर्वे टेलीस्कोप लॉन्च करेगा

चीन सितंबर, 2023 में उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी टाइम-डोमेन सर्वेक्षण सुविधा, वाइड फील्ड सर्वे टेलीस्कोप (WFST) लॉन्च करने के लिए तैयार है।

WFST के बारे में:

WFST, जिसमें 2.5 मीटर का प्राथमिक दर्पण और बड़े दृश्य क्षेत्र वाला प्राइम-फोकस कैमरा है, वर्तमान में इंजीनियरिंग डिबगिंग और पायलट अवलोकन प्रक्रियाओं से गुजर रहा है।

उद्देश्य:

टाइम-डोमेन अवलोकन अनुसंधान के माध्यम से गतिशील खगोलीय घटनाओं का पता लगाना और उनकी निगरानी करना।
इसमें धुंधले और दूर के आकाशीय संकेतों का पता लगाना शामिल है, जैसे कि आकाशगंगा से परे आकाशगंगाओं और आकाशगंगा समूहों से।
दूरबीन उत्तर पश्चिमी चीन के किंघई प्रांत में लेंघू खगोलीय अवलोकन आधार पर स्थित है।
बेस, जो लगभग 4,000 मीटर की औसत ऊंचाई पर स्थित है, अपने साफ रात के आसमान, स्थिर वायुमंडलीय स्थितियों, शुष्क जलवायु और न्यूनतम कृत्रिम प्रकाश प्रदूषण के कारण तारों को देखने के लिए इष्टतम स्थिति प्रदान करता है।
इन कारकों ने इसे यूरेशियन महाद्वीप पर सर्वश्रेष्ठ वेधशाला स्थलों में से एक के रूप में मान्यता दी है।
WFST परियोजना जुलाई 2019 में चीन के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और चीनी अकादमी के तहत पर्पल माउंटेन वेधशाला के बीच सहयोग के माध्यम से शुरू की गई थी।
यह एक बड़ी पहल का हिस्सा है जिसमें 2017 से लेंघु बेस पर 12 टेलीस्कोप परियोजनाओं का निर्माण शामिल है, जिसमें लगभग 2.7 बिलियन युआन (लगभग 370 मिलियन डॉलर) का कुल निवेश है।
अपनी चल रही परियोजनाओं के साथ, लेंघू बेस पूरा होने पर एशिया में सबसे बड़ा खगोलीय अवलोकन बेस बनने की ओर अग्रसर है।

चीन के बारे में:

राष्ट्रपति: शी जिनपिंग
पूंजी: बीजिंग
मुद्रा: रॅन्मिन्बी

भारतीय वायु सेना ने स्वदेशी सैन्य लड़ाकू पैराशूट प्रणाली का परीक्षण किया

भारतीय वायु सेना (IAF) ने मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम की प्रभावकारिता और फुलप्रूफ कार्यप्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जिसे एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट (ADRDE) द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है।

परीक्षण के बारे में:

परीक्षण के दौरान, भारतीय वायुसेना के एक प्रशिक्षित परीक्षण जम्पर ने जानबूझकर मुख्य पैराशूट को अलग कर दिया।
इसके बाद, रिजर्व पैराशूट स्वचालित रूप से रिजर्व स्टेटिक लाइन (RSL) के माध्यम से तैनात हो गया।
यह परिनियोजन रिज़र्व हैंडल के मैन्युअल सक्रियण की आवश्यकता के बिना हुआ
परीक्षण से पता चला कि बैरोमेट्रिक ऑटोमैटिक एक्टिवेशन डिवाइस (AAD) के उपयोग में आने से पहले ही रिजर्व पैराशूट को सक्रिय किया जा सकता था।
AAD को आपातकालीन स्थिति में रिजर्व पैराशूट को स्वचालित रूप से सक्रिय करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

ADRDE के बारे में:

स्थापना: 1969
मुख्यालय: कानपुर, उत्तर प्रदेश
निर्देशक: मनोज कुमार
ADRDE भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) की एक प्रयोगशाला है।

उत्तर कोरिया ने हीरो किम कुन ओके नाम से नई 'सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी' लॉन्च की

उत्तर कोरिया ने अपनी पहली सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी, पनडुब्बी नंबर 841 को हीरो किम कुन ओके नाम से लॉन्च किया है, जिसका अनावरण देश के स्थापना दिवस (09 सितंबर, 1948) की 75वीं वर्षगांठ से पहले किया गया था।
उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग-उन ने व्यक्तिगत रूप से परमाणु संचालित पनडुब्बी के आधिकारिक प्रक्षेपण की निगरानी की।

हीरो किम कुन ओके के बारे में:

हीरो किम कुन ओके, कोरियाई प्रायद्वीप और जापान के बीच जल क्षेत्र में गश्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक संशोधित सोवियत काल की रोमियो श्रेणी की पनडुब्बी है, जिसे उत्तर कोरिया ने शुरुआत में 1970 के दशक में चीन से हासिल किया था और बाद में घरेलू स्तर पर उत्पादन शुरू किया।
पनडुब्बी 10 लॉन्च ट्यूब हैच से सुसज्जित है, जिससे विशेषज्ञों का मानना है कि यह बैलिस्टिक मिसाइलों और क्रूज़ मिसाइलों से लैस है।
पनडुब्बी को "सामरिक" के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिससे पता चलता है कि इसमें पनडुब्बी-प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल (SLBM) नहीं हो सकती है जो अमेरिकी मुख्य भूमि तक पहुंचने में सक्षम है। इसके बजाय, इसके पास संभवतः छोटी, कम दूरी की एसएलबीएम या पनडुब्बी से प्रक्षेपित क्रूज़ मिसाइलें (SLCM) हैं जो दक्षिण कोरिया, जापान या अन्य क्षेत्रीय स्थानों को निशाना बनाने में सक्षम हैं।
इस पनडुब्बी के विकास ने क्षेत्र में, विशेष रूप से दक्षिण कोरिया और जापान के बीच चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि यह उत्तर कोरिया की नौसैनिक क्षमताओं और पड़ोसी देशों को धमकी देने की क्षमता को बढ़ाती है।

नवीनतम समाचार:

जुलाई 2023 में,उत्तरकोरिया ने उत्तर कोरिया के प्योंगयांग से दूसरी बार अपनी नई ठोस-ईंधन अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) ह्वासोंग-18 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।
जुलाई 2023 में अमेरिका ने 1980 के दशक के बाद पहली बार दक्षिण कोरिया में एक परमाणु-सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी को डॉक किया।

नासा के लुसी अंतरिक्ष यान ने क्षुद्रग्रह डिंकिनेश की प्रारंभिक छवियां रिकॉर्ड कीं

नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) का लुसी अंतरिक्ष यान ने मुख्य बेल्ट क्षुद्रग्रह डिंकिनेश की अपनी पहली तस्वीरें खींची हैं, जो 12 साल की यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है।

डिंकिनेश क्षुद्रग्रह की खोज एवं विशेषताएँ:

डिंकिनेश क्षुद्रग्रह को पहली बार 1999 में LINEAR सर्वेक्षण के भाग के रूप में खोजा गया था।
इसे मध्यम बड़े प्रकाश-वक्र आयाम वाले धीमे रोटेटर के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
दिनकिनेश को एस-प्रकार के क्षुद्रग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो मुख्य रूप से सिलिकेट्स और कुछ धातु से बनी संरचना का संकेत देता है।
लुसी के मिशन में ट्रोजन क्लाउड्स की यात्रा के हिस्से के रूप में 1 नवंबर, 2023 को दिन्किनेश की उड़ान शामिल है।
डिंकिनेश की छवियों को लुसी के उच्च-रिज़ॉल्यूशन कैमरे का उपयोग करके कैप्चर किया गया था, जिसे लुसी लॉन्ग रेंज टोही इमेजर (L'LORRI उपकरण) के रूप में जाना जाता है।

लुसी मिशन का इतिहास:

लूसी मिशन को नासा ने 2021 में फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया था।
यह 12 साल का मिशन है जिसे बृहस्पति के नौ ट्रोजन और दो मुख्य बेल्ट क्षुद्रग्रहों का बारीकी से निरीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
लुसी पहला अंतरिक्ष यान है जिसे विशेष रूप से ट्रोजन क्षुद्रग्रहों का अध्ययन करने के लिए भेजा गया है, जो सूर्य के चारों ओर बृहस्पति के कक्षीय पथ को साझा करते हैं।
डिंकिनेश के अलावा, लुसी ने हाल ही में यूरीबेट्स, पॉलीमेले, ल्यूकस और ल्यूकस सहित अन्य क्षुद्रग्रहों की तस्वीरें खींची हैं।

नवीनतम समाचार:

अगस्त 2023 में, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) के सोलर टेरेस्ट्रियल रिलेशंस ऑब्जर्वेटरी (STEREO-A) अंतरिक्ष यान ने लॉन्च के लगभग 17 साल बाद पृथ्वी पर अपनी पहली उड़ान भरी।

नासा के बारे में:

स्थापना: 29 जुलाई, 1958
मुख्यालय: वाशिंगटन, डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका
प्रशासक: बिल नेल्सन

समुद्री वैज्ञानिकों ने जीनोम डिकोडिंग के माध्यम से इंडियन ऑयल सार्डिन के आनुवंशिक रहस्यों का खुलासा किया

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)-केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान (CMFRI) के वैज्ञानिकों ने भारत में एक लोकप्रिय खाद्य मछली, इंडियन ऑयल सार्डिन (सार्डिनेला लॉन्गिसेप्स) के पूरे जीनोम को डिकोड करके एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है।
यह पहली बार है कि भारतीय उपमहाद्वीप की समुद्री मछली प्रजाति के जीनोम को डिकोड किया गया है।
उम्मीद है कि इंडियन ऑयल सार्डिन का डीकोडेड जीनोम मछली के जीव विज्ञान, पारिस्थितिकी में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए एक मूल्यवान संसाधन के रूप में काम करेगा।

डिकोडेड जीनोम के बारे में:

डिकोड किए गए जीनोम का आकार 1.077 जीबी है और इसमें कुल 46,316 प्रोटीन-कोडिंग जीन शामिल हैं।
यह शोध भारतीय जल और ओमान की खाड़ी में पाए जाने वाले भारतीय तेल सार्डिन के बीच आनुवंशिक विविधता को समझने में मदद कर सकता है।

अनुसंधान दल एवं प्रकाशन:

जीनोम डिकोडिंग को उन्नत अगली पीढ़ी की अनुक्रमण तकनीक के माध्यम से पूरा किया गया और CMFRI के समुद्री जैव प्रौद्योगिकी प्रभाग में प्रधान वैज्ञानिक डॉ. संध्या सुकुमारन के नेतृत्व में किया गया।
शोध के निष्कर्ष नेचर समूह द्वारा उच्च प्रभाव वाली पत्रिका "साइंटिफिक डेटा" में प्रकाशित किए गए हैं।

इंडियन ऑयल सार्डिन के बारे में:

इंडियन ऑयल सार्डिन जीनस सार्डिनेला से संबंधित है और एक किरण-पंख वाली मछली प्रजाति है।
यह भारतीय उपमहाद्वीप में एक महत्वपूर्ण मत्स्य संसाधन है और भारत के कुल समुद्री मत्स्य उद्योग में लगभग 10% का महत्वपूर्ण योगदान देता है।

CMFRI के बारे में:

स्थापना: 1947
मुख्यालय: कोच्चि, केरल
निदेशक: डॉ. ए. गोपालकृष्णन

सहस्र इलेक्ट्रॉनिक भारत का पहला स्थानीय रूप से निर्मित डेस्कटॉप मदरबोर्ड पेश करेगा

नोएडा, उत्तर प्रदेश (यूपी) में स्थित सहस्र इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस, सहस्त्र समूह का हिस्सा है और नवंबर, 2023 में बाजार में पहला मेड-इन-इंडिया कंप्यूटर मदरबोर्ड पेश करने की तैयारी कर रहा है।
मदरबोर्ड, जिसे नवीनतम इंटेल 13वीं पीढ़ी के चिपसेट के आसपास डिजाइन किया जाएगा, वर्तमान में परीक्षण के दौर से गुजर रहा है।

मुख्य विचार:

सहस्र सेमीकंडक्टर, सहस्र समूह का एक हिस्सा, इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टर्स (SPECS) के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना का हिस्सा है।
यह उन्हें उनके पूंजीगत व्यय पर 25% वित्तीय प्रोत्साहन के लिए पात्र बनाता है।
सहस्र का निर्माण हुआ-भारत में मदरबोर्ड की कीमत तुलनीय चीनी ब्रांडों की तुलना में 10-15% कम होने की उम्मीद है जो वर्तमान में भारतीय कंपनियों द्वारा आयात किए जाते हैं।
यह कदम इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला में स्थानीय मूल्यवर्धन बढ़ाने के भारत सरकार के प्रयासों के अनुरूप है।
सहस्र समूह के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक: अमृत मनवानी

नासा का कैप्सूल पहला क्षुद्रग्रह नमूना लेकर पृथ्वी पर उतरा

राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन (नासा) यूटा में कैप्सूल पैराशूटिंग के साथ, गहरे अंतरिक्ष से अपना पहला क्षुद्रग्रह नमूना सफलतापूर्वक प्राप्त किया
क्षुद्रग्रह शिकार अंतरिक्ष यान OSIRIS-REx प्राचीन क्षुद्रग्रह सामग्री को इकट्ठा करने और वितरित करने के लिए जिम्मेदार था।
नमूना कैप्सूल 100,000 किमी की दूरी से पृथ्वी की उड़ान के दौरान छोड़ा गया था और लगभग 4 घंटे बाद सैन्य भूमि के एक दूरदराज के इलाके में उतरा।
नमूना देने के बाद, मदर-शिप OSIRIS-REx ने अपना मिशन जारी रखा और वर्तमान में 2029 में उस तक पहुंचने की योजना के साथ क्षुद्रग्रह एपोफिस का पीछा कर रहा है।

OSIRIS-रेक्स के बारे में:

OSIRIS-REx का मतलब ऑरिजिंस, स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, सिक्योरिटी, रेगोलिथ एक्सप्लोरर है।
OSIRIS-REx किसी क्षुद्रग्रह से नमूना एकत्र करने वाला नासा का पहला मिशन है।
अंतरिक्ष यान सितंबर 2016 में लॉन्च हुआ और दिसंबर 2018 में निकट-पृथ्वी क्षुद्रग्रह बेन्नू पर पहुंचा।
अक्टूबर 2020 में, OSIRIS-REx ने सतह से एक नमूना एकत्र करने के लिए बेन्नू को संक्षेप में छुआ।
पृथ्वी पर लौटने तक अंतरिक्ष यान ने कुल 6.2 बिलियन किमी (4 बिलियन मील) की दूरी तय की।
मिशन का उद्देश्य हमारे सौर मंडल के प्रारंभिक इतिहास और पृथ्वी पर क्षुद्रग्रह प्रभावों के संभावित खतरे के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करना है।
OSIRIS-रेक्स गहरे अंतरिक्ष रोबोटिक मिशन से नासा का तीसरा नमूना था।

जेनेसिस अंतरिक्ष यान ने 2004 में सौर हवा के टुकड़े गिराए, लेकिन जब पैराशूट विफल हो गया और कैप्सूल जमीन पर गिर गया तो नमूने खराब हो गए।
स्टारडस्ट अंतरिक्ष यान ने 2006 में सफलतापूर्वक धूमकेतु की धूल पहुंचाई।
बेन्नू एक निकट-पृथ्वी क्षुद्रग्रह है जो नासा के OSIRIS-REx मिशन का लक्ष्य है।
जापान एकमात्र अन्य देश है जिसने क्षुद्रग्रह मिशनों की एक जोड़ी के माध्यम से लगभग एक चम्मच सामग्री एकत्र करके क्षुद्रग्रह के नमूनों को सफलतापूर्वक वापस लाया है।
4.5 अरब साल पहले हमारे सौर मंडल की शुरुआत से संरक्षित भवन ब्लॉक, नमूने वैज्ञानिकों को यह बेहतर ढंग से समझने में मदद करेंगे कि पृथ्वी और जीवन कैसे बने।

नासा के बारे में:

स्थापना: 29 जुलाई, 1958
मुख्यालय: वाशिंगटन, डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका
प्रशासक: बिल नेल्सन

ताइवान ने परीक्षण के लिए द्वीप की पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी नरवाल/हाई कुन लॉन्च की

ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन ताइवान के काऊशुंग शहर में एक बंदरगाह पर अपने परीक्षण चरण के दौरान द्वीप की पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी "हाई कुन" का उद्घाटन किया गया।
पनडुब्बी को अपना आधिकारिक नाम "हाई कुन" मिला, जो विशाल आकार की एक पौराणिक मछली से लिया गया है जो समान रूप से विशाल पक्षी में बदलने की क्षमता के लिए जानी जाती है।
पनडुब्बी का अंग्रेजी नाम "नरव्हाल" है, जो नेशनल ज्योग्राफिक की दुनिया के सबसे अजीब प्राणियों की सूची में शामिल एक दांत वाली व्हेल नरव्हाल से प्रेरित है।

हाई कुन के बारे में:

"हाई कुन" पनडुब्बी एक प्रसिद्ध अमेरिकी एयरोस्पेस और रक्षा कंपनी लॉकहीड मार्टिन द्वारा विकसित युद्ध प्रणाली से सुसज्जित है।
यह एमके-48 मॉड 6 एटी हेवी-ड्यूटी टॉरपीडो से लैस है, जो वर्तमान में अमेरिकी नौसेना के साथ सेवा में हैं।
पनडुब्बी की अधिकतम गति 55 नॉट है, जो लगभग 101 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर है।
यह गति ताइवान की सेवा में मौजूदा स्टेगोसॉरस श्रेणी की पनडुब्बियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले जर्मन निर्मित एसयूटी टॉरपीडो की तुलना में उल्लेखनीय रूप से 60% तेज है।
बंदरगाह और समुद्री-यात्रा दोनों परीक्षणों को पास करने के बाद ही इसे सेना को सौंपा जाएगा।
सफल होने पर ताइवान एक और पनडुब्बी बनाने की योजना बना रहा है, दोनों को 2027 तक तैनात किया जाएगा

ताइवान के बारे में:

अध्यक्ष: त्साई इंग-वेन
पूंजी: ताइपे
मुद्रा: नया ताइवान डॉलर

अधिग्रहण और विलय

सॉफ्टबैंक ने 115 मिलियन डॉलर के लेनदेन के माध्यम से भारत के ज़ोमैटो में निवेश कम किया

सॉफ्टबैंक विजन ग्रोथ फंड ₹947 करोड़ ($114.7 मिलियन) मूल्य के लेनदेन के हिस्से के रूप में, एक उल्लेखनीय खाद्य वितरण फर्म ज़ोमैटो में 1.17% हिस्सेदारी बेच दी है।

मुख्य विचार:

जापान के सॉफ्टबैंक समूह का हिस्सा, उद्यम पूंजी ने थोक सौदों में 94.7 रुपये प्रति शेयर पर 100 मिलियन शेयर बेचे।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों के मुताबिक, जोमैटो के शेयर खरीदने वाली कंपनियों में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मॉर्गन स्टेनली एशिया सिंगापुर, सोसाइटी जेनरल, गोल्डमैन सैक्स (सिंगापुर), इनवेस्को म्यूचुअल फंड और कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस शामिल हैं।
नवीनतम विकास के साथ, सॉफ्टबैंक उन निवेशकों में शामिल हो गया है जो आंशिक रूप से या पूरी तरह से कंपनी से बाहर निकल गए हैं। इसमें अमेरिका स्थित निजी इक्विटी फर्म टाइगर ग्लोबल भी शामिल है जिसने 28 अगस्त 2023 को 1,124 करोड़ रुपये (136 मिलियन डॉलर) में अपनी शेष हिस्सेदारी बेची थी।

ज़ोमैटो के बारे में:

स्थापित: 2008
मुख्यालय: गुरुग्राम, हरियाणा, भारत
संस्थापक: दीपिंदर गोयल और पंकज चड्ढा
CEO: दीपिंदर गोयल

CCI ने टाटा SIA एयरलाइंस के एयर इंडिया में विलय को मंजूरी दे दी

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने टाटा SIA एयरलाइंस लिमिटेड (TSAL) के एयर इंडिया लिमिटेड (AIL) में विलय को मंजूरी दे दी है, और पार्टियों द्वारा प्रस्तावित स्वैच्छिक प्रतिबद्धताओं के अनुपालन के अधीन एयर इंडिया में सिंगापुर एयरलाइंस द्वारा कुछ शेयरधारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है।
इस मंजूरी के साथ, एयर इंडिया संभावित रूप से देश की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय वाहक और इंडिगो के बाद दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन बन सकती है।
प्रस्तावित संयोजन में (ए) टाटा SIA एयरलाइंस लिमिटेड (TSAL/विस्तारा) का एयर इंडिया लिमिटेड (AIL/एयर इंडिया) में विलय की परिकल्पना की गई है, जिसमें AIL जीवित इकाई (विलयित इकाई) होगी और (बी) विलय पर विचार किया जाएगा। सिंगापुर एयरलाइंस लिमिटेड (SIA) और टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड (TSPL) द्वारा मर्ज की गई इकाई में शेयरों का अधिग्रहण और (सी) तरजीही आवंटन के अनुसार SIA द्वारा मर्ज की गई इकाई में अतिरिक्त शेयरों का अधिग्रहण।

मुख्य विचार:

सौदे के एक हिस्से के रूप में, SIA 25.1% हिस्सेदारी के लिए एयर इंडिया की विस्तारित शेयर पूंजी में 2,059 करोड़ रुपये लगाएगी।
संयुक्त इकाई में टाटा संस की शेष 74.9% हिस्सेदारी होगी।

CCI के बारे में:

स्थापना: 14 अक्टूबर 2003
मुख्यालय: नई दिल्ली, दिल्ली, भारत
अध्यक्ष: रवनीत कौर
CCI भारत में मुख्य राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नियामक है।
यह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है।

TSAL के बारे में:

TSAL TSPL और SIA के बीच एक संयुक्त उद्यम (जेवी) है, जिसमें TSPL और SIA की कुल शेयरधारिता में क्रमशः 51% और 49% हिस्सेदारी है।
TSAL "विस्तारा" ब्रांड नाम के तहत काम करता है। TSAL निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करने के व्यवसाय में लगी हुई है: (ए) घरेलू अनुसूचित हवाई यात्री परिवहन सेवा, (बी) अंतर्राष्ट्रीय अनुसूचित हवाई यात्री परिवहन सेवा, (सी) एयर कार्गो परिवहन सेवाएं; और (घ) चार्टर उड़ान सेवाएं (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय)।

LIC म्यूचुअल फंड ने उत्पाद पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए IDBI म्यूचुअल फंड के साथ विलय को सफलतापूर्वक पूरा किया

LIC म्यूचुअल फंड (LIC MF) ने IDBI म्यूचुअल फंड की योजनाओं का अधिग्रहण पूरा कर लिया है।
यह रणनीतिक कदम LIC MF के अपने उत्पाद की पेशकश को मजबूत करने और विविधता लाने, अपनी बाजार उपस्थिति का विस्तार करने और भारत में एक प्रमुख फंड हाउस के रूप में खुद को स्थापित करने के लिए अपने एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) को बढ़ाने के उद्देश्यों के अनुरूप है।
जून 2023 तक, LIC MF ने 18,400 करोड़ रुपये की संपत्ति का प्रबंधन किया, जबकि IDBI MF के पास 3,650 करोड़ रुपये की संपत्ति थी।

मुख्य विचार:

विलय के बाद, IDBI MF द्वारा पहले प्रबंधित 20 योजनाओं में से 10 को LIC MF द्वारा संचालित समकक्ष योजनाओं में विलय कर दिया जाएगा।
शेष 10 योजनाओं को LIC MF द्वारा स्टैंडअलोन पेशकश के रूप में लिया जाएगा।
इस एकीकरण से LIC MF की कुल योजनाओं की संख्या बढ़कर 38 हो गई है।
इस विलय के साथ, जिन निवेशकों ने IDBI MF योजनाओं में निवेश किया है, उन्हें इक्विटी, ऋण, हाइब्रिड, समाधान उन्मुख थीम, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) और इंडेक्स फंड को कवर करने वाले LIC MF की विविध उत्पाद पेशकशों तक पहुंच मिलेगी।

नवीनतम समाचार:

मार्च 2023 में, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने IDBI एसेट मैनेजमेंट से IDBI एमएफ की योजनाओं पर प्रबंधन अधिकार हासिल करने के लिए LIC म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

LIC म्यूचुअल फंड के बारे में:

स्थापना: 1989
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र
MD और CEO: टीएस रामकृष्णन
LIC MF एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी (AMC) है, जिसका प्रायोजक भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) है और अन्य हितधारक LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, GIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हैं।

IDBI एमएफ के बारे में:

स्थापना: 2010
मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र
MD और CEO: राज किशोर सिंह

GQG ने IDFC फर्स्ट बैंक के वी वैद्यनाथन से 5 करोड़ से अधिक शेयर हासिल किए

अमेरिकी निवेश फर्म जीक्यूजी पार्टनर्स ने IDFC फर्स्ट बैंक के प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) वी वैद्यनाथन से 5 करोड़ से अधिक शेयरों का अधिग्रहण पूरा किया।
उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर एक्सचेंज 94.5 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर हुआ।
इस लेनदेन में IDFC फर्स्ट बैंक की कुल इक्विटी का लगभग 0.8% शामिल था।
निधियों का उपयोग: वी वैद्यनाथन ने बिक्री से प्राप्त आय का उपयोग इस प्रकार करने की योजना बनाई
IDFC फर्स्ट बैंक के नए शेयरों की सदस्यता के लिए 229 करोड़ रुपये।
स्टॉक विकल्प का उपयोग करने से संबंधित आयकर के भुगतान के लिए 240.5 करोड़ रुपये।
पूर्व-प्रतिबद्ध कारणों के लिए 9.2 करोड़ रुपये।
इस डील के पूरा होने के बाद बैंक में वैद्यनाथन की हिस्सेदारी 0.58% (30 जून, 2023 तक) से बढ़कर 1.04% हो जाएगी।
जिन विकल्पों पर अभी विचार किया जाना है, उन पर विचार करते समय, वैद्यनाथन की शेयरधारिता IDFC फर्स्ट बैंक की कुल शेयर पूंजी का 1.23% होगी।
वैद्यनाथन को दिए गए स्टॉक विकल्प मूल रूप से एक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी कैपिटल फर्स्ट से थे।

कैपिटल फर्स्ट का IDFC बैंक में विलय कर दिया गया था, और दिसंबर 2018 में विलय के बाद, इन स्टॉक विकल्पों को IDFC फर्स्ट बैंक स्टॉक विकल्पों में बदल दिया गया था।

IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में:

मुख्यालय: मुंबई,महाराष्ट्र, भारत
MD एवं CEO: वी. वैद्यनाथन
टैगलाइन: ऑलवेज यू फर्स्ट

रेज़रपे ने डिजिटल इनवॉइसिंग और ग्राहक सहभागिता स्टार्टअप बिलमी का अधिग्रहण किया

रेज़रपे बेंगलुरु स्थित एक फिनटेक प्लेटफॉर्म ने मुंबई स्थित डिजिटल इनवॉइसिंग और ग्राहक सहभागिता स्टार्टअप बिलमी का अधिग्रहण कर लिया है।

साझेदारी का उद्देश्य:

व्यवसायों को हाइब्रिड मॉडल के माध्यम से अंतिम उपभोक्ताओं के साथ जुड़ाव बढ़ाने में सक्षम बनाना।
यह अधिग्रहण रेज़रपे द्वारा 8वां अधिग्रहण है।
अगस्त 2022 में एंड-टू-एंड डिजिटल भुगतान कंपनी ईज़ेटैप के अधिग्रहण के साथ रेज़रपे द्वारा ओमनीचैनल भुगतान क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद से यह विशेष रूप से पहला अधिग्रहण है।

नवीनतम समाचार:

अप्रैल, 2023 में व्यवसायों के लिए एक फिनटेक भुगतान और बैंकिंग प्लेटफॉर्म रेजरपे, इंटरनेट शॉपिंग के विकल्प के रूप में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा स्थापित एक गैर-लाभकारी कंपनी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) के साथ जुड़ गया।

बिलमी के बारे में:

स्थापित: 2018
संस्थापक: कुबेर प्रितमणि, जय हेमराजानी और रूपम जैन
BillMe ने अपनी स्थापना के बाद से 4,000 से अधिक व्यवसायों और 15,000 रिटेल पॉइंट ऑफ़ सेल (POS) को अपनी सेवाएँ प्रदान की हैं।

रेज़रपे के बारे में:

स्थापना: 2014
मुख्यालय: बैंगलोर, कर्नाटक
प्रबंध निदेशक (MD): शशांक कुमार
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO): हर्षिल माथुर

CCI ने सेंटेला मॉरीशस होल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा क्वालिटी केयर इंडिया लिमिटेड में कुल इक्विटी शेयरधारिता के लगभग 24.16% के अधिग्रहण को मंजूरी दी

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने सेंटेला मॉरीशस होल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा क्वालिटी केयर इंडिया लिमिटेड में कुल इक्विटी शेयरधारिता का लगभग 24.16% के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है।
प्रस्तावित संयोजन सेंटेला मॉरीशस होल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा क्वालिटी केयर इंडिया लिमिटेड (QCIL) में कुल इक्विटी शेयरधारिता के लगभग 24.16% के अधिग्रहण से संबंधित है।

अधिग्रहण

सेंटेला मॉरीशस होल्डिंग्स लिमिटेड मॉरीशस में शामिल एक नव निगमित विशेष प्रयोजन निवेश वाहन है और वर्तमान में इसका भारत में कोई संचालन नहीं है। अधिग्रहणकर्ता का मुख्य स्वामित्व और नियंत्रण एक इकाई द्वारा किया जाता है, जिसे

TPG समूह की अंतिम होल्डिंग कंपनी TPG इंक (TPG) के सहयोगियों द्वारा सलाह दी जाती है। अपनी सहायक कंपनियों और सहयोगियों सहित TPG को एक साथ 'TPG समूह' कहा जाता है।
TPG समूह वित्तीय सेवाओं, प्रौद्योगिकी, उपभोक्ता, यात्रा, मीडिया, रियल एस्टेट और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों पर प्राथमिक ध्यान देने के साथ अपने विभिन्न निवेशों के माध्यम से भारत में काम करता है।

लक्ष्य

QCIL एक गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय हैदराबाद में है। QCIL भारत में एक बहुविशेषता स्वास्थ्य सेवा प्रदाता है। यह भारत के विभिन्न शहरों में CARE हॉस्पिटल्स ब्रांड नाम के तहत मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पतालों का एक नेटवर्क संचालित करता है। केयर हॉस्पिटल्स के पास भारत के 6 राज्यों के 7 शहरों में 17 स्वास्थ्य सुविधाएं (16 अस्पताल और 1 क्लिनिक) हैं।

CCI ने BCP द्वारा क्वालिटी केयर इंडिया में 72.49% हिस्सेदारी (लगभग) के अधिग्रहण को मंजूरी दी

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने BCP एशिया II द्वारा क्वालिटी केयर इंडिया में लगभग 72.49% हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है।
प्रस्तावित संयोजन सेंटेला मॉरीशस होल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा क्वालिटी केयर इंडिया लिमिटेड (QCIL) में कुल इक्विटी शेयरधारिता के लगभग 24.16% के अधिग्रहण से संबंधित है।
अधिग्रहणकर्ता को ब्लैकस्टोन इंक के सहयोगियों द्वारा सलाह दी गई और/या प्रबंधित धनराशि द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
टारगेट 1997 में स्थापित एक बहु-विशेषता स्वास्थ्य सेवा प्रदाता है।
यह भारत के विभिन्न शहरों में 'केयर हॉस्पिटल्स' ब्रांड नाम के तहत मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पतालों का एक नेटवर्क संचालित करता है।
टारगेट, सीधे और अपने डाउनस्ट्रीम सहयोगियों के माध्यम से, भारत के 6 राज्यों के 7 शहरों में ~2,400 बिस्तरों के साथ 17 स्वास्थ्य सुविधाएं (16 अस्पताल और 1 क्लिनिक) सेवा प्रदान करता है।

CCI ने 2452991 ओंटारियो लिमिटेड द्वारा हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट में एक अतिरिक्त इकाई हिस्सेदारी के अधिग्रहण और 2743298 ओंटारियो लिमिटेड द्वारा हाईवे कंसेशन्स वन प्राइवेट लिमिटेड में इक्विटी हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने 2452991 ओंटारियो लिमिटेड द्वारा हाइवेज इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट में एक अतिरिक्त इकाई होल्डिंग के प्रस्तावित अधिग्रहण और 2743298 ओंटारियो लिमिटेड द्वारा हाईवे कंसेशंस वन प्राइवेट लिमिटेड में इक्विटी हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है।
2452991 ओंटारियो लिमिटेड (OTPP 1) और 2743298 ओंटारियो लिमिटेड (OTPP 2) पूरी तरह से ओंटारियो टीचर्स पेंशन प्लान बोर्ड (OTTPB) द्वारा नियंत्रित हैं।
OTTPPB दुनिया भर में कनाडा के ओंटारियो प्रांत में सक्रिय और सेवानिवृत्त शिक्षकों के पेंशन लाभ और पेंशन योजना परिसंपत्तियों के निवेश का प्रबंधन करता है।
राजमार्ग अवसंरचना ट्रस्ट (टारगेट ट्रस्ट) एक बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट है जो सेबी (इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट) विनियम, 2014 (इनविट विनियम) के तहत भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ पंजीकृत है।
टारगेट ट्रस्ट के पास वर्तमान में भारत में छह (6) सड़क संपत्तियां हैं, जो भारत में सड़कों और राजमार्गों के संचालन के व्यवसाय में लगी हुई है।
हाईवे कन्सेशंस वन प्राइवेट लिमिटेड (एचसी वन) भारत में सड़क संपत्तियों के प्रबंधन और संचालन के उद्देश्य से निगमित कंपनी है।
एचसी वन इनविट विनियमों के तहत लक्ष्य ट्रस्ट का निवेश प्रबंधक है और इनविट विनियमों के विनियमन 10 के अनुसार गतिविधियां करता है, जिसमें लक्ष्य ट्रस्ट की अंतर्निहित संपत्तियों/परियोजनाओं के संबंध में निवेश निर्णय लेना और परियोजना

की गतिविधियों की देखरेख करना शामिल है। InvIT विनियमों और उसके द्वारा किए गए परियोजना प्रबंधन समझौते के अनुपालन के संबंध में लक्ष्य ट्रस्ट के प्रबंधक।
प्रस्तावित संयोजन OTPP 1 द्वारा लक्ष्य ट्रस्ट में अतिरिक्त यूनिटहोल्डिंग के अधिग्रहण और ओटीपीपी 2 (प्रस्तावित संयोजन) द्वारा एचसी वन में इक्विटी हिस्सेदारी के अलग अधिग्रहण से संबंधित है।

CCI ने कुछ व्यक्तियों के साथ पीआई अपॉर्च्युनिटीज फंड-I स्कीम-II द्वारा TVS क्रेडिट सर्विसेज लिमिटेड में कुछ शेयरधारिता को मंजूरी दी

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने कुछ व्यक्तियों के साथ पीआई अपॉर्च्युनिटीज फंड-I स्कीम-II द्वारा TVS क्रेडिट सर्विसेज लिमिटेड में कुछ शेयरधारिता के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है।
पीआई अवसर निधि-I योजना-II, भारत के कानूनों के तहत स्थापित एक ट्रस्ट है और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ श्रेणी II वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) के रूप में पंजीकृत है।
पीआई अपॉर्चुनिटीज फंड-1 स्कीम-2 का निवेश उद्देश्य कंपनियों में वृद्धि और विकास चरण के निवेश में निवेश करना है।
पीआई अपॉर्चुनिटीज फंड-I स्कीम-II का प्रबंधन पीआई इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एलएलपी द्वारा ट्रस्टी के एक प्रतिनिधि के रूप में किया जाता है, जिसका नाम हाशम प्रेमजी प्राइवेट लिमिटेड है।
पीआई अपॉर्चुनिटीज फंड-I स्कीम-II का स्वामित्व और नियंत्रण प्रेमजी इन्वेस्ट लिमिटेड (प्रेमजी इन्वेस्ट) के पास है।
पीआई अपॉर्चुनिटीज फंड-I स्कीम-II प्रेमजी इन्वेस्ट का सहयोगी है जो प्रेमजी फाउंडेशन की निजी इक्विटी और उद्यम पूंजी निवेश शाखा है।
प्रेमजी फाउंडेशन की स्थापना प्रेमजी इन्वेस्ट की परोपकारी पहलों को आगे बढ़ाने के लिए की गई थी और अंततः इसका नियंत्रण श्री अजीम प्रेमजी द्वारा किया जाता है।
व्यक्तिगत अधिग्रहणकर्ता प्रेमजी इन्वेस्ट और उसके सहयोगियों और ट्रस्टी के वरिष्ठ स्तर के प्रबंधन कर्मचारी, भागीदार और सलाहकार हैं और व्यक्तिगत अधिग्रहणकर्ताओं द्वारा किया गया निवेश एक अलग निवेश है।
TVS क्रेडिट सर्विसेज लिमिटेड भारत में निगमित एक गैर-जमा स्वीकार करने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण NBFC (NBFC-NDSI) है। इसने 2010 में खुदरा-केंद्रित NBFC के रूप में कारोबार शुरू किया।
TVS क्रेडिट सर्विसेज लिमिटेड मुख्य रूप से भारत में दोपहिया वाहन ऋण, प्रयुक्त कार ऋण, नए और प्रयुक्त ट्रैक्टर ऋण, प्रयुक्त वाणिज्यिक वाहन ऋण, MSME ऋण, उपभोक्ता टिकाऊ ऋण और व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने में लगी हुई है। TVS क्रेडिट का भारत के बाहर कोई व्यवसाय संचालन नहीं है।
प्रस्तावित संयोजन अधिग्रहणकर्ताओं द्वारा टारगेट की 10.98% हिस्सेदारी (पूरी तरह से पतला आधार पर) के प्रस्तावित अधिग्रहण से संबंधित है।
PIOF-II टारगेट में लगभग 10.79% शेयरधारिता प्राप्त करेगा, जबकि व्यक्तिगत अधिग्रहणकर्ता सामूहिक रूप से टारगेट में 0.19% शेयरधारिता प्राप्त करेंगे।

RBI ने साहेबराव देशमुख शहरी सहकारी बैंक के कॉसमॉस सहकारी बैंक के साथ विलय को मंजूरी दी

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने महाराष्ट्र के पुणे में स्थित कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के साथ साहेबराव देशमुख सहकारी बैंक के समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है।
इस समामेलन की मंजूरी RBI द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 44ए की उप-धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार और उसी अधिनियम की धारा 56 के संयोजन में दी गई है।
समामेलन के परिणामस्वरूप, द साहेबराव देशमुख को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की शाखाएं अपना परिचालन जारी रखेंगी, लेकिन वे अब द कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी।

यूटेलसैट-वनवेब विलय को अंतिम रूप मिलते ही वनवेब भारत में सेवाएं देने के लिए तैयार है

यूटेलसैट कम्युनिकेशंस एसए और वनवेब ने शेयरधारकों से मंजूरी मिलने के बाद एक पूर्ण-शेयर विलय पूरा किया।
इस विलय से यूटेलसैट समूह बनेगा, जिसमें वनवेब अब एक सहायक कंपनी के रूप में काम करेगी और व्यावसायिक रूप से यूटेलसैट वनवेब के रूप में काम करेगी।
पेरिस में मुख्यालय वाली, विलय की गई इकाई में भारती एंटरप्राइजेज 21.2% हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ी शेयरधारक होगी।
समूह ने यूटेलसैट समूह के बोर्ड में सुनील भारती मित्तल को सह-अध्यक्ष और श्रविन भारती मित्तल को निदेशक नियुक्त किया है।
अखिल गुप्ता वनवेब के बोर्ड में निदेशक के रूप में बने रहेंगे, जो अब यूटेलसैट की 100% सहायक कंपनी है, जिसका संचालन केंद्र लंदन में रहेगा।

किताबें और लेखक

वाल्टर इसाकसन की 'एलोन मस्क' की जीवनी दूसरी बेस्टसेलर बन गई है

एलोन मस्क की जीवनी पुस्तक ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म सर्काना बुकस्कैन द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, अमेरिकी लेखक-पत्रकार वाल्टर इसाकसन की पुस्तक की लॉन्च के बाद पहले सप्ताह के दौरान मजबूत बिक्री देखी गई, जिसकी कुल 92,560 प्रतियां बिकीं।

एलोन मस्क के बारे में:

एलोन रीव मस्क (जन्म 28 जून, 1971) एक बिजनेस मैग्नेट और निवेशक हैं।
मस्क स्पेसएक्स के संस्थापक, अध्यक्ष, सीईओ और मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी हैं; एंजेल निवेशक, सीईओ, उत्पाद वास्तुकार और टेस्ला, इंक के पूर्व अध्यक्ष; एक्स कॉर्प के मालिक, अध्यक्ष और CTO; बोरिंग कंपनी के संस्थापक; न्यूरालिंक और ओपनएआई के सह-संस्थापक; और मस्क फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं।
ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार, सितंबर 2023 तक 241 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमानित कुल संपत्ति के साथ वह दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं, और फोर्ब्स के अनुसार $261 बिलियन, मुख्य रूप से टेस्ला और स्पेसएक्स दोनों में उनके स्वामित्व हिस्सेदारी से।

शोक सन्देश

पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) के प्रमुख अरुण कुमार सिन्हा का निधन

विशेष सुरक्षा समूह (SPG) के निदेशक, भारत के प्रधान मंत्री को निकटतम सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार अरुण कुमार सिन्हा का 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

अरुण कुमार सिन्हा के बारे में:

अरुण कुमार सिन्हा 1987 केरल कैडर के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी थे।
उन्होंने मार्च 2016 में SPG के निदेशक की भूमिका संभाली और शुरुआत में उन्हें पुलिस महानिदेशक के पद और मुआवजे के साथ 31 मई, 2024 तक के कार्यकाल के साथ अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया था।
अपनी जिम्मेदारियों के प्रति उनके समर्पण के परिणामस्वरूप 31 मई तक सेवा में एक साल का विस्तार हुआ, जो भूमिका के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
उनका करियर विविध था, उन्होंने अपने गृह कैडर राज्य केरल और केंद्र में सीमा सुरक्षा बल (BSF) में विभिन्न पदों पर कार्य किया।

SPG के बारे में:

स्थापना: 8 अप्रैल 1985
मुख्यालय: नई दिल्ली, दिल्ली
SPG एक विशिष्ट बल है जिसे विशेष रूप से देश के वर्तमान और पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके तत्काल परिवार के सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करने का काम सौंपा गया है।

इसका गठन 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद किया गया था।

प्रसिद्ध 'मार्गरीटाविले' गायक, जिमी बफेट का निधन

जिमी बफेट, अमेरिकी गायक-गीतकार, जो की वेस्ट के एक शांत निवासी से स्थायी "मार्गरीटाविले" लाइफस्टाइल ब्रांड के लिए जिम्मेदार अरबपति में बदल गए, का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया है।

जिमी बफेट के बारे में:

जिमी बफेट बफेट का जन्म 25 दिसंबर, 1946 को पास्कागौला, मिसिसिपी, संयुक्त राज्य अमेरिका (US) में हुआ था।
वह एक अमेरिकी गायक-गीतकार, संगीतकार, लेखक और व्यवसायी थे।
वह अपनी अनूठी संगीत शैली के लिए प्रसिद्ध थे जिसे "ट्रॉपिकल रॉक" के नाम से जाना जाता था, जो "आइलैंड एस्केपिसिस्म" की अवधारणा का जश्न मनाती थी।

उल्लेखनीय कार्य:

उनकी महत्वपूर्ण सफलता "मार्गरीटाविले" से मिली, जो उष्णकटिबंधीय लय से भरा एक मधुर गीत था, जो जल्द ही रिज़ॉर्ट संगीतकारों के लिए एक प्रमुख गीत बन गया और कुछ हद तक लापरवाह बेबी बूमर पीढ़ी के लिए एक प्रिय अवकाश गान बन गया।
उनके समर्पित प्रशंसक वर्ग, जिनमें अधिकतर बेबी बूमर शामिल हैं, को "पैरोथेड्स" के नाम से जाना जाता है।

केरल कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष वक्कोम पुरूषोतमन का निधन हो गया

केरल के पूर्व स्पीकर और वरिष्ठ कांग्रेस नेता वक्कोम पुरूषोतमन का 95 वर्ष की आयु में केरल के तिरुवनंतपुरम में निधन हो गया।

वक्कोम पुरूषोत्तमन के बारे में:

वक्कोम पुरुषोत्तमन का जन्म 12 अप्रैल 1928 को केरल के त्रिवेंद्रम के पास वक्कोम में हुआ था।
वह 35 से अधिक वर्षों तक अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य रहे हैं।
वह अट्टिंगल विधानसभा क्षेत्र से 5 बार केरल विधानसभा के लिए चुने गए और 1971-1977, 1980-1981, 2004-2006 तक तीन बार मंत्री बने।
वह 1982 से 1984 और फिर 2001 से 2004 तक केरल विधानसभा के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे।
वह अलाप्पुझा निर्वाचन क्षेत्र से दो बार लोकसभा के लिए भी चुने गए और 1984 से 1991 और 1989-1991 तक सेवा की।
पुरूषोत्तम ने 1993 से 1996 तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के छठे उपराज्यपाल, 2011 से 2014 तक मिजोरम के राज्यपाल और 2014 में दो महीने के लिए त्रिपुरा के राज्यपाल के रूप में कार्य किया।

इसरो के लॉन्च काउंटडाउन के पीछे की आवाज एन. वलारमथी का निधन

एन वलारमथी,प्रसिद्ध भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन रॉकेट लॉन्च काउंटडाउन के दौरान अपनी आवाज के लिए मशहूर (ISRO) वैज्ञानिक का चेन्नई, तमिलनाडु (TN) में निधन हो गया।

एन. वलारमथी के बारे में:

वलारमति का जन्म अरियालुर, तमिलनाडु (टीएन) में हुआ था।
वह 1984 में इसरो में शामिल हुईं और इनसैट 2ए, IRS IC, IRS ID और द टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट (TES) सहित विभिन्न मिशनों में योगदान दिया।
विशेष रूप से, उन्होंने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में रॉकेट लॉन्च के लिए उलटी गिनती की घोषणा की, जिसमें चंद्रयान -3 के लिए आखिरी उलटी गिनती भी शामिल थी।
वह एक भारतीय वैज्ञानिक और भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित रडार इमेजिंग उपग्रह (RIS) रिसैट -1 की परियोजना निदेशक हैं, जिसे 2012 में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था।

पुरस्कार एवं सम्मान:

वह पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के सम्मान में तमिलनाडु सरकार द्वारा 2015 में स्थापित अब्दुल कलाम पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली व्यक्ति हैं।

जिम्बाब्वे के पूर्व क्रिकेट दिग्गज हीथ स्ट्रीक का निधन

जिम्बाब्वे के पूर्व महान क्रिकेटर कप्तान हीथ स्ट्रीक का 49 साल की उम्र में निधन हो गया।

हीथ स्ट्रीक के बारे में:

स्ट्रीक जिम्बाब्वे के क्रिकेटर और क्रिकेट कोच थे, जिन्होंने जिम्बाब्वे की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए खेला और कप्तानी की।
वह टेस्ट क्रिकेट में जिम्बाब्वे के लिए 65 टेस्ट मैचों में 216 विकेट के साथ सर्वकालिक अग्रणी विकेट लेने वाले गेंदबाज थे और 1,990 रन बनाए और एकदिवसीय क्रिकेट में 189 एकदिवसीय मैचों में 239 विकेट लिए और 2,943 रन बनाए।
टेस्ट और वनडे दोनों में, वह अब तक जिम्बाब्वे के अग्रणी विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं।
वह जिम्बाब्वे के एकमात्र क्रिकेटर हैं जिन्होंने 100 से अधिक टेस्ट विकेट लिए हैं और वनडे में 2000 रन और 200 विकेट का डबल पूरा किया है।
वह जिम्बाब्वे की उस टीम के प्रमुख सदस्य थे जो 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में क्रिकेट के प्रमुख देशों के खिलाफ प्रतिस्पर्धी थी।
2021 में, स्ट्रीक को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के भ्रष्टाचार विरोधी संहिता के उल्लंघन की बात स्वीकार करने के बाद क्रिकेट से 8 साल का प्रतिबंध दिया गया था।

ऑस्ट्रेलियाई ओलंपिक तैराकी स्वर्ण पदक विजेता जॉन डेविट का निधन

ऑस्ट्रेलियाई पूर्व तैराकी चैंपियन जॉन थॉमस डेविट का 86 वर्ष की आयु में सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में निधन हो गया।

जॉन डेविट के बारे में:

जॉन डेविट का जन्म 4 फरवरी 1937 को ग्रैनविले, न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था।
उन्होंने रोम में 100 मीटर फ्रीस्टाइल में अपना एकमात्र व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता।
वह चार साल पहले मेलबर्न खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली 4x200 ऑस्ट्रेलियाई फ्रीस्टाइल रिले के भी सदस्य थे।
उन्होंने मेलबर्न में 100 फ्रीस्टाइल में रजत पदक और रोम में ऑस्ट्रेलियाई 4x200 रिले टीम के साथ कांस्य पदक जीता।
उन्होंने 1958 के कार्डिफ़ ब्रिटिश साम्राज्य और वेल्स में राष्ट्रमंडल खेलों में 3 स्वर्ण पदक भी जीते।
बाद में उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई ओलंपिक समिति में एक कार्यकारी के रूप में कार्य किया और सिडनी को 2000 ओलंपिक के लिए बोली जीतने में मदद की।
वह मेलबर्न में 2006 के राष्ट्रमंडल खेलों के लिए ऑस्ट्रेलियाई शेफ डे मिशन भी थे।

पुरस्कार एवं सम्मान:

डेविट को 1979 में "ऑनर स्विमर" के रूप में इंटरनेशनल स्विमिंग हॉल ऑफ फेम और 1986 में स्पोर्ट ऑस्ट्रेलिया हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था।
उन्हें 1989 में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का सदस्य बनाया गया था, और 2000 में ऑस्ट्रेलियाई खेल पदक प्राप्त किया।

प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट अजीत निनान का निधन

अपने उत्कृष्ट व्यंग्यचित्रों के लिए विश्व स्तर पर जाने जाने वाले राजनीतिक कार्टूनिस्ट अजीत निनान का 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

अजीत निनान के बारे में:

अजीत निनान का जन्म 1955 में हैदराबाद, तेलंगाना में हुआ।
वह एक भारतीय राजनीतिक कार्टूनिस्ट थे, जिन्हें 'इंडिया टुडे' पत्रिका में कार्टूनों की सेंटरस्टेज श्रृंखला और 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में निनान वर्ल्ड के चित्रण के लिए जाना जाता है।

उन्हें उनकी प्रसिद्ध कॉमिक स्ट्रिप, 'डिटेक्टिव मूंछवाला' के लिए भी जाना जाता था, जिसमें 1980 के दशक में इंडिया टुडे की टारगेट पत्रिका में इसी नाम के जासूस और उसके पालतू कुत्ते को दिखाया गया था।

पुरस्कार एवं सम्मान:

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्टूनिस्ट्स ने अगस्त 2022 में बेंगलुरु में इंडियन कार्टून गैलरी में श्री निनान को बार्टन लाइफ-टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया।

मोल्दोवा के प्रथम राष्ट्रपति मिर्सिया स्नेगुर का निधन

मिर्सिया स्नेगुर, जिन्होंने मोल्दोवा को स्वतंत्रता दिलाई और इसके पहले राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, उनका 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है।

मिर्सिया स्नेगुर के बारे में:

स्नेगुर का जन्म 17 जनवरी 1940 को मोल्दोवा के सोरोका जिले के ट्रिफ़ानेस्टी में हुआ था।
1968 से 1973 तक, उन्होंने फील्ड कल्चर के प्रायोगिक स्टेशन के निदेशक के रूप में कार्य किया।
1973 से 1978 तक उन्होंने कृषि मंत्रालय के मुख्य कृषि विज्ञान निदेशालय के निदेशक के रूप में कार्य किया।
1978 और 1981 के बीच, उन्होंने सेलेक्टिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ फील्ड क्रॉप्स में जनरल डायरेक्टर का पद संभाला।
उन्होंने 1989 से 1990 तक सर्वोच्च सोवियत के प्रेसीडियम के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।
इसके अतिरिक्त, उन्होंने 27 अप्रैल से 3 सितंबर, 1990 तक सर्वोच्च सोवियत के अध्यक्ष का पद संभाला।
उन्होंने 1990 से 1997 तक मोल्दोवा के पहले राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और देश के इतिहास में इस महत्वपूर्ण अवधि के दौरान महत्वपूर्ण योगदान दिया।

मोल्दोवा के बारे में:

अध्यक्ष: मैया संदू
राजधानी: चिशिनाउ
मुद्रा: मोल्दोवन लियू

हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका मालिनी राजुरकर का निधन हो गया

ग्वालियर घराने की प्रतिपादक, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका मालिनी राजुरकर का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

मालिनी राजुरकर के बारे में:

राजुरकर का जन्म 1941 में राजस्थान के अजमेर में हुआ था।
उन्होंने पूरे भारत के प्रमुख संगीत समारोहों में प्रदर्शन किया, जिनमें गुनीदास सम्मेलन (मुंबई), तानसेन समारोह (ग्वालियर), सवाई गंधर्व महोत्सव (पुणे), और शंकर लाल महोत्सव (दिल्ली) शामिल हैं।
वह संगीत की "टप्पा" शैली में अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध थीं, जो भारतीय अर्ध-शास्त्रीय गायन संगीत का एक मनोरम रूप है।
टप्पा की विशेषता इसकी तीव्र गति और जटिल धुनें हैं।
उन्होंने मराठी नाट्यगीते (मराठी संगीत नाटक) की अपनी प्रस्तुतियों के लिए लोकप्रियता हासिल की, जिसमें "पांडु-नृपति जनक जया," "नरवर कृष्णसामान," और "या भावनातिल गीत पुराने" जैसे गाने शामिल हैं।
मालिनी राजुरकर को 2001 में भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला।

3 इडियट्स अभिनेता अखिल मिश्रा का 67 वर्ष की उम्र में निधन

अभिनेता अखिल मिश्रा, जिन्होंने आमिर खान अभिनीत '3 इडियट्स' और 'भोपाल: ए प्रेयर फॉर रेन' जैसी फिल्मों में काम किया है, रसोई में एक दुर्घटना के बाद उनका निधन हो गया।
वह 57 वर्ष के थे

अखिल के बारे में

अखिल मिश्रा का जन्म 1965 में हुआ था।
उन्होंने 'हजारों ख्वाहिशें ऐसी', 'गांधी, माई फादर' जैसी फिल्मों और 'प्रधानमंत्री' जैसे टेलीविजन धारावाहिकों में काम किया है।
उन्होंने '3 इडियट्स' में लाइब्रेरियन दुबे की कैमियो भूमिका और टीना दत्ता और रश्मि देसाई अभिनीत उतरन में उम्मेद सिंह बुंदेला की भूमिका निभाकर लोकप्रियता हासिल की।
अखिल की पहली शादी 1983 में मंजू मिश्रा से हुई थी, जिन्होंने 1983 में उनकी पहली फीचर फिल्म 'धत तेरे...की' और धारावाहिक 'गृहलक्ष्मी का जिन्न' में उनके साथ काम किया था।
1997 में मंजू की मृत्यु के बाद, उन्होंने फरवरी 2009 में जर्मन अभिनेत्री सुजैन बर्नर्ट से शादी कर ली।

दो बार निर्वाचित इटली के राष्ट्रपति जियोर्जियो नेपोलिटानो का निधन

इटली के पूर्व राष्ट्रपति जियोर्जियो नेपोलिटानो का 98 वर्ष की आयु में रोम, इटली में निधन हो गया।

जियोर्जियो नेपोलिटानो के बारे में:

जियोर्जियो नेपोलिटानो का जन्म 29 जून 1925 को नेपल्स, इटली में हुआ था।
उन्होंने 9 साल और 4 महीने से अधिक समय तक इटली के राष्ट्रपति का पद संभाला, जिससे वह इतालवी गणराज्य के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रपति बन गए।
उन्होंने 2006 से 2015 तक इटली के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया।
वह कार्यालय के लिए दोबारा चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति थे और उन्होंने 2013 में दूसरा कार्यकाल शुरू किया और 2015 में पद से इस्तीफा दे दिया।
वह इस पद पर दोबारा चुने जाने वाले इटली के पहले और एकमात्र राष्ट्रपति थे।
वह संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा करने वाले इतालवी कम्युनिस्ट पार्टी के पहले अधिकारी भी थे।
2005 में, उन्हें पूर्व राष्ट्रपति कार्लो एज़ेग्लियो सिआम्पी द्वारा आजीवन सीनेटर नियुक्त किया गया था।

भारत की हरित क्रांति के अग्रदूत, प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन का निधन

भारत की प्रतिष्ठित हरित क्रांति के जनक, प्रोफेसर मोनकोम्बु संबाशिवन स्वामीनाथन, या एमएस स्वामीनाथन, जैसा कि वह लोकप्रिय रूप से जाने जाते हैं - का चेन्नई, तमिलनाडु (टीएन) में निधन हो गया।

एमएस स्वामीनाथन के बारे में:

एमएस स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त, 1925 को तमिलनाडु के तंजावुर जिले में हुआ था।
उन्होंने 1961 से 1972 तक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) के निदेशक के रूप में कार्य किया।
IARI में अपने कार्यकाल के बाद, उन्होंने 1972 से 1979 तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) में महानिदेशक और कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग में भारत सरकार के सचिव के रूप में कार्य किया।
उन्होंने 1979 से 1980 के बीच कृषि मंत्रालय में प्रधान सचिव का पद संभाला।
1980 से 1982 तक, उन्होंने योजना आयोग के कार्यवाहक उपाध्यक्ष और तत्कालीन सदस्य (विज्ञान और कृषि) के रूप में कार्य किया।
1982 से 1988 तक, उन्होंने फिलीपींस में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (IRRI) में महानिदेशक के रूप में कार्य किया, जिसे रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित किया जाता है।
2004 में, उन्हें राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत में किसान संकट और आत्महत्या के मामलों को संबोधित करना था।
ग्रेनाडा, स्पेन में आयोजित 20वीं अंतर्राष्ट्रीय पोषण कांग्रेस में उन्हें "इंटरनेशनल यूनियन ऑफ न्यूट्रिशन साइंसेज का लिविंग लीजेंड" भी चुना गया था।
वह 2007-13 की अवधि के लिए भारतीय संसद (राज्य सभा) के सदस्य भी थे।
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा उन्हें "आर्थिक पारिस्थितिकी का जनक" कहा गया था।

पुरस्कार एवं सम्मान:
1987 में, उन्हें प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया जिसके बाद स्वामीनाथन ने $200,000 की पुरस्कार राशि का उपयोग करके चेन्नई के तारामणि में एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन (MSSRF) की स्थापना की।
वह पद्म श्री (1967), पद्म भूषण (1972) और पद्म विभूषण (1989) सहित भारत के कुछ सर्वोच्च सम्मानों के प्राप्तकर्ता थे।
उन्हें कई अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान मिले, जिनमें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार (1971), अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार (1986), पर्यावरण उपलब्धि के लिए टायलर पुरस्कार (1991), फोर फ्रीडम अवार्ड (2000), अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक संघ का पदक (2000) और द प्लैनेट एंड ह्यूमैनिटी शामिल हैं।

दिल्ली स्थित भरतनाट्यम कलाकार और पद्म भूषण पुरस्कार विजेता सरोजा वैद्यनाथन का निधन हो गया

भारतीय कोरियोग्राफर, गुरु और एक उल्लेखनीय प्रतिपादक भरतनाट्यम सरोजा वैद्यनाथन का 86 वर्ष की आयु में दिल्ली में निधन हो गया।

सरोजा वैद्यनाथन के बारे में:
सरोजा वैद्यनाथन का जन्म 19 सितंबर, 1937 को बेल्लारी, कर्नाटक, भारत में हुआ था।
उन्होंने 1974 में नई दिल्ली में गणेश नाट्यालय की स्थापना की
अपने करियर में, उन्होंने 10 से अधिक पूर्ण लंबाई वाले बैले और लगभग 2,000 व्यक्तिगत भरतनाट्यम आइटमों को कोरियोग्राफ किया।
उन्होंने छात्रों को नृत्य शैली के साथ-साथ हिंदी, तमिल और कर्नाटक संगीत भी सिखाया।
उन्होंने दिल्ली में भरतनाट्यम समुदाय का निर्माण किया।

पुस्तकें:
सरोजा वैद्यनाथन ने भरतनाट्यम और कर्नाटक संगीत पर कई किताबें लिखीं, जिनमें "भारत के शास्त्रीय नृत्य," "भरतनाट्यम - एक गहन अध्ययन," "कर्नाटक संगीतम," और "भरतनाट्यम का विज्ञान" जैसे शीर्षक शामिल हैं।

पुरस्कार एवं सम्मान:
पद्म पुरस्कार: उन्हें भारत सरकार द्वारा दो प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। उन्हें 2002 में पद्म श्री और 2013 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला।
साहित्य कला परिषद सम्मान: सरोजा वैद्यनाथन दिल्ली सरकार द्वारा दिए गए साहित्य कला परिषद सम्मान की प्राप्तकर्ता थीं।
कलईमामणि शीर्षक: उन्हें तमिलनाडु इयाल इसाई नाटक मनराम द्वारा कलईमामणि उपाधि से सम्मानित किया गया था।
संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार: सरोजा वैद्यनाथन को नृत्य के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला।
भरत कलै सुदर: 2006 में उन्हें 'भारत कलाई सुदर' की उपाधि से सम्मानित किया गया।

'हैरी पॉटर' में डंबलडोर की भूमिका के लिए प्रसिद्ध अभिनेता माइकल गैंबोन का निधन

ब्रिटिश-आयरिश अभिनेता माइकल गैंबोन, बाद की "हैरी पॉटर" फिल्मों में जादूगर एल्बस डंबलडोर के किरदार के लिए प्रसिद्ध, का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है।

माइकल गैंबोन के बारे में:
माइकल जॉन गैंबोन का जन्म 19 अक्टूबर 1940 को आयरलैंड के डबलिन के काबरा उपनगर में हुआ था।
उन्होंने रॉयल नेशनल थिएटर के मूल सदस्यों में से एक के रूप में लॉरेंस ओलिवियर के साथ अपने अभिनय करियर की शुरुआत की।
गैम्बन ने ओथेलो (1965) में अपनी फिल्म की शुरुआत की।
माइकल गैंबोन कई में दिखाई दिएउल्लेखनीय फिल्में, जिनमें "द कुक, द थीफ, हिज वाइफ एंड हर लवर" (1989), "द विंग्स ऑफ द डव" (1997), "द इनसाइडर" (1999), "गोस्फोर्ड पार्क" (2001), "अमेजिंग ग्रेस" (2006), "द किंग्स स्पीच" (2010),

"क्वार्टेट" (2012), और "विक्टोरिया एंड अब्दुल" (2017)।
उन्होंने वेस एंडरसन की फिल्मों "द लाइफ एक्वाटिक विद स्टीव ज़िसौ" (2004) और "फैंटास्टिक मिस्टर फॉक्स" (2009) में भी भूमिकाएँ निभाईं।
1980 में नेशनल थिएटर में बर्टोल्ट ब्रेख्त की "द लाइफ ऑफ गैलीलियो" के जॉन डेक्सटर के मंचन में गैंबोन की शक्तिशाली आवाज और उपस्थिति को उजागर किया गया, जो एक लोकप्रिय सफलता बन गई।

पुरस्कार एवं सम्मान:

अपने छह दशक लंबे करियर में, उन्हें ए कोरस ऑफ डिसएप्रूवल (1985), ए व्यू फ्रॉम द ब्रिज (1987), और मैन ऑफ द मोमेंट (1990), 2 स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स और द सिंगिंग डिटेक्टिव (1986), वाइव्स एंड डॉटर्स (1999), देशांतर (2000), और परफेक्ट अजनबियों (2001) के लिए 4 बाफ्टा पुरस्कार मिले।
उन्हें पाथ टू वॉर (2002) और एम्मा (2009) के लिए 2 प्राइमटाइम एमी पुरस्कार नामांकन भी मिले।
2017 में, उन्हें आयरिश फिल्म एंड टेलीविजन अकादमी लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला।